

4-10 44 21 00, 4 43 42

ॐ नमो, नमो नमो
१११ १२

भाग १



विषयवस्तु

पृष्ठ संख्या

1—3

4—6

1. भूमिका
2. सिद्धान्तोक्त
निधियों का आबंटन और उनका उपयोग
पट्टीय शिक्षा नीति की समीक्षा
कार्यक्रम कार्यान्वयन
आर्थिक शिक्षा
प्रौढ़ साक्षरता
माध्यमिक शिक्षा
शिक्षक-शिक्षा
तकनीकी शिक्षा
विविधविद्यालय और उच्चतर शिक्षा
भाषा-विकास
सौभाग्योत्तम क्षेत्र विकास (शिक्षा) कार्यक्रम
अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और
महिलाओं की शिक्षा
शिक्षा के लिए संसाधन
3. प्रशासन
संगठनात्मक संरचना/ (ढाँचा)
अधीनस्थ कार्यालय/ स्वायत्त संगठन
कार्य
सतर्कता कार्यकलाप
सरकारी कार्य में हिन्दी का अगामी प्रयोग
प्रकाशन
विदेशों में प्रतिनिधुक्त/शिष्टमण्डल
बजट आकलन
व्यावसायिक विकास और कर्मचारियों का प्रशिक्षण
विज्ञान प्रदर्शनी
4. आर्थिक शिक्षा
आर्थिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण
ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड
नैट-औपचारिक शिक्षा
शिक्षा की संगणिकृत आयोजना
महिला साम्रख्या
विहार शिक्षा परियोजना
शिक्षा कमी परियोजना
लोक भूमिधसः सभी के लिए शिक्षा
सम्बन्धी जन-आन्दोलनः राजस्थान
शिक्षक शिक्षा
अध्ययन की सुख्य आयोजना
बाल ध्वन सौसाइटी

7—9

10—16

5.

भाषात्मिक शिक्षा

भाषात्मिक शिक्षा का व्यवसायीकरण

शैक्षिक प्रौद्योगिकी कार्यक्रम

स्कूलों में विज्ञान शिक्षा का सुधार

अन्तर्राष्ट्रीय गणितीय ओलिम्पियाड-स्कूल शिक्षा

स्कूल शिक्षा में पर्यावरण बोध

स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षा

राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परिचोजना

विकासी। बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा

मुम्बई के दीपन भवन बच्चों के माँरे गए या

विकासी। अधिकांशी और जवानों के बच्चों

को शैक्षिक रियायतें

योग को भीतराइन

संस्कृति/कला/शिक्षा के मूल्यों के सुदृढीकरण

के लिए एजीन्सियों को सहायता तथा नवाचार

कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने वाली शैक्षिक

संस्थाओं को सहायता

राष्ट्रीय एकता को दृष्टि से स्कूल

पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा

शिक्षकों को राष्ट्रीय प्रशंसा

स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में रू.प्राप्तिक

आदान-प्रदान कार्यक्रम

राष्ट्रीय खुला विद्यालय

राष्ट्रीय शिक्षक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद

राष्ट्रीय शैक्षिक कल्याण प्रतिष्ठान

केन्द्रीय भाषात्मिक शिक्षा बोर्ड

मजीदय विद्यालय

केन्द्रीय लिखती स्कूल प्रशान्न

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

उच्चार शिक्षा और अनुसन्धान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

इंटरिय गणनी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

केन्द्रीय विश्वविद्यालय

नए विश्वविद्यालयों की स्थापना

विशेषबला वाले अनुसन्धान संगठन

रमणीको शिक्षा

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी अभियांत्रिकी प्रशिक्षण संस्थान

राष्ट्रीय उद्यमई तथा गवार्ड प्रौद्योगिकी संस्थान

जीवन एवं वास्तुकला विद्यालय

रमणीको शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान

रमणीको शिक्षा के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज

बालकमेतर पाठ्यक्रमों और योग्य कार्य का विकास

‘गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम

तकनीकी शिक्षा की सहायता हेतु विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त परियोजना। संस्थागत नेटवर्क योजना। तकनीकी शिक्षा के महत्वपूर्ण क्षेत्र आधुनिकीकरण और अभवतरी का विकास। राष्ट्रीय तकनीकी मानव शक्ति सूचना भणाली गैर-विश्वविद्यालय क्षेत्रों से प्रत्यक्ष शिक्षा का विकास अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद सामुदायिक परित्तेलिक प्रशिक्षण कार्यक्रम परिषदाई प्रौद्योगिकी संस्थान, बैंकाक शैक्षिक अर्हता मूल्यांकन बोर्ड आर्थिक विनीत सहायता गैर-निगमित तथा अर्भाडित क्षेत्रों के नए संस्थाओं की स्थापना और विद्यमान संस्थाओं का सुदृढीकरण उद्योग संस्थान अन्तर्क्रिया सतत शिक्षा तकनीकी शिक्षा संस्था से अनुसन्धान और विकास भारतीय शैक्षिक परामर्शदाता रिनिटेड, नई दिल्ली आयात उपकरण के लिए पास-बुक लोपोबातन इजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान विन्नुअण् के माध्यम से तकनीकी संस्थाओं को सहायता प्रदान करना उच्च तकनीकीशोध पाठ्यक्रम सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम तकनीकी शिक्षा के लिए कोलाबो योजना, मनीला उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान

8

ग्रैंड शिक्षा

१९९१ की जनगणना की प्रभावशाली विशेषताएँ समग्र साक्षरता अभियान बर्दवान पूर्ण साक्षरता अभियान पाण्डिचेरी समग्र साक्षरता अभियान सिधदुर्गे से सम्पूर्ण साक्षरता रक्षणा कटक से सम्पूर्ण साक्षरता अभियान राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अन्तर् महत्वपूर्ण क्षेत्र केन्द्र आधारित कार्यक्रम का पुनर्गठन शैक्षिक रेजिस्टरा छात्र सहायतागत उत्तर साक्षरता और सतत शिक्षा टी० एन्० सी० क्षेत्रों से उत्तर साक्षरता अभियान श्रमिक विद्यापीठ प्रौद्योगिकी मदर्शन

शैक्षिक एवं तकनीकी संसाधन सहयोग।

प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय

अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस

राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान

मूल्यंकन

9.

संघ शामिल क्षेत्रों में शिक्षा

अवधान और निवेशाई दीपसमूह

चण्डीगढ़

दादरा और नगर हवेली

दमन और दीव

दिल्ली

लक्षदीप

पण्डिचेरी

75—80

10.

छात्रवृत्तियां

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना

अनु० जा० / अनु० जा० के छात्रों को योग्यता के प्रीक्षण की योजना

अनुमोदित आवासीय साध्यमिक स्थलों में

भारत सरकार की छात्रवृत्ति योजना

हिन्दी में उत्तर-मैट्रिक अध्ययनों के लिए

अहिन्दी भाषी राज्यों के छात्रों को छात्रवृत्तियां

संस्कृत अधीत अरबी और फारसी आदि

के अतिरिक्त श्रेण्य भाषाओं के अध्ययन में लगने हुई

परम्परागत संस्थाओं से उत्तीर्ण छात्रों को अनुसंधान

छात्रवृत्तियां

ग्रामीण क्षेत्रों से प्रतिभाशाली बच्चों के लिए

माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना

भारत तथा विदेशों में विभिन्न विषयों में

छात्रवृत्तियां अध्ययनों के लिए जवाहरलाल नेहरू

शिक्षावृत्ति की योजना

सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों के तहत विदेशी

सरकारों द्वारा प्रदान की जाने वाली

छात्रवृत्तियां / शिक्षावृत्तियां

यू० के०, कनाडा आदि की सरकारों द्वारा प्रदत्त

राष्ट्रमण्डलीय छात्रवृत्ति / शिक्षावृत्ति योजनाएं

नेहरू शताब्दी (ब्रिटिश) शिक्षावृत्तियां / पुरस्कार

ब्रिटिश तकनीकी सहयोग प्रशिक्षण कार्यक्रम

जवाहरलाल नेहरू स्मारक (यू० के०) छात्रवृत्तियां

ब्रिटिश विजिटरीय कार्यक्रम परिषद

81—82

11.

पुस्तक प्रीति तथा कापीपट्ट

राष्ट्रीय पुस्तक व्यास

पुस्तक संवर्धन कार्यक्रम तथा सैन्ट्रिक

संगठनों की वित्तीय सहायता

83—86

विश्वविद्यालय स्तर की विदेशी मूल की

सस्ती पुस्तकों का प्रकाशन

भारत-रूस साहित्यिक परियोजना

राष्ट्रीय पुस्तक विकास परिषद

पुस्तकों और प्रकाशनों के लिए

नई आयात-नीति

पुस्तक निर्यात और संवर्धन कार्यक्रम

अंतर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्यांकन

के लिए राजा राममोहन राय

राष्ट्रीय एजेसी

कापीराइट

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्याधिकार

प्रतिलिप्याधिकार के क्षेत्र में प्रशिक्षण सुविधाएं

प्रतिलिप्याधिकार प्रवर्तन सलाहकार परिषद

- | | | |
|----|--|---------|
| 12 | भाषाओं की प्रौद्योगिकी
हिन्दी की प्रौद्योगिकी और विकास
आधुनिक भारतीय भाषाओं (एम०आई०एल०) का
संवर्धन एवं विकास
अंग्रेजी भाषा शिक्षण में सुधार
संस्कृत तथा अन्य श्रेष्ठ भाषाओं की प्रौद्योगिकी | 87—91 |
| 13 | सामाजिक क्षेत्र विकास (शिक्षा) कार्यक्रम | 92—93 |
| 14 | बौद्ध सूत्रों कार्यक्रम और वंचित वर्ग के लिए शिक्षा को सुलभ बनाना
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की शिक्षा
अल्पसंख्यकों की शिक्षा
महिलाओं की शिक्षा | 94—95 |
| 15 | प्रबंध अनुवीक्षण और मूल्यांकन
राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा
केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (सी०ए०बी०ई०)
राष्ट्रीय शैक्षिक आयोगों और प्रशासन संस्थान
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए
अध्ययन, संगोष्ठियों, मूल्यांकन आदि के लिए सहायता-योजना
विभाग के लिए कम्प्यूटरीकृत प्रबंध सूचना प्रणाली
(सी०एम०आई०एस०) का विकास
आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992—97) और
वार्षिक-योजना (1992-93) को तैयार करना
शैक्षिक सांख्यिकी | 96—99 |
| 16 | यूनेस्को और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग
विकास के लिए एशिया प्रशांत शैक्षिक नवोत्थान कार्यक्रम (एपीड)
सबके लिए प्रशांत शिक्षा कार्यक्रम (अपील)
यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय
राष्ट्रीय आयोग का इकोसवा सत्र
यूनेस्को, पेरिक के आम सम्मेलन का 26वाँ सत्र
अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा ब्यौरा परिषद का 34वाँ सत्र | 100—105 |

महिलाओं व लड़कियों के लिए कुशलता-अभ्यासः-

संक्षेपतः प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए उपक्षेत्रीय कार्यशाला

प्रशिक्षण व भ्रमण महसूसार से धूरेस्को संस्थानि

क्रियाकलापों से क्षेत्रीय संस्थाओं पर विशेषज्ञों की दसवी बैठक

थाईलैंड, रियाध माय में प्रशिक्षा व भ्रमण महसूसार में शिक्षा में क्षेत्रीय संस्थाओं पर संलाहकार समिति का छठा सत्र

शिक्षा व उत्पादक कार्य के बीच मूल्यभान, पनरीक्षण

व उत्तम परस्परिक क्रिया क्षेत्रीय कार्यशाला

दक्षिण प्रशिक्षाई देशों में जन-शिक्षा-तकनीकी

आदान-प्रदान कार्यक्रम

दक्षिण प्रशिक्षाई देशों के लिए आर्थिक शिक्षक

प्रशिक्षकों के लिए पर्यावरण-शिक्षा में प्रशिक्षण कार्यशाला

दक्षिण प्रशिक्षाई उपलक्षेत्र के लिए जनसंख्या-शिक्षा में

एक-मुप-प्रशिक्षण-पर्यायक्रम

बम्बई में 25-29 नवम्बर, 1991 को लड़कियों के लिए

प्राथमिक शिक्षा के संवर्धन के लिए महिला-शिक्षकों की

शुभिका पर उप-क्षेत्रीय कार्यशाला

सबके लिए शिक्षा के सम्बन्ध में अन्तर्देशीय

परामर्शदात्री फोरम की प्रथम बैठक

मानव संसाधन विकास में महिलाओं से सम्बंधित विषयों को शामिल करने के तरीकों पर प्रशिक्षा में क्षेत्रीय सेमिनार

धूरेस्को द्वारा आयोजित अन्त्य संयोजना / बैठक / कार्यशालाओं / कार्यदलों में पारल की सहभागिता

धूरेस्को ज्वल के लिए योगदान

धूरेस्को अंगीत बोर्ड

विश्वपर में बास्केटबॉल परपरा और आयुनिकता पर प्रदर्शनी में भाग लेना

धूरेस्को का कार्यकारी-बोर्ड

विश्व विप्लव समिति

शिक्षा पर एस० ए० ए० आर० सी० तकनीकी समिति

विदेशी शैक्षिक सन्ध

विदेशों से आगतिक

धूरेस्को का सहभागिता कार्यक्रम

अन्तर्देशीय संस्कारों के लिए शिक्षा

धूरेस्को क्लब और सम्बन्ध स्कुल

प्रशिक्षा भ्रमण में 16वीं फोर्ट प्रतिदर्शिता

अन्तर्देशीय साक्षरता प्रत्यक्ष

विशान की लोकप्रियता के लिए 1991 का कालिा प्रत्यक्ष

धूरेस्को क्लब कार्यक्रम

धूरेस्को क्लब के भारतीय भाषा मन्त्रियों का भ्रमण

स्वीडिश मित्रियों, धूरेस्को क्लबों तथा सम्बन्ध मन्त्रियों के लिए विनीय संलापना

अभिलेख

स्वीडिश संलापना की अनुदान

केन्द्रीय आयोजित और राजश्री-नी-योजनाओं की लागू करने के लिए गज्यो सत्र शामिल क्षेत्रों की विनीय संलापना सक्की परिक्षा 148-156

शैक्षिक संस्थानों के आकृष्ट 157-182

चार्ट 183-201

महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों के लिए विनीय संलापना 202-207

भ्रमणसमिक चार्ट

1. 27m

1. भूमिका

1.10 मानव संग्राहण विकास मंत्रालय शिक्षा, युवक, महिला और बच्चों, कला, संस्कृति और खेल-कूद के क्षेत्र में मानव क्षमता का विकास करने के लिए सभी प्रयासों को एकीकृत करने के लिए 1985 में बनाया गया था। इस रिपोर्ट में चार विभागों, जो मंत्रालय के घटक हैं, के कार्यक्रमों पर देते हैं। ये रिपोर्ट निम्नलिखित भागों में प्रस्तुत की गई हैं —

भाग-1	शिक्षा
भाग-2	संस्कृति
भाग-3	युवा कार्य और खेल-कूद
भाग-4	महिला और बाल विकास

शिक्षा विभाग

1.2.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति (राशिनी) समूह में 1986 में स्वीकृत की गई थी और इसके तुरंत बाद इसका कार्यान्वयन शुरू कर दिया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति और केब (केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय बोर्ड) के अंतर्गत नीति संबंधी समिति श्री एन. जॉन्सन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री, की अध्यक्षता में स्थापित की गई थी। समिति का राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जुड़ी उन सभी घटनाओं को जनक इंग्रज पर प्रभाव पड़ा है, तथा राष्ट्रीय शिक्षा गान समिति समिति की अध्यक्षता में कार्य में गठना था। इस समिति ने 22 जनवरी, 1987 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट पर केब द्वारा विचार किया जाता है। केब का निर्णय प्राप्त रूप पर सरकार इस नीति को संशोधित किया जाने के संकेत में अपने दृष्टिकोण का अंतिम रूप देगा।

1.2.2 प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभिकरण, शैक्षिक अवसरों की समानता, महिला शिक्षा और विकास, स्कूली शिक्षा के व्यावसायिकरण, उच्च शिक्षा के समेकन, तकनीकी शिक्षा के आधुनिकीकरण, सभी स्तरों पर शिक्षा की प्रक्रिया और कौशल सुधार राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय प्रयासों के मुख्य अंश बने रहें।

1.2.3 प्रारम्भिक शिक्षा में पहले दाखिले पर बल दिया जाना था किन्तु अब स्कूल में बनाए रखने और उपलब्ध पर बल दिला जाने लगा-यह एक ऐसा बदलाव था जिसमें निवेश की प्रभावकारिता में सुधार लाने और साथ ही कार्यक्रमों का मूल्यांकन करते समय उनके लाभांशित हुए व्यक्तियों की संख्या तथा कार्यक्रमों पर किए खर्च को ही आधार मानने की बजाय उनके परिणामों को ध्यान में रखने के प्रति एक नया सोच परिलक्षित होता है। साथ ही पहले मात्र स्कूली शिक्षा पर महत्व दिया जाता था जिसे अब एक व्यापक दृष्टिकोण में परिणत कर दिया गया है जिसमें ऐसे कामकाजों बच्चों और बालिकाओं को जनक लिए स्कूल सुलभ नहीं होते, समग्र स्तर की वैकल्पिक शिक्षा पद्धति मूल्यांकन करने पर बल दिया गया। सहभागी सूक्ष्म आयोजना और स्थानीय स्तर क्षमता निर्माण की अवधारणाओं को व्यापक समर्थन दिया गया और प्रयोगात्मक परिोजनाओं में माध्यम से उनकी जांच परख की गई। शिक्षा के सर्वसुलभिकरण के दिश्य की प्राप्ति की कार्यनीति के लिए ये महत्वपूर्ण तत्व होंगे।

2.4 प्रौढ़ साक्षरता के क्षेत्र में पूर्ण साक्षरता अभियानों (पू-सा-अभि) में

प्रारम्भिक शिक्षा के और अधिक सर्वसुलभिकरण के लिए सामुदायिक सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। केरल राज्य का अनुसरण करते हुए मध्याह्न शांति क्षेत्र पाईचेरी, पश्चिम बंगाल का वर्धवान जिला, महाराष्ट्र के सिधुदुर्ग और कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिलों ने अभियान के माध्यम से पूर्ण साक्षरता प्राप्त कर ली है। ये अभियान देश के सौ से भी अधिक जिलों में या तो पूरी तरह से या आंशिक रूप में चल रहे हैं। इसके परिणाम 1991 की जनगणना के अन्तिम आंकड़ों में झलकते हैं जिनसे यह पता चलता है कि साक्षरता को दर पहली बार 50 प्रतिशत से अधिक हो पाई है। यह एक गौरव की बात है और साक्षरता के मोर्चे पर प्राप्त सफलता का परिचायक है कि लगातार दूसरे वर्ष भारत में गौरवशाली नोमा साक्षरता पुरस्कार प्राप्त किया है, इस बार यह पश्चिम बंगाल सरकार को मिला रहा है।

1.2.5 शिक्षा की विषय वस्तु में, राष्ट्रीय एकता, धर्मनिरपेक्षता, महिलाओं को और अधिक अवसर प्रदान किए जाने जैसे बुनियादी मूल्यों के प्रोत्साहन और विकास पर तथा पर्यावरणीय और जनसंख्या शिक्षा आदि पर बल दिया जाता रहा।

1.2.6 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने अक्टूबर-नवम्बर, 1991 के दौरान पेरिस में आयोजित यूनेस्को के 26वें महा-सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में यूनेस्को के आंध्रकार क्षेत्रों में 1992-93 के दो वर्षों के लिए कार्यक्रम और बजट अनुमोदित किए। इसी वर्षीय शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय किया गया है। इसके अतिरिक्त सभी के लिए शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय परामर्शदात्री तंत्र की दिसम्बर, 1991 में बैठक हुई जिसमें सन् 2000 ई० तक "सभी के लिए शिक्षा" प्राप्त करने के लिए जायिमना सम्मेलन में स्वीकृत उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न विकासवाचक एजेंसियों और यूनेस्को के सदस्य देशों द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा की गई।

1.2.7 शिक्षा के क्षेत्र में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विचार की गई कार्यनीतियों में निम्नलिखित की आवश्यकता स्वीकार की गई—

(I) कार्यक्रम/योजनाओं के कार्यान्वयन में राज्य/संघशासित क्षेत्रों का सहयोग और भागीदारी।

(II) वैश्विक प्रयासों/एजेंसियों का सहयोग जुटाना।

(III) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग और भागीदारी।

संस्कृति विभाग

1.3.1 वर्ष 1991-92 में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर कला तथा संस्कृति के प्रोत्साहन, विकास और प्रसार पर निरंतर बल दिया जाता रहा। क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों ने विभिन्न क्षेत्रों के लोगों में सांस्कृतिक जागरूकता लाने के लिए क्षेत्रीय संगीतों का आतिशय किया। इन केंद्रों में कतिपय मृत कला रूपों के प्रलेखन और परिरक्षण पर बल देते हुए लोक, जनजातीय तथा प्राचीन कला की ओर ध्यान दिया और साथ ही राष्ट्रीय एकता और सद्भावना के लिए अन्तः क्षेत्रीय सांस्कृतिक समारोह भी

आयोजित किए गए। वर्ष के दौरान हगरी, पेरू, कोरिया जनवादी जन गणराज्य, मंगोलिया, ओमान, कोलम्बिया, जाइन्, श्रीलंका और जिम्बावे के साथ सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों पर हस्ताक्षर/नवीकरण करने के अलावा जर्मनी में प्रदर्शनियों, सेमिनारों, निष्पादन कलाओं और एक फिल्म समारोह सहित सितम्बर, 91 में भारत उत्सव आयोजित किए गए। इस महोत्सव ने जर्मनी के लोगों के लिए हमारी संस्कृति की खिडकियां खोलने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

1.3.2 हमारी सांस्कृतिक विपुल अर्थात् हमारे ऐतिहासिक स्मारकों और पुस्तकालयों के संरक्षण और रख-रखाव के लिए उदात्त विभागीय संस्थाओं ने वर्ष के दौरान अपने कार्यक्रमों पर हस्ताक्षर/नवीकरण करने के अतिरिक्त प्रमुख संरचनात्मक संरक्षण के लिए 490 स्मारकों का काम अपने हाथ में लिया। देश के पिछड़े-पिछड़े भागों में गांव-गांव के सर्वेक्षण के दौरान खुदाई के क्षेत्र में भारतीय पुस्तकालयों द्वारा कुछ नए स्थानों की खुदाई की गई। भारतीय पुस्तकालयों में बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा और तमिलनाडु में अनेक स्थानों की खुदाई का काम किया। जिला मुजफ्फरपुर (बिहार) में कोल्हवा में किए गए खुदाई कार्य में अनेक भवितृपूर्ण सृष्टियों का पता चला जो कि मठ-परिसर तथा ईंट से बने मंदिर के अंग थे।

1.3.3 जहाँ साहित्य अकादमी साहित्य की प्रोत्साहन, विद्वानों का मान्यता प्रदान करने, साहित्य तथा साहित्यिक आलोचना के स्रोतों में सुधार लाने के अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्रयास करती रही वहाँ संगीत नाटक अकादमी ने संगीत, नृत्य, नाटक तथा जनजातीय/लोक संगीत के स्वरूपों, नृत्य और नाटक के पुनरोत्थान, संरक्षण, प्रलेखन और उसके प्रसारण सम्बन्धी अपने क्रियाकलाप जारी रखे। ललित कला अकादमी ने भी प्लास्टिक कलाओं को बढ़ावा देने के लिए अपने कार्यक्रमों और परियोजनाओं का आरम्भ किया।

युवा कार्य एवं खेल विभाग:

1.4.1 वर्ष 1991-92 को, वर्ष 1985-89 के दौरान सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए युवा कार्यक्रमों को पुनर्गठित करने के वर्ष की सज़ा दी जा सकती है। युवा कार्यक्रमों पर पर्याप्त बल दिया गया था ताकि युवाओं को अपनी शक्ति राष्ट्र निर्माण संबंधी कार्यक्रमों में लगाने के लिए नए अवसर प्रदान किए जा सकें। खेलों को विस्तृत आधार प्रदान करने और प्रतिभाओं का पता लगाने पर विशेष बल दिया गया ताकि निष्पादन में उत्कृष्टता प्राप्त करने और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बेहतर उपलब्धियां प्राप्त करने के उद्देश्य से इन प्रतिभाओं को विकसित और प्रोत्साहित किया जा सके।

1.4.2 युवा कार्य एवं खेल मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें, अन्य के साथ-साथ सभी राज्यों एवं संघशासित क्षेत्रों के युवा एवं खेल प्रभारियों ने भी भाग लिया। सम्मेलन में, कार्यक्रमों की गुणवत्ता एवं कवरेज में सुधार लाने के तैर तरीके सुझाए गए। युवा कार्य एवं खेल के क्षेत्र में वर्ष के दौरान, अन्य मुख्य कार्यक्रमों नीचे दिए गए हैं

(I) अपनाए गए गांवों में विश्वविद्यालयों के छात्रों के कार्यक्रम, राष्ट्रीयसेवा योजना के माध्यम से सामुदायिक विकास के लिए प्रयत्न जारी रहे। विश्वविद्यालय के छात्रों ने राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में भाग लेना जारी रखा। उन्होंने, एचआईवी/एड्स के संबंध में जागरूक उत्पन्न करने के लिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन की मदद से एक परियोजना भी शुरू की।

(II) नेहरू युवा केंद्रों के शासी निकाय का पुनर्गठन किया गया और कार्यक्रमों के लिए निधियां प्रदान करने की पुनः शुरुआत की गई। बोर्ड ने देश के सभी जिलों को शामिल करने के लिए अपने कार्यक्रमों का विस्तार करने और बड़े जिलों तथा जनजातियों के बाहुल्य वाले जिलों में अतिरिक्त केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया।

(III) राष्ट्रीय एकता शिविर, विश्वविद्यालय छात्र-समारोह, साहसिक कार्यक्रम एवं युवाओं के लिए प्रदर्शनों का आयोजन किया गया। जनजातीय युवाओं को सतत सहयोग देने और उनके लिए विशेष कार्यक्रमों को वित्त-पोषित करने पर विशेष ध्यान दिया गया।

(IV) बच्चों/युवाओं के व्यक्तित्व को विकसित करने के उद्देश्य से स्कूलास्म व गाइड्स आंदोलन ने अपने कार्यक्रमों एवं कार्यक्रमों में वृद्धि करना जारी रखा।

(V) इस विभाग ने राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम को सहयोग देना और मधुका राष्ट्र स्वयंसेवी कार्यक्रमों तथा विशेष रूप से एशिया क्षेत्र में मधुका राष्ट्र सहभागिता विकास कार्यक्रमों का मुद्दा बनाने के अपने प्रयास जारी रखे। इसमें युवाओं में अंतर्राष्ट्रीय समझ बढ़ाने तथा भाईचारे की भावना उत्पन्न हुई।

(VI) खेल के क्षेत्र में, योजनाओं को अद्यतन बनाने तथा जहां कहीं आवश्यक हो उनको और अधिक सुकर बनाने के लिए योजनाओं की समीक्षा करने का एक अभियान शुरू किया गया। इसके साथ ही खेलों में स्वेच्छिक निकायों, तथा खेलों में रुचि लेने वाले सरकारी और निजी उपक्रमों तथा खेलों की समझ रखने वाले व्यक्तियों के बीच विचारों का और अधिक आदान प्रदान किया गया। इसके परिणामस्वरूप, कई नए विचार उभर कर आए जो कि विद्यमान योजनाओं तथा नई योजनाओं की अवधारणा में उपयुक्त रूप से शामिल करने के लिए विकसित किए गए हैं।

(VII) चूंकि खेलों का विकास केवल सरकारी स्त्रोतों से प्राप्त आर्थिक सहायता के आधार पर नहीं हो सकता इसलिए विभिन्न खेलों के लिए राष्ट्रीय अकादमियां शुरू करने के उद्देश्य से निजी और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की विशेषज्ञता और सहयोग जुटाया गया है।

(VIII) प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने, भारत में राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट आयोजित करने तथा विदेशों में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय खेल संघ को (31.12.1991 तक) लागत 238.00 लाख रुपए की सहायता मंजूर की गई है। वर्ष के दौरान खेलों की कुछ खास खास उपलब्धियां निम्नलिखित हैं —

— अक्तूबर के दौरान कोलम्बो में आयोजित पांचवे दक्षिण एशियाई संघ खेलों में भारत ने 64 स्वर्ण, 59 रजत तथा 41 कांस्य पदक जीते।

— अक्तूबर के दौरान न्यूजिलैंड में आयोजित चौथी राष्ट्रमंडल कुश्ती चैम्पियनशिप में भारतीय दल ने 3 स्वर्ण, 1 रजत तथा 5 कांस्य पदक जीते तथा 8 देशों में दूसरे स्थान पर रहा।

— जून, 1991 के दौरान, अमेरिका में आयोजित जूनियर अमेरिकी ओपन टेनिस चैम्पियनशिप भारत के मिगुलैंडर पैस ने जीती।

— इंडोनेशिया में अगस्त के दौरान आयोजित चौथी महिला तथा पांचवीं पुरुष जूनियर एशियाई भारोत्तोलन चैम्पियनशिप में भारत ने 8 रजत तथा 5 कांस्य पदक जीते।

— जनवरी, 1992 में नई दिल्ली में आयोजित छठी इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हाकी टूर्नामेंट में भारत विजयी रहा।

— जनवरी, 1992 में इटली में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंट में श्री विश्वनाथ आनन्द ने ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की।

— जून, 1991 में नई दिल्ली में आयोजित विश्व महिला पावरलिफ्टिंग चैम्पियनशिप में भारत की टीम तीसरे स्थान पर रही।

— विश्व महिला भारोत्तोलन चैम्पियनशिप में भारत ने रजत पदक जीता।

महिला एवं बाल विकास विभाग

1.5.1 महिला तथा बाल विकास विभाग ने, महिला एवं बाल विकास के क्षेत्रों में अपने कार्यक्रमों को जारी रखा। इस प्रयोजन के लिए अपनाई गई कार्यनीति में महिलाओं में शिक्षा एवं जागरूकता पैदा करके उनके अधिकारों की प्राप्ति सुनिश्चित करना है। इस नीति में व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं रोजगार पर जोर दिया गया है ताकि महिलाएँ पुरुषों के समान आर्थिक विकास की मुख्य धारा का अंग बन सकें। प्राथमिकता का एक अन्य क्षेत्र है जिसमें बालिका शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देते हुए मृत्यु, पुरुष के बांधे भेद भाव बरते जाने की विभिन्न पद्धतियों पर नए सिरे से प्रहार किया गया है। महिलाओं को प्रदत्त संवैधानिक और कानूनी सुरक्षाओं से सम्बद्ध सभी मामलों की जांच पड़ताल करने तथा मौजूदा विधानों की समीक्षा करने के लिए, महिला एवं बाल विकास विभाग ने राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अर्धन राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गयी। महिलाओं के अधिकारों के लिए आयुक्त का कार्यालय स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया है। महिलाओं के मामलों के लिए प्रवर्तन एवं प्रशासनिक तंत्र को सुव्यवस्थित बनाना भी एक ऐसी महत्वपूर्ण पहल है,

जिसे गति मिल गई है। मार्क सम्मेलन के बालिका दशक के लिए एक व्यापक कार्रवाई योजना को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है।

1.5.2 बाल विकास एवं कल्याण के क्षेत्र में भी विभाग ने समेकित बाल विकास योजना (आई सी डी एस) नामक विश्व का सर्वाधिक विशाल पोष्टिक आहार कार्यक्रम विकसित किया है। इस कार्यक्रम में देश भर की 2594 परियोजनाओं (जिसमें राजकीय क्षेत्र की परियोजनाएँ भी शामिल हैं) के अर्धन 138 लाख बच्चों और 27 लाख गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाओं को शामिल किया गया है। आलोच्य वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत दी जाने वाली सेवाओं की कोटि में सुधार लाने तथा साथ ही देश भर में महिलाओं एवं बच्चों की सेवाओं को मिला कर कार्यक्रम के वास्तविक घटकों की उपादेयता में सुधार लाने का प्रयास किया गया है। किशोर बालिकाओं के स्वास्थ्य, पोष्टिक आहार और व्यावसायिक जरूरतों को जुटाने तथा भावी सामाजिक प्रहरियों के रूप में उनकी अन्तर्गत शक्ति को उभारने के लिए उनकी ओर ध्यान देना, इस नीति का एक अनिवार्य अंग है। बाल विश्व सम्मेलन और उत्तर जीवन सुरक्षा और बाल विकास पर विश्व घोषणा की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, बच्चों के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

1.5.3 यह विभाग अब इन्दिरा महिला योजना का ब्यौरा तैयार कर रहा है जिसका मुख्य उद्देश्य वर्तमान कार्यक्रम रूपरेखा की आभूतचूल पुनर्संरचना तथा महिलाओं एवं बच्चों के लिए प्रदान की जाने वाली सेवाओं की व्यापक प्रणाली का सृजन तथा महिलाओं को आर्थिक अधिकार प्रदान करना है। इस योजना में ग्रामीण स्तर पर लाभग्राही वर्ग के सृजन की परिकल्पना की गई है जो सुविधाएँ प्रदान करने की समेकित प्रणाली पर निगाह रखेगा तथा महिलाओं एवं बच्चों की चिन्ताओं को अभिव्यक्त करेगा।

2. ଅନୁସନ୍ଧାନ

2. सिंहावलोकन

निधियों का आबंटन और उनका उपयोग

2.1.1 वर्ष 1991-92 के दौरान केन्द्रीय क्षेत्रों में शिक्षा के लिए 1805.32 करोड़ रूपी का प्रावधान किया गया था। इसमें से 774.02 करोड़ रूपी गैर-योजनागत और 1031.30 करोड़ रूपी योजनागत था जिसमें सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम शामिल था।

2.1.2 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत चल रहे सभी कार्यक्रमों को राज्य और केन्द्रशासित प्रदेशों के निकट सहयोग से परियोजनानुकूल आधार पर लागू किया जाता रहा। फिर भी, जहां तक वित्तीय सहायता का सवाल था विभाग ने काठिन सामाजिक क्षेत्र के वास्तविक लक्ष्यों को बनाए रखने के पुराने प्रचलन को बदलने के योजना आयोग के उद्देश्य को ध्यान में रखा और वित्तीय अभाव के आधार पर विनाय लागता को कम कर दिया इसमें प्राथमिक शिक्षा, प्रौढ साक्षरता और व्यावसायिकता को सर्वसुलभ बनाने के लिए उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में जल्दत के आधार पर वित्त उपलब्ध किया जाना निर्धारित किया गया। उच्च और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में गैर-सरकारी सहायता पर भी निर्भरता कायम रखी गयी। लागत उपयोगिता और कार्यक्रम प्रदान करने की पद्धति में सुधार लाने के लिए व्यवस्थित मॉनिटरिंग और मूल्यांकन पर भी बल दिया गया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा

2.2.0 वर्ष 1990 में आचार्य रामभूति की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 की समीक्षा की गई। 26 दिसम्बर, 1990 को समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। 8-9 मार्च, 1991 को हुई केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (केब) की बैठक में रिपोर्ट पर विचार किया गया। रिपोर्ट की गहराई से जांच करने के लिए केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री, श्री एन जगन्मोहन रेड्डी की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त किया। समिति ने 22 जनवरी, 1992 को अपनी रिपोर्ट दे दी। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा शीघ्र ही इस रिपोर्ट पर विचार किए जाने की उम्मीद है।

कार्यक्रम कार्यान्वयन

2.3.1 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों को लागू करने के लिए तैयारी की गई प्राथमिकताओं और किए गए प्रयास नीचे दिए गए हैं -

प्रारंभिक शिक्षा

2.3.2 प्रारंभिक शिक्षा, जो शिक्षा विकास का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है के विषय में केवल दखिला पर ही जोर नहीं दिया गया बल्कि सहभागिता और उपलब्ध पर जोर देना स्वीकार किया गया है। शिक्षा के न्यूनतम स्तरों को एक नया परिपेक्ष्य देश भर में प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए लाया गया। आभेसन ब्लैक बोर्ड, औपचारिक शिक्षा, शिक्षक शिक्षा और शिक्षा के न्यूनतम स्तरों के प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार थे -

स्कूल आधार भूत सुविधाओं ब्यापको की शामिल करना। 5275

शामिल किए गए स्कूलों की संख्या।	40 04 लाख
स्वीकृत अतिरिक्त शिक्षक पदों की संख्या	1 5 लाख
अनौपचारिक केन्द्रों की संख्या	2.72 लाख
स्वीकृत शिक्षक शिक्षा की संख्या	324
(जिला तथा प्रशिक्षण सत्याएं शिक्षक शिक्षा कालेज एवं उच्च शिक्षा अध्ययन की सत्याएं)	
शुरू की गई एमएलएलएल परियोजनाओं की संख्या।	18
अनौपचारिक शिक्षा सहित प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्वीकृत 49 प्राथमिक और नवीन प्रयोगशालाओं की संख्या	

2.3.3 प्रौढ साक्षरता

(i) वर्ष 1990 के जनगणना के आँकड़ों ने देश में साक्षरता के पूर्ण परिदृश्य को बदल दिया है और पहली बार साक्षरता दर 50% से अधिक हो गयी जिसका अर्थ यह हुआ कि देश में अब निरक्षरों से अधिक साक्षरों की संख्या है।

(ii) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने भी केवल राज्य के एकाकुलम जिलों को सफलता का अनुकरण करते हुए पूर्ण साक्षरता अभियानों की प्रक्रिया के माध्यम से न केवल देश के 97 जिलों में पूर्ण या आंशिक रूप से अभियान चलाने में बल्कि बर्दान (पश्चिम बंगाल), गुजरात के गांधीनगर में, केन्द्रशासित प्रदेश पांडिचेरी में, सिंधुदुर्ग (महाराष्ट्र) और दक्षिण कन्नड (कर्णाटक) में पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने में काफी प्रगति की है।

(iii) ऐसे जिले जहां पूर्ण साक्षरता अभियान नव-साक्षरों के साक्षरता कौशल को सुदृढ़ बनाने का लक्ष्य प्राप्त कर चुके हैं, उत्तर साक्षरता अभियान भी शुरू किये गये हैं ताकि वे स्वतंत्र रूप से खुद शिक्षा प्राप्त करने के योग्य हो सकें।

(iv) प्रौढ शिक्षा के सभी कार्यक्रमों में आईपीसीएल सामग्रियों के प्रयोग को अनिवार्य बनाकर प्रौढ शिक्षकों के अध्यापन को स्तर प्रदान करने का प्रयास जारी रखा गया। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर की समीक्षा समिति द्वारा प्रयोग से पहले सभी सामग्रियों की सख्ती से जांच की गई थी।

(v) केन्द्र आधारित कार्यक्रम में सरोधान किया गया और इसे प्रभावों तथा परिणामों-मुख बनाने के लिए पुनर्गठित किया गया। सरोधित स्वीम में स्वेच्छिक संगठनों को और अधिक लचीला बनाया गया तथा नियमों को सरल बनाया गया ताकि उन्हें विशेष क्षेत्रों जैसे गांव, ग्राम समूह या किसी प्रखंड में निरक्षरता उन्मूलन के लिए बनाई गई परियोजनायें

प्रारम्भ करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

2.3.4 माध्यमिक शिक्षा

- (i) माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की स्कीम के अंतर्गत छात्रों के व्यावहारिक प्रशिक्षण पर बल दिया गया और लाभप्राप्तियों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रारंभ करने का काम प्रगति पर है ताकि तत्काल रोजगार और स्व-रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। स्कीम के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा के लिए रांशे-अंश-प्र-पं द्वारा शिक्षा के व्यावसायीकरण पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई।
- (ii) राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना के अंतर्गत, प्रशिक्षण सामग्री तैयार करने और जनसंख्या वृद्धि तथा पर्यावरण पर वीडियो कार्यक्रम का निर्माण करने पर बल दिया गया।
- (iii) शैक्षिक सामग्री और प्रक्रिया में सांस्कृतिक/कलात्मक निवेश को सुदृढ़ करे, स्कूल प्रणाली में मूल्य शिक्षा और स्कूल स्तर पर अभिनव कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सहायता दी गई।
- (iv) विशेष रूप से विज्ञान और गणित शिक्षण तथा अंग्रेजी भाषा में सुधार करके, शैक्षिक कार्यक्रमों को पर्यावरणीय स्वरूप देकर और शैक्षिक सुधारों को सुव्यवस्थित रूप से प्रारम्भ करके शिक्षण सामग्री और प्रक्रिया में सभी प्रकार के सुधार पर बल दिया गया।
- (v) परीक्षा संबंधी सुधार

2.3.5 शिक्षक शिक्षा

- (i) विद्यमान जिला शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थानों (डाइरेक्ट) में सुधार और इस स्कीम के अंतर्गत शामिल न किये गये प्रत्येक जिले में एक जिला शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना।
- (ii) स्कूल शिक्षकों का सामूहिक अनुस्थापन ताकि उन्हें रां शिं नीं के महत्वपूर्ण बिंदुओं से अवगत कराया जा सके।
- (iii) राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद को सुदृढ़ बनाना।
- (iv) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों में शिक्षा विभागों की स्थापना और उन्हें सुदृढ़ बनाना।

2.3.6 तकनीकी शिक्षा

- (i) आधुनिकीकरण और तकनीकी शिक्षा में अप्रचलनों को हटाने के कार्यक्रम के अंतर्गत 328 परियोजनाओं को 29.50 करोड़ रुपये की वितरित सहायता दी गई।

- (ii) संघ शासित क्षेत्र दिल्ली और आठ और राज्यों को सम्मिलित करने के लिए विश्व बैंक की सहायता से तकनीकी शिक्षा परियोजना का

अनुमानित: 1657 करोड़ रु के परिसर से सोलह राज्य और सब शासित क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। हालांकि परियोजना का प्रथम चरण

कार्यान्वयनाधीन है, दूसरे चरण के मार्च 1992 तक परिचालित होने की आशा है।

- (iii) ग्रामीण क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए सामुदायिक पॉलिटेक्निकों की संख्या 159 तक बढ़ गई है। ये संस्थाएं प्रति वर्ष औसतन लगभग 25,000 ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षित करेंगी।
- (iv) प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड ने 22,000 से अधिक छात्रों के प्रशिक्षण को सुसाध्य बनाया।
- (v) वर्ष के दौरान अखिल-भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थाओं में प्रारंभ होने वाले 231 नए कार्यक्रमों और 42 नई संस्थाओं को अनुमोदित किया।

2.3.7 विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा

- (i) स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से देश में उच्च शिक्षा पद्धति का लगातार विकास हुआ है। विश्वविद्यालयों की संख्या स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पर 25 से सातवां योजना के अंत तक 175 तक (28 औपनिवेशिक विद्यालयों सहित) और कलेजों की संख्या 700 से बढ़कर लगभग 7,000 हो गई। छात्रों का नामांकन स्वतंत्रता के समय पर 2 लाख से बढ़कर 1989-90 में 42 लाख हो गया। कुल 42 लाख नामांकन में से 37 लाख छात्र (88%) स्नातक कार्यक्रमों में नामांकित थे, 4 लाख (9.5%) स्नातकोत्तर में और 47,000 (1.1%) अनुसंधान में नामांकित थे। 55,000 (1.3%) छात्र डिप्लोमा अथवा प्रमाण पत्र कार्यक्रमों में नामांकित थे। छात्रों की संख्या लगभग 13 लाख (32%) थी। कुल नामांकन का लगभग 10% अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए था।
- (ii) 1980 के दशक के दौरान छात्र नामांकन की वृद्धि में स्पष्ट परिवर्तन आया है। यद्यपि छात्र नामांकन में 1985-86 तक प्रत्येक वर्ष औसतन 5% से ऊपर की वृद्धि हुई। वर्ष 1986-87 से छात्रों की वार्षिक वृद्धि प्रत्येक वर्ष 4.1% और 4.2% के बीच रही है वह भी अनुमान है कि यदि वृद्धि को दर से छोटी रही तो कुल दखिला 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक लगभग 7 लाख हो जाएगा।
- (iii) छात्रों के संकायवार ब्यौरे से पता चलता है कि लगभग 40% छात्र कला और मानविकी विषयों में, वाणिज्य में 22%, विज्ञान में 20%, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में 5%, कानून में 5%, चिकित्सा में 3.4%, और कृषि में 1% दाखिल थे। यद्यपि प्रत्येक संकाय में दाखिल छात्रों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। फिर भी कुल दाखिले में प्रत्येक संकाय के लिए दाखिले की प्रतिशतता स्थिर रही है।
- (iv) पचास पाठ्यक्रमों और मुख्य विश्वविद्यालयों में दाखिल छात्रों की संख्या 7वीं योजना के अंतर्गत 5 लाख थी। पिछले 2 व 3 वर्षों में दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के लिए काफी उत्साह रहा है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने एक लाख से अधिक छात्रों को दाखिल दिया है। 8वीं योजना अवधि के दौरान महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक क्षेत्र में मुक्त विश्वविद्यालय और दूरस्थ शिक्षा में एक मिलियन छात्रों के अतिरिक्त दाखिले को लक्ष्य होगा।
- (v) देश में उच्च शिक्षा की प्रणाली की आवश्यकताओं और 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई योजनाओं को ध्यान में रखते

हए क्वी पंचवर्षीय योजना के दौरान उच्च शिक्षा के विकास के लिए निर्धारित महत्वपूर्ण क्षेत्र होंगे:

- विश्वविद्यालयों या कालेजों में सुविधाओं का संकलन और सुदृढ़ करना।
- देश की विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नया रूप प्रदान करना।
- स्थापित कालेजों, विश्वविद्यालयों विभागों की स्थापना और प्रशिक्षण सुधारों को उत्साहित करना।
- मान्य सुविधाओं को तैयार करने के संबंध में अनुसंधान सुविधाओं को मजबूत बनाना।
- ग्रीड शिक्षा तथा जन संख्या शिक्षा जैसे विस्तार कार्यक्रमों में छात्रों को और अधिक भागीदार बनाना।
- शिक्षक प्रशिक्षण
- विश्वविद्यालय अग्रणी के प्रबंधन को आधुनिक बनाना तथा नया रूप देना।
- शिक्षा अग्रणी के अंतर्गत ही वित्तीय संसाधन तैयार करना।
- मुक्त विश्वविद्यालयों तथा दूरस्थ शिक्षा अग्रालों में एक मिलितन छात्रों का अतिरिक्त दाखिला।

2.3.8 भाषा विकास

- (i) भारत सरकार ने देश के विभिन्न भागों में अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी शिक्षकों के 1394 चयन (जनवरी, 1992 तक) के चयन व्यय को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की। वित्तीय हिन्दी-शिक्षक प्रशिक्षण कालेजों को सहायता दी गई थी। इन संस्थाओं ने लगभग 7,360 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया।
- (ii) केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय ने क्षेत्रीय भाषाओं में 14,000 व्यक्तियों के हिन्दी शिक्षण के लिए पत्राचार पाठ्यक्रमों की प्रशिक्षण की।
- (iii) केन्द्रीय भारतीय भाषा मन्थान, मैसूर ने आधुनिक भारतीय भाषाओं में हिन्दी भाषी क्षेत्रों से अपना शिक्षक-प्रशिक्षण का कार्यक्रम जारी रखा।
- (iv) केन्द्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान (सी-आई-ई-एफ-एल-ए) ने अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थाओं के कार्यक्रमों के समन्वय में प्रभावी प्रशिक्षण प्रदान किया। सी-आई-ई-एफ-एल-ए ने जिला केन्द्रों के माध्यम से अंग्रेजी भाषा शिक्षकों के पूर्ण प्रशिक्षण की स्कीमों को भी मॉनिटर किया।

2.3.9 शैक्षणिक क्षेत्र में शिक्षा (विशेष) कार्यक्रम (सी-आई-ई-एफ-एल-ए) उच्च स्तरीय क्षेत्र के लिए सी-आई-ई-एफ-एल-ए उस क्षेत्र में शैक्षिक विकास में वित्तिय की सामान्य दशा को समायोजित करने और उनके सामाजिक विकास के लिए केन्द्र सरकार से संबंधित उस क्षेत्र के राज्य को पुनः आश्वासन करने पर विशेष जल देती है।

2.3.10 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

- (i) यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए ब्रज भारतीय राष्ट्रीय आयोग (आई-एन-सी) शिक्षा विभाग ने अपने सविस्तर के साथ यूनेस्को के कार्य विशेषकर इसके कार्यक्रमों के निष्पन्न और उन्हें कार्यान्वित करने में महत्वपूर्ण योगदान देता रहा है। आई-एन-सी ने यूनेस्को के क्षेत्रीय कार्यक्रमों में प्रभावी बीदक निवेशों को निरंतर प्रदान किया।
- (ii) मानव संसाधन विकास मंत्री के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने 15 जनवरी, 1991 तक पेरिस में आयोजित यूनेस्को महासभा के 26वें सत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिक्षा सचिव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमण्डल ने अगस्त, 1991 में इस्लामाबाद में शिक्षा पर सार्क प्रयोगिकी समिति की तीसरी बैठक में सार्क सदस्य देशों के बीच गहरे सहयोग की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
- (iii) द्विपक्षीय सांस्कृतिक विनियम कार्यक्रमों और अन्य कारणों के शिक्षा धटक के कार्यक्रमों की गहन मॉनिटरिंग द्वारा बाह्य शैक्षिक संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए उपाय किए गए।
- (iv) निरक्षरता के निरुद्ध संघर्ष में उत्कृष्ट योगदान के लिए यूनेस्को ने पश्चिम बंगाल सरकार को नौवा साक्षरता पुस्तक प्रदान किया।
- 2.3.11 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं की शिक्षा

- (i) विधेयताओं को हटाने और अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों को शैक्षणिक अवसरों के समीकरण पर निरंतर दबाव डाला गया।
- (ii) शिक्षा में लड़कियों/महिलाओं को भागीदारी सुधारने के सभी प्रयास किए गए।
- शिक्षण के लिए संसाधन
- 2.4 0 वर्ष 1989-90 के लिए चालू मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद (जी-ओपी) 395,000 करोड़ रु. होने का अनुमान है। इसी वर्ष 1989-90 के लिए केन्द्र और राज्यों में शिक्षा विभागों का 73619 करोड़ रुपये का बजट है। यह निवेश सकल घरेलू उत्पाद के 3.5 फीसदी के क्रम में है।

3. ۷۸ ۴۴

3. प्रशासन:

संगठनात्मक संरचना (ढाँचा)

3.10 शिक्षा विभाग, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक घटक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पूरे प्रभार सहित राज्य मंत्री (मानव) के प्रभार में है। विभाग के सचिवालय का नेतृत्व सचिव द्वारा किया जाता है जिसको अपर सचिव तथा शिक्षा सलाहकार (तकनीकी) सहयोग देते हैं। यह विभाग ब्यूरो, प्रभागों, शाखाओं, डैस्कों, अनुभागों तथा एककों में संघटित है। प्रत्येक ब्यूरो एक संयुक्त सचिव/संयुक्त शिक्षा सलाहकार के प्रभार में होता है जिसे प्रभागीय प्रमुख सहयोग देते हैं। विभाग की संगठन रिपोर्ट के साथ संलग्न संगठन चार्ट में दर्शाया गया है।

अधीनस्थ कार्यालय/स्वायत्त संगठन

3.2.1 कई वर्षों से कई अधीनस्थ कार्यालय तथा स्वायत्त संगठन इस विभाग के अंतर्गत आए हैं। महत्वपूर्ण अधीनस्थ कार्यालय इस प्रकार हैं

— केन्द्रीय हिंदी निदेशालय (के०हि०नि०)

— वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग (वै०त०श०आ०)

— उर्दू-प्रोन्नति-ब्यूरो (उ०प्र०ब्यू०)

3.2.2 महत्वपूर्ण संगठन इस प्रकार हैं

— राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् (रा०शै०अनु०प्र०परि०) नई दिल्ली, स्कूल-क्षेत्र में संचालन करने वाली एक राष्ट्रीय स्तर की छोट सस्था है।

— राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान (रा०शै०यो०प्र०सं०) नई दिल्ली, शैक्षिक प्रवर्धन की समस्याओं में विशेषज्ञता वाली एक राष्ट्रीय स्तर की छोट सस्था है।

— विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि०वि०अनु०आ०) जो उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में समन्वय करता है तथा मानक निर्धारित करता है।

— अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (अ०भा०त०शि०परि०) नई दिल्ली जो तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में समन्वय करती है और मानक निर्धारित करती है।

निम्नलिखित संस्थाएं उच्चतर शैक्षिक अनुसंधान में लगी हुई हैं:

* भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान (भा०उ०अ०सं०) शिमला।

* भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् (भा०सा०वि०अनु०परि०) नई दिल्ली।

* भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् (भा०ऐ०अनु०परि०) नई दिल्ली।

* भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद् (भा०दा०अनु०परि०) नई दिल्ली।

— केन्द्रीय हिंदी संस्थान (के०हि०सं०) आगरा जो भारत तथा विदेशों में हिंदी का प्रचार करता है।

— राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली, संस्कृत में प्रोन्नति, विकास और अनुसंधान (स्कूल से उच्च शिक्षा स्तर तक) में लगा हुआ है यह एक जांच निकाय भी है।

— केन्द्रीय विद्यालय संगठन (के०वि०सं०) नई दिल्ली केन्द्रीय सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों के लाभार्थ स्कूल चलाता है।

— नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली प्रतिभाशाली ग्रामीण बच्चों के लाभार्थ स्कूलों को चलाती है।

— केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (के०मा०शि०बो०) नई दिल्ली जो स्कूलों को सम्बद्ध करता है और परीक्षाएं आयोजित करता है।

— राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली।

— तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में—

* भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर

* भारतीय खान स्कूल, धनबाद।

* राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान, कोलकाता

* राष्ट्रीय दलाई तथा गढ़ाई प्रौद्योगिकी, गुरुगढ़

* आयोजना तथा वास्तुकला स्कूल नई दिल्ली

* भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज, हैदराबाद।

* अहमदाबाद, बंगलौर, कलकता तथा लखनऊ स्थित नारनंद प्रवर्ध संस्थान (भा०प्र०सं०)

* भोपाल, कलकता, चण्डीगढ़ और मद्रास स्थित तत्परीक्षी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं (त०शि०प्र०सं०)

* बम्बई, दिल्ली, काठपुर, खड़गपुर तथा मद्रास स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (पी० प्रौ० सं०)

* क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज (कुल० ए०)

* राष्ट्रीय प्रौढ शिक्षा मंत्रालय, कोलकाता

* राष्ट्रीय मूल्यांकन संगठन (ए०म०सं०)

3.2.3 जबकि वि० वि० अनु० आयोग, केन्द्रीय विश्वविद्यालय और भा० प्रौ० जैसी संस्थाएं और स्वायत्त संगठन या तो संसाधित पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हैं या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किए गए हैं।

कार्य

3.3.0 शिक्षा एक समवर्ती विषय है, समवर्तता केन्द्रीय सरकार और राज्यों के बीच एक सार्थक हिस्सेदारी को लागू करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में निम्नलिखित का उल्लेख किया गया है—

“जबकि शिक्षा के संबंध में राज्यों की भूमिका और उनका उत्तरदायित्व में अनिवार्यता कोई परिवर्तन नहीं होगा, केन्द्रीय सरकार शिक्षा की कोटि और स्तरों (सभी स्तरों पर शिक्षण व्यवसाय सहित) को बनाये रखने, अनुसन्धान और प्रोन्नत अध्ययन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकास हेतु जनशक्ति के संबंध में समस्त देश की शैक्षिक अपेक्षाओं का अध्ययन और उनका अनुप्रवण करने, शिक्षा संस्कृति और मानव संसाधन के अन्तर राष्ट्रीय पहलुओं को देखभाल करने, और सामान्य तौर पर देश भर में शैक्षणिक पिछाई (संस्कृत) के सभी स्तरों पर उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा के राष्ट्रीय तथा संभेकित स्वरूप को लागू करने के लिए केन्द्रीय सरकार “व्यापक उत्तर दायित्व को स्वीकार करेगी”। यह विभाग राष्ट्रीय शिक्षा नीति, द्वारा तैयार की गयी भूमिका को पूरा करने के प्रयास करता रहा है तथा राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के निकट सहयोग से कार्य करता रहा है।

सतर्कता कार्यकाल

3.4.1 प्रशासन की गति को त्वरित करने तथा मुख्यालयों और अधीनस्थ कार्यालयों दोनों में विभाग के कर्मचारियों में अनुशासन बनाए रखने के लिए सतत प्रयास किए गए थे। मायघानी पूर्वक तथा सतर्कता बरतते हुए एक कार्यवाही योजना तैयार की गई थी तथा कुछ अनुभागों व अधीनस्थ कार्यालयों को अचानक सतर्कता जांच की गई थी। पांच अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां पूरी कर ली गई थीं और प्रत्येक मामले में उपयुक्त आदेश पास कर दिए गए थे। इसके अनिर्कृत आठ अधिकारियों (दो गजपत्रित अधिकारियों सहित) के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां आरंभ किए जाने का निर्णय लिया गया है। एक अधीनस्थ कार्यालय के एक गजपत्रित अधिकारियों तथा विभाग के 3 अधिकारियों (दो गजपत्रित अधिकारियों सहित) के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां जो पहले आरंभ की गई थीं, अब प्रगति पर हैं। इस विभाग से संबंधित 16 शिकायतें (जिसमें 11 गजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध शामिल हैं) पर प्रारंभिक जांच पड़ताल की कार्यवाही की गई थी। इनमें से 20 संगठनों ने भी लोक शिकायत निवारण निवारण कार्यप्रणाली भी स्थापित कर ली है तथा लोक शिकायत निवारण हेतु शिकायत अधिकारी मनोनीत कर लिये हैं।

3.4.3 अनुशासन और समन्वयन के अनुपालन पर पूर्ण रूप से बल दिया जाना जारी रहेगा।

सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रभावी प्रयोग

3.5.1 शिक्षा विभाग में इस समय 90 अनुभाग, 10 अधीनस्थ कार्यालय, एक सार्वजनिक उपक्रम और 75 स्वायत्त संगठन हैं। गजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय से प्राप्त वर्ष 1991-92 के लिए भारत सरकार की गजभाषा नीति को कार्यान्वित करने के लिए वार्षिक कार्यक्रम को इस विभाग, इसके अधीनस्थ कार्यालयों, और स्वायत्त संगठनों में इस अनुरोध के साथ परिचालित किया गया कि उसमें निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने और विभागीय गजभाषा कार्यन्वयन समिति (ओ एल ओ आई सी) की बैठकों की निर्धारित प्रगति की समीक्षा करने के लिए सभी सभव प्रयास किए जाने चाहिए। इसके अलावा, गजभाषा अधिनियम और नियमावली और उसके अन्तर्गत बनाए गए प्रशासनिक आदेशों के पालन की समीक्षा तिमाही प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से की गई थी तथा जहां अनिवार्य या उपचारी कदमों का सुझाव दिया गया था।

3.5.2 वर्ष के दौरान, विभाग की गजभाषा कार्यन्वयन समिति की तीन

(3) बैठकें जनवरी, 92 तक आयोजित की गई थीं। इसके अतिरिक्त, कुछ प्रभागों की अपनी गजभाषा कार्यन्वयन समितियां भी हैं तथा उनकी बैठकें निर्धारित रूप से आयोजित होती हैं। विभाग के गजभाषा एकक के अधिकारियों ने भी अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्त संगठनों इत्यादि की गजभाषा कार्यन्वयन समितियों की बैठकों में भाग लिया तथा उनमें हिन्दी के प्रभावी प्रयोग को बढ़ावा देने के विभिन्न उपायों पर भी चर्चा की।

3.5.3 वर्ष के दौरान तीन हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया तथा कार्यशालाओं में दिए गए प्रशिक्षण से कर्मचारी अत्यधिक लाभान्वित हुए।

3.5.4 गजभाषा विभाग की हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण के लिए 71 कर्मचारियों को नामित किया गया था, जिनमें से 23 कर्मचारियों को हिन्दी प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ पाठ्यक्रमों के लिए और 28 को हिन्दी टाइपिंग और 20 को हिन्दी आशुलिपि के लिए नामित किया गया था।

3.5.5 गजभाषा नियमों के पालन से संबंधित स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए, विभाग के 7 अधीनस्थ कार्यालयों/स्वायत्त संगठनों का निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को संबंधित अधिकारियों के ध्यान में लाया गया और उनके लिए उपचारमूलक उपाय सुझाए गए। गजभाषा ससदीय समिति ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली तथा भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला का दौरा तथा निरीक्षण किया।

3.5.6 विभाग में 16-20 सितम्बर, 1991 तक हिन्दी सप्ताह मनाया गया। इस अवसर पर, मानव संसाधन विकास मंत्री और शिक्षा सचिव का आंग से मन्कारी कामकाज में हिन्दी के व्यापक प्रयोग के लिए आग्रह करते हुए एक अपील और हिदायते जारी की गईं। इसके अतिरिक्त, हिन्दी आशुलिपि प्रतियोगिता, हिन्दी निबंध और हिन्दी टाइपिंग प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं थीं जिनमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थानों को पाने वाले कर्मचारियों को क्रमशः 500 300 और 200 रुपये का नकद पुरस्कार दिया गया।

3.5.7 गजभाषा समदीय समिति और समदीय कार्य मंत्रालय में हिन्दी मन्त्रालय समिति के पुनर्गठन हेतु न्यूनतम संख्या के नये नामांकन प्राप्त किए जा रहे हैं। पुनर्गठन के उपरान्त, समिति की एक बैठक शीघ्र ही बुलाई जायेगी।

3.5.8 आलोच्य वर्ष के दौरान वि.अ.आ. सहित 89 कार्यालय/केन्द्रीय विद्यालय जहां 80% से अधिक कर्मचारियों ने हिन्दी में कार्यमाध्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया था, गजभाषा नियमावली, 1976 के नियम 10(4) के अन्तर्गत उन्हें अभिमूर्चित किया गया।

प्रकाशन

3.6.0 प्रकाशन एकक ने द्विभाषी (हिन्दी और अंग्रेजी) सहित अंग्रेजी में 16 प्रकाशन प्रकाशित किए। एकक ने विदेशों में जाने वाले भारतीयों और भारत में अध्ययनरत विदेशी छात्रों के मूल शैक्षिक परिणाम पत्रों को अधि प्रमाणित करने का कार्य जारी रखा।

3.7.0 वर्ष 1991-92 के दौरान विदेश भेजे गए सरकारी अधिकारियों और गैर सरकारी अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति/शिष्ट पंडल.



8-9-91 को अवलम्बित शासनालय दिवस समारोह

शिष्ट मडलों, प्रतिनियुक्त
व्यक्तियों की संख्या

शिष्ट मडलों/ प्रतिनियुक्त विदेशी मुद्रा षटक
में शामिल व्यक्तियों की (अनुमानित रूपों
संख्या में)

22

38

653938 रु०

बजट प्राकलन

3.8.0 शिक्षा विभाग के सम्बन्ध में वर्ष 1991-92 और 1992-93 का कुल बजट प्रावधान निम्नलिखित है —

व्यौर	बजट प्राकलन	संशोधित	बजट प्राकलन
	1991-92	प्राकलन	1992-93
		1991-92	

प्राग सं० 47

शिक्षा विभाग 1805.32

व्यावसायिक विकास और कर्मचारियों का प्रशिक्षण

3.9.0. प्रशिक्षण सेल शिक्षा विभाग के लिए प्रशिक्षण आवश्यकताओं का

पता लगाने, उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने और विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए अधिकारियों और स्टाफ के कर्मचारियों को भेजने के लिए उत्तरदायी है ताकि उनके व्यावसायिक विकास को सुनिश्चित किया जा सके। वर्ष 1991-92 के दौरान भारत के 25 अधिकारियों को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों/ पाठ्यक्रमों के लिए नामित किया गया था। वे आई० ए० एस० अधिकारी शामिल नहीं हैं जिन्हें कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा अनिवार्य सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है। इसके अलावा दो अधिकारी वर्ष के दौरान विदेश में प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किए गए थे। शिक्षा विभाग में उप सचिव और इससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों के लिए दो कार्यशालाएं "डिवलपिंग सर्वोइडेन्स" विषय पर, एक दिसम्बर, 91 में तथा दूसरी जनवरी, 92 में आयोजित की गई थी। शिक्षा विभाग की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण आवश्यकताओं पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रबन्ध केन्द्र को एक परामर्शीय उत्तरदायित्व कार्य भी सौंपा गया।

तीन मूर्ति ध्वन में विज्ञान प्रदर्शनी

3.10.0 जवाहर लाल नेहरू के जन्म समारोह के एक प्राग के रूप में शिक्षा विभाग ने 14 नवम्बर से 30 नवम्बर, 1991 तक तीन मूर्ति ध्वन में विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित की। प्रधानमंत्री ने 14.11.91 को प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था। इस प्रदर्शनी का विषय "वैल्यू फार न्यू इंडिया" था।

4. 3 ମିଲିମିଟର

4. आरंभिक शिक्षा

4.1.1 आरंभिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण एक वैधानिक अधिकार है। संविधान की धारा 45 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में निर्दिष्ट करती है कि राज्य अधिकांश के लागू होने के दस वर्षों की अवधि में उन सभी बच्चों को जब तक वे 14 वर्ष की आयु वर्ष पूर्ण नहीं कर लेते तब तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का परवश प्रयास करेगा। उद्योग शिक्षा नीति, का अनुच्छेद (सेरा) 5.12 कहता है कि "यदि शिक्षा नीति स्कूल छोड़ जाने वाले बच्चों की समस्या हल करने का उच्च प्राथमिकता देगी और मुख्य अभियोजना पर आधारित अतिसाधना से अभिकट लाने के लिए देशभर में आरंभिक स्तर पर इसे लागू करेगी। यह प्रयास अनौपचारिक शिक्षा के नेटवर्क के साथ पूरी तरह से समन्वित रहेगा। यह सुनिश्चित होगा कि वे सभी बच्चों को 1990 तक लागू। 11 वर्ष तक की आयु प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें अनौपचारिक पद्धति से पाठ सार तक की स्कूली अथवा अशक, सम्मेलन शिक्षा देनी होगी। इसी तरह 1995 तक सभी बच्चों को 14 वर्ष तक की आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी।

4.1.2 वास्तव में, बच्चों से केन्द्र और राज्यो ने आरंभिक शिक्षा के संवर्धन में अत्यधिक प्रयत्न किया है। स्कूलों में आरंभिक सुविधाएं लागू। 2.34 लाख से 6.94 लाख तक और बच्चों का माध्यम 22.28 मिलियन से 129.4 मिलियन बढ़ा है। और आरंभिक शिक्षा की पहुंच से बाहर प्रयोग आबादी के 94% से वो अधिक पाग को उनके घर से एक किमी की दूरी में सुविधा दी गई। पिछले पांच वर्षों से उद्योग शिक्षा नीति की अनुपालना में विश्व के इस विभाग और संभवतः समस्त बड़े औद्योगिक टावर्क द्वारा प्रदान की जा रही शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए वैचारिक प्रयास किए गए हैं। स्कूलों की मूलतः बर्तीयारी सुविधाएं प्रदान करते, स्कूल छोड़ने वाले और कामकाजी बच्चों को अंशकालीन शिक्षा के लिए अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों को खोलने, शिक्षक प्रशिक्षण सुविधाओं और शिक्षक प्रभावशीलता में सुधार लाने, खोलने के मूलतः स्तरों को निर्धारित करने, शैक्षणिक प्रवर्धन के विकेन्द्रिकरण और स्कूलों को बलाने में समाज को समिलित करने, भेदभाव कम करने और प्रशिक्षण में सुधार लाने के लिए अनेक योजनाएं चलाई गई हैं। इनमें से अधिकांश योजनाएं लक्ष्य और अवसर, वार्षिक परीक्षा प्रचारी और अत्यधिकीय संसाधन सहायता को प्रभावी बनाने में महत्वाकांक्षी हैं। वर्ष 91-92 आदेशन ब्लैक बोर्ड, अनौपचारिक शिक्षा, शिक्षक शिक्षा के पुनर्गठन और पुनर्वचना के साथ साथ आधीन स्तर के शैक्षणिक कार्यक्रमों और क्षेत्र विशेष को यूबीईई परियोजनाओं में एम एलए एलए द्वारा अधिमान प्राप्ति में सुधार और समाज के सहभागिता के नए प्रयत्नों के लिए एक संसाधन आधार और जाने के निर्माण के साथ साथ योजनाओं को जारी रखने के लिए समर्पित था। इस वर्ष VIIईई योजना के लक्ष्योत्तर नीतियों में आरंभिक शिक्षा पर विचार किया गया और अंतिम रूप दिया गया ताकि 1985 तक आरंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाया जा सके।

सारणी — 4.1

1950-51 तक आरंभिक शिक्षा का प्रसार	1950-51	1989-90
आरंभिक स्कूलों की सं	2,320 लाख	5.50 लाख
निहित स्कूलों की सं	0.14 लाख	1.44 लाख
कक्षा I से V तक में नामांकन	19.15 मिलियन	97.3 मिलियन
लक्ष्यों का अनुच्छेद (सेरा)	13.77	57.8
लक्ष्यों का अनुच्छेद (सेरा)	5.38	34.5
कक्षा VI से VIII तक में नामांकन	5.13	32.1
लक्ष्यों का अनुच्छेद (सेरा)	2.59	20.3
I से VIII तक में नामांकन	11.8	11.8
लक्ष्यों का अनुच्छेद (सेरा)	22.28	129.4
लक्ष्यों का अनुच्छेद (सेरा)	16.36	78.1
	5.92	51.3

आदेशन ब्लैक बोर्ड

4.2.1 क्षमता में सुधार के अदृश्य के साथ पराधमिक स्कूलों में सुविधाओं में पर्याप्त सुधार लाने के लिए 1987-88 में प्रारम्भ हुई आदेशन ब्लैक बोर्ड योजना में तीन परस्पर निर्भरता तत्व हैं यानी (1) लक्ष्यों और लक्ष्योत्तर के लिए एक ब्ययपत्र और प्रथम टावलेट सहित सभी प्रयोग के उपकरण कम से कम दो को कमरे वाले सदन की व्यवस्था, (2) प्रत्येक स्कूल में कम से कम दो शिक्षक नियुक्ति से व्यवस्था एक महिला हो और (3) ब्लैक बोर्ड, नक्शा, मानचित्र, खिलौना और कार्यप्रणाली के लिए खिलौना सहित आवश्यक पठन सामग्री का प्रवेश। स्कूल प्रवर्धन के निर्माण के लिए कोष मुख्य रूप से प्रायोगिक विकास योजनाओं से प्रदान किए जाते हैं। अन्य दो चर्चों के लिए कोष इस विभाग द्वारा प्रदान किए जाते हैं। यह योजना देश के सभी ब्लॉक / पालिका क्षेत्रों में एक ब्ययपत्र रूप में आरंभिक स्कूलों को समिलित करने पर विशेष बल देती है।

4.2.2 वर्ष 1987-88 से 1990-91 की अवधि के दौरान 64% वाले देश के 69% ब्लॉकों में योजना कार्यान्वित की गई थी। इस विभाग द्वारा 523.41 करोड़ रूपय की सहायता निर्भरता की गई थी जिसमें से 150.09 करोड़ रूपय 1990-91 में जारी किए गए थे। वर्ष 1991-92 के दौरान आदेशन ब्लैक बोर्ड के लिए 100 करोड़ रु का आवधान है। यह योजना VIII वी योजना की समाप्ति तक जारी रहेगी।

4.2.3 उस स्थिति की ओर बढ़ने के क्रम में जहां प्रत्येक कक्षा के लिए एक कक्षा कम और एक शिक्षक है, यह प्रस्ताव किया गया कि प्रत्येक आरंभिक स्कूल में जहां नामांकन न्यायसंगत है, वहां एक तीसरा शिक्षक और तीसरा कक्षा कम प्रदान करने के लिए VIII वी योजना के दौरान आदेशन ब्लैक बोर्ड का प्रसार किया जाय। तीसरे शिक्षक के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाएगी जबकि राज्य सरकारों से अपेक्षा की जाएगी कि वे असाधारण गरीब योजना और राज्य योजना बजट से कक्षा कक्षा के निर्माण के लिए संसाधनों का पता लगाएं।

4.2.4 1991-92 तक आदेशन ब्लैक बोर्ड के अन्तर्गत उपलब्ध के अंकुशे सारिणी 4.2 में प्रस्तुत है।

शिक्षण अधिकारी है। बि.सि.परि. के नियमों/निकायों में शिक्षकों, गैर-सरकारी अधिकारियों, भारत सरकार और राष्ट्रीय स्तरों के संस्थानों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर दिया गया है। कार्यकारी दिवस राज्य परियोजना निर्देशिका को दिया गया है। बि.सि.परि.परि. और इसकी कार्यकारी समिति को बैठने, 19 और 20 जुलाई, 1991, 12 सितंबर, 1991 और 12 दिसंबर, 1991 को पटना में हुई थी। वित्तीय/सेवा संबंधी नियमों को तैयार किया गया और गैर-सरकारी अधिकारियों के सम्मेलन से लघु आयोगों/को के सहायता दी गई। जिलेदार कार्य-योगों/को को तैयार किया गया।

4.5.3 रिपोर्ट में सभी, प्रथम चरण और दोहास ऐसे चुनिन्दा जिले हैं, जहाँ कार्यपालन खोले हैं और रोजी जिले में साक्षरता अधिमान जैसे पूर्व-परियोजनाओं के कार्यक्रम शुरू करने में वचनबद्ध कार्य तथा डी-आई-ई-टी-ओ आदि में, इन्हें प्रयोग किया गया है। महिलाओं के कार्यक्षेत्रों के एक कोर-टेल का विकास करने, और शिक्षक संहिताओं के कार्यक्षेत्रों, राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद, राज्य सभा के केन्द्र और जिला अनुसंधान इकाइयों की सहभागिता के राज्य में बताई गई थी।

शिक्षण कार्य परियोजना

4.6.1. सीखा (सीडन की अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी) की सहायता से वर्ष 1987 से राजस्थान में इस परियोजना को कार्यनीतिगत किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राज्य के चुनिन्दा पुरुष तथा पिछड़े हुए गांवों में आर्थिक शिक्षा को जन-जन तक पहुंचाना है।

4.6.2. इस परियोजना से यह चर्चा चलता है कि शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में शिक्षकों की अनुपस्थिति एक मुख्य बाधा है। तदुसार इस परियोजना में यह परिकल्पना की गई है कि एकल शिक्षक स्कूलों में आर्थिक स्कूल शिक्षक के स्थान पर दो स्थानीय निवासियों को 'शिक्षा कर्मियों' के नाम से प्राप्त शिक्षित कार्यकर्ता हों, के एक दल को रखा जाए। स्थानीय व्यक्तियों की नियुक्ति निश्चित करने के लिए शिक्षा-कर्मियों के चयन में निम्नलिखित शिक्षकों के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हताओं पर जोर नहीं दिया जाता है। तथापि, शिक्षक के रूप में कार्यरत दल से कार्य करने के योग्य बनाने के लिए उन्हें एक सत्रा आधार पर प्रशिक्षण तथा शैक्षिक सहायता दी जाती है। मौजूदा आर्थिक स्कूल जब शिक्षा-कर्मियों द्वारा चलाए जाते हैं तो उन्हें "दिवस केन्द्र" कहा जाता है। इसके अलावा मध्यम शिक्षाकर्मियों से कर्मियों के लिए जो दिवस केन्द्र में धारा नहीं ले पाते हैं, उनके लिए प्रारंभ पाठशाला (रात्रि केन्द्र) चलाते हैं। परियोजना महिला शिक्षाकर्मियों की भरती पर भी जोर देते हुए स्थानीय महिलाओं को शिक्षाकर्मियों के रूप में कार्य करने के लिए तैयार करने हेतु विशेष प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की परिकल्पना करती है।

4.6.3. 30 नवंबर, 1991 तक परियोजना का कार्य-व्यय राज्य के 17 जिलों के 30 ब्लॉकों में 33 ब्लॉक इकाइयों वाले 361 गांवों में हो रहा था। शिक्षाकर्मियों की संख्या 765 थी (702 पुरुष तथा 63 महिलाएँ)। ये 361 दिवस केन्द्रों तथा 568 प्रारंभ पाठशालाओं की देख-रेख कर रहे थे जिन्हें कुल नामिका 30,330 था। 31 मार्च, 1992 तक राज्य 8 ब्लॉक इकाइयों को शामिल करने का प्रयास है जिसमें 1383 शिक्षा कर्मियों द्वारा 615 दिवस केन्द्रों तथा 1383 प्रारंभ पाठशालाओं की देख-रेख करने की प्रयास है।

4.6.4. 1990 के उत्तरार्ध में शिक्षा कर्म परियोजना का एक संलग्न

अध्ययन किया गया था। अध्ययन से पता चलता है कि परंपरागत स्कूलों के बच्चों की तुलना में शिक्षाकर्म स्कूलों में अध्ययन कर रहे बच्चों का उपलब्ध स्तर एक में है।

4.6.5. वर्ष 1991-92 के बजट अनुमान में 230 लाख रुपए का बजट प्रावधान है।

लोक जुबिलस: सभी के लिए शिक्षा सम्बन्धी जन आन्दोलन: राजस्थान

4.7.1. राजस्थान में स्वीडिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास भविष्य (सीडा) से प्राप्त सहायता के साथ "लोक जुबिलस" राजस्थान में सभी के लिए शिक्षा सम्बन्धी जन आन्दोलन नामक एक नई शैक्षिक परियोजना आरम्भ करने का प्रयास है। इस परियोजना का उद्देश्य राज्य के लिए वर्ष 2000 तक जन शिक्षा को जूटा कर तथा उनकी सहभागिता से सभी के लिए शिक्षा प्राप्त करना है।

4.7.2. सीखा 20 मिलियन स्वीडिश क्रोना (लगभग 8 करोड़ रुपये) की राशि तक इस परियोजना के प्रथम चरण के लिए सहायता देने के लिए सहमत हो गया है। ये उपरवर्ती चरणों में सहायता पर निवार करने के लिए सहमत हो गए हैं, जो चरण-1 की प्रति संबंधी कार्य के एक संयुक्त मूल्यांकन पर आधारित होगा। "कार्लोई योजना"-प्रथम चरण (1992-94) नामक एक दस्तावेज उनके औपचारिक अनुसंधान के लिए सीखा को रखा गया है। परियोजना का चरण-1, 1 अक्टूबर, 1992 से आरम्भ होने की आशा है और वर्ष 1992-94 से 2 वर्ष की अवधि के अन्तर 25 से अधिक स्कूलों को शामिल करेगा। चरण-1 के लिए कुल परियोजना परियोजना 20.1 करोड़ रुपए तक का अनुमान है और यह राशि सीखा और भारत सरकार के बीच समान भाग में बांटी जाएगी और राजस्थान सरकार के बीच इसका अनुपात 3:2:1 होगा। पहले चरण के बाद दूसरा चरण वर्ष 1994-99 और तीसरा चरण 3-4 वर्ष की अवधि का होगा।

4.7.3. राजस्थान सरकार ने, जिसने पहले से ही इस परियोजना का अनुसंधान कर दिया है, सभी आर्थिक उपाय कर रही है ताकि परियोजना की प्रथम में ही आरम्भ किया जा सके। इस परियोजना से संबंधित कुछ पूर्व-परियोजना संबंधी नियामकता पहले से ही आरम्भ किया जा चुके हैं और कुछ स्कूलों में कुछ आर्थिक कार्य भी आरम्भ किया गया है।

4.7.4. बजट आकलन 1991-92 में 100 लाख रुपए का बजट भावना किया गया है। (वर्ष 1990-91 के दौरान पूर्व-परियोजना संबंधी नियामकताओं के लिए 21 लाख रुपए की राशि का पहले ही उपयोग किया जा चुका है।)

शिक्षक शिक्षा

4.8.1. शिक्षक शिक्षा की पुनः संरचना और पुनर्गठन की केन्द्रीय माओजित योजना को 1978-83 से कार्यनीतिगत किया जा रहा है। इसका उद्देश्य देश में शिक्षक शिक्षा अग्राणी की सुदृढ़ बनाना है ताकि वह स्कूलों और सीक तथा गैर-औपचारिक शिक्षा अग्राणियों को अग्रणी प्रशिक्षण और शैक्षिक सहायता प्रदान कर सके। इस योजना के निम्न पांच घटक हैं—

— शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में परिकल्पित मुख्य-मुख्य लोगों की जानकारी देने और उनकी व्यावसायिक समता में सुधार करने के उद्देश्य से 1989-90 तक प्रतिवर्ष लगभग पांच लाख स्कूल

अध्यापकों को पुनः प्रशिक्षण,

—मौजूदा उपयुक्त प्राथमिक शिक्षक शिक्षा संस्थाओं का दर्जा बढ़ाकर या जहाँ आवश्यक हो वहाँ नई संस्थाएँ स्थापित करके लगभग 400 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना, ताकि जिला स्तर पर प्राथमिक शिक्षा कालेजों को समग्र शैक्षिक और प्रशिक्षण सहायता प्रदान की जा सके।

—लगभग 250 माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण और उनमें से लगभग 50 का उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थान के रूप में तथा शेष का शिक्षक शिक्षा कालेजों के रूप में विकास,

—राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों का सुदृढ़ीकरण और

—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों में शिक्षा विभागों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण,

4.8.2 वर्ष 1987-88 की अवधि के दौरान योजना के अंतर्गत हुई उपलब्धियों तालिका 4.4 में दर्शाई गई है:—

तालिका-4.4

शिक्षक शिक्षा उपलब्धियाँ

1987-88 से 1991-92 तक
कुल (22-2-92 तक)

1	खुबं का गाँव राशि	187.29 करोड़ रुपये
2	अध्यापकों के पुनः प्रशिक्षण के साप्ताहिक कार्यक्रम 12.96 करोड़ रुपये में।	
3	अध्यापकों के पुनः प्रशिक्षण के साप्ताहिक कार्यक्रम 12.96 करोड़ रुपये में।	
4	अध्यापकों के पुनः प्रशिक्षण के साप्ताहिक कार्यक्रम 12.96 करोड़ रुपये में।	
5	ऐसी जिला शिक्षक शिक्षा संस्थाओं की संख्या 287 जिन्हें स्वीकृत दी गई	
6	ऐसी शिक्षक शिक्षा कालेजों की संख्या जिन्हें 25 स्वीकृत दी गई	
7	ऐसी उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थानों की संख्या 12 जिन्हें स्वीकृत दी गई	
8	उन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की संख्या जिन्हें 24 सम्मिलित किया गया।	

4.8.3 जबकि वर्ष 1990-91 में मुख्य रूप से पहले से संस्वीकृत परियोजनाओं का समेकन किया गया। वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान बचे हुए जिलों को शामिल करने के लिए नई परियोजनाएँ संस्वीकृत की जा रही हैं। पांडिचेरी के लिए एक जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान पहले ही संस्वीकृत किया जा चुका है। वर्तमान वर्ष के दौरान बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, उड़ीसा, मणिपुर, मेघालय तथा मिजोरम इत्यादि में अनेक जि.शि.प्र. सं./सो.टी.ई./आई.ए.एस.टी. परियोजनाएँ संस्वीकृत किए जाने की आशा है। अब तक संस्वीकृत परियोजनाओं, जिन्होंने कार्य करना प्रारंभ कर दिया है, उनका राज्य-वार ब्यौरा तालिका 4.5 में दिया गया है।

4.8.4 रा.शि.प्र.सं. (नीपा) रा.श.प्र.सं. एवं प्र.प. तथा इसके क्षेत्रीय

कालेजों द्वारा जि.शि.प्र. सं. के संभव के लिए अब तक 10 प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं जिनमें 222 व्यक्तियों ने भाग लिया। शेष वर्ष के दौरान कुछ अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाने की आशा है।

4.8.5 आवश्यक धननों को बनाने के लिए तथा पदों का सृजन करने और उन्हें भरने के लिए समय को ध्यान में रखते हुए जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों, शिक्षक शिक्षा केंद्रों तथा उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थानों को स्थापित करना एक लंबी अवधि वाला क्रियाकलाप है। फिर भी लगभग 150 जि.शि.प्र. सं. संस्थानों ने कार्य करना तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने प्रारंभ कर दिए हैं। बाह्य एजेंसियों के जरिए वर्ष 1987-88 के दौरान संस्वीकृत ऐसे कुछ संस्थानों का प्रारंभिक किया जा रहा है। अब रिपोर्ट प्राप्त हो रही हैं जिनको जांच की जा रही है।

4.8.6 राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषदों को सुदृढ़ करने के लिए मार्गदर्शी रूपरेखाएँ तैयार की जा रही हैं। जैसे ही इन रूपरेखाओं को अंतिम रूप दे दिया जाएगा, इस घटक का कार्यान्वयन शुरू हो जाएगा।

4.8.7 विश्वविद्यालय शिक्षा विभागों को सुदृढ़ बनाने के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का शिक्षा संबंधी पैराल इस मामले पर ध्यान दे रहा है।

तालिका 4.5

दिसंबर, 1991 को संचालित जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	जि.शि.प्र.सं. की संख्या	संघासित जि.शि.प्र.सं. की संख्या
1	2	3	4
1	आंध्र प्रदेश	23	23
2	अरुणाचल प्रदेश	1	—
3	असम	12	8
4	गोवा	1	1
5	गुजरात	13	—
6	हरियाणा	8	2
7	हिमाचल प्रदेश	4	—
8	जम्मू व कश्मीर	14	6
9	केरल	14	7
10	मध्य प्रदेश	45	30
11	महाराष्ट्र	11	—
12	मणिपुर	1	—
13	मेघालय	3	—
14	मिजोरम	1	1
15	नागालैंड	1	—
16	उड़ीसा	11	11
17	पांडिचेरी	1	—
18	पंजाब	7	7
19	राजस्थान	27	27
20	सिक्किम	1	1
21	तमिलनाडु	21	14
22	त्रिपुरा	1	—

जि.शि.प्र.सं. जहाँ प्रयागवाच्यों को तैनात किया गया है और/अथवा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और/अथवा जिन मामलों में राज्य/संघशासित क्षेत्रों ने आवर्ती सहायता मांगी है उन्हें संचालित समझा गया है।

विला सम्बन्धित शिक्षण प्रशिक्षण एवं राज्य शैक्षणिक-पब्लिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को नया रूप देकर तथा सक्षमता आधारित शिक्षण को उनके स्कोर कार्यक्रमों तक भेजित बनाकर न्यूनतम शिक्षण स्तर को लागू करने के लिए भी प्रयास किया गया।

बाल प्रबन्धन सोसाइटी

4.11.1 धीकत जवाहर लाल नेहरू की प्रेरणा पर बाल प्रबन्धन सोसाइटी, नई दिल्ली की स्थापना की गई तथा इसे घातल सल्लर द्वारा 1955 में सोसाइटी प्रबन्धन अभिन्धम के अंतर्गत प्रकीकृत सोसाइटी के रूप में स्थापित किया गया। यह शिक्षा विभाग द्वारा पूर्णतः विलोपित एक स्वायत्त संगठन है। यह सोसाइटी 5-16 वर्षों के आयु वर्ग के बच्चों में प्रबन्धन कार्यकलापों को बढ़ावा देने में अपना योगदान देती है। विशेषकर समाज के अर्थिक रूप से शिकड़े हुए वर्गों तथा अन्य वर्गों के बच्चे प्रबन्धन एवं निबन्धन कलाओं, पर्यावरण, खगोल विज्ञान, भूदोलप्रती, प्रकीकृत कार्य कलाप एवं राशीतिक कार्यकलापों तथा विज्ञान-संघी कार्यकलापों में अपनी-अपनी पसंद के कार्यकलापों का अध्ययन कर सकते हैं। समिति के 52 बाल प्रबन्धन केन्द्र हैं जो सारी दिल्ली में फैले हुए हैं और यह दो जवाहर बाल भवनों, का भी विलोपन कर रही है जिनमें से एक श्रीनगर में तथा दूसरा मंडी में है। बाल प्रबन्धन का प्रतीय प्रशिक्षण संसाधन केन्द्र इच्छुक व्यक्तियों को, जिनमें शिक्षक और शिक्षक प्रशिक्षक भी शामिल हैं, बाल प्रबन्धन प्रणाली में प्रशिक्षण प्रदान करता है। देश में राज्य तथा जिला बाल प्रबन्धन भारतीय बाल प्रबन्धन समिति से संबद्ध हैं, जो उन्हें सामान्य मार्गदर्शन, प्रशिक्षण सुविधाओं और सूचना स्वर्गतरण की व्यवस्था करते हैं। बाल प्रबन्धन का उद्देश्य है स्वतंत्र व सुरक्षाल वातावरण में बच्चे का बहुमुखी विकास।

4.11.2 बाल प्रबन्धन ने बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने के लिए अनेक विज्ञान संबंधी कार्यक्रम आरंभ किए:

- (क) भारतीय बाल प्रबन्धन समिति परिलर में कम मूल्य तथा बहु-आयामी दृष्टिकोण वाला एक विज्ञान पार्क बनाया गया।
- (ख) अन्य बाल भवनों के शिक्षकों के लिए खगोल विज्ञान पर कार्यशालाएँ तथा सौर ऊर्जा सेल आयोजित किए गए ताकि अन्य राज्यों के बच्चों को विज्ञान कार्यकलापों में शामिल किया जा सके।
- (ग) बाल प्रबन्धन में एन सी एस टी सी-विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग के सहयोग से कम लागत की टूलीन तैयार करने, बाल तापमंडल की देखरेख एवं उसका अनुप्रक्षण और वास्तव्य की वैज्ञानिक व्याख्या विभव पर एक-एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इन

कार्यशालाओं में राज्य बाल भवनों के बालकों और शिक्षकों ने भाग लिया।

4.11.3 बच्चों में पर्यावरण संबंधी जागरूकता पैदा करने के लिए पर्यावरण से जुड़े कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

(क) मुख्य विशेषज्ञों के एक प्रतीय समेलन का आयोजन किया गया। यह समेलन बच्चों को पर्यावरण की स्थिति पर अपने धारों और विचारों को साभने रखने का एक मंच उपलब्ध करवाने का उद्दिष्टीय प्रयास था। इस समेलन ने बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा की और बाल प्रतिनिधियों ने एक चार्टर तैयार किया जिसे न्यायिक के प्रीतिरिफ विषय समेलन में देखा गया।

(ख) सभी अभियों के सह-अस्तित्व के महल और परिस्थितिक संकुलन की आवश्यकता पर बाल देने के लिए एक साप्ताहिक पर्यावरण जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। राज्य बाल-भवनों, अर्द्धिवासी एवं सल्लर क्षेत्रों के बच्चों ने इसमें भाग लिया।

(ग) बच्चों की स्वनाल्लक प्रतिभा को अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों में वर्गों खण्ड अभिन्धन, मल्लार मिलन और प्रीत्य शिविर शामिल हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों को हमारी समृद्ध सांस्कृतिक पराहर और विख्यात कलाकारों और प्रेरक व्यक्तियों से परिचित करवाया।

(ख) बच्चों को सध्यावनापूर्ण भातोल में रहने की शिक्षा देने के लिए एक प्रतीय बाल-सभा आयोजित की गई। एक बाल-संभालन का भी उद्घाटन किया गया।

(ड) बाल-प्रतिभा को, विशेषकर विभव वर्गों की बाल प्रतिभा को स्वनाल्लक अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करने के बाल प्रबन्धन की चेष्टा के घाग के रूप में विकलांग बच्चों लिए "अभिन्धेरा" नामक एक पांच दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

4.11.4 नेतृत्व-गुणों और राशीरिक अनुशासन के विकास के लिए एक 12 दिवसीय गोवा यात्रा का आयोजन किया गया

4.11.5 अर्द्धिप्रतीय एकता की भावना को बाल प्रदान करने के मंतव्य से जर्जन संघीय गणराज्य और साहस के सहयोग से सांस्कृतिक अभिन्धम कार्यक्रम आयोजित किए गए।

5. 4870, 48

5. माध्यमिक शिक्षा

माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायिकरण

5.1.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में शिक्षा के व्यावसायिकरण को दृढ़ता प्रदानकताओं की केन्द्रीय प्रयोजित योजना, जो फरवरी, 1988 में शुरू की गई थी, उत्साहपूर्ण कार्यान्वयन की जाती रही। इस योजना के मुख्य दिव्य विचार प्रसार के शैक्षिक आवश्यक प्रदान करना ताकि वैश्वीकरण जगत् की बढ़ती की बढ़ती जा सके, अवसरानुसृत जनशक्ति की मांग तथा प्रगति के बीच असमानता को कम किया जा सके, और उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों के लिए कोई विकल्प प्रदान किया जा सके।

5.1.2 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का चयन क्षेत्र व्यावसायिक संकेतकों, जगत् कार्यालयों से प्रयोजितों के आधार पर किया जाता है, और जिला प्रशासनिक योजनाओं के अंतर्गत जनशक्ति आवश्यकताओं का एक सामान्य मूल्यांकन किया जाता है। कुछ हद तक इससे यह सुनिश्चित होता है कि छात्रों को उन व्यावसायिक क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जाता है जिनमें तबत अथवा मजदूरी रोजगार के अवसरों का आश्वासन दिया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यपद्धति आवश्यकता आधारित है और सामाजिक रूप से सगत है, पाठ्यपद्धति तथा शैक्षिक सामग्री के विकास की जिम्मेदारी को स्थानीय विशेषज्ञ संगठनों के सहयोग से राज्य/संघ शासित क्षेत्रों पर छोड़ दिया गया है। तथापि, यह निष्कर्ष की गई है कि व्यावसायिक सिद्धान्त और प्रयोग को कुल शैक्षिक समय का लगभग 70% दिया जाना चाहिए। नैकरी के वक्ता प्रशिक्षण पाठ्यपद्धतिओं का एक अतिरिक्त घाग है। शेष समय को यात्राओं के अध्ययन और सामान्य आधार पाठ्यक्रम को आवंटित किया जाता है।

5.1.3 योजना के अंतर्गत राज्य स्तर पर प्रतिस्पर्धी निकायों सहित राष्ट्रीय स्तर पर एक संयुक्त व्यावसायिक शिक्षा परिषद (जो सौ बी.ई.) गठित की गई है ताकि विभिन्न एजेंसियों/संगठनों द्वारा आयोजित व्यावसायिक कार्यक्रमों के नीति-निर्देश-निर्देश, आयोजना और समन्वय निर्धारित किए जा सकें। जै. सी. बी. ई. के विभिन्न भगालयों/विभागों, सरसर-सदस्यों, राज्य सरकारों, क्षेत्रीय संगठनों, व्यावसायिक शिक्षा से विशेषज्ञों और अग्रिम भारतीय व्यावसायिक निकायों से अपने सदस्य प्रतिनिधि हैं और इसके अन्धध केन्द्रीय शिक्षा मंत्री हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि जै. सी. बी. ई. द्वारा निर्धारित कार्य को निम्नान कारगर ढंग से किया जा रहा है केन्द्रीय शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में जै. सी. बी. ई. की एक स्थायी समिति भी गठित की गई है।

5.1.4 इस समय 27 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में यह योजना कार्यान्वित की जा रही है। सार्वभौमिक के अंत तक कक्षा-XI और XII में एक साथ 3.94 लाख छात्रों की नामांकन संख्या स्थित 7988 व्यावसायिक अनुभाग अनुमोदित किए जा चुके थे। 1990-91 के दौरान 1128 अतिरिक्त अनुभाग अनुमोदित किए गए थे। 1991-92 के दौरान अत्य 1400 व्यावसायिक अनुभाग संवीकृत करने का प्रस्ताव है। इस प्रकार 1991-92 के अंत तक व्यावसायिक धारा में 5.85 लाख छात्रों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो गई होगी। 1991-92 के दौरान + 2

पर अनुमानित नामांकन 66.05 लाख है। इसका अंशय व्यावसायिक धारा की और लगभग 8.7% को अनुसूचित जाति लोग। तथापि, संभवतया वास्तविक नामांकन कम होगा क्योंकि उपलब्ध सुविधाओं की अधिकतम उपयोगिता का लक्ष्य प्राप्त न हो सके।

5.1.5 माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायिकीकरण की योजना में व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में स्वीकृत संगठनों द्वारा शुरू किए गए नवीन कार्यक्रमों की अभिलेखि सहायता देने का आश्वासन है। 1991-92 के दौरान 6 क्षेत्रीय संगठनों को लगभग 16.217 लाख रु. की वित्तीय सहायता दी गई है।

5.1.6 माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायिकीकरण की योजना में, अध्ययन की अवधि और पाठ्यक्रम पूरा हो जाने के बाद दोनों के दौरान छात्रों के व्यावसायिक प्रशिक्षण पर परीक्षण से बल दिया गया है + 2 स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वालों के लिए प्रशिक्षण शामिल करने के वाले 1956 में प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 में संशोधन किया गया था। बाद में, सितम्बर, 1987 में और इसके बाद अगस्त, 1988 में प्रशिक्षुता नियमों में संशोधन किया गया था जिसके द्वारा प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत व्यावसायिक छात्रों को शामिल करने के लिए 20 विषय क्षेत्रों को अधिसूचित किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत इस प्रकार के और विषयों की अधिसूचित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

5.1.7 बम्बई, कलकत्ता, मद्रास तथा कानपुर स्थित शिक्षा विभाग के चार क्षेत्रीय प्रशिक्षण प्रशिक्षण निकायों के माध्यम से प्रशिक्षु अधिनियम कार्यान्वित किया जा रहा है। एक निर्धारित संख्या में प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण देने की सुविधाएं प्रदान करना प्रशिक्षु अधिनियम के आध्यात्मों को अंतर्गत आने वाले अनेक स्थानों की एक संवैधानिक जिम्मेदारी है। 1990-91 तक दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों में छात्रों की 119.08 लाख रु. की राशि उपलब्ध कराई गई थी। 1991-92 के दौरान (नवम्बर, 91 तक) इस अर्थस्य के लिए उतरी क्षेत्र को 1.00 लाख रु. की राशि उपलब्ध कराई गई है।

5.1.8 व्यावसायिक छात्रों को, बसने के निर्धारित न्यूनतम स्तर पूरा करते हैं, तत्काल रोजगार सुनिश्चित करने के लिए प्रयोजितों को आवश्यकताओं के अनुसूचित निर्देशित व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए कार्यवाही की जा रही है। जै. सी. बी. ई. द्वारा सामान्य बीमा निगम और जीवन बीमा निगम के सहयोग के क्रमशः सामान्य बीमा तथा जीवन निगम में इस प्रकार के व्यावसायिक पाठ्यक्रम पहले ही शुरू किए गए हैं। रेलवे बोर्ड के सहयोग से रेलवे वणिज्यिक कर्मचारियों के लिए एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम तैयार किया गया है और उसे 1991-92 के दौरान 5 स्कूलों में शुरू किया गया है। आशय है कि 1992-93 में और स्कूलों में यह पाठ्यक्रम शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार व्यावसायिक के सहयोग से व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। दिल्ली के 3 स्कूलों में 1991-92 से तीन विभिन्न पाठ्यक्रम, अर्थात् जिकिन्स प्रयोगशाला तकनीक, एकरे तकनीक और नैत्र तकनीक शुरू किए गए हैं। 1992-93 के दौरान और अधिक स्कूलों को शामिल किया जाएगा।

5.1.14 अर्थात निरीक्षण, मूल्यांकन तथा समीक्षा योजना के लिए एक आंकड़ा आधार तैयार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। योजना के निर्माण पहलुओं पर वास्तविक आंकड़ों का संग्रह किया गया है और उसका विश्लेषण किया जा रहा है। एक्टों/संघ शालित क्षेत्रों से निर्धारित रूप से योजना प्रवाह के लिए एक संगठनात्मकत प्रक्रिया पद्धति भी

तैयार की जा रही है। आशा है कि अस्तित्वित प्रबंध सुचना पद्धति विनीय वर्ष 1992-93 से चारु हो जाएगी।

5.1.15 1991-92 के दौरान योजना का बजट 89.00 करोड़ रु. है जिन्मे से नवम्बर, 1991 तक 16.34 करोड़ रु. की राशि टी गई थी।

शैक्षिक प्रौद्योगिकी कार्यक्रम

5.2.1 व्यापक रूप से शिक्षा सुलभ कराने और उससे कोटिपरक सुधार लाने के लिए चौथी योजनावर्ष के दौरान वर्ष 1972 से केन्द्रीय क्षेत्र से एक शैक्षिक प्रौद्योगिकी कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत पाँच सौ अंश प्रोग्रामों में एक शैक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र खोला गया था और शैक्षिक प्रौद्योगिकी कक्ष स्थापित करने के लिए 21 राज्यों को 100% सहायता प्रदान की गई थी।

5.2.2 इन्स्टीटूट के आगमन से मसाला सुविधाओं के विस्तार और शैक्षिक सम्पदोन्मुख की संभावनी याग की देखरे में शिक्षा मन्त्रालय ने उपर्युक्त के माध्यम से शैक्षिक प्रौद्योगिकी के दौरान कार्यक्रम तैयार करने की जिम्मेदारी लेने का निर्णय किया। तदनुसार मन्त्रालय द्वारा पाँच अंश प्रोग्रामों और आठ राज्यों, अर्थात् आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश से राज्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थाओं में एक केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने और अन्य राज्यों में शैक्षिक प्रौद्योगिकी कक्षों को सुदृढ करके विकेन्द्रीकृत आधार पर शैक्षिक क्षेत्र के अन्दर शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम तैयार करने की सुविधाएं उपलब्ध कराने की एक योजना तैयार की गई थी।

5.2.3 पशुधन शिक्षा नीति के अंशधर पर करने के लिए शैक्षिक प्रौद्योगिकी योजना को 1987 से समर्थित किया गया था ताकि शैक्षिक दूरदर्शन तथा कृष्य कार्यक्रम निर्माण क्षमताओं को सुदृढ किया जा सके और उन्हें सातवीं योजना के दौरान प्राथमिक स्कुलों की एक लाख रोजी टेलीविजन सेट और पाँच लाख रेडियो एवं कैसेट प्लेयर्स की आपूर्ति करके व्यापक रूप से उपलब्ध कथा जा सके।

5.2.4 शिक्षा और शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों की संचार माध्यम समय आवश्यकता से संबंधित अप्रार सेवाओं के उपयोग का अध्ययन करने तथा उनकी सिफारिश करने के लिए आमत, 1987 में संयोजक के रूप में डा० विरूप कर्नाटक के साथ एक दल गठित किया गया था। सरकार दल की सिफारिशों पर विचार कर रही है।

5.2.5 केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान और सभी छः एस० आई० ई० टी० में कार्यक्रम निर्माण शुरू हो गया है। वास्तव में, शैक्षिक वर्ष 1988-89 से कार्यक्रम निर्माण की जिम्मेदारी की, जिसे उस समय तक के सौ सौ सं० और दूरदर्शन के बीच 50 50 आधार पर आपस में निभाया जा रहा था, के सौ सौ सं० और एस० आई० ई० टी० द्वारा संपाल लिया गया है। इस समय उपग्रह आधारित शैक्षिक दूरदर्शन सेवा में प्राथमिक स्तर पर कक्षा तथा उनके शिक्षकों के लिए समय निर्माण के आधार पर प्रत्येक पाँच क्षेत्रीय भाषाओं, अर्थात् गुजराती, हिन्दी, मराठी, उड़िया तथा तेलुगु में 45 मिनट की अवधि के लिए प्राप्त शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण की व्यवस्था है। ये कार्यक्रम बच्चों के लिए सीधे तौर से शुरूवार तथा प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिए प्रत्येक रविवार प्रसारित किए जाते हैं। 5-8 और 9-11 वर्ष के आयु वर्ग में बच्चों के लिए प्रत्येक दिन अलग से कार्यक्रम है।

5.2.6 छः इन्स्टीटूट राज्यों में सभी उच्च और निम्न शक्ति के दान्यभांदरी द्वारा ये शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। हिन्दी में ये कार्यक्रम पाँच हिन्दी भाषी राज्यों, अर्थात् हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, तथा राजस्थान और संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ द्वारा भी प्रसारित किए जाते हैं।

5.2.7 कम्पैड और हैटपचाइ से सुविधाएं जोड़ने की उपलब्धता के कारण प्रसारण समय का नवम्बर, 1991 से पुन निर्धारण किया गया है।

5.2.8 केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान में अक्टूबर, 1991 तक 646 शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम और 914 भाषा रूपान्तर तैयार किए हैं। इसने 1986, 1987, 1988 तथा 1989 की प्रमुख अवधि के दौरान एस० आई० एच० टी० के कार्यक्रमों के लिए 450 कंप्यूटो का भी निर्माण किया है। एस० आई० ई० टी० द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रमों की संख्या सारणी 5.1 में दी गई है।

सारणी 5.1

जुलाई, 1991 तक राज्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रमों की संख्या

कार्यक्रमों की संख्या

राज्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी

संस्थान

1 आंध्र प्रदेश	562
2. बिहार	105
3 गुजरात	805
4 महाराष्ट्र	1058
5 उड़ीसा	107
6. उत्तर प्रदेश	604

5.2.9 एस०आई०ई०टी० द्वारा प्रबंध और तकनीकी कामों के सम्बन्ध में की जा रही सम्बन्धों के कारण अपेक्षित स्तर की पर्याप्त उपपदन क्षमता प्राप्त करने में उसकी प्रगति धीमी रही है। एस०आई०ई०टी० के कार्यक्रमों में संचार के उपाय सुझाने के लिए गठित कार्यदल ने अन्य बातों के साथ एस०आई०ई०टी० को राज्य सरकारों के तत्वावधान में पंजीकृत सोसायटियों के रूप में स्वायत्त संगठन में परिवर्तन करने का भी सुझाव दिया। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के एस०आई०ई०टी० स्थापन हो चुके हैं। बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के एस०आई०ई०टी० शीघ्र ही सोसायटी के रूप में पंजीकृत होने वाले हैं, जबकि गुजरात सरकार के माध्यम पर बातचीत चल रही है।

5.2.10 शैक्षिक टेलीविजन कार्यक्रमों के निर्माण से निजी निर्माताओं की शामिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। रा०सौ०अनु० च प्रयोग में सी०आई०ई०टी० के लिए वीडियो / फिल्म तैयार करने के लिए कार्यरत निर्माताओं की शामिल करने हेतु कार्य पद्धतियां विकसित करने के लिए एक समिति गठित की है। बाहरी निर्माताओं को दिये गये व शैक्षिक टेलीविजन वीडियो कार्यक्रम तैयार हो चुके हैं और अन्य आठ कार्यक्रम पूरे होने वाले हैं।

5.2.11 शैक्षिक टेलीविजन योजना के तहत सी टी वी सेट और आग सी सी पी विनरित करने का एक महत्वकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया

गया था राज्य सरकारों और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा श्रव्य कार्यक्रम निर्माण के लिए धन मंजूर किया जा रहा है। केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान ने स्कूल शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न शैक्षिक विषयों पर 1100 से भी अधिक श्रव्य कार्यक्रम तैयार किए हैं। राज्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थानों द्वारा या तो स्वयं या बाहरी एजेंसियों के माध्यम से श्रव्य कार्यक्रमों के निर्माण के लिए तेज प्रयास किये जा रहे हैं। केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा तैयार लगभग 40 वीडियो और श्रव्य

कार्यक्रमों की एक सूची तैयार की गई है जो जिला शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थानों को अपने शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सार्वक संचार सहायता प्रदान करेंगे।

5.2.12 शिक्षा प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों के अंतर्गत उपलब्धियों का सार सारण 5.2 में प्रस्तुत है।

तारिका 5.2

शैक्षिक प्रौद्योगिकी : उपलब्धियाँ

	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	कुल
व्यय राशि (करोड़ रु० में)	111.74	16.20	16.50	14.57	3.15	64.56
शामिल किए गए शक्ति राशियाँ	13	29	31	32		32
की संख्या						
विस्तारित टी वी सेटों की संख्या	10049	12049	2799	6232	—	31129
विस्तारित रेडियो व कैसेट प्लेयर की संख्या	37562	67735	49963	72863	315	231228
संख्या को-ऑपरेटिव						
1 सी-आर्जी-टी-वी की जारी की गई राशि (रु० करोड़ में)	5.28	3.10	3.146	2.37	1.00	15.89
2 एस-आर्जी-टी-वी की जारी की गई राशि (रु० करोड़ में)	1.40	1.53	2.20	0.44	0.63	6.65
(6 इन्फेंट राय, आर आर, विस्तार, गुणवत्ता, महारथ, उर्वार और उत्तर प्रदेश)				0.45		
3 ई-टी-वी सेटों की जारी की गई राशि (रु० करोड़ में)	0.22	0.26	0.54	—	—	1.02
4 टी-वी / जल-सौकर-पै-के लिए एम्बो / सच शक्ति प्रदेशों की जारी की गई राशि (रु० करोड़ में)	7.15	11.19	10.60	11.66	0.33	40.81
5 जल-सौकर-पै-के लिए साफ़-पेयन का विकास (रु० करोड़ में)	—	—	—	0.10	0.19	0.29

स्कूलों में विज्ञान शिक्षा का सुधार

5.3.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, में परिकल्पित धारणा के अनुरूप विज्ञान शिक्षा की कोटि में सुधार और वैज्ञानिक मानसिकता को प्रोत्तन करने के लिए, स्कूलों में विज्ञान शिक्षा में सुधार की कन्द प्रयोजित स्कीम 1987-88 की अंतिम तिमाही के दौरान शुरू की गई थी। इस स्कीम के अंतर्गत उच्च प्राथमिक स्कूलों को विज्ञान किटों के प्रबंध के लिए एक अपेक्षित स्तर तक सैकेण्डरी और हायर स्कूलों में विज्ञान प्रयोगशालाओं के प्रोत्तन और सुदृढीकरण के लिए सैकेण्डरी और हायर सैकेण्डरी स्कूलों में विज्ञान प्रयोगशालाओं के प्रोत्तन और सुदृढीकरण के लिए, सैकेण्डरी और हायर सैकेण्डरी स्कूलों में पुस्तकालयों के प्रोत्तन, विज्ञान शिक्षा के जिला ससाधन केन्द्रों की स्थापना शैक्षिक मामलों के विकास में और विज्ञान व

गणित के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए राज्यों / सच शामिल क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह स्कीम विज्ञान शिक्षा नवाचारों परियोजनाएँ और ससाधन सधरण कार्यक्रमों शुरू करने के लिए विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय स्वेच्छक संगठनों को भी वित्तीय सहायता प्रदान करती है। हालांकि इस स्कीम का उद्देश्य आठवीं योजना के अंत तक एक चरम क्रम में सभी सरकारी और सरकार से सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक, सैकेण्डरी और हायर सैकेण्डरी स्कूलों को इसमें शामिल करना है। इस मंत्रालय ने वित्तीय रुकावटों को देखते हुए 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक कुल विद्यमान स्कूलों का 55% शामिल करने का प्रस्ताव रखा है।

5.3.2 1990-91 तक इस स्कीम के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियों के आकड़े तथा 1991-92 के दौरान पूर्वानुमान उपलब्धियों नीचे की सारणी 5.3 में दिए गए हैं।

सारणी 5.3

विज्ञान शिक्षा : उपलब्धियाँ

	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	पूर्वानुमान कुल
व्यय राशि (करोड़ रु० में)	29.27	29.16	21.60	20.50	23.99	124.61
शामिल किए गए राज्य / सच शामिल	19	15	21	24	25	32
क्षेत्र शामिल किए गए स्कूलों की संख्या						
1. उच्च प्राथमिक (विज्ञान सेट)	20,719	14,037	8,463	5,791	6,000	55,010

	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	कुल
स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	कुछ नहीं	25	7	6	12	50
शामिल किए गए स्कूलों की संख्या	कुछ नहीं	7298	4,512	4,876	6,000	22,68
सहायता प्राप्त स्कूलों की संख्या	कुछ नहीं	6	9	7	10	17
					5-(नए)	

स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षा

5.6.1 स्कूलों में संगणक साक्षरता तथा अध्ययन (कलास) की एक प्रमुख परियोजना 248 चुनिंदा माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में 1984-85 में, इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग तथा शिक्षा विभाग द्वारा संयुक्त रूप से, छात्रों व शिक्षकों को संगणक अनुप्रयोग के विस्तार तथा इसकी समताओं से एक अध्ययन माध्यम के रूप में परिचित करने के लिए शुरू की गई थी। वर्ष 1989-90 तक परियोजना के अंतर्गत 2598 स्कूलों को शामिल किया गया था। स्कूल शिक्षकों को प्रशिक्षित करने तथा भाग लेने वाले स्कूलों को तर्कसंगत सहायता उपलब्ध करने के लिए साठ संसाधन केन्द्र स्थापित किए गए हैं। हार्डवेयर का रखरखाव तथा इसकी स्थापना की जिम्मेदारी संगणक रखरखाव निगम की बनी रही तथा रांशै-अनु-प्र-परिषद् इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए प्रमुख एजेंसी बनी रही। परियोजना की संचालन समिति की अध्यक्षता इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग तथा शिक्षा विभाग के सचिवों द्वारा संयुक्त रूप से की गई। वर्ष 1985-86 तक स्कूलों ने 2 बी-बी-सी माइक्रो का एक सेट प्राप्त किया। वर्ष 1987-88 से आगे

इसकी संख्या 5 बी-बी-सी माइक्रो तक बढ़ गई। पिछले वित्तीय वर्ष से एक निर्णय यह लिया गया कि उन (1249) पुराने स्कूलों को अतिरिक्त 3 बी-बी-सी माइक्रो उपलब्ध कराए जाएंगे जहाँ अभी तक केवल 2 कम्प्यूटर हैं। अतः वर्ष 1990-91 से कोई नया स्कूल शामिल नहीं किया गया है। परियोजना का मूल्यांकन वर्ष 1986 में अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र, अहमदाबाद द्वारा किया गया था।

5.6.2 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में निर्धारित उद्देश्यों के अनुसरण में वर्ष 1987-88 में एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया गया जिसके अंतर्गत पूरे देश के 13,000 उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को शामिल किया गया। तथापि, निधियों की कमी के कारण तथा अन्य प्रशासनिक कारणों से 13,000 स्कूलों को शामिल किए जाने का प्रस्ताव पूरा नहीं किया जा सका। परियोजना में आगे विस्तार के लिए इसकी समीक्षा की जा रही है।

5.6.3 स्कूलों में संगणक साक्षरता और अध्ययन (कलास) परियोजना के अंतर्गत उपलब्धता निम्न तालिका में दर्शाई गई है:—

तालिका 5.5

कलास परियोजना: उपलब्धता

	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	कुल
					(31.3.92 तक प्रवर्धित)	
छात्रों की गई राशि (करोड़ रु. में)	5.39	5.98	6.00	5.86	6.00	29.23
सहायता प्राप्त राज्यों की संख्या (संख्या)	31	31	32	—	—	32
शामिल किए गए स्कूलों की संख्या (संख्या)	1949	2327	2598	—	—	2598

राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना:

(स्कूल तथा अनौपचारिक शिक्षा)

5.7.1 राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना को अप्रैल, 1980 में औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली में जनसंख्या शिक्षा के संस्थापकत्व करने के मुख्य उद्देश्य से प्रारम्भ की गई थी। इस कार्यक्रम के क्रियाकलापों को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष तथा यूनेस्को के साथ स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग के साथ विकसित किया गया था। रांशै-अनु-प्र-परिषद् इसे तकनीकी सहायता प्रदान करती है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसे आठवीं पंचवर्षीय योजना में राज-राशि परियोजना को बढ़ाने का निर्णय किया है। जनसंख्या शिक्षा का लक्ष्य युवा

छात्रों को जनसंख्या, विकास तथा जीवन की कोटि के बीच अन्तःसम्बन्ध की जानकारी देना है। इसके अतिरिक्त यह उनमें जनसंख्या संबंधी मुद्दों के प्रति तर्कसंगत प्रतिक्रिया तथा जिम्मेदार व्यवहार विकसित करने तथा उनमें स्वस्वप्राप्तक मूल्यों के प्रति उत्साह बढ़ाने का प्रयास करती है ताकि वे स्वयं अच्छे निर्णय ले सकें तथा जो बाद में छोटा परिवार पद्धति को बढ़ावा देंगी। यह योजना इस समय उन्नत राज्यों तथा संघ शासित प्रशासनों में कार्यान्वित की जा रही है।

5.7.2 वर्ष 1991-92 के दौरान निम्नलिखित क्षेत्रों में मुख्य क्रियाकलाप थे:—

— प्रशिक्षण, शैक्षणिक तथा अनुसूचक सामग्री तैयार करना

— शिक्षक-शिक्षकों की आवश्यकता तथा राज्य जनसंख्या शिक्षा सेंटों में नए रूप से नियुक्त किए गए परियोजना कार्मिकों को सख्त प्रशिक्षण प्रदान करना।

— परियोजना के प्रभावी रूप से कार्यान्वयन के लिए राज्य शैक्षिक अधिकारियों जैसे स्कूल बोर्ड, पाठ्य पुस्तक बोर्डों तथा शैक्षणिक संगठनों के साथ बैठकें आयोजित करना।

— समुदाय तथा गैर-सरकारी संगठनों की सक्रिय सहभागिता के साथ-साथ सह-पाठ्यचर्या क्रियाकलाप आयोजित करना।

— जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रमों का प्रभाव तथा स्कूल शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर छात्रों तथा शिक्षकों से जागृत तथा प्रतिक्रिया क्रियाकलापों का पता लगाने के लिए मूल्यांकन तथा अनुसंधान क्रियाकलाप करना।

5.7.3 वर्ष के दौरान किए गए क्रियाकलाप निम्नलिखित थे -

— विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या शिक्षा में महत्वपूर्ण विकास के लिए सामग्री जैसे कि पाठ्यचर्या सामग्री, प्रशिक्षण तथा शैक्षणिक सामग्री, मूल्यांकन, अनुसंधान, सह-पाठ्यचर्या क्रियाकलाप, विजली माध्यम तैयार किया गया।

— चित्र कथाओं का विकास किया गया तथा उन्हें छात्रा गया। फिर उन्हें कक्षाओं में देखा गया तथा उस पर छात्रों की प्रतिक्रिया ली गई और उसका विश्लेषण किया गया। इन पोस्टरों और चित्र कथाओं के रूप में तैयार की गई सामग्री को फिर ग्रैनेको के क्षेत्रीय कार्यलय बैंकाक में और आग्रे समीक्षा तथा इसे अपनाए जाने के लिए भेजा गया।

— जनसंख्या वृद्धि तथा पर्यावरण में दो नीडियो कार्यक्रमों के मांदिशी सिद्धांतों को दर्शाने वाले इन नीडियो कार्यक्रमों के मैनुअल भी तैयार किए गए।

— राज्य जनसंख्या शिक्षा सेंटों से 25 परियोजना कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया तथा लगभग 400 शिक्षकों, तथा प्रिंसिपलों को चार क्षेत्रीय कालों द्वारा प्रशिक्षित किया गया।

— राज्य जनसंख्या शिक्षा सेंटों तथा कुछ क्षेत्रीय शिक्षा केन्द्रों द्वारा पूरे देश में जनसंख्या शिक्षा सप्ताह मनाया गया। जनसंख्या शिक्षा सप्ताह को 17 जुलाई, 1991 को विश्व जनसंख्या दिवस समारोह के साथ मनाया गया।

— जनसंख्या शिक्षा पर झोत पुस्तक मुद्रित की गई तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा राज्य जनसंख्या शिक्षा सेंटों की भेंटों गई। खोल पुस्तक की प्रतियों को ग्रैनेको क्षेत्रीय कार्यलय, यूएनएफ़ो-एनपीएड, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय, मास्कोविच भवन तथा अन्य क्षेत्रीय एजेंसियों को भेजा गया।

— परियोजना क्रियाकलापों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राखी-अग्रिम परिवर्द्ध के संकाय सदस्यों द्वारा विभिन्न राज्यों में जाकर राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रमों का अनुप्रवण किया गया।

5.7.4 रा. जनशिक्षा परियोजना (स्कूल तथा गैर-औपचारिक शिक्षा)

के लिए बजट आवधन वर्ष 1991-92 के लिए योजनागत के अंतर्गत 100 लाख रु. हैं।

विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा

5.8.1 वैश्वानिक रूप से यह शिक्षा हो चुका है कि अल्प विकलांगों की यदि सामान्य स्कूल में सम्यक्ष बच्चों के साथ-साथ पढ़ाया जाए तो वे शैक्षिक तथा मानसिक रूप से और अधिक प्रति कर सकते हैं। विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों/शैक्षणिक संगठनों के लिए स्कूलों में आवश्यक सुविधाएँ भूईया करने के लिए शत प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ख्याय की स्वीकृत मंडे है पुस्तकें तथा रोखन सामग्री का धना. परिवहन धना, वर्दी धना, पढ़ाने वाले का धना (निर्भर) बच्चों के लिए), प्रशिक्षण धना (निचले धारा की विकलांगता वाले विकलांगों के लिए), उपकरण धना तथा छात्रावास शुल्क जहा आवश्यक हो। इसके साथ-साथ योजना में शिक्षकों के वेतन व भोत्साहन, सहायन कर्तों की स्यापना, विकलांग बच्चों का अकालन करना, शिक्षकों के प्रशिक्षण, स्कूलों में वास्तुकला अवरोधों को हटाने, विकलांग बच्चों के लिए विशेष निर्देशात्मक सामग्री के विकास तथा निर्माण, आदि का भी आवधान है। कि-अनु-उा के माध्यम से चुनिन्दा विश्वविद्यालयों/संस्थाओं को विकलांग बच्चों के शिक्षकों के लिए विशेष शिक्षा पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाने के लिए भी सहायता दी जाती है। राखी-अनु-उा तथा चार क्षेत्रीय शिक्षा कालों द्वारा भी प्रशिक्षण सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं।

5.8.2 योजना को सभी आंध्र प्रदेश, बिहार, गोआ, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, दिल्ली तथा अरुणाचल प्रदेश में निम्नोक्त ढीप समूह में कार्यान्वित किया जा रहा है।

5.8.3 विकलांगों के लिए संयोजित शिक्षा को एक प्रतिनिक सहायता प्राप्त योजना है जिसमें यह परिकल्पना की गई है कि सामान्य स्कूलों में विकलांगता सहित बच्चों की शिक्षा के लिए सदस्य-विशिष्ट नीतियों का विकास करे। इस परियोजना को कार्यान्वित करने के साथ-साथ विकलांग बच्चों को प्रदान की जाने वाली विभिन्न सुविधाओं के लिए होने वाले ख्याय को खर्च करने के लिए राज्यों/संघशासित प्रशासनों की सहायता प्रदान की जाती है। इस परियोजना के अंतर्गत हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान तथा तमिलनाडु राज्यों से एक ब्लाक तथा दिल्ली और बड़ीया नगर निगम को भी शामिल किया गया है।

5.8.4 इस योजना के अन्तर्गत इस समय 8000 स्कूलों के लगभग 28,000 बच्चे लाभ प्राप्त कर रहे हैं। सभी संख्या में बच्चे विशेष शिक्षकों तथा अन्य अभ्यास सामग्री के माध्यम से अग्रवर्द्ध लाभ प्राप्त कर रहे हैं। वर्ष 1991-92 के दौरान 4.00 करोड़ रुपये के बजट आवधन में से विभिन्न राज्यों, संघशासित प्रशासनों तथा शैक्षणिक संगठनों को 1.43 करोड़ रु. की वार्षिक राशि प्रदान की गई है। (30-11-91 को)

युद्धों को दौरान संशय बलों के बारे गए या विकलांग अधिकारी और जवानों के बच्चों को शैक्षिक दियायते।

5.9.1: केन्द्र सरकार और अधिकांश राज्यों एवं संघसंघित क्षेत्रों ने वर्ष 1962 में भारत-चीन युद्ध और 1965 एवं 1971 के भारत-पाक युद्धों के दौरान मारे गए या स्थायीरूप से विहाय रहे काफ़ी एक एवं अर्द्ध-सैनिक बलों के जवानों को औद्योगिक शिक्षा देना जारी रखा।

5.9.2 वर्ष 1988 के दौरान ये रियायतें श्री लंका में कार्रवाई के दौरान मारे गए/विकलांग हुए भारतीय शान्तिप्रेमी/अन्तर्-द्वितीय रिजर्व पुलिस बल के बच्चों और सिविलियन क्षेत्र में सेवक ऑपरेशन के दौरान मारे गए/विकलांग हुए संरक्षक बलों के कर्मियों के बच्चों के लिए भी बढ़ा दी गयी।

5.9.3 वर्ष 1991-92 में 1 लाख रुपए के कजट आवधान में से 4 छात्रों ने 57,585.00 रु० की हल रियायती का लाभ उठाया।

योग को प्रोत्साहन:

5.10.1 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शारीरिक स्वास्थ्य को प्रोत्साहन देने के लिए योग की अतिमहित उपस्थिति को समझे हुए देश में शारीरिक शिक्षा के विकास के लिए समूची कार्यक्रम के एक अंग के रूप में योग को प्रोत्साहन देने के लिए एक योजना लागू कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत अजल भारतीय स्तर की योग संस्थाओं को निम्नलिखित पहलुओं को जोड़कर अन्य रखरखाव तथा मौलिक अनुसंधान, शिक्षक प्रशिक्षण जैसे पहलुओं सहित सभी पहलुओं पर, कार्यक्रमों के लिए विकास संबंधी खर्च के लिए, वित्तीय सहायता दी जाती है। योग के निम्नलिखी पहलुओं को प्रोत्साहन देने के लिए स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा योग संस्थाओं को निम्न 3 सहायता दी जा रही है।

5.10.2 इस योजना के अंतर्गत कैम्प/याम शीमान माघन योग महिर समिति, लोनावला (पुणे) को रखरखाव तथा अनुसंधान और शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर विकास संबंधी खर्च के लिए सहायता दिया जाता जारी है। वर्ष 1991-92 के दौरान के एस एस आई एम समिति को 10 लाख रुपये का योगांगत तथा 15.00 लाख रुपये का योगनेतर अनुदान प्रदान किया गया (30.11.1991 की स्थिति के अनुसार)।

5.10.3 वर्ष 1981-82 में एक वर्ष के लिए केन्द्रीय विद्यालयों में योग को प्रयोग के तौर पर एक अलग विषय के रूप में शुरू किया गया था। उसी समय से इस प्रयोग का प्रयोग-विद्यालयों के और केन्द्रीय विद्यालय संगठन में योग को अपने शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के साथ जोड़ने का निर्णय लिया है। एनबीईई, 1986 के प्रकाश में एक योग को बृहत् पैमाने पर शुरू की शुरू करने का प्रस्ताव है। तदनुसार वर्ष 1989-90 से एक नई केन्द्र भारतीय योजना शुरू की गई की जिसके अंतर्गत योग संस्थाओं को योग शिक्षकों को प्रशिक्षण देने तथा इस उद्देश्य के लिए आवश्यक सुविधाएं तैयार करने की लिए सहायता दी जाती है। वर्ष 1989-90 में इस योजना के कार्यान्वयन का आर्थिक वर्ष होने के कारण इससे राज्य सरकारों द्वारा अपने अध्यापकों को प्रशिक्षण हेतु न भेजे जाने के कारण इस योजना को बहुत प्रोत्साहन नहीं मिल पाया। यह भी अनुभव किया गया कि इस कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए इससे राज्य सरकारों का भी समर्थन किया जाना अनिवार्य है। इसलिए वर्ष 1990-91 के दौरान योजना आयोग ने परामर्श करते यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकारों को उनके निम्नमाधन अथवा सैद्धांतिक योग संस्थाओं को अपने अध्यापकों के प्रशिक्षण का भव्य करने के लिए अनुदान राशि दे दी जाए। इसका परिणाम यह निकला कि राज्य सरकारों ने इस योजना में उत्साह प्रदर्शित किया है।

5.10.4 वर्ष 1991-92 के दौरान 80.00 लाख रुपयों योजना आवधान में से 18.51 लाख रुपये की अनुदान राशि उत्तर प्रदेश और पंजाब राज्य को जारी कर दी गई है। (30.11.1991 की स्थिति)

संस्कृति/कला/शिक्षा के मूल्यों के सुदृढीकरण के लिए एरोसियों को सहायता तथा नवाचार कार्यक्रमों को कार्यान्वयन करने वाली औद्योगिक संस्थाओं को सहायता

5.11.1 भारत सरकार द्वारा यह परिकल्पना की गई है कि भारत को सांस्कृतिक विरासत को और समृद्ध बनाना जाना चाहिए और कला, शिक्षा, आदि जैसे धुनात्मक कार्यक्रमों पर जोर दिया जाना चाहिए। इन व्यापक उद्देश्यों के अंतर्गत, संस्कृति/कला/शिक्षा के मूल्यों को समृद्ध बनाने के लिए एरोसियों की सहायता तथा नवाचार कार्यक्रमों की ताकि सरकारों (राज्यों, शैक्षिक संस्थाओं, पंचायती राज संस्थाओं, पंचायत समितियों, सार्वजनिक नगरों, और गैर-लाभकारी कंपनियों की सहायता की जा सके। इस योजना के अंतर्गत, निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए, सहायता प्रदान की जाती है:—

(क) औद्योगिक विषय-वस्तु एवं प्रक्रिया में सांस्कृतिक/कलात्मक निवेश को समृद्ध बनाना।

(ख) स्कूल प्रभावी में मूल्य-शिक्षा व सुदृढीकरण, और

(ग) स्कूल स्तर पर मुख्य नवाचारी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन।

5.11.2 उपर्युक्त योजना के अंतर्गत, वर्ष 1990-91 के दौरान, आठ सहायता को 31.61 लाख रु० की सीमा तक वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। चारों वर्ष 1991-92 के दौरान, 60 लाख रुपए का कजट आवधान है। 60.00 लाख के समूची आवधान को मार्च, 1992 के पहले उपयोग कर लिए जाने की संभावना है।

5.11.3 इस योजना के अंतर्गत वर्ष 1991-92 के दौरान, जिन कार्यक्रमों को सहायता प्रदान की गई, में निम्न प्रकार है:—

1. गवर्नर महोदयताएं, नई दिल्ली दिल्ली में 3-4 सप्ताह के लिए आर्थिक स्कूने के मेमबेकालीन शिक्षकों के प्रशिक्षण के आयोजन के लिए
2. भारतीय केन्द्रीय सांस्कृतिक 10 राज्य/राज्य समितियों को आमंत्रित करने के लिए 100 स्कूलों में 100 आवधान निम्नलिखित कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए आवंटित करने।
3. निम्नलिखित कार्यक्रमों को सहायता के लिए निम्नलिखित कार्यक्रमों को सहायता के लिए आवंटित करने।
4. अनुसंधान और अन्य सांस्कृतिक एवं शैक्षिक शिक्षा पर निम्नलिखित शिक्षा संस्थाएं, शैक्षणिक परामर्शों का आयोजन करना।
5. सरकार शिक्षा सचिव, योजनात्मक प्रयोग के दौरान व योजनाएं सरकारों के लिए आर्थिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए आवंटित करने।
6. उत्तराखण्ड राज्य राज्य शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए आवंटित करने।

उपरोक्त उद्देश्यों, स्कूली एक काल या दो कालों के निर्माण से संरचनात्मक के (ए स्तर आयु) सांस्कृतिक तथा सामुदायिक संस्थाएं, राष्ट्रीय स्तर पर आम के विपुल योजनाएं, आदि के संदेश को फैलाने के लिए सांस्कृतिक नितिविधियों को बढ़ावा देना।

ली गई है। कंप्यूटर एप्लक के लिए उपकरणों की खरीद कर ली गई है और गैर-नीय अभियंताओं को सुरक्षित रखने के लिए एक स्टॉग रूम बनाया गया है।

5.15.10 वर्ष 1991-92 के दौरान 100.00 लाख रूपए की एक योजना का आवधान है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद:

5.16.1 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (राष्ट्रीय-अनु-और प्र-पं) की स्थापना 1 सितंबर, 1961 को एक स्थायक संगठन के रूप में की गई थी। स्कूली शिक्षा और शिक्षा के प्रशासनिक सुधार तथा उपलब्धता लाना इसके मुख्य अंश हैं। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एं. जी. अनु-और प्र-पं अपने सचिव-निर्वाहियों को आर्ग-ई-टी-ओ शिक्षा क्षेत्रीय कार्यालय अजमेर, भोपाल, मुम्बई और मैसूर तथा पूरे देश में प्रायः राज्य की राजधानियों में इसके समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों के जरिए अनुसंधान, विकास, प्रशिक्षण, विचार और शैक्षिक योजना के प्रचार-प्रसार से संबंधित कार्यक्रम आयोजित करती है।

5.16.2 वर्ष 1991-92 के दौरान स्कूली शिक्षा और शिक्षा विकास से संबंधित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए जिसमें राज्य की संकुल सहाय के लिए केन्द्रीय प्रोजेक्ट योजनाओं का कार्यान्वयन भी शामिल है लगातार और ठोस प्रयास किए गए।

5.16.3 राश्री-अनु-और प्र-पं परिषद ने शिक्षा क्षेत्र, एलसीईपी में यूनिसेफ से सहायता प्राप्त परियोजनाओं से संबंधित कार्यक्रमों का समन्वय और अनुवीक्षण करना भी जारी रखा है।

क्षेत्रीय कार्यालयों और शिक्षा क्षेत्रीय कार्यालयों के नेटवर्क के जरिए राज्य और सचय शामिल क्षेत्र सरकारों से निकट संपर्क बनाए रखा गया और राज्यों तथा सचय शामिल क्षेत्रों के शिक्षा विभागों/निदेशालयों, राज्य शिक्षा संस्थानों/राज्य स्तर-अनु-और प्र-पं परिषदों तथा देशों की अन्य एजेंसियों द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में सक्रिय सहयोग प्रदान किया गया।

5.16.4 वर्ष 1991-92 के दौरान राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा विभिन्न उपलब्धियों नीचे दी गई है—

शिशु देखभाल और शिक्षा

5.16.5 राश्री-अनु-और प्र-पं देश में शिशु देखभाल और शिक्षा कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रमों संबंधित किए हैं। शिशु देखभाल के प्रमुख कार्यक्रमों में मुख्यतः शिक्षा, शिक्षा-शास्त्रियों के लिए सामग्री विकास, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए शिक्षण संस्थानों के लिए प्रशिक्षण और लैबोरेटरी द्वारा चलाए जा रहे शिशु देखभाल केंद्रों के कार्यक्रमों, दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में पूर्व-स्कूली शिक्षा कार्यक्रम के प्रभाव से संबंधित अनुसंधान अध्ययनों, सड़का संकल्पना के विकास के लिए कार्यक्रम पर आधारित अभियान, नेत्र बधित बच्चों के साथ प्रत्यक्ष कार्यक्रम बनाने और खिलौने बनाने की प्रतिस्पर्धाओं पर केन्द्रित थे।

5.16.6 यूनिसेफ से सहायता प्राप्त शिशु देखभाल और शिक्षा परियोजना में नया मास्टर प्लान (अपवादन) अपनाया। इसके अन्तर्गत क्याग लैने वाले 12 राज्यों के लिए राज्य कार्ययोजनाओं को अन्तिम रूप

शिक्षा के माध्यम से होने वाली सामाजिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूल की परीक्षाओं और सेतु (वैयारी परक) पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रमों को प्रदान कर रहा है। खुला विद्यालय के स्तर की अधिक भारतीय स्तर पर प्रतिष्ठित करने के उद्देश्य से इसे केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से अलग करके एक स्वतन्त्र अस्तित्व वाले स्थायक अस्तित्व वाले स्थायक संगठन अर्थात् राष्ट्रीय खुला विद्यालय सेवायुक्ति (रा-खुला-वि-संग-वि) के रूप में निगम 23 नवंबर 1989 में पंजीकृत किया गया। वर्ष 1990 के पश्चात्, इसे अपने शिशुओं की माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक परीक्षाओं के संचालन और उनके प्रमाण पत्र देने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस अधिकार के अन्तर्गत राष्ट्रीय खुला विद्यालय अब एक तीन-तरीक माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक परीक्षाएं आयोजित कर चुका है जिले भारतीय विधिविद्यालय सच ने भाग्यता प्रदान कर दी है।

5.15.2 राष्ट्रीय खुला विद्यालय, समूचे भारत में कार्यरत अधिकृत संस्थाओं की सहायता से दूरस्थ शिक्षण प्रणाली के जरिए शिक्षा प्रदान करता है।

वर्ष 1991 में इन अधिकृत संस्थाओं की संख्या 143 थी किन्तु अब इनकी संख्या बढ़कर 192 हो गई है। वर्ष 1992-93 के दौरान 200 अधिकृत संस्थाओं से भी अधिक लाखों लाभित किया गया है।

5.15.3 वर्ष 1991-1992 में 60,000 माध्यमिक के लिए (36,000 और उच्चतर माध्यमिक के लिए 24,000) का लाख रखा गया था किन्तु छात्रों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए 36,000 नामांकन किए गए। अधिकृत संस्थाओं की गति की मद्देनजर रखते हुए वर्ष 1992-93 में 40,000 नामांकन का लक्ष्य रखा गया है।

5.15.4 वर्ष 1991 में 76,158 छात्रों की परीक्षा ली गई थी जिनमें परिणाम भोवित कर दिये गये। राष्ट्रीय खुला विद्यालय द्वारा इन छात्रों को प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए। इस संभव में स्वयं राष्ट्रीय खुला विद्यालय द्वारा ही संपूर्ण कार्यक्रमों पूरे कर लिए गए जिन्हें केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा अब पूरा किया जाता रहा है।

5.15.5 वर्ष 1991-92 में, आन्तरिक मूल्यांकन प्रणाली शुरू की गई थी। राष्ट्रीय खुला विद्यालय में ही 34,016 छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं को कंप्यूटरी के माध्यम से न किया गया। राष्ट्रीय खुला विद्यालय द्वारा ही छात्रों की उनके परीक्षा परिणाम गणन दिए गए। राष्ट्रीय खुला विद्यालय की कंप्यूटर यूनिट की अधिकृत मार्कि रीडर और पी-सी एं-टी-ओ उपलब्ध कराये और सुदृढ़ किया गया।

5.15.6 खुला विद्यालय द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान करने के मामले एक व्यावसायिक एप्लक की स्थापना की गई, और सार व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पहचान की गई।

5.15.7 दो गैर-परंपरागत पाठ्यक्रम विकसित किए गए जिसमें पहला स्वास्थ्य शिक्षा तथा दूसरा महिलाओं की स्थिति से सम्बंधित था।

5.15.8 छात्रों को पठन पाठन सामग्री के रूप में 26 लाख पुस्तिकाओं को मुद्रित व वितरित किया गया।

5.15.9 राष्ट्रीय खुला विद्यालय के लिए नवीन ओपेला औद्योगिक विकास मंत्रालय (नोएडा) से एक एकड भूमि खरीदी गई। इस प्लॉट से सटे हुए एक एकड से अधिक की भूमि की खरीद का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है। राष्ट्रीय खुला विद्यालय पर एक फिल्म तैयार कर

दिया गया और इन राज्यों के प्रमुख कार्याधिकारियों के लिए एक महीने का गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया गया।

5.16.7 शिशु देखभाल और शिक्षा में आगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण पर एक प्रशिक्षण फिल्म (स्थिर दृश्य फिल्म) विकसित की गई। तीन प्रकाशन अर्थात् (I) शिशु देखभाल और शिक्षा कार्यक्रम (II) छोटे बच्चों और (III) अलग-अलग बच्चों के लिए प्रोत्साहन कार्यक्रमों नामक प्रकाशन निकाले गए।

प्रारंभिक शिक्षा को सर्व सुलभ बनाना

5.16.8 व्यावहारिक शिक्षकों, अडमान और निकोबार दीप समूह में कक्षा III के लिए सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक तैयार करने, आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के तहत अडमान और निकोबार दीप समूह तथा दादरा व नगर हवेली में शिक्षक अनुस्थापन कार्यक्रम के सदर्भ में माधन सप्तर व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने, आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के तहत प्राइमरी स्कूलों को सप्लाई की गई सामग्रियों की उपयोगिता के विचार पर अनुसंधान अध्ययन एकल/द्वि शिक्षक स्कूलों में शिक्षकों की ममत्ताओं का पता लगाने संबंधी अध्ययन, प्राथमिक शिक्षा अधिनियमों और उनके अनुप्रयोगों का अध्ययन और प्राइमरी स्कूलों बच्चों के अध्ययन शब्द भण्डार (हिन्दी) के कोटिकरण से प्राप्त पुनर्निर्माण के परिप्रेक्ष्य में शिक्षाप्रद सामग्री के संशोधन से संबंधित कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया गया है।

5.16.9 यूनिसैफ से सहायता प्राप्त विभिन्न परियोजनाओं के तहत भी कार्यक्रमों जारी रहे। पोषण स्वास्थ्य शिक्षा और पर्यावरण मफाई (एन-एच-ई-डी-एफ) परियोजना से संबंधित रिपोर्ट तैयार की गई। प्राइमरी शिक्षा के लिए व्यापक पहुँच (सी-एच-पी-ई) पर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। छह राज्यों के चुनिन्दा ब्लॉकों में क्षेत्र-गहन शिक्षा परियोजना (ए.आई-ई-पी) पर विभिन्न कार्यक्रमों जारी रहे।

5.16.10 प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए अनौपचारिक शिक्षा को एक विशेष कार्यनीति के रूप में लिया गया। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में भाग लेने वाले बच्चों के लिए प्रारंभिक स्तर पर अध्ययन-शिक्षण सामग्री के विकास के वास्ते कदम उठाए गए हैं। एम-एल-एल पर आधारित शिक्षाप्रद सामग्री के संकेतों को बढाने का कार्य प्रारंभ पर है। वर्ष के दौरान चलाई गई अन्य अनौपचारिक शिक्षा परियोजना का सम्बन्ध पर्यावरण अध्ययन में अनौपचारिक शिक्षा के अध्ययन शिक्षण कार्यक्रमों के विकास में सामग्री उत्पादन पर पाठ्यक्रम मागों के अध्ययन तथा अनौपचारिक शिक्षा के लिए प्रभावी प्रथाओं और शिक्षण पद्धतियों पर शिक्षक पुस्तिकाओं की पहचान से था। परिषद ने शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए प्रत्येक 10 राज्यों (अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर) में संसाधन व्यक्तियों का सैट तैयार किया और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए विकसित की गई विविध कार्यनीति के अनुसार उन्हें प्रशिक्षित किया गया। बच्चों की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के वास्ते उपकरणों के साथ-साथ शिक्षक पुस्तिकाओं को विकसित किया जा रहा है। अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों को चलाने के लिए कई गैर-सरकारी संगठनों और विभिन्न राज्यों को मुख्यतः सामग्री विकास और प्रशिक्षण के लिए परामर्श सुविधाएं प्रदान की गईं।

शिक्षा का न्यूनतम स्तर (एच एल एल)

5.16.11 मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित समिति द्वारा

प्राथमिक स्तर की न्यूनतम शिक्षा स्तर के संबंध में की गई सिफारिशों की रिपोर्ट में सम्मिलित सिफारिशों जनवरी, 1991 से राशै-अनुप-परि- द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। वर्ष के दौरान मुख्य कार्यक्रमों रहे हैं न्यूनतम शिक्षा स्तर रिपोर्ट का हिन्दी में अनुवाद और मुद्रण, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार में कार्यान्वयन के लिए ब्लॉकों का चयन, ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम के कार्यान्वयन को सुकर बनाने के लिए एक मुख्य ग्रुप निर्धारित करना, विद्यमान औपचारिक स्कूल/राशै-अनुप-पाठ्य-पुस्तकों का विश्लेषण, शिक्षकों/राशै-अनुप-निर्देशकों के लिए दस्ती किताबों जैसी प्रशिक्षण सामग्री का विकास और हिन्दी, गणित तथा पर्यावरणीय अध्ययन में आईटम पुस्तकों का तैयार करना।

स्कूल स्तर पर शिक्षा की विषय-वस्तु तथा प्रक्रिया का अनुस्थापन

5.16.12 इस कार्यक्रम के अन्तर्गत दूसरी और तीसरी पाषा की पाठ्य-पुस्तकों के तैयार करने, राष्ट्रीय एकीकरण की दृष्टि से सामाजिक विज्ञान और भाषाओं की पाठ्य-पुस्तकों का मूल्यांकन करने, सामाजिक विज्ञान शब्दवली और तकनीकी शब्दों को तैयार करने तथा नैतिक/उपयोगी शिक्षा का ढांचा तैयार करने, पूरक पुस्तकों का विकास करने, शिक्षकों के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास संबंधी संसाधन पुस्तक का विकास और सामाजिक विज्ञान प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षण पैकेज का विकास करने पर अधिक बल दिया गया।

5.16.13 दूसरी और तीसरी पाषा के रूप में हिन्दी और उर्दू में कक्षा VIII के लिए पाठ्य-पुस्तकों को अंतिम रूप दिया गया। इतिहास की संसाधन पुस्तकों, दस्ती पुस्तकों को तैयार करने तथा शिक्षण उपकरणों के रूप में चार्ट और नक्शों को तैयार करने का काम भी शुरू किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा योजना की धोषणा के बाद विकसित नई पाठ्य-पुस्तकों के उपयोग के सम्बन्ध में प्रमुख व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण/अनुस्थापन कार्यक्रम आयोजित किए गए।

स्कूल में विज्ञान शिक्षा का सुधार

5.16.14 स्कूल स्तर पर विज्ञान और गणित की शैक्षिक सामग्री को दोहराना, शिक्षकों का प्रशिक्षण तथा विज्ञान और गणित शिक्षा में सुधार लाने के लिए निर्देशित कार्यक्रमों का विस्तार जारी रहा।

5.16.15 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण को सुदृढ़ करने के लिए राशै-अनुप-परि ने विज्ञान किटों को विकसित करना जारी रखा और मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में विज्ञान कार्यशालाओं के आयोजन में उनके तकनीकी स्टाफ को प्रशिक्षित करके और मशीनों के स्थापन में सहायता करके राज्यों को अपनी विशेषज्ञता का लाभ पहुंचाया। राज्यों और संस्थागत क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विज्ञान किटों का बैंच निर्माण शुरू किया गया। कक्षा V से VIII तक पर्यावरण संबंधी अध्ययन (विज्ञान) की शिक्षक दस्ती पुस्तक की संशोधित पांडुलिपि को अंतिम रूप दिया गया। प्राथमिक स्कूल विज्ञान के लिए कम लागत के उपकरणों के विकास संबंधी परियोजना को योजना तैयार की जा रही है।

5.16.16 बच्चों में वैज्ञानिक प्रतिभा का संवर्धन करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए 7 से 15 नवम्बर, 1991 तक बच्चों के लिए जवाहरलाल नेहरू प्रदर्शनी आयोजित की गई।

स्कूलों (कक्षा) में कम्प्यूटर साक्षरता और अध्ययन

5.16.17 राशै-अनुप-परि ने कक्षा परियोजना के लिए केन्द्रीय

तन्वीकी और अनुसूचना धर्मेशी के रूप में काम करना जारी रहा। तीन-तीन सप्ताह की अवधि के शिक्षक प्रशिक्षण के दो कार्यक्रम आयोजित किए गए। पीपीज के लिए छात्रों तथा शिक्षकों के लिए शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यपथ विकसित की गई। अन्य संस्थान केन्द्रों के विभागों के लिए भी अनुसूचना कार्यक्रम आयोजित किए गए।

5.16.18 स्त्रियों की लैमिनेटिक सोर्टें और भाषा-देख रेकन के मूलभूत संघी कार्यक्रमालय जारी रहेगे। कीबी-सी के लिए चार सप्ताह के पुस्तकालय पाठ्यक्रम हेतु शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यपथ भी जारी कर के दौरान विकसित की जायी।

शिक्षा का व्यावसायिकरण

5.16.19 उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के व्यावसायिकरण के कार्यक्रम के कार्यालय संबंधी कार्यवाह्य जारी रहे जिन्हें व्यावसायिक शिक्षकों के लिए सेवागमनी कार्यक्रमों के समन्वयकों के लिए अनुसूचना विभाग में शिक्षा के व्यावसायिकरण संबंधी प्रमुख कार्यकर्ताओं के लिए कार्यक्रम और अधिक अनुसूच खाले शिक्षकों के लिए कार्यक्रम केन्द्रों में शिक्षा के व्यावसायिकरण कार्यक्रम के कार्यालयन का सौके पर निरीक्षण तथा +2 स्तर पर शिक्षा के व्यावसायिकरण के प्रभावी कार्यालयन के लिए अनेक व्यावसायिक के पाठ्यक्रम का विकास/संशोधन शामिल है। टेक्नालॉज डिजाईन पर एक मोडिटी मैकेट और इलेक्ट्रॉनिक्स पर एक नियमावली का विकास किया गया है। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों पर लार्सैन पोपुलराइजेशन फोल्डर प्रकाशित किए गए।

5.16.20 कर्मिक और म्हापट्ट में पहले आयोजित शिक्षा के व्यावसायिकरण के कार्यक्रम का सौके पर निरीक्षण की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा चुका है। वर्ष 1991-92 के लिए निजीगत व्यावसायिक शिक्षा संबंधी अनेक कार्यक्रम और कार्यक्रम संबंधी कार्य जारी है। शिक्षक शिक्षा

5.16.21 पञ्जी-अनुसूचपहि ने राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनशिशिएन परि) के सचिवालय के रूप में कार्य करना जारी रखा। भारत शिक्षा के विद्य-कोश के निर्माण का कार्य जारी रहा। आर्थिक और माध्यमिक स्तर के लिए शिक्षा पाठ्यपथों के निर्माण सम्बन्धों में बिना-निर्देशों और पाठ्यपथों पर आधारित विभिन्न पाठ्यपथों क्षेत्रों में छात्र शिक्षकों के लिए शैक्षणिक सामग्री का विकास किया जा रहा है। 'आर्थिक शिक्षक शिक्षकों के लिए बाहु-सटीम शिक्षण संबंधी सेवागमनी रेकन का विकास' परियोजना के अन्तर्गत मानक तैयार किए गए हैं और माध्यमिक तथा सीनियर माध्यमिक स्कूल शिक्षकों के लिए सेवागमनी शिक्षा के पाठ्यक्रम की कपोरछाप और दिया शिक्षकों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। शिक्षा की कोटि सुधार के लिए शिक्षकों के निर्माण अनुसूचना के लिए दिया निर्देश भी विकसित किए जा रहे हैं।

5.16.22 क्षेत्रीय शिक्षा कोलेज (कोलिज्को) ने मुम्बई तथा मैसूर में चार वर्ष की अवधि के सेवागमनी शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम जारी रखे जो कीबी, कीएएसी, अथवा कीएएसी, कीएएसी, कीएएसी का भी एक वर्ष का नौएससी कोलेज पाठ्यक्रम भी प्रदान करते हैं।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की शिक्षा

5.16.23 विद्यमान शिक्षक-शिक्षा सामग्री का अनुसूचित जाति के बच्चों की दृष्टि से विरलेषण किया गया। अनुसूचित जाति के बच्चों की शिक्षा में

बाधा डालने वाली समस्याओं को सुलझने के लिए रा-ओ-शिफ के प्रमुख कार्यकर्ता के लिए एक निष्पक्षशी तैयार करने का कार्य जारी रहा। गौरी और इर-रा में अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए पाठ्यपथों के विकास के लिए कदम उठाए गए।

शैक्षणिक स्तर से निम्न अल्पसंख्यकों की शिक्षा

5.16.24 शैक्षणिक रूप से निम्न अल्पसंख्यकों द्वारा अर्जित स्त्रियों के शिक्षणों में अनुसूचित जनजात के लिए रा-ओ-अनुसूचपहि ने शैक्षणिक निवेश प्रदान करना जारी रखा।

महिला सभ्यता के लिए शिक्षा

5.16.25 1991-92 के दौरान रा-ओ-अनुसूचपहि ने (i) आर्थिक शिक्षा से लक्षितों की पक्षाई जारी रखी और लक्षितों पक्षाई करने के तथ्यों का अध्ययन (ii) लक्षितों के शिक्षकों की पीपिटी और निम्नलिखित की समन्वय और (iii) भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षितों की शिक्षा के सुलभकरण के संबंध में पुनर्लेख द्वारा आयोजित अध्ययन की परियोजनाओं पर कार्य करना जारी रखा। महिला शिक्षा प्रभावी और विकास के प्रमुख कार्यकर्ता के लिए एक साल सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। लिंग अनुपात के घटते तथा शिक्षा और सेवा साधन पर इसके प्रभाव पर भी एक सेमिनार आयोजित की गई। हिन्दी में ए-ओ-एल-मैट्रिकल भारतीय सचिव में महिलाओं की छवि को भ्रष्टान करने वाले 14-18 आयु वर्ग के लिए भारतीय डी.डी. मैट्रिकल के विकास तथा आर्थिक और भाषा-क स्तर के लिए प्रमुख अध्ययन सामग्री तैयार करने जिसमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी, ललित कला, उद्योग, कृषि, वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्रों में महिलाओं के योगदान को उजागर करना जारी रखा। और समन्वय/लेक्चर सत्रों की सहायता से लक्षितों के बीच आर्थिक शिक्षा के सर्व सुलभकरण को सुझावा देने के लिए व्यावहारिक नीति तैयार करने संबंधी कार्यवाहा की रिपोर्ट को प्रसार के लिए अंतिम रूप दिए जा रहे हैं। 'भारत में ए-ओ-एल की व्यावसायिक तन्वीकी और अधिकभवन शिक्षा को शिक्षा करने के उपाय' संबंधी परियोजना की रिपोर्ट भी तैयार की जा चुकी है।

अन्यों की शिक्षा

5.16.26 कार्यक्रमों और कार्यकर्ताओं में, मुख्यतः से, जहाँ से बच्चों की विशेष जानकारी को प्राप्त करने के लिए संगठनात्मक सहायता देकर सामान्य शिक्षकों की समता को बढ़ाकर सामाजिक के लिए पाठ्यपथों और शैक्षणिक सामग्री के विकास, तथा विशेष अल्पसंख्यकों के शिक्षण तथा अनुसूचितों की अधिकतर कदम के विकास, तथा विशेष अल्पसंख्यकों के शिक्षण करने, अल्पसंख्यकों को स्कूल में लाने तथा उन्हें स्कूल से ठीकने तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा भारत सरकार के अन्य समन्वय विभागों की नीति निर्धारण तथा अल्पसंख्यकों की शिक्षा संबंधी योजनाओं के कार्यालयन में सहायता प्रदान करना, अल्पसंख्यकों को सामान्य शिक्षा प्रभावी में समीकित करने के लिए विशेष तरीकों के विकास पर बल दिया गया। अल्पसंख्यकों की शिक्षा से सम्बंधित कार्यक्रमों की योजना बनाने और प्रबंध में राज्य सरकारों को सहायता भी प्रदान की गई।

5.16.27 'मर सुदि के बालकों के अभिभावकों के लिए दूरस्थ स्कूल' परियोजना के अन्तर्गत 4 कार्यक्रम तैयार करके दूरस्थीन द्वारा अर्जित किए गए। 'विद्यमान बच्चों की हिन्दी में शिक्षा देने के लिए संगठन की सहायता से पठन-पाठन कार्यक्रमों का विकास' पर कार्य चल रहा है। नए

शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में विशेष शिक्षा पर एक पाठ मुद्रांक की रूपरेखा तैयार की गई है। राशी-अनुसंधान दृष्टिकोण से सहायता प्राप्त "विकासी" की संज्ञित शिक्षा" परियोजना के अंतर्गत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन पर एक निबन्ध-सूचक (मैनुअल) विकसित कर रही है।"

शैक्षिक प्रौद्योगिकी की उपयोगिता

5.16.28 हिन्दी क्षेत्र में ए-लेट शैक्षिक दूरदर्शन सेवा को आवश्यक सामग्री से युक्त करने के लिए आर्थिक स्तर पर 5-8 और 9-11 आयु वर्ग के बच्चों तथा शिक्षकों के लिए शैक्षिक दूरदर्शन (ई-टी-वी) कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। अक्टूबर, 1991 तक 38 ई-टी-वी कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इसके अतिरिक्त 50 ई-टी-वी कार्यक्रम उदिया और गुजराती में डब किए गए।

5.16.29 हिन्दी में लगभग 500 टी-वी कार्यक्रमों वाले 200 से अधिक कैप्शन तैयार किए गए और इन्वेंट के माध्यम से प्रसारण के लिए दूरदर्शन को भेजे गये। उदिया में भी इन्हीं की संख्या के ई-टी-वी कार्यक्रमों वाले कैप्शन तैयार और प्रसारित किए गए।

5.16.30 नवीदय विद्यालयों की कक्षा VII के लिए हिन्दी में कार्यक्रमों सहित शिक्षणीय मासिक रूप से विकसित। बच्चों के लिए सामान तिरों और कार्यक्रमों के 24 शैक्षिक टेडियो कार्यक्रम पूर्ण किए गए।

5.16.31 कर्मियों के विभिन्न वर्गों के लिए शैक्षिक प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

5.16.32 सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत भारीशाल, चीन और त्रिनीदाद की शैक्षिक दृष्टक-कक्ष कार्यक्रम संपादित किए जा रहे हैं।

शैक्षिक सर्वेक्षण और डेटा प्रोसेसिंग

5.16.33 उत्तर प्रदेश में आर्थिक स्कूल भय-को का एक सचन सर्वेक्षण नमूने आधार पर प्रारम्भ किया गया है। देश में शिक्षक-शिक्षा और इसके संबंध पहलुओं का स्तर निखित करने के लिए आर्थिक और लेने-बे-बे शिक्षा का बहु-अभिल-भारतीय सर्वेक्षण शुरू किया गया है।

पट्टीय अभिषा लीन

5.16.34 कक्षा X कक्षा के अंत में प्रतिभाषान छात्रों का पता लगाने और गुणात्मक शिक्षा पाने के लिए उन्हें वितीय सहायता देने ताकि उनको प्रतिभा और अभिषक विकसित हो सकें और वे अपने-अपने विषय क्षेत्रों के साथ-साथ देश के लिए उपयोगी बन सकें, इसके लिए पट्टीय प्रतिभा खोज स्वयंसेवक डिवाजन को गई है। परीक्षणों के दो स्तरों के आधार पर पट्टीय प्रतिभा खोज स्वीन के सहायक-भूतिया प्रदान करने के लिए 750 छात्र चुने गये।

शैक्षिक भनोचिकन परामर्श और मार्गदर्शन

5.16.35 पट्टीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने शैक्षिक और भावनात्मक मार्गदर्शन से अपना ती यात्रा की अर्द्धि का डिप्लोमा जारी रखा। परामर्श और मार्गदर्शन से संबंधित अनुसंधान (शोध), विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम, बच्चों में स्वभाविक सम्यकव्यवस्था का पता लगाना और मनोविज्ञान, में प्रशिक्षण संबंधी सामग्री का विकास आदि इस क्षेत्र के मुख्य कार्यक्रम हैं।

5.16.36 पट्टीय शैक्षिक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा संस्थापित

"पट्टीय शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक परीक्षण मुद्रांकालय" देश भर के विद्वानों द्वारा प्रस्तुत किया गया।

पट्टीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना

5.16.37 इस कार्यक्रम के अंतर्गत जनसंख्या शिक्षा पर एक पट्टीय स्वतंत्र मुद्रांक, परिपक्वता पर एक वीडियो कार्यक्रम और अनौपचारिक शिक्षा क्षेत्र के लिए निदेशीय सामग्रीयों विकसित की गई। परिषद ने जनसंख्या शिक्षा में एक भ्रमणपर पाठ्यक्रम भी विकसित किया है।

परिक्षा सुधार

5.16.38 वर्ष 1991-92 के दौरान लेने-बे-बे कक्षाओं के लिए विज्ञान में भू-विज्ञान क्षेत्र को तैयार करने के लिए, इकाई परीक्षणों, आर्थिक परीक्षणों और वार्षिक परीक्षणों के विकास हेतु कार्यशालाएं आयोजित की गईं। कक्षा VI से VIII के लिए विज्ञान में मानक प्रमाण परीक्षण और आर्थिक स्तर पर गणित और विज्ञान में लक्षण विषयक परीक्षण तैयार किए जा रहे हैं। निम्नलिखित नमूनों में कक्षा VIII के लिए अंग्रेजी में भौतिक अन्धास का पूर्व परीक्षण किया जा रहा है। "इतिहास में वस्तुनिष्ठ आधारित परीक्षण के मुद्दों" और "समान विज्ञान की परीक्षा में वैज्ञानिक मूल्यों अभिषा" के प्रशिक्षण के लिए दो पट्टीय कार्यशालाएं आयोजित की गईं। निम्नलिखित रूपों में आर्थिक स्कूल के बच्चों की उपलब्धि के आंकड़ों का विश्लेषण प्रगति पर है।

नवीदय विद्यालयों को तकनीकी सहायता

5.16.39 पट्टीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने सचन अभिषा को यथासंभव निष्पक्ष बनाने और माहौल संबंधी कार्यों से होने वाले पक्षपात को कम करने के लिए लिखित प्रश्नों से युक्त अनेक परीक्षाओं (मासिक सामान्य परीक्षा, यात्रा-परीक्षा और अकादमिक परीक्षा) की सहायता से शैक्षिक सत्र 1991-92 के लिए 275 जवाहर नवीदय विद्यालयों में वडिखले के लिए परीक्षार्थी आयोजित की। देश के 275 जिलों में 3200 केंद्रों पर सचन परीक्षाएं आयोजित की गईं।

5.16.40 वर्ष 1992-93 के लिए जवाहर नवीदय विद्यालयों में वडिखले के लिए सचन परीक्षाओं के आयोजन की अभिषा पहले की प्रारम्भ हो चुकी है।

शैक्षिक अनुसंधान संवाद

5.16.41 पट्टीय शैक्षिक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण समिति की शैक्षिक अनुसंधान और नवाचार समिति (ई-आर-आई-सी) ने स्कूल शिक्षा और शिक्षक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान परियोजनाओं का प्रयोजन करना जारी रखा। शैक्षिक अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार के प्रयासों के एक भाग के रूप में ई-आर-आई-सी ने जिला शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थाओं (डी-आई-ई-टी) संकाय के लिए प्रथम स्तर का अनुसंधान कार्य प्रभावी पाठ्यक्रम आयोजित किया। शैक्षिक अनुसंधान में वर्तमान आर्थिकताओं के संबंध में आवश्यक उत्पन्न करने के उद्देश्य से चालू वितीय वर्ष के दौरान पश्चिमी क्षेत्र में शैक्षिक अनुसंधान पर एक क्षेत्रीय सेमिनार आयोजित किया जाना है।

5.16.42 एडवोकेट-ई-आर-टी में शैक्षिक अनुसंधान और नवाचार सर्वेक्षण परियोजना को एक सप्ताह का रूप दिया गया है। शैक्षिक अनुसंधान के पांचवें सर्वेक्षण से 1988 से 1992 की अवधि समितित है और इसमें सभी शोध प्रश्नों, स्वतंत्र अनुसंधानों और शिक्षा तथा इससे जुड़े

क्षेत्रों में देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित नवाचारों के शोध निष्कर्षों को सम्मिलित किया जाएगा।

प्रकाशन तथा प्रसार

5.16.43 अप्रैल से अक्टूबर, 1991 के दौरान विभिन्न श्रेणियों के 141 शीर्षक तैयार किए गए थे। इनमें 78 पाठ्य पुस्तकें, 6 अनुसूक्त रीडर, पत्रिकाओं के 29 अंक तथा 28 अन्य प्रकाशन सम्मिलित हैं। वर्ष के शेष भाग में प्रकाशनों की विभिन्न श्रेणियों के 180 शीर्षक तैयार हो जाने की उम्मीद है।

क्षेत्रीय सेवाएँ

5.16.44 एन-सी-ई-आर-टी ने राज्यों की वास्तविक शैक्षिक आवश्यकताओं के आधार पर तैयार किए गए कार्यक्रमों और क्रियाकलापों पर आधारित देश में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार के लक्ष्यों को प्राप्त करने में लगी एन-सी-ई-आर-टी/एम्-ई-आर-डी/राज्य सरकारों और राज्य शैक्षिक एजेंसियों के बीच सम्पर्क के प्रभावी नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से अपने 17 क्षेत्रीय कार्यालयों की कार्य प्रणाली का पुनर्गठन किया है। संशोधित रूपाल्पकताओं को कार्य प्रणाली की पुनरीक्षा के लिए एन-सी-ई-आर-टी के मुख्यालयों में 29 और 30 अक्टूबर, 1991 को क्षेत्रीय परामर्शदाताओं और शिक्षा के क्षेत्रीय कालों के प्राचार्यों की बैठक आयोजित की गई थी। एन-सी-ई-आर-टी ने क्षेत्र अधिकारियों के साथ साथ राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा और साक्षात्कारों के प्रशासन, जवाहर नवोदय विद्यालयों की चयन परीक्षाओं और राज्य व राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए शिक्षकों के चयन के लिए सहायता बढ़ाई।

बजट प्रावधान

5.16.45 वर्ष 1991-92 के लिए राशौ-अप्रूपण का बजट प्रावधान योजनागत के अंतर्गत 350.00 लाख रुपये और योजनागत के अतर्गत 2220.00 लाख रुपये हैं।

राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान

5.17.1 राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान (एन-एफ-टी-डब्ल्यू) धर्माध्य दान अधिनियम, 1890 के अंतर्गत वर्ष 1962 में गठित किया गया था। प्रतिष्ठान का मुख्य लक्ष्य दशमीय छात्रों में रहने वाले शिक्षकों को वित्तीय सहायता देना है। प्रतिष्ठान को निम्नलिखित जवाबदेही सौंपी गई है:

- समूह तैयार करना।
- प्रो. डी.सी. शर्मा मेमोरियल अवार्ड के लिए प्रत्येक वर्ष तीन शिक्षकों का चयन करना।
- शिक्षक दिवस मनाना।
- संसदीय योजनाओं के अंतर्गत शिक्षकों/अग्रियों को वित्तीय सहायता देना।

5.17.2 संसदीय योजनाएँ जिसके अंतर्गत वित्तीय सहायता दी जाती है नीचे दी गई हैं:

- (i) उत्कृष्ट सेवा देने वाले श्रुविख्यात शिक्षकों को वेतन सहित अवकाश।

(ii) स्कूली शिक्षकों के कर्जों की व्यवसायिक शिक्षा के लिए सहायता।

(iii) गंधीय रोगों के शिकार शिक्षकों के चिकित्सा-खर्च की प्रतिपूर्ति।

(iv) गंधीय दुर्घटनाओं की स्थिति में शिक्षकों को निःशुल्क सहायता।

(v) शिक्षकों के शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए आर्थिक सहायता और

(vi) शिक्षक सदस्यों का निर्माण।

5.17.3 इस वर्ष के दौरान 18,10,478/- रु. की राशि की वित्तीय सहायता नीचे दिए गए स्तरों के अनुसार दी गई है:

क्र. सं.	योजना का नाम	लाभार्थी/राज्य इकाईयों की सं.	वित्तीय सहायता की राशि
1	श्रुविख्यात शिक्षकों को वेतन सहित अवकाश	आज प्रदेश से 2 शिक्षक	3,896/- रु.
2	स्कूली शिक्षकों के कर्जों को व्यवसायिक शिक्षा के लिए सहायता	आज प्रदेश से 50 शिक्षक गोवा में 41 शिक्षक महाराष्ट्र से 56 शिक्षक तमिलनाडु से 42 शिक्षक उत्तर प्रदेश से 3 शिक्षक पंजाब से 4 शिक्षक दिल्ली से 1 शिक्षक दमन से 6 शिक्षक पंडिचेरी से 17 शिक्षक	1,00,000/- रु. 23,925/- रु. 1,01,502/- रु. 33960/- रु. 2562/- रु. 2270/- रु. 555/- रु. 7822/- रु. 19471/- रु.
		220	2,92,067/- रु.
3	गंधीय रोगों से पीड़ित शिक्षकों/अग्रियों के लिए चिकित्सा उपचार	आज प्रदेश से 7 शिक्षक केरल से 3 शिक्षक महाराष्ट्र से 3 शिक्षक उत्तर प्रदेश से 2 शिक्षक	56,843/- रु. 13,982/- रु. 16,090/- रु. 20,000/- रु.
		15	1,06,915/- रु.
4	शिक्षक सदस्यों का निर्माण	(i) उत्तर प्रदेश की राज्य कार्य समिति (ii) केरल की राज्य कार्य समिति	7,50,000/- रु. 5,00,000/- रु.
			12,50,000/- रु.
5.	व्यक्तिगत-सम्पर्क की 40वीं वर्ष गोट और शिक्षक कल्याण के अंतर्गत शैक्षिक प्रयोग (पूर्व वर्ष का)	महाराष्ट्र के 893 शिक्षक	1,57,600/- रु.

कुल: 18,10,478/- रु.

5.17.4: प्रत्येक वर्ष, 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर शिक्षकों के महत्व को बताने के उद्देश्य से

स्त्रा सामग्री के रूप में एक इस्तहार प्रकटित किया जाता है। श्री पी० वि०, आलोकन शिक्षक, जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट हाईस्कूल, महा गंडिबेरी को पोस्टर तैयार करने के लिए 5000/- रु० की राशि का मुगलान किया गया था। शिक्षक दिवस के अवसर पर, प्रतिष्ठान के कार्यकलापों के संबंधित विस्तृत सूचना वाली पुस्तिका का विमोचन, मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा किया गया। पुस्तिका को, व्यापक प्रचार के लिए, सभी राज्य कार्य-समितियों एवं 1990 के राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों के बीच परिचालित कर दिया गया है।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी० बी० एस० ई०):—

18.1' भीजूदा शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने और शिक्षा को सामाजिक रूप से और अधिक प्रासंगिक बनाने का, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का सतत प्रयास रहा है। छात्रों के बहुमुखी विकास के उद्देश्य से, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कई कार्यक्रम शुरू किए जा चुके हैं। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण निम्नलिखित हैं:—

विशेष ग्रीड साक्षरता अभियान (एस०ए०एन०डी०)

18.2' केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शैक्षिक सत्र 1991-92 से हफ्ताओं IX व XI में विशेष ग्रीड साक्षरता अभियान (एस० ए० एन० डी०) शुरू कर दिया है जो कि सन् 1992-93 से IX से XII तक की सभी कक्षाओं के लिए भी बढ़ा दिया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य माध्यमिक एवं सीनियर माध्यमिक स्तर पर छात्रों को जुटाना है। यद्यपि इस कार्यक्रम काय को स्कूलों में शुरू करने को अनिवार्य बना दिया है। तथापि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने छात्रों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सकारात्मक कार्य-व्ययन का एक ढांचा तैयार कर दिया है। ऐसे छात्रों को जो एक वर्ष में एक व्यक्ति को साक्षर बनाते हैं, 5 अंकों से पुरस्कृत किया जाएगा, प्रति वर्ष दो व्यक्तियों को साक्षर बनाने वाले छात्रों को 6 अंकों से और प्रति वर्ष तीन या अधिक व्यक्तियों को साक्षर बनाने वाले छात्रों को 10 अंकों से पुरस्कृत किया जाएगा। अंकों के अतिरिक्त छात्रों, अध्यापकों और स्कूलों के प्रभामा-पत्र, दृष्टिगत तथा पुरस्कार दिए जाएंगे। बोर्ड ने इस संबंध में आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए हैं और वह कार्यक्रम की मॉनिटरिंग के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।

जनसंख्या शिक्षा

18.3' जनसंख्या संबंधी राष्ट्रीय संचालन समिति के निर्देशों के जवाब में, बोर्ड ने एक व्यापक विवरणिका तैयार की है जिसमें शिक्षकों के लिए [से दिशानिर्देश हैं जिससे वे राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के अंग के रूप में लौकिक शिक्षक गतिविधियों को स्कूल कार्यक्रम में शामिल कर सकें।

तीके पर मूल्यांकन की नई प्रणाली

18.4' वर्ष 1983 से दिल्ली और मद्रास क्षेत्रीय कालेजों के माध्यम से मौके पर मूल्यांकन की प्रणाली शुरू की गई है। वर्ष 1991 के दौरान बोर्ड की कार्य प्रक्रिया में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ जिससे फलस्वरूप मौके पर मूल्यांकन का विकेन्द्रीकरण हो गया है। बोर्ड ने, परीक्षार्थियों की संख्या 200 तक होने पर कम से कम एक परीक्षक प्रायोजित करना अनिवार्य बनाकर मौके पर मूल्यांकन को सरल बनाने का निर्णय लिया है।

18.5' बोर्ड 'शॉर्ट स्कूल' खोलेंगे। जिनके चारों ओर मूल्यांकन वार्य के लिए 10 स्कूल होंगे। अपर मुख्य परीक्षा के अधीन पड़ोसी स्कूलों के दस से पन्द्रह परीक्षक होंगे।

18.6' परीक्षाओं में अनुसूचित तहकों के प्रयोग को रोकने के लिए

बोर्ड ने अनेक दीर्घावधि तथा अल्पावधि उपाय किए हैं। अल्पावधि उपायों में बोर्ड ने दिल्ली में वर्ष 1992 की परीक्षाओं से प्रश्न पत्रों के अनेक सैट बनाने का निर्णय लिया है। प्रश्न पत्रों के विभिन्न सैट एक ही कमरे के छात्रों को वितरित किए जायेंगे। यह आशा की जाती है कि इस प्रणाली से नकल करना काफी कठिन हो जाएगा। शिक्षा निदेशालय दिल्ली के परामर्श से उन स्कूलों का पता लगाया जा रहा है जिनमें अनुचित तरीकों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता है। तथा (परीक्षा) केन्द्र निर्धारित करते समय विशेष सतर्कता बरती जाएगी। बोर्ड अनुसूचण करने तथा प्रभावी निरीक्षण सुनिश्चित करने के लिए ऐसे केन्द्रों में विशेष प्रेषक भेजेंगे। बोर्ड ने केन्द्र अधीक्षक को छात्रों की तलाशी लेने के लिए प्राधिकृत करने का भी प्रस्ताव रखा है ताकि परीक्षा हाल में भ्राम्यो के प्रवेश को रोक जा सके।

18.7' दीर्घावधि के उपायों में बोर्ड मानक स्कूल मूल्यांकन पद्धति आजमा रहा है जिसमें छात्रों को श्रेणी क्रम देने का अधिकार स्कूलों को दिया जाएगा तथा छात्रों को अंक देने का अधिकार बोर्ड के पास रहेगा। मुक्त पुस्तक (ओपन बुक) परीक्षा तथा 'प्रश्न एवं उत्तर पुस्तिका' भी प्रयोग के तौर पर अपनाई जा सकती हैं। परीक्षा के विभिन्न आयामों पर अनुसंधान अध्ययन संचालित किए जायेंगे तथा परीक्षा परिणामों का स्कूल वार आवधिक विश्लेषण भी किया जाएगा।

संबन्धन के उद्धार मानक

18.8' इमारत बनाने के लिए पर्याप्त भूमि प्राप्त करने के लिए स्कूलों को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसे ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने स्कूलों को संबन्धन देने की अपनी प्रक्रिया को तीन वर्गों में, ख तथा ग के अंतर्गत संशोधित किया है:

वर्ग क इसमें वे सभी स्कूल शामिल हैं जो उपनिचमों में दी गई संबन्धन की बुनियादी शर्तें पूरी करते हैं।

वर्ग ख: के अंतर्गत स्कूल को संबन्धन देने पर विचार किया जा सकता है-

(क) इसे संबंधित राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र के शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता दी गई हो अथवा बंबाकी प्रमाण पत्र दिया गया हो

(ख) इसके पास संबन्धन उपनिचम के अनुसार पर्याप्त भूमि न हो किंतु इतना क्षेत्र हो जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो-

— मिडिल स्कूल के लिए 250 वर्ग मीटर क्षेत्र + 1 वर्ग मीटर प्रति नामांकित छात्र के लिए।

— माध्यमिक स्कूल के लिए 570 वर्ग मीटर क्षेत्र + 1 मीटर प्रति नामांकित छात्र के लिए।

— उच्चतर माध्यमिक स्कूल के लिए 750 वर्ग मीटर क्षेत्र + 1 वर्ग मीटर प्रति नामांकित छात्र के लिए।

(ग) वेतन राज्य सरकार तथा संघ शासित क्षेत्रों के वेतनमानों के अनुसार हो।

(घ) संबन्धन की अन्य शर्तें पूरी करता हो। ऐसे सभी स्कूलों का एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा निरीक्षण किया जाएगा।

वर्ग ग: इसमें वे स्कूल शामिल हैं जिन्हें संबंधित संघ शासित क्षेत्र के शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता दी गई हो लेकिन जिनके पास संबन्धन उपनिचम

के अनुसार न तो पचीस प्रतिशत से अधिक और न ही वर्ग छह से अधिक शिक्षित क्षेत्र हो।

वेतन राज्य सरकार के वेतनमानों के अनुसार ही तथा संबन्धन की अन्य बातें पूरी करते हैं। यदि ऐसे स्कूल यह सम्मानित कर सकें कि वे प्रथम प्रायः करने के लिए स्वीकृत से प्रकाश कर दें हैं तो कोई अन्य बातों की जांच करने के पश्चात् पूरी तरह से तत्पर संबन्धन के लिए उन पर विचार कर सकता है। तत्पर संबन्धन केवल उनकी स्कूलों को दिया जाएगा जिन्हें राज्य शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता दी गई हो अथवा उस संघ द्वारा शिक्षित क्षेत्र में अपना कोई हो।

प्रधान पत्रों का गठन से विशालेयन

5.18.9 आने वाले वर्षों में मानक निर्धारित करने तथा परीक्षा के लिए एक वैज्ञानिक पद्धति तैयार करने के लिए 1989-90 में विभिन्न विषयों में नमूना प्रधान पत्र तैयार किए गए थे। 1990 में गठित तथा विज्ञान विषयों में तथा वर्ष 1991 से अन्य मुख्य विषयों में यह नमूना पर प्रधान पत्र तैयार किए गए। इसके अनुसार में, कोई से कक्षा XII तथा V स्तर पर प्रमुख विषयों के प्रधान पत्रों का गठन से विशालेयन किया है। स्कूलों में प्रभाउ रहे शिक्षकों, मुख्य परीक्षकों तथा राज्य-एक कुल कार के मूल्यांकन विशेयों से मिल कर बने कार्यकारी दलों ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रधान पत्रों का विशलेयन किया है तथा जहाँ आवश्यक है परिवर्तन सुझाए हैं।

रोजगारीमुख रेलवे व्यापारिक पाठ्यक्रम

5.18.10 शिक्षा को और अधिक रोजगारमुख बनाने की सरकार की नीति के अनुसार में, केम्पारिण कोई ने हाल ही में + स्तर पर एक अन्य रोजगार संबंधी पाठ्यक्रम व्यापक रेलवे प्रायः किया है। पाठ्यक्रम के लिए पाठ्य विवरण तथा पठन पाठन सामग्री रेल विभाग तथा राज्य-एक एज प्रवर्ग के सहयोग से तैयार की गई है। शुरू में, अंतिम पाठ्यक्रम शिक्षा वर्ष 1991-92 से दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता, गोवर्धन के कुछ चुने हुए स्कूलों में प्रायः किया गया है। 1992-93 में पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए नवंबर, कलकत्ता, गीहाटी तथा सिक्किम में एक-एक कुल कार अन्य स्कूलों का पता लगा लिए जाने की सम्भावना है। पाठ्यक्रम के अन्तिम-तन्त्र तथा वदरेय अन्त्यव्यय आयु से छात्रों का चयन करना है ताकि कार्य तथा सेवा की सही भावना मन में बैठाने का सके। इस पाठ्यक्रम की मुख्य विशेषता यह है कि यह संकल छात्रों को एक लाभदायक कार्य क्षेत्र चुनने का अवसर प्रदान करता है। ये छात्र भारतीय रेल विभाग में सीधे व्यापार लिपिक/लिंक कलक्टर के रूप में नियुक्त किए जायेंगे।

नवीन विद्यालय सन्धि

5.19.1 प्रतिभाशाली छात्रों विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को अच्छी आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने श्रीरतल अन्त्येय विद्यालयों से एक नवीन विद्यालय खोलने की योजना लागू की है। देश में अब तक 275 नवीन विद्यालय खोले जा चुके हैं जो 22 राज्यों और 7 संघ क्षेत्रों में फैले हैं। पांच नवीन विद्यालय खोलने की प्रकृति अभी हाल ही में दी गई है।

5.19.2 नवीन विद्यालय में भेजा छात्र कक्षा से दिया जाता है। इस तथ्य की ध्यान में रखते हुए कि इस प्रकार से दक्षिण अफ्रीका छात्रों के पहले माध्यमिक/क्षेत्रीय पाषा में अध्ययन किया होगा, उन्हें कक्षा VI अथवा VIII तक उच्चतम आधार पर से ही शिक्षा प्रदान की जाती है तथा इस दौरान पाषा विषय की सह भाषा के रूप में हिन्दी/अंग्रेजी दोनों में

समय शिक्षण प्रायः किया जाता है। तत्पश्चात्, समान माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी होगा। इस स्तर पर भाषावी क्षेत्र नवीन विद्यालय से दूसरे नवीन विद्यालय में 30% स्थानांतरित किया जाता है। यह स्थानांतरण, हिन्दी भाषी और अहिन्दी भाषी जिलों के बीच होता है। 5.19.3 अब तक 275 नवीन विद्यालयों द्वारा चुने गए छात्रों का वीए इस प्रकार है:-

सकले	लक्ष्मिणी	ग्रामीण	समृद्धि	अनुसूचित	अनुसूचित-अधिकांश	कुल
55927	22222	60528	17621	150900	8405	53844
72%	28%	77%	23%	20%	11%	69%

5.19.4 नवीन विद्यालय सह-शिक्षा वाले की मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए है। इस लिए शारी क्षेत्रों के बच्चों का दक्षिण अधिकतम एक चौथाई तक ही सीमित है।

अन्त्येय नवीन विद्यालय से यह सुनिश्चित करने के भाषा किए जाते हैं कि कम से कम एक निवासी लक्ष्मिणी हो।

5.19.5 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के पक्ष में आरक्षण समितित मिले हैं उनको जनसंख्या के अनुपात में होता है नशाते कि किसी मिले में ऐसा आरक्षण राष्ट्रीय औसत से कम न हो।

निर्माण कार्य कार्यक्रम

5.19.6 280 नवीन विद्यालयों से से 160 विद्यालय स्थायी स्वरूप में स्थानांतरित कर दिए गए हैं। 171 विद्यालयों में निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और 35 विद्यालयों में निर्माण कार्य क्रमशः प्रथम चरण और शून्य चरण में है। द्वितीय चरण में 187 विद्यालयों के अतिरिक्त बचने के लिए वर्ष 1991-92 में 150.45 करोड़ रुपये की राशि की स्वीकृत प्रदान की गई है।

शिक्षण स्तर को प्रोत्साहन:

5.19.7 चूंकि सभी नवीन विद्यालय आवासीय है तथा दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित है अच्छे शिक्षकों/प्रधानाचार्यों को आकर्षित करने के लिए निर्धारित प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं:-

- (i) उस स्थान पर उपलब्ध निर्यात अंशान. सुविधात अभाव।
- (ii) अधिकतम दो बच्चों के लिए प्रति माह 150/- रुपये प्रति वर्ष को दर से बच्चों के लिए शिक्षण घंटा।
- (iii) छात्रों के साथ रह रहे हाउस मास्टर और शिक्षकों को निर्यात अन्त्येय सुविधाएँ।
- (iv) सभी शिक्षकों को निर्यात पम्पाहन भोजन।
- (v) सन्धि के नियमानुसार प्रति/वर्षी को निर्भुक्त के लिए सुविधा।
- (vi) जहाँ शिक्षकों की नेमारी की जाती है वहाँ नवीन विद्यालयों। बच्चों का बिना प्रवेश परीक्षा के दक्षिण। और ऐसे बच्चों व निर्यात छात्रवत्त की सुविधा।
- (vii) प्रतिमाह 100 रुपये का शिक्षण घंटा।

कार्यन्तियों का व्यावसायिक विकास

5.19.8 नवीन विद्यालय सन्धि से इस पद्धति में प्रतिमाह और सक्ष

गुप्त की सुनिश्चित करने के अद्वैत आप में हालांकि एक नवी पद्धति है, प्रविष्टि में अब तक स्वरूप (अन्तर्भाव) शिक्षकों और गैर शिक्षण मंत्रालयों के लिए विभिन्न प्रकार के एक ही पैदा होना आधुनिक प्रविष्टि प्रयोग आधुनिक समावेश आधुनिक, विषय-वार आधुनिक मंत्रालयों आदि का अद्ययन किया गया इन आधुनिकों की अवधि में से कम एक सप्ताह से लेकर अधिक एक माह तक की रही। ये आधुनिक नीचा, सी सी आ टी, राश्री-आ और प्रो-पेक्ट सी आई आई एल आदि के सहयोग में आयोजित किए गए। स्मिति ने "पठन प्रेशली" में पत्राचार आधुनिक में घाग लेने के लिए सी आई आई एक से शिक्षकों को प्रोत्साहित किया।

प्रय

19.9 राज्य/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन-वार नवीदय विद्यालयों के चालन में वार वारों के दौरान किया गया कुल योजनागत व्यय रिपोर्ट-9 में दिया गया है।

नवीदय विद्यालयी स्कूल प्रशासन

20.1 केन्द्रीय विद्यालयी स्कूल प्रशासन की स्थापना स्वायत्त संगठन के प में 1961 में की गई थी। केन्द्रीय विद्यालयी स्कूल प्रशासन का अद्वैत चाली शरणार्थियों के बच्चों की शिक्षा संस्थाओं को चलाना, प्रवेश रण और उनकी सहायता करना है।

20.2 केन्द्रीय विद्यालयी प्रशासन 30 स्कूल चला रहा है। तसे से 5 आवासीय स्कूल हैं। ये स्कूल देशभर में फैले हैं। इसमें प्रो की संख्या 1100 से भी अधिक है। ये स्कूल केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बन्ध है और छात्रों का अधिष्ठान भारतीय सेकेण्डरी स्कूल में सीनियर सेकेण्डरी स्कूल परीक्षाओं के लिए तैयार करते हैं। स्कूल में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी के अलावा विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान या विद्यालयी एच हिन्दी माया पहली कक्षा से ही पढाए जाते हैं।

20.3 स्कूलों में विद्यालयी माया, संगीत एव कुल शिक्षकों के माध्यम आधुनिक विद्यालयी लोगों के साथ मिल कर कार्य करके विद्यालयी संस्कृति धर्मों को भी बनाए रखा गया है।

20.4 केन्द्रीय विद्यालयी विद्यालयी लोगों की चली अन्तर्भादी हो स्थानों में स्थित हैं। स्थानीय विद्यालयी समुदाय तथा राज्य सरकार के धर्माचारियों से अतिव सम्बन्ध बनाए रखने के लिए प्रत्येक विद्यालय के एक स्थानीय सलाहकार स्मिति गठित की गई है। स्मिति विद्यालयी चली प्रकृति की सम्स्थाओं की सुलझाने के अलावा विद्यालय की वि का अनुवीक्षण करती है।

20.5 शिक्षा के स्तर में सुधार लाने और विद्यालय और अन्तर्भाव को हट लाने के अद्वैत से प्रत्येक प्रातःकालीन विद्यालय द्वारा अभिभावक एक सप् गठित किए जाने की सम्भावना है।

प्र-विद्यालय शिक्षा के लिए सुविधाएं

20.6 केन्द्रीय विद्यालयी विद्यालय प्रशासन विद्यालयी बच्चों को उत्तर मातृ शिक्षा के लिए सुविधाएं भी प्रदान करता है। केन्द्रीय विद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न विद्यालयों के प्रतिभाशाली अतीनी विद्यालयी नौ को प्रशासन 15 छात्रवृत्तियों की प्रदान करता है। 17 से 22 वर्ष उम्र के छात्र और अधिकांश अंग्रेजी बोलने वाले छात्र छात्र

विज्ञान, अभिव्यक्ति, औद्योगिक और शिक्षक प्रशिक्षण (विज्ञानी मान्यता प्राप्त संस्था में) से डिग्री अन्तर्भाव डिप्लोमा अभ्यास के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त करने के पात्र है। 5 छात्रवृत्तियां 55% और अधिकांश अतिव करने वाले तथा डिप्लोमा आधुनिकों में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए स्वीकृत है।

कर्मचारीवृद्ध—विद्यालय

5.20.7 शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए केन्द्रीय विद्यालयी विद्यालय प्रशासन ने शिक्षकों को निम्नलिखित व्ययों के लिए मॉडल और प्रोत्साहन दिया

- अनुभव का आदान प्रदान;
- विद्यालय शिक्षा के नवीनतम परिवर्तनों, आधुनिक प्रकृतियों और नकाशों का परिचय प्राप्त करना,
- कार्य की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए औद्योगिक नीति को नवीन अवधारणाओं और मांगों का समावर्तन;
- आधुनिक शिक्षण प्रवृत्त लक्ष्यों को सम्भालना,
- कारगर शिक्षकों और प्रवृत्तियों के रूप में उनसे अतिवित्त अतिव भूमिकाओं, कोशलों और जानकारी की सम्कल्पना करना, और गुणात्मक सुधार पर विशेष बल देते हुए संस्था स्तर पर सुधार के लिए कार्यवाई योजना तैयार करना।

कार्यवृद्ध कार्यक्रम

5.20.8 केन्द्रीय विद्यालयी विद्यालय प्रशासन के छात्र उच्चतम माध्यमिक और एक माध्यमिक विद्यालय कला परिचयना के अंतर्गत आते हैं। ये विद्यालय हैं—दार्जीलिंग, मसूरी, डलहौजी, बाबलकुप, शिमला, मुकगाई और चन्द्रगिरि स्थित सीएसटी।

अन्तर्भाव शिक्षकों के लिए प्रोत्साहन प्रस्ताव 5.20.9 शासी निदेशों से शिक्षकों के लिए प्रोत्साहन प्रस्ताव की योजना का अनुमोदन कर दिया है, जिसका विवरण इस प्रकार है:

क्रम	शिक्षकों की श्रेणी	प्रस्ताव की संख्या
1	प्रधानाचार्य, मुख्याध्यक्ष (मिडिल स्कूल)	एक
2	वी जी टी	एक
3	टी जी टी	एक
4	वी आर टी / अन्य	एक

5.20.10 शासी बोर्ड ने इस बात का भी अनुमोदन किया कि प्रस्ताव-विज्ञान सेवा-निवर्तन की आयु पूरी करने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के सेवा-निवर्तन के लिए भी पात्र होने और प्रत्येक प्रस्ताव की राशि 1000 रुपए होगी।

पूर्व-माध्यमिक विद्यालय

5.20.11 निचले स्तर पर छात्रों की नीव अच्छी नहीं थी, बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम काफी खराब रहे, छात्र आधुनिक पूरा नहीं कर पाए। इस विशिष्ट परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने 1989-90 के सत्र से 20 पूर्व-माध्यमिक विद्यालय खोले। 1990-91 में 20 और पूर्व-माध्यमिक विद्यालय खोले गये। 1991-92 में 20 और पूर्व-माध्यमिक

केन्द्रीय तन्त्रिणी विद्यालय प्रशासन के स्कूलों के क्षेत्रीय आयोजन:

5.20.12 केन्द्रीय तन्त्रिणी विद्यालयों की परंपरा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने मसूरी, निलकुम्हे और कलिंगों स्थित स्कूलों में क्षेत्रीय खेल, साक्षरता और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए।

5.20.13 देश भर में फैले सभी केन्द्रीय तन्त्रिणी विद्यालयों के बहुत से विद्यार्थियों ने इन आयोजनों में भाग लिया।

सभीक्षा समिति:

5.20.14 केन्द्रीय तन्त्रिणी विद्यालयों में शिक्षा के स्तर और उसकी विषय वस्तु में सुधार लाने के लिए सरकार ने अप्रैल 1991 में एक समीक्षा समिति का गठन किया था जिसे इसके कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन, अवसरचना और शैक्षिक मानकों और अन्य क्षेत्रों के अध्ययन का काम सौंपा गया था। समिति ने नवंबर, 1991 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

बजट प्रावधान:

5.20.15 केन्द्रीय तन्त्रिणी विद्यालय प्रशासन के लिए वर्ष 1991-92 का बजट प्रावधान 421 लाख रुपए था।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

5.21.1 उन प्रतिरक्षा कर्मियों के बच्चों, जिनकी शिक्षा में उनके अधिवाहकों का एक भागई क्षेत्र से दूसरे भागई क्षेत्र में स्थानांतरण के परिणामस्वरूप बाधा पड़ती थी तथा अध्ययन के पाठ्यक्रम बदल जाते थे, सहित केन्द्रीय सरकार के स्थानांतरणीय केन्द्रीय कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केन्द्रीय विद्यालय योजना वर्ष 1963-64 में प्रारम्भ की गई थी।

5.21.2 केन्द्रीय विद्यालयों की खोलने और उनका प्रबंध करने के कार्य की देखरेख के लिए 1965 में केन्द्रीय विद्यालय संगठन नामक स्वायत्तशासी संगठन की स्थापना की गई थी। संगठन पूर्णतः सरकार द्वारा वित्तपोषित है।

5.21.3 आरम्भ में रक्षा कर्मचारियों की बहुतायत वाले स्थानों में तत्समय कार्यरत रेजिमेंटल स्कूलों को 1963-64 के दौरान केन्द्रीय विद्यालय के रूप में अधिग्रहण किया गया था। इस समय केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या 743 है, जिनमें 6,00, 197 छात्र अध्ययनरत हैं। 30 अप्रैल 1991 को स्वीकृत शिक्षकों की संख्या 37,770 थी। दिसम्बर 1991 / जनवरी 1992 में 23 नए केन्द्रीय विद्यालयों की स्वीकृति के आदेश जारी किए गए हैं।

केन्द्रीय विद्यालयों का वितरण

5.21.4 केन्द्रीय विद्यालय ऐसे स्थानों पर खोले जाते हैं, जहां केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की घनी आबादी है। रक्षा प्रतिष्ठानों में विद्यालय रक्षा मंत्रालय की सिफारिश पर खोले जाते हैं। सिविल क्षेत्र के संबंध में आयोजन भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के कर्मचारी कल्याण सचों द्वारा किया जाता है। केन्द्रीय विद्यालय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और उच्च शिक्षण संस्थाओं के परिसरों में भी खोले जाते हैं। केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या निम्नलिखित है:

क) रक्षा क्षेत्र	343-6
ख) नागरिक क्षेत्र	251-14
ग) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	134-2
घ) उच्च शिक्षा संस्थाएँ	15-1

743+23=766

प्रवेश नीति

5.21.5 केन्द्रीय विद्यालय योजना के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए नागरिक / रक्षा क्षेत्र के स्कूलों में प्रथम प्राथमिकता केन्द्रीय सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चों को दाखिल करने के संबंध में दी जाती है। तथापि, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा उच्च शिक्षा संस्थाओं के केन्द्रीय विद्यालयों में प्रथम प्राथमिकता संबंधित संगठन के कर्मचारियों के बच्चों को दाखिल करने के बारे में दी जाती है।

5.21.6 प्रत्येक केन्द्रीय विद्यालय में नए दाखिलों में से क्रमशः 15% तथा 71/2 दाखिले अनुभूति जाति तथा अनुभूति जनजाति के स्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चों के लिए आरक्षित रखे जाते हैं। यदि ऐसे बच्चों उपलब्ध नहीं होते हैं, तो सामान्य वर्ग के बच्चों को दाखिल कर लिया जाता है।

परीक्षा परिणाम

5.21.7 केन्द्रीय विद्यालयों ने देश में स्कूल स्तर पर शिक्षण प्रणाली में अपना स्थान बनाया है। के. मां. शि. बो. द्वारा संचालित परीक्षाओं में उनके पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत गैर केन्द्रीय विद्यालयों के पास होने वाले छात्रों के प्रतिशत से अधिक है जैसा कि सारणी 5.6 तथा 5.7 से स्पष्ट है।

सारणी 5.6

केन्द्रीय विद्यालयों के उम्मीदवारों की संख्या और अखिल भारतीय माध्यमिक स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा में उनकी उत्तीर्ण प्रतिशतता में वृद्धि

उत्तीर्ण प्रतिशत (कक्षा-IX)

वर्ष	केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या	छात्रों की संख्या	केन्द्रीय विद्यालय	गैर केन्द्रीय विद्यालय	अन्क
1989	327	18510	94 00	89 80	- 4.2
1990	360	21247	85 70	74 90	+ 10.4
1991	396	24536	82 02	80 77	+ 1.2

नोट—गैर केन्द्रीय विद्यालयों के 1989 से आगे के परिणाम केवल उन छात्रों के हैं जिन्होंने प्राइवेट छात्र के रूप में और पत्राचार के माध्यम से परीक्षा दी

सारणी 5.7

छात्रों की संख्या में वृद्धि और ए. आई. एस. एम. सी. परीक्षा में उनका उत्तीर्ण प्रतिशत

वर्ष	केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या	छात्रों की संख्या	केन्द्रीय विद्यालय	उत्तीर्ण प्रतिशत (कक्षा-X)	अंक
1989	465	30502	93 4	90 3	- 3.1
1990	520	34815	89 05	74 18	+ 14.8
1991	577	36225	87 8	80 08	+ 7.8

नोट: गैर केन्द्रीय विद्यालयों के 1990 से आगे के परिणाम केवल उन छात्रों के हैं, जिन्होंने प्राइवेट छात्र के रूप में और पत्राचार के माध्यम से परीक्षा दी है।

सह पाठ्यचर्या कार्यक्रमों में उपलब्धि

5.21.8 केन्द्रीय विद्यालयों में सहपाठ्यचर्या कार्य कलाप में भी ख्याति प्राप्त की है जिनमें खेल-कूद, आउटडोर कार्यक्रम, पर्यावरण शैक्षिक कार्यक्रम और ललित और अभिनव कला शामिल है। केन्द्रीय विद्यालय के छात्र स्थानीय तथा क्षेत्रीय प्रतियोगिताओं में पुरस्कार जीतने के अतिरिक्त भारत सरकार के पर्यावरण विभाग द्वारा आयोजित निम्न प्रतियोगिताओं, सोवियत बैंड नेहरू अवार्ड, रॉकन विडन पेंटिंग कम्पटीशन जैसे और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रति वर्ष पुरस्कार जीत रहे हैं। अधिकांश केन्द्रीय विद्यालय प्रकृति और साहसिक कार्य क्लब संचालित करते हैं जो क्रमशः भारतीय विश्व वन्य जीवन निधि और भारतीय राष्ट्रीय साहसिक कार्य प्रतिष्ठान से सम्बद्ध हैं। प्रत्येक वर्ष लगभग 10000 छात्रों को वटहन आरोहण में प्रशिक्षित किया जाता है और लगभग 550 को हिमखड़ी में ट्रेकिंग के लिए भेजा जाता है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन भारतीय विद्यालय क्रीड़ा प्रतिष्ठान और भारत स्काउट तथा गाइड का एक सदस्य राज्य है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों और खेलकूदों में छात्रों की व्यापक सहभागिता पर भी बल दिया जाता है जिसके लिए सभी केन्द्रीय विद्यालयों में सभी कक्षाओं के लिए स्कूल समय-सारणी में परियोजना का प्रावधान है।

राष्ट्रीय एकता

5.21.9 प्रत्येक केन्द्रीय विद्यालय एक लघु भारत है जहाँ शिक्षण तथा अध्ययन की प्रक्रिया में विभिन्न विधाओं तथा विभिन्न रीति रिवाजों को मानने वाले के साथ विभिन्न भाषा वर्गों से सम्बद्ध शिक्षक और छात्र जुट हुए हैं। ये छात्र एक ही रापथ लेते हैं, समान वर्दी में उसी ध्वज के नीचे समान गीत गाते हैं और ममान पाठ्यचर्या और सह-पाठ्यचर्या कार्यक्रमों का पालन करते हैं।

5.21.10 केन्द्रीय विद्यालय समुदाय गायन कार्यक्रमों में अग्रणी रहे हैं। क्षेत्रीय प्रतियोगिताओं के लिए अन्तर विद्यालय प्रतियोगिताएँ प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती हैं। सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राष्ट्रीय महत्त्वों को पोषित करने की दृष्टि में नाटको, विविध प्रदर्शनों, भाषणों, वाद-विवादों, कविता-पाठों, कहानियों कहने जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों प्रत्येक विद्यालय में स्कूल पाठ्यचर्या का एक अभिन्न भाग हैं।

5.21.11 केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर संयोजनाओं के रूप में राष्ट्रीय एकता और अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना को लिया गया है। इन परियोजनाओं के अंतर्गत, प्रत्येक वर्ष प्रदर्शनीया आयोजित की जाती हैं।

खेल कूद कार्यक्रमों द्वारा व्यक्तित्व विकास

5.21.12 निम्नलिखित कारणों से खेल कूद के क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष उत्साही व दीर्घकालिक प्रयास किए जाते हैं —

- (I) व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए
- (II) योग्यता का पता लगाकर उन्हें विकसित करना तथा
- (III) खिलाड़ियों के जोश व नेतृत्व गुणों को विकसित करने के लिए।

इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गए

शिक्षण कैम्प

5.21.3 प्रत्येक वर्ष शिक्षण कैम्प आयोजित किए जाते हैं जिसमें प्रोत्सावकाश में करीब 400 छात्रों (लड़के व लड़कियों दोनों) को विभिन्न खेल कूदों में निशित शिक्षण व प्रशिक्षण मिलता है इसके साथ भारत के स्कूल खेल कूद संघ द्वारा आयोजित किए जाने वाले टूर्नामेंट में केन्द्रीय विद्यालय दलों की भागीदारी से पहले सम्भव व शिक्षण कैम्प आयोजित किए जाते हैं

विभिन्न स्तरों पर केन्द्रीय विद्यालय मुकाबले आयोजित करना

5.21.14 केन्द्रीय विद्यालयों में विद्यालय, उप क्षेत्रीय, क्षेत्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद मुकाबले आयोजित करने के लिए वर्षवार योजना तैयार व कार्यान्वित की गई है। प्रत्येक वर्ष इन सभी मुकाबलों में करीब 35 / 000 छात्र भाग लेते हैं।

खेल

5.21.15 केन्द्रीय विद्यालय, आई-आई टी, मद्रास (बास्केट बाल व वालीबाल के लिए) केन्द्रीय विद्यालय क्रिकेट, घुण (हाकी के लिए) तथा केन्द्रीय विद्यालय न 1 ग्यालियर (क्रिकेट के लिए) चार खेल छात्रावास चला रहा है। भोजन व रहने, खेलकूद किट व पोषक आहार का पूरा खर्च केन्द्रीय विद्यालय उठाते हैं जिसके लिए केन्द्रीय विद्यालय मुख्यालय द्वारा प्रत्येक महीने प्रत्येक छात्र 385 रु का छात्रावास अनुदान दे रहा है।

मुख्यालय

साहसिक कार्यक्रम

5.21.16 के वि. सं. प्रतिवर्ष व्यापक स्तर पर पर्यटनरोहण कार्यक्रम आयोजित करता है। इस वर्ष लड़कों व लड़कियों के 6 दलों में लगभग 250 विद्यार्थियों की मई / जून, 1990 में रुद्रगिर ताल क्षेत्र में पर्यटनरोहण के लिए आयोजित किया गया।

स्काउट / गाइड कार्यक्रम

5.21.17 स्काउट / गाइड कार्यक्रमों केन्द्रीय विद्यालयों में भीतर तक पैठ चुके हैं। पंजीकृत स्काउट व गाइडों की संख्या बढ़कर लगभग 60,000 तथा प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या 5,000 हो गई है। प्रतिवर्ष शिक्षकों व विद्यार्थियों के प्रशिक्षण के अनेकों कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इनमें, शिक्षकों के लिए प्राथमिक से नेतृत्व-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा विद्यार्थियों के लिए विभिन्न दक्षता बैच, प्रधानमन्त्री शौन्ड प्रतियोगिता प्रशिक्षण शिविर तथा राज्य पुरस्कार व राष्ट्रपति पदक प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण शिविर शामिल हैं। ये सभी कार्यक्रम इकाई, जिला, मंडल तथा क्षेत्र वि. सं. राज्य स्तरों पर आयोजित किए जाते हैं। पुनर्देशन में 6-9 जनवरी, 1991 को 960 स्काउट व गाइडों के लिए के. वि. सं. राज्य रैली आयोजित की गई।

विज्ञान प्रदर्शनी

5.21.18 विज्ञान शिक्षा में विज्ञान प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय विद्यालयों में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिनमें क्षेत्रीय दूर, विज्ञान प्रदर्शनीया, विज्ञान प्रदर्शनी तथा वैज्ञानिक विषयों पर चर्चा सम्मिलित हैं। इस प्रकार की सहभागिता से न केवल शिक्षकों को छात्रों की वैज्ञानिक प्रतिभा का ज्ञान होता है बल्कि इसमें छात्रों को विज्ञान के क्षेत्र में नवीन प्रयोग व रचनाओं की प्रेरणा मिलती है तथा उनमें विज्ञान वैज्ञानिक भावना तथा सामाजिक पर्यावरणीय चेतना के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। विज्ञान प्रदर्शनीया प्रति वर्ष स्कूल, क्षेत्रीय व राष्ट्रीय स्तरों पर आयोजित की जाती हैं।

युवा संसद

5.21.19 छात्रों को संसदीय प्रक्रियाओं तथा व्यवहार से अवगत करने के लिए तथा उनमें अनुशासन, दूसरों के विचारों के प्रति सहिष्णुता, खुली चर्चाओं तथा वादविवाद द्वारा निर्णयों पर पहुंचने तथा उनमें सामाजिक आवश्यकताओं, संसदीय आचार तथा संस्कृति के प्रति चेतना पैदा करने के विचार से सभी विद्यालयों में युवा संसद आयोजित की जाती है।

6. આ ફરિયાદો અંગ્રીક .

6. उच्चतर शिक्षा

और अनुसन्धान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि. अनु. आ.)

उच्चतर शिक्षा पद्धति का संवर्धन

6.1.1 वर्ष 1991-92 के आरंभ में विश्वविद्यालयों और कालेजों में कुल छात्र नामांकन 44.25 लाख था। यह थिहले वर्ष के नामांकन के मुकाबले 1.78 लाख अधिक था। विश्वविद्यालय विभागों में नामांकन 7.32 लाख था और सभ्य कालेजों में 36.93 लाख था। कला शैकाय से नामांकन कुल नामांकन का 40.4% था। विज्ञान और नगिन्य संकायों से प्रशिक्षण विभाग 19.6 अंक 21.9 थी। प्रथम डिग्री स्तर पर नामांकन 38.99 लाख (88.1%) कालेज स्तर पर 4.20 लाख (9.5%), अनुसन्धान स्तर पर 0.49 लाख (1.1%) और डिप्लोमा तथा प्रभावि-पत्र स्तर पर 0.57 लाख (1.3%) था।

6.1.2 वर्ष के दौरान अध्यापकों की संख्या में 2.63 लाख की वृद्धि हुई। इसमें से 0.59 लाख विश्वविद्यालय विभागों तथा विश्वविद्यालय कालेजों में थे तथा शेष सभ्य कालेजों में थे। विश्वविद्यालयों में 58,661 अध्यापकों में से, 7509 प्रोफेसर थे, 15369 प्रोफेसर थे, 33437 लेक्चरर थे तथा 2346 ट्यूटलर / प्रशिक्षक थे। सभ्य कालेजों में, जखि अध्यापकों की संख्या 28,421 थी और लेक्चररी की संख्या 167047 थी और शिक्षकों / प्रशिक्षकों की संख्या 8996 थी।

6.1.3 वर्ष 1991-92 के दौरान, दो विश्वविद्यालयों अर्थात् उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय, जलगांव तथा भोनीमनियम सुन्दरानर विश्वविद्यालय, तिरुनेलली स्थापित किए गए थे और इस प्रकार, देश में विश्वविद्यालयों की कुल संख्या 148 तक पहुंच गई।

भारत में उच्चतर शिक्षा

6.1.4 वर्ष 1991-92 के आरंभ में भारत में विश्वविद्यालयों की संख्या 13.67 लाख के मुकाबले में 14.37 लाख थी। कालेजों स्तर पर, भारत में नामांकन कुल नामांकन का 34.2% था। छात्रों का नामांकन, केवल से सबसे अधिक (53.0%) था जबकि पंचाव (48.2%), दिल्ली (46.3%), हरियाणा (42.2%), हरियाणा (42.2%), मेघालय / नागालैण्ड / मिजोरम (39.0%), तमिलनाडु (38.5%) और पंजाब बंगाल / त्रिपुरा / सिक्किम में (38.4%) था। बिहार (16.4%) में भारत में नामांकन सबसे कम था।

वि. अनु. आ. के कार्यक्रम तथा क्रियाकलाप

6.1.5 वर्ष के दौरान विज्ञान बुद्धि, अनुसन्धान महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्य किया गया है, वे इस प्रकार हैं:— स्वायत्त कालेज, पाठ्यक्रमों की पुनरीक्षण, अध्यापकों के अनुसन्धान के लिए शैक्षिक स्टाफ कालेज, लेक्चररी की पदों के लिए पात्रता-परीक्षा, अन्तर विश्वविद्यालय केन्द्र और संकाय, दूरस्थ शिक्षा। शिक्षा-प्रतिष्ठा / व्यापक-प्रतिष्ठा, विशेष सहायता कार्यक्रम, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अवस्थापना-को सुदृढ़ करने सभ्य-की समिति (सी. ओ. एस. आई. एस. टी.) कार्यक्रम, ग्रीड शिक्षा और राष्ट्रीय साक्षरता निरान अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों, विकलांगों और

भारत में शिक्षा, विश्वविद्यालय, राज्य सरकार तथा वि. अनु. आ. के बीच अन्तर-सम्बन्ध तथा उपसहयता, आयोजना क्षेत्रों पर प्रेरित प्रणय के वैकल्पिक मॉडल तथा जन संघार और शैक्षिक प्रौद्योगिकी क्षेत्र (टेक्नो.) का विस्तार करना। विभिन्न योजनाओं के सम्बन्ध में वि. अनु. आयोग द्वारा किए गए प्रचारों का सक्षिपत स्वरूप प्रसिद्धित प्रेषणों में दिया गया है।

स्वायत्त-कालेज

6.1.6 वि. अनु. आयोग ने स्वायत्त कालेजों की अपनी योजना के ऊपर स्वायत्त की संकल्पना को प्रोत्साहित करते तथा उसके संदर्भों के लिए अपने प्रचारों को जारी रखा। आलोच्य अवधि के दौरान, और अधिक कालेजों को स्वायत्तता की राई प्रदान किया गया था जिससे इस प्रकार कालेजों की कुल संख्या दिसम्बर, 1991 तक 106 तक पहुंच गई।

पाठ्यक्रमों को पुनः तैयार करना

6.1.7 सामान्य शिक्षा से अन्तर आत्मक पाठ्यक्रमों को पुनः तैयार करने की योजना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रथम डिग्री पाठ्यक्रमों को समुदाय की परीक्षण और विकासालय आवश्यक्तों के अधिक अनुसन्धान करने और शिक्षा को कार्य / क्षेत्र / व्यावहारिक अनुभव और उत्पादकता से जोड़ने की दृष्टि से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आरम्भ की गई थी। अनेक विश्वविद्यालयों और कालेजों ने इन पाठ्यक्रमों को आरंभ कर दिया है। इसके अतिरिक्त, पाठ्यक्रमों को पुनः तैयार करने के कार्यक्रम को प्रोत्साहन दिए जाने के उद्देश्य से, वि. अनु. आ. ने दिसम्बर, 1991 तक विज्ञान में 11, मानविकी और सामाजिक विज्ञान में 18 तथा व्यावसायिक शिक्षा में एक-कुल 30 पाठ्यक्रमों विकास केन्द्र (या वि. के.) अध्यापन और पत्रन को नई सामग्री को आधुनिक बनाने, उसे तैयार करने और विकास करने को ध्यान में रखते हुए विद्यमान पाठ्यक्रमों की पुनरीक्षा करने के लिए स्थापित किए हैं। 27 केन्द्रों की मॉडल पाठ्यक्रम पर विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहित किए जाने हेतु राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाळाओं में चर्चा की गई थी। वर्ष के दौरान, वि. अनु. आयोग ने व्यापक परिकल्पना हेतु सी. ओ. एस. टी. के प्रकाशन तथा ग्रन्थि आई सेक्टर, दिल्ली विश्वविद्यालय के ऊपर उनकी विषयों के प्रकाशन को मान लिया जिसके लिए आयोग प्रकाशन को लागू हेतु 50 प्रतिशत अधिक सहायता देने के लिए सहमत हो गया। इस बीच, वि. अनु. आयोग ने उन 314 कालेजों को अपना सहयोग देना जारी रखा जो कालेज विज्ञान सुधार कार्यक्रम को लागू कर रहे हैं। इसी प्रकार, 784 कालेज, कालेज समितियों तथा सामाजिक विज्ञान सुधार कार्यक्रमों के सम्बन्ध में सहायता प्राप्त कर रहे हैं।

6.1.8 वि. अनु. आयोग विश्वविद्यालयों तथा बहु-संकाय कालेजों में शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा और खेलरूप में तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम आरंभ किए जाने के लिए सहमत हो गया। आर्थिक परणों में, प्रत्येक विद्यार्थी के केवल एक कालेज, जिसमें टैक और फोल्ड जिनमार्किंग

योग, कण्डिरागिनि युनिट जैसी सुविधाी न्गतम सुविधाएं उपलब्ध हैं, की पाठ्यक्रम की आरंभ करते के लिए चुना जा सका। दिसम्बर, 1991 तक, 6 विश्वविद्यालयों और 27 कालेजों ने पाठ्यक्रम को आरंभ किया है जिसके लिए आयोजन वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

विश्वविद्यालयों की विकास सम्बन्धी योजनाओं के अभाव तैयार करने के लिए आठवीं योजना की मार्गदर्शी कल्पेछाई:—

6.1.9 किन्तु आयोजन ने आठवीं योजना सम्बन्धी सलाह दी कि वे पर विश्वविद्यालयों को दी गई कल्पेछाईओं में, उनके यह सलाह दी कि वे विश्वविद्यालय पद्धति से बाहर की प्रौद्योगिकी तथा संस्थाओं विशेष रूप से वे जो विश्वविद्यालय शिक्षा को अधिक उपयोगी बनाने के उद्देश्य से अनुसन्धान और विकास के लिए समर्पित हैं, वे सम्पर्क को विकसित करें। विश्वविद्यालयों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उभरते हुए उन क्षेत्रों को अपनाते को प्रोत्साहित किया जाएगा जो इलेक्ट्रॉनिक-विज्ञान, संगणक विज्ञान, जैव-प्रौद्योगिकी, समुद्र-विज्ञान तथा पर्यावरण और ऊर्जा-अव्ययन जैसे सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए कार्या प्रसंगिक हैं।

6.1.10 वे मार्गदर्शी कल्पेछाईं विद्यमान कार्यक्रमों के समेकन पर अकाश जाती है। नए विशेषज्ञता वाले पाठ्यक्रमों अथवा नए विभाग खोलने की प्रेरणाक उत्पन्न-विषय क्षेत्रों वृद्धिकोण के साथ तैयार की जा सकती है जिसके विकास विश्वविद्यालयों से विद्यमान सुविधाओं द्वारा जारी रखा जा सकता है। विकासशील विश्वविद्यालयों के मामले में, नए विभाग खोलने आने की निर्धारण, क्षेत्र में अव्ययन उपलब्ध ऐसी ही सुविधाओं तथा जन-शक्ति आवश्यकताओं के अध्ययन को ध्यान में रखते के बाद, पूरे क्षेत्र अथवा राज्य में इस प्रकार के विभागों के लिए समग्र आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

6.1.11 इसके अतिरिक्त मार्गदर्शी कल्पेछाई में विश्वविद्यालयों से यह अनुरोध किया गया है कि सभी विभागों के लिए अध्ययन सहायता उपलब्ध कराई जाए और अध्ययनकों तथा छात्रों के लिए वीडियो-टेपों पर अभुक्ष विषयों में पाठ्यक्रम सम्बन्धी क्षेत्र तैयार किए जाए ताकि वे अपनी-अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र में और अध्ययन के प्रगती-विज्ञान में हुईं उन्नति के साथ चले बनाए रखें। विश्वविद्यालयों को यह भी सलाह दी गई है कि वे परामर्शी सेवाओं तथा उपयुक्त वैज्ञान प्रौद्योगिकी के साथ सम्पर्क स्थापित छात्रों के लिए आम सुविधाओं में भी सुधार लाएं।

6.1.12 आठवीं योजना के दौरान संस्थागत विकास योजनाओं के अनर्पित अन्तर-आतक तथा आतकोतर अध्ययन तथा अनुसन्धान सुविधाओं के विकास के लिए आवश्यकताओं को किन्तु आयोजन सहायता पद्धति की संशोधन कर दिया गया है, विश्वविद्यालयों को अब पुस्तकालय खोलने और भविष्य आवास के लिए शत प्रतिशत सहायता पुस्तक प्रयोगशालाओं, कक्षा-कक्षों, केन्द्रीय-कार्यशाला, प्रयोग-शाला, परीक्षा-शाला, परीक्षा-शाला, गैट-हाउस, छात्रावास, शिक्षक-छात्रावास, कार्यकारी-कक्षाएँ।

गुरु-प्रवण, विजिटिंग-संभव परिसर आदि और विश्वविद्यालय मुद्रणालयों की स्थापना / सुधार स्वास्थ्य क्षेत्रों और विद्यमान छात्रावसी में सुविधाओं के सुधार के लिए आयोजन द्वारा नमश. 75% और 50% के मुकामले में 75 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। विश्वविद्यालयों को अब सफेक विकास, जल-आपूर्ति और विद्युत संहति परिसर विकास के लिए 75% सहायता मिल सकेगी। सातवीं योजना अवधि में ऐसी सहायता के लिए कोई अवधान नहीं था।

कालेजों के विकास सम्बन्धी योजनाओं के अभाव तैयार करने के लिए आठवीं योजना की मार्गदर्शी कल्पेछाई

6.1.13 आठवीं योजना के दौरान कालेजों के विकास के लिए किन्तु आयोजन की नीति के चार मुख्य कार्यक्रम हैं: अवर्धित (क) शिक्षा के मानकों और कोटि का सुधार; (ख) उच्चतर शैक्षिक सुविधाओं में असमानताओं और क्षेत्रीय असमताओं का उन्मूलन; (ग) पाठ्यक्रमों की पुनःसंरचना और विविधता (घ) योग्य कालेजों को स्वायत्तता का दर्जा प्रदान करना।

6.1.14 इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, आयोजन उन कालेजों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा जो न्यूनतम पात्रता शर्तों को पूरा करते हों और अपेक्षित व्यवहार्यता और सामर्थ्य से युक्त हों और केवल मानकों के लिए प्रयास कर रहे हों जिससे कि वे पुस्तक-कैलों को सुदृढ़ करें, उपग्र-आतक स्तर पर उपयुक्त शिक्षण के लिए अनिवार्य सुविधाएँ वैज्ञानिक उपकरण, भवन के निर्माण, अध्ययन तथा तकनीकी कर्मचारी, स्थापन के कर्मचारी वर्गों के छात्रों के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम, निशान-कार्यक्रम, परीक्षा-सुधार और चारत में शैक्षिक-समेलन, कार्यशालाओं / लेनिनारों में शिक्षकों की प्रगतीदारी, संहति पुस्तकों और प्रिन्सिपलों जैसी अपनी-अपनी सुविधाओं आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। असमानताओं और क्षेत्रीय असमताओं को दूर किए जाने की दृष्टि से, उन कालेजों को भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जो निम्नलिखित आठवीं योजना वाले क्षेत्रों में स्थित कालेजों के गहन विकास के लिए और अनुसुचित जनजाति के छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

दक्षता में सुधार

6.1.15 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिसम्बर, 1991 तक 110 विश्वविद्यालयों को संगणक सम्बन्धी सुविधाएं सस्वीकृत की हैं। इसके अतिरिक्त आयोजन ने इस अवधि तक 7216 कालेजों को संगणक सम्बन्धी सुविधाएं सस्वीकृत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की। प्रशिक्षण और अनुसन्धान के लिए इन सुविधाओं को उपयोग में लाए जाने के अतिरिक्त, उनका उपयोग छात्र-रिक्त, लेखों और प्रशासन तथा प्रबन्ध के अपेक्षित अन्य आंकड़ों के रण-रक्षण के लिए किया जा सकता है।

शिक्षक-वर्गों, प्रशिक्षण और निष्पादन मूल्यांकन

6.1.16 वर्ष के दौरान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने लेकपशिय की पात्रता निर्धारित करने तथा मार्गदर्शकों और सामाजिक-विज्ञानों से कनिष्ठ अनुसन्धान शिक्षाकर्त्तया प्रदान करने के लिए अर्हक-परीक्षा संचालित की। इसी प्रकार किन्तु आयोजन की 156 शैक्षिक स्तर कालेज ने 4601 शिक्षकों को शक्तिगत करते हुए, 156 अनुसन्धान कार्यक्रम आयोजित किए। इसी प्रकार, सेवागत शिक्षकों के लिए 308 पुनर्कक्षा पाठ्यक्रम तैयार किए गए थे जिसमें 8369 शिक्षकों को शक्तिगत किया गया था। जनवरी, 1990 में योजना अवधि में हुई बैठक में शिक्षा विभाग की वर्ष 1990-91 की वार्षिक-योजना पर निर्णय लेते समय, यह निर्णय लिया गया था कि आठवीं योजना में एं एस्ए

नी योजनाओं को सत्यापन रूप देने से पूर्व, वि. अनु. आ. को योजना की विधुत रूप से पुनरीक्षा करनी चाहिए। तदनुसार, वर्ष 1990-91 के दौरान आयोग द्वारा गठित एक समिति द्वारा कार्यक्रम की पुनरीक्षा पूरी की गई थी।

5.1.17 समिति ने फरवरी, 1991 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। आयोग द्वारा रिपोर्ट पर विस्तृत रूप से विचार किये जाने तक यह निर्णय लिया गया था कि विश्वविद्यालयी को विद्यमान पद्धति के आधार पर, 31 मार्च, 1992 तक तत्पर आधार पर निम्नीय सहायता प्रदान की जानी जारी रखी जाए। विशेष सहायता कार्यक्रम

5.1.18 वि. अनु. आ. ने दिसम्बर, 1991 तक विज्ञान, इंजीनियरी और भौतिकी में विशेष सहायता के 109 विभागों तथा 41 उच्च अध्ययन केंद्रों को सहायता प्रदान करती जारी रखी। मानविकी और सामाजिक-विज्ञान से उच्च अध्ययन के 16 केंद्रों तथा विशेष सहायता वाले 101 विभागों को सहायता प्रदान की गई थी। इसके अतिरिक्त, विज्ञान से 47 विभागीय अनुसंधान सहायता परियोजनाएँ और मानविकी तथा सामाजिक विज्ञानों से 22 क्रियात्मक को जा रही हैं। आयोग ने उनके विभागों की भावना समाप्त की क्योंकि उनका विमानन, विशेषकर-समिति द्वारा यथा-भूलाभिकत अधिकतम स्तर का नहीं पाया गया था।

सी. ओ. एस्. आई. एस. टी. कार्यक्रम

5.1.19 दिसम्बर, 1991 तक विज्ञान और भौतिकी शिक्षा तथा अनुसंधान में अवस्थापना को सुदृढ़ करने की योजना के अन्तर्गत 111 विभागों को सहायता प्रदान की गई है।

सुर-क-उ-डी-विटी कार्यक्रम

5.1.20 एक स्थायी समिति विश्वविद्यालय पद्धति में सुर-क-उ-डी-विटी कार्यक्रम को प्रभावी रूप से क्रियात्मक करने में सहायता करती है। समिति ने फरवरी, 1991

आयोजित बैठक में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यक्रमालयों की समीक्षा की। इसके कार्यक्रम को प्रति के वार में संतोष व्यक्त किया और सुनिश्चिती अनुसंधान तथा सुर-क-उ-डी-विटी के अनुसंधान— दोनों में, असाधारण उपलब्धियों की प्रशंसा की। जहाँ तक परियोजनाएँ, शैक्षिक-निदेश का सम्बन्ध है, यह काफी लागत-प्रभावी पाया गया है। कुछ सरसाएँ अन्त-अन्तर्गत विशिष्ट क्षेत्रों में प्रदर्शक केंद्रों के रूप में प्रकट हुई हैं। उन्नीस सत्रिय ग्रुप विकसित किए हैं और मूल प्रस्तावों में यथा-परिकल्पित अनिवार्य-कार्यकालों को आयोजित किया है। इस कार्यक्रम से, आठ एड्ड डि. तथा तथा शैक्षिक कार्यक्रमालयों के प्रति सहजीवी दृष्टिकोणों के लिए विश्वविद्यालय पद्धति पर एक संकाशक प्रभाव पड़ा है।

6.1.21 समिति का यह दृष्टिकोण था कि कार्यक्रम को प्रभावी रूप से क्रियात्मक करने तथा इसके कार्यक्रमालयों का निरीक्षण करने के लिए एक से शृंगारक बजट और प्रोजेक्ट विश्वविद्यालय संकाय की सहायता की जानी चाहिए। ये इस क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न संस्थाओं से सुविधाओं तथा विशेषज्ञता के पूरक प्रयोग को सुकर बनाएँ। प्रस्तावित संकाय की देखभाल करने के लिए एक समन्वय समिति गठित की गई है।

अवकाश के वैकल्पिक अधिक

6.1.22 वर्ष के दौरान, वि.अनु.आ. द्वारा रिपोर्ट पर सम्पन्नित शीर्षक ज्ञान समिति की रिपोर्ट शिक्षा विभाग को प्रस्तुत कर दी गई थी। समिति,

विश्वविद्यालय पद्धति पर नई माँगों के अनुसंधान में विभिन्न विश्वविद्यालयों/विश्वी की संरचना, प्रक्रिया, और उत्तरदायित्वों सहित प्रमुख पद्धति की पुनरीक्षा करने के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) की "कार्यवाही योजना" के परिणाम के रूप में स्थापित की गई थी। समिति की प्रमुख विशेष-दृष्टिकोण के साथ, विश्वविद्यालयों की प्रमुख दृष्टिकोण तथा बृहत् सम्भावित थीं। इसने विश्वविद्यालय, - स्थापना, स्थापना, आयोजना, नियंत्रण और विश्वविद्यालयों, राज्य सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बीच अन्तःसम्बन्ध जैसे पहलुओं पर भी जल दिया। शिक्षारित्री विश्वविद्यालय पद्धति में विभिन्न पदधिकारियों/प्रधिकारियों तथा निकायों के अधिकारों तथा कार्यों को परिभाषित करती है।

6.1.23 रिपोर्ट मार्च, 1991 में हुई कंसिंस-वर्क की बैठक में प्रस्तुत की गई थी। कंसिंस-वर्क ने, इस रिपोर्ट की दूरगामी प्रतिक्रियाओं पर विचार करते हुए, यह इच्छा व्यक्त की कि रिपोर्ट की जांच करने के लिए, एक कंसिंस-वर्क समिति गठित की जानी चाहिए। तदनुसार, गुजरात के शिक्षा मंत्री, श्री कश्मन दास शोभेरी की अध्यक्षता में, एक कंसिंस-वर्क समिति का गठन ज्ञान समिति की जांच करने के लिए किया गया।

सामान्य सुविधाएँ और सेवाएँ

6.1.24 बंगलौर, बम्बई और कलकत्ता में संगणक पर आधारित आधुनिक सुचना/प्रलेखन केन्द्र पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं। इन केंद्रों से शिक्षकों और छात्रों की सुचना तक पहुँच में सुधार आया है तथा उन्हें अपने-अपने विषयों में अद्यतन प्रलेखन उपलब्ध करने के साथ-साथ ये केन्द्र उन्हें आवश्यक यथा विश्वविद्यालय सभाओं सहायता उपलब्ध करते हैं। इसके अतिरिक्त वि. अनु. आयोग ने विश्वविद्यालयीय प्रणाली के अन्तर्गत राष्ट्रीय शोध सुविधाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्रों से अंतर विश्वविद्यालय केंद्रों की स्थापना की है। वर्ष के दौरान विश्वविद्यालयों, शिक्षा माध्यम शोध केंद्रों और दूर-दूर-स्थल केंद्रों के विभिन्न सुचना विभागी के कार्यक्रमों को मुख्यधारा में लाने, इनमें समन्वय स्थापित करने तथा इसे सुदृढ़ बनाने के लिए एक अंतर विश्वविद्यालय सहभागिता जैसे आकार की शैक्षिक संस्था के लिए एक अंतर विश्वविद्यालय सहभागिता की संकल्पना भी तैयार की गई। तत्परति में स्थापित होने वाली माध्यम-उच्च, संसाधन-मंडल और परिवर्ती-मंडल (एस्-एस्-टी-टी) छात्र प्रणाली का स्थापन उद्योग के लिए भी वैश्विक विश्वविद्यालय से वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुविधा के रूप में एक छात्र केंद्र स्थापित किया गया। ये केंद्र परमाणु विज्ञान केंद्र, ज्योतिष और खगोल भौतिकी के क्षेत्र में अंतर विश्वविद्यालय केंद्र, पूरा अंतर विश्वविद्यालय सहकारिता, इंटीर स्पष्टिक विकास केंद्र अनाविश्वविद्यालय के अलावा है।

समाचार माध्यम और शैक्षिक अतिथि

6.1.25 "देशव्यापी कक्षाकक्ष" का दूरदर्शन द्वारा प्रसारण करके विश्व-अनु. आयोग ने उच्च शिक्षा के लिए दिए गए समय का उपयोग करने में पहले की है। सातवीं योजना अवधि के दौरान आयोग पहले से ही कालेजों को चलायक रूप में रूपांतरित करने पर प्रयत्न कर रहा था। विश्व-अनु. आयोग की इन-स्टेड परियोजना के लिए एक भागी योजना तैयार की गई जिसमें उच्च शिक्षा के क्षेत्र से इन-स्टेड की समग्र सभाओं भावी अकादमी के लिए प्रशिक्षण किया जाएगा। आयोग इस समय पूरा विश्वविद्यालय, गुजरात विश्वविद्यालय (अहमदाबाद), (केन्द्रीय अखिली और विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद), जर्मिया मिलिया इस्लामिया (नई दिल्ली) जोधपुर विश्वविद्यालय, मद्राई

[illegible]

प्रौढ, सतत और विश्वास्य कार्यकर्ता

[illegible]

(क)	शामिल निम्नविद्यालय की संख्या	93
(ख)	शामिल कालेजों की संख्या	1284
(ग)	विश्वविद्यालय और कालेजों के माध्यम से प्रौढ शिक्षा केंद्रों की संख्या	17940
(घ)	कार्यलयक साक्षरता हेतु जन कार्यक्रम	93
	विश्वविद्यालय+ 1284 कालेज	
(फ)	निम्नलिखित के माध्यम से जनसंख्या शिक्षा विश्वविद्यालय और कालेजों से जनसंख्या शिक्षा कल्पना प्रौढ शिक्षा केंद्रों पर जनसंख्या शिक्षा समशी कार्यलय	1286
1	संलग्न शिक्षा कार्यक्रम	16780
(१)	जन शिक्षण निालयम	794
		1096

1.1.27 उपर्युक्त कार्यक्रमों की समीक्षा हेतु, एक उप-समिति का गठन किया गया। उप-समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

[illegible]

पुनर्गठित किया गया है तथा इसे प्रौढ़ और सतत शिक्षा के विभागों/केन्द्रों की सीमा से बाहर कर दिया गया है। विश्वविद्यालय/कॉलेजों के स्टाफ को प्रशिक्षण के अर्थशास्त्र विभाग में जारी रखने की सलाह दी गई।

छात्रवृत्ति और शिक्षावृत्ति

[illegible][illegible][illegible]

नल्पसंख्यक समुदायों में कमजोर वर्गों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में वास्ते शिक्षण कक्षाएं

1.32 विन्ध्य-आ-ने अल्पसंख्यक समुदायो में कमजोर वर्गों के लिए निम्नोरी परीक्षाओं के वास्ते शिक्षण कक्षाएँ आयोजित करने हेतु केंद्रों विद्याविद्यालय और कलेज) को सहायता देना परकार रखा है।

[illegible]

महिला अध्ययन

6.1.34 आयोग विश्वविद्यालयों को महिला अध्ययन में अनुसंधान के लिए सुसज्ज परियोजनाएं शुरू करने तथा अवर-स्नातक व उतर-स्नातक स्तरों पर पाठ्यविवरण के विकास एवं संगत विस्तार कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता देता रहा है।

6.1.35 आयोग ने सामाजिक विज्ञान तथा इकोनॉमिक्स और प्रौद्योगिकी सहित विज्ञान और मानविकी में महिला उम्मीदवारों के लिए अंतराकाशिक अनुसंधान एसोसिएट शिक्षा के 40 पदों का भी सृजन किया है। दिसम्बर 1991 तक सहायता के लिए महिला अध्ययन के विषयों से संबंधित उन्नत अनुसंधान परियोजनाएं अनुमोदित की हैं। महिला अध्ययन स्थायी समिति ने 21 विश्वविद्यालयों और 11 कालेजों/विश्वविद्यालय विभागों को महिला अध्ययन/सेल स्थापित करने के लिए सहायता की सिफारिश की।

संशोधित मार्गदर्शी रूपरेखाएं

6.1.36 आठवीं योजना अवधि के दौरान, कालेजों के विकास और योजनाओं जैसे शिक्षक शिक्षावृत्ति, न दिए गए अनुदान, आयोजना फोरम और भारतीय लेखों द्वारा विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तकों को तैयार करने के लिए, वर्ष के दौरान, नई मार्गदर्शी रूप रेखाएं तैयार की गई थीं और निर्धारित की गई थी।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (आई-जीएन-ओ-यू)

6.2.1 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सितम्बर, 1985 में की गई थी जिसका उद्देश्य देश की शिक्षा पद्धति में मुक्त विश्वविद्यालय व दूरस्थ शिक्षा पद्धति का शुरू करना व बढ़ावा देना है तथा पद्धतियों में सत्रों का समन्वय निर्धारण करना है। इस विश्वविद्यालय के प्रमुख लक्ष्यों में, जनसंख्या के बड़े हिस्से विशेषकर अभुविधा प्राप्त वर्गों को उच्चतर शिक्षा के व्यापक अवसर प्रदान करना, सतत शिक्षा कार्यक्रमों का आयोजन करना और विशेष लक्षित वर्गों यथा महिलाओं, पिछड़े क्षेत्रों व पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उच्चतर शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेष कार्यक्रमों का आयोजन शामिल है।

6.2.2 इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, शैक्षिक तथ्यों व गति के सबध में लचीली व मुक्त विश्वविद्यालय स्तरीय शिक्षा, पाठ्यक्रमों के संयोजन, नामांकन के लिए अर्हता प्रवेश-आयु, मूल्यांकन तरीकों आदि की नवावारी प्रणाली की व्यवस्था करता है।

6.2.3 विश्वविद्यालय ने समकित बहु-माध्यम शैक्षिक कार्यनीति को अपनाया है जिसमें मुद्रित सामग्री, दृश्य-श्रव्य सहायक सामग्री, शिक्षकों प्रणाली, सपर कक्षाएं तथा प्रीम्पकलोन स्कूल शामिल हैं। विश्वविद्यालय ने सतत आंतरिक मूल्यांकन की प्रणाली को अपनाया है।

शैक्षिक कार्यक्रम

6.2.4 विश्वविद्यालय ने 1987 में अपने शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रारम्भ किया था और अब तक 16 कार्यक्रम प्रारम्भ किए जा चुके हैं। इन कार्यक्रमों में आहार व पोषाहार में प्रमाणपत्र-पाठ्यक्रम, स्नातक उपाधि के लिए तैयारी कार्यक्रम, प्रबंध, दूरस्थ शिक्षा-अंग्रेजी में सर्जनात्मक लेखन, व कम्प्यूटर अनुप्रयोग, प्राचीन विकास एवं विकास एवं उच्चतर शिक्षा में डिप्लोमा कार्यक्रम तथा कला/वणिज्य/विज्ञान तथा पुस्तकालय व सूचना विज्ञानों में

स्नातक-उपाधि कार्यक्रम के साथ-साथ व्यवसाय प्रशासन में मास्टर डिग्री शामिल है। विश्वविद्यालय ने अभी तक 900 पुस्तिकाएं प्रकाशित की हैं जिनमें पाठ्यक्रम सामग्री शामिल है और इनके अनुसूचक के रूप में, इसने 410 से अधिक दृश्य और 300 श्रव्य कार्यक्रम तैयार किए हैं।

6.2.5 1991-92 के दौरान इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में विभिन्न अध्ययन कार्यक्रम के लिए पंजीकृत छात्रों की कुल संख्या 60,280 थी। इसके साथ विश्वविद्यालय में छात्रों का कुल नामांकन 1.64 लाख से अधिक पहुंच गया है। विश्वविद्यालय ने मौजूदा कार्यक्रमवार पंजीकरण को अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया है। प्रारंभ में, जनवरी, 1992 से शुरू हुए प्रबंध कार्यक्रम में पाठ्यक्रमवार पंजीकरण लागू किया गया है। उन छात्रों की संख्या, जिन्होंने 31-3-91 तक अपने अध्ययन कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरे कर लिए थे, 8476 थी।

कर्मचारी

6.2.6 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने अब तक लगभग 160 शिक्षकों तथा करीब 900 तकनीकी, व्यावसायिक, प्रशासनिक और सहाय्यक कर्मचारियों की पत्तों को है। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय लगभग 250 समन्वयक तथा सहायक समन्वयकों और 6500 से अधिक शैक्षिक परामर्शदाताओं को अंतराकाशिक आधार पर सेवाओं का उपयोग कर रहा है।

छात्र सहयोग सेवाएं

6.2.7 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने एक व्यापक छात्र सहयोग सेवा नेटवर्क तैयार किया है जिसमें देश के विभिन्न भागों में स्थित 16 क्षेत्रीय केंद्र और 171 अध्ययन केंद्र शामिल हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के अध्ययन केंद्र में निम्नलिखित सेवाओं की व्यवस्था है —

- विशेष शैक्षिक कक्षाएं, समस्या का निदान करने वाले सत्र, आदि,
- सूचना, परामर्श और मार्गदर्शन,
- पुस्तकालय सुविधाएं,
- श्रव्य-दृश्य सुविधाएं,
- छात्र की सभी शैक्षिक सामग्री प्राप्त करता है और उनके मूल्यांकन की व्यवस्था करता है।

मुक्त विश्वविद्यालय तथा सुदूर शिक्षा पद्धति की प्रोन्नति और उसका समन्वय

6.2.8 किसी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के कार्यों के निष्पादन के अतिरिक्त, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय देशभर में सुदूर शिक्षा में सत्रों के समन्वय और उनके निर्धारण का शीर्षस्थ निकाय है। इस कार्य के निष्पादन के लिए, विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड ने शिक्षा विभाग तथा वि० अ० आ० के परामर्श से डॉ० गा० रा० मु० वि० अधिनियम के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय के रूप में एक सुदूर शिक्षा परिषद (डी० ई० सी०) स्थापित करने का निर्णय किया है।

6.2.9 डॉ० गा० रा० मु० वि० के कुलपति डॉ० ई० सी० की अध्यक्षता करेंगे और इसमें विश्वविद्यालय प्रबंध बोर्ड, शिक्षा विभाग, वि० अ० आ०, राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों और परम्परागत विश्वविद्यालयों में पत्राचार अध्ययन सस्थानों के प्रतिनिधि और कुछेक प्रख्यात शिक्षाविद शामिल होंगे।

6.2.10 डॉ० ई० सी० देश में मुक्त विश्वविद्यालयों तथा अन्य सुदूर शिक्षा

संस्थाओं का एक नेटवर्क तैयार करने के उपाय करेगा। देश में मुक्त विश्वविद्यालय तथा सुदूर शिक्षा पद्धतियों के स्तरों की प्रोत्ति, समन्वय तथा अनुसंधान के अपने प्रमुख कार्यों के अतिरिक्त, डी० ई० सी० को राज्य विश्वविद्यालयों तथा परम्परागत विश्वविद्यालयों के पत्राचार अध्ययन संस्थानों की वित्तीय सहायता उपलब्ध करने की जिम्मेवारी भी सौंपी जाएगी।

प्रसारण

6.2.11 20 मई, 1991 से दूरदर्शन द्वारा इ० गा० रा० मु० वि० के कार्यक्रमों का प्रसारण शुरू होना, वर्ष 1991-92 के दौरान एक प्रमुख उपलब्धि थी। दूरदर्शन प्रत्येक सोमवार बुधवार तथा शुक्रवार को प्रातः 6.30 बजे से आधे घंटे का एक कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है।

समाचार पत्रिका

6.2.12 इ० गा० रा० मु० वि० ने 1992 में भारतीय मुक्त अध्ययन पत्रिका नामक एक व्यावसायिक पत्रिका शुरू करने का निर्णय किया है।

दौक्षान्त समारोह

6.2.13 विश्वविद्यालय ने अप्रैल, 1991 में अपना दूसरा दौक्षान्त समारोह आयोजित किया जब 3276 छात्रों को डिप्लोमा प्रदान किए गए थे। डा शंकर दयाल शर्मा, भारत के उप-राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे।

आर्थिक सहायता प्रदान करना

6.2.14 1991-92 के दौरान धारण मरकम ने इ० गा० रा० मु० वि० को इसके विकास तथा अनुसंधान के लिए ५.२० करोड़ रु० प्रदान किए हैं। इसमें योजनाएँ निधियों के रूप में 7.76 करोड़ रु० का प्रावधान शामिल है।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय

6.3.1 अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1921 में की गई थी, एक प्रमुख केन्द्रीय विश्वविद्यालय है। यह विश्वविद्यालय अपने आवासीय स्वरूप के लिए विख्यात है। इसमें 13 आवासीय हॉल हैं जिनमें दो महिलाओं के लिए शामिल हैं। इसमें 55 छात्रावास सम्मिलित हैं। इस विश्वविद्यालय में कुल 19630 छात्रों का नामांकन है जिनमें स्त्रियों में नामांकित छात्र भी शामिल हैं। 21 देशों का प्रतिनिधित्व कर रहे विदेशी छात्रों की नामांकित संख्या 367 है।

6.3.2 विश्वविद्यालय की संकाय संख्या 1162 है। गर शिक्षण कर्मचारियों की संख्या 5177 है।

6.3.3 विश्वविद्यालय ने शिक्षण और परीक्षा के निर्धारित कार्यक्रम को समय पर पूरा करने का प्रबंध किया। मृत्युका कार्य को वाक्षणीय चिन्तित पठन जांच पद्धति की सहायता में आधुनिक बनाया गया था। इसके अतिरिक्त प्रवेश और परीक्षा कार्य के संगणकीकरण की योजना तैयार की गई है जिसके लिए आवश्यक यंत्र प्राप्त किए गए हैं।

6.3.4 भारतीय भाषाओं और संस्कृति का हाल ही में स्थापित तुलनात्मक अध्ययन केन्द्र तुलनात्मक भारतीय माहित्य में एम० फिल० तथा पी० एच० डी० कार्यक्रम के अतिरिक्त भारतीय साहित्य में उत्तर एम० ए० डिप्लोमा शुरू करने का प्रस्ताव कर रहा है।

6.3.5 शारीरिक स्वास्थ्य और खेल शिक्षा विभाग की स्थापना वर्ष

1990-91 के दौरान की गई थी। हाल ही में स्थापित नीति अध्ययन केन्द्र ने नीति अध्ययन में पी० एच० डी० और उत्तर एम० ए० डिप्लोमा शुरू किया है।

6.3.6 भौतिक और वनस्पति विभागों, को वि० अ० आ० द्वारा एक विशेष सहायता विभाग के रूप में मान्यता जारी रही। वि० अ० आ० ने अनुसंधान योजना विभाग का विस्तार प्राणीविज्ञान विभाग में किया।

6.3.7 नवसृजित संग्रहालय विद्या विभाग संग्रहालय विद्या में उत्तर एम० एस्स० सी० डिप्लोमा संचालित करता है।

6.3.8 1991-92 के दौरान, वाणिज्य विभाग ने मास्टर डिग्री, अर्थात् वित्त तथा नियंत्रण का मास्टर और पर्यटन प्रशासन का मास्टर हेतु व्यावसायिक अध्ययन केन्द्रों को नये कार्यक्रम भी शुरू किए।

6.3.9 संगणक विज्ञान विभाग अनेक पाठ्यक्रम अर्थात्, एम० सी० ए०, पी० डी० सी० ए०, डी० सी० पेनल इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा प्रोसेसिंग में पाठ्यक्रम संचालित कर रहा है। मेकेनिकल इंजीनियरी विभाग ने चालू सत्र के दौरान विभिन्न नए पाठ्यक्रम शुरू किए और नई प्रयोगशालाएँ स्थापित की।

6.3.10 आर्थोपेडिक सर्जरी विभाग ने भारतीय आर्थोपेडिक संघ का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया जिसमें देश के सभी भागों से प्रख्यात आर्थोपेडिक सर्जनों और शिक्षकों द्वारा व्याख्यान दिए गए थे।

6.3.11 वर्ष के दौरान, बालक और बालिका कालेजों के भवन, वाणिज्य संकाय, कला भवन और इन्क्वैरी कल इंजीनियरी विभाग का विस्तार जैसे प्रमुख निर्माण कार्य पूरे किए गए थे।

6.3.12 500 बिस्मर वाले जे० एन० चिकित्सा कालेज अस्पताल में एक डायरिखा उपचार और प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया गया था। विश्वविद्यालय ने इलमल अडविषा विभाग में एक मादक वस्तु संग्रहालय स्थापित किया। विश्वविद्यालय का एक औषध विज्ञान प्रयोगशाला और एक पशुगृह निर्मित करने का भी प्रस्ताव है।

6.3.13 प्रयुक्त रसायन शास्त्र विभाग का निम्नलिखित दो नये पाठ्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है—

(1) पर्यावरण विज्ञान में एम० एस्स० सी० (तकनीकी) पाठ्यक्रम।

(2) संस्कारण व इंजीनियरी में एम० टेक० पाठ्यक्रम।

6.3.14 अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय महिला कालेज को आठवीं योजना प्रस्तावों के अंतर्गत पहली प्राथमिकता के रूप में भवन, उपकरण व अन्य आवश्यकताओं के लिए पचास लाख रु० सन्निहित किए गए। कैरियर योजना केन्द्र, कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, कोम्पैक्ट टेक्नोलॉजी, ब्यूटी कल्चर आदि चला रहा है। केन्द्र ने घरेलू महिलाओं के लिए लघुकालिक कुशलता प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आरंभ किए हैं।

6.3.15 विश्व० अनु० आ० ने पुस्तकालय विज्ञान विभाग का शैक्षिक स्टाफ कालेज के अंतर्गत लेक्चरर/पुस्तकालय अध्यक्ष हेतु पुनर्धर्मा पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए देश के तीन केन्द्रों में से एक के रूप में चयन किया है।

6.3.16 अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का मौलाना आजाद पुस्तकालय छात्रों, संकाय सदस्यों व अन्यो हेतु प्रतिदिन 18 घंटे की पुस्तकालय सेवा प्रदान करता है। 31.10.90 तक कुल 8,02,770 पुस्तकें थीं। इसके

निहित विश्वविद्यालय के पास विभिन्न भाषाओं में दुर्लभ व मूल्यवान पुस्तकालय हैं।

3.17. सिविल इंजीनियरी विभाग, संस्थानिक नेटवर्क योजना के अंतर्गत ग्र. क्वालिटी मोनिटरिंग प्रयोगशाला के विकास हेतु मानव संसाधन विकास मंत्री से अनुदान प्राप्त कर रहा है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरी प्रयोगशाला, नामपुर योजना के निष्पादन में सहायता कर रही है।

3.18. इलेक्ट्रोनिक्स विभाग ने निम्नलिखित दो परियोजनाओं के अंतर्गत दशोर्गी सुविधाएं सफलतापूर्वक कार्यान्वित व विकसित की हैं —

(क) माइक्रोप्रोसेसर ऐप्लिकेशन में अतःश्रेणी शोध व शिक्षा केन्द्र

(ख) आई सी डिजाईन व इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में शिक्षा व शोध केन्द्र

3.19 शिक्षण व भाषादर्शन केन्द्र छात्रों को विशेष रूप से शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयार करने के लिए उचित शिक्षण कार्यक्रम चला रहा है।

3.20 प्रो. जिआकल हसन, प्रधानाध्यापक विश्वविद्यालय पोलिटेक्निक ने तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान चंडीगढ़ ने वर्ष 1991 के लिए एट अकेडेमिक एवार्ड से सम्मानित किया।

3.21 आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत विश्व अनु. आयोग ने अभी तक इंजीनियरी व प्रौद्योगिकी संकाय तथा आधुनिक संकाय को क्रमशः 275 लाख रु. व 585 लाख रु. के अतिरिक्त 721 लाख रु. का मुदान सस्वीकृत किया है।

3.22 चालू वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय का अनुमानित योगनेतर व्यय 1936 लाख रु. था। पिछले वर्ष के दौरान वास्तविक व्यय 3611 लाख रु. था।

नारस हिन्दू विश्वविद्यालय (बी. एच. यू.)

3.41 नारस हिन्दू विश्वविद्यालय एक शिक्षण तथा आवासीय विश्वविद्यालय के रूप में 1916 में अस्तित्व में आया। इसमें 114 विभागों सहित 3 संस्थान तथा 14 संकाय हैं। इसके अलावा इसका एक घटक कालेज तथा चार कालेज विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार में हैं। विश्वविद्यालय के परिसर में 1000 बिस्तरों वाला आधुनिक अस्पताल है। विश्वविद्यालय में लगभग 13,000 छात्र दाखिल हैं। इसके शिक्षण तथा प्रशिक्षण स्टाफ की संख्या क्रमशः लगभग 1281 व 6350 है। श्री वेणुति नाथन सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति तथा प्रो. आर. पी. सोनी विश्वविद्यालय के कुलपति हैं।

3.42 वर्ष के दौरान विभिन्न संकायों के कुछ अध्यापकों को उनके अपने-अपने अनुसंधान/विद्वत्ता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मान/पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुषम जीवविज्ञान के प्रो. एस. पी. सन्याल का पंचल कालेज आफ पैथोलॉजिस्ट, लंदन के अध्यापक के रूप में चयन किया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रो. ए. के. बनर्जी (पत्रकारिता व सभ्यता), प्रो. एच. सी. नेथर (उर्दू), प्रो. पी. सी. सूद (भौतिकी), प्रो. आर. पी. द्विवेदी (प्राच्य अध्ययन व धर्म विज्ञान) व प्रो. के. पी. श्रीवास्तव (प्राणि विज्ञान) को सेवामुक्त अध्यापक के रूप में नियुक्त किया। सी. एस. आई. आर. ने प्रो. ओ. पी. मल्होत्रा (रसायन विज्ञान) प्रो. एस. एस. कनुंगू (प्राणि विज्ञान) प्रो. से. जे.

ओमिनिक (प्राणि विज्ञान) व प्रो. डी. पी. वर्मा (सूक्ष्म जीव विज्ञान) को सेवा मुक्त वैज्ञानिक के रूप में नियुक्त किया गया। प्रो. सी. एम. जयवाला (विधि) को पर्यावरण विधि आयोग, स्विट्जरलैंड का सदस्य नियुक्त किया गया।

6.4.3 विश्वविद्यालय के कुछ संकाय सदस्यों को देश के विभिन्न संगठनों/विभागों में महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया गया। प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रो. पी. रामाव को विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार में सचिव नियुक्त किया गया है। प्रो. बी. बी. घर को घनबाद में सी एस आई आर के केंद्रीय खान शोध स्टेशन का निदेशक नियुक्त किया गया है। प्रो. डी. पी. सिंह (खान इंजीनियरी) को अवध विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। प्रो. आई. सी. तिवारी (निरीधक सोशल मेडिसन) को (स्वास्थ्य) योजना आयोग में सलाहकार नियुक्त किया गया है।

6.4.4 विश्वविद्यालय का प्लेटिनम जयन्ती समारोह का 20 जनवरी, 1991 को आरंभ किया गया। समारोह को महत्व देने के लिए सूचना मंत्रालय ने विशेष सम्मार्क टिकट निकाली। आलोच्य वर्ष के दौरान समारोह के भाग के रूप में कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय भाषण, सेमिनार व सम्मेलन आयोजित किए गए।

6.4.5 विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल अस्पताल के प्रत्येक बिस्तर का वार्षिक रखरखाव अनुदान 1,10.91 से 6,000 रु. से बढ़कर 12,000 रु. कर दिया गया था। खेल विकास योजना के अंतर्गत 88.15 लाख रु. की लागत पर हाल के निर्माण के लिए युवा कार्यकलाप व खेल विभाग ने 52.20 लाख रु. का अनुदान अनुमोदित किया था।

6.4.6 नेपाल के प्रधानमंत्री श्री जी. पी. कोइराला को डाक्टरेट आफ लॉ की सम्मानार्थ डिग्री प्रदान की गई।

6.4.7 भारतीय विश्वविद्यालय सच ने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के प्लेटिनम जयन्ती समारोह के भाग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय राष्ट्रीय युवा उत्सव 1991-92 आयोजित करने का विश्वविद्यालय का अनुरोध स्वीकार कर लिया है। राष्ट्रीय प्रभोचरी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रौद्योगिकी संस्थान के दो छात्रों को नियुक्त किया गया था। विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय स्वयं सेवी छात्र दल ने इम्फाल में आयोजित राष्ट्रीय संघटन कैम्प में भाग लिया। विश्वविद्यालय ने नेहरूभारत विश्वविद्यालय में आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय युवा उत्सव में 4 स्वर्ण पदक प्राप्त किए।

6.4.8 विश्वविद्यालय ने पूर्वी क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कबड्डी टूर्नामेंट उ० प्र० अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, पूर्वी अंचल (बी) अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बास्केटबाल टूर्नामेंट अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खो-खो (महिला) टूर्नामेंट, उ० प्र० अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय फुटबाल टूर्नामेंट व उ० प्र० अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय तैराकी टूर्नामेंट जीते।

6.4.9 विश्वविद्यालय का वर्ष 1991-92 का प्रत्याशित रखरखाव अनुदान 1990-91 के दौरान 44.85 करोड़ रु. के व्यय के स्थान पर 48.02 करोड़ रु. था।

दिल्ली विश्वविद्यालय

6.5.1 उच्च शिक्षा के प्रमुख संस्थान के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय देश के विभिन्न भागों के साथ-साथ विदेशों से भी छात्रों को आकर्षित करता है। वर्ष 1991-92 के दौरान कुल 1,83,792 छात्र नामांकित थे। इसमें से

विभिन्न कालेजों, संकायों व विश्वविद्यालय के विभागों में 1,05,379 नियमित छात्र थे। महिला शिक्षा बोर्ड में 11,792 गैर-कालेजीय छात्र नामांकित थे तथा 55,000 पचास पाठ्यक्रम व सतत शिक्षा स्कूल में तथा 11,615 बाह्य उम्मीदवार सेल (प्राइवेट छात्र) में।

6.5.2 वर्ष के दौरान दो नए कालेज एक यमुना पर क्षेत्र में डा० भीमपुत्र अम्बेडकर कालेज तथा दूसरा (जोक्नी) गांव में आचार्य नेत्र दत्त कालेज के नाम से कार्य करना आरंभ कर चुके हैं। प्रौद्योगिकी संकाय के अधीन उत्पादन व उद्योग इंजीनियरी विभाग व इंस्ट्रुमेंटेशन व कंट्रोल इंजीनियरी विभाग के नाम से दो नए विभाग आरंभ किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान विभिन्न संकायों तथा विभिन्न स्तरों पर कई नए पाठ्यक्रम आरंभ किए गए हैं।

6.5.3 विश्वविद्यालय के संकाय में 258 प्रोफेसर, 318 रीडर, 165 लेक्चरर व 18 शोध एसोशियेट हैं जिससे कुल संख्या 759 हो गई है।

वर्ष 1991-92 के दौरान विश्वविद्यालय के निम्नलिखित संकाय सदस्यों को गौरवशाली सम्मान/पुरस्कार प्रदान किए गए:—

- i) प्रो० आर० एन० सक्सेना को क्रमशः प्राणीविज्ञान तथा चिकित्सा विज्ञान क्षेत्रों में उनके महत्वपूर्ण योगदान को ध्यान में रखते हुए भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा एफएनएन और राष्ट्रीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का हरि ओम न्यास पुरस्कार प्रदान किया गया।
- ii) प्रो० पी० बी० मंगला को राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तकालयाध्यक्षता के ग्रांत्साहन के लिए उनके अभिनव और उत्कृष्ट योगदान के लिए आईएफएएलएन स्वर्ण पदक और प्रमाण पत्र प्रदान किया गया।
- iii) प्रो० सुभाष चक्रवर्ती को "वी० के० मेनन और भारतीय संघ" पर कार्य करने हेतु दो वर्ष के लिए नेहरू शिक्षावृत्ति प्रदान की गई।

6.5.4 विश्वविद्यालय ने वर्ष 1991-92 के दौरान डा० अरुण गोज, राष्ट्रीय, गणतन्त्र को डी० लिट० की सामानिक उपाधि प्रदान करने के लिए एक विशेष दीक्षा समारोह का आयोजन किया।

6.5.5 वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय के छात्रों ने खेलों के मैदान में श्रेष्ठता दिखाई। विश्वविद्यालय ने क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए तीसरे वर्ष लगातार मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जीती।

6.5.6 शिक्षकों, छात्रों और कर्मचारियों के सक्रिय सहयोग से विश्वविद्यालय ने उत्तर काशी के लिए भूकम्प सहायता कोष स्थापित किया।

6.5.7 वर्ष 1991-92 के लिए विश्वविद्यालय का अनुसंधान व्यय वर्ष 1990-91 के 25.92 करोड़ रु० के व्यय की तुलना में 31.55 करोड़ रु० है।

हैदराबाद विश्वविद्यालय

6.6.1 हैदराबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1947 में एक संसद अधिनियम द्वारा की गई थी। इसमें स्नातकोत्तर व अनुसंधान अध्ययन के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। वर्ष के दौरान, 872 छात्रों को देश के 13 पित्र पित्र केन्द्रों पर आयोजित प्रवेश परीक्षा के परिणाम के आधार पर विश्वविद्यालय में दाखिला दिया गया। वर्ष के दौरान छात्रों का कुल नामांकन 1820 था जिसमें 246 अ० जा०, 45 अ० ज० जा० तथा 22

विकलांग अभ्यार्थी शामिल हैं। वर्ष के दौरान महिला छात्रों की संख्या 696 थी जो कि कुल छात्रों का लगभग 38% है।

6.6.2 प्रो० बी० एच० कृष्णामूर्ति को 11.6.1991 से दूसरी अवधि के लिए पुनः कुलपति नियुक्त किया गया।

6.6.3 विश्वविद्यालय के शिक्षक संकाय में 72 प्रोफेसर, 69 रीडर व 63 लेक्चरर थे। शिक्षण कर्मचारियों की संख्या 1041 है।

6.6.4 वर्ष के दौरान, योग्यता छात्रवृत्तियों (55) तथा योग्यता व साधन छात्रवृत्तियों (215) के माध्यम से विश्वविद्यालय के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई, इसके अतिरिक्त, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा (76) तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा (170) अनुसंधान वृत्ति छात्रों की अनिवार्य शोध अध्यापकता प्रदान की गई। वर्ष के दौरान यू०जी०सी०, सीएस०आई०आर०, आईसीएस०आर०, डीएसटी०डी०एच०, आईसीएस०आर० आदि ने विश्वविद्यालय की 89 अनुसंधान परियोजनाओं को लगभग 3.76 करोड़ रु० दिए।

6.6.5 वर्ष के दौरान, कार्यकारी परिषद की पाच बैठकें तथा शैक्षिक परिषद की दो बैठकें हुईं। कोर्ट की वार्षिक बैठक 7 12 91 को आयोजित हुई।

6.6.6 विश्वविद्यालय ने 308 छात्रों के लिए 1 30 करोड़ रु० को अनुमानित लागत वाले छात्रावास के निर्माण का कार्य आरंभ किया जिसका शिलान्यास मानव ससाधन विकास मंत्री ने किया।

6.6.7 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय के विकास हेतु आठवीं योजना के लिए 9.88 करोड़ रु० के नियतन की स्वीकृति दी है।

जामिया मिलिया इस्लामिया

6.7.1 जामिया मिलिया इस्लामिया, जो 1962 से विश्वविद्यालय समस्या के रूप में कार्य कर रही थी, को 26 दिसम्बर, 1988 से एक संसद अधिनियम द्वारा एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय का स्तर प्रदान किया गया। विश्वविद्यालय नर्सरी स्तर से स्नातकोत्तर तथा शोध स्तरों तक सम्बन्धित शिक्षा प्रदान करता है।

6.7.2 वर्ष 1990-91 में छात्रों की संख्या 7,935 थी जिसमें से पूर्व स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र की संख्या 5,239 थी (पुरुष 3724 तथा महिला 1515), अ०जा०, अ०ज०जा० और पिछड़े वर्गों के छात्रों की संख्या क्रमशः 410, 34 और 108 है। 21 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले विदेशी छात्रों की संख्या 144 है। शिक्षण कर्मचारियों की संख्या 358 और शिक्षण कर्मचारियों की संख्या 890 है।

6.7.3 विश्वविद्यालय में 27 विभागों सहित छः संकाय हैं। इसमें 14 छात्रावास हैं जिसमें 907 छात्र रहते हैं। जामिया में कामकाजी महिलाओं के लिए भी एक छात्रावास है जिसमें 68 महिलाएं रह सकती हैं।

6.7.4 जन संचार अनुसंधान केन्द्र जन संचार, रेडियो, ब्रह्म-दृश्य और टेलीविजन तथा फिल्म निर्माण में कार्यक्रम और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की पेशकश करता है। यह वि० अ० आ० कर देखावटी कक्षा कार्यक्रम तैयार करता है। जिसे दूरदर्शन द्वारा प्रसारित किया जाता है। तथा सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के लिए दृश्य-श्रव्य कार्यक्रम तैयार करता है।

6.7.5 जामिया में प्रौढ़ तथा सतत शिक्षा एवं विस्तार विभाग, राज्य संसाधन केन्द्र बाल शिक्षा निर्देश केन्द्र, कोचिंग और कैरियर प्लानिंग केन्द्र

या बालक माता केन्द्र जैसी ओके, सक्रिय अनौपचारिक इकाइयों हैं। ग्रीड और सरत शिक्षा विभाग तथा विस्तार शिक्षा से जनसंख्या शिक्षा पर कार्यक्रम चलाने के अतिरिक्त विस्तार शिक्षा में एक आन्तरिक छिड़ी पाठ्यक्रम आरंभ किया है।

7.6 राज्य संसाधन केन्द्र भास्करों और नव साक्षरों के लिए पठन सामग्री तैयार करता है। जल दिशा निर्देश केन्द्र बच्चों, अधिपाठकों, कौशर और बालिकाओं, शिक्षकों और व्यावसायिकों के लिए विकासालय काई संभल करता है। कोलिंग एंड केरियर प्लानिंग केन्द्र सेन्ट्रोलेन्डोआ, जय संकारी, सार्वजनिक और निजी उपक्रमों द्वारा आयोजित विभिन्न नियोजी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए सुव्यवस्थित कोचिंग की व्यवस्था करता है। जाधिया के छात्रों के लिए प्रतीक पुस्तकी दिल्ली क्षेत्र में रह रहे भविष्य कवित वर्गों के बच्चों और महिलाओं को शिक्षा प्रदान करते हैं।

6.7 जाधिया मिलिया इस्लामिया में विश्वविद्यालय/कालेज शिक्षकों हेतु अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए एक एकेडेमिक स्टाफ कालेज की स्थापना की है। विश्वविद्यालय का डा० जाकिर हुसैन इस्लामी अध्ययन संस्थान आयुक्त विश्व की समस्याओं के समाधान पर विशेष बल सहित इस्लाम की तर्क संगत संमेल को बढ़ावा देता है। तृतीय विश्व अख्यत अकादमी तीसरी दुनिया के देशों के सामाजिक, आर्थिक अध्ययन के लिए अनुसंधान सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं।

6.7.8 जाधिया फ्रेंच, रूसी, गुलार्गियाई जैसी विदेशी भाषाओं के लिए शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। जाधिया राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यालय करता है जो छात्रों से सामाजिक जागरूकता पैदा करती है। विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों से संबंधित छात्रों तथा ऐसी गतिविधियों में सहभागिता की भावना उत्पन्न करने के लिए एलसीसी कार्यक्रम भी चलाता है। 'सौर्य विज्ञान' जाधिया के बीएए (ऑनर्स) पाठ्यक्रम का एक गौण विषय है।

6.7.9 जाधिया में एक केन्द्रीय पुस्तकालय है जिसमें 2 लाख से अधिक पुस्तकों का संग्रह है। विश्वविद्यालय में हाल ही में पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में एक आत्मिक डिग्री पाठ्यक्रम आरंभ किया है।

6.7.10 वर्ष 1991-92 के लिए विश्वविद्यालय का अनुमानित अनुसंधान खर्च, वर्ष 1990-91 के 692 लाख रु० की तुलना में 805 लाख रु० है।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली (जेएनयू)

6.8.1 जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1966 में सरदर के एक अधिनियम के तहत की गयी थी। विश्वविद्यालय में 7 स्कूल और 24 अध्ययन केन्द्र हैं। इसके अलावा इसमें एक जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र भी है। विश्वविद्यालय में लगभग 3800 छात्र सम्मिलित हैं। इसके अध्ययन और गैर अध्ययन कार्यक्रमों की संख्या लगभग 375 और 1347 है। प्री पी-एल हस्तक्षेप विश्वविद्यालय के कुलाधिपति तथा प्रो० एम० एस० अम्बानी कुलपति हैं।

6.8.2 शैक्षिक वर्ष 1990-91 के दौरान, विश्वविद्यालय के विभिन्न स्कूलों/केन्द्रों द्वारा 12 राष्ट्रीय अन्तर्देशीय सेमिनारों/संवेदन-कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था।

6.8.3 निम्न स्कूलों के संकय सदस्यों द्वारा 38 अनुसंधान

परियोजनाएं पूर्ण कर ली गई थीं जिनमें 91 परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर था। ये परियोजनाएं केन्द्रीय संकय सहित विभिन्न राष्ट्रीय/अन्तर्देशीय प्रौद्योगिकी द्वारा आयोजित की गईं। विश्वविद्यालय के संकय सदस्यों द्वारा भारतीय तथा विदेशी दोनों पत्रिकाओं में (55 पुस्तकें/समाहित खंड तथा 323 लेख प्रकाशित किए गए थे। इसके अतिरिक्त, विभिन्न पुस्तकों में 155 अध्याय जोड़े गये।

6.8.4 जवाहरलाल नेहरू पुस्तकालय की सदस्यता 4,020 है। वर्ष के दौरान लगभग 50,000 लिपिग्रन्थ तथा 11,781 खंड और बंधाए गए हैं। अब पुस्तकालय में खंडों और लिपिग्रन्थ का कुल संग्रह लगभग 4 लाख और 8 लाख है।

6.8.5 विश्वविद्यालय के अकादमिक स्टाफ कालेज द्वारा राजनीति शास्त्र, अधिशास्य तथा समाजविज्ञान में छा० पुनर्वास पाठ्यक्रम तथा एक अनुसंधान पाठ्यक्रम आयोजित किए गए। इन पाठ्यक्रमों में 219 शिक्षकों ने भाग लिया। विश्वविद्यालय ने प्रशासनिक स्टाफ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन किया था।

6.8.6 विश्वविद्यालय के पर्यवरण विज्ञान स्कूल में रेडिएशन भावीय, जिसमें आवृत्तियों के व्यापक वर्गों (0.2-10 जीएचएडि०) पर सूक्ष्मतरंगों का पता लगाने की क्षमता है का निर्माण, विकास तथा जांच का कार्य अभिलान्तरणक हो गया है। इस उपकरण का प्रयोग स्वीकृत सुरक्षा स्तर से बहुत नीचे के वैक्यूमम रेडिएशनों तथा सूक्ष्मतरंग आवृत्तों से रिमाल क्षेत्र को मापने के लिए भी किया जा सकता है।

6.8.7 विश्वविद्यालय विज्ञान उपकरण केन्द्र में विश्वविद्यालय के विभिन्न स्कूलों के लिए आवश्यकतापूर्वक इलेक्ट्रोफ्रेटिक उपकरणों, उच्च तापमान सेमलर जैबल तथा फोटो रिजोसिस उपकरणों का निर्माण किया।

6.8.8 आयुर्विज्ञान इजीनरिंग एवम् देश के विभिन्न भागों के बहुत से वैज्ञानिकों को रिकार्मिनेट खीयनए० तकनीकी में शामिल विभिन्न कार्यविधियों में मूल प्रशिक्षण प्रदान करता है। यह प्रशिक्षण उनमें से बहुतों को इस धारा से कि धारा में ऐसे "जटिल" प्रयोग किए गए जा सकते हैं जिनसे पाने से संभवता करता है। एकक द्वारा किए गए विभिन्न प्रयोगों से अतत फसल देने में सक्षम करते में सुधार होगा।

6.8.9 राष्ट्रीय जलसुचन्यात्मक केन्द्र की स्थापना जैव प्रौद्योगिकी विभाग के क्षेत्र में विश्वविद्यालय के जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र में वैज्ञानिकों की वैज्ञानिक सूचना आवश्यकताओं को जुटाने के लिए की गई। यह निम्न जैव, आन लार्डन और मेडलार्डन खाज सुविधाओं से सुसज्जित है। जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र स्कूलों बच्चों के माध्यम से वैज्ञानिक प्रकृति तथा जैव प्रौद्योगिकी के प्रति जागरूकता उत्पन्न करते का कार्य इनके संकय सदस्यों द्वारा आयुर्विज्ञान के विभाग परलुओं पर दिए जाने वाले व्याख्यान में उपस्थित होने का निमंत्रण देकर करता है।

6.8.10 विश्वविद्यालय में भारतीय सांस्कृतिक संसाधन केन्द्र के सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत अन्तर्देशीय अध्ययन स्मृती के क्षेत्र प्रश्रयन और अन्तराष्ट्रीय अध्ययन केन्द्र में नेलन मंडेला चैयर स्थापित करते का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है।

6.8.11 निम्न कार्य में सामान रूप से प्रगति होती रही। 200 छात्रों को के लिए छात्रावास प्रदान के निर्माण, खरीदारी केन्द्र, पर्यटन विज्ञान स्कूल, अर्थशास्त्र प्रशासन और प्रशासनिक, प्लांक के विस्तार कार्य को पूरा किया गया। प्रतिस्थापन आवास इकाइयों, सामुदायिक केन्द्र और

कर्मचारी क्लब का निर्माण कार्य पूरा होने वाला था। सम्मेलन स्थल और क्रीड़ा स्थल का निर्माण कार्य प्रगति पर था।

6.8.12 वर्ष 1991-92 के लिए विश्वविद्यालय का अनुमानित अनुरक्षण व्यय 15.50 करोड़ रुपये है जबकि 1990-91 में यह 13.52 करोड़ रुपये था।

उत्तरी पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय

6.9.1 उत्तरी पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय की स्थापना 1973 में संसद के एक अधिनियम द्वारा हुई थी। इसके अधिकार क्षेत्र में मेघालय, मिजोरम और नागालैंड के तीन राज्य भी आते हैं। विश्वविद्यालय का मुख्यालय शिलांग में है। वर्ष 1991-92 में छात्रों की संख्या 14,963 थी जिसमें स्नातकोत्तर छात्रों सहित 12,307 अवर-स्नातक, 397 शोध छात्र और 1346 विरिद्ध छात्र थे। विश्वविद्यालय के शिक्षण कर्मचारियों की संख्या 348 और शिक्षणोत्तर कर्मचारियों की संख्या 7,999 है।

6.9.2 डा० सी० एन० राव विश्वविद्यालय के कुलपति और प्रो० बैरिस्टर पोकेज नए उपकुलपति हैं। विश्वविद्यालय के कोर्ट का पुनर्गठन 8 मई, 1991 को हुआ था। विश्वविद्यालय का छठा सम्मेलन जुलाई, 1991 में सम्पन्न हुआ था।

शिलांग परिसर

6.9.3 विश्वविद्यालय ने परिसर विकास पर ध्यान केन्द्रित करना जारी रखा। 131.96 लाख के अनुमानित व्यय पर अनेक भवनों को पूरा किया गया है। गैस संयंत्र पशु आवास आदि जैसे नए कार्यों पर 32.40 लाख रुपये का अनुमानित व्यय हुआ।

6.9.4 विश्वविद्यालय ने पर्यावरण अध्ययन विज्ञान और संस्कृति में भारत-अमेरिकी चिंतनीय विषय पर एक सेमिनार आयोजित किया। अनेक विभागीय सेमिनार भी आयोजित किए गए।

मिजोरम परिसर

6.9.5 वर्ष 1991-92 में मिजोरम परिसर ऐजल के लिए भवनों तथा नए संकाय पदों से सम्बन्धित नई स्कीमों के लिए 191 लाख रुपये की कुल राशि आवंटित की गई थी।

नागालैंड परिसर

6.9.6 कृषि विज्ञान स्कूल और ग्रामीण विकास मेड्युमिफेमा, नागालैंड के लिए आठवीं योजना के अन्तर्गत कुल 50 लाख रुपये स्वीकृत किए गए थे।

6.9.7 वर्ष 1991-92 में योजनाएँ स्कीमों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय का अनुमानित व्यय 1035.00 लाख रु० और योजनागत स्कीमों के लिए 568.65 लाख रुपये बैठता है।

पांडिचेरी विश्वविद्यालय

6.10.1 पांडिचेरी विश्वविद्यालय की स्थापना संसद के एक अधिनियम द्वारा अक्टूबर, 1985 में एक शिक्षण-सम्बन्धन विश्वविद्यालय के रूप में हुई थी। इस विश्वविद्यालय के अधिकार-क्षेत्र में तमिलनाडु क्षेत्र पांडिचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आते हैं।

6.10.2 वर्तमान में विश्वविद्यालय के दो निदेशालय, छः स्कूल, तेरह विभाग और दस केन्द्र हैं। विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अठारह संस्थाएँ हैं

जिनमें से म्यारह पांडिचेरी, दो कराइकल में, एक एक माहे और यनम में तथा तीन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित हैं। विश्वविद्यालय दो प्रमाण-पत्र, एक अवर-स्नातक, तीन स्नातकोत्तर डिप्लोमा और सोलह स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, सत्रह विषयों में एम.फिल और डॉक्टरेल कार्यक्रम चलाती है। समय की दृष्टि से प्रासंगिक वैतनिक परियोजनाएँ चल रही हैं।

6.10.3 विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या 668 है। विश्वविद्यालय के पास 21 प्रोफेसरो, 37 रीडरों और 53 प्राध्यापकों का संकाय है। यहाँ शिक्षणोत्तर कर्मचारियों की संख्या 409 है।

6.10.4 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय को षष्ठी योजना आबंटन के रूप में अब तक 10.16 करोड़ रुपये की मजूरी दी है। आठवीं योजना के दौरान चार नए विभाग/केन्द्र प्रारंभ किए जाने हैं जो इस प्रकार हैं (i) जैव-प्रौद्योगिकी केन्द्र (ii) भू-विज्ञान विभाग (iii) समाज शास्त्र विभाग (iv) हिन्दी विभाग जैव-प्रौद्योगिकी विभाग ने इस विश्वविद्यालय में विंतरित सूचना उप केन्द्र स्थापित करने के लिए 5.83 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं।

6.10.5 विश्वविद्यालय का तीसरा दीक्षांत समारोह जनवरी, 1992 के प्रथम सप्ताह में संपन्न हुआ।

6.10.6 वर्ष 1990-91 के व्यय 2.76 लाख रुपये के मुकाबले वर्ष 1991-92 के दौरान अनुरक्षण व्यय 3.65 लाख होने का अनुमान है।

विश्व भारती

6.11.1 गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शिक्षा संस्था विश्व-भारती, विश्वभारती अधिनियम, 1951 द्वारा एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया।

6.11.2 श्री पी० वी० नरसिंह राव 23 दिसम्बर, 1991 से तीन वर्ष के लिए विश्व भारती विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त किए गए। प्रो० सत्यसाची भट्टाचार्य 10 दिसम्बर, 1991 से 5 वर्ष की अवधि के लिए विश्वविद्यालय के उपकुलपति नियुक्त किए गए।

6.11.3 विश्वविद्यालय के छात्रों की संख्या लगभग 5000 है। शिक्षण और शिक्षणोत्तर कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 493 और 1,670 थी।

6.11.4 शान्तिनिकेतन में नियम भवन स्थापित करने के लिए विश्वभारती विश्वविद्यालय के जापानी पुरा छात्र ने 20 लाख रु० का दान दिया ताकि भारतीय जापानी सांस्कृतिक विमिश्रण को बढ़ावा दिया जा सके। नियम भवन के निर्माण के लिए शिला-न्यास समारोह 16 सितम्बर, 1991 को आयोजित किया गया।

6.11.5 वर्ष के दौरान निर्माण परियोजनाओं में संतोषजनक प्रगति हुई इनमें शामिल हैं ईन्दु गोष्ठी राष्ट्रीय एकता केन्द्र के लिए स्थायी भवन का निर्माण, उत्तर शिक्षा सदन के लिए नये भवन और पूर्वपाली बाल छात्रावास के विज्ञान खंड के लिए रसोई घर का निर्माण। विश्वविद्यालय परिसर में भारतीय इस्पात प्राधिकरण (सेल) द्वारा निर्मित किए जा रहे अतिथि भवन का शिला-न्यास इस वर्ष के दौरान किया गया।

6.11.6 विश्वविद्यालय जन-साक्षरता के महत्वाकांक्षी उद्देश्य से जुड़ा रहा है। इसका उद्देश्य बीरभूमि के संपूर्ण जिले को शामिल करना है।

6.11.7 विश्वभारती ने अध्ययन के निम्नलिखित तीन पाठ्यक्रम प्रारंभ किए। (i) मानव विज्ञान में दो वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (ii) ग्राम विकास में दो वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (iii) स्कूल और कालेज के छात्रों के लिए

कार्यक्रम श्रृंखला के अन्तर्गत सुविधायन निर्दिष्ट वार्षिक ओरिन्स सिवर्ड स्कर्म ने दिल्ली, उत्तरा, लखनऊ, मद्रास, कलकत्ता और पाकिस्तानी विश्वविद्यालयों में व्याख्यान दिए। इसके अतिरिक्त विख्यात भारतीय दार्शनिक ओरिन्समर एन्के-चटर्जी ने लखनऊ, बम्बई और कालीकट की संस्थाओं/विश्वविद्यालयों में व्याख्यान दिए। वर्ष के दौरान परिवर्त ने अपने अकादमिक केंद्र, लखनऊ, एस्सीवी-विश्वविद्यालय, तिरुवनंति और हैदराबाद के केन्द्रीय विश्वविद्यालय में नीतिशास्त्र, समाज दर्शन और विश्वव्यापक दर्शनशास्त्र पर तीन पुस्तकें पाठ्यक्रम आयोजित किए। आई-सी-सी-आर के शिक्षार्थियों का एक समेलन अकादमिक केंद्र, लखनऊ में आयोजित किया गया।

6.15.4 परिवर्त ने कुछ दार्शनिक युगों पर संवाद को सुकर बनाने के लिए दिल्ली, बालौर और लखनऊ में कुछ विख्यात वार्षिकों और अन्य वार्षिकों को शिक्षार्थियों और शोधकर्तों के बीच एक बैठक आयोजित करते हुए "सीट द फिलॉसफ" कार्यक्रम प्रारंभ किया।

6.15.5 परिवर्त ने "सिख्य लीडर" आयोजित की जिनके अन्तर्गत दार्शनिकों को एक मंच पर एक साथ लाते हुए एक विख्यात वार्षिक के नवोदय प्रकाशन पर चर्चा की गई। इसने वार्षिक चर्चाओं और विभिन्न क्षेत्रीय केंद्रों पर विचार-विमर्शों का भी आयोजन किया।

6.15.6 लखनऊ में परिवर्त के पुस्तकालय के लिए दर्शनशास्त्र की अनेक पुस्तकों के अधिमध्य के अतिरिक्त परिवर्त ने जर्मन के तीन संस्कृत्य प्रकाशित किए। अपने प्रकाशन कार्यक्रम के अन्तर्गत परिवर्त ने वर्ष के दौरान भारतीय दर्शन के विभिन्न पहलुओं पर चार वाच्य प्रकाशित किए।

6.15.7 परिवर्त के अपने शैक्षिक कार्यक्रमों के अलावा, परिवर्त ने दर्शन के विभिन्न पहलुओं पर शैक्षिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए 14 विश्वविद्यालयों/संस्थाओं को वित्तीय सहायता बनाने का निर्णय किया है।

6.15.8 वैश्विक दार्शनिक और भारतीय सभ्यता की सांस्कृतिक गहराई जैसी कि यह अतीत में विकसित हुई और जो हमारे अपने समय में आधुनिक है के विषय और अतः आधुनात्मिक अध्ययन के समय में के वैश्य से परिवर्त आदर्श योजना कार्यक्रम के एक भाग के रूप में "भारतीय विज्ञान दर्शन और संस्कृति का इतिहास" शैक्षिक की परियोजना चला रही है।

भारतीय शैक्षणिक अनुसंधान परिवर्त

6.16.1 भारतीय शैक्षणिक अनुसंधान परिवर्त 1972 में एक स्वायत्त और औद्योगिकी, पुस्तक, पुस्तकालय, मुद्राशास्त्रीय और समाजिक संघटन संहिता इतिहास विभिन्न क्षेत्रों में किस्त सहायता प्रदान करने के लक्ष्य से परिवर्त आदर्श योजना कार्यक्रम के एक भाग के रूप में चला रही है। राष्ट्रीय आन्दोलन के अध्ययन पर विशेष बल दिया गया है।

6.16.2 आलोच्य अवधि के दौरान परिवर्त ने 27 शोध परियोजनाएं, 109 छात्रवृत्तियां और 79 अध्ययन-यात्रा अनुदान, शोध प्रबन्धों सहित शैक्षणिक कार्य लक्षित किए और प्रकाशन सहायता के लिए 14 जर्नल/काद-विवरण अनुदीर्घित किए गए। रोमिनार/समेलन/कांग्रेस के आयोजन के लिए भारतीय इतिहास कांग्रेस और दक्षिण भारतीय इतिहास कांग्रेस सहित 165 व्यावसायिक संगठनों को वित्तीय सहायता दी गई है।

6.16.3 परिवर्त ने 21-26 दिसम्बर, 1991 को मानव-जाति के वैज्ञानिक

और सांस्कृतिक विकास के इतिहास के अन्तर्गामी आन्दोलन-युगों के आठवें सत्र की मेजबानी की और यूरो के सदस्यों और भारतीय इतिहासकारों के बीच संवाद का आयोजन किया। परिवर्त के तत्वावधान में 6 विदेशी छात्र शोध-कार्य के लिए भारत आए। जबकि चीन, बंगलादेश, मंगोलिया और पाकिस्तान के छात्र विदेशी छात्रों की छात्रवृत्ति स्कीमों के अन्तर्गत भारत आए और दुर्गरािया और पूर्वी रोवियत सत्र के छात्र सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अन्तर्गत शोध-कार्य के लिए भारत आए।

6.16.4 वर्ष 1991-92 के दौरान परिवर्त ने 12 प्रकाशन निकालवाए। भारतीय शैक्षणिक समीक्षा (XIV खण्ड) के अलावा परिवर्त के मुख्य प्रकाशन में तलिननाड और केरल के अभिलेखों के वर्षीय की सूची भारत में अग्रदूतों। और स्वाज पाटी के उदय (राष्ट्रीय आन्दोलन के खोज) और अग्र आन्दोलन के परिणामों से संबंधित, दस्तावेज 1891-1970 शामिल हैं। परिवर्त की वार्षिक पत्रिका "सिन्टी" में इतिहास प्रेस को प्रकाशन के लिए भेजा गया है।

6.16.5 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान परिवर्त के पुस्तकालय-सह-प्रलेख केंद्र ने 1992 पुस्तकें और 7 नई पत्रिकाएं प्राप्त की हैं। इस केंद्र में माइक्रोफिल्म/माइक्रोफिश की सामग्रियों का भी पर्याप्त संग्रह है।

6.16.6 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान परिवर्त ने निर्दिष्ट शासन से भारत के आधिक इतिहास पर पुस्तकों के 17 खण्ड निकालने के लिए कदम उठाए हैं। सामग्री का संग्रह पुनः निर्धारित आदर्श योजना अवधि में पूरा कर लिए जाने का प्रस्ताव है।

6.16.7 भारतीय/दक्षिण एशिया अभिलेखों में सामाजिक और प्रशासकीय शब्दों का शब्दकोश निकालने के लिए परिवर्त ने चर्चत/परियोजना शुरू की है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सामाजिकीन बोर्ड की दो बैठकें और परामर्शदात्री समिति की एक बैठक हुई और 35000 कार्ड तैयार किए गए हैं। विज्ञानमय के अभिलेख पर 6 खण्डों में कार्य जारी रहा और इसे प्रकाशन के लिए तैयार किया जा रहा है। भारतीय अभिलेखों पर दूसरी परियोजना सर्वो योजना अवधि के लिए पुनः निर्धारित किया गया है और 4 खण्डों में सामग्री प्राप्त किए गए हैं।

भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला

6.17.1 भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला, जो 20 अक्टूबर, 1965 से चल रहा है, का लक्ष्य जीवन के भौतिक विचारों और समस्याओं का स्वतंत्र सर्चनात्मक ज्ञान है। यह एक आवासीय अनुसंधान केंद्र है और यह गहरे मानवीय महत्व से जुड़े क्षेत्रों में सर्चनात्मक विचारों को आगे बढ़ाना

है। यह शैक्षिक अनुसंधान, खासकर मानविकी भारतीय संस्कृति, दृष्टान्तात्मक धर्म सामाजिक और भूकृति विज्ञानों जैसे बुने हुए विषयों में अनुसंधान के लिए अभ्युत्त माहौल प्रदान करता है।

6.17.2 यह संस्थान तीन भागों से तीन खण्डों की अवधि तक के लिए शिक्षावृत्ति प्रदान करता है। पिछले वर्ष के दौरान 28 शिक्षावृत्ति योगियों के मुकामले वर्ष 1992-92 के दौरान 35 शिक्षावृत्ति योगी थे। इस संस्थान ने स्वयं की तीन राष्ट्रीय रोमिनारों का और शास्त्री भारत-कनाडा संस्थान, भारतीय मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण और कला, संस्कृति और पाषाणों के विभाजन अकादमी के सदस्यों से दो रोमिनारों का आयोजन किया। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे निहारों के बीच पारस्परिक आदान-प्रदान के लिए 17 साप्ताहिक लेखनारों का आयोजन किया गया।

दोषान ने इस वर्ष के दौरान 15 अकाशम निकालवाए। इनमें इस वर्ष के दौरान 1500 पृष्ठान्तों और अपने सप्ताह में जोड़ा। इस सेवान प्रोफेसरी में व्याख्यान दिया और "भारतीय सभ्यता में सामाजिक आर्थिक आन्दोलनों और संस्कृत भाषाओं पर बहु-अवधारणी दत्त परियोजना विकसित की गई है और पूरी शीघ्र ही योजना अन्तिम में इस कार्य किया जाएगा। इस वर्ष के दौरान भागविकों और सामाजिक विज्ञान के लिए इस सभ्यता के अन्तर्-विश्वविद्यालय केन्द्र में सम्पूर्ण भारत के विभिन्न और विश्वविद्यालयों से अद्वैतज्ञ लेखक/प्रोफेसर आये।

अन्य योजनाएँ

[illegible]

6.18.0 डॉ० जाकिर हुसैन मेमोरियल कालेज ट्रस्ट वर्ष 1973 में डॉ० जाकिर हुसैन (प्रापुर्व दिल्ली कालेज) के प्रभुत्व और आनुसूचित जाति (विभागीय) कालेज के लिए स्थापित किया गया था। कालेज का आनुसूचित छात्रों विधिबिद्यालय अनुदान आयोग और ट्रस्ट द्वारा 95.5 के अनुपात में वहन किया जाता है। इसके अतिरिक्त विधिबिद्यालय अनुदान समग्र समग्र पर किया गया है। इसकी योजनाओं को मंजुरी देता है। इन योजनाओं पर होने वाले खर्च को ऐसे कार्यक्रमों के लिए वि.अ.आं. द्वारा प्राप्त अर्थात् सहायता-पत्रों के अनुसार वहन किया जाता है। वृत्तिक ट्रस्ट के पास अपना कोई संस्थापन नहीं है अतः अनुपुक्त छात्रों को पूरा करने के लिए भारत सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा अनुदान दिया जाता है। ट्रस्ट के प्रशासकीय खर्च को भी पूरा करने के लिए वि.पी.य. सहायता दी जाती है।

अखिल भारतीय उच्च शिक्षा—संस्थान के लिए सहायता योजना:

6-19-0 इस योजना का लक्ष्य शिक्षा की पारम्परिक विद्याविधालय को पद्धति से अलग शिक्षा के कार्यक्रम चलाने वाले कुछ स्कूलों के संगठनों को स्थायीता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत स्थापना उन संस्थानों को दी जाती है जो ग्रामीण समुदाय के विशेष हित से संबंधित और तभी कार्यक्रम चलाते हैं। वहाँ के दौरान इस योजना के अंतर्गत केवल (I) के श्री आर्य समाज, (II) श्री अहिंसावादी धर्मप्रवर्तक, उपनिषद्वादी स्कूल, ओरेन्टले, (III) लोक भारतीय, लोक भारतीय सनोस और (IV) मित्र निकेतन, वेल्फेयर, को विशेष प्राथमता दी गई है।

राष्ट्रीय मूल्यांकन संयोग की स्थापना

6.20.1 पड़ोस शिवा नीति, 1986 और कार्यन्वयन के लिए कार्ययोजना में पड़ोस स्थान की स्थापना को प्रावधान है ताकि सेवा में धर्मों के लिए विचारधालय हियो, जो इसके लिए अनिवार्य अवकाश नहीं है, की अनिवार्यता को समर्थन करने की पद्धति को सुकर बनाया जा रहे। इसके लिए पड़ोस मूल्यांकन संगठन को स्वायत्त पञ्जीकृत संस्था के रूप में स्थापित किया गया है ।

6.20.2 राष्ट्रीय मूल्यांकन संगठन निम्न कार्य करेगा:—

(क) विशेष नौकरी, जिसके लिए डिप्लोमा या डिग्री की जरूरत नहीं है, के लिए उम्मीदवारों की योग्यता निर्धारित करने और प्रमाणित करने के लिए स्वेच्छिक आधार पर जांच करना।

(ख) उम्मीदवारों को उनकी स्वतंत्र इच्छा पर जांच की सुविधा प्रदान करना और जिन उम्मीदवारों को विशेष पेशे/नौकरों के लिए योग्य

प्रभाषित किया जाता है, ऐसे पदों/सेवाओं पर नियुक्ति के लिए बिना किसी अन्य अर्हताओं पर जोर देते हुए योग्य होंगे,

(ग) पेशे के विस्तृत ब्यौरे के आधार पर जांच की प्रक्रिया निष्पत्ति करना। विशेष पेशे के लिए अनिवार्य ज्ञान की जरूरतों, योग्यता, कौशल और रुचियों का पता लगाने के लिए पेशे की विवेचना और

(घ) जीव की प्रक्रिया के विकास, इसके अशासन, इसमें प्राप्त की गई उपलब्धि, सम्पूर्ण पद्धति के प्रयोग और ऑपनल मार्केट रीडर आदि में राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन सम्यक् के रूप में कार्य करना और

(क) विशेष प्रेशे के लिए अनिवार्य ज्ञान, कुशलता, क्षमता, कौशल, योग्यता, और रुचि को जांच के लिए पद्धतियों और तकनीकों का विकास करना,

અંતરાષ્ટ્રીય સહયોગ

6.21.0 कई वर्षों से भारत के प्रति विदेशी शिक्षार्थियों की लवच बढ़ती रही है। यह अमेरिका, इस्ट्यूट ऑफ इंजिनरिंग, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एजुकेशनल फाइनेंसल इन इंडिया, थाओ फ़ोर्नाडियन प्रोग्राम इन इंडिया द्वारा आयोजित अनुसंधान परियोजनाओं की बढ़ती संख्या से स्पष्ट है। वर्ष 1979-82 के दौरान भारत सरकार द्वारा संयुक्त अनुसंधान प्रस्तावों की संख्या वर्ष 1990-91 की संख्या 254 की तुलना से 287 थी। सरकार ने भारतीय विश्वविद्यालयों और विदेश स्थित उनकी सह-कार्यालयों के बीच कई द्विपक्षीय समझौते की संख्या को है। विदेश के विदेशी विश्वविद्यालयों के सभ्यता से होने वाले विपक्षीय आतंरिकीय सम्बन्धन/संगोष्ठ/सोमन शिविर की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। देश में भारतीय विश्वविद्यालय से अंतर्गत लेखा/प्रोफेसर के रूप में विदेशी विद्वानों की नियुक्ति के लिए निवेदनों की संख्या भी बढ़ती रही है। भारत में सामाजिक विज्ञानों/मानविकी आदि के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए विदेशी विद्वानों की प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने अन्यान्य संयुक्त करने की प्रक्रिया उधार लने की है।

॥१६॥ ३-६॥-कन।डियन इंस्टिट्यूट

[illegible]

6.22.2 वर्ष 1991-92 के दौरान संस्थान ने भारतीय अध्येताओं को अपने शैक्षिक अनुसंधान करने तथा कनाडा के अध्येताओं के साथ विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए 28 शिक्षावृत्ति प्राप्त की। इसी प्रकार कनाडा के 16 अध्येताओं ने भारत की विषयगत और विकाससम्बन्ध प्रक्रियाओं के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान किया।

6.22.3 शास्त्री भारत कनाडा संस्थान को भारत सरकार द्वारा दिए गए पृथक् पर निर्मित संस्थान के भवन का भारत के राष्ट्रपति द्वारा 15 मई, 1991 को उद्घाटन किया गया। संस्थान के निदेशक पाडल की मई,

1991 में भारत में पहली बार बैठक हुई। संस्थान ने एक पुस्तकालय का भी निर्माण किया है जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी विषयों से इतर विषयों पर 10,000 पुस्तकें विद्यमान हैं।

भारतीय संयुक्त राज्य शैक्षिक अभियान

6.23.1 भारतीय संयुक्त राज्य शैक्षिक अभियान की स्थापना फरवरी, 1950 में एक द्विपक्षीय करार के अंतर्गत की गयी थी जिसे ज्ञान के अर्थिक, आदान-प्रदान के माध्यम से भारत और संयुक्त राज्य अमेरीका के लोगों के बीच सहयोगन की बढ़ावा देने के लिए 1963 में एक नये करार द्वारा प्रति स्थापित कर दिया गया था।

6.23.2 द्विपक्षीय यू. एस.-इण्डियाई का निदेशक मण्डल प्रतिवर्ष अध्ययन के नये क्षेत्रों को सँझते देता है जिनके लिए शिक्षावर्गियों की परामर्श की जाती है। यह प्रतिष्ठान सामाजिक विज्ञानों और मानविकी में विश्वविद्यालय के वरिष्ठ और कनिष्ठ स्नातक के लिए 3-7 महीने की अवधि के लिए अनुसंधान अनुदान प्रदान करता है।

6.23.3 शैक्षिक वर्ष 1991-92 के दौरान 36 प्राध्यापकों, 15 शोधकर्ताओं और 6 विद्यार्थियों को 3-9 महीने की अवधि के लिए अनुदान दिया गया।

अमेरिकी भारतीय अध्ययन संस्थान

6.24.1 अमेरीकी भारतीय अध्ययन संस्थान जो कि मैनेपोसिया, रिचमोंड, कोलम्बिया, हावर्ड, पेरेस्वानिया, वाशिंगटन आदि जैसे प्रमुख 57 अमेरीकी विश्वविद्यालयों का समाय है। 1961 से भारत में (क) विद्यावृत्तियों, (ख) भारतीय भाषाओं के शिक्षण (ग) शोध कार्यो के परिणामी के प्रकाशन (घ) सेमिनारों, सम्मेलनों और कार्यशालाओं के आयोजन तथा (ङ) वाचनाली में कला और पुस्तक के इतिहास के शोध केंद्रों तथा नई दिल्ली में संगीत और एथनो-भूजिकालाजी के क्षेत्र के माध्यम से संयुक्त राज्य में भारतीय शिक्षा, संस्कृति और सभ्यता की प्रीति के उद्देश्य से कार्य कर रहा है।

6.24.2 वर्ष 91-92 के दौरान संस्थान ने संयुक्त राज्य अमेरीका के विश्वविद्यालयों और संकाय समिष्टियों और पी.एच.डी. के विद्यार्थियों तथा अनुसंधान संगठनों को मानव विज्ञान से लेकर प्राणि-विज्ञान तक के क्षेत्र में इतर बात की ओर मानव विवे बिना की शिक्षावृत्तिया प्राप्त करने वाले व्यक्तिओं की पहुँचाया क्या है, लगभग 176 शिक्षावृत्तियों प्रदान की।

6.24.3 अमेरीकी-भारतीय अध्ययन संस्थान अमेरीकी छात्रों के लिए बंगाली, हिन्दी, तमिल, तेलुगु और उर्दू भाषाओं के शिक्षण की व्यवस्था करता है।

6.24.4 संस्थान का कला एवं पुस्तक केंद्र के पास विभिन्न भाषीय भाषाओं और अर्थों 125,000 सेवार और प्रलेखित छाया चित्रों तथा 17,000 स्नाइडों की अभिलेखीय सूचिका है। अथी तक दक्षिण और उत्तर भारत की भारतीय महिला वास्तुकला के विश्व कोष के 6 भाग प्रकाशित हो चुके हैं और शेष क्षेत्रों के संबंध में कार्य चालू रहा है।

6.24.5 एथनो-भूजिकालाजी अभिलेखालार और अनुसंधान केंद्र का मनुष्य वस्तुस्थ है भारतीय निम्नान एवं मौलिक कलाओं का एक अभिलेखालाग। निकसित करना है तथा अर्थिक व्यापक रूप से भारत की दूरदर्शन कलाओं की ज्ञान व संभान से उत्पति करना तथा भारत में एथनो-भूजिकालाजी के अध्ययन के लिए प्रेरित करता है। केंद्र के पास

इस समय लगभग 8,000 छात्रों की श्रव्य रिकार्डिंग तथा 600 छात्रों की वीडियो रिकार्डिंग है। इस केंद्र में एक पुस्तकालय भी है जिसमें इस विषय की लगभग 7,000 पुस्तकें और 75 पत्र-पत्रिकाएँ हैं।

भारतीय विश्वविद्यालय संघ

6.25.1 भारतीय विश्वविद्यालय संघ विश्वविद्यालयों का एक शैक्षिक संगठन है जो विश्वविद्यालय प्रशासकों और शिक्षाविदों के लिए पारस्परिक हिन्दी के विषयों पर विचारों के आदान-प्रदान और जर्नो के लिए एक मंच का कार्य करता है। यह संघ उच्च शिक्षा के संबंध में एक शैक्षणिक समूह के रूप में कार्य करता है और उच्च शिक्षा पर अनेक प्रकाशन और अनुसंधान लेख, पुस्तकें और पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित करता है।

6.25.2 वरिष्ठ संघ का वित्त पोषण अधिकारोंगत सदस्य विश्वविद्यालयों द्वारा दिये गये वार्षिक चंदे से होता है फिर भी उच्च शिक्षा के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अनुसंधान अध्ययन करने के लिए संघ की संस्कार द्वारा अनुदान दिया जाता है। संस्कार की सहायता से स्थापित अनुसंधान कक्षा द्वारा किये जाने वाले कार्यकर्ताओं के लिए तथा कुछ हद तक संघ के अंगरक्षक व्यय की पूर्ति करने के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

6.25.3 वर्ष 91-92 के दौरान भारतीय विश्वविद्यालय संघ ने निम्न प्रकार की योजनाएँ पूरी की:

- पश्चिमा में दूरस्थ शिक्षा संस्थानों की निर्देशिका भाग-I भारत और भाग-II पाकिस्तान तथा श्रीलंका।
- विश्वविद्यालयों में वित्तीय छात्रे
- निर्वाह भाषा की औद्योगिक अर्थ्य पाठ्यक्रमों में अवसरआतक छात्रों को भाष्यन भाषा सीखने में सार सभ्यी अनुदान।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अलेखों के 5 विषयों के संबंध में प्रतिक्रिया का अध्ययन।
- कृषि विज्ञान में प्रथम बैंक पुस्तक
- योजना पैथालाजी
- मान्यकरण पूर्ण अभिया

6.25.4 यह प्रकाशन उच्च शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर साहित्य की प्रीति में योगदान देने निम्न विषयों पर अनुसंधान परिचिजनार्थ/अध्ययन:—

- उच्च शिक्षा के सन्दर्भ में शैक्षिक लगात अध्ययन
- विश्वविद्यालयों के संसाधनों का पुनर्गन
- अध्ययनक मूल्यांकन और संस्थागत मूल्यांकन संबंधी विचार-विमर्श
- मुद्रा विज्ञान एवं एस एसएस

— सुक कोषिण/लेख विधि से संबंधित प्रथम बैंक प्रीति पर है और उनके वर्ष के अंत तक पूरा हो जाने की संभावना है।

6.25.5 "विश्वविद्यालय प्रशासकों के लिए वित्तीय प्रथ बैंक में सम्मूर्त का प्रयोग" विषय पर 2 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये

गये जिनमें से एक 26 दिसम्बर, 1991-1 जनवरी, 1992 तक चण्डीगढ़ में और दूसरा दक्षिण पारत में आयोजित किया गया।

6.25.6 वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रकाशन निकाले गये:—

- बायरेक्ट्री ऑफ वूमेन स्टडीज इन इंडिया
- डायरेक्ट्री ऑफ डिस्टैंस एज्युकेशन इंस्टिट्यूट्स — पार्ट-1, इंडिया,
- हायर एज्युकेशन इन इंडिया. रिट्रोस्पेक्ट एण्ड प्रोस्पेक्ट
- बाईबिलोग्राफी इन डॉक्टरेल डिसेंटेशन: नैचुरल एण्ड अल्पाइड साइंस 1986-87.
- बाईबिलोग्राफी इन डॉक्टरेल डिसेंटेशन— सोशल साइंस इन ह्यूमनीटीज 1987-1988 एण्ड
- क्यूश्न बैंक बुक सीरीज-अग्रोनोमी

6.25.7 आलोच्य वर्ष में मोनोग्राफों का पुनर्मुद्रण किया गया और प्रश्न बैंक पुस्तक संकलन निकाली गई है।

राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसरशिप योजना

6.26.0 लब्ध प्रतिष्ठित विद्वानों और अध्येताओं को सम्मान देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसरशिप स्कीम 1949 में आरम्भ की गई थी। वर्तमान में 2 राष्ट्रीय प्रोफेसर हैं जो इस प्रकार हैं:—

डॉ० सी०आर० राव, गणित

डॉ० श्रीमती एच०एस० सुब्बालक्ष्मी कर्नाटक संगीत शास्त्री, राष्ट्रीय प्रोफेसर 5000/- रु० की मासिक परिनिब्धियां तथा आकाशमिक अनुदान पाने के पात्र होते हैं।

पंजाब विश्वविद्यालय चण्डीगढ़

6.27.0 पंजाब राज्य का पुरः गठन हो जाने से पंजाब विश्वविद्यालय को पंजाब पुरः गठन अभिनियम-1966 के उपबन्धों के अंतर्गत अंतराज्य निमित्त निकाय घोषित किया गया। विश्वविद्यालय का अनुरक्षण व्यय इस

समय पंजाब सरकार और चण्डीगढ़ संघ प्रशासन द्वारा 40:60 के अनुपात में वहन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय का विकासालमक व्यय मुख्यतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मार्ग निर्देशों के अनुसार विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए विशेष खंडुर कित्ते गये अनुदानों में से ही किया जाता है। तथापि विश्वविद्यालय को भी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संशुद्धित विकास अनुदान की राशि के समुत्पन्न राशि देनी पड़ती है। और ऐसी अनेक परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों का वित्त पोषण करना होता है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजनाओं के अंतर्गत नहीं आते हैं। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार हर वर्ष विश्वविद्यालय को एक समुचित राशि ऋण के रूप में देती है। वर्ष 1991-92 के दौरान विश्वविद्यालय को अपने विकास कार्यक्रमों के लिए 50 लाख रु० ऋण के रूप में दिये गये।

विश्वविद्यालयों और कालेजों के शिक्षकों के वेतनमान में संशोधन

6.28.0 विश्वविद्यालयों और कालेजों के शिक्षकों के वेतन मामलों में संशोधन की जो योजना जुलाई 1988 में घोषित की गयी थी उसे केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा कार्यान्वित कर दिया गया है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिए विशेष कक्ष

6.29.0 यह कक्ष जो कालेजों और विश्वविद्यालयों में दखिले और निष्क्रियता में आरक्षण संबंधी नीति की समीक्षा करने के लिए उपादायी है, इसे एक अवर-सचिव को सौंप कर सुदृढ़ बना दिया गया है। यह अवर सचिव केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का समन्वय करता है। यह कक्ष अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति आयोग को तथा संसद को भी आरक्षण के संबंध में सूचना देने के लिए सम्पर्क एकक के रूप में भी कार्य करता है। कालेजों और विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों के शिक्षकों/छात्रों/कर्मचारियों से बहुत बड़ी संख्या में प्राप्त अभ्यावेदनों की इस कक्ष द्वारा जांच की गई और जहां आवश्यक समझा गया मामलों पर संबंधित अधिकारियों से सम्पर्क किया गया।

1. For the first time, the

7. तकनीकी शिक्षा

7.1.1 तकनीकी शिक्षा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान देने तथा लोगों के जीवन के स्वरूप को सुधारने वाले उपराष्ट्र और सेवाओं के मुख्य सार्वजनिक स्वरूप का एक महत्वपूर्ण घटक है। इस क्षेत्र के महत्व को भावना प्रदान करते हुए, प्रतिष्ठित पंचवर्षीय योजनाओं में तकनीकी शिक्षा के विकास पर बहुत बल दिया गया है।

7.1.2 पिछले चार दशकों के दौरान देश में तकनीकी सुविधाओं का चमत्कारिक विकास हुआ है। किन्तु, इसके क्षेत्र की वृद्धि, संगठित करने के साथ-साथ असांगठिक और ग्रामीण क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप इसकी सुलभता और इसकी प्रासंगिकता और उत्पादकता में सुधार के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अभी तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त इस शालाब्दी के अंत तक मानवार्थिक, औद्योगिक तथा शिल्पवैज्ञानिक क्षेत्रों में आगामी परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए, इस प्रणाली को बृहत्तर प्रासंगिकता और वास्तविकता में अपनी भूमिका निभाने में समर्थ बनाए जाने की आवश्यकता है। इन तर्कों के आधार पर तकनीकी शिक्षा प्रणाली को और परिमार्जित करने के लिए अनेक कार्यक्रम किए गए। इनमें आधुनिकीकरण तथा अप्रचलन को दूर करना, संस्था उद्योग के तालमेल को बढ़ाना, उद्योग और सेवा क्षेत्र में कार्य कर रहे तकनीकी कर्मियों के ज्ञान और कौशल के दायन के लिए सतत शिक्षा प्रदान करना तथा ग्रामीण क्षेत्र में औद्योगिकों का स्थानांतरण संश्लिष्ट है।

7.1.3 आलोच्य अवधि के दौरान तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण विकास देखे गये। विभिन्न कार्यक्रमों तथा योजनाओं के कार्यान्वयन में पर्याप्त प्रगति की गई। पॉलिटेक्निकों को अपनी क्षमता, गुणात्मकता तथा कार्य दक्षता में सुधार लाने योग्य बनाने के लिए देश में तकनीकी शिक्षा प्रणाली के अग्रज की दृष्टि में विश्व बैंक की सहायता से एक बड़ी परियोजना प्रारम्भ की गई। वैधानिक अधिकारों के साथ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने उसे दिए गए लक्ष्यों को पूरा करने का कार्य जारी रखा।

7.2.0 वर्ष के दौरान तकनीकी शिक्षा के अन्तर्गत कार्यक्रमों/योजनाओं तथा उनकी उपलब्धियों का व्यौर नीचे प्रस्तुत किया गया है—

भारतीय औद्योगिकी संस्थान

7.3.1 बम्बई, दिल्ली, खड़गपुर, कानपुर और भद्राल में 5 भारतीय औद्योगिकी संस्थानों की स्थापना तकनीकी शिक्षा के प्रमुख केन्द्रों के रूप में की गई थी। ये संस्थान अन्तर-आगत तथा आन्तरिक स्तर पर इंजीनियरी और प्रयुक्त विज्ञान में प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। ये संस्थान इंजीनियरी और औद्योगिक तथा विज्ञान-विषय के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए प्रमुख केन्द्र हैं। इन संस्थानों में अपेक्षाओं द्वारा अन्तर-विषयक अनुसंधान (बहुविध) और प्रयुक्त, दोनों भी किया जाता है।

7.3.2 सा प्रौ-संस्थानों में इंजीनियरी और औद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में

4 वर्षीय अन्तर-आगत कार्यक्रम संचालित किए। ये भौतिकी, रसायन विज्ञान, तथा गणित में 5 वर्ष की अवधि के संश्लिष्ट निष्ठात-उपधि पाठ्यक्रम भी प्रदान करते हैं।

7.3.3 विभिन्न विशिष्टताओं के साथ विभिन्न विषयों में 1½ वर्ष एग्रेटेड डिग्री पाठ्यक्रम और एक वर्षीय आतकोतर डिप्लोमा पाठ्यक्रम चले हुए क्षेत्रों में भी संचालित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त संस्थाओं ने इंजीनियरी विज्ञानों, मानविकीय तथा समाज-विज्ञानों में पीएचडी और कार्यक्रम प्रदान किए। विशिष्टता के चुने हुए क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करने और अनुसंधान के लिए उच्च केन्द्र संस्थान में स्थापित किए गए हैं।

7.3.4 भारतीय औद्योगिकी संस्थानों ने औद्योगिकी विकसित करने में तथा इसके प्रयोजनओं को इसके अन्तर्गत में प्रशंसनीय योगदान किया है। प्रयोच्यता के अन्तर्गत अथवा संस्थानों की अपनी पहल पर चले किए गए अनुसंधान कार्य में अनेक उद्योग लाभान्वित हुए हैं। कई सेट्ट, अन्तर्देशीय स्तर के उल्लेख अनुसंधान कार्यागत इन संस्थाओं के अनुसन्धान संभव्य कार्यकलापों की सफल कक्षाओं पर प्रकाश डालते हैं। संस्थानों को परामर्श और संबद्ध कार्यकलाप में पर्याप्त गुणवत्ता प्राप्त हुए हैं।

7.3.5 प्राञ्चों संस्थानों द्वारा किए गए अन्य सार्थक योगदान अन्य इंजीनियरी/शिल्पवैज्ञानिक संस्थानों को पाठ्यवर्षीयों अदि के विकास में उनके द्वारा प्रदत्त वितीय सहायता है। संस्थानों से उत्पीछे जाते हैं उच्च स्तरीय दक्षता, मूल्य और परिपक्वता की भावना अर्जित की है। वर्ष के दौरान, संस्थानों में, प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण/सुरते उपकरणों की बदलना जारी रखा। संस्थानों ने संस्थागत नेटवर्क योजना के अन्तर्गत क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों की उनकी प्रयोगशालाओं और संकायों के विकास में सहायता करने के कार्य को जारी रखा।

7.3.6 10 महीने की अवधि का एक विशेष प्राथमिक पाठ्यक्रम, प्राञ्चों संस्थानों में अनुज्ञा/अनुज्ञाओं के छात्रों के दाखिले में सुधार करने के लिए जारी रहा। इसने प्राञ्चों संस्थानों अनुज्ञा/अनुज्ञा जनजाति की दाखिला करने में पर्याप्त रूप से सुधार किया है। इसने अनुज्ञा/अनुज्ञा के छात्रों को निरुत्क छात्रों के अतिरिक्त जैन-खर्च, खुशी और विवेकाधीन अनुदानों के रूप में संस्थानों से वितीय-सहायता मिलनी भी जारी रही।

7.3.7 वर्ष के दौरान, प्राञ्चों संस्थान, कानपुर में संगणक-नेटवर्क, कृमि-इंटीग्रेज, हाई-वाल्ज डांसिंग, हाई-टैम्बर सुपर क-ज्जनीति, क-पीज नैटिवस, अन्त-चिन-फिन्स, सी-एडी-सी-एडम, रोवेटिस और फलैक्सीबिल आटोमेशन, रीमिन मैटिरिक्स की विशेषताओं में सुधार, प्लासमा रिफाइनरीशन लेजर, हाई ग्राट पट्ट डीएएसपी, स्टर्न रायन स्केट्सकपी और सतत जैल नॉटिंग, प्राञ्चों सं, बम्बई ने उपरती हुई प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों को शामिल करने के लिए विविधीकरण किया, प्राञ्चों-सं, खड़गपुर ने वर्ष के दौरान पाठ्यवर्षी सार्वना में तथा प्रेडिग पद्धति में प्रमुख परिवर्तन आरंभ किया जिसमें "ओपन बुक" "टेक होम" परीक्षा तथा नैसिधमा स्तर पर

वर्धमान तथा कार्यक्षम अंडीयों पादपक्रम शामिल है। अन्य कार्यक्रमों में आयुजिन, खड़क ग्लिकिंग मिल और खड़क औद्योगिकों के लिए संशोधित-परीक्षण, जी-टीनिक-वास्तुकला के लिए वेब-मेकर शामिल हैं। फाउन्डेशन दिल्ली ने विकासशील विश्व में अनेक संस्थानों के साथ औद्योगिकी स्थानांतरण तथा सहयोगी प्रयत्नों के लिए, उद्योगों के साथ तालमेल स्थापित किया और सहयोग दिया। फाउन्डेशन, मद्रास ने फाइबर डिजिटल प्रोसेसिंग, मेटल कोटिंग और फाइबर के लिए उपयोगी अवयव विकसित करने के क्षेत्र में प्रथमयोग अग्रणी की। संस्थान ने जैव-सामान तथा जैव औद्योगिकी विषयों में अन्तर-विषयक कार्य भी जारी रखा।

7.3.8 अनेक फाउन्डेशन ने, राशीनली, से निर्दिष्ट निर्देशों को कार्यान्वित करने के लिए अपनी-अपनी कार्यवाई योजना तैयार कर ली थी। संस्थान ने योजना आयोग द्वारा खसोखसल, आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, विशिष्ट क्षेत्रों के विकास के लिए बल अवस्थापालक सुविधाओं, जिसे अतिरिक्त छात्रावासों और स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण, अधीनस्थलों की आधुनिकीकरण, उभरे हुए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नए पादपक्रमों को आरंभ करना, अभ्यर्तित उपकरण का निरालण, कोटिंग-युधार के लिए नए कार्यक्रमों को आरंभ करना, स्टाफ और संकाय विकास और फाउन्डेशन पद्धति को अधिकतमक आत्म-अवलम्बी तथा लगातार-प्रगती बनाना शामिल है, को सुदृढ बनाने पर बल दिया जाएगा।

7.3.9 असम-समझौते के अनुसार, भारत सरकार अन्य बातों के साथ-साथ, असम में एक फाउन्डेशन स्थापित करने के लिए सहमत हो गई है। इस फाउन्डेशन संस्थान की स्थापना के लिए उत्तरी गुवाहाटी में एक नया स्थल चुना गया है। राज्य सरकार, प्रुमि के अधिसूचना की दिशा में कदम उठा रही है।

भारतीय प्रबन्ध संस्थान

7.4.1 प्रबन्ध के क्षेत्र में शिक्षा, प्रशिक्षण, शोध और परामर्श देने के दक्षय में भारत सरकार द्वारा अहमदाबाद, बंगलौर, कलकता और लखनऊ में एक-एक करके चार भारतीय प्रबन्ध संस्थान स्थापित किए गए थे।

7.4.2 अहमदाबाद, बंगलौर और कलकता के तीन संस्थानों ने विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी अपने सामान्य शैक्षिक कार्यक्रमों अर्थात् स्नातकोत्तर कार्यक्रम, प्रबन्ध में शिक्षावास्तुत कार्यक्रम, प्रबन्ध विकास कार्यक्रम, संगठन (आयोजन) आधारित कार्यक्रम तथा उद्योगों के लिए शोध और परामर्श के कार्यक्रम जारी रखे।

7.4.3 लखनऊ स्थित जैव भारतीय प्रबन्ध संस्थान ने वर्ष 1985-86 के सत्र से कार्य करना आरंभ किया है। यह अभी विकास के चरण में है। यह शोध शीलय तथा परामर्श सेवाएं प्रदान कर रहा है।

7.4.4 राशीनली के अनुवर्ती के रूप में, इन संस्थानों ने अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना की है जो कृषि, आनीय विकास, लोक पद्धति, प्रबन्ध, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास आदि जैसे गैर-निर्मित और अवर प्रबन्ध क्षेत्रों की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं।

7.4.5 इन संस्थानों की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन तथा इनके दायरे का विस्तार करने की प्रक्रिया में इन संस्थानों को अधिक से

अधिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए उपेक्षित उपाय करने के उद्देश्य से एक विस्तृत समीक्षा अधीनगत की जा रही है।

राष्ट्रीय औद्योगिक अधिवायिकी प्रशिक्षण संस्थान

7.5.1 भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र विकास की सहायता से वर्ष 1963 में एक स्वायत्त निकाय के रूप में राष्ट्रीय औद्योगिक अधिवायिकी प्रशिक्षण संस्थान की बन्दई में स्थापना की गई थी।

7.5.2 यह संस्थान औद्योगिक अधिवायिकी में आतकोप कार्यक्रम, (एस्टेडक के समकक्ष) औद्योगिक अधिवायिकी में छात्रवृत्ति कार्यक्रम, (पीएचडी-डी के समकक्ष) तथा कम्प्यूटर और अनुभवीगी में डिप्लोमा कार्यक्रमों को प्रेशकश करता है। यह औद्योगिक अधिवायिकी और प्रबन्ध तकनीक के विभिन्न क्षेत्रों में एक से हो सलान की अग्रणी के अल्पकालिक कार्यकारी विकास कार्यक्रमों का संचालन भी करता रहा है। संस्थान अनुभवयोग अनुसंधान में लगा हुआ है तथा औद्योगिकी, इंजीनियरी, कार्य संचालन अनुसंधान, संयचना प्रगती और कम्प्यूटर, विपणन, मार्केट और अन्य संबद्ध उत्पादकता और प्रबन्ध क्षेत्रों के विभिन्न पक्षों पर परामर्श भी देता है।

7.5.3 संस्थान वैधानिक संगठनों की आवश्यकता के अनुकूल एक विशेष प्रकार का कार्यक्रम भी चलाता है जिसे इकाई पर आधारित कार्यक्रम (युनिट बेस्ड प्रोग्राम) के नाम से जाना जाता है।

7.5.4 संस्थान ने प्रायोगिक आधार पर मद्रास, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई-महाराष्ट्र, बंगलौर और कलकता स्थित केन्द्रों का प्रसार किया है ताकि इन केन्द्रों में और इंट-निर्दिष्ट उद्योगों की अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके।

7.5.5 इसके अतिरिक्त औद्योगिकी इंजीनियरों के क्षेत्रों में कार्यक्रमों की सुदृढ बनाने के लिए संस्थान ने विभिन्न क्षेत्र में अनुसंधान क्रियाकलापों का विस्तार किया है। इन कार्यक्रमों में औद्योगिकी स्थानांतरण, विशेष तौर पर महिला उद्योगों के लिए उद्यम विकास कार्यक्रम, परिवहन इंजीनियरों और प्रबन्ध में कार्यक्रमों, काम करने की परिस्थिति के क्रमिक तब आदि शामिल हैं।

राष्ट्रीय धातु उद्योग औद्योगिकी संस्थान, रांची

7.6.1 राष्ट्रीय धातु उद्योग औद्योगिकी संस्थान रांची की स्थापना धातु उद्योग औद्योगिकी में प्रशिक्षण और अनुसंधान के एक शीर्ष संस्थान यूएन-डी-सी के सहयोग से भारत सरकार द्वारा वर्ष 1966 में की गई थी। यह भवनाय द्वारा पूर्ण वित्त पोषित एक स्वायत्त संस्थान है।

7.6.2 यह संस्थान उच्च डिप्लोमा पादपक्रम, एमस्टेडक पादपक्रम, पृथिवी पादपक्रम और इकाई पर आधारित (युनिट बेस्ड) कार्यक्रम प्रदान करता है जो धातु और उद्योग औद्योगिकी के क्षेत्र में उद्योगों द्वारा अपेक्षित है। यह धातु औद्योगिकी में मार्गदर्शन करता है तथा मधुलत अनुसंधान का संचालन करता है तथा कई संगठनों को औद्योगिक परामर्श और परीक्षण सेवाएं प्रदान करता है।

7.6.3 संस्थान ने सितम्बर, 1990 में कुल 62 छात्रों के साथ धातु उद्योग औद्योगिकी में अपना अग्रहता उच्च डिप्लोमा पादपक्रम आरंभ किया। सालीय छात्रों ने सफलतापूर्वक 17वां पादपक्रम पूरा किया।



सामुदायिक पालिटेकनीक, गुडियट्टम (तमिलनाडु) में मोटर रेवाइडिंग में प्रशिक्षण

इसने एम-टेक पाठ्यक्रम का छात्र बैच अगस्त, 1990 में ग्यारह छात्रों सहित आरंभ किया जिसमें एक पूर्व बैच के छात्र सहित आठ छात्रों ने पांचवां पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया। वर्ष 1990-91 के दौरान संस्थान ने नौवां पुनर्धर्ष पाठ्यक्रम आयोजित किया जिसमें 115 आयोजित उम्मीदवारों ने भाग लिया। तीन संगठनों द्वारा आयोजित 76 उम्मीदवारों के लिए सात विशिष्ट पाठ्यक्रम आयोजित किए गए थे।

7.6.4 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के तहत अपने विकास के लिए संस्थान ने एक कार्यवाई योजना दस्तावेज तैयार किया है। संस्थान ने विभिन्न उद्योगों को औद्योगिक परामर्श तथा परीक्षण सेवाएं प्रदान करना जारी रखा। संस्थान द्वारा प्रलेखन और संसूचना सुधार सेवा को सुदृढ़ किया जा रहा है। संस्थान अपने उन अनुसंधान कार्यक्रमों को विस्तार के लिए प्रयास कर रहा है जो वर्तमान औद्योगिकी समस्याओं के साथ-साथ अन्य शैक्षिक क्षेत्रों में प्रत्यक्ष रूप से प्रासंगिक हैं। संस्थान ने निर्माण इंजीनियरी में एसोसिएटशिप के एक चार-वर्षीय पाठ्यक्रम की शुरुआत 1991-92 से की है जो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में 30 छात्रों की दाखिला क्षमता सहित पयानुमोदित है।

योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली

7.7.1 योजना एवं वास्तुकला विद्यालय की स्थापना जुलाई, 1995 में, भारत सरकार द्वारा मानव आवासों तथा पर्यावरण में संबंधित शैक्षिक कार्यक्रमों में प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक प्रमुख संस्थान के रूप में की गई थी। यह भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित एक स्वायत्त निकाय है। स्कूल को दिसम्बर, 1979 में विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था ताकि वह शोध और विस्तार कार्यक्रमों को और आगे बढ़ाने तथा अवर स्नातक, स्नातकोत्तर और डाक्टरेट की अपनी डिग्रियां प्रदान करने के लिए अपने शैक्षिक कार्यक्रमों के दायरे का और अधिक विस्तार करने में समर्थ हो। यह विद्यालय वास्तुकला में स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम, और (i) शहरी एवं क्षेत्रीय योजना, (ii) परिवहन योजना और (iii) आवास निर्माण में विशेषज्ञता सहित योजना में मास्टर डिग्री पाठ्यक्रम आयोजित करता है। यह विद्यालय शहरी अभिकल्पना, वास्तुशिल्पीय संरक्षण, ध्वन इंजीनियरी और प्रबंध, भू-दृश्य वास्तुकला और पूर्व भू-दृश्य वास्तुकला और पीएचडी कार्यक्रमों में भी विशिष्टता सहित वास्तुकला में मास्टर डिग्री पाठ्यक्रम संचालित करता है।

7.7.2 वर्ष 1991-92 में, वास्तुकला में स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम में 374, अध्ययन में स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम में 62, मास्टर डिग्री पाठ्यक्रमों में 241 और पीएचडी कार्यक्रम में 12 छात्रों सहित स्कूल में कुल 689 छात्र दाखिल थे।

7.7.3 स्कूल ने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के अनुसंधान में इसके विकास के लिए, एक कार्यवाही योजना तैयार की है। आलोच्य वर्ष के दौरान, 290 सीटों वाले एक छात्रावास, एक अतिथि गृह एवं महारानी बाग परिसर में 71 स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण कार्य पूर्ण होने वाला था। विशिष्ट अनुसंधान कार्यक्रमों और विस्तार कार्यक्रमों के माध्यम से अनुसंधान एवं विस्तार संबंधी क्रियाकलाप तीव्र कर दिये गये हैं।

तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (त-शि-प्र-सं)

7.8.1 पोलिटेक्निक शिक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण देने तथा पोलिटेक्निक शिक्षा के समूचे सुधार के लिए विभिन्न सेवाएं प्रारंभ करने के लिए सन् 1960 के मध्य में भोपाल, कलकत्ता, चंडीगढ़ और मद्रास में

चार तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई। ये संस्थान शिक्षकों को अल्पकालिक प्रशिक्षण देने तथा उन्हें पाठ्यचर्या विकास और संबंधित कार्यकलापों से परिचित करने के अतिरिक्त पोलिटेक्निकों के डिप्लोमा और डिग्रीधारी शिक्षकों को 12 माह / 18 माह की अवधि के दीर्घकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पेशकश करते हैं। भोपाल और मद्रास के संस्थान शिक्षक प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की शिक्षा देने के स्तर पर पहुंच गए हैं। ये यूएन-डीपीए परियोजना के अंतर्गत शैक्षिक फिल्म निर्माण, राष्ट्रीय परीक्षण सेवाओं, अनुदेशकीय पैकेजों आदि को तैयार करने के कार्यों में भी संबद्ध हैं। आलोच्य अवधि के दौरान इन संस्थानों ने अपने कार्यक्षेत्रों में आने वाले विभिन्न क्षेत्रों में कार्यकलापों को जारी रखा और पोलिटेक्निकों, उद्योगों, उच्च शिक्षा संस्थानों, शोध संगठनों और अन्य संसाधन प्रणालियों के बीच तालमेल बढ़ाने के कार्य जारी रखे।

7.8.2 विश्व बैंक की सहायता से राज्यों में पोलिटेक्निकों की क्षमता, गुणात्मकता और कार्य दक्षता बढ़ाने के लिए 1990-91 के दौरान भारत सरकार द्वारा प्राप्ति की गई एक बड़ी परियोजना में तकनीकी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों को सम्मिलित किया गया। वे सहभागी राज्यों को पोलिटेक्निक शिक्षकों को प्रशिक्षण देने, नये और उपरत हुए क्षेत्रों में पाठ्यचर्या तैयार करने, शिक्षा, शोध और विकास, मानव संसाधन विकास, तथा परियोजना का व्यौरा तैयार करने और परियोजना के कार्यान्वयन में भी व्यावसायिक सहायता देंगे।

7.8.3 त-शि-प्र-सं के कार्यक्रमों और उनकी गतिविधियों की मूल्यांकन समिति द्वारा समीक्षा की गई है। समिति ने हाल ही में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में, तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण, पाठ्यचर्या विकास, अनुदेशात्मक सामग्री विकास, अनुसंधान एवं विकास परामर्शी क्षेत्रों में उनके द्वारा किए गए अग्रगामी कार्य की प्रशंसा की है और विस्तार सेवाओं ने उनकी प्रावी उन्नति और सुदृढ़ता के लिए अनेक सिफारिशें की हैं।

तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

7.9.1 आर्थिक कार्य एवं विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभागों द्वारा हस्ताक्षरित महत्वपूर्ण (अभ्रेला) करार के अन्तर्गत देश की प्रमुख तकनीकी समस्याएँ जैसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रबंध संस्थान, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर, रूड़की विश्वविद्यालय, अन्ना विश्वविद्यालय, मद्रास, भारतीय खान स्कूल, धनबाद, योजना एवं वास्तुकला, नई दिल्ली और राष्ट्रीय औद्योगिकी इंजीनियरी, प्रशिक्षण संस्थान बम्बई अनुसंधान एवं विकास पर अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग से परियोजनाएँ चला रही हैं। उपस्करों, विशेषज्ञ सेवाओं और प्रशिक्षण के रूप में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नार्वे, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन आदि विकसित देशों के द्विपक्षीय फंडों और यूएन-डीपीए यूनेस्को जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से इस प्रयोजन के लिए सहायता प्राप्त कर रहे हैं। ये संस्थान यूएएसए इंडिया रूपी फंड से सहायता का उपयोग करते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संयुक्त शोध के लिए संयुक्त राज्य अमरीका में अपने सहयोगियों के साथ भी सहयोग कर रहे हैं। इस प्रकार के सहयोगों का उद्देश्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के उभरते क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान एवं जनशक्ति का विकास करना है। भारत और ईईसी-सो-केन्द्रीय कृत करार के अंतर्गत प्रमुख भारतीय संस्थाएँ और यूरोपीय संस्थाएँ प्रबंध संस्थाओं में सहयोग कर रही हैं।

7.9.2 भारत सरकार और कनाडा सरकार द्वारा अगस्त, 1991 को संस्थागत सहयोग के लिए भारतीय तकनीकी शिक्षा सोसायटी,

तन्त्रि-ग्रन्थों, ग्रन्थ और तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल और भारतीय पीनोडिक पद्धति के अंगत मानव संस्थापन विकास मन्त्रालय को सहयोग देने के उद्देश्य से कनाडा में कनाडा संघुपय के कार्लो जे के सच और संस्थाओं के बीच सम्बन्ध का एक ज्ञान हस्ताक्षरित किया गया था।

7.10.3 निम्नानुसार रूप में, छात्री योजना के दौरान डी-डी-एन की सहायता से डिजाइन छात्री, संघुपय प्रौद्योगिकी एवं सामग्री के क्षेत्र में यूनेस्को में अन्य प्रतिरोधी संस्थाओं और क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों के बीच सहयोग बनाये रखने का निर्णय लिया गया है।

क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज

7.10.1 क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों की स्थापना योजना के अंतर्गत केन्द्रीय योजना में, विभिन्न विकास परियोजनाओं हेतु प्रशिक्षित तकनीकी जनशक्ति के लिए देश की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रमुख राज्यों में भलेय के एक-एक करके सत्रह कालेज स्थापित किए गए हैं। भलेय कालेज, केन्द्र सरकार और राज्य सरकार का एक संयुक्त एवं सहयोगी उद्यम है। जबकि सभी सत्रह कालेज, इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी विभाग के क्षेत्र में प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। इनमें से चौदह कालेजों में आन्ध्रप्रदेश और झारखण्ड प्रदान करते हैं। इनमें से उपलब्ध है। सभी क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों में वर्तमान दसिखा भर्मा, अन्ध्र आतक के लिए 4910 और आन्ध्रप्रदेश पाठ्यक्रमों के लिए 1420 के क्रम में हैं।

7.10.2 धृष्टी शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के संदर्भ से कार्यवाही योजना के दस्तावेज, छात्री पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इनके विकास के लिए सभी कालेजों द्वारा तैयार कर लिए गए हैं। इनके दस्तावेजों में, संशोधित कालेजों के संपूर्ण संरचना, उद्देश्य और विस्तृत कार्यवाही चार्ट (चाईट) निहित हैं। भलेय कालेज के संख्या से 1991-92 की वार्षिक योजना को उनके कार्यवाही दस्तावेजों के अनुसार अतिरिक्त रूप दिया गया है।

7.10.3 वर्ष के दौरान कार्यवाही कार्यक्रम के अनुसंधान विकास के लिए निर्दिष्टित पर जोर दिया गया था: शैक्षिक कार्यक्रमों का विस्तार एवं इनका विविधीकरण, प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण, छात्रों और कर्मचारियों की सुख-सुविधाओं से सुधार, छात्रावासों (लॉड्स) और कनिष्ठ विभागों के लिए) का निर्माण, उचित कालेजों से सामान्य क्षेत्रों के लिए सुविधाओं का विस्तार और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साथ संस्थापन नेटवर्क की योजना के तहत कालेजों में प्रयोगशालाओं का विकास करना।

7.10.4 आठवीं योजना अवधि के दौरान क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों और डिग्री विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के बीच अन्ध्रप्रदेश हेतु अंतिम रूप दिया जा रहा है।

आन्ध्रप्रदेश पाठ्यक्रमों और शोध कार्य का विकास

7.11.1 आन्ध्र सरकार इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आन्ध्रप्रदेश और शैक्षिक शिक्षा का विकास करने की योजना के तहत 16 राज्य सरकारों और 24 गैर-सरकारी आन्ध्रप्रदेश संस्थाओं को सीधे सहायता दे रही है। इस योजना में शोध और विकास (आरएण्ड डी.) के क्षेत्र में विशेष रूप से कार्पी योजना दिया है।

7.11.2 फरवरी, 1991 में इंजीनियरी में आन्ध्रक उद्दिष्टि वाली परीक्षा

आयोजित की गई जिसके आधार पर जुलाई, 1991 में आन्ध्रप्रदेश पाठ्यक्रमों में परिवर्तित किए गए थे।

गुजरात सुधार कार्यक्रम

7.12.1 कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश में तकनीकी शिक्षा प्रणाली - गुजरात और मानक से सुधार लाना है। इस उद्देश्य की पूर्ति एम-टेक की पीएचए-डी जैसे दीर्घकालिक कार्यक्रमों, अल्पकालिक पाठ्यक्रमों तब तकनीकी संस्थाओं के संलयन सदस्य हेतु छात्री और पाठ्यक्रमों विकास-कार्यक्रमों में अशाकालिक सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से है रही है। पाँच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, भारतीय विज्ञान संस्थान नागौर, छहवीं विश्वविद्यालय से संस्थापित गुजरात केन्द्रों के माध्य से दीर्घकालिक और अल्पकालिक कार्यक्रमों को सुधार किया जा रहा है भारतीय तकनीकी शिक्षा बोसधर्मी द्वारा विभिन्न इंजीनियरी कालेजों और पॉलिटेक्निकों में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान पॉलिटेक्निक शिक्षकों हेतु अशाकालिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। छात्री के क्षेत्र में अशाकालिक सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन मन्त्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा हो रहा है।

7.12.2 पूर्व वर्षों से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे शिक्षकों के अतिरिक्त 125 शिक्षकों को एम-टेक के लिए तथा 80 शिक्षकों को पीएचए-डी के लिए आने वाले वर्षों में प्रशिक्षित करना है। पाठ्यक्रमों विकास कार्यक्रमों का आयोजन भा-प्रौ-सं, भा-वि-सं, भा-टी-सं और ए-डी को विश्वविद्यालय में स्थित 7 केन्द्रों पर हो रहा है। प्रयोग/शोध स्कूल कार्यक्रमों के तहत भारतीय तकनीकी शिक्षा बोसधर्मी, नई दिल्ली के माध्यम से 2400 डिग्री और डि-ग्रेडों शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। जहाँ तक अल्पकालिक पाठ्यक्रमों का संबंध है, गुजरात सुधार कार्यक्रम केन्द्र बजट की सीमा के अंतर्गत जितना अधिक संभव हो जना पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए स्वतंत्र है। छात्री से प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत उपलब्ध बजट के अनुसार क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा डिग्री/डि-ग्रेडों शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाना है।

तकनीकी शिक्षा की सहायता हेतु विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त परियोजना

7.13.1 तकनीकी शिक्षा प्रणाली को पुनर्निर्मित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक प्रमुख परियोजना शुरू की है जिसे विश्व बैंक समूह की सहायता से दो मिले-जुले चरणों से कार्यान्वित किया जाएगा। ताकि राज्य सरकारें अपने पॉलिटेक्निकों को समता, गुणवत्ता और क्षमता में सरोभवन कर सकें। वर्ष 1990-91 की अवधि से लगभग 567 मिलियन अमरीकी डालर की विश्व बैंक साख/ऋण सहायता सहित 1650 करोड़ रु. से अधिक की अनुमानित लागत वाली यह परियोजना अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित/मान्यता प्राप्त 16 राज्यों और एक संघ शासित प्रदेश के पॉलिटेक्निकों को शामिल करेगी। इस परियोजनाओं में देश के लगभग 80% अनुमोदित पॉलिटेक्निकों को शामिल किया गया है। यह मुख्यतः राज्य-क्षेत्र परियोजना है तथा संपूर्ण लागत धारा लेने वाली राज्य सरकारों द्वारा VIII/IX योजना-अवधि के दौरान भर्मा-अन्ध्र राज्य के योजनागत आवंटनों से प्रदान की जाएगी। यह परियोजना शिक्षा विभाग के संपूर्ण मॉडर्नीकरण सहायता और अनुसंधान के अंतर्गत चलाए जा रहे कार्यवाही के जारी हैं जिसके लिए परियोजना में देश में चार तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को सुदृढ़ बनाने और प्रमुखमन्त्रालय कांसल्टेंट इंडिया लिमिटेड से एक राष्ट्रीय परियोजना

कार्य-व्यय एकत्र करी स्थापना कीजिए एक केन्द्रीय बटक को प्रावधान किया गया है।

7.13.2 लार्सन, 832 क्यूब रूफ अनुमति प्राप्त वाली बिहा, क्यूब, केरला, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, वस्त्र-ताना प्रदर्शकों, गुणवत्ता वाले परिधानों के पहनाए जाने को चुनने और इसे निर्मित किया जा रहा है। दिसम्बर, 1990 में औद्योगिक कक्ष पर हस्ताक्षर हो जाने के उपरान्त पहला चरण तकनीकी रूप से अग्रेसर हो गया।

[illegible]

संख्या ११८
तेदवर्क
मोजन

७१८१। यह योजना भारतीय औद्योगिक संस्थानों जैसे भुवनेश्वर प्रौद्योगिकी संस्थान, आईआईएम और केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों जैसे गुजरात कृषि विज्ञान संस्थान तथा राज्य प्रौद्योगिकी संस्थानों जैसे उत्तराखण्ड कृषि विज्ञान संस्थानों को जीव मेडिकल प्रौद्योगिकी के अन्तर्गत समायोजित करने के लिए १९८१-८२ के दौरान शुरू की गई थी ताकि देशवासियों का विकास के क्षेत्रों में विविधता के अभाव को प्रतिकूल तथा साथ साथ प्रौद्योगिकी में संशोधन दिया जा सके।

7.14.2 भारत की पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान नेटवर्क योजना काध्यम से 199 प्रयोगशालाओं को सहायता दी गई है और इस प्रयोगशाला 4.95 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। 1990-91 के दौरान 1 करोड़ की लागत और प्रयोगशालाओं को सहायता दिए जाने को प्रस्ताव है।

7.7.4.3 योजना के प्रावधानों के अनुसार, नेटवर्क की अनुमोदित योजना के लिए 5 लाख रुपये की राशि के अनुदान को सहायता दी जाती है जिसमें से 50% विभाग द्वारा और शेष 50% संबंधित संस्था द्वारा वहन किया जाता है।

ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਿਖਰੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ

(क) प्रौद्योगिकी के उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भुविधाओं का सुदृढीकरण करना जहाँ कमजोरी विद्यमान है

[illegible]

विशाल / औद्योगिकी, अतुरक्षण
वायु-कमवर्षन, एप्रो-मिक्स,
इंजीनियरी, उत्पादन विकास / डिजाइन और
मुद्रण औद्योगिकी, प्रबंध निशान और
एडमिनीस्ट्रेशन !

7.15.2 साप्ताहिक योजना अन्वयित के दौरान 347 परिवोजनाओं के सहायार्थ 39.30 करोड़ रुपये की राशि दी गई थी। 1991-92 के दौरान 82 परिवोजनाओं को 731.00 लाख की सहायता दी गई।

(ख) उपरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का सञ्चय

[illegible]

— उपरती हुई प्रौद्योगिकियों के पहचाने गए क्षेत्रों में आधुनिक
प्रयोगशालाओं के स्वरूप में मूल ढांचे का विकास करना ।

— कार्यकर्ताओं और पाठ्यक्रमों का पता लगाकर उच्चस्तरीय कार्य के लिए एक मजबूत आधार का विकास करना।

— प्रौद्योगिकी के सीमावर्ती क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर पर अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों के लिए सुविधाएँ और महाभारत प्रदान करना ताकि उन्नत देशों के संदर्भ में प्रौद्योगिकी की दूरी को अल्पतः खाल किया जा सके।

— मानवशक्ति का विकास ।

— सक्कय प्रशिक्षण के लिए सुविधायें ।

— अनुसंधान एवं विकास सस्थाओं और प्रयोजना एजेंसियों सहित अन्य संस्थानों के साथ संव्य विकसित करना ।

— सहायता प्राप्त संस्थाओं द्वारा विकसित किए गए विशेषज्ञता के क्षेत्रों में संचालित कार्य ।

7.15.4 इस योजना के अंतर्गत सहायता के लिए निम्न लग्न क्षेत्रों का चयन किया गया है कि : उच्च विद्यालय, परिवार इकोनॉमी, स्कूल प्रौद्योगिकी, ग्रीनट सेरोमि, एंथ्रोपेनोफिरिक विज्ञान, रिप्रायजिटिविटी इकोनॉमी, पंचसहयोगिता इकोनॉमी, जल संसाधन प्रबंध, ऑडियोलॉजी, कम्प्यूटरविज्ञान और फाइबर ऑप्टिक्स, लेजर प्रौद्योगिकी, इन्फार्मेटिक्स, डिजिटलिजेशन, सिखा प्रौद्योगिकी, समन्वित-प्रतिष्ठ विद्यालय/कामगृह प्रतिष्ठान, शिक्षा-योग्यता, ओरिएंटल और कुशल विद्यालय। सरकारी योजना के अंतर्गत, 458 परिवोजनाओं की सहायता के लिए 57.33 करोड़ रुपये की राशि मुक्त की गई है। 1991-92 के दौरान 8.99 करोड़ रुपये की राशि मुक्त की गई है। 1990-91 में 99 परिवोजनाओं को सहायता देने का निर्धारण था।

(ग) नए और/अथवा उभर प्रौद्योगिकी कार्यक्रम और विशेषज्ञता के क्षेत्रों में नए पाठ्यक्रमों की प्रशिक्षण करना

7.7.15 यह एक नई योजना है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के भाग के रूप में 1987-88 के दौरान संस्थापित की गई थी। यह योजना गणतंत्र के लिए औद्योगिक और विज्ञान पर प्रौद्योगिकी विकास की महत्त्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। हाल के वर्षों में प्रौद्योगिकी

के परामर्श और समझे हुए क्षेत्रों से प्रौद्योगिकी के ऐसे बहुत से नए क्षेत्र विकसित किए गए हैं जो हमारी राष्ट्रीय आवश्यकताओं से जुड़े हैं और जहाँ अनुपम विशेषज्ञता के साथ मानवशक्ति का विकास किए जाने की आवश्यकता है। प्रौद्योगिकी के विद्यार्थीय नए/उन्नत क्षेत्रों का परा लोभाय गया है जहाँ इस योजना के अंतर्गत कार्यक्रमों/परियोजनाओं को सहायता दी जाएगी।

7.15.6 1987-90 के दौरान 67 परियोजनाओं की सहायता 11.22 करोड़ की राशि से गई थी। 1991-92 के दौरान 7.95 करोड़ रुपये की राशि के साथ 70 परियोजनाओं को सहायता दिए जाने की योजना है। 7.15.7 सितम्बर, 1991 के दौरान, काओले, मराल चाओले, दिल्ली में महत्वपूर्ण क्षेत्रों की इन सभी तीन योजनाओं के अंतर्गत संबंधित परियोजनाओं के प्रभाव को मूल्यांकन करने के लिए वार्षिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी।

आधुनिकीकरण और अद्यतनों का विस्तार

7.16.1 यह योजना छठी योजना अर्थात् आर्थिक प्रदान चतुर्था इंजीनियरी कालेजों से आधुनिक उपकरण और मशीनों के प्रदान करने के अंश से आरंभ की गई थी ताकि 100% प्रत्यक्ष केन्द्रीय सहायता के आधार पर प्रौद्योगिकी उद्योग और पाठ्यचर्या संबंधी परिसरों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

7.16.2 सातवीं योजना अर्थात् के दौरान और विशेष रूप से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाते जाने के बाद से इस योजना के कार्य क्षेत्र और आयामों में विलार किया गया ताकि तकनीकी विज्ञानविद्यालय और विज्ञानविद्यालयों के प्रौद्योगिकी कालेज, पॉलिटेक्निक सहित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों और अन्य इंजीनियरी कालेजों को समर्थित किया जा सके तथा मानव संसाधनों संबंधी पुनर् अभिकल्पित चीजों को हटाया जा सके। इन योजना के उद्देश्यों को निर्माणसार पुन परिभाषित किया गया है:

- इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थानों में मशीनशालाओं और कार्यशालाओं में अपरचित मशीनों और उपकरणों का हटाना।
- प्रौद्योगिकी के सीध विकास के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या को आधुनिकीकरण करना।
- छात्रों को आधुनिक प्रौद्योगिकी मशीनशाला कार्य का अनुभव प्रदान करना।

- नई मशीनशालाओं का निर्माण।
- मशीनों का मानव संसाधन और सहायक स्टाफ का प्रशिक्षण।

7.16.3 सातवीं योजना के दौरान और 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या और प्रति वर्ष जारी किए अनुदान की राशि के आंकड़े निम्नसार हैं:—

तालिका 7.3

वर्ष	सहायता प्राप्त परियोजनाओं (करोड़ रुपये में)		
	की संख्या	की गती अनुदान	राशि
1985-86	131		15.00
1986-87	151		18.00

1987-88	529	60.00
1988-89	603	52.70
1989-90	400	37.00
1990-91	328	30.60
1991-92	334	30.00

राष्ट्रीय तकनीकी मानव शक्ति सुचना प्रणाली

7.17.1 राष्ट्रीय तकनीकी मानव शक्ति सुचना प्रणाली की स्थापना भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय एवं राज्य विशेष क्षेत्रों पर इंजीनियरी तथा तकनीकी मानव शक्ति की अनुसंधान एवं प्रयोगिता के अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए की गई है ताकि सुव्यवस्थित आधार पर तकनीकी शिक्षा की आयोजना एवं विकास किया जा सके। इस प्रणाली में मुख्यतः मानव शक्ति अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली का एक मध्य क्षेत्र तथा विश्व-विश्व राज्य में स्थित चार अधिकार/व्यावहारिक प्रशिक्षण केंद्रों सहित 21 मध्य क्षेत्र शामिल हैं।

7.17.2 संयुक्त-अनुसंधान कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम आर्थिक आंकड़े विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों के आतकों एवं शैक्षिक संस्थानों और मशीनशाला क्षेत्र की उन संस्थाओं से इंजीनियरी तथा तकनीकी मानव शक्ति की निर्माण करते हैं, निर्माण रूप से तथा वार्षिक आधार पर एकत्रित किए जा रहे हैं। 21 मध्य क्षेत्रों में से 17 क्षेत्र जो अधिकतर देश के घुने हुए इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी संस्थाओं से स्थित हैं, विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों के आतकों का अनुसंधान अध्ययन संघलित करते तथा शैक्षिक संस्थानों के सर्वेक्षण के लिए उत्तरदायी हैं जब कि जो प्रशिक्षण/व्यावहारिक प्रशिक्षण केंद्रों से स्थित केन्द्र निर्माण संस्थाओं से आंकड़े एकत्र करने के लिए उत्तरदायी हैं।

7.17.3 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अन्तर आतक थापन, वर्ष 1984 तक के आंकड़े एकत्र किए गए हैं और वर्ष 1985 के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है। यहाँ तक कि कुछ मध्य क्षेत्रों ने 1988 से आगे आंकड़ा संकलन, अवलोकन थापन का कार्य शुरू कर दिया है ताकि आंकड़ा बैंक को नया और अद्यतन बनाया जा सके।

7.17.4 उपरोक्त आंकड़ों के आधार पर, निर्माण और पड़ोसी के लिए वर्ष 1982-85 से संकलित वार्षिक तकनीकी मानव शक्ति जानकारी प्रयोगों की संकलित किया गया है। वर्ष 1983 से 1986 के लिए उत्तर प्रदेश, उड़ीसा जम्मू कश्मीर व केरल की इसी प्रकार की रिपोर्ट पूरी की जा चुकी है।

7.17.5 अक्सर, विद्यार्थी उड़ीसा के लिए संकलित वर्ष 1982 से 1986 के लिए इंजीनियरी मानव शक्ति अनुसंधान क्षेत्रों पर रिपोर्ट की पूरी की जा चुकी है। इस वर्ष के दौरान इंजीनियरी रूपरेखा तथा इसके उपनिर्माण निर्धारण (1983-84) तैयार किए जा चुके हैं।

7.17.6 उपरोक्त रिपोर्टें विभिन्न क्षेत्रों के आतकों के लिए उपलब्ध योजना अनुसंधान के प्रकार पर सुचना प्रदान करती हैं इससे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में आतकों की समग्र की पद्धति और विविध क्षेत्रों में अनुसंधान की सीमा का भी स्पष्टता मिलता है।

7.17.7 अक्सर, 1989 में राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति ने सिफारिश की कि योजना जारी रहनी चाहिए तथा इसे अनुसंधान क्षेत्र से और अधिक सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए। सरकार ने रिपोर्ट स्वीकार कर ली है तथा सिफारिशों को लागू करने की जा रही है।

गैर विश्वविद्यालय क्षेत्रों में ग्रामीण शिक्षा का विकास

7.18.0 विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षित प्रबन्धकर्मियों जनशक्ति पर अत्यधिक निर्भरता की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार ने कुछ ऐसे गैर विश्वविद्यालय क्षेत्रों को सहायता प्रदान करने का कार्यक्रम शुरू किया है जो अखिल भारतीय स्तर पर कार्य कर रहे हैं तथा प्रबंध अध्ययन से दो वर्ष का पूर्ण कॉलेज तथा तीन वर्ष का अंगकॉलेज स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रदान कर रहे हैं। अखिल भारतीय परबंध अध्ययन बोर्ड/अंगकॉलेजिअल की सिफारिशों के आधार पर संस्थानों को सहायता प्रदान की जाती है। इस कार्यक्रम के तहत भारत सरकार कुछ संस्थाओं को प्रबंध कार्यक्रमों के संरक्षण तथा इन्हें विकास के लिए सहायता प्रदान कर रही है। आज की स्थिति में असंश्लिष्ट, असंगठित व सेवा क्षेत्रों में कार्यक्रमों का अत्यंत आवश्यक है। सभी भारतीय समाज कल्याण व व्यापार प्रबंध अध्ययन कलाका से अनभिज्ञित व असंगठित क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम तैयार करने का अनुभव किया गया है।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद

7.19.1 अनुमोदित मानकों के अनुकूल तकनीकी शिक्षा के संयोजित विकास की सुनिश्चित करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (अंगकॉलेजिअल) का गठन 1945 में राष्ट्रीय विशेषज्ञ विकास के रूप में तकनीकी शिक्षा के विकास पर केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों की सलाह देने के लिए किया गया। सनवर्ती सूची में शिक्षा के शामिल होने से पहले ही तकनीकी संस्थाओं में मानकों का सम्मन्धन और निर्धारण केन्द्रीय सरकार का संवैधानिक उत्तरदायित्व रहा है।

7.19.2 गैर सरकारी इंजीनियरी कालेजों की संख्या में हो रही वृद्धि की मज्जा से निपटने के लिए संसद के एक अधिनियम द्वारा अंगकॉलेजिअल को सार्वजनिक दर्जा प्रदान किया गया। अंगकॉलेजिअल में पूरे देश में इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी प्रबंध नगर आयोजना जैसे क्षेत्रों में डिप्लोमा डिग्री पाठ्यक्रम संचालित करने वाली सभी तकनीकी संस्थाएँ व विश्वविद्यालय के तकनीकी विभाग आते हैं।

7.19.3 इस परिषद ने अपनी कार्यकारी समिति तथा कार्यय, महाम, बमर्ई और कलाका स्थित चार क्षेत्रीय समितियों के माध्यम से कार्य करता शुरू कर दिया। परिषद ने इंजीनियरी व प्रौद्योगिकी में तकनीकीशिक्षण, अंतर-जातक व स्नातकोत्तर स्तर पर अखिल भारतीय अध्ययन बोर्ड स्थापित किए हैं। आनकोतर बोर्ड ने कई नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम तथा तकनीकशिक्षण शिक्षा के लिए विश्व बैंक सहायता के भण्डार में इंजीनियरी व प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम आरम्भ करने की सिफारिश की है। वास्तुशिल्प के क्षेत्र में शिक्षा के विकास के लिए परिषद ने वास्तुशिल्प परिषद के साथ एक आपसी सूझबूझ के तालम पर भी हस्ताक्षर किए। परिषद की विशेषज्ञ समिति की अग्रील, 1991 में बैठक हुई तथा इतने नए पाठ्यक्रमों व कार्यक्रम आरम्भ करना अनुमोदित किया। तकनीकी संस्थाओं में दक्षिण के लिए भारतशरी स्मोखाओं तथा विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए मानकों और मानदंडों को परिषद ने अनुमोदित कर दिया।

7.19.4 आलोच्य वर्ष के दौरान परिषद ने 42 नई संस्थाओं तथा तकनीकी संस्थाओं में 231 कार्यक्रम आरम्भ करने की सफलता दी।

सामुदायिक परितैजिक

7.20.1 सामुदायिक परितैजिक योजना की 1978-79 में 36 परितैजिकों में प्रयोगात्मक आधार पर तकनीकी शिक्षा प्रणाली में निवेशों से होने वाले

लाभों में ग्रामीण समाज को उचित रूप से भागीदार बनाने के विचार से सीधी केन्द्रीय सहायता योजना के अंतर्गत संस्थापित किया गया। योजना में ऐसी परिकल्पना की गई है कि ग्रामीण समुदाय के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रयोगार्थ तथा गैर औद्योगिक प्रशिक्षण के माध्यम से स्व-और मजदूरी दिलाने वाले योजना के अवसर जुटाने में केन्द्र बिन्दु का काम करेगा। इसका उद्देश्य ग्रामीणों को प्रेरित करना, सामाजिक, उद्योग तथा जनता को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की जीवन प्रक्रिया में गुणात्मक संघार करना है। जबकि योजना में व्यक्तिगत की भागीदारी अनिवारित विशेषता है, अधिक महत्व शोधित अनुसंधान प्राप्त तथा समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को दिया गया है। सहायता स्थायीतः सामाजिक परिवर्तनों के अनुभवकारी 100 तकनीकी/ व्यावसायिक व्यावसायों की योजनाओं/मुख्य कुशलता विकास प्रशिक्षण देने के लिए रखा गया है। आयोजित किए जाने वाले विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का भ्रमाव नहीं किया गया है तथापि महिलाओं अल्पसंख्यकों व पछाईं जीव व छोड़ कर जाने वाली को प्रोत्साहित किया गया। संपूर्ण देश में आजकल 152 सामुदायिक परितैजिक (दिसम्बर 1991 तक) कार्य कर रहे हैं। सभी अल्पसंख्यक क्षेत्रों-जो खिली को योजना के अर्थात शामिल कर लिया गया है। सामुदायिक परितैजिक निर्भरिखित कार्य करते हैं।

- सामाजिक सर्वेक्षण,
- जनशक्ति विकास और प्रशिक्षण,
- प्रौद्योगिक, स्थानांतरण,
- दलमशीलता विकास की और तकनीकी व सहायक सेवाएँ;
- सूचना प्रसृत।

7.20.2 सामुदायिक परितैजिक योजना में आरम्भकी सहायता हेतु ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास केन्द्रों की स्थापना करना शामिल है। तकनीकी के विकास नवीनकरण व अनुकूलन के लिए ग्रामीण प्रौद्योगिक विकास केन्द्रों के रूप में ग्रामीण आवश्यकता के अनुसार अभी तक 15 डिप्लोमा स्तर के संस्थानों का चयन किया गया है जैसे कि सामुदायिक परितैजिक के लिए आर व डी पद्धति। योजना के अर्थात ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास केन्द्रों को आला अनुदान दिए जा रहे हैं।

7.20.3 योजना के प्रथम कार्यन्वयन हेतु सामुदायिक परितैजिक ने दूर-दूरज के ग्रामीण इलाकों में विस्तार केन्द्रों की स्थापना की है ताकि इस प्रणाली द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ और सेवाएँ गांवों के ठीक पास ही उपलब्ध कराई जा सकें। ग्रामीण सचय, पवनचक्की, धुआँ रहित सुखा, ग्रामीण शौचालय, सौर यंत्र खेती के उपकरण इत्यादि सहित प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और अनुमोदित मदों की ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए सामुदायिक परितैजिकों ने अच्छी भूमिका निभाई है। इन संस्थाओं ने अनेक संस्कारों गैर-सरकारी निषकों के साथ कारगर सहाय्य किया है। कई सामुदायिक परितैजिक भारत सरकार के विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा ग्रामीण पहिलाओं के लिए जल, स्वास्थ्य, संचारता पर आयोजित अखिल भारतीय समन्वित परियोजनाओं के निष्पादन में सीधे शामिल हैं। उनसे से कई सामुदायिक सहायता सेवाएँ जैसे सामुदायिक बायो-गैस पद्धति, सामुदायिक कुड़ा निपटन पद्धति तथा जल स्वास्थ्य व सफाई जागरूकता कार्यक्रमों पर स्वास्थ्य सेवाओं योजना व कार्यन्वयन में सक्रिय रूप से व्यस्त हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उत्पन्न करना

7.20.4 योजना के माध्यम से मुख्य रूप से रोजगार गैर औपचारिक अल्पकालिक प्रशिक्षण उपलब्ध करना है, विभिन्न स्तरों में संक्षमता तथा आवश्यकता आधारित पाठ्यक्रमों के माध्यम से अथवा आवश्यकतानुसार बहुदक्षता के माध्यम से हैं ये संस्थाएं मंरीक वर्ष 25,000 ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षित करती है। इनमें से लगभग 35-40 प्रतिशत स्त्रोजगार में लग जाते हैं।

- 7.20.5 इन योजनाओं से उपलब्ध कराए गए रोजगारों को हम विस्तृत रूप से तीन श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं -
- (i) इस योजना में सीधे चलन रोजगार,
 - (ii) अतिरिक्त धुवकों को खत रोजगार,
 - (iii) ग्रामीण परियोजनाओं/उद्योगों तथा सेवाओं में चलन रोजगार,

7.20.6 वर्ष के दौरान स्कूल बीच में जोकर जाने वालों सहित 20,000 से अधिक ग्रामीण युवाओं व महिलाओं को, विभिन्न तंत्रोंको/व्यावसायिक व्यावसायों में प्रशिक्षित किया गया है तथा उनमें से कई स्व रोजगार में लग चुके हैं।

7.20.7 वर्ष के दौरान योजना के कार्यन्वयन तथा इसके अक्षरों के पुनरीक्षण के लिए इलाहाबाद, भोपाल, कानपुरा, भद्रास में चार क्षेत्रीय कार्यशालाएं तथा इसके साथ ही दिल्ली में क्षेत्रीय टी टी आई सम्मन्धकों की राष्ट्र स्तर की बैठक आयोजित की गई थी। (1) महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम (2) आय-व्यापन, तन्त्रीकी आर्थिक क्रियाकलापों द्वारा नव-साक्षरों के लिए उत्तर साक्षरता सतत शिक्षा (3) क्षेत्र विशिष्ट व संस्कृति विशिष्ट जनजाति क्षेत्र सघटक कार्यक्रम (4) (1) कम लागत के घर (ii) ग्रामीण लोगों के लिए सुरक्षित पीने का पानी (iii) ग्रामीण सञ्चरता (iv) गैर पारंपरिक व वैकल्पिक उर्जा स्रोत (v) कृषि फार्मिंग व कृषि सिंचाई तथा (vi) ग्रामीण परिवहन वाली ग्राम्यिक क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी स्थानांतरण आदि को महत्व देने हुए योजना के कार्यक्रमों व कार्यक्रमकारों के विस्तार का प्रस्ताव है।

7.20.8 अगस्त, 1991 में इसके रजत जंयती समारोह के दौरान टी टी टी आई, भोपाल से सामुदायिक पालिटेक्निक पर भद्रश्री आयोजित की गई थी। मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह ने भद्रश्री का शुभारंभ किया तथा सामुदायिक पालिटेक्निक के कार्यकलापों की प्रशंसा की।

प्रशिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम

7.21.1 प्रशिक्षुता अभिनियम, 1961 (ये संशोधित) के अन्तर्गत इंजीनियरी स्नातकों तथा डिप्लोमाधारियों के लिए प्रशिक्षुता कार्यक्रम कानपुर, कलकत्ता, बम्बई तथा भद्रास स्थित चार प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्डों के माध्यम से कार्यवीर्यत किया जा रहा है। उद्योगों के साथ बहुत साने के लिए बोर्डों की राज्य स्तरीय समितियां हैं। प्रशिक्षुओं को दिया जाने वाला वजीफा प्रशिक्षण संस्थाओं तथा भारत सरकार द्वारा आधा-आधा वहन किया जाता है।

7.21.2 पिछले तीन वर्षों के दौरान 31 अक्टूबर की स्थिति के अनुसार मंरीक वर्ष कार्य में लगे प्रशिक्षुओं की संख्या नीचे सारणी में दी गई है:

सारणी 7.4
प्रशिक्षुओं की संख्या

	31 10 88	31 10 90	31 10 91
कुल अधिकारी	21736	21053	22075
आगत प्रशिक्षुओं	6102	6042	6879
डिप्लोमाधारी	15634	15011	15196
अनुसूचित जाति	838	714	908
अनुसूचित जनजाति	171	148	167
अन्यसंयुक्त	1456	1057	1335
विद्यार्थी	11	10	33
महिलाएं	1345	1836	2089

7.21.3 बोर्डों द्वारा कुछ इंजीनियरी कालेजों तथा पालिटेक्निकों के अतिरिक्त वर्ष के छात्रों के लिए प्रशिक्षुता प्रशिक्षण की कोटि में सुधार तथा जीवन वृत्तिक मार्गदर्शन कार्यक्रम के लिए कई पंचवर्षी विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए। बोर्ड, सूचना प्रद लेखों की प्रकाशनाएं भी प्रकाशित करते हैं। इनमें से कुछ प्रशिक्षण सैनुअल भी तैयार करते हैं।

7.21.4 10+2 व्यावसायिक छात्रों के लिए प्रशिक्षुता प्रशिक्षण की एक नई योजना भी वर्ष 1988-89 से शुरू की गई थी।

7.22.1 प्रशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान, बैकाल एक स्वायत्त अंतराष्ट्रीय संस्थान है, जो इंजीनियरी विज्ञान और सभ्यत्व विषयों में उच्च शिक्षा प्रदान करता है। यह 20 से अधिक देशों से लगभग 600 छात्रों को परिक्षण करता है और इसके अंतराष्ट्रीय संकाय सदस्य हैं। यह संस्थान भारत सहित विभिन्न देशों के सदस्यों के एक अंतराष्ट्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा अभिशासित है जिसके सदस्य भारत सहित विभिन्न देशों से आते हैं।

7.22.2 भारत सरकार प्रशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान (ए-आई-टी-डी) की निर्मितरित सहायता प्रदान करते के लिए संस्थान हो गई है -

- इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी के विशिष्ट क्षेत्रों में भारतीय शिक्षकों/विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति के संपूर्ण खर्च का वहन।
- निर्मितरित एक या अधिक अक्षरों के प्रयोग के लिए 3.00 लाख रु० के वार्षिक अनुदान का उपयोग -
- (क) भारत से उपकरणों की खरीद
- (ख) पुस्तकों की खरीद तथा घरत में प्रकाशित अकादमीय तथा तकनीकी के चन्दे के लिए भुगतान, तथा
- (ग) भारत में शिक्षा संबंधी गतिविधियों पर व्यय।

7.22.3 वर्ष 1991-92 के दौरान भारत सरकार द्वारा विदेशी यात्रा पर पूर्ण रूप से बंद होने के कारण 9 भारतीय विशेषज्ञ ए-आई-टी-डी बैकाल में प्रतिनियुक्त किए गए। संस्थान की भारत में उपकरण की खरीद व शिक्षा से सम्बंधित कार्यकलापों के लिए 2,99,472 रु० का अनुदान दिया गया।

शैक्षिक अर्हता मूल्यांकन बोर्ड

7.23.1 यह मूल्यांकन बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत पदों और सेवाओं में पदों के लिए शैक्षिक और व्यावसायिक अर्हताओं को मायता प्रदान करने के प्रयोजनार्थ भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। शिक्षा विभाग में तकनीकी शिक्षा व्यूरो इस बोर्ड के सचिवालय का कार्य करता है और अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग इस बोर्ड के अध्यक्ष है।

7.23.2 आलोच्य वर्ष के दौरान मूल्यांकन बोर्ड द्वारा मायता हेतु विचार के लिए आठ विशेषज्ञ समिति बैठकें/उप-समिति बैठकें आयोजित की गईं।

अन्तर्राष्ट्रीय सञ्चालनों से ध्यान लेने के लिए अतिरिक्त विनियम सहायता

7.24.1 तकनीकी शिक्षा व्यूरो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी और शिक्षा सम्मेलन के क्षेत्र के शिक्षकों को स्वार्ह किया, की यात्रा का खर्च देने के लिए आंशिक विनियम सहायता योजना का प्रबंध करता है। विशिष्ट युवा शिक्षकों पर विशेष रुचि से विचार किया जाता है।

गैर निर्गमित तथा असंगठित क्षेत्रों के संस्थानों का सुदृढीकरण व स्थापना

7.25.1 हमारी तकनीकी और अव्वक्रीय शिक्षा पद्धति का अनुसंधान अभी तक मुख्यतः संगठित निर्गमित क्षेत्र की ओर उन्मुख हो रहा है। तथापि हमारे विकास प्रयासों का विशेष प्रभाव केवल तभी सम्भव होगा यदि हम गैर निर्गमित और असंगठित क्षेत्रों के निष्पादन में सुधार करते हैं जो लगभग 90% कार्य बल को रोजगार प्रदान करता है।

7.25.2 इसके अनुसार, सालों व आठवों पंचवर्षीय योजना के दौरान इस उद्देश्य के लिए विद्यमान संस्थानों की सुदृढ करने के लिए योजना तैयार की गई।

इन क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश भर में कुछेक चुनिन्दा इकाइयों सर की संस्थाओं में उद्यमशीलता तथा प्रबंध विकास केन्द्रों और उद्यमशीलता विकास केन्द्रों की स्थापना का प्रावधान है।

7.25.3 इस योजना को केन्द्र से वितीय सहायता प्रदान करके चार पालीटेक्नीकों में एक पाल्पेट प्रोजेक्ट के रूप में नियमित किया जा रहा है। आठवों पंचवर्षीय योजना के दौरान इस योजना में उद्योग-संस्थान अंतर्किया योजना को समीक्षित करके, इसके क्षेत्र एवं गतिविधियों को कायम रखने तथा उनका विस्तार करने की भी परिकल्पना की गई है।

7.26.1 उद्योग संस्थान अंतर्किया

उद्योग संस्थान अंतर्किया की योजना वर्ष 1988-89 के मध्य शुरू की गई थी। योजना के निम्न तीन मुख्य तत्व हैं-

- (क) इंजीनियरी कालेजों तथा उद्योगों के बीच अंतर्किया।
- (ख) पालीटेक्नीकों तथा उद्योगों के मध्य अंतर्किया।
- (ग) आई-आईटी, दिल्ली में एक "प्रौद्योगिकी प्रतिष्ठान" की स्थापना।

7.26.2 चुनिन्दा इंजीनियरी कालेजों के विषय में इस योजना में उद्योग और संस्थान के बीच एक संयुक्त परियोजना को परिकल्पना की गई है। इसने प्रति संस्थान के लिए दो संकाय सदस्यों के अनुपात से उद्योग के

साथ संकाय आदान-प्रदान की परिकल्पना भी की गई है। पालीटेक्निक स्तर पर संकाय आदान-प्रदान केवल दो संकाय सदस्यों के अनुपात में होगा।

7.26.3 इस उद्देश्य के लिए, 23 इंजीनियरी कालेज तथा 156 पालीटेक्निक चूने गए। इस योजना के अंतर्गत अब तक स्वीकृत 21 इंजीनियरी कालेजों और 11 पालीटेक्नीकों में से 18 इंजीनियरी कालेजों तथा 6 पालीटेक्नीकों में संकाय आदान प्रदान कार्यक्रम शुरू कर दिया है। अब तक वर्ष 1990-91 के लिए चार परियोजनाओं को स्वीकृत दे दी गई है। इस वर्ष 12 और नई परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं। इन परियोजनाओं पर, इसी प्रयोजन के लिए गठित विशेषज्ञ समिति विचार करेगी।

7.26.4 आई आई टी दिल्ली में स्थापित किया जाने वाला प्रस्तावित प्रौद्योगिकी अनुसंधान प्रतिष्ठान उद्योग द्वारा आयोजित वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी की समस्याओं के समाधान के लिए संस्थान के अनुसंधान तथा परामर्शो समताओं के निष्पादन तथा साथ ही नवाचार और प्रौद्योगिकी अपन करने के लिए उत्तरदायी होगी।

सतत शिक्षा

7.27.1 फरवरी, 1988 में शुरू किए गए सतत शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योगों तथा अन्य क्षेत्रों में सेवाएत व्यवसायियों की सतत विकसित करना है जिससे कि देश के भीतर इंजीनियरी और प्रबंध जनशक्ति का स्तर उच्चा हो सकेगा।

7.27.2 इस प्रयोजन के लिए आरंभ में 10 केन्द्र तय किए गए जिनमें 5 आई-आईटी-ए 4 टी-टी-आई-आई तथा मैसूर स्थित आई-एस-टी-आई शामिल हैं। मैसूर स्थित आई-एस-टी-आई केन्द्र शिक्षण माध्यमों का परीक्षण भी करता है तथा इस कार्यक्रम का संपूर्ण शैक्षिक समन्वय तथा भागीदारी करता है।

7.27.3 अब तक पिछ-पिछ क्षेत्रों की 129 पाठ्यक्रम सामग्री तैयार की जा चुकी है तथा प्रशिक्षण माध्यमों के आधार पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों से लगभग 28,900 सेवाएत व्यवसायियों को लाभ पहुंचा है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को स्वतःपेयण आधार पर आयोजित किया जाता है।

7.27.4 इन कार्यक्रमों की सफलता को देखते हुए, इस योजना के कार्यक्रम के लिए आठ और केन्द्रों को शामिल किया गया है।

तकनीकी शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान तथा विकास:-

7.28.1 उक्त योजना 1987-88 के दौरान निम्नलिखित उद्देश्यों को लेकर शुरू की गई थी:-

- उच्च अध्ययन/अनुसंधान के मीजुद केन्द्रों का सुदृढीकरण तथा पुनर्संरचना।
- भूतन्त्र ढांचे की रचना तथा इसे अद्यतन बनाना।
- इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी तथा प्रबन्ध में अनुसंधान परियोजनाओं को सहायता तथा प्रयोजन।

7.28.2 वर्ष 1991-92 के दौरान 44 परियोजनाओं का वित्तपोषण किया गया। यह योजना अपेक्षितवा बड़ी सख्या में इंजीनियरी कालिजों में अनुसंधान की प्रोत्साहन देने में सहायक रही। इस योजना में भौतिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, प्रबन्ध प्रौद्योगिकी ऊर्जा प्रबंध, उच्च वास्तु इंजीनियरी, रसायन इंजीनियरी, संचित शक्ति सामग्री, तत्सु विज्ञान संरचनात्मक

इंजीनियरी एवं यातायात इंजीनियरी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल किया गया। युवा संकथ सदस्यों के प्रस्तावों पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

भारत शैक्षिक परामर्शदाता लिमिटेड, नई दिल्ली:

7.29.1 इस मंत्रालय के अधीन आने वाला एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र संस्थान भारत शैक्षिक परामर्श लि. 17 जून, 1981 को कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन स्थापित किया गया था। यह केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स के मार्गदर्शन में कार्य करता है। इसमें एक अशर्कालिक गैर-सरकारी अध्यक्ष तथा पूर्णकालिक प्रबंध निदेशक हैं।

7.29.2 वर्ष 1990-91 के दौरान निगम ने एशियाई विकास बैंक को तकनीकी सहायता (टीएच) प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए एक ही वर्ष में तीन बार चुना गया और बंगला देश में एक मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु चयन किया गया। मारोशस विश्वविद्यालय का मास्टर प्लान तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण परियोजना को सफलता पूर्वक पूरा कर लिया गया और मास्टर प्लान के कार्यान्वयन को शुरू कर दिया गया।

7.29.3 देश में इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन और प्रौद्योगिकी केन्द्र, कलकत्ता को स्थापना का महत्वपूर्ण कार्य पूरा हो गया है और यह भवन सौंप जाने के लिए तैयार है। इसने देश में तकनीकी शिक्षा (पालेटेक्निकों) को सुदृढ़ करने के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजना को तैयार करने में भी सहायता पहुंचाई है।

7.29.4 सिने इथोपिया, जाम्बिया, मारोशस और जोर्डन को शैक्षिक सहायता की आपूर्ति को भी सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

7.29.5 वर्ष 1990-91 के लिए कंपनी की आय 3.40 करोड़ रुपये है। निगम के टैक्स देने के पश्चात् वर्ष 1990-91 के लिए कुल आय 17.31 लाख रु. है।

7.29.6 कंपनी ने वर्ष 1990-91 के लिए 7.50 लाख रु. के लामाश की आदायगी करने की घोषणा की है।

उपस्करों तथा उपभोग्य वस्तुओं के आयात के लिए पास बुक योजना/सीमा शुल्क छूट प्रमाण-पत्र।

7.30.0 अनुसंधान के कार्यों के लिए वैज्ञानिक उपस्करों के तेजी से आयात तथा उन्हें प्राप्त करने के लिए वर्ष 1988 से एक पास बुक योजना शुरू की गई है।

इसके द्वारा वैज्ञानिक तथा तकनीकी उपस्कर, साज-सामान तथा उपभोग्य वस्तुओं के आयात शुल्क के बिना ही आयात करने की छूट मिलेगी। इस योजना के अन्तर्गत, आयात के लिए सस्था के प्रमुख को यह प्रमाणित करने का अधिकार होगा कि इसकी बहुत जरूरत है तथा "इसका निर्माण भारत में नहीं होता", की शर्त भी पूरी होनी चाहिए। अनुमानित सीआईएफ़ कोमत की अधिकतम सीमा एक वर्ष के लिए उपस्कर के लिए 3 करोड़ रु. तथा उपभोग्य वस्तुओं के लिए 1.5 करोड़ रु. होगी। इसमें कोई एक उपभोग्य वस्तु शामिल नहीं होगी जिसकी एक वर्ष में कुल सीआईएफ़ कोमत 5 लाख रुपये से अधिक होती है तथा कोई एक उपस्कर तथा साज-सामान जिसकी सीआईएफ़ कोमत 5 लाख रु. से अधिक होती है जिसके लिए सीडीआई प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। इस योजना में राष्ट्रीय महत्व के निजी रूप से वित्त पोषित अनुसंधान सस्थाएं तथा कलेज भी शामिल हैं। शिक्षा विभाग में

तकनीकी शिक्षा ब्यूरो विश्वविद्यालय, कलकत्ता तथा संस्थाओं को पास बुक जारी करने के लिए जिम्मेदार है। 30 नवम्बर, 1991 तक की रिपोर्टों के अनुसार अधिकांश के दौरान लगभग 222 पास बुके तथा 1025 सीडीआई प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं।

संत लॉगोवाल इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी संस्थान:-

7.31.1 संत लॉगोवाल इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना पंजाब राज्य में विरोध तकनीकी जनशक्ति को पूरा करने के लिए की जा रही है। यह सस्था विभिन्न स्तरों पर कई तरह से पाठ्यक्रमों को प्रदान करेगी ताकि राज्य की विशिष्ट जरूरतों को संभूक्त तरीके से पूरा किया जा सके। वर्ष 1992-93 के दौरान, प्रारम्भ में आवश्यक अवस्थापना का सृजन करके शैक्षिक सत्र को निम्नलिखित पांच प्रमाण पत्र तथा तीन डिप्लोमा पाठ्यक्रमों से शुरू किया गया -

प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम:

- 1 इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्रों की सर्विस तथा रखरखाव।
- 2 टी.वी. मैकेनिक।
- 3 डाटा एन्ट्री आपरेशनस तथा वर्ड प्रोसेसिंग।
- 4 कम्प्यूटर सर्विस तथा रख, रखाव।
- 5 वेल्डिंग।

डिप्लोमा पाठ्यक्रम:

- 1 इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरी
- 2 इन्स्ट्रुमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल
- 3 कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग अथवा प्रयोग।

7.31.2 वर्ष के दौरान कुल 176 छात्रों, जिसमें से 20% लड़कियाँ थीं, ने दाखिला लिया राज्य की वास्तविक जनशक्ति की जरूरत के अनुसार डिग्री पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए संस्थान में और विस्तार करने तथा स्तरोन्नत करने पर विचार किया जाएगा।

7.31.3 इस संस्थान का 20 दिसम्बर, 1991 को मानव ससाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह द्वारा औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के घाघ्यप से तकनीकी संस्थाओं को सहायता प्रदान क रना।

7.32.1 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्चतर शिक्षा अनुसंधान के विकास के लिए इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी में विश्वविद्यालय व्यवस्थित संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

योजना के अन्तर्गत इस समय 32 ऐसे विश्वविद्यालय व्यवस्थित संस्थाओं को शामिल किया गया है। अवर स्नातक शिक्षा सुविधाएं प्रदान करने के अलावा, ये संस्थाएं इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी के विभिन्न विषयों में काफी संख्या में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चला रही हैं। इनमें से कुछ संस्थाएं प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाने के लिए उच्चतर स्तर पर मौलिक तथा प्रायोगिक अनुसंधान कार्य में लगी हैं। तथा उन्होंने अपनी उपलब्धियों से राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त किया है विभिन्न अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रमों को जारी रखने तथा विभिन्न सुविधाओं जैसे कि शिक्षण, भवन प्रयोगशालाएं, छात्रावास तथा स्टाफ क्वार्टरों के समेकन के लिए विश्वविद्यालय व्यवस्थित संस्थाओं के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है।

7.32.2 विश्वविद्यालय व्यवस्थित संस्थाओं में विभिन्न स्नातकोत्तर

पाठ्यक्रमों में इस समय लगभग 1600 एम-ई/एम-टैक के छात्र दाखिल हैं।

उच्च तकनीक-शिवन पाठ्यक्रम:

7.33.1 अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने फरवरी 1978 में आयोजित अपनी बैठक में सिफारिश की कि चुनिन्दा पालिटेक्निकों को वित्तीय सहायता दी जाए ताकि वे उच्च तकनीकी पाठ्यक्रम शुरू कर सकें जिससे तकनीक-शिवन उद्योग और ग्रामीण क्षेत्र की भिन्न-भिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अर्पणित समता (योग्यता) प्राप्त कर सकें। इस सिफारिश के अनुसार वर्ष 1981-82 में छठी योजना में उच्च तकनीकी पाठ्यक्रम की एक योजना शुरू की गई। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, उपकरण इंजीनियरी, गडार्ड प्रौद्योगिकी, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक, वातानुकूलन और प्रशीतन, ऊर्जा के परिवर्तनीय साधन और ग्रामीण प्रौद्योगिकीय विकास एवं प्रबंध, जैसे महत्वपूर्ण विषयों में उच्च तकनीकी पाठ्यक्रम आरम्भ करने के लिए दस संस्थाओं को चुना गया।

7.33.2 उच्च तकनीकी पाठ्यक्रम योजना पर पुर्णविचार करने के लिए 11 से 13 सितम्बर, 1991 को एस बी एम पॉलिटेक्निक, बम्बई में एक कार्यशाला आयोजित की गई। विभिन्न संस्थानों में वर्तमान उच्च तकनीकी पाठ्यक्रम को जारी रखने तथा उच्च तकनीकी पाठ्यक्रम योजना के क्षेत्र एवं कार्यकलाप का संशोधित तथा अद्यतन मानकपत्रों के अनुसार विस्तार किए जाने की सिफारिश की। इसके साथ-साथ यह भी सिफारिश की गई कि इस योजना के अंतर्गत शुरू किए गए उच्च डिप्लोमा पाठ्यक्रम, सम्बद्ध क्षेत्र में इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी में प्रथम डिग्री के समकक्ष समझे जाए।

7.33.3 आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त तकनीकी शिक्षा क्षेत्रीय परियोजना के अन्तर्गत इस योजना के क्षेत्र तथा कार्यकलापों के विस्तार तथा मशीनगत अद्यतन मानकपत्रों से योजना के कार्यान्वयन का भी प्रस्ताव किया गया।

सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम

7.34.0 अधिकांश सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों में विज्ञान, शिक्षा एवं प्रौद्योगिकी आदि के क्षेत्र की मामलों के आदान-प्रदान का प्रावधान है। मनुष्य इसके साथ-साथ रोजगार के उद्देश्य से भारत तथा दूसरे देशों में प्रदान की जानी वाली डिग्री और डिप्लोमा में साम्यता लाने के लिए दोनों देशों की उच्च शिक्षा संस्थाओं के बीच शैक्षिक सम्बन्ध बनने के लिए शिष्टमण्डलों के पारस्परिक दौरे भी शामिल हैं।

तकनीकी शिक्षा के लिए कोलम्बो स्टाफ कालेज योजना

7.35.1 तकनीकी-शिक्षा के लिए कोलम्बो स्टाफ कालेज योजना, मनीला का मुख्य लक्ष्य कोलम्बो योजना क्षेत्र में तकनीक-शिवन शिक्षा और प्रशिक्षण की पुनर्वता में सुधार करना है जिसे सदस्य देशों में सेवारत प्रशिक्षण एवं स्टाफ विकास कार्यक्रम में सक्रिय भाग लेने वाले तकनीकी शिक्षकों, शिक्षाकोविदों, प्रशिक्षकों तथा तकनीकी शिक्षा पद्धति के स्टाफ की जरूरतों को पूरा करके प्राप्त किया जा सकता है। कालेज के मुख्य कार्य हैं—

1. व्यवसायिक तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम प्रदान करना;
2. तकनीकी शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन सम्मेलन आयोजित करना;
3. विशेष पाठ्यक्रमों को आरम्भ करने में सहायता करना;

4. अनुसंधान करना और उसे बढ़ावा देना तथा उसका समन्वय करना।

5. प्रशिक्षण सुविधाओं के विकास में सहायता करना;

6. तकनीकी शिक्षा के बारे में सूचना एकत्रित करना तथा उसका प्रसार करना।

7.35.2 उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तकनीकी शिक्षा के लिए कोलम्बो स्टाफ कालेज योजना, मनीला ने कालेज आधारित पाठ्यक्रम, उपक्षेत्रीय कार्यशालाएं और स्वदेशी पाठ्यक्रम जैसे कई कार्यक्रम आरम्भ किए हैं। भारत सरकार सी बी एस सी के कार्य-कलापों में सहायता करती है तथा इसके कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए निम्न सदस्य तकनीकी शिक्षा प्रशासकों को आयोजित करती है।

उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी संस्थान:

7.36.1 उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी संस्थान 1985 में इटानगर (अरुणाचल प्रदेश) में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों के लिए विज्ञान धाराओं के साथ-साथ इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कुशल जनशक्ति पैदा करने के लिए स्थापित किया गया था। जहां शिक्षा विभाग उन्पु-क्षेत्रीय/प्रौद्योगिकी संस्थान को आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन दे रहा है वहीं इसे उत्तर पूर्वी परिषद् के माध्यम से वित्तीय सहायता भी दी जा रही है। उन्पु-क्षेत्रीय/प्रौद्योगिकी संस्थान की प्रौद्योगिकी तथा प्रायोगिक विज्ञान के क्षेत्र में दो वर्ष की अवधि वाले प्रमाण-पत्र डिप्लोमा, डिग्री के लिए माध्यम कार्यक्रमों की श्रृंखला के लिए एक अकेले संस्थान के रूप में माना जाता है। संस्थान ने अगस्त, 1986 में अपना शैक्षिक कार्यक्रम आरम्भ किया जिसमें प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों को दाखिला दिया गया। डिप्लोमा तथा डिग्री पाठ्यक्रमों के दाखिले क्रमशः 1988 और 1990 में किए गए। इस संस्थान में निम्न पाठ्यक्रम प्रदान किए जाते हैं:—

प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम

1. निर्माण प्रौद्योगिकी
2. अनुरक्षण इंजीनियरी (इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रॉनिक्स)
3. अनुरक्षण इंजीनियरी (यांत्रिक)
4. वन विज्ञान
5. धूमि संरक्षण।

डिप्लोमा पाठ्यक्रम:

1. कृषि इंजीनियरी
2. सिविल इंजीनियरी
3. कम्प्यूटर विज्ञान
4. इलेक्ट्रॉनिक एवं इलेक्ट्रिकल संचार इंजीनियरी
5. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी
6. यांत्रिक इंजीनियरी

डिग्री पाठ्यक्रम:

1. कृषि इंजीनियरी
2. सिविल इंजीनियरी
3. कम्प्यूटर विज्ञान
4. इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरी
5. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी
6. यांत्रिक इंजीनियरी

7. वन-विद्या

लिए उत्तर पूर्वी हिल यूनीवर्सिटी से अध्ययी तौर पर सम्पन्न किया ग
है।

7.36.2 1990-91 से उन्पूर्वी क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान को तीन वर्ष के

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

8. ग्रीक शिक्षा

8.1.1 ग्रीक साक्षरता मिशन, जो वर्ष 1995 तक 15-35 आयु वर्ग में 80.00 मिलियन निक्षेपों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने के उद्देश्य से मई, 1988 में आरंभ किया गया था, अपने संचालन के चौथे वर्ष से प्रवेश कर गया है। इस मिशन ने कई बार इस बात की पुष्टि की है कि निक्षेपता का अमूल्य एक अव्यवहार्य संकल्प नहीं है बल्कि यह संभव, व्यवहार्य है और इसे प्राप्त किया जा सकता है। पहला स्वसाधक संकेत, भारत के महा-परीक्षक और जनगणना आयुक्त द्वारा जारी किए गए वर्ष 1991 की जनगणना के आधारेण आंकड़ों से मिला। पहले बार, देश ने 50 प्रतिशत की सीमा को पार करते हुए साक्षरता दर के साथ, निक्षेपों की अपेक्षा साक्षर व्यक्तियों की बड़ी संख्या की विशिष्टता को प्राप्त किया है।

8.1.2 एक और महत्वपूर्ण विकास देश में ग्रीक शिक्षा कार्यक्रम के अनेक शैक्षिक वैकल्पिक मॉडलों के परीक्षण के बाद, हमने एक मॉडल को अंतिम रूप से निर्धारित किया है जिससे हमें काफी आशा स्थिति है और विष्णवास प्राप्त हुआ है कि निक्षेपता पर निजीगत और सार्वजनिक प्रयासों तथा समाज के सभी वर्गों के लोगों के संघटन के समन्वयक रूप में काम चला जा सकता है। अधिकारिता सभी रखी है इसे एक व्यवहार्य प्रभाव के रूप में स्वीकार कर लिया है और इसकी अनुपयोगिता को देश के विभिन्न भागों में प्राप्त की गई साक्षरता (वर्षा एक विविध मानक के) तथा अन्तर्देशीय रूप से प्रदान की गई मापता से भी ओका जा सकता है। एनीकुलम जिले में अधिमान संघर्ष के जरिए प्राप्ता की गई आर्थिक सफलता के बाद, पश्चिम बंगाल में बर्द्धमान जिले, संघ शक्ति क्षेत्र पण्डितपुर, महाप्राइ सिंधुदुर्ग और कर्नाटक में दक्षिण कन्नड़ जिले को पूर्ण रूप से साक्षर घोषित कर दिया गया है।

वर्ष 1991 को जनगणना की प्रभावशाली विशेषताएं:—

8.2.1 देश के साक्षरता आंकड़े भारत के महा पंजीकृत द्वारा संकलित दशवर्षीय जनगणना कार्यक्रमों पर आधारित हैं। 1991 जनगणना जो वर्ष के पहले पाग में हुई थी की अन्तिम आंकड़े यह दर्शाते हैं कि देश में 7 वर्ष की आयु और इससे ऊपर की जनसंख्या के लिए साक्षरता दर जो 1981 में 43.56 प्रतिशत थी वह 1991 में बढ़कर 52.11 प्रतिशत हो गई है और 8.55 प्रतिशत व्यावृद्ध की वृद्धि पंजीकृत (टिक्स्ट) हुई है। कर्नाक पुरुष साक्षरता दर 56.37 प्रतिशत से 63.86 प्रतिशत तक बढ़ गई है और महिला साक्षरता दर 29.75 प्रतिशत से 39.42 प्रतिशत से बढ़ गई है।

8.2.2 अपर्युक्त आंकड़ों से निम्नलिखित प्रभावशाली विशेषताएं निरूपित हुई हैं:

— 1981 और 1991 के बीच साक्षरता की विकास दर 8.55 प्रतिशत है जो 1971—81 के बीच साक्षरता की विकास दर के साक्ष्य समीची आ सन्तुष्टी है और यह 6.97 प्रतिशत की।

— देशक के दोन महिला साक्षरता (9.67%) के विकास की दर पुरुष साक्षरता (7.49%) से अधिक है।

— 1991 में साक्षरों (7 वर्ष की आयु और इससे ऊपर) की संख्या जो 352.00 मिलियन थी वर्ष 1981 में 234.00 मिलियन में साक्षरों की संख्या से बहुत दुर्लभी है।

— 1991 में निक्षेपों (7 वर्ष और इससे ऊपर) की संख्या 324 मिलियन के क्रम में है जो 1981 में 302 मिलियन से अधिक वृद्धि है।

— 1991 में साक्षरों की संख्या में वृद्धि 118 मिलियन हुई जबकि निक्षेपों की संख्या में अनुपम वृद्धि मात्र 22 मिलियन की।

— मिजोरम (81.23%), लक्षद्वीप (79.23%) और चंडीगढ़ (78.73%) के अनुपम में केवल की साक्षरता दर (90.59%) में सबसे ऊपर है।

— इस सीटी के अंत में बिहार (38.54%) गुजरात (38.81%) और दादर और नगर हवेली (39.45%) है। महिला साक्षरता दरों में वृद्धि राज्य/संघशासित क्षेत्र सिक्किम (19.88%)

— लक्षद्वीप (15.56%) नागालैण्ड (15.44%) दमन और दीव (14.37%) हरियाणा (14.05%) मणिपुर (14.03%) अरुणाचल तथा निकोबार द्वीप समूह (13.07%) पण्डितपुर (12.76%) त्रिपुरा (12.00) और केरल (11.28%) में बहुत शीघ्र रही है।

— 22 राज्यों/संघशासित प्रदेशों में साक्षरता दर अखिल भारतीय साक्षरता दर 52.11 प्रतिशत से अधिक है परंतु बिहार, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मेघालय, छत्तीसगढ़ के आठ राज्यों और संघशासित प्रदेश दादर तथा नगर हवेली में महत्वपूर्ण साक्षरता दर अभी भी 50% से कम है। मेघालय को छोड़कर ये सभी राज्य/संघशासित प्रदेश महिला साक्षरता के मामले में अखिल भारतीय स्तर से भी नीचे हैं।

8.2.3 वर्ष 1981 और 1991 के लिए 7 आयु वर्ग और इससे ऊपर की जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता दर दर्शाते वाला एक तुलनात्मक विवरण-4 में दिया गया है।

समग्र साक्षरता अधिमान

8.3.1 समग्र साक्षरता के अधिमानों में इसकी शुरुआत पर प्रमुख बल दिया गया है। इसमें प्रमुख कार्य नीति का भी गठन किया गया है। पर-पुनरुत्थान और केवल में पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने से हुई सफलता से इन अधिमानों में कुछ ऐसी विविधता पाते उजागर हुई हैं जो इन अधिमानों को बेजोड़ बनाते हैं और ये अन्य कार्यक्रमों से निम्न हैं। ये अधिमान क्षेत्र-विशिष्ट, समन्वयक स्वयं सेवा पर आधारित, लागत प्रभावी और उत्पादनीय हैं। ये अधिमान आम तौर पर जिला साक्षरता समितियों द्वारा ही चलाये जाते हैं, जो जिला समाहले मुख्य सचिव/परिपट की उपलब्धता

में सीमावर्ती दलीकरण अधिभयान के अंतर्गत पंजीकृत होते हैं। सर्वो के दौधन नये दृष्टिकोणों में कुछ विशिष्ट लक्ष्यों का अवलोकन किया गया है। ये लागू निर्धारित हैं:-

— समग्र साक्षरता अधिभयान मांग तथा आयुर्वी सेवों की मांगों को पूरा करते हैं। दूसरे शब्दों में लोगों की आयुर्वी तंत्र की व्यवस्था करने से पूर्व ही संस्थापनक मांग उत्पन्न हो जाती है।

— समग्र साक्षरता अधिभयानों में गुणवत्ताक संस्कृति की इलाक मिलती है। यह जन-अधियान के रूप में कार्यान्वित की जाती है जहाँ कहीं भी कोई सी व्यक्ति इसे अपना सकता है, योगदान कर सकता है और इसमें भाग ले सकता है। यह एक गाँव की बात है और यह गाँव के लोगों, भट्टेली पंचायत उपखंडा तापुक् अध्याय और तक मिलों को भी अपना समय, शक्ति का योगदान करने में आकर्षित करते हैं और इन अधिभयानों के संसाधन पूरी तरह से स्वयं-सेवी आधार पर चलेते रहते हैं जिससे किसी प्रकार के पुरस्कार, अभिलेख उपखंडा प्रोत्साहन की संभावना नहीं है।

— यद्यपि समग्र साक्षरता अधिभयान को वास्तविक तात्पर्य कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करता है फिर भी यह एक सार्वभौमिक नामांकन तथा कमी-कमी बच्चों को बुझने में बनाए रखने, टीकाकरण, पंचायत समिति वार्तलाप, छोटे परिवार के मानदण्डों का प्रचार-प्रसार, मातृत्व संरक्षण और शिशु देखरेख, महिला संभावना और शक्ति प्रदान और शक्ति एवं सामाजिक सदभावना आदि जैसा अधिभयान भी बन सकता है

— प्रत्येक समग्र साक्षरता अधिभयान जिला, तापुक्/खण्ड, मातृत्व, पंचायत और गाँव स्तर पर जन-अनुष्ठान सुविचारित प्रबंध ढांचा है। यह प्रबंध समितियों अधिकांशतः गैर सरकारी अधिकारियों द्वारा बनायी जाती है और यह अपभार-शारी विहीन तथा सहभागिता के रूप में कार्य करती है जिससे निचले स्तर पर लोगों की भागेदारी को सुकर बनाया जा सकता है।

— जिला समारोह, जो अपने पहले आई० आर० डी० पी०, एर० आर० ई० पी० आर० एर० एर० जी० पी०, ये० आर० आई० आर० जैसे विनोदित कार्यक्रमों के कार्यन्वयन और कार्यन तथा व्यवस्था को बनाए रखने की समस्याओं में पहले से व्यस्त रहते थे, अब नेचल प्रदान करने में प्रेरणा तथा दिशा-निर्देश और इन अधिभयानों के लिए संगठनात्मक संभावना प्रदान करने में समर्थ उभरे रहते हैं और साक्षरता के उपकरण के माध्यम से अब वे सामाजिक परिवर्तन के विश्लेषण एजेन्ड बन गए हैं।

— राज्य सरकारों के समग्र योगदान को न केवल जिला समारोहों के व्यतिरिक्त रूप में धारा लेकर सुनिश्चित किया जाता है बल्कि इन अधिभयानों को नेचल प्रदान कर अन्य भागों और अधिकारियों को इसके लिए नेचल प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जो इनमें भाग लेते हैं और वे इन अधिभयानों के लिए 2:1 के अनुपात में केन्द्र तथा राज्य में इनकी लागत तथा अंश प्रदान करते हैं।

— पू० स० अ० का समग्र महत्त्वपूर्ण पहलू है साक्षरता के अधिभयान में कुछ पूर्व निर्धारित सारों को प्राप्त करने में इसका अवैधिक समर्थन। इसका अर्थ यह है कि प्रयोग की शिक्षण/अध्ययन

समर्थनों को सुनिश्चित करने के लिए जांच कर ली गई है कि निर्धारित न्यायन और पूर्व निर्धारित मानदण्डों के अनुसार है। न दृष्टिकोण में प्रत्येक पाठक द्वारा साक्षरता के कुछ काम से कम से कम और अंश गाना को प्राप्त करने पर बल देता है ताकि ये परिवार सीमावर्ती और देश के विकास में उसके प्रभावी योगदान के लिए भागिदक मुद्रता बन सके।

8.3.2 पूर्ण साक्षरता अधिभयान जो केवल राज्य संभारित प्रदेशा पहिचने और दक्षिण कानक (कर्नाटक) नर्देवन (पश्चिम बंगाल) सिंधु (महाराष्ट्र) में पहले से ही सफलतापूर्वक समाप्त किया गया है, इस समग्र देश के 97 जिलों (क्षेत्रों) में या तो पूर्ण रूप (55) या अंशिक रूप (42) चल रहा है। इस पहिचने के पूर्ण स्तर इस अध्याय के अंत विवरण में दिए गए हैं। राज्य सरकारों, पू० स० के माध्यम से अधिक से अधिक जिलों को शामिल करने के लिए बहुत अधिक प्रयत्नकता रही है। जिला है कि वर्ष के अंत में कुल साक्षरता अधिभयान : अभिलेखित आता है पहले से ही प्राप्त किया जा चुका है।

8.3.3 रिपोर्टों से भी पता चलता है कि जहाँ पचीस पहिचला निर्माण स्थान किया है वहाँ समाज के तत्कालीन सभी वर्गों में उत्साहपूर्वक व किया। इसका प्रमुख महिलाओं, कमजोर वर्गों और जनजातीय क्षेत्रों अधिभयान रहा है। इस उत्साह और अध्ययन स्तरों, अध्ययन, अध्यय कार्यान्वयन और प्रशिक्षण के सार्व में उपलब्धियों से परिचित किए व की सहभागिता को लागूय सभी अधिभयानों में लागू किया जा रहा : अपनी तक प्राप्त हुई रिपोर्टों से पता चलता है कि एक पूर्ण साक्ष अधिभयान के विशिष्ट लाभ के बावजूद, विभिन्न राज्य और उनके व निध्यादन एक समान नहीं रहा है। निर्धारित शर्तों के कारण ग अध्ययनका उत्पन्न हो गई है —

— वर्ष 1990-91 (अगस्त-नवम्बर, 90) के दौरान अशाल सामाजि धन्योत्तक घटनाएँ

— अनेक जिला सभाओं और प्रमुख जिला अधिकारियों का बीच ही स्थानांतरण,

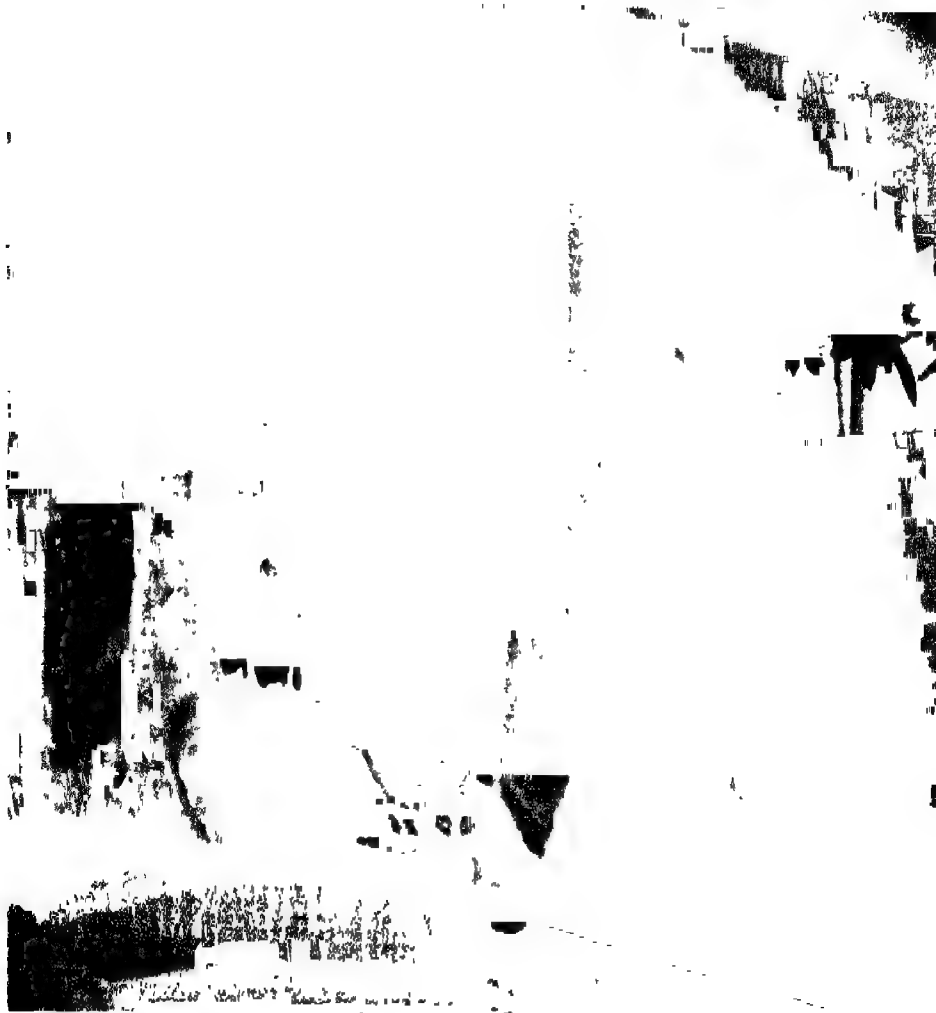
— लोक सभा और राज्य सभा के चुनाव (जिनमें जिला प्रशासन पूर्ण प्रतिक्रिया की मांग की (तथा बाह्य, चक्रवात, खर्च, पूँजा जैसे प्राकृतिक विपदाओं केनेने) सामान्य जीवन को अंश-छा कर दिया और जिला प्रशासन का ध्यान पू० स० अ० से हटा दि

8.3.4 तथापि, इन कमियों के बावजूद वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण सफर प्राप्त की गयी। इन अधिभयानों का सारांश निम्नलिखित है:-

नर्देवन पूर्ण साक्षरता अधिभयान

8.4.0 9-50 वर्ष की आयु वर्ग के 12.00 लाख व्यक्ति-ों को पूर्ण सा बनाने का एक अधिभयान सितम्बर, 1990 में प्रारंभ किया था। अधिभयान के अंत में विशालविद्ये, सामाजिक वैज्ञानिकों, जोड़ शिक्षकों : प्रबंध विशेषज्ञों के दल ने एक निष्पक्ष मूल्यांकन संचालित किया गया यह अवलोकित किया गया था कि पूर्ण साक्षरता अधिभयान पहिचानसंक्रमण स्तरक 9,86,829 व्यक्ति साक्षर बनाये। ये जो साक्षरता दर का 82.22% है। पू० स० अ० नर्देवन अपने कुशल प्र सुचना जिसमें अध्ययन की प्रगति का अनुभवण वैज्ञानिक रूप से किया सकता है, प्रबंध संरचना ऐसी थी कि सीमावर्ती के सभी वर्गों के भाग ले सकते हैं और विभिन्न स्तरों जिला प्रशासन और स्थानीय स्तरा

14 नवम्बर, 1991 को तीन घूँटि भवन में "नए भारत के लिए मूल्य" नामक अख़्बारी का उद्घाटन



निकायों के बीच अच्छा सम्बन्ध होने के कारण प्रतिष्ठित था। उप-पट्टभूति में औद्योगिक रूप से मुख्यमंत्री एवं वकील बाला सरकार के वरिष्ठ अन्य मंत्रियों की उपस्थिति से वर्धमान में आयोजित प्रभावशाली समारोह में 24 अगस्त 1991 को लिखा पूर्ण साक्षर की घोषणा की। वर्धमान के पूर्ण साक्षरता अभियान के सफलतापूर्वक प्रयोग, जिसमें उत्तर-साक्षरता चरण की शामिल किया गया है, ने जिला के सामाजिक भ्रष्टाचि में कुछ महत्वपूर्ण प्रगति को उभारने की अनुमति प्रदान की।

जनक सामाजिक विज्ञान तथा अनुसंधान के किसी भी संस्थान द्वारा इस अभियान के प्रभाव के संबंध में कोई अनुसंधान आयोजित नहीं किया गया। एक चार सदस्यीय गैर सरकारी दल ने (जिसमें एक स्वतंत्र पत्रकारों की शामिल है) (अमरी रिपोर्ट में यह देखा कि इस अभियान से प्राथमिक कक्षा में छात्रों के नामान्न में वृद्धि हुई है और इसमें टीकाकरण अभियान के प्रति उच्च विराट प्रक्रिया हुई है। सामाजिक सत्यता की घोषणा में मिला है, महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है तथा सामाजिक और शैक्षिक परिवर्तन के एक विशालकाय एजेंट के रूप में गांव शिवा समुदाय का भाद्रुभाव हुआ है, तथा विभागों और सरकार संबंधी शिवाकलापी में बेहतर आंतरिक संबंध स्थापित हुए हैं।

परिचालकरी समग्र साक्षरता अभियान

(पुलवाई अरिलेनी इयन्मन)

8.5.0 इस अभियान में यह परिकल्पना की गयी है कि 12000 व्यक्तियों की एक खस-सेवी कोर के माध्यम से 15-45 आयुवर्ग में लगभग एक लाख व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा। कुल साक्षरता अभियान की पहिना पर आधारित था, चलाय गए अग्रेशन अरिलेनी से प्रतिष्ठित परिनाजालक और गुणालक तत्व प्राप्त हुए—

— इस अभियान में 15-40 आयु वर्ग के लगभग 90000 अनुसूचित व्यक्तियों को शामिल किया गया और लगभग 70,000 व्यक्तियों को साक्षर बनाया जिससे 89.04 प्रतिशत साक्षरता दर की उपलब्धि हुई।

— साक्षरता के लिए एक व्यापक प्रकार अभियान चलाया गया था जिससे साक्षरता के लिए एक शानदार जागृति और प्रेरणा उत्पन्न हुई है।

— संच क्षेत्र के सभी गांवों में साक्षरता कार्य के लिए सहभागिता स्मितीया स्थापित की गई थीं, जिनका कार्य संयोजक के रूप में कार्य करते के लिए व्यक्तियों का पता लगाना और एक सूचीबद्ध नेट कार्य के एक मात्र के रूप में शैक्षिक आयोजकों के रूप में था। भूमिका निभाने के लिए उन्हें प्रशिक्षित तथा प्रेरित करना था।

— लगभग 12,000 शैक्षिक कार्यकर्ताओं को अनुदेशकों, सार्वजनिक दलों के सदस्य, सहभागिताओं, संस्कृतिक दलों के आयोजकों, कला के रूप में शैक्षिक आधार पर कार्य करते के लिए अपनी सेवाओं का योगदान देने के लिए जुटाया गया था।

सिंधु दुर्ग में सम्पूर्ण साक्षरता

8.6.1 सिंधु दुर्ग में सम्पूर्ण साक्षरता के लिए कार्यक्रम 1 दिसम्बर, 1990 को शुरू किया गया था। एक सर्वेक्षण अक्टूबर, 1990 में किया गया था। इस सर्वेक्षण के अनुसार 27,830 अथवा 15-35 आयुवर्ग के थे तथा 23746 अथवा 36-60 आयु वर्ग के थे। टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान द्वारा आयोजित सर्वेक्षण के अनुसार प्रतिष्ठित का पता चला है:

— 76.2 प्रतिशत अथवा 36-60 आयुवर्ग के थे जिन्होंने पढ़ीय साक्षरता निगम का मानदण्ड प्राप्त किया है।

— 85 प्रतिशत अथवा 15-35 आयुवर्ग के हैं जिन्होंने पढ़ीय साक्षरता निगम का मानदण्ड प्राप्त किया है। दोनों वर्गों को मिलाने से साक्षरता की उपलब्धता 82.5 प्रतिशत बनती है।

8.6.2 अभियान की शक्ति विभिन्न एजेंसियों के सम्बन्ध पर निर्भर करती है अर्थात् सरकारी विभागों, शैक्षिक संस्थाएँ, स्वयं रखने वाले अलग-अलग व्यक्ति, शैक्षिक संगठन, संचार साधन इत्यादि। इससे जिला, खण्ड तथा ग्राम स्तर पर समुचित समितियाँ बनाई गई हैं और इससे युवान का प्रभाव सुगम बन गया है। यह जिला पूर्ण रूप से शिक्षित घोषित किया गया है। इसकी घोषणा मानव संसाधन विकास मंत्री ने महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री तथा महाराष्ट्र के अन्य वरिष्ठ मंत्रियों की उपस्थिति में एक सार्वजनिक समारोह में 29 दिसम्बर, 1991 को की थी।

दक्षिण कन्नड़ में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान

8.7.1 दक्षिण कन्नड़ में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान 2 अक्टूबर, 1990 में शुरू किया गया था जिसने 2.44 लाख व्यक्ति 9-35 आयुवर्ग के शामिल किए गए थे जिसमें अक्टूबर, 1990 से जून 1991 तक 30,000 शैक्षिक कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया था। अधिकारिता शैक्षिक कार्यकर्ता कक्षा के, जिन्हें अभियान शुरू किए जाने से पूर्व प्रोत्साहन अनुत्पन्न और प्रशिक्षण दिया गया था। सम्पूर्ण साक्षरता अभियान को, सभी स्तरों पर जन सहभागिता और उप परियोजनाओं के माध्यम से सुगठित तथा बहुल ही साक्षरता पूर्वक सुशोषित किया गया था। जिला परिवर्तन निर्धारण द्वारा इस कार्य में बहुत रुचि ली और उन्होंने सभी विकास कार्यकों में नवसाक्षरों को आमंत्रित किया। एक सिनायम कन्वेंट जैसे भ्रष्टाचर कलाकारी ने गति जग्रा रचनाओं और नव साक्षरों के लिए शैक्षिक तैयार करके अत्यन्त सार्वक सहायता की।

8.7.2 इस जिले को 28 दिसम्बर 1991 को आयोजित एक समारोह में पूर्ण शिक्षित घोषित किया गया था।

पट्टीय साक्षरता निगम के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र

8.8.1 सम्पूर्ण साक्षरता अभियान शुरू किए जाने के अतिरिक्त राष्ट्रीय साक्षरता निगम के अन्य प्रसिद्ध क्षेत्र हैं। अभियान की विकासित गति और विषयवस्तु, सभी साक्षरता कार्यक्रमों में क्षेत्र दृष्टिकोण को अपनाना और लगातार ऐसा वातावरण पैदा करना जो साक्षरता के अनुकूल हो।

(क) अभियान की विकासित गति और विषयवस्तु

8.8.2 साक्षरता अभियान के तीन महत्वपूर्ण पहलु हैं:

— कार्यक्रम की अवधि

— कार्यक्रम की विषयवस्तु

— साह परिचय

8.B.3 यदि कार्यक्रम की अवधि छोटी है और यदि अथवा अध्यापन की गति और भारी की बनाए रखते हैं तो इससे उनकी प्रेरणा बढ़ेगी और इससे शीघ्र और बेहतर अध्ययन में सहायता मिलेगी। इस बात की ध्यान में रखते हुए एक प्रेरणा-उत्प्रेरित तकनीकी अवधि "आख्यान की निरूपित गति और विषयसूची" तैयार की गई थी। नई तकनीक में तीन संयोजित भाग हैं। अनेक भाग में युग्मादी साक्षरता और अनेक के अध्ययन लिए गए हैं। इसके अलावा कानिया, आध्यात्म प्रेरितता, अध्ययन परिणामों के मूल्यांकन और इत्यादि शामिल हैं। प्रत्येक भाग इस अन्तः प्रेरित विचारों को संसाधन उपलब्ध करने हैं जहाँ इस नई विचारधारा के अनुसार तकनीकी संसाधन उपलब्ध करने हैं और वे सभी ब्रह्म-रहित तथा संयोजित भागों के साथ तैयार हैं। अब इन भागों को सम्पूर्ण साक्षरता अभियान में जारी माना में उभरी। किता जा रहा है। यह बात सुनिश्चित करने के लिए कि अध्यापन की विकसित गति और विषय बसू तकनीक के अंतर्गत तैयार की गई सामग्री राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत नियोजित अध्ययन के खरो के अनुसूची को, इस सामग्री की जांच की जाती है। और इसका इस क्षेत्र में उपयोग किए जाने से पूर्व आई पी सी एल पुनरीक्षण समिति द्वारा अनुमोदित की जाती है।

(ख) दृष्टिकोण क्षेत्र

8.B.4 बौद्ध शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापन गता दृष्टिकोण अग्रणी और खंडित हो गया था। लोककला अनेक परिणामाओं, केंद्रों और अभ्यासों को दर्शाते करने के कार्य में लगे रहे। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का नया दृष्टिकोण "क्षेत्र दृष्टिकोण" निर्माणांतर के साथ है।

- संचालन के समय और निकट क्षेत्र
- साक्षरता और आने के प्रतीतिपरित मानदण्डों को प्राप्त करने के लिए प्रतिफल और न कि केवल दक्षिण की संस्था पर,
- विशेष-चरण पद्धतियों द्वारा अच्छे विश्वसनीय और समर्पित कार्यकलापों को बनाने करना,
- समर्पिताता और संचार तकनीकों द्वारा कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण
- सम्पूर्ण भविष्य में मुख्य बात अभ्यासों पर दिया जाएगा।
- अध्ययन के परिणामों को सतत निगा जाएगा। और यह औपचारिक सहभागिता, जिना किसी तरह धर्मनो और सुभाषणक होगी।
- ध्वन्या में विषय की सुनिश्चित करने के लिए व्यापक जाच प्रक्राण की पद्धति द्वारा समर्पित सभी खरो पर अनुसूचना के लिए एक निकटवर्ग पद्धति शुरू करना।

8.B.5 क्षेत्र दृष्टिकोण को विचारधारा सम्पूर्ण साक्षरता अभियान में शामिल की गई है तथा अब एक एल पी सी एल बीनिक एजीसी के केन्द्र आधारित कार्यकलापों में शामिल की गई है।

(ग) वातावरण का निर्माण

8.B.6 भारत ज्ञान-विज्ञान-तन्त्रा के संघटनापूर्वक पूरा होने से साक्षर के लिए संकायिक मांग उत्पन्न करने में सहायता मिलती है। साक्षरता अब एक गुणिमूलक अवस्था के रूप में समझा जा रहा है (जैसे पीने पानी तथा प्रतिरक्षण) और मानव संसाधन विकास के लिए एक मू. इसकी के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। इसका सामाजिक आंदोलन रूप में लोग उठने के लिए जिससे इसका स्थान बन रहा है, व ज्ञान-विज्ञान सामंति में एक राष्ट्रीय स्तर आंदोलन समिति गठित की जासकी एक आम सभा है और एक कार्यकारी समिति जो कि व साक्षरता मिशन की अगुआई, और दित प्रति दित के आधार पर कार्य के परीक्षण तथा कार्यबन्धन, मिलने से सम्पूर्ण साक्षरता अभियान कवाचित के कानियों को मादुम करने, और अनुरोधित परिणाम प्राप्त के के लिए समय पर उपचारणिक उपाय करने में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन सहायता करता है। यह उन क्षेत्रों और मिलने का पता लगाते से सहायता करता है जहाँ सम्पूर्ण साक्षरता अभियान चलने के लिए समय व स्थिति है। यह प्रशिक्षण, उत्तर साक्षरता और सतत शिक्षा र एल आई एक पर कार्यशालाएं आयोजित करता है। यह साधकत्वों के करने से (व्यावसायिक, नैतिक, स्वास्थ्य, साहस्य, सृजा प्रवृत्ति), भागीदर प्रेरण, प्रशिक्षण-व-अनुदेश प्रेरण, प्रचार प्रवृत्ति (पुस्तक) और उस विवरण कार्य में सहायता करता है।

8.B.7 इसी तरह गांधीवादी तथा सर्वोदय के कार्यकर्ताओं के बैठक 11 से 1990 में 5 खण्डों का दौरा किया जिससे लगभग 10 लाख लै कानियों को इससे भाग लेने की प्रेरणा मिलती है।

क्षेत्र आधारित कार्यक्रम का पुनर्गठन

8.9.1 अब एक एल पी सी केन्द्र आधारित कार्यक्रम का पुनरीक्षण कि गया है तथा इसका संशोधन किया गया है और सभी राज्य सरकारों अनुरोध किया गया है कि वे नई योजना के अनुसार अपनी परिणामा की पुर्नोदित करें। परिणामा निर्माण और इसकी कार्यबन्धन नीति विवरण भागीदारी रूप रखाए जाते की गई है। संशोधित योजना निर्माणांतर महत्वपूर्ण पहलु हैं।

(1) क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण के लिए सक्षम आंदोलन निरक्षरों की कु संस्था का पता लगाने तथा जाने के लिए डाकू सावधानीपूर्वक घर घर सर्वेक्षण आयोजित करना अनुरोध है। बौद्ध शिक्षा केंद्रों की स्थापना लिए समान्य स्थान, तकनीकी अध्ययन सामग्री को जलदा, परीक्षा लिए एक पद्धति तैयार करना, भागीदारी, समन्वय, मूल्यांकन और साक्षरता तथा सतत शिक्षा/इस परिणामा के लिए चुना गया क्षेत्र गाँव अथवा गाँवों का समूह, एक मजदूर, पंचायत, एक पंचायत रति एक तादुका या एक जिला हो सकता है। शरीर यह है कि इस प्रकार किये गये सूक्ष्म आंदोलन का लक्ष्य, ती नई समय अवधि, जो एक या वर्ष हो सकती है, उससे सम्पूर्ण निरक्षरता उत्पन्न हो जाना चाहिए

(ii) वातावरण निर्माण:

वातावरण निर्माण कार्यकलापों में जागतिक अनुसंधानक कर्मों चाहिए जिसका उद्देश्य जन विश्वास को गतिशील बनाया, साक्षरता के। याता उत्पन्न करना संस्था कानियों और अभ्यासों को गतिशील बनाया इस अभियान के लिए सभी निम्न के माध्यमों और कलाओं का उपयोग किया जाना चाहिए ताकि संदेश का व्यापक प्रसार हो और इस अभियान

लिए प्राप्त अधिमान सन्निधियों बनाई जानी चाहिए।

(iii) **अर्थव्यवस्था:** पुनर्निर्मित परियोजनाएं छोटी होंगी, जोस और सघन होंगी और अल्पकाल से 100 केंद्र प्रति और इसका प्रभावी परियोजना समन्वयक होगा। एक केंद्र में अल्पकाल परियोजना दो कार चलाई जाएंगी।

इसके अतिरिक्त अनुदेशकों और प्रेरकों को उनके अनुभव और उनके लिफाफे को ध्यान में रखते हुए समुचित ढंग से चुना जाएगा। उन्हें सेवा कालीन और पूर्ण सेवा प्रशिक्षण दिया जाएगा। एक परियोजना सलाहकार समिति इसके दैनिक कार्यों के प्रबंध में सहायता करेगी।

(iv) मान्यता और मूल्यांकन कारगर भागीदारी के लिए एक उपयुक्त एमआईएस तैयार किया गया है। मूल्यांकन प्रक्रिया जो अंतर्गत है मूल्यांकन परिणामों को केवल केवल से है और बाहरी एमआईएस द्वारा सघन मूल्यांकन कार्यक्रम के प्रबंधक द्वारा मूल्यांकन के लिए है।

8.9.2 नई परियोजना को इन विशेषताओं के अतिरिक्त, महिलाओं को सहभागिता और विकास निष्कर्षों, कार्यक्रमों और कार्यक्रमों के साथ समर्थन स्थापित करने पर, प्राथमिकता दी गई है।

8.9.3 संशोधित योजना अधिकांश राज्य/क्षेत्र शासित क्षेत्रों द्वारा स्वीकार की गई है और बहुत ही राज्य सरकारों ने अपनी परियोजनाओं को पुनर्निर्मित करना शुरू कर दिया है और संशोधित पद्धति पर अपने अंशदात योजना शुरू कर दिया है।

शैक्षिक एमआईएस

8.10.1 शैक्षिक एमआईएस को सहायता को केन्द्रीय योजना 1987-88 में शुरू की गई थी। यह योजना राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत शुरू की गई थी और एन एस ई की कार्यकारी समिति द्वारा स्थापित शैक्षिक एमआईएस के उप-कार्य की निगरानी को ध्यान में रखते हुए संशोधित की गई थी ताकि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत परिकल्पित नीतियों को कारगर तथा प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। राज्य सरकार / संशोधित क्षेत्र प्रशासनों और राज्य संसाधन केंद्रों की संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं जिन्हें योजना को संचालित करने के लिए आवश्यक उपाय करने की सलाह दी गई है।

8.10.2 अब कार्यक्रम के कार्यान्वयन में बहुत नीति किसी विशिष्ट क्षेत्र में स्वयंसेवी आधारित संपूर्ण साक्षरता अभियान होगी। यह भी निर्णय किया गया है कि अधिकारी में परम्परागत केंद्र आधारित कार्यक्रम की स्थापना कोई सामान्यता नहीं बढ़ाई जाएगी। इसके बजाय, उन शैक्षिक एमआईएस को, जिनका समाज सेवाओं में सामान्य रूप से और ग्रीड शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से समर्थन का अच्छा लिफाफा है और जो निरक्षरता-उन्मूलन की क्षेत्र-विशिष्ट अभियान/स्वयंसेवी आधारित कार्यक्रमों, आज शैक्षिक परिणामों-मुख्य योजना शुरू करते के इच्छुक हैं, अल्पकाल की अवधि में पालीव्या अपनी समता, अनुभव तथा विशेषज्ञता, संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर और उस आधार पर, जो उन्हे क्षेत्र में इन कार्य के दौरान तैयार किया है कुछेक गांवों, पंचायतों, पंचायतों या ब्लॉक के किसी गांव में स्वयंसेवी आधारित टुकड़ों को अपनाकर संपूर्ण साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करने सामर्थ्य प्रस्ताव तैयार करेंगी। अनुदेशकों/स्वयंसेवियों को किसी गुणान की कल्पना नहीं की गई है। संपूर्ण शैक्षिकता की दृष्टिकोण में होने चाहिए। तथापि, उन कार्यक्रमों को अंतर्गत गुणान किया जा सकता

है जो परियोजनाओं के कार्यान्वयन में पूर्णकालिक रूप में संबद्ध होंगे। केवल उन मामलों में अनुदेशकों को भेजे प्रोत्साहनों पर विचार किया जाएगा जहां यह नितांत आवश्यक और पूरी तरह अव्ययपूर्ण होगा।

8.10.3 मान्य संसाधन विकास मंत्री द्वारा 12 अक्टूबर, 1991 को राज्यो संप्रसारित क्षेत्रों में शिक्षा अधिकारों तथा ग्रीड शिक्षा निदेशों की एक बैठक के समक्ष संशोधित दिशा-निर्देशों की मुख्य विशेषताएं प्रस्तुत की गई थीं। तत्पश्चात् 15-11-1991 को आयोजित एक अन्य बैठक में परियोजना निर्माता को सुझाव देने के लिए शैक्षिक एमआईएस के एक चयनित चर्चा के समक्ष मुख्य विशेषताएं प्रस्तुत की गई थी। संशोधित दिशा निर्देशों के तहत में शैक्षिक एमआईएस की जानकारी देने के लिए निदेश, गुणान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, चण्डीगढ़, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में राज्य संसाधन केंद्रों ने 15 कार्यशालाएं आयोजित की हैं ताकि वे संशोधित दृष्टिकोण को संकल्पना को आसक्ति बना सके और परियोजना का कार्यान्वयन सतोषजनक ढंग से कर सकें। अनुश्रवण पद्धति और प्रबंधक पद्धति को विकसित किया गया है ताकि परियोजनाओं का निरीक्षण संगठन के माध्यम से किया जा सके।

8.10.4 अब तक 14 शैक्षिक एमआईएसों ने अलग से 3, निदेश में 1, राज्य प्रदेश में 2 उड़ीसा में 3 और उत्तर प्रदेश में 5-एच वर्ष की अवधि के अंतर 14 खंडों को पूरी तरह से साक्षर बनाते के लिए संपूर्ण साक्षरता परियोजनाएं शुरू की हैं। चालू वर्ष के दौरान प्रगती योजना के अंतर्गत सवीकृत ग्रीड शिक्षा केंद्रों तथा उन शिक्षण निलामों की जारी परियोजनाओं के लिए 317 शैक्षिक एमआईएसों को सहायता अनुदान दिए गए हैं।

8.10.5 सर्वोच्च तथा गांधीवादी प्रेरणा वाली शैक्षिक एमआईएसों द्वारा अनुभव, 1990 के दौरान शुरू किए गए आकर सेवा अभियान के तहत में 4, राज्य स्तर की कार्यशालाएं और 60 खिला स्तर की कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं ताकि उन्हें विशिष्ट सचन और संबद्ध क्षेत्र में संपूर्ण साक्षरता की परियोजनाओं के संशोधित दिशा-निर्देशों तथा उनके निर्धारण से परिचित कराया जा सके। संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित प्रमाण पहले ही प्राप्त किए जा चुके हैं और दिसम्बर, 1991 में जो आईएस सन्निधित द्वारा 14 परियोजनाओं अनुमोदित की गई हैं।

8.10.6 साक्षरता तथा ग्रीड शिक्षा कार्यक्रम से दिल्ली में छात्रों की सहभागिता के लिए पटेल शिक्षा सोसायटी, नई दिल्ली से संवीकृत एक केन्द्रीय कक्षा में वर्षभर अपने कार्यक्रमों जारी रखे।

छात्र सहभागिता

8.11.1 वर्ष के दौरान, साक्षरता कार्यक्रमों में भाग लेने वाले स्कूलों तथा छात्रों/विद्यार्थियों के छात्रों की संख्या में पश्चिम घाट हुई। विश्वविद्यालयों/कलेजों के एन एस एस के लगभग 4.00 लाख छात्रों के अतिरिक्त, उड़ीसा में लगभग 4.00 लाख स्कूलों छात्रों, अन्यथा में लगभग 1.60 लाख स्कूलों छात्रों ने साक्षरता की प्रीति से संशोधित एक या अन्य कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लिया। देश के 69 जिलों में शुरू किए गए सभी संपूर्ण साक्षरता अभियानों में अधिकतर स्वयंसेवी भी छात्र थे।

8.11.2 आलोच्य वर्ष के दौरान इस संबंध में महत्वपूर्ण प्रगति यह हुई कि शैक्षिक सत्र 1991-92 से केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपने सभी

संशोधित स्कूलों के कक्षा IX और XI में "विशेष ग्रीक साक्षरता अभियान" (साक्षर करने का प्रयोग जो 1992-93 के सत्र में कक्षा IX से XII तक सभी कक्षाओं पर लागू किया जाएगा)। साक्षर कार्य, जो पाठ्यपथ में शामिल कार्य अनुपलब्ध के अंग के रूप में अब तक छात्रों द्वारा किया जाता था उन "साक्षर" द्वारा भी किया जाएगा। जबकि कार्य अनुपलब्ध प्रतिभित संश्लेषी गतिविधियों तक सीमित होगा, वास्तविक शिक्षण साक्षर द्वारा किया जाएगा। केन्द्र-विद्यार्थियों से प्रतीकों शिक्षित बनाने की संख्या के आधार पर अत्यंत कम अत्यंत कम शिक्षित बनाने की संख्या की है। एक व्यक्ति को शिक्षित बनाने के लिए 5 अंक, दो व्यक्ति को शिक्षित बनाने के लिए 8 अंक और तीन या इससे अधिक व्यक्तियों को शिक्षित बनाने के लिए 10 अंक और साक्षर स्वल्प दिए जाएंगे।

उत्तर साक्षरता और सतत शिक्षा

8.12.1 नव-साक्षरों को पुनः निरक्षर बनने से रोकने तथा उनके प्रतिभा साक्षरता स्तर पर प्रत्यक्ष कोशिश को सुदृढ़ करने, बनाए रखने तथा नित्य प्रति के जीवन में प्रयोग करना सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (एलएनएलएन) से प्रेरितता की गई है कि जन शिक्षण निलयाय (केएनएसएन) की स्थापना करके उत्तर साक्षरता और सतत शिक्षा को संस्थागत रूप दिया जाए। एलएनएलएन, विभिन्न सरकारों और नैर-सरकारी एजेंसियों द्वारा चलाए जाने के लिए 32318 जन शिक्षण निलयों की संसदीयता की गई है जिनमें 25000 पहले ही कार्य आरम्भ कर चुके हैं। 1991-92 के अंत तक कुछ और जन शिक्षण निलयों द्वारा कार्य आरम्भ कर दिए जाने की आशा है।

8.12.2 साक्षरता प्रदान करने के परंपरागत केंद्र आधारित दृष्टिकोण के बजाय जन अभियान दृष्टिकोण की नीति अपनाए जाने पर यह महसूस किया गया कि केंद्र आधारित नव-साक्षरों की उत्तर-साक्षरता और सतत शिक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार की गई राष्ट्रीय के रूप में जन शिक्षण निलय, पूर्ण साक्षरता अभियानों से शामिल किए गए क्षेत्र / जिले में सभ्य रूप से लागू नहीं किया जा सकता। तदुपरा, उत्तर साक्षरता और सतत शिक्षा नीतियों की समीक्षा करने और पूर्ण साक्षरता अभियानों के संदर्भ में कोई दावा प्रदान के लिए की संलग्न सेवा की आवश्यकता में एक उप-दल गठित किया गया। इस दल ने अन्य मामलों 'साक्षर-साक्षर' यह पाया कि साक्षरता की श्रेणी में परिभाषित होने वाले लोगों के स्तर में काफी भिन्नता है और इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि पूर्ण साक्षरता अभियानों के माध्यम से साक्षर बने लोगों के पुनः निरक्षरता की कोटि में आ जाने का खतरा बना रहता है।

8.12.3 इसलिए इस दल ने यह महसूस किया कि विभिन्न दलों के लिए शिक्षण नीतियों निष्पक्ष होनी चाहिए और एक ही प्रकार की शिक्षण नीति सभी क्षेत्रों के लिए अनुपलब्ध नहीं होगी। इसलिए इसमें यह निष्कर्ष निकाला कि उत्तर-साक्षरता कार्यक्रम पुनर्स्थापना, सतत और वास्तविक जीवन और कार्य स्थितियों के अनुकूल लोगों के प्रयोग तक होगा कि चाहिए। इस प्रयोग के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उत्तर-साक्षरता कार्यक्रम नव-साक्षरों की सभी श्रेणियों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला होगा चाहिए, (ii) मूल पठन-लेखन और पहले ही प्राप्त किए गए-अक्षर संश्लेषी कोशिका का प्रयोग करके यह व्यक्तिगत, सामूहिक और व्यवसायिक विकास से जोड़ें जाए (iii) कुछ-IV या पी-प्लान-I प्रकार की पाठ्य सभ्यता प्राप्त की जाए ताकि अभिन्न साक्षरता और पर्याप्त कार्यक्षम साक्षरता के बीच की खाई

पाटी जा सकें और (IV) तक 30-40 घंटे का 'सेप्ट' भाग्य प्राप्त किया जाए जिसके माध्यम से नव-साक्षरों को धीरे-धीरे परिचित कराने पर से निर्भरता खत्म करने और आत्म-निर्भर स्थापित स्थिति प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

टी-यू-एन-पी-सी क्षेत्रों में उत्तर साक्षरता अभियान

8.13.1 जबकि उत्तर साक्षरता और सतत शिक्षा के संबंध में दल द्वारा की गई सिफारिशों साक्षर के निष्पादन है, उत्तर साक्षरता और सतत शिक्षा के विभिन्न मॉडल निम्नलिखित किए जा रहे हैं और उन क्षेत्रों / जिलों में प्रयोग किए जा रहे हैं जहां पूर्ण साक्षरता अभियान पहले ही स्थापित हो चुके हैं। उदाहरण के लिए वर्धमान जिले में उत्तर साक्षरता अभियान राष्ट्रीय शिक्षा समिति के समूची मार्गदर्शन और निरीक्षण में पूर्णतया वैयक्तिक आधार पर चलाया जा रहा है। जन शिक्षण निलयान द्वारा 5 से 8 गांवों के 5000 नव-साक्षरों की जरूरतों की पूरा किए जाने की बजाय प्रत्येक गांव में कम से कम एक सतत शिक्षा केंद्र की स्थापना के लक्ष्य के साथ निम्नोन्नीकरण पर कल किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा समितियों (सीई-सी) और शहरी शिक्षा समितियों (यूई-सी) का गठन जिले में उत्तर साक्षरता अभियान का संचालन है। ये समितियां शिक्षण केंद्रों को आधारभूत ढांचे से संबंधित समस्याएं देने और अंतर्गत-प्रयोगीय संबंध स्थापित करने से संबंधित मामलों की देखभाल करते हैं, प्रभावी रखे हैं। नव-साक्षरों के लिए एक समाचार पत्र प्रकाशित किया जा रहा है और दैनिक जीवन में साक्षरता के उपयोग पर बाला, हिन्दी और उर्दू में एक पत्रिका प्रकाशित की गयी है। नव-साक्षरों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करने, नव-साक्षरों और कार्यक्षमताओं के लिए खेल-सह-सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं आयोजित करने, विकास संबंधी कार्यक्षमताओं पर वीडियो-कैसेट दिखाने सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों और अंदरूनीकरण में साक्षरता-स्वातंत्र्य लाने आदि जैसे वातावरण-निर्माण के कार्यक्षमताएं निरंतर आधार पर शुरू किए जा रहे हैं।

8.13.2 इसी प्रकार 9-35 आयु वर्ग के 3.00 लाख नव-साक्षरों और 1.00 लाख अर्द्ध-साक्षरों के लिए आठ प्रदेशों के नैल्सी-जिले में उत्तर साक्षरता अभियान जन चैतन्य केंद्र (जेसी-के) के रूप में एक संस्था के माध्यम से चलाया जा रहा है। अत्यंत जन चैतन्य केंद्र 40 शिक्षकों को जरूरतों को पूरा करता है। जन चैतन्य केंद्र के नेतृत्व के लिए 3 चैतन्य केंद्रों और 3 नव-साक्षरों को एक संश्लित होती है। जबकि जन चैतन्य केंद्रों के कार्यों के निरीक्षण और समन्वय के लिए प्राप्त पंचायत स्तर और मंडल स्तर पर समितियां होगी, जिला स्तर पर / उत्तर साक्षरता कार्यक्रम की आयोजना, कार्य-योजना और निरीक्षण के लिए किया साक्षरता समिति कार्य करती रहेगी। अत्यंत जन चैतन्य केंद्र नव-साक्षरों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए एक पठन कक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक कक्षा और निवास मंच के रूप में कार्य करता है और कक्षा कक्षा में ही जोड़ देने वालों तथा कक्षा में नहीं आने वालों को शामिल करने के लिए 2 या 3 साक्षरता केंद्र चलाएंगे। अत्यंत जन चैतन्य केंद्र के नव-साक्षरों की कुल, चतुर्धन, स्वस्थ, बच्चों की देखभाल, सामाजिक निष्ठा, सामाजिकिक पक्षता, राष्ट्रीय अखंडता आदि से संबंधित विषयों पर 50 प्रश्नों का एक सैट दिया जा रहा है। अपने दैनिक जीवन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर निवार-निवार करने के लिए नव-साक्षरों की सांस्कृतिक निवार गांधी की आदर्शिता की जाएगी।

8.13.3 अन्य क्षेत्रों / जिलों में जहां कुल साक्षरता अभियान पूरे हो चुके हैं, वहां स्थानीय जरूरतों, नव-साक्षरों की आवश्यकताओं और स्थितियों को ध्यान में रखते हुए उत्तर साक्षरता अभियान शुरू किए जा चुके हैं / किए

जा रहे हैं और इन अभियानों के साथ-साथ उत्तर साक्षरता कार्यक्रमों के विदेशीकरण पर बल दिया जा रहा है ताकि कुछ समय के बाद समुदाय खुद निरंतर आधार पर कार्यक्रम अपनाए।

अधिक विद्यार्थी (युवा-वीथी-)

8.14.1 वर्ष 1991-92 में देश के विभिन्न औद्योगिक और शहरी केंद्रों में दैनिकी अभिक विद्यार्थी कार्यक्रम चलाते रहे। औद्योगिक कामगारों, उनके परिवार के सदस्यों, स्वेचाल-प्राप्त सदस्यों और प्रशिक्षित कामगारों आदि को मै-अप-बैचलिक, बनकर और सतत शिक्षा तथा बहुसंसाधन प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने के रूप में ये सेवाएं के रूप में कार्य करते रहे। इनमें से 7 अभिक विद्यार्थी दिल्ली में केन्द्रीय सरकार द्वारा, 3 अभिक विद्यार्थी विश्वविद्यालयों द्वारा, 25 अभिक विद्यार्थी स्वायत्त निकायों द्वारा और शेष 8 अभिक विद्यार्थी राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे हैं।

8.14.2 अभिक अभिक विद्यार्थी के पास केन्द्रीय स्तर के लिए वृत्तिक कार्यक्रम होते हैं जो एक निदेशक, विज्ञान से या तीन पूर्णकालिक कार्यक्रम अधिकारियों की सहायता प्राप्त होती है, के निवेदनाधीन होते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक अभिक विद्यार्थी विभिन्न कुशलता प्रदान करने और अशक्तता आधार पर विशिष्ट क्षेत्रों से सम्बद्ध पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए संसाधन व्यक्तियों की सेवाएं भी लेता है। कार्यक्रम शुरू करने या पाठ्यक्रम शुरू करने के पहले सभी अभिक विद्यार्थी द्वारा सामाजिक अधिकार रूपरेखाएं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना तय की जाती है। ऐसी रूपरेखा लाभार्थियों और संसाधनों की आवश्यकता जनशक्ति की दृष्टि समक्ष रखने से मदद देती है जो अत्यधिक लाभ देने के लिए बढ़ाई जा सकती है। अभिक विद्यार्थी द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों में निरक्षर, अर्द्ध-साक्षर, कुशल, अर्द्ध-कुशल और अकुशल व्यक्तियों जैसे शहरी, अर्द्ध-शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में रह रहे समाज के सभी वर्गों के लोगों की मदद की है। ये कार्यक्रम अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, शारीरिक रूप से विकलांगों और व्यक्तियों जिनमें जैसे समाज के कमजोर वर्गों के लिए भी लाभप्रद रहे हैं।

8.14.3 अभिक विद्यार्थी की इस स्कीम की पुनरीक्षा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के महादेशिक की अध्यक्षता में गठित एक विशेषज्ञ दल द्वारा की गई है और अभिक विद्यार्थी के सुदृढीकरण के लिए और कार्यक्रम की विषय-वस्तु के संदर्भ के लिए ची, विशेषज्ञ दल की रिपोर्टें व्यवस्थित रूप से समक्ष रखी गई थी। तथापि, व्यवस्थित रूप से निर्मित व्यक्तियों बाधाओं के कारण अभिक विद्यार्थी की स्कीम को प्रभावित पुनःप्राप्त नहीं मान सकी।

8.13.4 अभिक विद्यार्थी से विज्ञानप्रज्ञा और सिल्वर से स्कोल्डक नवावों से लगभग 8000 और 8033 व्यक्तियों को साक्षर बनाया। अभिक विद्यार्थी स्वयं प्रदर्शक और जनश्रेष्ठों से समय साक्षरता अभियानों के साथ अपना सक्रिय रूप से सम्बद्ध रही। अभिक विद्यार्थी दिल्ली में बीछने के मूलतः स्तर (एक्जाम्पलर) को प्राप्त करने की समीति अपनाते हुए दिल्ली की गंती बस्तियों में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम में लीखने को गुणवत्ता सुधारों की स्वयं विज्ञान अभियानों को शुरू किया। दिल्ली विकास अभियानों की स्वयं विज्ञान से दिल्ली और नई दिल्ली की कुछ सुनिश्च गंती बस्तियों में "गंती बस्ती शिक्षा और प्रशिक्षण परियोजना" को कार्यान्वित किया। संवत् अभिक विद्यार्थी और राष्ट्रीय खुला विद्यालय द्वारा संयुक्त प्रभागीकरण के माध्यम से स्थित निम्नलिखित व्यवस्थाओं में भाग्यवत् कार्यक्रम आयोजन करने के लक्ष्य के साथ सतत

शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय खुला विद्यालय के साथ संयोजित किए गए।

औद्योगिकी प्रदर्शनी-

8.15.1 कार्यक्रम की गति और गुणवत्ता में सुधार के लिए और शिक्षण/शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक मेहतर वातावरण बनाने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान के परिणामों के प्रयोग के उद्देश्य से औद्योगिकी शिक्षा शास्त्रीय निवेदनों का पता लगाने और उनसे सुधार के लिए कार्य जारी रहा। क्षेत्रीय अनुसंधान, अन्तर्देशीय, जम्बू द्वारा विकसित संशोधित रूपरेखाएं देशभर के अनेक राज्य संसाधन केंद्रों द्वारा अपनाई जा रही हैं। केन्द्रीय विद्युत अभियानिकी अनुसंधान विभाग, दिल्ली द्वारा जॉर्जेल जॉर्ज वैक्स विकसित किए गए हैं और ये अनेक जिलों के जनशिक्षण निलयों में प्राप्त किए जा रहे हैं। अनेक स्थानों पर 200 जनाशिक्षण सौ-पी-एस पहले की स्थापित किए जा चुके हैं। 200 अभियानिकी सीमा जॉर्ज वैक्स अनेक औद्योगिकी प्रदर्शनी विलों में और इन विलों में भी स्थापित किए गए जाते चालू वर्ष के दौरान समग्र साक्षरता अभियान कार्यान्वित होने हैं। संशोधित स्टेडों और ब्लॉक बोर्डों की डिजाइनिंग और निर्माण के लिए अनुसंधान और विकास कार्य जारी हैं। सूक्ष्म कम्प्यूटर आधारित बहु-प्रदेश प्रदर्शनी प्रणाली, सूचना पर, ग्रॉस प्रणाली, एल-ई-डी प्रदर्शनी प्रणाली और विद्युत कार्य सूचक प्रणाली विकसित की गई हैं और देश के अनेक राज्य संसाधन केंद्रों द्वारा आजमाई जा रही हैं।

8.15.2 1989-90 तक साक्षरता के लिए शिक्षण के प्रकाशन माध्यम को बढ़ावा देने के लिए नौडिओ आधारित सूचना के प्रयोग हेतु अन्तीगड (डायन) बीकनेर (अनुसंधान), रांची (विद्यार्थी), और झाबुआ (नव्य प्रदर्शक) विलों के सुनिश्च 100 जन शिक्षण निलयों में एक नवागामी परियोजना "विवेक दर्शन" कार्यान्वित की जा रही है। भारतीय जन सेवा संस्थान, नई दिल्ली द्वारा इस परियोजना के कार्य प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया है। मूल्यांकन अध्ययन का मूल निष्कर्ष यह है कि अनेक सीमाओं और अवरोधों (बधाई) के बावजूद कार्य में प्रयोगात्मक गांवों की साक्षरता और अन्य विकासालय मुद्दों के बारे में प्रयोगात्मक गांवों के भागीदारी में आसक्तता और रुचि बढ़ाने में प्रभावी रही। इनसे स्वास्थ्य, स्वास्थ्य-विज्ञान, बालकों की देखभाल, प्रतिरक्षण, परिवार-कल्याण, व्यक्तित्व-समाधि, अधिवासशी, देश और बाल-विवाह के विरुद्ध चेतना जाई है। इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा के परामर्श से सूचना के उपकरण रूप में इस्तेमाल की कला विज्ञान प्रदान करने के उपकरण के रूप में नौडिओ आधारित तकनीक के प्रयोग की समाधान का पता लगाना जा रहा है। अगले वित्तीय वर्ष के दौरान अन्तीगड (उत्तर प्रदेश) और बीकनेर (राजस्थान) के 80 और गांवों को शामिल करने के लिए कार्यक्रम के विस्तार का प्रस्ताव किया जाता है।

शैक्षिक एवं तकनीकी संसाधन सहयोग:

8.16.0 राज्य संसाधन केंद्रों ने पूरे देश में ग्रीड शिक्षा कार्यक्रम को सौंपित और तकनीकी संसाधन सहायता प्रदान करने का कार्य जारी रखा। सभी राज्य संसाधन केंद्रों ने आई-पी-सी एल-आइएम तैयार करने और संसाधन व्यक्तियों और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के साथ-साथ पूर्ण साक्षरता अभियान को आयोजित और कार्यान्वयन में सक्रिय रूप में भाग लिया। राज्य संसाधन केंद्रों के कार्यक्रमों की समीक्षा 26-27 जून, 1991 को संयोजित ग्रीड शिक्षा निदेशकों और राज्य संसाधन इकायों के निदेशकों

की बैठक में की गयी। पहले से ही प्रारंभ किए गए टी-एलसी और पब्लिश प्रारंभ किए जाते रहने पर पूर्ण साक्षरता अभियान (टी-एलसी) की विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए उनके कार्यक्रमों को अधिक कारगर बनाने के लिए राज्य संसाधन इकाइयों को वित्तीय सहायता देने की प्रति में संशोधन किया गया।

प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय:

8.17.0 प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय (डी० ए० ई०) जो इस विभाग का अधीनस्थ कार्यालय है, प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य करता रहा। वर्ष के दौरान निदेशालय की विभिन्न गतिविधियां इस प्रकार रही।

(I) सामग्री की तैयारी और निगमन: आप सी० सी० एल० समिति, जो पठन/पाठन सामग्री की जांच के लिए निदेशालय का अंग है, की 12 बैठकें हुईं जिनमें पूर्ण साक्षरता अभियान वाले जिलों/क्षेत्रों में सूचना रूप से भ्रमण किए जाते के लिए तैयार की गई सामग्री की कोटि और विवरणशु में सुधार सम्बन्धी सुझाव दिए। निदेशालय द्वारा तैयार की गई आई० सी० एल० आइएम "खिलती कलियां" की नगनें की प्रतियों के सेट की विशेषता एल में मंजूरी दी और मुद्रित कारवाय। अक्सर साइड शीट्स/डी०, शक्ति स्रोत आक्रम, कोयंबादूर, दिल्ली संकर्षित समिति और की० जी० एल० एल०, पानीपत (हरियाणा) आदि को आई० सी० सी० एल० सामग्री की तैयारी में अभिव्यक्त दिया गया। वर्ष के दौरान विभिन्न राज्य संसाधन इकाइयों पूर्ण साक्षरता जिलों (टी० एल० सी०) और कुछ कालेजों की भी संसाधन सहायता दी गई।

(II) प्रत्यक्ष पठन अगली टेक्स्ट पूर्ण साक्षरता अभियानों के लिए एक पन्नीकेशन सामन्तदेअर वैकल्पिक विकसित किया गया है और देश के अनेक पूर्ण साक्षरता अभियान जिलों एन आई सी एन ई टी अगली के माध्यम से कार्यान्वयन के लिए अपनाया गया है। नए इडिकेज पर आधारित एक पथक वैकल्पिक एलसीएस के लिए विकसित किया गया है। माथीन कार्यसाधक साक्षरता परियोजनाओं (आर एफ एल पी) राज्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम (एल ए ई पी) एस सी वी की भी अदि के लिए एक वैकल्पिक विकसित किया जा रहा है। वर्ष 1991-92 के दौरान इन वैकल्पिक कार्यान्वित होने की आशा है। लैचक एलसीएस के लिए एफ० आई० एल० हेतु पन्ड प्रशिक्षण कार्यक्रम और पूर्ण साक्षरता अभियान जिलों के लिए 10 अर्थ कार्यक्रमों ने 1991-92 के अंत तक पूर्ण हो जाते की आशा है। की आई० सी० एल० के छ. कार्यक्रम पहले ही आयोजित किए जा चुके हैं। (III) अनुसंधान विभिन्न व्यक्तियों तथा सरग्राओं को संघि गए 23 अनुसंधान अध्ययनों में से अब तक 10 अध्ययन पूरे हो चुके हैं। चल रहे अध्ययनों में से कुछ साक्षरता के लिए निरक्षर की मोसाहन और उपरलिख स्तर, विकास के अर्थ भटकों तथा कमजोर वर्गों पर प्रौढ़ शिक्षा का प्रभाव, प्रौढ़ शिक्षा में स्वाध्याय भ्रमण, प्रौढ़ शिक्षा की प्रीअरि, लोक संनार, माथमों की सामता, प्रौढ़ शिक्षा में नीच में पढाई छोड़ने की संनार, नव-साक्षरों की पठन कवि के प्रत्येक के से सम्बन्धित हैं।

(IV) जन माध्यम और संनार सहायता वर्ष 1991-92 के दौरान इस क्षेत्र में जनक ऐचक और आच्छर्यजनक विकास हुए। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

(क) सामन्तदेअर/कार्यक्रम सामग्री की तैयारी: उत्तम कोटि की और प्रीअरिबित करने वाली आठ फिन्ट/वीडियो कार्यक्रम तैयार किए गए और

राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित किए गए तथा राज्य संसाधन केन्द्रों, राज्य प्रौढ़ शिक्षा निदेशालयों और प्रतिष्ठित लैचक एलसीएसों को वितरित किए गए। निन्नापुर और मुजम्मरपुर के समन साक्षरता केन्द्र के प्रलेखन की फिन्ना बनाई गई। 40 भ्रमणों वाला एक काराणाडिक "गोराहा" बन्वाई दूरदर्शन द्वारा प्रसारित किया जा रहा है जिसमें संगणक की सहायता की कठपुतलियों और सजीब अभिनय का प्रयोग करके भनीजनमुक्त शैक्षिक कार्यक्रम बनाया गया है। जनसंचार माध्यम अभियानों के भाग के रूप में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के संदेश संगणकीकृत डिस्कटो और डाक सामग्री पर छपे जाते हैं।

(ख) प्रौढ़ साक्षरता के लिए रेडियो शिक्षा में परियोजना (पी.आर.इ.ए.एल) इस परियोजना के तहत रेडियो के माध्यम से साक्षरता शिक्षा का प्रथम दौर पूरा किया गया और इस कार्यक्रम के दूसरे चरण के सम्बन्ध में योजना बनाने के लिए शाली लुपरेखा पर विचार करने के लिए 5-6 दिसम्बर, 1991 को एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया।

(ग) पोस्ट बक्स में 9999 और लैचक एलसीएस, दूरदर्शन, रेडियो और आखबारों में दिए निगमनों के जवाब में प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय को लगभग 1500-2000 पत्र प्राप्त हुए। व्यक्तियों/समूहों ने लैचक साक्षरता कार्यक्रमों, साक्षरता के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भारीदारी इतकत तैयार करने, मुकुट नटक लिखने, पूर्ण साक्षरता जिलों में भागीदारी जैसे विभिन्न कार्यक्रमों से रुचि दिखाई। अनुवर्ती कार्रवाई के लिए ज्वर, यूनीसेफ की सहायता से निर्धारित एक निजी एजेंसी एड-कन्टैक्ट और एक अन्तर्राष्ट्रीय विज्ञापन औगालिनी एड मटर द्वारा संगणकीकृत किए गए। यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए गए कि व्यक्तियों/समूहों द्वारा प्राप्त उत्तरों का लैचक साक्षरता कार्य के लिए उपयोग हो।

(घ) साक्षरता के सम्बन्ध में राष्ट्रीय इशतार प्रतियोगिता: राष्ट्रीय इशतार प्रतियोगिता के अनर्गत उच्चतर माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए एक खुली प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसका विवरण था "लिटिंग फार नेशनल इन्टिदेशन इन इडिया" 500-रु० के प्रथम पुरस्कार 300/रु० के द्वितीय पुरस्कार और 200/रु० के तृतीय पुरस्कार के अतिरिक्त कुछ साधना पुरस्कार भी दिए गए। इस प्रतियोगिता में काफी सख्या में छात्रों ने भाग लिया।

(ङ) जनसख्या शिक्षा: प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय ने 15 जिलों के राज्य संसाधन केन्द्रों की शैक्षिक और तकनीकी संहायता के लिए शिक्षा को अतिरिक्त आग के रूप में युएलएलसीएस द्वारा वित्त पोषित प्रियोजना के कार्यान्वित करना जारी रखा। राज्य संसाधन केन्द्रों ने छोटा परिवार, विवाह की उचित अगु, जनसंख्या और विकास आदि जैसे विषयों पर शैक्षिक और अनुवर्ती सामग्री प्रकाशित की।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों को लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करते समय इन कार्यक्रमों को आवश्यक अभिव्यक्त प्रदान करने के अर्थ में से जनसंख्या शिक्षा की विषय-वस्तु उपयुक्त रूप से समाकलित की गई। राष्ट्रीय संवाहन-संगिति और प्रशिक्षण पुनरीक्षा समिति की रिफरिरी के अनुपालन में प्रयोगात्मक आधार पर उद्देश्य के गंज मिले हैं सम्पूर्ण साक्षरता अभियान में जनसंख्या शिक्षा के भटक को समाकलित किया गया। (च) प्रशिक्षण: निदेशालय ने प्रमुख कार्यक्रमों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के भटकों को समीपित करने के लिए आवश्यक कदम उठाये हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र राज्य में प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही लैचक एलसीएस

के प्रतिनिधियों को क्षेत्र आधारित साक्षरता कार्यक्रमों के प्रतिपादन में पांच प्रतिशत कार्यक्रमों के माध्यम से अधिव्यवस्था दिया गया। उड़ीसा, बर्हिट, उत्तर प्रदेश और बिहार में की लोकतांत्रिक एजेंसियों के लिए मार्च, 1992 के अंत तक ऐसे कार्यक्रमों को आयोजित करने का प्रभाव किया गया। निदेशालय ने मुजफ्फरपुर (बिहार), सीनगर (उत्तर प्रदेश) और 24 परगना (पश्चिम बंगाल) के समूची साक्षरता अभियान जिलों में प्रशिक्षण में भी मदद की।

अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस:

8.18.1 8 सितम्बर, 1991 को नई दिल्ली में आयोजित एक सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया था। मुख्य अतिथि के रूप में उप-राष्ट्रपति की उपस्थिति और विख्यात शिक्षाविद और वैज्ञानिक डा. जे.एन. कोटाड़ी की अध्यक्षता से सम्मेलन की शोभा बढ़ी। सम्मेलन में पहली बार पांच बड़े राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों के प्रतिनिधियों और एक-केन्द्रण गणतन्त्र (कोरिया ई) की एलन के आइडवाणी (भारतीय जनता पार्टी), श्री सैमुएलिन चौधरी (भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), श्री विमान पाई मेहता (जनता पार्टी) और श्री चतुर्गुप्त मिश्र (भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी) ने भी भाग लिया। इन सबल देशों में निरक्षरता दन्तु का घबराव फैलने के लिए अपनी पार्टी के समग्र एकात्मकता और समर्थन देने का वचन दिया।

8.18.2 यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए बने भारतीय राष्ट्रीय आयोगों की सिफारिशों पर यूनेस्को की अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता पुस्तकालय जूरी ने पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य के सात जिलों में समूची साक्षरता अभियान के पञ्च-प्रदर्शन में उनके श्रेष्ठ सहयोग के लिए और अग्रगण्य उपलब्धियों की दृष्टि से विशेषकर बर्हाना और मिर्जापुर जिलों में अग्रगण्य उपलब्धियों के लिए 1991 का गोपा पुस्तकालय प्रदान किया। यूनेस्को के चैरिस् रियल मुख्यालय में 9 सितम्बर, 1991 की आयोजित पुस्तकालय विवरण सम्मेलन में पश्चिम बंगाल सरकार की जन शिक्षा और प्रसार मंत्री श्रीमती अर्जुन कर द्वारा यह पुस्तकालय प्रदान किया गया।

राष्ट्रीय प्रौढ शिक्षा संस्थान (एन.आई.ई.)

1990 प्रौढ शिक्षा के सभी प्रकार के कार्यक्रमों को शैक्षिक तकनीकी और शोध संशोधन प्रदान करने के लिए 1 जनवरी, 1991 को एक स्वायत्त निकाय के रूप में एन.आई.ई. की स्थापना की गई। एन.आई.ई. प्रौढ शिक्षा के क्षेत्र में देश और विदेश में अन्य एजेंसियों के साथ समन्वयात्मक, सहयोगात्मक और मैक्रो-मैक्रो भूमिका निभाएगा। संस्थान की कार्यकारी समिति की दो बैठकें पहले ही हो चुकी हैं जिनमें प्राध्यापक वर्ग की नियुक्ति वर्ग के कार्यक्रमों से संबंधित मामलों और अन्य मामलों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सीनियर फैल्लो और रिसर्च फैल्लो और शोध संशोधकों के वरिष्ठ पदों पर नियुक्तिवा परले ही कर दी गई हैं। एक पुस्तकालय-प्रलेखन केंद्र भी स्थापित किया गया है और इस हवाई के लिए एक अनुपुत्री व्यवसायी को नियुक्त किया गया। लक्ष्मी अम्बेश के कार्यक्रमों में विकसित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित अल्पकालिक की परियोजनाएं प्रारम्भ की गई हैं:

(1) साक्षरता से लिए समानता को और

इस परियोजना के प्रथम चरण में शोध अध्ययनों के आधार पर पुस्तकों और प्रविष्टियों के बीच साक्षरता दरों में विषमताओं को उजागर करने के लिए एक बर्हाना। वेपर तैयार करना शामिल है। कार्यवाई योजना के

साध-साध शोध के लिए क्षेत्रों का पता लगाने के विचार से तीन दिनांश (11-13 जनवरी, 1992) को एक सेमिनार आयोजित किया गया।

(ii) प्रौढशिक्षा कार्यक्रमों में मूल्यांकन की रूपालकताओं: इस परियोजना का उद्देश्य प्रौढ शिक्षा कार्यक्रमों पर मूल्यांकन रिपोर्टों का अध्ययन करना है, ताकि प्रौढ शिक्षा कार्यक्रमों के मूल्यांकन करने के लिए ढांचा विकसित किया जा सके।

(iii) उत्तर-साक्षरता में संश्लेषण तकनीकी

प्रयोगात्मक परियोजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि समूची साक्षरता अभियान जिलों में साक्षरता प्रतिनिधियों का समर्थन किया जा सके। इनमें (क) साक्षरता के मूल पाठ-विषयों के लिए सामग्री और अनुपूरक सामग्री के लिए ओडियो टेपिंग, 'सामग्री और (ख) नव-साक्षरताओं के लिए साप्ताहिक ब्रौड शिट का डिजाइन और उत्पादन शामिल है। ताकि नव साक्षरताओं की आपूर्ति हेतु तकनीक संसाधन सहायता और व्यवस्थित भवितरण पैकजिजम प्रदान किए जा सकें।

(iv) आई.पी.सी.एल. आगमन का मूल्य निर्धारण इस अध्ययन के अंतर्गत आई.पी.सी.एल. के अधीन तैयार की गई सामग्री के वैकल्पिक का विवरण करना है ताकि यह निश्चित किया जा सके कि तैयार किया गया मैट्रिगियन पढ़ने वालों के लिए आवश्यकताओं साक्षरता प्राप्त करने में सक्षम है अथवा नहीं।

(v) अध्ययन निष्कर्ष मूल्यांकन: इस अध्ययन के अंतर्गत (I) दो एल.सी. विलो और (II) अन्य कार्यक्रमों के अध्ययन निष्कर्षों का मूल्यांकन करने के लिए किया जाएगा।

मूल्यांकन

8.20.1 राष्ट्रीय साक्षरता निशान के अंतर्गत दो प्रकार का मूल्यांकन किया जाएगा। अर्थात् पाठकों का मूल्यांकन और प्रभाव मूल्यांकन। आई.पी.सी.एल. का मुख्य रूप से प्रौढ शिक्षा कार्यक्रमों में प्रयोग किया जा रहा है। निम्नलिखित के लिए अध्ययन और कसत करने का प्रारंभ है। अन्य प्रकार में नियमित अन्वेषण पर 3 परीक्षण आयोजित करना अपेक्षित है। यह भी अपेक्षा की जाती है कि 3 माह में पूर्ण करने पर आइएम से दिए गए 9 परीक्षणों को उपरोक्त करना अनिवार्य है। एन.एल.एम. में यथा निर्धारित उसी स्तर तक की साक्षरता और कक्षा कुशलता पाठकों को प्राप्त करने चाहिए। इसलिए पाठकों के मूल्यांकन हेतु आइएम की खाड़ी से पाठकों द्वारा आत्म-मूल्यांकन के लिए पहले से ही प्रक्रिया तैयार कर ली है। प्रभाव मूल्यांकन के लिए सामाजिक विकास, अनुसंधान और प्रबंधन के 7 संस्थानों ने 1978-85 तक की अवधि के दौरान 56 मूल्यांकन अध्ययन किया है। इनके द्वारा प्रसार की गई 56 रिपोर्टों में अन्तिम कार्यक्रमों के संशोधन और पुनर्निर्माण के प्रकाशित कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए 26 बाह्य एजेंसी को कार्यक्रमों के मूल्यांकन के लिए चुना गया। जिन्हें 31 अध्ययन करने का कार्य सौंपा गया। अभी तक इन एजेंसियों ने केवल 17 रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं, जिनमें कुछ सिफारिशें प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम को और अधिक कार्य-व्यवस्था से संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में की गई

है। प्रौढ शिक्षा निदेशालय में एक कार्य समूह की संस्था की गई है ताकि इन रिपोर्टों में की गई सिफारिशों का परीक्षण किया जा सके।

8.20.2 जैसा कि पहले ही वर्णन किया जा चुका है एन० एल० एम० अब एक निश्चित समय में विशिष्ट क्षेत्रों के अंदर निरक्षरता उन्मूलन के लिए साप्ताहिक अभियान संगठित कर रही है। साक्षर घोषित किए जाने के लिए

योग्य क्षेत्र (अर्थात् एक राज्य, जिला, ब्लॉक मण्डल) हेतु यह निर्णय किया जा रहा है कि इन क्षेत्रों में एन० एल० एम० में नियोजित किए गए मास्टरों का पराजय कम से कम 80% तक प्राप्त करें। टी० एल० के की मूल्यांकन का कार्य जिन मूल्यांकन एजेंसियों को सौंपा गया है। जहाँ यह सलाह दी जा रही है कि वो इस पहली का विशेष रूप से मूल्यांकन करें।

परिमित

विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कार्यान्वित किए जा रहे संपूर्ण साक्षरता अभियानों के व्ययों का विवरण।

क्रम सं-परियोजना क्षेत्र (जिला, आदि)	सहभागिता (लाख व्यक्तियों में)	लाभित आयु वर्ग	क्रम सं-परियोजना क्षेत्र (जिला, आदि)	सहभागिता (लाख व्यक्तियों में)	लाभित आयु वर्ग
1 आन्ध्र प्रदेश			27 राजपूत	5.91	9-35
1 बिहार	9.00	9-35	28 गुजरात	4.00	9-35
2 कुश्मा	7.50	9-35	29 मद्रास	3.32	9-35
3 जिला हैदराबाद	5.74	15-35	30 सिक्किम		
4 मेलौर	7.00	9-35	31 पच्छिम बंगाल		
5 बिशाखा पटनम	7.00	9-40	31 दुर्ग	6.00	15-45
6 कन्नूर	5.60	15-35	32 मद्रास पुर	1.07	15-35
7 महबूब नगर	0.69	15-35	33 मद्रास	3.55	15-35
और 2 नगर क्षेत्र			34 राजपुर (8 लाख)	3.00	15-45
8 छत्तिसगढ़	7.10	9-35	35 रत्नाम		
9 निजामाबाद	4.50	15-35	बिलास पुर (6 लाख)	3.51	15-45
10 पश्चिम गोदावरी	6.00	9-40	36 रत्नाम		
11 करीम नगर	10.00	9-35	37 बेतुल (कोटाक्षेत्र-गोदावरी)		
12 नल गोन्ड	7.00	15-45	(लाख)	0.50	15-45
13 आन्ध्र प्रदेश के प्रत्येक जिलों में एक मंडल			38 पद्मगढ़ (7 लाख)		
विजयानगरम	3.00	9-45	39 पद्मगढ़		
पूर्व गोदावरी			40 बम्बई शहर	1.16	6-35
कृष्णा			41 जिला पुणे (ग्रामीण)	5.00	15-35
गुंटूर			42 लंदन	2.20	15-35
प्रकाशम			43 अरुणाचल		
अनंतपुर			43 जिला सुन्दर गढ़	6.00	9-40
रेगा रेड्डी			44 उडुपेट्टा शहर	1.50	10-60
अदिला बाद			45 गन्धम	10.00	9-45
वायल			46 किन्नोर	3.50	6-50
14 मेडक (9 मंडल)	1.80	9-35	47 पञ्जाब		
15 वायल			पञ्जाब में 7 जिला	2.50	15-45
बिहार			48 तमिलनाडु		
16 मुजफ्फरपुर	10.00	12-35	कमलानगर	2.40	15-35
17 जमशेद पुर	1.80	6-50	49 पी-टी-टी सिन्धु	1.00	15-35
18 राखी	10.00	6-45	50 पुडुकोट्टाई	2.30	15-35
19 माधे पुर	2.85	9-35	51 कन्ना कुमारी	0.84	15-35
किल्ली			52 मद्रास	4.20	15-35
20 अम्बेडकर नगर	0.61	9-45	53 डॉ॰ अम्बेडकर	4.80	15-35
21 गोवा समूचा राज्य	1.00	10-35	54 एन आर्केड		
गुजरात			54 बिसमेलवेली कट्टाप्पेयन	2.80	15-35
22 19 जिलों में			55 उत्तर प्रदेश		
100 तालुक	30.00	15-35	55 फरीदपुर	5.00	6-45
हरियाणा			56 मेरठ	4.25	9-45
पानी पत	2.00	15-45	पश्चिम बंगाल		
हिमाचल प्रदेश			57 मिदनापुर	20.00	9-60
24 सिमरी	1.00	9-45	58 गुवाली	9.00	9-50
कानीटक			59 बीरभूम	6.87	9-50
25 बीजा पुर	5.50	9-35	60 कूच बिहार	8.00	9-50
26 मडगा	4.00	9-35	61 कुरु	11.40	10-50
			62 उत्तर 24 परगना	17.00	9-50

63.

1-11-14

1-11-14

4 00

9-40

64 11 11 11

9-35

(11/11, 11/11)

11 11 11 11 11

(11/11, 11/11)

11 11 11 11 11

(11/11, 11/11)

11 11 11 11 11

(11/11, 11/11)

11 11 11 11 11

9. ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ¹⁰ ¹¹ ¹² ¹³ ¹⁴ ¹⁵ ¹⁶ ¹⁷ ¹⁸ ¹⁹ ²⁰ ²¹ ²² ²³ ²⁴ ²⁵ ²⁶ ²⁷ ²⁸ ²⁹ ³⁰ ³¹ ³² ³³ ³⁴ ³⁵ ³⁶ ³⁷ ³⁸ ³⁹ ⁴⁰ ⁴¹ ⁴² ⁴³ ⁴⁴ ⁴⁵ ⁴⁶ ⁴⁷ ⁴⁸ ⁴⁹ ⁵⁰ ⁵¹ ⁵² ⁵³ ⁵⁴ ⁵⁵ ⁵⁶ ⁵⁷ ⁵⁸ ⁵⁹ ⁶⁰ ⁶¹ ⁶² ⁶³ ⁶⁴ ⁶⁵ ⁶⁶ ⁶⁷ ⁶⁸ ⁶⁹ ⁷⁰ ⁷¹ ⁷² ⁷³ ⁷⁴ ⁷⁵ ⁷⁶ ⁷⁷ ⁷⁸ ⁷⁹ ⁸⁰ ⁸¹ ⁸² ⁸³ ⁸⁴ ⁸⁵ ⁸⁶ ⁸⁷ ⁸⁸ ⁸⁹ ⁹⁰ ⁹¹ ⁹² ⁹³ ⁹⁴ ⁹⁵ ⁹⁶ ⁹⁷ ⁹⁸ ⁹⁹ ¹⁰⁰ ¹⁰¹ ¹⁰² ¹⁰³ ¹⁰⁴ ¹⁰⁵ ¹⁰⁶ ¹⁰⁷ ¹⁰⁸ ¹⁰⁹ ¹¹⁰ ¹¹¹ ¹¹² ¹¹³ ¹¹⁴ ¹¹⁵ ¹¹⁶ ¹¹⁷ ¹¹⁸ ¹¹⁹ ¹²⁰ ¹²¹ ¹²² ¹²³ ¹²⁴ ¹²⁵ ¹²⁶ ¹²⁷ ¹²⁸ ¹²⁹ ¹³⁰ ¹³¹ ¹³² ¹³³ ¹³⁴ ¹³⁵ ¹³⁶ ¹³⁷ ¹³⁸ ¹³⁹ ¹⁴⁰ ¹⁴¹ ¹⁴² ¹⁴³ ¹⁴⁴ ¹⁴⁵ ¹⁴⁶ ¹⁴⁷ ¹⁴⁸ ¹⁴⁹ ¹⁵⁰ ¹⁵¹ ¹⁵² ¹⁵³ ¹⁵⁴ ¹⁵⁵ ¹⁵⁶ ¹⁵⁷ ¹⁵⁸ ¹⁵⁹ ¹⁶⁰ ¹⁶¹ ¹⁶² ¹⁶³ ¹⁶⁴ ¹⁶⁵ ¹⁶⁶ ¹⁶⁷ ¹⁶⁸ ¹⁶⁹ ¹⁷⁰ ¹⁷¹ ¹⁷² ¹⁷³ ¹⁷⁴ ¹⁷⁵ ¹⁷⁶ ¹⁷⁷ ¹⁷⁸ ¹⁷⁹ ¹⁸⁰ ¹⁸¹ ¹⁸² ¹⁸³ ¹⁸⁴ ¹⁸⁵ ¹⁸⁶ ¹⁸⁷ ¹⁸⁸ ¹⁸⁹ ¹⁹⁰ ¹⁹¹ ¹⁹² ¹⁹³ ¹⁹⁴ ¹⁹⁵ ¹⁹⁶ ¹⁹⁷ ¹⁹⁸ ¹⁹⁹ ²⁰⁰ ²⁰¹ ²⁰² ²⁰³ ²⁰⁴ ²⁰⁵ ²⁰⁶ ²⁰⁷ ²⁰⁸ ²⁰⁹ ²¹⁰ ²¹¹ ²¹² ²¹³ ²¹⁴ ²¹⁵ ²¹⁶ ²¹⁷ ²¹⁸ ²¹⁹ ²²⁰ ²²¹ ²²² ²²³ ²²⁴ ²²⁵ ²²⁶ ²²⁷ ²²⁸ ²²⁹ ²³⁰ ²³¹ ²³² ²³³ ²³⁴ ²³⁵ ²³⁶ ²³⁷ ²³⁸ ²³⁹ ²⁴⁰ ²⁴¹ ²⁴² ²⁴³ ²⁴⁴ ²⁴⁵ ²⁴⁶ ²⁴⁷ ²⁴⁸ ²⁴⁹ ²⁵⁰ ²⁵¹ ²⁵² ²⁵³ ²⁵⁴ ²⁵⁵ ²⁵⁶ ²⁵⁷ ²⁵⁸ ²⁵⁹ ²⁶⁰ ²⁶¹ ²⁶² ²⁶³ ²⁶⁴ ²⁶⁵ ²⁶⁶ ²⁶⁷ ²⁶⁸ ²⁶⁹ ²⁷⁰ ²⁷¹ ²⁷² ²⁷³ ²⁷⁴ ²⁷⁵ ²⁷⁶ ²⁷⁷ ²⁷⁸ ²⁷⁹ ²⁸⁰ ²⁸¹ ²⁸² ²⁸³ ²⁸⁴ ²⁸⁵ ²⁸⁶ ²⁸⁷ ²⁸⁸ ²⁸⁹ ²⁹⁰ ²⁹¹ ²⁹² ²⁹³ ²⁹⁴ ²⁹⁵ ²⁹⁶ ²⁹⁷ ²⁹⁸ ²⁹⁹ ³⁰⁰ ³⁰¹ ³⁰² ³⁰³ ³⁰⁴ ³⁰⁵ ³⁰⁶ ³⁰⁷ ³⁰⁸ ³⁰⁹ ³¹⁰ ³¹¹ ³¹² ³¹³ ³¹⁴ ³¹⁵ ³¹⁶ ³¹⁷ ³¹⁸ ³¹⁹ ³²⁰ ³²¹ ³²² ³²³ ³²⁴ ³²⁵ ³²⁶ ³²⁷ ³²⁸ ³²⁹ ³³⁰ ³³¹ ³³² ³³³ ³³⁴ ³³⁵ ³³⁶ ³³⁷ ³³⁸ ³³⁹ ³⁴⁰ ³⁴¹ ³⁴² ³⁴³ ³⁴⁴ ³⁴⁵ ³⁴⁶ ³⁴⁷ ³⁴⁸ ³⁴⁹ ³⁵⁰ ³⁵¹ ³⁵² ³⁵³ ³⁵⁴ ³⁵⁵ ³⁵⁶ ³⁵⁷ ³⁵⁸ ³⁵⁹ ³⁶⁰ ³⁶¹ ³⁶² ³⁶³ ³⁶⁴ ³⁶⁵ ³⁶⁶ ³⁶⁷ ³⁶⁸ ³⁶⁹ ³⁷⁰ ³⁷¹ ³⁷² ³⁷³ ³⁷⁴ ³⁷⁵ ³⁷⁶ ³⁷⁷ ³⁷⁸ ³⁷⁹ ³⁸⁰ ³⁸¹ ³⁸² ³⁸³ ³⁸⁴ ³⁸⁵ ³⁸⁶ ³⁸⁷ ³⁸⁸ ³⁸⁹ ³⁹⁰ ³⁹¹ ³⁹² ³⁹³ ³⁹⁴ ³⁹⁵ ³⁹⁶ ³⁹⁷ ³⁹⁸ ³⁹⁹ ⁴⁰⁰ ⁴⁰¹ ⁴⁰² ⁴⁰³ ⁴⁰⁴ ⁴⁰⁵ ⁴⁰⁶ ⁴⁰⁷ ⁴⁰⁸ ⁴⁰⁹ ⁴¹⁰ ⁴¹¹ ⁴¹² ⁴¹³ ⁴¹⁴ ⁴¹⁵ ⁴¹⁶ ⁴¹⁷ ⁴¹⁸ ⁴¹⁹ ⁴²⁰ ⁴²¹ ⁴²² ⁴²³ ⁴²⁴ ⁴²⁵ ⁴²⁶ ⁴²⁷ ⁴²⁸ ⁴²⁹ ⁴³⁰ ⁴³¹ ⁴³² ⁴³³ ⁴³⁴ ⁴³⁵ ⁴³⁶ ⁴³⁷ ⁴³⁸ ⁴³⁹ ⁴⁴⁰ ⁴⁴¹ ⁴⁴² ⁴⁴³ ⁴⁴⁴ ⁴⁴⁵ ⁴⁴⁶ ⁴⁴⁷ ⁴⁴⁸ ⁴⁴⁹ ⁴⁵⁰ ⁴⁵¹ ⁴⁵² ⁴⁵³ ⁴⁵⁴ ⁴⁵⁵ ⁴⁵⁶ ⁴⁵⁷ ⁴⁵⁸ ⁴⁵⁹ ⁴⁶⁰ ⁴⁶¹ ⁴⁶² ⁴⁶³ ⁴⁶⁴ ⁴⁶⁵ ⁴⁶⁶ ⁴⁶⁷ ⁴⁶⁸ ⁴⁶⁹ ⁴⁷⁰ ⁴⁷¹ ⁴⁷² ⁴⁷³ ⁴⁷⁴ ⁴⁷⁵ ⁴⁷⁶ ⁴⁷⁷ ⁴⁷⁸ ⁴⁷⁹ ⁴⁸⁰ ⁴⁸¹ ⁴⁸² ⁴⁸³ ⁴⁸⁴ ⁴⁸⁵ ⁴⁸⁶ ⁴⁸⁷ ⁴⁸⁸ ⁴⁸⁹ ⁴⁹⁰ ⁴⁹¹ ⁴⁹² ⁴⁹³ ⁴⁹⁴ ⁴⁹⁵ ⁴⁹⁶ ⁴⁹⁷ ⁴⁹⁸ ⁴⁹⁹ ⁵⁰⁰ ⁵⁰¹ ⁵⁰² ⁵⁰³ ⁵⁰⁴ ⁵⁰⁵ ⁵⁰⁶ ⁵⁰⁷ ⁵⁰⁸ ⁵⁰⁹ ⁵¹⁰ ⁵¹¹ ⁵¹² ⁵¹³ ⁵¹⁴ ⁵¹⁵ ⁵¹⁶ ⁵¹⁷ ⁵¹⁸ ⁵¹⁹ ⁵²⁰ ⁵²¹ ⁵²² ⁵²³ ⁵²⁴ ⁵²⁵ ⁵²⁶ ⁵²⁷ ⁵²⁸ ⁵²⁹ ⁵³⁰ ⁵³¹ ⁵³² ⁵³³ ⁵³⁴ ⁵³⁵ ⁵³⁶ ⁵³⁷ ⁵³⁸ ⁵³⁹ ⁵⁴⁰ ⁵⁴¹ ⁵⁴² ⁵⁴³ ⁵⁴⁴ ⁵⁴⁵ ⁵⁴⁶ ⁵⁴⁷ ⁵⁴⁸ ⁵⁴⁹ ⁵⁵⁰ ⁵⁵¹ ⁵⁵² ⁵⁵³ ⁵⁵⁴ ⁵⁵⁵ ⁵⁵⁶ ⁵⁵⁷ ⁵⁵⁸ ⁵⁵⁹ ⁵⁶⁰ ⁵⁶¹ ⁵⁶² ⁵⁶³ ⁵⁶⁴ ⁵⁶⁵ ⁵⁶⁶ ⁵⁶⁷ ⁵⁶⁸ ⁵⁶⁹ ⁵⁷⁰ ⁵⁷¹ ⁵⁷² ⁵⁷³ ⁵⁷⁴ ⁵⁷⁵ ⁵⁷⁶ ⁵⁷⁷ ⁵⁷⁸ ⁵⁷⁹ ⁵⁸⁰ ⁵⁸¹ ⁵⁸² ⁵⁸³ ⁵⁸⁴ ⁵⁸⁵ ⁵⁸⁶ ⁵⁸⁷ ⁵⁸⁸ ⁵⁸⁹ ⁵⁹⁰ ⁵⁹¹ ⁵⁹² ⁵⁹³ ⁵⁹⁴ ⁵⁹⁵ ⁵⁹⁶ ⁵⁹⁷ ⁵⁹⁸ ⁵⁹⁹ ⁶⁰⁰ ⁶⁰¹ ⁶⁰² ⁶⁰³ ⁶⁰⁴ ⁶⁰⁵ ⁶⁰⁶ ⁶⁰⁷ ⁶⁰⁸ ⁶⁰⁹ ⁶¹⁰ ⁶¹¹ ⁶¹² ⁶¹³ ⁶¹⁴ ⁶¹⁵ ⁶¹⁶ ⁶¹⁷ ⁶¹⁸ ⁶¹⁹ ⁶²⁰ ⁶²¹ ⁶²² ⁶²³ ⁶²⁴ ⁶²⁵ ⁶²⁶ ⁶²⁷ ⁶²⁸ ⁶²⁹ ⁶³⁰ ⁶³¹ ⁶³² ⁶³³ ⁶³⁴ ⁶³⁵ ⁶³⁶ ⁶³⁷ ⁶³⁸ ⁶³⁹ ⁶⁴⁰ ⁶⁴¹ ⁶⁴² ⁶⁴³ ⁶⁴⁴ ⁶⁴⁵ ⁶⁴⁶ ⁶⁴⁷ ⁶⁴⁸ ⁶⁴⁹ ⁶⁵⁰ ⁶⁵¹ ⁶⁵² ⁶⁵³ ⁶⁵⁴ ⁶⁵⁵ ⁶⁵⁶ ⁶⁵⁷ ⁶⁵⁸ ⁶⁵⁹ ⁶⁶⁰ ⁶⁶¹ ⁶⁶² ⁶⁶³ ⁶⁶⁴ ⁶⁶⁵ ⁶⁶⁶ ⁶⁶⁷ ⁶⁶⁸ ⁶⁶⁹ ⁶⁷⁰ ⁶⁷¹ ⁶⁷² ⁶⁷³ ⁶⁷⁴ ⁶⁷⁵ ⁶⁷⁶ ⁶⁷⁷ ⁶⁷⁸ ⁶⁷⁹ ⁶⁸⁰ ⁶⁸¹ ⁶⁸² ⁶⁸³ ⁶⁸⁴ ⁶⁸⁵ ⁶⁸⁶ ⁶⁸⁷ ⁶⁸⁸ ⁶⁸⁹ ⁶⁹⁰ ⁶⁹¹ ⁶⁹² ⁶⁹³ ⁶⁹⁴ ⁶⁹⁵ ⁶⁹⁶ ⁶⁹⁷ ⁶⁹⁸ ⁶⁹⁹ ⁷⁰⁰ ⁷⁰¹ ⁷⁰² ⁷⁰³ ⁷⁰⁴ ⁷⁰⁵ ⁷⁰⁶ ⁷⁰⁷ ⁷⁰⁸ ⁷⁰⁹ ⁷¹⁰ ⁷¹¹ ⁷¹² ⁷¹³ ⁷¹⁴ ⁷¹⁵ ⁷¹⁶ ⁷¹⁷ ⁷¹⁸ ⁷¹⁹ ⁷²⁰ ⁷²¹ ⁷²² ⁷²³ ⁷²⁴ ⁷²⁵ ⁷²⁶ ⁷²⁷ ⁷²⁸ ⁷²⁹ ⁷³⁰ ⁷³¹ ⁷³² ⁷³³ ⁷³⁴ ⁷³⁵ ⁷³⁶ ⁷³⁷ ⁷³⁸ ⁷³⁹ ⁷⁴⁰ ⁷⁴¹ ⁷⁴² ⁷⁴³ ⁷⁴⁴ ⁷⁴⁵ ⁷⁴⁶ ⁷⁴⁷ ⁷⁴⁸ ⁷⁴⁹ ⁷⁵⁰ ⁷⁵¹ ⁷⁵² ⁷⁵³ ⁷⁵⁴ ⁷⁵⁵ ⁷⁵⁶ ⁷⁵⁷ ⁷⁵⁸ ⁷⁵⁹ ⁷⁶⁰ ⁷⁶¹ ⁷⁶² ⁷⁶³ ⁷⁶⁴ ⁷⁶⁵ ⁷⁶⁶ ⁷⁶⁷ ⁷⁶⁸ ⁷⁶⁹ ⁷⁷⁰ ⁷⁷¹ ⁷⁷² ⁷⁷³ ⁷⁷⁴ ⁷⁷⁵ ⁷⁷⁶ ⁷⁷⁷ ⁷⁷⁸ ⁷⁷⁹ ⁷⁸⁰ ⁷⁸¹ ⁷⁸² ⁷⁸³ ⁷⁸⁴ ⁷⁸⁵ ⁷⁸⁶ ⁷⁸⁷ ⁷⁸⁸ ⁷⁸⁹ ⁷⁹⁰ ⁷⁹¹ ⁷⁹² ⁷⁹³ ⁷⁹⁴ ⁷⁹⁵ ⁷⁹⁶ ⁷⁹⁷ ⁷⁹⁸ ⁷⁹⁹ ⁸⁰⁰ ⁸⁰¹ ⁸⁰² ⁸⁰³ ⁸⁰⁴ ⁸⁰⁵ ⁸⁰⁶ ⁸⁰⁷ ⁸⁰⁸ ⁸⁰⁹ ⁸¹⁰ ⁸¹¹ ⁸¹² ⁸¹³ ⁸¹⁴ ⁸¹⁵ ⁸¹⁶ ⁸¹⁷ ⁸¹⁸ ⁸¹⁹ ⁸²⁰ ⁸²¹ ⁸²² ⁸²³ ⁸²⁴ ⁸²⁵ ⁸²⁶ ⁸²⁷ ⁸²⁸ ⁸²⁹ ⁸³⁰ ⁸³¹ ⁸³² ⁸³³ ⁸³⁴ ⁸³⁵ ⁸³⁶ ⁸³⁷ ⁸³⁸ ⁸³⁹ ⁸⁴⁰ ⁸⁴¹ ⁸⁴² ⁸⁴³ ⁸⁴⁴ ⁸⁴⁵ ⁸⁴⁶ ⁸⁴⁷ ⁸⁴⁸ ⁸⁴⁹ ⁸⁵⁰ ⁸⁵¹ ⁸⁵² ⁸⁵³ ⁸⁵⁴ ⁸⁵⁵ ⁸⁵⁶ ⁸⁵⁷ ⁸⁵⁸ ⁸⁵⁹ ⁸⁶⁰ ⁸⁶¹ ⁸⁶² ⁸⁶³ ⁸⁶⁴ ⁸⁶⁵ ⁸⁶⁶ ⁸⁶⁷ ⁸⁶⁸ ⁸⁶⁹ ⁸⁷⁰ ⁸⁷¹ ⁸⁷² ⁸⁷³ ⁸⁷⁴ ⁸⁷⁵ ⁸⁷⁶ ⁸⁷⁷ ⁸⁷⁸ ⁸⁷⁹ ⁸⁸⁰ ⁸⁸¹ ⁸⁸² ⁸⁸³ ⁸⁸⁴ ⁸⁸⁵ ⁸⁸⁶ ⁸⁸⁷ ⁸⁸⁸ ⁸⁸⁹ ⁸⁹⁰ ⁸⁹¹ ⁸⁹² ⁸⁹³ ⁸⁹⁴ ⁸⁹⁵ ⁸⁹⁶ ⁸⁹⁷ ⁸⁹⁸ ⁸⁹⁹ ⁹⁰⁰ ⁹⁰¹ ⁹⁰² ⁹⁰³ ⁹⁰⁴ ⁹⁰⁵ ⁹⁰⁶ ⁹⁰⁷ ⁹⁰⁸ ⁹⁰⁹ ⁹¹⁰ ⁹¹¹ ⁹¹² ⁹¹³ ⁹¹⁴ ⁹¹⁵ ⁹¹⁶ ⁹¹⁷ ⁹¹⁸ ⁹¹⁹ ⁹²⁰ ⁹²¹ ⁹²² ⁹²³ ⁹²⁴ ⁹²⁵ ⁹²⁶ ⁹²⁷ ⁹²⁸ ⁹²⁹ ⁹³⁰ ⁹³¹ ⁹³² ⁹³³ ⁹³⁴ ⁹³⁵ ⁹³⁶ ⁹³⁷ ⁹³⁸ ⁹³⁹ ⁹⁴⁰ ⁹⁴¹ ⁹⁴² ⁹⁴³ ⁹⁴⁴ ⁹⁴⁵ ⁹⁴⁶ ⁹⁴⁷ ⁹⁴⁸ ⁹⁴⁹ ⁹⁵⁰ ⁹⁵¹ ⁹⁵² ⁹⁵³ ⁹⁵⁴ ⁹⁵⁵ ⁹⁵⁶ ⁹⁵⁷ ⁹⁵⁸ ⁹⁵⁹ ⁹⁶⁰ ⁹⁶¹ ⁹⁶² ⁹⁶³ ⁹⁶⁴ ⁹⁶⁵ ⁹⁶⁶ ⁹⁶⁷ ⁹⁶⁸ ⁹⁶⁹ ⁹⁷⁰ ⁹⁷¹ ⁹⁷² ⁹⁷³ ⁹⁷⁴ ⁹⁷⁵ ⁹⁷⁶ ⁹⁷⁷ ⁹⁷⁸ ⁹⁷⁹ ⁹⁸⁰ ⁹⁸¹ ⁹⁸² ⁹⁸³ ⁹⁸⁴ ⁹⁸⁵ ⁹⁸⁶ ⁹⁸⁷ ⁹⁸⁸ ⁹⁸⁹ ⁹⁹⁰ ⁹⁹¹ ⁹⁹² ⁹⁹³ ⁹⁹⁴ ⁹⁹⁵ ⁹⁹⁶ ⁹⁹⁷ ⁹⁹⁸ ⁹⁹⁹ ¹⁰⁰⁰ ¹⁰⁰¹ ¹⁰⁰² ¹⁰⁰³ ¹⁰⁰⁴ ¹⁰⁰⁵ ¹⁰⁰⁶ ¹⁰⁰⁷ ¹⁰⁰⁸ ¹⁰⁰⁹ ¹⁰¹⁰ ¹⁰¹¹ ¹⁰¹² ¹⁰¹³ ¹⁰¹⁴ ¹⁰¹⁵ ¹⁰¹⁶ ¹⁰¹⁷ ¹⁰¹⁸ ¹⁰¹⁹ ¹⁰²⁰ ¹⁰²¹ ¹⁰²² ¹⁰²³ ¹⁰²⁴ ¹⁰²⁵ ¹⁰²⁶ ¹⁰²⁷ ¹⁰²⁸ ¹⁰²⁹ ¹⁰³⁰ ¹⁰³¹ ¹⁰³² ¹⁰³³ ¹⁰³⁴ ¹⁰³⁵ ¹⁰³⁶ ¹⁰³⁷ ¹⁰³⁸ ¹⁰³⁹ ¹⁰⁴⁰ ¹⁰⁴¹ ¹⁰⁴² ¹⁰⁴³ ¹⁰⁴⁴ ¹⁰⁴⁵ ¹⁰⁴⁶ ¹⁰⁴⁷ ¹⁰⁴⁸ ¹⁰⁴⁹ ¹⁰⁵⁰ ¹⁰⁵¹ ¹⁰⁵² ¹⁰⁵³ ¹⁰⁵⁴ ¹⁰⁵⁵ ¹⁰⁵⁶ ¹⁰⁵⁷ ¹⁰⁵⁸ ¹⁰⁵⁹ ¹⁰⁶⁰ ¹⁰⁶¹ ¹⁰⁶² ¹⁰⁶³ ¹⁰⁶⁴ ¹⁰⁶⁵ ¹⁰⁶⁶ ¹⁰⁶⁷ ¹⁰⁶⁸ ¹⁰⁶⁹ ¹⁰⁷⁰ ¹⁰⁷¹ ¹⁰⁷² ¹⁰⁷³ ¹⁰⁷⁴ ¹⁰⁷⁵ ¹⁰⁷⁶ ¹⁰⁷⁷ ¹⁰⁷⁸ ¹⁰⁷⁹ ¹⁰⁸⁰ ¹⁰⁸¹ ¹⁰⁸² ¹⁰⁸³ ¹⁰⁸⁴ ¹⁰⁸⁵ ¹⁰⁸⁶ ¹⁰⁸⁷ ¹⁰⁸⁸ ¹⁰⁸⁹ ¹⁰⁹⁰ ¹⁰⁹¹ ¹⁰⁹² ¹⁰⁹³ ¹⁰⁹⁴ ¹⁰⁹⁵ ¹⁰⁹⁶ ¹⁰⁹⁷ ¹⁰⁹⁸ ¹⁰⁹⁹ ¹¹⁰⁰ ¹¹⁰¹ ¹¹⁰² ¹¹⁰³ ¹¹⁰⁴ ¹¹⁰⁵ ¹¹⁰⁶ ¹¹⁰⁷ ¹¹⁰⁸ ¹¹⁰⁹ ¹¹¹⁰ ¹¹¹¹ ¹¹¹² ¹¹¹³ ¹¹¹⁴ ¹¹¹⁵ ¹¹¹⁶ ¹¹¹⁷ ¹¹¹⁸ ¹¹¹⁹ ¹¹²⁰ ¹¹²¹ ¹¹²² ¹¹²³ ¹¹²⁴ ¹¹²⁵ ¹¹²⁶ ¹¹²⁷ ¹¹²⁸ ¹¹²⁹ ¹¹³⁰ ¹¹³¹ ¹¹³² ¹¹³³ ¹¹³⁴ ¹¹³⁵ ¹¹³⁶ ¹¹³⁷ ¹¹³⁸ ¹¹³⁹ ¹¹⁴⁰ ¹¹⁴¹ ¹¹⁴² ¹¹⁴³ ¹¹⁴⁴ ¹¹⁴⁵ ¹¹⁴⁶ ¹¹⁴⁷ ¹¹⁴⁸ ¹¹⁴⁹ ¹¹⁵⁰ ¹¹⁵¹ ¹¹⁵² ¹¹⁵³ ¹¹⁵⁴ ¹¹⁵⁵ ¹¹⁵⁶ ¹¹⁵⁷ ¹¹⁵⁸ ¹¹⁵⁹ ¹¹⁶⁰ ¹¹⁶¹ ¹¹⁶² ¹¹⁶³ ¹¹⁶⁴ ¹¹⁶⁵ ¹¹⁶⁶ ¹¹⁶⁷ ¹¹⁶⁸ ¹¹⁶⁹ ¹¹⁷⁰ ¹¹⁷¹ ¹¹⁷² ¹¹⁷³ ¹¹⁷⁴ ¹¹⁷⁵ ¹¹⁷⁶ ¹¹⁷⁷ ¹¹⁷⁸ ¹¹⁷⁹ ¹¹⁸⁰ ¹¹⁸¹ ¹¹⁸² ¹¹⁸³ ¹¹⁸⁴ ¹¹⁸⁵ ¹¹⁸⁶ ¹¹⁸⁷ ¹¹⁸⁸ ¹¹⁸⁹ ¹¹⁹⁰ ¹¹⁹¹ ¹¹⁹² ¹¹⁹³ ¹¹⁹⁴ ¹¹⁹⁵ ¹¹⁹⁶ ¹¹⁹⁷ ¹¹⁹⁸ ¹¹⁹⁹ ¹²⁰⁰ ¹²⁰¹ ¹²⁰² ¹²⁰³ ¹²⁰⁴ ¹²⁰⁵ ¹²⁰⁶ ¹²⁰⁷ ¹²⁰⁸ ¹²⁰⁹ ¹²¹⁰ ¹²¹¹ ¹²¹² ¹²¹³ ¹²¹⁴ ¹²¹⁵ ¹²¹⁶ ¹²¹⁷ ¹²¹⁸ ¹²¹⁹ ¹²²⁰ ¹²²¹ ¹²²² ¹²²³ ¹²²⁴ ¹²²⁵ ¹²²⁶ ¹²²⁷ ¹²²⁸ ¹²²⁹ ¹²³⁰ ¹²³¹ ¹²³² ¹²³³ ¹²³⁴ ¹²³⁵ ¹²³⁶ ¹²³⁷ ¹²³⁸ ¹²³⁹ ¹²⁴⁰ ¹²⁴¹ ¹²⁴² ¹²⁴³ ¹²⁴⁴ ¹²⁴⁵ ¹²⁴⁶ ¹²⁴⁷ ¹²⁴⁸ ¹²⁴⁹ ¹²⁵⁰ ¹²⁵¹ ¹²⁵² ¹²⁵³ ¹²⁵⁴ ¹²⁵⁵ ¹²⁵⁶ ¹²⁵⁷ ¹²⁵⁸ ¹²⁵⁹ ¹²⁶⁰ ¹²⁶¹ ¹²⁶² ¹²⁶³ ¹²⁶⁴ ¹²⁶⁵ ¹²⁶⁶ ¹²⁶⁷ ¹²⁶⁸ ¹²⁶⁹ ¹²⁷⁰ ¹²⁷¹ ¹²⁷² ¹²⁷³ ¹²⁷⁴ ¹²⁷⁵ ¹²⁷⁶ ¹²⁷⁷ ¹²⁷⁸ ¹²⁷⁹ ¹²⁸⁰ ¹²⁸¹ ¹²⁸² ¹²⁸³ ¹²⁸⁴ ¹²⁸⁵ ¹²⁸⁶ ¹²⁸⁷ ¹²⁸⁸ ¹²⁸⁹ ¹²⁹⁰ ¹²⁹¹ ¹²⁹² ¹²⁹³ ¹²⁹⁴ ¹²⁹⁵ ¹²⁹⁶ ¹²⁹⁷ ¹²⁹⁸ ¹²⁹⁹ ¹³⁰⁰ ¹³⁰¹ ¹³⁰² ¹³⁰³ ¹³⁰⁴ ¹³⁰⁵ ¹³⁰⁶ ¹³⁰⁷ ¹³⁰⁸ ¹³⁰⁹ ¹³¹⁰ ¹³¹¹ ¹³¹² ¹³¹³ ¹³¹⁴ ¹³¹⁵ ¹³¹⁶ ¹³¹⁷ ¹³¹⁸ ¹³¹⁹ ¹³²⁰ ¹³²¹ ¹³²² ¹³²³ ¹³²⁴ ¹³²⁵ ¹³²⁶ ¹³²⁷ ¹³²⁸ ¹³²⁹ ¹³³⁰ ¹³³¹ ¹³³² ¹³³³ ¹³³⁴ ¹³³⁵ ¹³³⁶ ¹³³⁷ ¹³³⁸ ¹³³⁹ ¹³⁴⁰ ¹³⁴¹ ¹³⁴² ¹³⁴³ ¹³⁴⁴ ¹³⁴⁵ ¹³⁴⁶

9. संघ शासित क्षेत्रों में शिक्षा

9.1.0 संघ शासित क्षेत्रों में शिक्षा केन्द्रीय सरकार का विशेष उत्तरदायित्व रहा है। प्रत्येक संघ शासित क्षेत्र के संबंध में वर्ष के दौरान आरंभ किए गए शैक्षिक कार्यक्रमों का लेखा इस अध्याय में दिया गया है।

अठमान और निकोबार द्वीपसमूह

9.2.1 संघशासित क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं का ब्यौरा इस प्रकार है—

	सरकारी	सहायता प्राप्त	प्रोवेंट
1 पूर्ण-प्राथमिक	2	—	21
2 प्राथमिक	178	—	6
3 मिडिल	41	—	—
4 माध्यमिक	25	—	2
5 सीनियर सेनेयर	39	1	—
6 कॉलेज	2	—	—
7 पॉलिटेक्निक	2	—	—
	289	1	31

9.2.2 वर्ष के दौरान, संघशासित क्षेत्र को प्रशासन का 5 नए प्राथमिक स्कूल खोलने, 5 प्राथमिक स्कूलों को मिडिल स्कूलों के स्तर तक और 3 मिडिल स्कूलों को माध्यमिक स्कूलों के स्तर तक तथा 2 माध्यमिक स्कूलों को सी० मा० स्कूलों के स्तर तक 'उन्नत करने का प्रस्ताव है।

प्रशासकीय योजना

9.2.3 कक्षा-I/III तक सभी बच्चों को मध्याह्न भोजन प्रदान किया जाता है। 212 बच्चों को 115/- रु० प्रतिमाह की दर से छात्रवास वसूली प्रदान किया जाता है। वर्ष के दौरान, 3948 बच्चों को निःशुल्क वर्दियां प्रदान की गई थीं। 4473 बच्चों को निःशुल्क यात्रा रिवायत की अनुमति दी गई थी।

प्रौढ़ शिक्षा

9.2.4 प्रौढ़ शिक्षा की योजना वर्ष के दौरान कार्यरत रही। वर्ष के दौरान आरंभ की गई योजना का प्रमुख दबाव द्वीपसमूह के सभी भागों में नौसिखियों का पता लगाने और उन्हें प्रेरित करने पर था। विभिन्न स्कूलों तथा कालेजों से स्वयंसेवकों को पता लगाया गया था और कार्यक्रम आरंभ करने से पूर्व उन्हें अनिवार्य प्रशिक्षण दिया गया था। के० मा० शि० बो०, नई दिल्ली ने इस शैक्षिक सत्र के सभी स्कूलों में कार्यपुनर्वच के माग के रूप में कार्यरत साक्षरता कार्यक्रम आरंभ किए हैं।

गैर-औपचारिक शिक्षा

9.2.5 6-11 वर्षों के आयु-वर्ग में स्कूल न जाने वालों तथा पढ़ाई बीच में छोड़ जाने वालों को गैर-औपचारिक शिक्षा प्रदान की जा रही। संघशासित क्षेत्र में इस समय गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्रों की संख्या 34 है जिसमें 728 बच्चे दाखिल हैं।

विज्ञान-शिक्षा

9.2.6 विज्ञान शिक्षा सेमिनार के अंतर्गत, अध्ययन सगोष्ठियां, प्रदर्शनीयां, चित्रकारी प्रतियोगिताएं, कार्यशालाएं संचालित की गयी थीं। बिरला औद्योगिक तथा तकनीकी संग्रहालय, कलकत्ता के सहयोग से "जीवन के उद्भव" पर एक राज्य स्तरीय विज्ञान अध्ययन गोष्ठी संचालित की गई थी जहाँ छात्र प्रथम आनंद था, उसे बम्बई में हुई राष्ट्रीय विज्ञान अध्ययन-गोष्ठी में इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था।

राज्य शिक्षा संस्थान

9.2.7 पोर्ट ब्लेयर में एक राज्य शिक्षा संस्थान कार्यरत है। इस यूनिट का नेतृत्व एक प्रधानाचार्य द्वारा किया जा रहा है तथा लेक्चरर और कार्यलय के अन्य कर्मचारी उन्हें सहयोग दे रहे हैं। यह यूनिट सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों, स्कूलों के निरीक्षण, विकास आदि की समेकित शिक्षा के लिए उत्तरदायी है। अंग्रेजों के लिए एक जिलाकेन्द्र भी इस संस्थान के माध्यम से संचालित है।

व्यावसायिक शिक्षा

9.2.8 संघशासित क्षेत्र के प्रशासन ने अपने स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा की योजना को कार्यान्वित करना जारी रखा। मत्स्यचालन और सौन्दर्य संस्कृति में व्यावसायिक पाठ्यक्रम सी० माध्यमिक स्कूलों के +2 स्तर पर आरंभ किए गए थे।

तकनीकी-शिक्षा

9.2.9 पहले ही आरंभ किए गए दो पॉलिटेक्निकों ने छात्रों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करना जारी रखा। पहले पॉलिटेक्निक में विद्युत यंत्रिकी और सिविल इंजीनियरी में पाठ्यक्रम पढ़ाये जाते हैं जबकि दूसरे पॉलिटेक्निक में विद्युत तथा होटल प्रबंध के पाठ्यक्रम पढ़ाये जाते हैं। एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जिसमें सिविल, यंत्रिकी, रेडियो-टेलीविजन, आर्गुलिपि की सुविधाएं उपलब्ध हैं, वे भी कार्यरत हैं। इन संस्थाओं में कुल नामांकन 400 हैं।

चण्डीगढ़

9.3.1 चण्डीगढ़ प्रशासन विभिन्न स्कूलों को चला रहा है जो इस प्रकार हैं:

	सरकारी	प्राइवेट गैर-सहायता प्राप्त स्कूल
प्रथमरी स्कूल	29	26
मिडिल स्कूल	9	19
माध्यमिक स्कूल	37	14
सी० माध्यमिक स्कूल	20	1
	95	60

इसके अतिरिक्त, माध्यमिक तथा सी० माध्यमिक के 6 स्कूल हैं जिन्हें चण्डीगढ़ प्रशासन से सहायता मिल रही है।

व्यावसायिक शिक्षा

9.3.2 चण्डीगढ़ प्रशासन ने अपने स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना जारी रखा। गृह विज्ञान, वाणिज्य, इंजीनियरी और अर्थ-शैलिक के क्षेत्रों में 20 व्यावसायिक पाठ्यक्रम चण्डीगढ़ प्रशासन के अंतर्गत विभिन्न सी० माध्यमिक स्कूलों में आरम्भ किए गए हैं। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की संख्या जो वर्ष 1990-91 में 15 थी वह वर्ष 1991-92 में बढ़कर 20 हो गई है।

प्रौढ़ शिक्षा

9.3.3 राज्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत, 160 केन्द्र कार्यरत हैं। ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत 100 केन्द्र और 38 जन-शिक्षण-निलयन संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ में कार्यरत हैं।

गैर-औपचारिक-शिक्षा

9.3.4 इस योजना के अंतर्गत, 4506 छात्रों को 105 केन्द्रों में शिक्षा प्रदान की जा रही है और निःशुल्क लेखन-सामग्री, वर्दियाँ और मध्याह्न-भोजन उपलब्ध कथया जा रहा है।

भार्यदर्शन कैरियर सैल

9.3.5 राज्य शिक्षा संस्थान, सैक्टर-32 में चल रहा मार्ग दर्शन कैरियर सैल विभिन्न पाठ्यक्रमों को संचालित करता है। इसकी सेवाओं का चण्डीगढ़ के स्कूलों और कलेजों में पढ़ रहे छात्रों द्वारा उपयोग किया जा रहा है। केन्द्र के प्रचार के अंतर्गत सामाजिक रूप से उपयोग उत्पादक कार्य भी किया जा रहा है।

दरदर और नागर हवेली

शैक्षिक संस्थाएं

9.4.1 संघ शासित क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न शैक्षिक संस्थाएं इस प्रकार हैं —

	सरकारी	सहायता प्राप्त	प्राइवेट
(i) पूर्व-प्राथमिक	—	—	—
(ii) प्राथमिक	109	11	1
(iii) मिडिल	38*	2	2
(iv) माध्यमिक	4	—	3
(v) उच्चतर माध्यमिक	5*	—	—

(* एक नवोदय विद्यालय सहित)

9.4.2 वर्ष के दौरान, संघ शासित क्षेत्र के प्रशासन ने 1 नया प्राथमिक स्कूल तथा 1 सी० माध्यमिक स्कूल खोला।

अपेणा योजना

9.4.3 कक्षा 7 तक सभी छात्रों को निःशुल्क मध्याह्न-भोजन उपलब्ध कथया जाता है, इसके अतिरिक्त, सभी अनु० जा०/अनु० जन० जा० के छात्रों को अभ्यास/नोट-बुके, पाठ्य-पुस्तके और अन्य अध्यापन सहायक-सामग्रीयां निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। अनु० जा०/अनु० जन० जाति के छात्रों को प्रत्येक वर्ष दो जोड़ी कपडे और एक जोड़ी जूते तथा मोजे भी मुहैया कएए जाते हैं। वार्षिक परीक्षाओं में अनु०जा०/अनु० जन०जाति के छात्रों को नकट-पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, उत्तर-वैदिक-अभिवृत्तिया भी प्रदान की जाती हैं।

प्रौढ़ शिक्षा

9.4.4 यहा 50 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र हैं जिनसे लगभग 1500 छात्र लाभान्वित हो रहे हैं। एक सौ ग्रामीण शैक्षिक साक्षरता परियोजना (ग्रामशैक्षिकपरि०) कार्यरत हैं जिनसे लगभग 3000 छात्र लाभान्वित हो रहे हैं। सरकार द्वारा 100 गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्रों को खोलने के लिए अनुमोदन भी दे दिया गया है।

विज्ञान शिक्षा

9.4.5 विज्ञान शिक्षा के सुधार की योजना को लागू करने का सशरशासित क्षेत्र के प्रशासन का प्रस्ताव है। प्रत्येक वर्ष विज्ञान-प्रदर्शनिया और अध्ययन-गोष्ठियां आयोजित की जाती हैं।

तकनीकी शिक्षा

9.4.6 संघशासित क्षेत्र में एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत है।

दमन और दीव

9.5.1 दमन और दीव सभशासित प्रदेश में कार्यरत विभिन्न शैक्षिक संस्थान निम्नलिखित हैं:—

प्राथमरी स्कूल	50
मिडिल स्कूल	16

माध्यमिक स्कूल	17
सीनियर माध्यमिक स्कूल	2
सरकारी कालेज	1

9.5.2 संघर्षासित प्रदेश के सभी स्कूलों में पके धवन हैं और एकल शिक्षक वाला कोई स्कूल नहीं है।

और... योजनाएँ

9.5.3 6-11 आयुवर्ग में प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए एक योजना का अनुमोदन किया गया है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के छात्रों को निःशुल्क बर्तियाँ, पाठ्यपुस्तकें और लेखन सामग्री प्रदान की जाएगी।

9.5.4 दिसम्बर, 1990 से प्रारंभिक स्तर पर छात्रों के लिए शुरू की गयी मध्यमिक योजना का प्रारंभ चल रहा है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के कक्षा I से IV तक के बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान किया जाता है।

जनजातीय कल्याण

9.5.5 जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत जनजातियों के कल्याण के लिए संघर्षासित प्रदेश सरकार ने विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन को जारी रखा। इनमें आश्रम-शालाओं का विकास, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का भावधान, लेखन सामग्री, बर्तियाँ, चलते-फिरते पुस्तकालय का रख-रखाव, ग्रामीण पुस्तकालय और कक्षा I से X तक की जनजातीय छात्रों के अभिभावकों को नकद भोत्साहन शामिल है। उपचारे शिक्षण कक्षाएं भी चलायी जा रही हैं।

जनशिक्षण निलायम

9.5.6 वर्ष के दौरान आठ जन शिक्षण निलायम केन्द्र जारी रखे गये। ये केन्द्र ग्रामीणों को शैक्षिक पुस्तकें, पत्रिकाएँ और समाचार पत्र प्रदान करते हैं।

प्रौढ़ शिक्षा

9.5.7 दम्पन और दीव में 1200 प्रौढ़ों के दाखिले सहित साठ प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों ने कार्य करना जारी रखा।

बाल धवन

9.5.8 वर्ष 1987-88 के दौरान स्थापित बाल धवन ने अपने विभिन्न कार्यक्रमों का प्रारंभ जारी रखा। बाल धवन द्वारा नवम्बर, 1991 तक आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों पर चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 3.75 लाख रुपये की राशि खर्च की गयी।

दिल्ली

9.6.1 शैक्षिक वर्ष 1991-92 के दौरान शिक्षा निदेशालय ने 17 मिडिल स्कूल खोले, 17 मिडिल स्कूलों को माध्यमिक स्तर तक स्तरोन्नयन, 26 माध्यमिक स्कूलों का सीनियर माध्यमिक स्कूलों में स्तरोन्नयन, 3 माध्यमिक और सीनियर माध्यमिक स्कूलों का विभाजन किया गया। तत्पश्चात् शिक्षा की कोटि में सुधार लाने के लिए, 28 विद्यमान / सीनियर माध्यमिक स्कूलों को संयुक्त मॉडल स्कूलों में परिवर्तित किया गया।

9.6.2 वर्ष 1991-92 के दौरान दिल्ली में चल रहे विभिन्न प्रकार के स्कूलों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं —

दिल्ली प्रशासन

संस्थान का प्रकार	सरकारी	सहायता प्राप्त	गैर सहायता प्राप्त	नई दिल्ली नगर पालिका स्कूल	नगर निगम स्कूल	दिल्ली केन्द्र बोर्ड
पूर्व ग्रामीण स्कूल	—	—	—	21		
प्रबन्धी स्कूल	—	—	—	68 (+4 सहायता प्राप्त और 4 गैर सहायता प्राप्त)	1674 (280 निजी तथा 50 सहायता प्राप्त)	6
अन्य ग्रामीण स्कूल	206	29	256	9 (+3 मिडिल नवयुग स्कूल)		
माध्यमिक स्कूल	171	35	95	9		
सीनियर माध्यमिक स्कूल	536	143	146	5 (+2 सीनियर माध्यमिक नवयुग स्कूल)		

छात्रों को निःशुल्क परिचय

9.6.3 इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की छात्रों को भोत्साहन देना है ताकि वे अपना अध्ययन जारी रख सकें। इस समय लगभग 120 गांवों से शहरी क्षेत्रों में 12 स्कूलों में अध्ययनरत लगभग 4100 छात्र इस सुविधा का लाभ उठा रही हैं। वर्ष 1991-92 के दौरान

इस योजना के लिए निदेशालय ने 10.00 लाख रुपये का बजट आवधान रखा है।

बुक बैंक योजना

9.6.4 इस योजना के अन्तर्गत कक्षा 6 से 12 में अध्ययनरत उन जरूरतमंद छात्रों को पुस्तकें प्रदान की जाती हैं जिनके अभिभावकों को आय 500/- रुपए प्रतिमाह से कम है। वर्ष के दौरान इस योजना के अन्तर्गत 40000 छात्रों को लाभान्वित किए जाने की आशा है।

शिक्षण सुविधाएं

9.6.5 यद्यपि जे-जे कालोनिया, पिछड़े क्षेत्रों और गंदी बस्तियों के कुछ बच्चों माध्यमिक परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने में फिर भी निधियों अथवा विशिष्ट शिक्षण सुविधाओं के अभाव में उन्हें और अधिक अवसर नहीं मिल पाते हैं। ऐसे छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सक्षम बनाने के उद्देश्य से चिकित्सा, सी.ए. / आई.सी. इंजिनियरिंग और इंजीनियरी पाठ्यक्रमों आदि जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में वर्ष 1991-92 के दौरान 28 शैक्षिक क्षेत्रों सहित जहाँ से प्रत्येक से एक लड़के और एक कन्या स्कूल को इसमें शामिल किया गया। वर्ष 1991-92 के दौरान, इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 15 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है।

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए उपचारी शिक्षण

9.6.6 इस योजना के अन्तर्गत उन स्कूलों में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए उपचारी शिक्षण केंद्रों की स्थापना करना है जहाँ उनका दाखिला कुछ छात्रों के दाखिले में 51 प्रतिशत से अधिक है। वर्ष 1991-92 के लिए अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति की श्रेणियों के लगभग 4000 छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए 2.00 लाख रुपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, दिल्ली प्रशासन द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों में शिक्षा का प्रसार करने के उद्देश्य से विदियों, पाठ्यपुस्तकों, प्रध्याह्न भोजन की निशुल्क आपूर्ति और कई छात्रवृत्तियों जैसे अन्य प्रोत्साहन प्रदान किए जा रहे हैं। इस योजना के अन्तर्गत लगभग 400 छात्रों के लाभान्वित होने की आशा है।

ग्रौढ़ शिक्षा

9.6.7 इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1991-92 के लिए गजधानी में साक्षरता के प्रसार के लिए 40 लाख रुपए का प्रावधान है।

सांघकालीन स्कूल

9.6.8 इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे छात्रों को प्रोत्साहित करना है जो विभिन्न कारणों से अपना अध्ययन जारी नहीं रख सके। इस समय सशरासित क्षेत्र के विभिन्न भागों में प्रौढों के लिए 4 सीनियर माध्यमिक और 8 माध्यमिक स्कूल चलाए जा रहे हैं जिनमें 6000 प्रौढ़ अध्ययनरत हैं।

औपचारिक शिक्षा

9.6.9 6-11 और 11-14 आयु वर्गों में सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए सार्वजनिक वचनबद्धता को पूरा करने हेतु शिक्षा निदेशालय उन बच्चों के लिए 74 गैर-औपचारिक शिक्षा केंद्र चला रहा है जो कभी भी स्कूल नहीं गए अथवा औपचारिक शिक्षा के दौरान पढ़ाई बीच में छोड़कर चले गये। वर्ष 1991-92 के दौरान, इस योजना के अंतर्गत लगभग 2000 बच्चों को लाभ पहुंचाने की आशा है। इस योजना

के अन्तर्गत वर्ष 1991-92 के लिए एक लाख रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है।

अध्ययन केंद्र

9.6.10 अध्ययन केंद्रों की स्थापना का उद्देश्य उन छात्रों को सुविधाएं प्रदान करना है जिनके आवास के समीप उपयुक्त अध्ययन केंद्र नहीं है। केंद्र की स्थापना करते समय, ग्रामीण/गंदी बस्तियों के क्षेत्र अथवा घने आबादी वाले क्षेत्रों की वरीयता दी जाती है। वर्ष 1991-92 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत 0.70 लाख रुपए का बजट प्रावधान किया गया है।

अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मुक्त योग्यता छात्रवृत्तियां

9.6.11 इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष एक प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाती है और ऐसे अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के कक्षा 5 के वे छात्र यह परीक्षा देने के पात्र होते हैं जिनमें 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों। इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति के लिए एक नए छात्रों का चयन किया जाता है। छात्रवृत्ति दर 500 रुपए प्रतिवर्ष है दिल्ली प्रशासन ने छात्रवृत्ति की राशि को 1000 रुपए तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव किया है। इस योजना के तहत 1.25 लाख रुपए का बजट प्रावधान है।

पत्राचार विद्यालय

9.6.12 पत्राचार विद्यालय अपनी तरह का एक पहला मस्यौदा है जो माध्यमिक, तथा सीनियर माध्यमिक स्तरों पर सभी तीन विषयों अर्थात् मानविकी, वाणिज्य और विज्ञान में पत्राचार पाठ्यक्रमों के जरिए शिक्षा प्रदान करता है तथा स्कूल में छोड़कर जाने वालों, गृहस्थियों, दूर दराज क्षेत्रों में नेनात भूमिक अथवा अर्ध-सैनिक बलों के कार्मिकों को जो अपनी शिक्षा जारी रखने की इच्छा रखते हैं और जो किसी कारणवश नियमित रूप में स्कूल में नहीं जा सकते उनको शैक्षिक जरूरतें पूरा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इस समय पत्राचार विद्यालय लगभग 27,000 छात्रों को शैक्षिक जरूरतों को पूरा कर रहा है।

व्यावसायिक शिक्षा

9.6.13 इस योजना के अन्तर्गत लगभग 6200 छात्रों के लाभान्वित होने की आशा है। दिल्ली प्रशासन के स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 1991-92 के दौरान 91 लाख रुपए का बजट प्रावधान है।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद

9.6.14 मई, 1998 में दिल्ली प्रशासन के तहत राशैअ और प्रो परिषद की स्थापना एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गयी। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रो परिषद के समग्र पर्यवेक्षण में चार जिला शिक्षा प्रशिक्षण मस्यौदों की स्थापना की गयी। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रो परिषद के कार्यक्रमों में शैक्षिक कार्यकलापों का प्रसार करना है ताकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 और कार्यवाही योजना में निहित विचारों को व्यवहारिक स्वरूप दिया जा सके। इस प्रयोजनार्थ लगभग 100 कार्यक्रमों में राशैअ और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्रशिक्षित तीन हजार सात सौ शिक्षकों को प्रशिक्षित किये जाने की आशा है।

पंजाबी, हिन्दी, संस्कृत और उर्दू अकादमियाँ

9.6.15 संघशासित क्षेत्र दिल्ली में सभी स्तरों पर इन भाषाओं के प्रचार और विकास के उद्देश्य से इन अकादमियों की स्थापना की गयी। ये अकादमियाँ विभिन्न सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन और कार्यान्वयन कर रही हैं। इन भाषाओं के शिक्षण हेतु दिल्ली प्रशासन के विभिन्न स्कूलों में पंजाबी और उर्दू शिक्षकों को तैनात किया गया है।

दिल्ली नगर निगम

9.6.16 दिवंगम का शिक्षा विभाग आइमरी शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। 3-5 आयु वर्ग के बच्चों के लिए पूर्व आइमरी कक्षाएँ भी चलायी जाती हैं। वर्ष 1991-92 के दौरान दिवंगम के कार्यकरण के अंतर्गत 1674 आइमरी स्कूल चल रहे हैं इसके अतिरिक्त 721 नर्सरी कक्षाएँ इनके द्वारा चलाई जा रही हैं। बच्चों की जो वर्ष 1990-91 के दौरान 6,99,243 थी वह वर्ष 1991-92 में बढ़कर 7,31,615 हो गई है।

9.6.17 दिवंगम, अपने स्कूल के बच्चों को विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान करता है। सभी बच्चा को निशुल्क पुस्तकें मुहैया की जाती थीं। अनुसूचित जाति के बच्चों और श्रेणी IV के कर्मचारियों को निशुल्क वर्दी प्रदान की जाती थी। आइमरी-नर्सरी के बच्चों को मध्याह्न भोजन भी मुहैया किया जाता है। दिवंगम स्वास्थ्य योजना भी कार्यान्वित कर रहा है जिसके अंतर्गत बिकिता एवं चरम बच्चों को प्रदान की जाती है।

9.6.18 दिवंगम द्वारा शिक्षा के विकास के लिए योजनागत के अंतर्गत 2675 00 लाख रु. और योजनागत के अंतर्गत 9036 00 लाख रु. का एक बजट आवधान किया गया है।

नई दिल्ली नगरपालिका

9.6.19 नई दिल्ली नगरपालिका, जो एक स्थानीय निकाय है, वह भी 21 पूर्व आइमरी स्कूल, 68 आइमरी स्कूल मिडिल स्कूल, 9 माध्यमिक स्कूल और 5 सी० सैकेण्डरी स्कूलों सहित दिल्ली में विभिन्न स्कूल चला रही है। इसके अतिरिक्त दिल्ली में मिडिल स्तर के 3 नवयुग स्कूल और 2 नवयुग सी० सैकेण्डरी स्कूल भी चला रही हैं।

9.6.20 शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, नवदिवंगम पालिका छात्रों को विभिन्न प्रोत्साहन जैसे कक्षा I से VIII तक के छात्रों को निशुल्क अभ्यास पुस्तकें, कक्षा I से V तक के छात्रों को निशुल्क लेखन सामग्री और नर्सरी से VIII तक की कक्षा के छात्रों को निशुल्क वर्दियाँ प्रदान करती है।

9.6.21 इलेक्ट्रॉनिकी, रेडियो और दूरदर्शन मरम्मत केंद्रों एवं टेलरिंग, टैक्सटाइल डिजाइन सूई से संबंधित कार्य इत्यादि जैसे व्यवसायों में कार्य अनुभव एवं शौक केन्द्र प्रारंभ किए गए हैं। नयी दिल्ली नगर पालिका ने अपने सी० सैकेण्डरी स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा आरंभ की है। चालू वर्ष के दौरान, योजना के अंतर्गत लगभग 300 छात्रों को लाभ होगा।

लक्षद्वीप

9.7.1 लक्षद्वीप द्वीप समूह में कार्यरत विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं की संख्या निम्नलिखित है।

1	नर्सरी स्कूल	9
2	जूनियर बेसिक स्कूल	19
3	सीनियर बेसिक स्कूल	4

4	हाई स्कूल	9
॥	जूनियर कलेज	2
	कुल	43

9.7.2 इसके अलावा, एक नवोदय विद्यालय और 10 बालवाडियों भी चल रही हैं।

प्रोत्साहन योजनाएं

9.7.3 सभी छात्रों को निशुल्क अध्यास पुस्तकें, लेखन सामग्री पुस्तकें, लेखन सामग्री मुहैया की जा रही हैं। 1 से 7 वी कक्षा के सभी अन्ज-जान के छात्रों को मध्याह्न भोजन मुहैया किया जाता है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वालों की कुल संख्या लगभग 11,214 है। उन सभी अन्ज-जान के छात्रों को, जिनके अपने ही द्वीपसमूहों में कालेज अध्ययन की सुविधाएँ नहीं हैं, निशुल्क छात्रावास सुविधाएँ भी प्रदान की जाती हैं।

सेवागत प्रशिक्षण/पाठ्यक्रम

9.7.4 वर्ष के दौरान, आइमरी स्कूल शिक्षकों के लिए 2 सेवागत पाठ्यक्रम और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के लिए एक पाठ्यक्रम संचालित किए गए थे। शेष अवधि के दौरान, दो और पाठ्यक्रम भी आयोजित करने का प्रस्ताव है।

व्यावसायिक शिक्षा

9.7.5 वर्ष 1988-89 के दौरान संघ शासित प्रदेश द्वारा प्रारंभ की गई व्यावसायिक शिक्षा की योजना चल रही है। हाई स्कूलों में लड़कियों के लिए कार्यशिल्प की और लड़कों के लिए फिशरी प्रौद्योगिकी प्रारंभ की गई है। व्यावसायिक शिक्षा की और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए संघ शासित प्रदेश के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित पदों का सृजन किया गया है —

कार्य शिल्प अनुदेशक	3
यात्रिकी अनुदेशक	3
मत्स्य (फिशरी) अनुदेशक	3

तकनीकी शिक्षा

9.7.6 संघ शासित प्रदेश के कवारती के एक तिहाई में कटिंग एवं टेलरिंग, आशुलिपि और बर्द्धिंगरी सिखाई जाती है।

पाडिचेरी

9.8.1 वर्ष की दौरान पाडिचेरी प्रशासन, विभिन्न शैक्षिक गतिविधियों को कार्यान्वित करता रहा है। इन गतिविधियों का लेखा निम्नलिखित है—

शैक्षिक संस्थाएं

9.8.2 वर्ष 1991-92 के दौरान संघ शासित प्रदेश में कार्यरत विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं के ब्यौरे निम्नलिखित है —

	सरकारी	निजी
पूर्व आइमरी स्कूल	41	131
आइमरी स्कूल	261	71
मिडिल स्कूल	83	35
हाई स्कूल	56	20

- उच्चतर माध्यमिक स्कूल (एलएचटीसीजी) जूनियर कलेज और नवीनतम विद्यार्थी सहित) 26
- कालेज (शैक्षिक) 7
- छात्रवृत्ति योजनाएँ 2
- 9.8.3 संघ शासित प्रदेश निर्भरित छात्रवृत्ति योजनाएँ कार्यान्वित कर रहा है:—
- राष्ट्रीय छात्रवृत्तियाँ
 - राष्ट्रीय ग्रण छात्रवृत्तियाँ
 - आत्मसेवा छात्रवृत्तियाँ
 - स्कूली शिक्षकों के बच्चों के लिए छात्रवृत्तियाँ
 - ग्रामीण क्षेत्रों के मेधावी बच्चों के लिए छात्रवृत्तियाँ
 - आयता पुरस्कार
 - अन्य आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए छात्रवृत्तियाँ (आ. उ. वि. पं.)
 - उपस्थित छात्रवृत्तियाँ
 - राजनैतिक उल्लिखितों के लिए छात्रवृत्तियाँ
 - विज्ञान मेधावी छात्रवृत्तियाँ
 - छात्राओं को योग्यता साधन प्रदान करना एवं योग्यता पुरस्कार छात्रवृत्तियाँ
 - ओल्साहन पुरस्कार

9.8.4 इन छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 1991-92 के दौरान लाभ प्राप्त करने वालों की संख्या लगभग 26000 होगी।

ग्रोष्ठ शिक्षा/गैर औपचारिक शिक्षा:

9.8.5 जन साक्षरता अभियान के दौरान 90571 निरक्षर दखिल किए गए हैं। इनमें से 68435 ने साक्षरता के कम से कम स्तर प्राप्त कर लिया है। वर्ष 1991-92 के दौरान नीसिबियों के लिए एक कार्यक्रम संचालित करने का निर्णय लिया गया है। संघ शासित प्रदेश पांडिचेरी की 30 नवम्बर, 1991 को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित कर दिया गया है।

विज्ञान शिक्षा:

9.8.6 वर्ष 1988-91 के दौरान 83 मिलियन स्कूलों/56 हाई स्कूलों/18 उच्चतर माध्यमिक से विज्ञान शिक्षण की कोटिंग में सुधार करने के लिए "स्कूलों से विज्ञान शिक्षा में सुधार करने के लिए" नामक योजना कार्यान्वित की गई थी। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 1991-92 के दौरान 5 मिलियन और 6 हाई स्कूल इसमें शामिल करने का प्रस्ताव है।

व्यावसायिक शिक्षा:

9.8.7 तमिलनाडु एवं पांडिचेरी में +2 पाठ्यक्रमों की देशकला की गई है जिसमें दो शिक्षा की चारए अर्थात (1) शैक्षिक और (2) व्यावसायिक शामिल है। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, तमिलनाडु सरकार ने निर्भरित प्रमुख क्षेत्रों और संबंधी व्यावसायिक विषयों का पता लगाया है:—कृषि, वाणिज्य और व्यवसाय, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी, गृहविज्ञान, स्वास्थ्य और जिवविध।

9.8.8 विभिन्न उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में निर्भरित व्यावसायिक पाठ्यक्रम अंतर्भूत किए गए हैं। शैक्षिक सहायक, लेखाविद्या संहित सैक्रेटरीय और आर्थिक, मत्स्य पालन, दो पहिया स्कूटर की परम्परा एवं उभयरा रण्ड रखा। प्रयत्न रण्ड रखा, विपणन एवं विज्ञानकारी, व्यवसाय एवं संगणक संबंधी कार्यक्रम तैयार करना। रेडियो एवं टूरिज़्म रण्ड रखा, एवं परम्परा, प्रशिक्षण एवं वातावरण उत्पन्न, पकाना एवं निष्ठा (बैकिंग) एवं कनवर्षनरी) विद्युत प्रशीतन का रण्ड रखा एवं सफाई बुलाई। कुंस डिजाईनिंग एवं साजसज्जा (डैकिंग), संघटित एवं प्रार्थन, रेखा उल्पादन एवं कृषि।

उच्चतर शिक्षा:

9.8.9 संघ शासित प्रदेश, पांडिचेरी में 6 कला कालेज, पीजी-अध्ययन के लिए। केन्द्र 1 विधि कालेज, 3 पॉलिटेक्निक, 1 कृषि कालेज और 1 इंजीनियरी कालेज है। डिप्लोमा नामक एक चिकित्सा कालेज की है जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित और अभिशर्षित है और एक दंत कालेज है जो राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। ये पांडिचेरी विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं। पांडिचेरी का इंजीनियरी कालेज, पांडिचेरी से संबद्ध एक स्वायत्त निकाय है। कपाइकल का कृषि कालेज, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोइंबाटोर से संबद्ध है। पांडिचेरी और कपाइकल के तीन पॉलिटेक्निक, तकनीकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, मद्रास से संबद्ध हैं। विधि कालेज और अन्य छह कला कालेज एवं पीजी-अध्ययन केन्द्र पांडिचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं।

9.8.10 विश्वविद्यालय शिक्षा के अंतर्गत बीए (इतिहास) और बीएएससी (प्राणी विज्ञान) पाठ्यक्रम (महिला भारतीय देशन राजकोय कालेज में आरंभ किए गए हैं) विधि कालेज, पांडिचेरी एलएलबी में तीन वर्षीय साधकालीन पाठ्यक्रम आरंभ किया गया है। एमए (इतिहास अध्ययन) एलएफिल (जनसंहति), प्राणि विज्ञान एवं तमिल) और पीएलएडी (जनसंहति) पाठ्यक्रम अंतर्भूत किए गए हैं।

तकनीकी शिक्षा:

9.8.11 मोतीलाल नेहरू राजकीय पॉलिटेक्निक में संगणक अनुप्रयोग में 18 माह का आत्मकोतर डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया है। माह में एक पूर्णतः तकनीकी स्कूल गठित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

‘0. ଅନ୍ତର୍ଗତ’

10. छात्रवृत्तियाँ

10.10 शिक्षा विभाग भारत तथा विदेश में विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थाओं में आगे अध्ययन/अनुसंधान के लिए भारतीय छात्रों/अध्येताओं के लिए अभिहित अनेक छात्रवृत्तियों/शिक्षावृत्तियों को अभिशामित करता है। इन छात्रवृत्तियों में भारत सरकार की छात्रवृत्तियाँ और निदेशा द्वारा प्रदान की गई शिक्षावृत्तियाँ-दोनों-शामिल हैं। ऐसे ही कुछ प्रमुख कार्यक्रम निम्नके अन्तर्गत वर्ष 1991-92 के दौरान छात्रवृत्तियाँ/शिक्षावृत्तियाँ प्रदान की गई थी, इस प्रकार हैं—

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना

10.20 इस योजना के अन्तर्गत योग्यता एवं साधन के आधार पर उत्तर मैट्रिक अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं। छात्रवृत्तियों की दरें दिवस-अध्येताओं के लिए 60/- रु. प्रतिमाह से 120/- रु. प्रतिमाह तथा अध्ययन के पाठ्यक्रम पर निर्भर करते हुए, छात्रावासधारियों के लिए 100/- रु. से 300/- रु. प्रतिमाह तक भिन्न-भिन्न होती हैं। छात्रवृत्तियों की पात्रता के लिए आय-सीमा 25,000/- रु. प्रति वर्ष है।

राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना

10.30 इस योजना में योग्यता एवं साधन के आधार पर उत्तर मैट्रिक अध्ययन के लिए व्याज रहित ऋण का प्रावधान है। ऋण का रजिष्ट्र अध्ययन के पाठ्यक्रम पर निर्भर करते हुए 720/- रु. से 1750/- रु. प्रति वर्ष तक भिन्न-भिन्न होता है। कुछ अनुमत्य छूटों को अनुमान देने के बाद छात्रवृत्तियों की पात्रता के लिए आय-सीमा 25,000/- रु. प्रति वर्ष है। यह योजना राज्य सरकारों/मध्य शासित क्षेत्र के प्रशासनों के जरिए कार्यान्वित की जा रही है।

अनु-जा/अनु-जन्जातियों के छात्रों की योग्यता के प्रोत्थन की योजना:

10.41 यह योजना वर्ष 1987-88 में आरंभ की गई थी। इस योजना का उद्देश्य अनु-जा अनु-जन्जातों के छात्रों की योग्यता को उनके अतिरिक्त प्रशिक्षण (कोचिंग) देने हुए, स्कूलों विषयों में उनकी शैक्षिक क्षमियों को दूर करने तथा उन व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में जहाँ प्रविष्टि प्रायोगिक परीक्षा पर आधारित है, में उनके दाखिले की सुकर बनाने की दृष्टि में सहायता करना है। अनु-जा/अनु-जन्जातों के वे छात्र, जिन्हें इस योजना के अन्तर्गत चुना जाता है, उन्हें अच्छे आवासीय स्कूलों में रखा जाता है, जहाँ विशेष अध्ययन के लिए पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं। यह योजना राज्य सरकारों/मध्य शासित क्षेत्र के प्रशासनों के जरिए संचालित की जा रही है।

10.42 यह योजना 50 स्कूलों में 1000 छात्रों (670 अनु-जातियों तथा 330 अनु-जन्जातियों) के लिए प्रावधान करते हुए आरंभ की गई थी। विभिन्न राज्यों की स्कूलों का आबंटन अनु-जा/अनु-जन्जात समुदायों की उनकी निरक्षर जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। उपचार्य शिक्षण (कोचिंग) कक्षा IX स्तर में आरंभ होता है और यह तब तक जारी रहता है जब तक छात्र कक्षा XII पूरी नहीं कर लेता है। इसके अतिरिक्त,

विशेष शिक्षण (कोचिंग) कक्षा XI और XII में भी उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत, कोई आय-सीमा नहीं है।

अनुमोदित आवासीय माध्यमिक स्कूलों में भारत सरकार की छात्रवृत्ति योजना

10.51 इस योजना का उद्देश्य उन प्रतिभाशाली के साथ निर्धन छात्रों (11-12 वर्ष के आयु-वर्ग) को शिक्षा के -2 स्तर तक अच्छे आवासीय स्कूलों में अध्ययन के लिए शैक्षिक सुविधाएँ प्रदान करना है। पात्रता के लिए अभिभावकों/सरकारों की आय-सीमा 25,000/- रु. प्रति वर्ष है। प्रति वर्ष 500 छात्रों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान करने के लिए चुना जाता है। इन छात्रवृत्तियों में से 50% छात्रवृत्तियाँ अखिल भारतीय योग्यता पर परीक्षित की जाती हैं और शेष 50% छात्रवृत्तियाँ राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को निर्धारित न्यूनतम मानकों को पूरा करने के आधार पर उनकी जनसंख्या के अनुसार आवंटित की जाती हैं। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को क्रमशः 15% तथा 71.2% छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं। अध्ययन सरकार द्वारा नियत की गई दरों/सीमा पर जेब-खर्च वरदा वस्त्र-पना और प्रेषण प्रसारों के अतिरिक्त शिक्षा शुल्क, आवासीय प्रयोग, पुस्तकों तथा लेखन सामग्रियों की लागत की पूरी राशि के पात्र हैं। अध्येताओं और उनके रक्षकों को इस प्रयोजनार्थ निर्धारित दरों के अनुसार यात्रा अनुदान अनुपलब्ध है।

10.52 वर्ष 1990-91 में इस योजना को समाप्त किए जाने का निर्णय लिया गया था। तथापि, उस वर्ष की परीक्षा में चुने गए छात्रों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान कर दी गई हैं।

हिन्दी में उत्तर-मैट्रिक अध्ययनों के लिए अहिन्दी भाषी राज्यों के छात्रों को छात्रवृत्तियाँ:

10.60 यह योजना 1955-56 में आरंभ की गई थी और इस योजना का उद्देश्य अहिन्दी भाषी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में हिन्दी के अध्ययन को प्रोत्साहित करना तथा इन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों को जहाँ हिन्दी का ज्ञान अनिवार्य है वहाँ अध्ययन तथा अन्य पद पर निगरानी रखने के लिए उपयुक्त कार्यात्मक उपलब्ध करना है। वर्ष 1991-92 के दौरान विभिन्न अहिन्दी भाषी राज्यों/मध्य शासित क्षेत्रों को 2,500 छात्रवृत्तियाँ आवंटित की गई थीं। छात्रवृत्तियों की दरें 50/- रु. से 125/- रु. तक भिन्न-भिन्न हैं जो अध्ययन के पाठ्यक्रम पर निर्भर करती हैं।

संस्कृत अर्थात् अरबी और फारसी आदि के अतिरिक्त श्रेण्य भाषाओं के अध्ययन में लगी हुई परम्परागत संस्थाओं से ज्योर्ण छात्रों को अनुसंधान छात्रवृत्तियाँ:

10.70 वर्ष 1991-92 में इस छात्रवृत्ति के लिए 20 अध्येताओं को चुना गया था।

ग्रामीण-क्षेत्रों से प्रतिभाशाली बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना:

10.8.0 यह योजना 1971-72 में चल रही है। इस योजना का लक्ष्य शैक्षिक अवसरों की बृद्धि स्थानता प्राप्त करना और ग्रामीण क्षेत्रों की सामर्थ्य प्रतिभाओं के विकास को अच्छे स्कूलों में उच्च शिक्षा प्रदान करते हुए प्रोत्साहन देना है। यह योजना राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों के जरिए क्रियान्वित की जा रही है। छात्रवृत्तियों का वितरण प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र में सामुदायिक विकास खण्डों के आधार पर किया जाता है। छात्रवृत्ति मिडिल स्कूल स्तर (कक्षा VI/VIII) के अन्त में पुरस्कृत की जाती है और +2 स्तर सहित माध्यमिक स्तर तक जारी रहती है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद/राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषदों की मदद से राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा छात्रों का चयन किया जाता है। छात्रवृत्तियों की दर 30 रुपये से 100 रुपये प्रतिमाह के बीच होती है जो अध्ययन के पाठ्यक्रम पर आधारित होती है। इस योजना की समीक्षा मई, 1990 में की गयी थी और बेहतर परिणाम प्राप्त करने के उद्देश्य से मूल्यांकन का कार्य नीचा को सौंपा गया है।

भारत तथा विदेशों में विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर अध्ययनों के लिए जवाहर लाल नेहरू शिक्षावृत्ति की योजना

10.9.1 भारत की आजादी के चालीस वर्ष पूरे होने तथा पंडित जवाहर लाल नेहरू की जन्म शताब्दी के कार्यक्रम के एक भाग के रूप में भारत तथा विदेशों में विभिन्न स्नातकोत्तर अध्ययनों के लिए जवाहर लाल नेहरू शिक्षावृत्ति योजना आरम्भ की गयी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आमतौर पर जवाहर लाल नेहरू के नाम पर प्रतिष्ठित शिक्षावृत्तियां प्रदान करना है।

10.9.2 इस योजना का उद्देश्य स्नातकोत्तर अध्ययनों के लिए सुयोग्य छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ऐसे विदेशी छात्रों को, जो भारतीय इतिहास, सभ्यता और संस्कृति, मानविकी/भारत के सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में न्यूनतम विकास जैसे विषयों में स्नातकोत्तर अध्ययन करना चाहेंगे, उन्हें वरीयता दी जाएगी। 20 छात्रवृत्तियां अर्थात् भारत में अध्ययन के लिए 10 भारतीय छात्रों को विदेशों में अध्ययन के लिए 5 भारतीय छात्रों को और भारत में अध्ययन के लिए विदेशों से 5 छात्रों को प्रदान की जाएगी।

10.9.3 एक कारपस निधि के रूप में 7.00 करोड़ रुपये की राशि रखी जाएगी। इस कारपस निधि पर प्रतिवर्ष अर्जित व्याज के शिक्षावृत्ति के प्रयोजनार्थ प्रयोग किया जाएगा।

सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों के तहत विदेशी सरकारों द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्तियां/शिक्षावृत्तियां

10.10.0 इन कार्यक्रमों के अंतर्गत, विदेशों में उच्च अध्ययन के लिए भारतीय छात्रों/नागरिकों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष विभिन्न विदेशी सरकारों और एजेंसियों को उपलब्ध कराए जाते हैं। इस प्रभाग द्वारा 30 नवम्बर, 1991 तक इन छात्रवृत्तियों को वार्षिक उपयोग का देश-वार ब्यौरा निम्नलिखित है:-

- 1 बुल्गारिया
- 2 चीन
- 3 बैकरोस्लोवाकिया
- 4 जर्मनी
- 5 हंगरी
6. इंडोनेशिया
7. इटली
- 8 जापान
- 9 नार्वे
10. पोर्लैंड
- 11 पुर्तगाल
- 12 तुर्की
- 13 यूएसए
14. युगोस्लाविया

48

यू.के., कनाडा आदि की सरकारों द्वारा प्रदत्त राष्ट्रमंडलीय छात्रवृत्ति/शिक्षावृत्ति योजनाएं

10.10.0 इस योजना के अंतर्गत, यू.के., कनाडा, हांग-कांग, नाइजीरिया, ट्रिनीदाद और टुबागो और अन्य राष्ट्रमंडल देशों में उच्च अध्ययन/अनुसंधान/प्रशिक्षण के लिए भारतीय राष्ट्रियों को छात्रवृत्ति/शिक्षावृत्तियां प्रदान की जाती हैं। राष्ट्रमंडल विश्वविद्यालयों के संघ से प्राप्त पेशकश के आधार पर छात्रवृत्तियों की सख्या निर्धारित करती है। इस योजना के अंतर्गत 30 नवम्बर 1991 तक 65 अध्ययताओं को विदेश भेजा जा चुका है।

नेहरू शताब्दी (ब्रिटिश) शिक्षावृत्तियां/पुरस्कार

10.12.0 इस योजना के अंतर्गत भारतीय छात्रों को उच्च अध्ययन/अनुसंधान के लिए यू.के. भेजा जाता है। ये शिक्षावृत्तियां ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की जाती हैं। 30 अक्टूबर, 1991 तक 10 अध्ययताओं को विदेश भेजा गया।

ब्रिटिश तकनीकी सहयोग प्रशिक्षण कार्यक्रम

10.13.0 इस योजना के अंतर्गत 30 नवम्बर, 1991 तक 11 उम्मीदवारों को विदेश भेजा गया।

जवाहरलाल नेहरू स्मारक (यू.के.) छात्रवृत्तियां

10.14.0 इस योजना के अंतर्गत 30 नवम्बर 1991 तक 2 उम्मीदवारों को विदेश भेजा गया।

ब्रिटिश विजिटिंग कार्यक्रम परिषद

10.15.0 इस योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत 174 वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों और चिकित्सा विशेषज्ञों को उनके विशेषज्ञता के क्षेत्रों में मुख्य विकास के आपसी मूल्यांकन के लिए 30 नवम्बर 1991 तक लाभान्वित किया गया।

“ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३ ॥ ”

11. पुस्तक प्रोन्नति और कापीराइट

11.1.0 शिक्षा के क्षेत्र में पुस्तकें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आज जबकि सारे देश में शिक्षा सुविधाओं का विस्तार हुआ है, पुस्तकों और विभिन्न विषयों की पुस्तकों की मांग बढ़ रही है। शिक्षा विभाग के पुस्तक प्रोन्नति प्रभाग की ऐसी कई योजनाएँ और कार्यक्रम हैं जिनका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ उचित मूल्यों पर अच्छे स्तर की पुस्तकों के प्रकाशन को बढ़ावा देना, देशी लेखकों को प्रोत्साहन देना, लोगों में पुस्तकें पढ़ने की रुचि पैदा करना तथा भारतीय पुस्तक उद्योग को मजबूत करना है। इस सब में कार्यन्वित किए जा रहे कुछेक महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का संक्षिप्त व्यौरा निम्नलिखित पैराग्राफों में दिया गया है।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास

11.2.1 शिक्षा विभाग के अधीन, स्वायत्त संगठन के रूप में कार्यरत राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की स्थापना 1957 में की गई थी जिसका उद्देश्य उचित कीमत पर अच्छी पठन सामग्री का प्रकाशन करना और उसे प्रोत्साहन करना तथा लोगों में पुस्तकों के प्रति रुचि उत्पन्न करना था। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के मुख्य कार्यकलाप हैं पुस्तकें प्रकाशित करना, लेखकों, मंचित्रकारों व प्रकाशकों को सहायता देना तथा पुस्तकों का संवर्धन करना। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास माधुराज पाठकों के लिए, असमी, बंगाली, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, कन्नड, मलयालम, मराठी, उडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू में अनेक विषयों की पुस्तकें प्रकाशित करता है और उचित कीमत पर उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने अब तक विभिन्न भाषाओं में 5400 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित की हैं। न्यास उचित कीमत पर डिक्टोमा, अवर-स्लाइड तथा स्लाइडोस्कोप स्तर की पाठ्यपुस्तकें व मदरस पुस्तकें प्रकाशित करने तथा बच्चों और नवसाक्षरों के लिए पुस्तकें प्रकाशित करने के लिए, लेखकों, चित्रकारों तथा प्रकाशकों को वित्तीय सहायता देता है। न्यास (क) पुस्तक मेले, उत्सव तथा प्रदर्शनियाँ आयोजित करके, (ख) गोष्ठियाँ, संगोष्ठियाँ तथा कार्यशालाएँ आयोजित करके, (ग) पुस्तक मेले तथा प्रदर्शनियाँ आयोजित करने के लिए विनोय सहायता देकर, (घ) राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह को आयोजित करके, (ङ) स्कूलों में पाठक क्लब की स्थापना को प्रोत्साहित करके सारे देश में पुस्तकों तथा पुस्तक पढ़ने की आदत को बढ़ावा देता है। न्यास विभिन्न देशों में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों में भाग लेकर, विदेशों में भारतीय पुस्तकों को लोकप्रिय बनाता है। वर्ष के दौरान किए गए कार्यक्रमों का व्यौरा निम्नलिखित है :

(क) प्रकाशन कार्यक्रम

11.2.2 विभिन्न भाषाओं में प्रकाशन कार्यक्रम तैयार करने समय यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न किया जाता है कि राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की विभिन्न शृंखलाओं के अंतर्गत प्रत्येक भाषा में सामान्य रुचि की विविधतापूर्ण पुस्तकें शामिल हों।

11.2.3 नेहरू बाल पुस्तकालय शृंखला का उद्देश्य मनोरंजक एवं शानदार साहित्य के भंडार का सृजन करना है जिसे बच्चे रुचि लेकर पढ़ सकें। यह सारे देश में बच्चों को उनकी मातृ भाषा में सामान्य पठन

सामग्री उपलब्ध करके राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है। अब तक विभिन्न विषयों पर 2755 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं जिनमें अनुवाद तथा पुनर्मुद्रण भी शामिल हैं। इनमें इतिहास, लोक-तालिम, उत्सव, स्वतंत्रता संग्राम, विज्ञान तथा औद्योगिकी, पेड़-पौधे, कल्पनात्मक साहित्य, खेल-कूद, आदिवासी जीवन, भारतीय चित्रकला, विशिष्ट भारतीयों का व्यक्तित्व एवं कृतित्व तथा महान भारतीय लेखकों की कृतियों के उद्धरण शामिल हैं। अप्रैल से दिसंबर, 1991 की अवधि के दौरान 112 पुस्तकें प्रकाशित की गई थीं।

11.2.4 नवसाक्षरों के लिए पठन सामग्री शृंखला के अंतर्गत लघु कथाएँ, जीवनीयाँ, उपन्यासिकाएँ, लोक कथाओं के लिखितरण, प्रासंगिक मुद्दों पर लेख तथा कार्यात्मक उपयोगी जानकारी प्रकाशित की जाती है। इस सामग्री को अपीष्ट दर्शकों के लिए उपयुक्त बनाने के लिए इस शृंखला में पुस्तकें उसी बोली में लिखी जाती हैं जिसमें इसके पाठक परिचित हों, और इसमें 30-40% स्थान चित्रों के लिए सुरक्षित रखा जाता है। अब तक 60 पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी हैं जिसमें से 11 पुस्तकें अप्रैल से दिसंबर, 1991 के दौरान प्रकाशित की गई थीं। नवसाक्षरों के लिए तमिल में पठन सामग्री तैयार करने के लिए पंडिचेरी में 22 जून से 2 जुलाई, 1991 तक एक कार्यशाला आयोजित की गई थी।

11.2.5 राष्ट्रीय जीवनी शृंखला में सुविख्यात भारतीयों अथवा उन भारतीयों के जीवनचरित का वर्णन है जो भारत के साथ करीब से जुड़े हैं और जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों जैसे, धर्म, दर्शन, इतिहास, साहित्य, संगीत तथा विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब तक 112 से अधिक जीवनीयाँ प्रकाशित की जा चुकी हैं और उनकी कुल संख्या भाषा अनुवाद मिलाकर लगभग 721 है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान 21 पुस्तकें प्रकाशित की गई थीं।

11.2.6 आदान-प्रदान विशेष महत्व की शृंखला है क्योंकि सृजनात्मक साहित्य के आदान-प्रदान के जरिए राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में इसकी उपयोगिता अद्वितीय है। यह एक भारतीय भाषा के सुविख्यात साहित्यिक कृतियों को, जिसमें उपन्यास, नाटक, लघुकथाएँ शामिल हैं, दूसरे भाषायी क्षेत्रों के लोगों को प्रस्तुत करता है। इसके अतिरिक्त, विशेष काल अथवा एक अथवा अधिक विशिष्ट लेखकों की रचनाओं का संग्रह प्रकाशित किया जाता है। पहले ही, इस शृंखला में 12 भारतीय भाषाओं में 870 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी हैं जिनमें से 9 पुस्तकें अप्रैल से दिसंबर, 1991 के दौरान प्रकाशित की गई थीं।

11.2.7 "इंडिया-लैंड एंड पीपुल" शृंखला के अंतर्गत प्रकाशित पुस्तकें भौतिक पर्यावरणों, विभिन्न सांस्कृतिक परंपराओं तथा पेड़-पौधों की जानकारी देती हैं जिन्होंने भारत की सामाजिक संस्कृति एवं विविध रूपों स्वरूप को समृद्ध किया है। क्योंकि ये पुस्तकें उन पाठकों के लिए लिखी जाती हैं जो विषय से परिचित नहीं हैं, अतः इन्हें विषय के विशेषज्ञों द्वारा गैर-तकनीकी भाषा में लिखा जाता है और इनमें प्रामाणिक व अधतन जानकारी दी जाती है। अब तक अंग्रेजी सहित प्रमुख भारतीय भाषाओं में

433 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी हैं जिनमें से पांच अप्रैल से दिसंबर, 1991 के दौरान प्रकाशित की गईं।

11.2.8 या इंडिया लाइब्रेरी श्रृंखला के अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए पुस्तकें प्रकाशित करने का मुख्य उद्देश्य है — सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक सकल्यनाओं व उन मुद्दों और विकल्पों की जानकारी देना, जिनका आने वाले वर्षों में नवयुवकों को सामना करना पड़ेगा, उनको जिज्ञासा को जागृत करना और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना। माहस कथाएँ, यात्रावृत तथा जीवन में आगे बढ़ने के अवसरों संबंधी पुस्तकें भी इस श्रृंखला में शामिल हैं। अप्रैल और दिसंबर, 1991 के दौरान 7 पुस्तकें प्रकाशित की गई थीं।

11.2.9 पापुलर साइंस श्रृंखला का उद्देश्य है — औसत शिक्षित पाठक को उसके परिवेश से अवगत कराना, दिन-प्रतिदिन के जीवन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका को समझने योग्य बनाना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास को बढ़ावा देना। यह सुनिश्चित करने के लिए यथासंभव प्रयास किया जाता है कि जो भी सूचना दी जाए वह वैज्ञानिक रूप से प्रामाणिक व विश्वसनीय हो। अप्रैल से दिसंबर, 1991 के दौरान चार पुस्तकें प्रकाशित की गईं।

(ख) प्रकाशन में सहायता

11.2.10 उचित क्रोमट पर स्वीकार्य कोटि की पुस्तकों के प्रकाशन को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय पुस्तक न्यास निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत लेखकों, चित्रकारों व प्रकाशकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

पुस्तकों के रियायती प्रकाशन की योजना

11.2.11 इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने पहले ही उच्च शिक्षा के लिए लगभग 780 पुस्तकों के प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता दी है। इसी प्रकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भी एक योजना है जिसके अंतर्गत विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकें तैयार करने के लिए सहायता दी जाती है। तथापि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग व राष्ट्रीय पुस्तक न्यास दोनों ही उत्कृष्ट लेखकों और विशेषज्ञों द्वारा विशेष रूप से भारतीय छात्रों के लिए सर्वातपूर्वक प्रलेखित एवं अच्छी तरह से लिखी पाठ्य एवं सदर्भ पुस्तकों की उपलब्धता को लेकर गंभीर रूप से चिंतित हैं। सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद दोनों संगठन इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यदि इन्हें और अधिक सम-व्यापक ढांचे के अंतर्गत निष्पादित किया जाए तो उनको योजनाएं और ज्यादा प्रभावकारी होंगी। विस्तृत चर्चा के उपरान्त इन राष्ट्रीय संगठनों ने अपनी-अपनी योजनाओं के सम-व्यापक कार्यक्रमों के लिए अब एक नौति ढांचा तैयार किया है तथा आपसी सूझबूझ संबंधी ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।

बच्चों और नव-साक्षरों के लिए पुस्तकों के निर्माण के लिए सहायता देने की योजनाएं

11.2.12 राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने निजी प्रकाशकों और स्वैच्छिक एजेंसियों को बच्चों और नव-साक्षरों तथा स्कूल बीच में छोड़ कर जाने वाले के लिए उच्च कोटि की पुस्तकों का निर्माण करने के लिए वित्तीय सहायता देने की एक योजना शुरू की है जिसमें न्यास लेखक और चित्रकार दोनों को सीधा भुगतान करता है और इसके अतिरिक्त पाठ्यलिपियों के तैयार करने का खर्च वहन करता है।

(ग) पुस्तक प्रोत्साहन

11.2.13 राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के पुस्तक प्रोत्साहन कार्यक्रमों में पुस्तक मेले, पुस्तक उत्सव, पुस्तकों से संबंधित विषयों पर कार्यशालाएँ, सेमिनार और समोष्ठियाँ आयोजित करना, राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह का आयोजन आदि शामिल हैं। 14 से 20 नवंबर, 1991 तक सातवाँ राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह मनाया गया। वर्ष के दौरान न्यास ने मंदिर पुस्तक उत्सव (31 अगस्त — 8 सितंबर, 1991), भोपाल पुस्तकमेला (28 सितंबर — 6 अक्टूबर, 1991), नई दिल्ली, कलकत्ता 19 — 17 नवंबर, 1991 के बीच तथा दिल्ली में 28 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच वाला पुस्तक मेला आयोजित किया। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने नई दिल्ली नगरपालिका समिति के लगभग 25 चुने हुए विद्यालयों व पाठक क्लब की भी एक बड़ी परियोजना आरम्भ की है।

पुस्तक संवर्धनात्मक कार्यक्रमों तथा स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता

11.3.0 पुस्तक संवर्धनात्मक कार्यक्रमों तथा स्वैच्छिक संगठनों के वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत स्वैच्छिक संगठनों को प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, सेमिनार, कार्यशालाएँ और सम्मेलन आदि के आयोजन के लिए तदर्थ आधार पर अनुदान दिया जाता है। यह योजना, सामूहिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत लेखकों के प्रतिनिधि-मंडल ने आदान-प्रदान पर हुए खर्च की भी व्यवस्था करती है।

विश्वविद्यालय स्तर की विदेशी मूल की सस्ती पुस्तकों का प्रकाशन

11.4.0 विभाग, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत संघ की सरकारों के सहयोग से तीन कार्यक्रमों का संचालन कर रहा है। इन परियोजनाओं के अंतर्गत विश्वविद्यालय स्तर की मानक विदेशी पाठ्यपुस्तकों और सदर्भ पुस्तकों के नवीनतम संस्करणों का, जिनके समतुल्य भारतीय पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं, सस्ते प्रकाशन के रूप में प्रकाशन किया जाता है। अब तक 763 ब्रिटिश, 1668 अमरीकी और 650 सोवियत रूस की पुस्तकों को प्रकाशित किया जा चुका है। चालू वर्ष के दौरान 38 अमरीकी और 68 सोवियत रूस की पुस्तकें प्रकाशित करने की सिफारिश की गई है।

भारत-सोवियत संघ साहित्यिक परियोजना (बीसवीं शताब्दी साहित्य परियोजना)

11.5.0 भारत और सोवियत संघ के ममान्यायिक सृजनात्मक साहित्य के प्रकाशन के लिए स्थापित शताब्दी भारत-सोवियत समिति ने दोनों देशों की 20 वीं शताब्दी की मुख्य साहित्यिक रचनाओं का लगभग 20-20 खण्डों में अनुवाद प्रकाशित करने के लिए एक परियोजना तैयार की है। इसके प्रथम दो खण्डों का निर्माण मास्को में, भारत महोत्सव के दौरान किया गया। साहित्य अकादमी, जो भारतीय पक्ष की ओर से परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए एक विशिष्ट एजेंसी है ने इस संबंध में किए गए कारगर के अनुसार इन दोनों खण्डों की हजार-हजार प्रतियाँ खरीदी हैं। सोवियत पक्ष द्वारा हिंदी अनुवाद के लिए भेजे गए तीसरे, चौथे और पांचवें खण्डों की पाठ्यलिपियों का भारतीय विशेषज्ञों द्वारा संपादन किया गया और उन्हें प्रकाशित करने की स्वीकृति दे दी गई। पाठ्यलिपियों के प्रकाशन के लिए उन्हें सोवियत संघ को वापस कर दिया गया। वर्ष 1995 तक सभी खण्ड प्रकाशित हो जाने की आशा है।

राष्ट्रीय पुस्तक विकास परिषद

11 60 देश में पुस्तकों के प्रकाशन की प्रगति की समीक्षा करने और पुस्तक उद्योग तथा व्यापार के विकास के लिए किए जाने वाले उपायों के सबब में सरकार को परामर्श देने, अच्छी कौटि की विशेष प्रयोजन की पुस्तकों की उपलब्धता को बढ़ाने आदि के लिए 6 11 90 को राष्ट्रीय पुस्तक विकास परिषद का पुनर्गठन किया गया है।

पुस्तकों और प्रकाशनों के लिए नई आयात नीति

11 70 पुस्तकों और, प्रकाशनों के लिए नई आयात नीति अप्रैल 1990 से लागू की गई है और यह नीति मार्च 1993 तक चलती रहेगी।

पुस्तक निर्यात और संवर्धन कार्यक्रम

11 80 भारत पुस्तक प्रकाशित करने वाले प्रमुख देशों में से एक है। विदेशों में भारतीय पुस्तकों की बिक्री और अनुवाद/पुनर्मुद्रण के दायित्वों को प्रोत्साहित करने के लिए और विदेशों से मुद्रण कार्य प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में भाग लेकर और भारतीय पुस्तकों की विशेष प्रदर्शनियां आयोजित करके व्याख्या सहित सूची-पत्रों तथा बाजार अध्ययन विवरणिकाओं आदि के परिचालन द्वारा वाणिज्यिक प्रचार तथा बाजार अध्ययन करके हमारी पुस्तकों की बिक्री के लिए उपाय किए जा रहे हैं। सांस्कृतिक विनियम कार्यक्रम के अंतर्गत 1991-92 के दौरान मालद्वीव और चीन में भारतीय पुस्तकों की प्रदर्शनियां आयोजित की गई।

अंतर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्यांकन के लिए राजा राममोहन राष्ट्रीय एजेंसी

11 90 अंतर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्यांकन प्रणाली का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्षेत्र में स्वदेशी प्रकाशनों के निर्यात को बढ़ावा देना है और दिन प्रतिदिन के कार्यों में नियंत्रित पुस्तक व्यवहारों को अधिकतम कम करना है। यह एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है जिससे प्रत्येक पुस्तक की अलग-अलग पहचान सफाई निर्धारित की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्यांकन प्रणाली अभी तक तो भारत में अपनी प्रारंभिक अवस्था में है किन्तु इसके अन्वाया भी यह प्रणाली पुस्तक व्यापार के लिए पुस्तकालयों और सूचना प्रणाली तथा अनुसंधान अध्येताओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। पहली जनवरी 85 से लेकर 31 अक्टूबर 1991 तक करीब-करीब 1 75 छोटे बड़े प्रकाशक और लेखक इस व्यवस्था के सदस्य हो गए हैं और उनके हजारों प्रकाशन आज अंतर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्यांकन से जुड़े हुए हैं।

कापीराइट

11 10.1 कापीराइट कार्यालय की स्थापना जनवरी 1958 में कापीराइट अधिनियम 1957 की धारा 9 के अनुसूचन में की गई थी। मौजूदा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कापीराइट अधिनियम कापीराइट संशोधन अधिनियम 1983 और कापीराइट संशोधन अधिनियम 1984 द्वारा संशोधित किया गया।

राष्ट्रपति ने प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) अध्यादेश, 1991 28 दिसंबर, 1991 को जारी किया है। इस संशोधन द्वारा प्रतिलिप्यधिकार की अवधि 50 से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई है।

11 10.2 प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय समय-समय पर यथा संशोधित प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम 1957 के प्रावधानों के अंतर्गत निम्नलिखित श्रेणियों की कृतियों को पंजीकृत करता है

- (क) साहित्यिक नाटकीय
- (ख) संगीत एवं अभिलेख
- (ग) चर्चित
- (घ) कलात्मक

इसके अतिरिक्त, कापीराइट कार्यालय प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम 1957 की धारा 49 के अनुसार विभिन्न श्रेणियों की कृतियों से संबंधित प्रतिलिप्यधिकार रजिस्टर में परिवर्तनों को पंजीकृत करता है। वर्ष के दौरान अधिनियम के अंतर्गत 1741 कृतियों का पंजीकरण किया गया है।

11 10.3 कापीराइट बोर्ड, जो एक अर्ध-न्यायिक निकाय है, का आदित-सितंबर, 1958 में गठन किया गया था। प्रतिलिप्यधिकार मंडल के क्षेत्राधिकार में भारत के सभी भाग आते हैं। मंडल प्रतिलिप्यधिकार पंजीकरण में संशोधन संबंधी मामलों और

- * सामान्य जनता के लिए प्रतिकथित कृतियों
- * अप्रकाशित भारतीय कृतियों
- * अनुवाद करने और उसके प्रकाशन तथा
- * किन्ती प्रयोजनों से रचित और प्रकाशित कृतियों

को अनुज्ञाति प्रदान करने के लिए प्रतिलिप्यधिकार सौंपने से संबंधित विवादों की सुनवाई करता है।

11 10.4 यह प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम 1957 के अंतर्गत अपने समक्ष किए गए अन्य विविध मामलों की भी सुनवाई करता है। मंडल की बैठकें देश के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित की जाती हैं ताकि लेखकों, रचनाकारों और बौद्धिक संपदा के स्वामियों को उनके निवास अथवा कार्यालय के समीप न्याय की सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके। प्रतिलिप्यधिकार मंडल 8 मई, 1990 को 4 वर्ष के लिए अर्थात् 31 मार्च 1994 तक के लिए पुनर्गठित किया गया। वर्ष के दौरान मंडल ने 38 मामलों पर निर्णय लिए।

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्यधिकार

11 11.1 भारत साहित्यिक एवं कलाकृतियों के संरक्षण संबंधी बर्न और युनिवर्सल प्रतिलिप्यधिकार संधि नामक दोनों अंतर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्यधिकार संधियों का सदस्य है। इन दोनों संधियों में 1971 में संशोधन करके उन मामलों में किन्ती विशिष्ट प्रयोजनों से विदेशी मूल की पुस्तकों के पुनर्मुद्रण और अनुवाद के लिए विकासशील देशों को अनिवार्य अनुज्ञाति जारी करने का अधिकार प्रदान किया, जिन मामलों में प्रतिलिप्यधिकार स्वामी स्वतंत्र बातचीत के जरिए ये अधिकार देने को राजी न हो। भारत ने इन संधियों को 1971 पुस्तकों के लिए सहमति प्रदान की है।

11 11.2 भारत विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (वीपी) अनेवा जो साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के संरक्षण संबंधी बर्न कंवेशन का अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय है, के शासी निकाय के विचार-विमर्श में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

11 11.3 वीपी अंतर्राष्ट्रीय संपदा शिक्षण संबंधी राष्ट्रीय कार्यशाला का दिल्ली में 21-25 अक्टूबर, 1991 को आयोजन किया गया। यह कार्यशाला दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षा विभाग और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (वीपी) के सहयोग से आयोजित की गई। वीपी ने ब्रिटेन

संयुक्त राज्य अमेरिका, आस्ट्रेलिया और थाईलैंड से एक-एक विशेषज्ञ - कुल चार विशेषज्ञ और वीपों के दो वरिष्ठ अधिकारी कार्यशाला में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्त किए। यह कार्यशाला मई 1990 के बाद से वीपों द्वारा भारत में आयोजित पहली बैठक थी और पहले ऐसी शिक्षण कार्यशाला थी जिसमें शैक्षणिक समुदाय ने भाग लिया। महसूस किया गया कि बौद्धिक संपदा के बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय महत्व को मद्देनजर रखते हुए इस देश में इसे विधिक अध्ययन के क्षेत्र के रूप में स्थापित किए जाने की आवश्यकता है।

11.11 4 विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (वीपों) के महानिदेशक डा० अर्पंड बोम्ब ने वीपों के उप महानिदेशक श्री शाहिद अली खा और वीपों के निदेशक (काउंसिलर) श्री ज्योफ्रे यू के साथ 22 से 25 जनवरी, 1992 के बीच भारत का दौरा किया तथा उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री, वाणिज्य राज्य मंत्री, उद्योग राज्य मंत्री तथा अन्य मंत्रियों से मुलाकात की।

प्रतिलिप्यधिकार के क्षेत्र में प्रशिक्षण सुविधाएं

11.12 0 वीपों ने अपने सहयोग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विकासशील देशों में प्रतिलिप्यधिकार से संबंधित अधिकारियों के लिए प्रतिलिप्यधिकार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। वर्ष के दौरान, इस विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों ने वीपों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।

1 शिक्षा विभाग के निदेशक श्री आर० एन० तिवारी ने कापीराइट और नेबरिंग राइट्स से संबंधित विस्मात्सक सहयोग की वीपी स्थायी समिति के 15-18 अप्रैल 1991 तक जेनेवा में आयोजित छठे सत्र में भाग लिया।

2 श्री आर० एल० रायचन्दानी, डेस्क अधिकारी प्रौढ़ शिक्षा ने 11-22

नवम्बर, 1991 तक बुडापेस्ट में आयोजित प्रतिलिप्यधिकार और संबद्ध अधिकार संबंधी वीपी प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।

प्रतिलिप्यधिकार प्रवर्तन सलाहकार परिषद

11 13 0 भारत सरकार ने एक प्रतिलिप्यधिकार प्रवर्तन सलाहकार परिषद का गठन किया है ताकि सभी सदस्यो/संघ-क्षेत्रों में प्रतिलिप्यधिकार के प्रवर्तन को सुदृढ़ और कारगर बनाया जा सके और सामान्य जनता और प्रवर्तन प्राधिकारियों दोनों को प्रतिलिप्यधिकार चोरी के अपराध और प्रतिलिप्यधिकार के कारण मरक्षण के सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व के बारे में शिक्षित किया जा सके। परिषद का कार्य, प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा करना और सरकार को प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन में सुधार के उपाय सुझाना है। प्रतिलिप्यधिकार प्रवर्तन सलाहकार परिषद की पहली बैठक 6 दिसंबर 1991 को नई दिल्ली में सत्र हुई जिसमें विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। शिक्षा विभाग ने कापीराइट लागू करने में संलग्न अधिकारियों के लिए 13-14 जनवरी, 1992 को नई दिल्ली के लोधी रोड स्थित भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय केंद्र में कापीराइट और इसके लागू करने के संबंध में एक प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की। कापीराइट के मामलों में लागू करने वाले अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और उच्च शैक्षिक जगत और कापीराइट उद्योगों के नक्काओ के आगे लाने के उद्देश्य से देश में आयोजित यह कार्यशाला अपने आप में पहला था। कार्यशाला का उद्घाटन माननीय वाणिज्य राज्य मंत्री श्री पी० चिदम्बरम द्वारा किया गया था और दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री वी० एन० कृपाल ने इसको अध्यक्षता की। इसमें आन्ध्र प्रदेश बिहार चडोगाह दिल्ली हरियाणा मध्य प्रदेश महाराष्ट्र पंजाब राजस्थान, मिक्किम और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने भाग लिया था।

2. 203¹ 4 5 6 7

12. भाषाओं की प्रोन्नति

12.1.0 भाषाएँ शिक्षा का महत्वपूर्ण माध्यम होती हैं इस कारण राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इनके विकास के लिए महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अतः भारतीय सविधान की आठवीं अनुसूची में हिन्दी और अन्य चौदह भाषाओं को सुचीबद्ध किया गया है जिसमें एक और संस्कृत तथा उर्दू भाषा को अपनाया गया है तथा दूसरी और अंग्रेजी जैसी भाषा को अपना कर इनकी प्रोन्नति तथा विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है। इस उत्तरदायित्व को पूरा करने में, मूलभूत रूप से कई स्थायित्व संगठन और अधीनस्थ कार्यालय अर्थात् केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल (के०हि०शि०मं०), आगरा, अपने चार केन्द्रों सहित, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (रा०सं०सं०) नई दिल्ली अपने आठ विद्यापीठों सहित, केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान (के०भा०धा०सं०), मैसूर अपने चार क्षेत्रीय केन्द्रों और दो उर्दू प्रशिक्षण और अनुसंधान केन्द्रों सहित, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय (के०हि०नि०), नई दिल्ली, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग (वै०त०श०आ०) और उर्दू संवर्धन ब्यूरो (उ०सं०ब्यू०) विभाग की सहायता करते हैं। इसके अलावा भाषा संबंधित कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए गैर सरकारी एजेंसियाँ भी शामिल हैं। आन्तर्गत वर्ष के दौरान विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए इन गैर-सरकारी एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। विभाग ने अपना चल रही योजनाओं तथा कार्यक्रमों को जारी रखा है। वर्ष 1991-92 के दौरान भाषाओं की प्रोन्नति तथा विकास से संबंधित किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का निम्नलिखित है।

हिंदी की प्रोन्नति और विकास

12.2.1 हिंदी की प्रोन्नति, विकास तथा प्रचार प्रसार में लंग स्वेच्छिक संगठनों को प्रोत्साहित करने के केन्द्रीय सरकार प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही विनीत महायत्ना उपलब्ध करा रही है। कई वर्षों से, इस योजना के तहत विनीत सहायता प्राप्त करने वाले संगठनों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। सरकारों महायत्ना से, इन संगठनों में से कुछ संगठनों का इतना विकास हुआ कि अब वे प्रमुख संस्थान बन गए हैं जो एक राज्य की अपेक्षा अधिक राज्यों में एक साथ चल रहे हैं। हिंदी की प्रोन्नति तथा प्रचार प्रसार को दृष्टि से प्रकाशनों को प्रकाशित करने के वास्ते स्वेच्छिक संगठनों/सोसाइटियों, व्यामों और व्यक्तियों को भी वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। कुल मिलात अनुमान की 80 प्रतिशत की दर से सहायता प्रदान की जाती है।

केन्द्रीय हिंदी निदेशालय

12.2.2 निदेशालय तरह हिंदी और तरह क्षेत्रीय भाषाओं पर आधारित द्विभाषी कोशों का संकलन कर रहा है। अब तक तरह शब्द कोशों अर्थात् हिंदी-असमी, हिंदी-गुजराती, हिंदी-कश्मीरी, हिंदी-मराठी, हिन्दी-मलयालम, हिन्दी-उड़िया, हिन्दी-सिंधी, हिन्दी-तमिल, हिन्दी-तेलुगु हिन्दी-उर्दू, उड़िया-हिन्दी, और मलयालम-हिन्दी शब्द कोशों प्रकाशित किए हैं। निदेशालय से बारह त्रिभाषी शब्द कोश निकाले हैं जबकि बारह हिन्दी पर आधारित तथा बारह क्षेत्रीय भाषाओं पर आधारित त्रिभाषी शब्द कोश संकलित किए जा रहे हैं। निदेशालय ने "भारतीय भाषा कोश

परिचय" का संकलन करने के अलावा एक बहुभाषी शब्द कोश और तत्सम शब्दों का एक शब्द कोश भी प्रकाशित किया है। सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के अन्तर्गत चेक-हिन्दी और जर्मन-हिन्दी, (खण्ड 1 और 11) के शब्दकोश प्रकाशित किए गए संयुक्त राष्ट्र सघ भाषा शब्दकोश कार्यक्रम के अन्तर्गत, हिन्दी-चीनी, हिन्दी-अरबी, हिन्दी-फ्रेंच और हिन्दी-स्पेनी के शब्दकोश प्रकाशित किए गए। इनके अलावा, हिन्दी-कश्मीरी और हिन्दी-असमी की बोलचाल की गाइडें भी प्रकाशित की गईं। एक त्रिभाषी शब्द कोश बनाने का कार्य प्रगति पर है। हिन्दी और पड़ोसी देशों की भाषा के द्विभाषी शब्द कोशों की तैयारी को एक परियोजना शुरू की गई है। इनमें से दस ऐसे शब्द कोशों, हिन्दी-फारसी, हिन्दी-सिंधी और हिन्दी-हिन्दिरायाई भाषा पर कार्य चल रहा है।

12.2.3 निदेशालय हिन्दी पत्रिकाओं जैसे "यूनको दूत" (अंग्रेजी पत्रिका का हिन्दी रूपांतर शीर्षक "यूनेस्को कुरियर"), "भाषा" (तिमाही), "वार्षिकी" (एनुअली) और साहित्य माला (भारतीय भाषा और साहित्य पर पुस्तकें) भी निकाल रहा है।

12.2.4 निदेशालय अंग्रेजी, तमिल, मलयालम और बंगाली माध्यम से पत्राचार कार्यक्रमों के जरिए हिन्दी शिक्षण की योजना भी कार्यान्वित कर रहा है। चालू सत्र के दौरान इन कार्यक्रमों में लगभग 15,000 नामांकन होने की संभावना है। छात्रों के लिए अध्ययन के साधनों के तौर पर कुछ रिकार्ड और कैसटें भी तैयार किए गए। छात्रों की कठिनाइयों को दूर करने के वास्ते व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम आयोजित किए गए।

12.2.5 निदेशालय ने अहिन्दी भाषी राज्यों के छात्रों के लिए हिन्दी भाषा क्षेत्रों में अध्ययन के लिए अध्ययन-दौर आयोजित किए और अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के अनुसंधान अध्येताओं को यात्रा-अनुदान भी जारी किए गए। अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में भारतीय साहित्य के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए संगोष्ठियों का आयोजन करने के अलावा अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी के मूल लेखन को प्रोत्साहित करने के वास्ते नव हिन्दी लेखकों की कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। प्रत्येक वर्ष अहिन्दी भाषी हिन्दी लेखकों को पुस्कार दिए जाते हैं।

12.2.6 हिन्दी के प्रचार-प्रसार के वास्ते अहिन्दी भाषा राज्यों को कुछ पुस्तकें निःशुल्क भेजी गई हैं। हिन्दी पुस्तकों की प्रदर्शनी लगाना भी निदेशालय का एक अन्य कार्यक्रम है। निदेशालय बोलचाल की हिन्दी को राजभाषा बनाने के लिए एक सर्वेक्षण भी कर रहा है।

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग

12.2.7 हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली का विकास करने सभी विषयों में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकें तथा सदस्य साहित्य तैयार करने के लिए अक्टूबर, 1961 में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग (वै०त०श०आ०) की स्थापना की गई थी ताकि विश्वविद्यालयों के शिक्षण माध्यम को बदल कर सुविधाजनक बनाया जा सके।

12.2.8 कृषि, आर्थिकीय, और रक्षा शास्त्राचार्यों के दूसरे संस्करण पर मुद्रण कार्यबल रहा है।

शास्त्राचार्य

12.2.9 आयो 1 ने अब तक पाँच लाख से अधिक वैज्ञानिक और तकनीकी (परिभाषित) शास्त्र विभाजन करके अकाशित किए हैं। आयो 1 ने अंतरिक्ष विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, वायु विज्ञान और मुद्रण मशीनगोली से ची शास्त्राचार्य अकाशित की है। "संश्लेषित अकाशिक शास्त्राचार्य" (कंप्यूटर ऑफसेट पर आधारित) और विज्ञान-बोध शास्त्राचार्य ची अकाशित किए हैं। वर्ष के दौरान संवर्धित संसाधन/निष्ठाओं के प्रयोग के लिए 50,000 से अधिक पत्रिकाविक शास्त्रों को अतिरिक्त ऊपर दिया गया आयो 11, राज्य भाषा अकाशितगोली को क्षेत्रीय भाषाओं से शास्त्राचार्य निर्माण करने के लिए विविध संसाधन और तकनीकी सहायता दे रहा है।

परिभाषित शास्त्र कोष

12.2.10 वैज्ञानिक तथा तकनीकी शास्त्राचार्य आयो 1 ने अब तक अठनीस परिभाषित शास्त्र कोष निकाले हैं।

चीन ऐसे शास्त्रकोष मुद्रणधीन है और 10 तैयार किए जा रहे हैं। "सामाजिक विषय का व्यापक परिभाषित शास्त्रकोष" भी तैयार किया जा रहा है।

पत्र (पीएचएन) भारतीय परिभाषित शास्त्राचार्य

12.2.11 अपनी तक, निम्नली नेछठों अनुवादकों और प्रकाशकों का जीव निःशुल्क निवण का निर्णय 13 अतिरिक्त भारतीय शास्त्र समग्र अकाशित किए जा चुके हैं। सात अतिरिक्त भारतीय शास्त्र समग्र तैयार किए जा रहे हैं।

विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तक अध्यापन एवं निष्ठाधी पत्रिका

12.2.12 वैज्ञानिक एवं तकनीकी शास्त्राचार्य आयो 1 ने हिन्दी ग्रन्थ अकाशितगोली, राज्य, पाठ्य-पुस्तक बोर्ड एवं विश्वविद्यालय अकाशिक संस्करणों से हिन्दी एवं क्षेत्रीय भाषाओं से 9377 विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तकें अकाशित की हैं। आयो 1 ने इण्डोनेशिया, आर्जुतिरान एवं कतार के क्षेत्र से भी 362 पुस्तकें तैयार की हैं। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शास्त्राचार्य आयो 11, "विज्ञान, रिगम सिन्धु" नामक एक निम्नली पत्रिका भी अकाशित करता है।

शास्त्राचार्य प्रकाशितपुस्तिकाया कार्यशाला

12.2.13 आयो 1 द्वारा निकषित शास्त्राचार्य के संयुक्तित अंगों को संवर्धित एवं लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से, वैज्ञानिक एवं तकनीकी आयो 1 मौलिक विज्ञानों के निविधन विषयों से विश्वविद्यालय/काउनेज के शिक्षकों के लिए कार्यशालाएं आयोजित करता है। वर्ष के दौरान ऐसी 12-15 कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। अभी तक 227 से अधिक विश्वविद्यालय/काउनेज शिक्षकों ने शास्त्राचार्य प्रकाशितपुस्तिका करण प्रारंभ कर लिया है।

शास्त्राचार्य का संशोधकीकरण

12.2.14 आयो 1 संशोधन की प्रविधियायक करने, व्यापक विषय समग्र-वार और विषय-वार शास्त्र संशोधी को अद्यतन बनाने और उनका मुद्रण करने और कंप्यूटर आधारित पद्धति शास्त्राचार्य बैंक की सहायता करने के लिए डाटा बेस का प्रचन करने के उद्देश्य से वैज्ञानिक एवं तकनीकी शास्त्राचार्य आयो 1 ने इस परियोजना को 1989 से सुरु किया

था और इस परियोजना के अन्तर्गत अभी तक, 2.5 लाख तकनीकी शब्दों को डाटाबेस में प्रत जा चुका है।

क्षेत्रीय हिन्दी संस्करण (पीएचएनएस)

12.2.15 गैर हिन्दी भाषी राज्यों से हिन्दी शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य के अनुसरण में, क्षेत्रीय हिन्दी संस्करण (पीएचएनएस) निम्नकी मुख्यतया आधार में स्थित है, और जिसके केन्द्र दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, मैसूर और शिलांग में स्थित हैं। निम्नात एवं परगत अभाषण पाठ्यक्रम और जैसे कई मलयाली प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/कायम अयोजित करता रहा है। के अन्तर्गतिय इलाकों से हिन्दी शिक्षकों के लिए प्रसार कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। गैर हिन्दी भाषी क्षेत्रों से हिन्दी शिक्षकों के लिए संस्थान में पाठ्य पुस्तकों एवं शैक्षिक सामग्री को भी विकसित किया है।

12.2.16 विदेशियों को हिन्दी पढ़ाने के लिए "विदेशी से हिन्दी के प्रसार" नामक योजना के अन्तर्गत संस्थान द्वारा एक पूर्ण विकसित शैक्षिक पाठ्यक्रम बनवाया जा रहा है। बाह्य क्षेत्र के दौरान प्रसार संस्कार ने उनके राष्ट्री के 50 छात्रों को छात्रगुल से सम्मानित किया है।

12.2.17 संस्थान के रजत समारोह के अवसर पर "हिन्दी सेवी सम्मान योजना" नामक खीम की स्थापना की गई। इस योजना के अन्तर्गत अनेक वर्ष व्यक्तियों को हिन्दी के विकास एवं प्रसार-प्रसार, हिन्दी प्रकाशित, कृति साहित्य, वैज्ञानिक एवं तकनीकी हिन्दी साहित्य और के क्षेत्र से उनके विशिष्ट योगदान के लिए पुस्तकों से सम्मानित किया जाना है।

आर्थिक भारतीय भाषाओं (एनआईएन) का संवर्धन एवं विकास

क्षेत्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर (पीआईआईएनएस)

12.3.1 निम्नात सूत्र कायचित करने के लिए आधुनिक भारतीय भाषाओं से शिक्षकों को अकाशित करने के उद्देश्य से, क्षेत्रीय भारतीय भाषा संस्थान (पीआईआईएनएस) अनेक वार क्षेत्रीय भाषा क्षेत्रों एवं दो कई प्रशिक्षण अनुसंधान केन्द्रों से निविधन एवं सेवा साहित्य क्षेत्रों के कर्तव्य शिक्षकों के लिए पूर्ण शैक्षिक वर्ष का पाठ्यक्रम चला रहा है। लगभग 200 शिक्षकों ने आधुनिक आधार पर चलाना जा रहे निम्न और बंगाली के अन्तर्गत पाठ्यक्रमों में प्रान किया है।

भाषा-रक्षता की मान्यते के लिए भाषाओं से प्रचलित परीक्षण तैयार करने के उद्देश्य से संस्थान ने सात भाषाओं से परीक्षा नद तैयार की हैं। जबकि अन्य भाषाओं में परीक्षण तैयार करने का कार्य भविष्य पर है।

12.3.2 अन्तर्गतिय भाषाओं में कई पुस्तकें अकाशित करने के अतिरिक्त संस्थान ने कई अन्तर्गतिय एवं स्वीमा अन्तर्गतिय भाषाओं से व्याकरण, शास्त्राचार्य एवं अतिरिक्त भी तैयार की हैं।

12.3.3 आधुनिक भारतीय भाषाओंको संवर्धित एवं असाधित करने के उद्देश्य से, अकाशिक के लिए स्वीच्छक संसाधनों एवं व्यक्तियों को सहायता दी जा रही है। इसी अन्तर्गत, अनेक आधुनिक भारतीय भाषाओं के संवर्धन कार्यक्रमों में लगे व्यक्तिक संसाधनों को भी क्षेत्रीय संस्थाना प्राप्त हो रही है।

तत्को-ए-उर्दू बोर्ड/उर्दू संवर्धन ब्यूरो

12.3.4 1969 में गठित तत्को-ए-उर्दू बोर्ड, उर्दू भाषा के संवर्धन एवं विकास पर सरकार की सलाह-मशविषा देन वाली शीर्ष सस्था है। बोर्ड का अध्यक्ष मानव संसाधन विकास मंत्री होता है और संसद सदस्य, उर्दू विद्वान और परिषद सदस्य, इसके सलाहकार बोर्ड के सदस्य होते हैं।

12.3.5 उर्दू संवर्धन केन्द्र, बोर्ड की सिफारिशों को कार्यान्वित करता है, इसके सचिवालय के रूप में भी कार्य करता है। वर्ष के दौरान मुख्य कार्यकलाप निम्न प्रकार से रहे—

लगभग 30 पुस्तकों को प्रकाशित किए जाने की संभावना। नौ विषयों में तकनीकी शब्दों के शब्द-संग्रह प्रकाशित किए गए। 12 खण्डों के उर्दू-विश्वकोश और पांच खण्डों के अंग्रेजी उर्दू शब्द कोश के प्रकाशन का कार्य प्रगति पर।

अर्द्धवार्षिक अनुसंधान पत्रिका 'फिकर-ए-तहकीक' प्रकाशित की जा रही है।

दश भर के 38 मुलेखन-प्रशिक्षण केन्द्रों को विनोय महायता प्रदान की जा रही है। इनमें से मान केवल महिलाओं के लिए है।

नौ नए पुस्तक प्रदर्शनीया आयोजन की गई।

गृष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की पाठ्य पुस्तकों का उर्दू अनुवाद किया गया।

पुस्तकों की धार्मिक खरीद के साथ-साथ, उर्दू में पुस्तकों के प्रकाशन के लिए संगठनों एवं व्यक्तियों को विनोय महायता प्रदान की जा रही है। भाषा संवर्धन कार्यकलापों के लिए 14 मा-यात्रा प्राप्त संस्थाओं को वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई।

संदर्भ-सूची ग्रंथ के बयलीम हजार कार्ड तैयार किए गए।

उर्दू की प्रोन्नति के संबंध में गुजराल समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की जांच के लिए समिति:

12.3.6 सरकार ने उर्दू की प्रोन्नति के संबंध में गुजराल समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की जांच के लिए अला सरदार जाफरी की अध्यक्षता में फरवरी, 1990 में एक विशेष समिति का गठन किया। समिति ने 18 सितंबर, 1990 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। समिति की सिफारिशों संबंधित विभागों के परामर्श से तैयार की जा रही हैं।

सिंधी की प्रोन्नति

12.3.7 सिंधी परामर्शदात्री समिति वर्ष के दौरान कार्य करती रही और इस संबंध में उचित सलाह देती रही।

12.3.8 संसाधनों की कमी के कारण सिंधी विकास बोर्ड का गठन नहीं किया जा सका।

12.3.9 वर्ष के दौरान सिंधी के विकास के लिए कार्यक्रमों को घन उल्लेख करने की एक स्कीम जारी रही। इस स्कीम के तहत पुस्तकालयों और संगठनों को मुफ्त वितरण के लिए 90 पुस्तकें खरीदने का प्रस्ताव है, 5 लेखकों को उनके पुस्तकों के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाने हैं, स्वेच्छिक संगठनों/एजेंसियों की भाषा-प्रोन्नति गतिविधियों के

लिए सहायता दी जाएगी। 5000 तकनीकी शब्दों के समानार्थी शब्दों के तैयार हो जाने की आशा है।

अंग्रेजी भाषा शिक्षण में सुधार

12.4.0 देश में अंग्रेजी के पठन/पाठन के स्तरों में पर्याप्त सुधार लाने के लिए सरकार प्रत्येक राज्य में कम से कम एक जिला अंग्रेजी भाषा केन्द्र स्थापित करने के लिए केन्द्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान (सी-आई-ई-एफ-एल) के माध्यम से सहायता दे रही। अब तक छत्तीस केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं। सरकार केन्द्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान (सी-आई-ई-एफ-एल) के माध्यम से विभिन्न राज्यों के क्षेत्रीय अंग्रेजी संस्थान और अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थानों को भी सहायता दी जा रही है।

संस्कृत तथा अन्य श्रेणय भाषाओं की प्रोन्नति

12.5.1 भारतीय सांस्कृतिक विरासत का परिरक्षण संरक्षण, विकास और प्रचार और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में इसके महत्व को देखते हुए भारत सरकार के विकास कार्यों में हमेशा बल दिया गया है। इन लक्ष्यों का प्राप्ति करने और शिक्षा तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में संस्कृत भाषा की प्रोन्नति और विकास के लिए विविध प्रकार के कार्यक्रम तैयार और कार्यान्वित किए गए हैं। अरबी और फारसी भाषाओं के विकास के लिए भी कार्यक्रम कार्यान्वित किए गए हैं। आलोच्य अवधि के दौरान निम्नलिखित विकाससाधक कार्यक्रम कार्यान्वित किए गए।

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली

12.5.2 राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक स्थापन संगठन है जिसकी स्थापना संस्कृत के संरक्षण और प्रचार पाठुलिपियों के प्रकाशन और संरक्षण तथा प्रशिक्षण कार्यकलाप आयोजित करने संस्कृत शिक्षण और अनुसंधान के विकास के लिए 1970 में की गई थी। इसके छ. घटक केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ हैं जो इलाहाबाद, गुवापुर, बयपुर, जयपुर, लखनऊ और पुरी में स्थित हैं। इससे संबंधित इकायन निजी संस्थान भी हैं। जो परीक्षाएँ लेने का काम करते हैं।

12.5.3 संस्थान ने निम्नलिखित कार्यक्रम भी प्रारंभ किए हैं। (i) प्रख्यात वयोवृद्ध संस्कृत विद्वानों की सेवाओं का उपयोग, (ii) विशेष अधिष्ठायास पाठ्यक्रम (iii) संस्कृत पुस्तकों की खरीद (iv) संस्कृत साहित्य तैयार करना, (v) दक्कन कालेज, (vi) छात्र-वृत्तियां प्रदान करना, (vii) दुर्लभ पाठुलिपियों की खरीद और प्रकाशन (viii) संस्कृत अरबी और फारसी के विद्वानों को समानार्थी राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में प्रमाण-पत्र देना (केवल विद्वानों को ही भुगतान किया जाएगा)। पुरस्कारों के लिए चयन मंत्रालय में प्राथमिक चयन समिति द्वारा किया जाता है। पहले ये स्कीमें मंत्रालय में चलाई जाती थीं परंतु, अब इन्हें राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान को सौंप दिया गया है।

स्वेच्छिक संस्कृत संगठनों/आदर्श संस्कृत महाविद्यालयों/शोध संस्थानों को वित्तीय सहायता।

12.5.4 शिक्षकों के वेतन, छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों भवनों की मरम्मत फर्नीचर और पुस्तकालयों के लिए पुस्तकों आदि पर होने वाले आवर्ती और अनावर्ती खर्च को पूरा करने के लिए इस स्कीम के अंतर्गत पंजीकृत स्वेच्छिक संस्कृत संगठनों/संस्थाओं को अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। सस्वीकृत खर्च का पचहत्तर प्रतिशत सरकार देती

है जबकि 25% खर्च संगठन वहन करते हैं। जिन वैदिक संस्थाओं में भौखिक वैदिक परंपरा सुरक्षित रखी जा रही हैं उनके मामले में कुल संस्कृत व्यय का 95% सरकारी अनुदान के रूप में होता है। देश भर के लगभग छ सौ संस्कृत संगठन इस स्कीम के अंतर्गत लाभान्वित हुए।

12.5.5 कुछ ऐसे शैक्षिक संस्कृत संगठनों को आदर्श संस्कृत महाविद्यालय के रूप में मान्यता दी गई है जिनमें भाषा विकास और स्नातकोत्तर अध्ययन प्रारंभ करने की क्षमता हो। इनके कुल संस्कृत व्यय का 95% आवर्ती और 75% अनावर्ती व्यय की दर से वित्तीय सहायता दी जाती है। अब तक चौदह संस्कृत शिक्षण संस्थानों और दो स्नातकोत्तर शोध संस्थानों को इस स्कीम के अधिकार क्षेत्र में लाया गया है। इनमें से चार बिहार में (लामा, देवहार कोलहान्दा और हुलासगत), तीन उत्तर प्रदेश में (वृन्दावन, हरिद्वार और मैन्पुर) तीन तमिलनाडु में (दो मालापुर में एक काचीपुरम में) दो हरियाणा में (अम्बाला और भागोला) (पलवल), दो महाराष्ट्र में (बम्हाई और पूजा) एक केवल में (बालूसरी) और एक हिमाचल प्रदेश में (जागला रोहर) में स्थित हैं।

केन्द्रीय संस्कृत सलाहकार बोर्ड/समितियाँ

12.5.6 केन्द्रीय संस्कृत सलाहकार बोर्ड एक सलाहकार निकाय है, जो देश में संस्कृत के प्रचार प्रोन्नति और विकास से संबंधित नीतिगत मामलों में भारत सरकार को सलाह देती है। मार्च, 1989 को तीन वर्ष की अवधि के लिए इसका पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठित बोर्ड की तीन बैठकें क्रमशः 4 जुलाई, 1989, 15 सितंबर, 1989 और 1 सितंबर, 1990 को हुई हैं।

विश्वविद्यालयवत संस्थानें।

12.5.7 श्री लालबहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली और राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति को 1987 में विश्वविद्यालय वत संस्थानें घोषित किया गया। ताकि शास्त्रीय परंपराओं को सुरक्षित रखा जा सके, शास्त्रों की व्यवस्था प्रारंभ की जा सके, आधुनिक संदर्भ में इनकी प्रासंगिकता स्थापित की जा सके और शास्त्रीय ज्ञान को अद्यतन बनाया जा सके तथा इन विषयों में उत्कृष्टता प्राप्त की जा सके ताकि ये विद्यापीठ एक पृथक स्वरूप प्राप्त कर सकें।

इन विद्यापीठों ने शैक्षिक वर्ष 1991 से काम करना प्रारंभ कर दिया है।

राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के माध्यम से संस्कृत के विकास की स्कीम

12.5.8 यह केन्द्रीय योजना स्कीम है जिसको राज्य सरकारें चला रही हैं। निम्नलिखित पांच मुख्य कार्यक्रमों के लिए भारत सरकार द्वारा शत प्रतिशत आधार पर सहायता दी जा रही है।

(क) विपन्न स्थित में रह रहे सुविधायित संस्कृत विद्वानों को वित्तीय सहायता।

इस स्कीम के अंतर्गत 4000 रु० से कम वार्षिक आय वाले 1450 सुविधायित विद्वानों को प्रति वर्ष अधिकतम 4,000 रु० की वित्तीय सहायता दी जाती है वर्ष 1992-93 तक इस सूची में सत्तर विद्वानों के शामिल किए जाने की आशा है।

(ख) संस्कृत पाठशालाओं का आधुनिकीकरण

संस्कृत की परंपरागत और आधुनिक शिक्षा में समायोजना के लिए परंपरागत संस्कृत पाठशालाओं में चुनिंदा आधुनिक विषय पढ़ाने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति को सुकर बनाने के लिए अनुदान दिया जाता है।

(ग) हाई स्कूलों और माध्यमिक स्कूलों में संस्कृत पढ़ाने के लिए सुविधाएँ प्रदान करना।

जिन राज्यों की सरकारें संस्कृत पढ़ाने के लिए सुविधाएँ उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं हैं वहाँ माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में नियुक्त होने वाले संस्कृत अध्यापकों के वेतन पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए अनुदान दिया जाता है।

(घ) हाई स्कूलों और माध्यमिक स्कूलों में संस्कृत पढ़ाने वाले छात्रों को छात्रवृत्तियाँ

माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में संस्कृत पढ़ाने के लिए छात्रों को आकर्षित करने के लिए योग्यता छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं। कक्षा (ix) और (x) के लिए 25 रु० प्रतिमाह की दर से और कक्षा (xi) और (xii) के लिए 35 रु० प्रतिमाह की दर से कक्षा (ix) से (xii) तक के छात्रों को मामान्य छात्रवृत्तियाँ प्रदत्त की जा रही हैं।

इस स्कीम के अंतर्गत प्रति वर्ष लगभग 3000 छात्र लाभान्वित हो रहे हैं।

(ङ) संस्कृत की प्रोन्नति के लिए स्कीम चलाने के लिए राज्य सरकारों को अनुदान

राज्य सरकारें संस्कृत को विकास और प्रचार के लिए शिक्षकों के वेतन बढ़ाने, वैदिक विद्वानों सम्मान देने, विद्वत सभाएं आयोजित करने, संस्कृत शिक्षण के लिए सायकलीन कक्षाएँ लगाने, कालीदास समारोह मनाने आदि से संबंधित अपना कार्यक्रम बनाने और उनके कार्यान्वयन के सबध में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। इस स्कीम के अंतर्गत 1991-92 के दौरान तीन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सहायता देने का विचार है। वर्ष 1992-93 के दौरान और अधिक राज्यों को अनुदान के लिए इन कार्यक्रमों में शामिल करने की आशा है।

वैदिक अध्ययन की भौखिक परंपरा का संरक्षण/अखिल भारतीय वक्तुल कौशल प्रतियोगिता

12.5.9 (i) वैदिक अध्ययन की भौखिक परंपरा के संरक्षण के लिए विशेष प्रोत्साहन के रूप में वर्ष 1988 में एक स्कीम प्रारंभ की गई थी जिसके अंतर्गत प्रत्येक स्वाध्यायी से अपेक्षा की जाती है कि वह बारह वर्ष से कम आयु के दो छात्रों को वेद की किसी विशेष शाखा में प्रशिक्षित करेगा। वर्ष 1990-91 के दौरान ऐसी चौदह इकाईयों को सहायता दी गई। वर्ष 1991-92 के दौरान आठ और इकाईयों का चयन किया गया। इस स्कीम के अंतर्गत विद्वानों को 1250 रु० का मानदेय और दो छात्रों को 175 रु० प्रति माह वृत्तिका स्वरूप दिया जाता है।

(ii) परंपरागत संस्कृत पाठशालाओं में संस्कृत शिक्षण की विभिन्न शाखाओं में प्रतिभाशाली छात्रों में वक्तुल कौशल को प्रोत्साहित करने के लिए अखिल भारतीय वक्तुल कौशल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। सभी राज्यों से एक शिक्षक सहित आठ छात्रों का दल इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। गत वर्ष की प्रतियोगिता बम्बई में 26 से 28 दिसंबर, 1990 तक आयोजित की गई थी जिसमें 12

ज्यों की टीमें ने भाग लिया। इस वर्ष की प्रतियोगिता के फरवरी, 1992 में कभी आयोजित होने की आशा है।

7. राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान

12.5.10 राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान (आरव्वीव्वीय्यो) की स्थापना एक ज्ञात निकाय के रूप में अगस्त, 1987 में की गई थी। मौखिक वैदिक ग्रन्थ का परीक्षण, वैदिक ज्ञान की अंशु में शोध और आधुनिक वैज्ञानिक प्रौद्योगिकीय और सांस्कृतिक विकास में वैदिक ज्ञान की मानसिकता आदि को पता लगाना प्रतिष्ठान के कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं। अलोच्य वर्ष के दौरान राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रमों का प्रारम्भ किए गए:

- फरवरी, 1991 में एक अखिल भारतीय वैदिक सम्मेलन आयोजित किया गया।
- वर्ष के दौरान शिमला (हिमाचल प्रदेश), हैदराबाद, (आंध्र प्रदेश), मैसूर (उत्तर प्रदेश) और पुरी (ओडिसा) में चार क्षेत्रीय वैदिक सेमिनार आयोजित किए गए।
- सहित्य अकादमी के सहयोग से दिल्ली में वेद और ज्योतिष पर अखिल भारतीय सेमिनार आयोजित किया गया।
- बंगलौर में अभिनव विद्या भारतीय ट्रस्ट और अन्य के सहयोग से वैदिक गणित पर एक सम्मेलन कार्यशाळा का आयोजन किया गया।

- वृष्टि विज्ञान भांडल द्वारा मथुरा में वृष्टि विज्ञान पर सेमिनार आयोजित किया गया।
- अग्नि की प्रेष्य ऋग्वेद के मंत्रों को आडियो कैसेटों में ध्वनिकृत किया गया राष्ट्रीय संस्कृत विद्या पीठ, तिरुपति में उपलब्ध वैदिक भद्रोचारी की 762 टेपों को डब किया गया।
- श्री जगन्नाथ वेदालकार द्वारा लिखित प्रतिष्ठान का प्रथम प्रकाशन अर्थात् "ज्योतिषम् ज्योतिष" जारी किया गया।
- दिल्ली के युवा संस्कृत अध्यापकों के लिए वैदिक कक्षाएं आयोजित की गईं जिनमें कुछ छात्रों को प्राप्त विद्वानों ने भी वेदों से संबंधित विषयों पर व्याख्यान दिए।

8. अरबी और फारसी के प्रचार और विकास में लगे स्वीच्छक संगठनों को वित्तीय सहायता

12.5.11 इस योजना के अन्तर्गत अरबी और फारसी के संवर्धन के लिए कार्य कर रहे पञ्जीकृत स्वीच्छक संगठनों के शिक्षकों के वेतन, छात्रवृत्ति, फर्नीचर पुस्तकालय की पुस्तकों आदि तथा अरबी और फारसी के विकास के लिए चलाए जा रहे अन्य कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। स्वीकृत व्यय पर पचहत्तर प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध है। अलोच्य वर्ष के दौरान लगभग दो सौ अरबी और फारसी स्वीच्छक संस्थानों को वित्तीय सहायता दी गई।

3. ^ሰተተዋል ^ሰበገረጽ ^ሰመጥተዋል ^ሰየገረጹ

13. सीमावर्ती क्षेत्र विकास (शिक्षा) कार्यक्रम

13.1.1 सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम का उद्देश्य गुजरात, जम्मू और कश्मीर, पंजाब और राजस्थान राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों में शैक्षिक विकास करना है। इसमें पाकिस्तान से साथ लगने वाले 18 सीमाक्षेत्र और 79 ब्लॉक शामिल हैं। इस कार्यक्रम के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन को प्रथम वर्ष (सातवीं योजना के दूसरे वर्ष) अर्थात् 1986-87 के दौरान सचिवों की समिति द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार तीन सीमावर्ती राज्यों अर्थात् राजस्थान, गुजरात और पंजाब में इस कार्यक्रम को गृह मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया गया। वर्ष 1987-88 से इस कार्यक्रम को पुनः अनुस्थापित किए जाने के लिए इसके कार्यान्वयन का कार्य शिक्षा विभाग को हस्तान्तरित कर दिया गया ताकि सीमावर्ती क्षेत्रों में शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। इसका उद्देश्य यह था कि यह कार्यक्रम तत्काल शिक्षा पर ही अपना ध्यान केंद्रित करे क्योंकि शिक्षा ही सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास का महत्वपूर्ण साधन है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत समग्र मानव ससाधन विकास पर जोर दिया गया है। इस कार्यक्रम में किए गए प्रयास, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत शुरू किए जाने वाले कार्यक्रमों सहित राज्य शैक्षिक विकास कार्यक्रमों के प्रकट हैं।

13.1.2 शिक्षा सचिव की अध्यक्षता वाली, एक सस्वीकृत समिति जिम्मेदार योजना आयोग, राज्य सरकारों और संबद्ध मंत्रालयों के प्रतिनिधि होते हैं राज्य सरकारों के प्रस्तावों को शीघ्रता पूर्वक निपटारती रहती है। जो कि शिक्षा विभाग द्वारा तैयार की गई रूपरेखाओं के अनुसार कार्य करती है। समिति ने मार्च, 1991 में हुई अपनी बैठक में इन चार राज्यों में जहाँ सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है में सीमावर्ती ब्लॉकों के निकटवर्ती ब्लॉकों में इस योजना के विस्तार का निर्णय लिया।

13.1.3 1991-92 की वार्षिक योजना में 55 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जिसका उपयोग चालू कार्यक्रमलाभों और आंशिक रूप से कुछ नए कार्यक्रमलाभ शुरू करने संबंधी प्रतिबद्ध जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

13.1.4 राज्य सरकारों को अनुदान, उन्हें दिए गए पिछले अनुदानों में से उनके द्वारा किए गए व्यय की स्थिति और वास्तविक उपलब्धियों के आधार पर प्रदान किए जाते हैं।

13.1.5 वर्ष 1987-88 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत की गई उपलब्धियाँ सारणी-13.1 में दी गई हैं

तालिका 13.1

सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम

उपलब्धियाँ

(करोड़ रु० में)

	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92
कुल की गई राशि (करोड़ रु० में)	25.00	45.50	50.00	49.50	55.00 (अनुमानित) एनवीए पात्रता
दिए गए अनुदानों के गन्तव्य व्यय (करोड़ रु० में)					
गुजरात	3.56	5.20	8.57	3.18	6.00
राजस्थान	7.38	7.22	11.93	7.93	10.00
पंजाब	5.24	9.20	8.90	11.04	11.00
जम्मू और कश्मीर	8.82	23.88	20.58	27.33	28.00

13.1.6 अर्थात् तक निम्नलिखित के लिए सहायता प्रदान की गई

- स्कूलों में अनिवार्य सुविधाओं का प्रावधान (4858)
- प्राइमरी, उच्च प्राइमरी, मिडिल, उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के लिए भवनों का निर्माण (2699)

— सीनियर सैकेण्डरी स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को शुरू करना तथा व्यावसायिक शैक्षिकों का निर्माण (39)

— छात्रावास भवनों तथा स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण (178)

— जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना (1)

— विद्यमान स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाओं तथा प्रयोगशालाओं का निर्माण (5959)

— प्रौढ शिक्षा तथा गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्रों तथा जन-शिक्षण नितायनों का गठन (2130)

— पालिटेक्निकों तथा आई०टी०आई० की स्थापना तथा सुदृढ़ करना (36)

— जिमनाजियम हॉल तथा युवा प्रशिक्षण केन्द्रों का निर्माण (59)

4. ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁਝ ਹੋਰ

ਹੋਰ ਹੋਰ ਹੋਰ ਹੋਰ

ਹੋਰ ਹੋਰ

14. बीन सूत्रीय कार्यक्रम और वंचित वर्ग के लिए शिक्षा को सुलभ बनाना

14.1.0 बीस सूत्रीय कार्यक्रम 1986 के सूत्र संख्या 10 के अन्तर्गत औपचारिक तथा अनौपचारिक बुनियादी शिक्षा तथा ग्रीड शिक्षा से प्रगति को निरीक्षण पूर्व निश्चित नामांकन लक्ष्यों के संदर्भ में, भौतिक एवं वित्तीय राशियों के आधार पर किया जाता है। शिक्षा के विषय वस्तु की मूल्यवान् रिपोर्टें, अनौपचारिक तथा मूल्य सूचक शिक्षा के साथ वर्ष 1990-91 की बुनियादी एवं ग्रीड शिक्षा की भौतिक प्रगति रिपोर्टें कार्यक्रम कार्यान्वयन मानचित्र को प्रेरित करती हैं। वर्ष 1991-92 के लिए बुनियादी एवं ग्रीड शिक्षा के राज्य वार नामांकन लक्ष्य निर्धारित किए गए। अग्रेज से सितम्बर, 1991 की अवधि में आर्द्धवार्षिक वित्तीय तथा भौतिक प्रगति रिपोर्टें कार्यान्वयन मानचित्र की चेक की गई थी।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की शिक्षा

14.2.1 वर्ष 1990-91 डा० बी०आर० अम्बेडकर का शताब्दी वर्ष था। शताब्दी समारोह के लिए तत्काल प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में स्थापित राष्ट्रीय समिति ने यह निर्णय किया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए कार्यक्रम, एक और वर्ष अर्थात् 1991-92 से भी जारी रहेगा। शिक्षा विभाग ने अपने अधीन संगठनों को ये निर्देश जारी किए हैं कि ये जन्म शताब्दी समारोह शानदार ढंग से मनावे के लिए कार्यक्रम और कार्यक्रमालय शुरू करें और यह कार्यक्रमालय चालू वर्ष से भी जारी रखें। इन कार्यक्रमों में सामूहिक विचार-विमर्श, गतिविधियाँ, निबंध प्रतियोगिताएँ, डा० अम्बेडकर की जीवनी और उनकी कृतियों के संग्रह का प्रकाशन इत्यादि शामिल हैं। उच्च शिक्षा संस्थाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के दाखिले का सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण समितियों स्थापित की गई थीं। डा० बी०आर० अम्बेडकर शताब्दी समारोह के संबंध में गठित राष्ट्रीय समिति की उपसमितियों में शिक्षा विभाग भी प्रतिनिधि था।

14.2.3 मानव संसाधन विकास मंत्री ने 30 अगस्त, 1991 को अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित संसद सदस्यों की एक बैठक आयोजित की और उसमें अनुसूचित जनजाति की शिक्षा तथा साक्षरता से सम्बन्धित मामलों पर विचार विमर्श किया। संसद सदस्यों ने जनजातियों की शिक्षा से सम्बन्धित अनेक पहलुओं पर अपने विचार व्यक्त किए। ये विचार कार्यान्वयन के लिए सभी संबंधित एजेंसियों को भूचित कर दिए गए हैं।

14.2.4 अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को शिक्षित करने की और ध्यान देकर समस्यानाओं को दूर करने तथा शैक्षिक अवसरों में बराबरी लाने पर जोर दिया। आपेक्षित ब्लैक बोर्ड, अनौपचारिक शिक्षा और ग्रीड शिक्षा आदि की योजनाओं के अन्तर्गत राज्य को यह सलाह दी गयी थी कि वे उन खण्डों के चयन को उच्च प्राथमिकता प्रदान करें जहाँ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के लोग बहुसंख्यक हैं। शैक्षिक वर्ष 1991-92 के दौरान 275 नवीकृत विद्यालयों में कक्षा VI से 18,600 छात्रों के कुल दाखिले से से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति की संख्या उनकी जनसंख्या प्रतिशतता क्रमशः 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत के मुकाबले क्रमशः 19 प्रतिशत और 11 प्रतिशत थी।

14.2.5 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति के छात्रों के योग्यता स्तर को ऊँचा उठाने की योजना, जो 1987-88 से शुरू की गई थी, राष्ट्रीय/स्थल शासित प्रदेशों द्वारा कार्यान्वित की जाती रही। इस योजना के अन्तर्गत, उपचारी प्रशिक्षण कक्षा IX से XII तक दिया जाता है, इसके अलावा उनकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने के लिए कक्षा XI और XII में विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है।

14.2.6 अन्य सुविधाएँ जैसे शिक्षा संस्थाओं में स्थानों का आराक्षण (अनुसूचित जाति के लिए 15% अनुसूचित जाति के लिए 7.1/2%) प्रदेश प्रशासकों से आर्द्धक अर्धक प्राप्त करने से छूट मौद्रिक पूर्व छात्रवृत्तियों से आराक्षण, केन्द्रीय विद्यालयों में नि:शुल्क शिक्षा, विश्वविद्यालय स्तरीय अनुसंधान शिक्षावृत्तियों अनुसंधान पर्सोनाल्टिशप, शिक्षावृत्ति इत्यादि में आराक्षण दिया जाता रहा।

14.2.7 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान एक ऐसी योजना संचालित कर रहा है जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जाति के जो छात्र संयुक्त प्रवेश परीक्षाओं में बहुत छोटे अंकों की कमी के कारण सफल नहीं हो पाते हैं उन्हें और आगे प्रशिक्षण दिया जाता है तथा संगत पाठ्यक्रम में दाखिला दिया जाता है।

14.2.8 आठवीं पंचवर्षीय योजना और वार्षिक योजना 1992-93 के लिए शिक्षा विभाग की अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना और अनुसूचित जाति के लिए जनजातीय उप-योजना तैयार की गयी। आठवीं योजना की विशेष घटक योजना तथा जनजातीय उप-योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित परिलब्ध शिक्षा विभाग के विभाज्य परिलब्ध का क्रमशः 13.29% तथा 9.72% है।

अल्पसंख्यकों की शिक्षा

14.3.1 शिक्षा विभाग ने 23 जुलाई, 1990 को अल्पसंख्यकों की शिक्षा पर एक दल का गठन किया। इसके विचारार्थ विषय थे :-

(क) केन्द्र तथा राज्य के विविध भूभागों/विभागों, सोसाइटीय तथा संगठनों द्वारा अल्पसंख्यकों की शिक्षा के संवर्धन में की गई शिक्षारिशी तथा सुझावों को समीक्षा करना।

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा निम्न भविष्य में किए जाने वाले कुछ उपायों पर शिक्षारिशी करना।

14.3.2 इस दल ने 15 जनवरी, 1991 को सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। मार्च, 91 में एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जा अल्पसंख्यक शिक्षा दल की शिक्षारिशी पर निर्णय/विचार प्रकट करना। अधिकार प्राप्त समिति ने अपनी रिपोर्ट सितम्बर, 1991 में प्रस्तुत कर दी।

प्रशिक्षण कक्षाएं

14.3.3 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक छात्रों के प्रशिक्षण के लिए विश्वविद्यालयों और कालेजों को सहायता प्रदान करने की योजना का कार्यान्वयन जारी रखा। छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। यह योजना 20 विश्वविद्यालयों और 33 कालेजों में कार्यान्वित की जा रही है। अल्पसंख्यक समुदायों के लिए शिक्षण कक्षाओं के संबंध में वि० अ० आ० उप समिति ने प्रगति की समीक्षा करने और निरीक्षण करने के लिए एक छोटी समिति का गठन किया।

पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा

14.3.4 स्कूल पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा अन्य बातों के साथ साथ अस्पृश्यता, जातिवाद और सम्प्रदायवाद हटाने के विचार से की जा रही है। मूल्यमंक कार्यक्रम अब एक राष्ट्रीय स्तर की संचालित समिति द्वारा देखा जाता है।

सामुदायिक पोलिटेक्निक

14.3.5 कार्वाइ योजना के अंतर्गत निर्धारित सभी 41 अल्पसंख्यक संकेन्द्रित जिलों को सामुदायिक पोलिटेक्निकों अथवा उनके विस्तार केन्द्रों में शामिल किया गया है।

महिलाओं की शिक्षा

14.4.1 जैसा कि रिपोर्ट में अन्य दर्शाया गया है, 1990-91 में कुल नामांकन के अनुपात में लड़कियों का नामांकन प्राथमिक स्तर पर 41.4%, मिडिल स्तर पर 37.4%, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 33% तथा उच्च शिक्षा स्तर पर 33.3% है।

14.4.2 शिक्षा में महिलाओं/लड़कियों की भागीदारी में सुधार के लिए वर्ष के दौरान सभी ओर से प्रयत्न किए गए। विशिष्ट उपायों के ब्यौरे भी दिये गये हैं:

— आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत भारत सरकार 1987-88 से प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों के 93303 पदों सृजन करने के लिए सहायता प्रदान की जो कि मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा ही भरे जाने हैं। अद्यतन रिपोर्टों के अनुसार शिक्षकों के 69926 पद भरे जा चुके हैं जिसमें 57.39% महिला शिक्षक हैं।

— लड़कियों के लिए बने एन०एफ०ई० केन्द्रों को 90% सहायता दी थी। लड़कियों के एन०एफ०ई० केन्द्रों की संचित संख्या 81282 है।

— महिला समस्या (महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा परियोजना गुजरात, कर्नाटक तथा उत्तर प्रदेश राज्यों कार्यान्वयनाधीन है जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना तथा उन्हें अनौपचारिक, प्रौद्योगिक शिक्षा प्रदान करना है।

— सतर्क कार्यवाही द्वारा, नवोदय विद्यालयों में लड़कियों प्रवेश सुनिश्चित है। (कुल 78149 छात्रों में से इनमें लड़कियों की संख्या 22 222 है।)

— प्रौढ शिक्षा केन्द्रों में महिलाओं के दाखिले पर विशेष ध्यान दिया गया था। श्रमयोग्य कार्यात्मक माहिरता कार्यक्रम दाखिले किए गए 16 77 लाख प्रौढ निवासियों में महिलाएं थीं (54.50%)।

5. ગઢ, અડધું અને અડધું

15. अर्थ, अनुवीक्षण एवं मूल्यंकन

राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति को संघ ने 1986 में स्वीकृत प्रदान की तथा उसके बाद उसका कार्यान्वयन शुरू हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की परीक्षण के अनुसार, केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की नीति संबंधी एक समिति आकाश प्रवेश के मुख्यमंत्री, श्री एच. जगदीश रेड्डी की अध्यक्षता में स्थापित की गई। समिति ने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लागू होने के बाद हुई दो नए प्रतिनिधियों को भी ध्यान में रखते की अवस्था की गई थी शिक्षा नीति तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति समीक्षा समिति की रिपोर्ट से संबंध था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 22 जनवरी, 1992 को अस्तुत की। रिपोर्ट पर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा विचार किया जाना है। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों प्राप्त होने पर ही सरकार नीति में संशोधन करते संबंधी अपने निष्कर्षों को अंतिम रूप देगी।

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (सीएससीबी)

15.2.1 राज्य शिक्षा मंत्रियों, महासचिवों, शिक्षाविदों से युक्त केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड शिक्षा के क्षेत्र की भूमिकाओं की समीक्षा, कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के विश्लेषण और नीति-निर्धारण संबंधी सलाह देने के माध्यम से शिक्षा नीति के प्रबंध के लिए आवश्यक साधन उपलब्ध करवाने वाला, राष्ट्रीय स्तर का निकाय बना रहा।

15.2.2 केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का 19 अक्टूबर, 1990 को तीन वर्ष की अवधि के लिए पुनर्गठन किया गया। इस पुनर्गठित बोर्ड की पहली बैठक 8 और 9 मार्च, 1991 को हुई दिल्ली में हुई। इस बैठक में प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और विश्वविद्यालय वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदि के लिए शिक्षा के क्षेत्र के विभिन्न महत्वपूर्ण नीति विषयों पर विचार-विमर्श किया गया।

15.2.3 केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई की गई है।

राष्ट्रीय शैक्षिक आयोगों और भ्रमण संस्थान

15.3.1 भारत सरकार द्वारा स्थापित संस्थान के रूप में स्थापित राष्ट्रीय शैक्षिक आयोगों और भ्रमण संस्थान ने निर्धारित कार्यक्रमों को जारी रखा:-

- वरिष्ठ शैक्षिक भ्रमणों का प्रशिक्षण और स्थिति निर्धारण।
- शैक्षिक आयोगों और भ्रमण संस्थान की समस्याओं पर अनुसंधान (18 अनुसंधान अध्ययन चल रहे हैं)।
- एजेंटों और अन्य संगठनों के लिए विस्तार और परामर्श सेवाएं।
- शैक्षिक आयोगों और भ्रमण संस्थान से सम्बद्ध विषयों पर रोजिनास, कार्यशालाएं और सम्मेलन। (1991-92 के दौरान केवल प्रशिक्षण कार्यक्रम/रोजिनास/कार्यशालाएं आयोजित किए जाने निर्धारित हैं।)

-- अन्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, यूनेस्को, यूएनडीपी, आई-आईसीपी, एडमपडल सचिवालय इत्यादि को प्रशिक्षण तथा अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करना।

-- शिक्षा प्रबंध पर संस्थाओं को तकनीकी सहायता प्रदान।

15.3.2 संस्थान ने निर्धारित भ्रमण निकाले।

-- महिला तथा बालिका

-- यूनेस्को-यूएनडीपी अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शैक्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम पर रिपोर्ट।

-- शैक्षिक आयोगों तथा भ्रमण संस्थान की प्रवृत्ति।

-- "शैक्षिक आयोगों तथा भ्रमण संस्थानों के लिए पर्यावरण शिक्षा में अतिरिक्त भारतीय रोडमार्क" पर रिपोर्ट।

-- सभी के लिए शिक्षा-एक अधिक अर्थपूर्ण।

15.3.3 सरकार द्वारा 1989 में गठित की गई एक समिति द्वारा संस्थान के कार्य में तथा भूमि की समीक्षा की गई। समीक्षा-समिति की रिपोर्ट पर भ्रमण द्वारा जुलाई, 1990 में गठित एक अधिकार प्राप्त समिति द्वारा जांच की गई। समीक्षा-समिति की रिपोर्ट पर अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों का सरकार द्वारा अनुमोदन कर दिया गया और उन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है।

15.3.4 अधिकार प्राप्त समिति की कुछ प्रमुख सिफारिशों निर्धारित हैं -

- नीचा को शैक्षिक आयोगों तथा भ्रमण संस्थान के एक अलग केन्द्र के रूप में विकसित किया जाना चाहिये।
- नीचा को विद्या स्तर पर कार्यकर्ताओं अथवा कालेजों के प्रिंसिपलों तथा अन्यो के प्रशिक्षण की जिम्मेदारी। वरिष्ठ-स्तर राज्य स्तर की इकाइयों को स्थानांतरित की जानी चाहिये।
- नीचा को अपने कार्यक्रमों तथा प्रक्रियाओं को बड़ा गुना चाहिए, जहां उसकी संभावना है, जहां उसके कार्यक्रमों की जरूरत है और जहां इसके भ्रमण बनाने का कार्यक्षेत्र है। यह प्रशिक्षण आवश्यकताओं के संबंध में पर आधारित होना चाहिये।
- कार्योन्मुख अनुसंधान तथा अनुसंधान अन्य रूपों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक आयोगों और भ्रमण संस्थान राज्य स्तरीय आयोगों और भ्रमण संस्थानों, उपयुक्त विश्वविद्यालयों विभागों और प्रबंध एवं सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थानों के साथ नेटवर्क व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु स्थापना करें।

-- राष्ट्रीय शैक्षिक आयोगों व भ्रमण संस्थान (एनईपीएल) के प्रमुख कार्य में से, राज्यो व संघशासित राज्यो में ऐसी संस्थाओं

के विकास को प्रोत्साहित करना एवं उनको सहयोग देना होगा जो शैक्षिक अभियाना व प्रशासन के कार्यों के लिए जिम्मेदार होंगे।

- विभिन्न राज्यों के अपना खुद के प्रशासनिक अनुक्रम, प्रबंध प्रणालियाँ, प्रतीकों की पद्धति और पद्धतियाँ व नियम होते हैं। एन-आई-सी-पी-ए, ऐसे ढाँचों और प्रणालियों को पहचानने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन एवं कार्य अनुसंधान कार्यक्रम संचालित कर सकती है, जो प्रभावी, लागत-प्रभावी सुमार्हय हों।
- पूरे निकाय एवं शोध-स्टाफ के लिए निम्नानुसंधान-मूल्यांकन की प्रणाली होनी चाहिए। मूल्यांकन, अधिकारातः विकास-पुष्ट होना चाहिए।

शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए अध्ययन, संगोष्ठियों, आदि के लिए सहायता योजना:

15.4.1 शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए अध्ययन, संगोष्ठियों, मूल्यांकन आदि की योजना का उद्देश्य, शिक्षा-विकास कार्यक्रमों की तैयारी का कार्यान्वयन एवं मूल्यांकन से संबंधित समस्याओं को हल करना है।

15.4.2 योजना का उद्देश्य, संगोष्ठियों/कार्यशालाओं, प्रभाव एवं मूल्यांकन अध्ययनों आदि के आयोजन के लिए प्रत्येक प्रस्ताव के गुण-दोष के आधार पर योग्य संस्थाओं एवं व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ऐसे कार्यक्रमों की शिक्षा-नीति, इसके कार्यान्वयन एवं संबंधित समस्याओं से संबद्ध किया जाना होगा।

15.4.3 वर्ष 1991-92 के दौरान, एक सम्मेलन, एक प्रशिक्षण कार्यक्रम, चार मूल्यांकन अध्ययनों के आयोजन एवं एक पत्रिका को प्रकाशित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गयी।

विभाग के लिए कम्प्यूटरीकृत प्रबंध सूचना प्रणाली (सी-एम्-आई-एस) का विकास:

15.5.1 कम्प्यूटरीकृत प्रबंध सूचना प्रणाली की गति में वृद्धि लाने और विभाग के अंदर ही विशेषज्ञता उत्पन्न करने के उद्देश्य से, आयोजना, अनुवीक्षण एवं सांख्यिकी डिजीन के अंतर्गत, एक सी-एम्-आई-एस-एकक की स्थापना सितम्बर, 1985 में की गयी। इसके अस्तित्व में आने के समय से ही, यह एकक, एन-आई-सी-पी के सहयोग से इस मंत्रालय में कम्प्यूटरीकृत प्रबंध सूचना प्रणाली को विकसित करने में लगा रहा है। एन-आई-सी-पी ने डी-सी-एम्-कॉन्सो 486 प्रणाली के चार टर्मिनलों की स्थापना की है। आठवीं पंच वर्षीय योजना में, प्रत्येक प्रभाग में कम्प्यूटर की सुविधाएं प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इस प्रयोजन के लिए, विभिन्न प्रभागों में स्वतंत्र प्रणाली, 20 डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और पी-सी-के के साथ 30 कम्प्यूटर टर्मिनलों को स्थापित करने का प्रस्ताव है।

15.5.2 इस समय, इस एकक के पास दो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटरों वाले दो पर्सनल कम्प्यूटर पी-सी/एस-टी-0 और पी-सी/ए-टी-0 हैं और 600 एल-पी-एम्-की गति वाला एक लाईन प्रिंटर है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में, पी-सी/ए-टी-0 को चार और टर्मिनलों द्वारा संबंधित करने और एकक के लिए अतिरिक्त पी-सी-0 और लेजर प्रिंटर को स्थापित करने का प्रस्ताव है। एकक को मजबूत बनाने में, निम्न पध्तिथ में प्रणाली-विश्लेषक कम्प्यूटर ऑपरेटर्स/आंकड़ा प्रक्रम सहायकों आदि के नए पदों का सृजन शामिल है।

15.5.3 वर्ष 1991-92 के दौरान, सी-एम्-आई-एस-एकक ने कम्प्यूटरीकरण के लिए निर्धारित परियोजनाएँ शुरू की हैं—

प्रशासन

- आंतरिक सम्मेलन के उद्देश्य से, नाम, पद, प्रभाग, अनुप्रभाग, कार्यप्रणाली-विधि आदि जैसे बुनियादी क्षेत्रों में शिक्षा-विभाग के समूह "ख" व समूह "ग" के अधिकारियों से संबंधित डाटाबेस का सृजन।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय में स्टाफ पोशिशन पर निगरान रखने के लिए तैयार किए गए डाटाबेस व रीफ्रेक्टवेअर।
- शिक्षा विभाग की वेतन-बिल प्रणाली।
- शिक्षा विभाग के समूह "क" के कर्मचारियों के सामान्य पध्तिथ निधि खाते का अनुवीक्षण प्रारंभ कर दिया गया है।
- सातवां पंचवर्षीय योजना का विवरण।

सांख्यिकी

- प्रकाशन—एजुकेशन इन इंडिया खण्ड-I (5) 1987-88
- वर्ष 1984-85 के लिए "एजुकेशन इन इंडिया" खंड III : प्रकाशन के लिए सस्याओं के आय-व्यय संबंधी विवरण: आकड़े/खण्ड II (ग) की सारणियों का मसौदा तैयार किए गया।
- एजुकेशन इन इंडिया-खण्ड-III-परीक्षा परिणाम, 1984-85 अं 1985-86
- बुनियादी शैक्षिक सांख्यिकी, 1989-90 और 1990-91 के लिए डाटाबेस और उत्पादित सारणियों का सृजन।
- इंडिया स्टूडेंट गोइंग आर्बर्ड-1987-88 प्रारंभ कर दिया गया
- इंडियन ट्रेनिंग गोइंग आर्बर्ड-1987-88 प्रारंभ कर दिया है
- भारत में स्त्रुली शिक्षा पर बुनियादी सूचना का प्रकाशन प्रारंभ कर दिया गया है।
- "ए" हैडबुक ऑफ एजुकेशनल एण्ड एलाइ स्टेटिस्टिक्स-1991" नामक प्रकाशन के लिए विकसित डाटाबेस और उत्पादित सारणियाँ।

आयोजना

- शिक्षा विभाग की बुनियादी योजनाओं पर वर्ष 1990-91 के लिए वार्षिक कार्य-योजना।
- शिक्षा के बजट-व्यय पर राज्य की रूपरेखा।
- समस्त राज्यों की जिला रूपरेखा तैयार करना।
- जिलेवार शैक्षिक रूपरेखा-1981 तैयार करना।

पुस्तक संदर्भ

- पञ्चम मोहन राय राष्ट्रीय एकक के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संरचनात्मक (आईएसबीएन) प्रणाली का निर्माण।
- प्रकाशनालय धुबन प्रणाली के लिए आंकड़ा प्रविष्टि साफ्टवेयर विकसित किया गया।
- अनु० अति/अनु० जब अति एकक
 - वर्ष 1983-84 और 1984-85 (एस्० और सी०) के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के शिक्षा-विकासी पर अधिक आधारी समीची।
 - 15.5.4 कंप्यूटर के प्रति जागरूकता लाने तथा कंप्यूटर संचालन और साफ्टवेयर अनुभवों से युक्तिवादी विशेषज्ञता सुलभ करने के लिए इस एकक ने उपयोगकर्ताओं को समय-समय पर बुविभाए प्रदान की है।
 - राष्ट्रीय धुबन केन्द्र द्वारा शिक्षा विभाग के लिए अंश धुबन प्रणाली परियोजना का विकास
 - राष्ट्रीय धुबन केन्द्र ने इस विभाग को कंप्यूटर आधारित प्रत्यक्ष धुबन प्रणाली के विकास में साफ्टवेयर तथा हार्डवेयर की सहायता प्रदान करना जारी रखा। वर्ष 1991-92 के दौरान इसकी मुख्य विशेषताएँ निम्नानुसार हैं
 1. सीसीएसएम सीओएसएसओएस 80486 प्रणाली प्रतिष्ठित की गई और 32 टर्मिनल प्रतिष्ठित करने के लिए विभिन्न कक्षों में केबल बिछाई गई।
 2. राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की पूर्ण साक्षरता परियोजना संबंधी रिपोर्टों का अनुवीक्षण करने के लिए प्रयत्न तैयार किए गए। राष्ट्रीय धुबन केन्द्र नेटवर्क के जरिए आंकड़े प्रोसेस करते, रिपोर्ट तैयार करते तथा उन्हें सेवने के लिए साफ्टवेयर को विकसित किया गया। उपयोगकर्ता संदर्भ मैनुअल और साफ्टवेयर प्रचालन मैनुअल भी निकाले गए।
 3. ग्रीड शिक्षा से संबंधित सैलैन्स एजेंसियों के लिए सहायता अनुदान धुबन प्रणाली के बारे में उपयोगकर्ता सटर्न मैनुअल प्रकाशित किया गया।
 4. दैनिक अवर्तनों को डायरी करने की प्रणाली का अध्ययन किया गया और दैनिक आगंतिकों को डायरी करने तथा अनुवीक्षण के तरेम से विभिन्न रिपोर्ट तैयार करने और उन्हें ग्रीड शिक्षा ब्यूरो में किमन्वित करने हेतु साफ्टवेयर विकसित किया गया।
 5. अनैपिचरिफिक शिक्षा के संबंध में सैलैन्स एजेंसियों को सहायता अनुदान देने का अध्ययन किया गया और आंकड़ा संबंधी डाँचा विकसित किया गया। आंकड़ा प्रविष्टि और आंकड़ा परिचालन अनेक रिपोर्टों तथा रोजमर्रा के पत्रों जैसे विभागित पत्र, संस्कीर्णित पत्र, विलर, उपवीणिता प्रमाण-पत्र, अनुसूचक आदि के लिए साफ्टवेयर का विकास किया गया।
 6. व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में दो रायों के इकट्ठे किए हुए आंकड़ों को डेटा-बेस फाइलों में अंकित किया गया। आंकड़ों को तैयार बनाने और रिपोर्ट तैयार करने के लिए साफ्टवेयर विकसित किया गया। आंकड़ों को तैयार बनाया गया और रिपोर्ट तैयार की गई। संरचनागत स्तर पर आंकड़े प्राप्त करने के लिए प्रयत्न तैयार कर लिए गए हैं और साफ्टवेयर विकास कार्य शुरू कर दिया गया है।

7. सैलैन्स संरचना/उत्तरती और फरती संस्थाओं को वितीय सहायता की योजना को कंप्यूटीकृत करने के लिए साफ्टवेयर विकसित किया गया।
8. अन्तर्राष्ट्रीय अरजेलाओं की अनुसंधान परियोजनाओं के लिए विभिन्न परिपटी को विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा प्रमाण द्वारा दी जा रही वितीय सहायता की योजना का अध्ययन किया गया और आंकड़े भरने तथा धुबन पत्रों और संस्कीर्णित पत्रों को तैयार करने के लिए साफ्टवेयर विकसित किया गया।
9. सैलैन्स आंकड़ों के सुधार के लिए कंप्यूटीकरण संबंधी केन्द्रीय योजनागत स्कीम को नौ एज्यों में किमन्वित किया गया। इस परियोजना के साफ्टवेयर को राष्ट्रीय धुबन केन्द्र के केन्द्रीय केन्द्र, हैदराबाद में विकसित किया गया और इसके आंकड़े राष्ट्रीय धुबन केन्द्र के राज्य केन्द्र में प्रोसेस किये जा रहे हैं। यह स्कीम अन्य राज्यों में भी लागू की जा रही है।
10. अविशेष प्रत्यक्ष धुबन प्रणाली विकसित की गई है जिससे यह पता लगाया सभव हो जाता है कि वर्ष के दौरान अनुभवों में कितनी फाइले खोती गई कितनी फाइले रिफाई की गई कितनी फाइले रिफाई कम से हैं कितनी फाइले गड की गई और कितनी फाइले की माइक्रो फिल्टे बनावी गई।
11. शिक्षा विभाग से सम्बन्धित अनेक संकेत राब्डों की पहचान की गई और संस्पष्ट प्रश्न धुबन प्रणाली किमन्वित की गई।
12. बी. आई. पी. संदर्भ धुबन प्रणाली, फाईन संचालन धुबन।
13. केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में काम्यूटीकरण के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए एक साफ्टवेयर-अध्ययन किया गया तथा साधता-अध्ययन की रिपोर्ट प्रकाशित की गई।
14. वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग को तकनीकी शब्दों की अंग्रेजी-हिन्दी शब्दावली तैयार करने के लिए परामर्श एवं सहायता सेवाएँ प्रदान की गई।
15. अंगिक विद्यापीठों से आकट्टे इकट्ठे करने के लिए निवेश-प्रयत्न (रनपुट प्रोफार्म) तैयार किये गये।
16. पब्लिश जवाहर लाल नेहरू के जन्म दिवस समारोह के एक भाग के रूप में "भारत के नए युवक" विषय पर विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित करने के संबंध में तीन मुक्ति धवल से एन आई सी स्टाल में एक भारगणित टर्मिनल लगाया गया।
17. स्कूल तथा समकक्ष साफ्टवेयर तथा जैनिक एव इसके सम्बन्ध साफ्टवेयर पर रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आरम्भ किया गया तथा काम्यूटर के प्रयोग में कई अधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया गया।
18. वार्षिक रिपोर्ट तथा अन्य विभिन्न अध्ययनों के सम्बन्ध में समय-समय पर प्रस्तुतीकरण चार्ट एवं ग्राफ तैयार किए।
19. वार्षिक रिपोर्ट आठवीं पंचवर्षीय योजना, वार्षिक योजना दस्तावेज, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का समीक्षा-समिति की रिपोर्ट, जैसे दस्तावेज तैयार करने के लिए काम्यूटर के आयुधनिकीकरण तथा प्रयोग के एक भाग के रूप में कम्प्यूटल स्वरचलन प्रक्रियाएँ एवं तकनीके विकसित की गई।

20. निम्न को साफ्टवेयर अनुरक्षण सहायता प्रदान की गई—

- (क) प्रौढ शिक्षा ब्यूरो की स्वेच्छक एजेंसियों को अनुदान।
- (ख) प्रौढ शिक्षा निदेशालय को पोस्ट बाक्स संख्या 9999
- (ग) विसंगत पत्रों, प्रतिलिप्याधिकार रजिस्टर तथा सूचक-पत्र तैयार करने के लिए प्रतिलिप्याधिकार कार्यालय।
- (घ) साप्ताहिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए संसदीय आवासन।
- (ङ) विश्वविद्यालय पार्श्व—सूचना पद्धति।
- (च) अनौपचारिक शिक्षा आंकड़े।

आजर्बी पंचवर्षीय योजना (1992-97) और वार्षिक योजना (1992-93) को तैयार करना

15.6.1 शिक्षा विभाग के आठवें पंचवर्षीय योजना प्रस्तावों तथा वार्षिक योजना प्रस्तावों को, योजना आयोग के मार्गदर्शी पत्र में उल्लिखित प्राथमिकताओं तथा विशेष मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, तैयार किया गया है। शिक्षा विभाग के प्रस्तावों पर 10 दिसम्बर, 1991 को योजना आयोग के सचिव की बैठक में विचार किया जाएगा।

महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा

15.6.2 मानव संसाधन विकास मंत्रों ने 15 मुख्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों/शिक्षा मंत्रियों के साथ; शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति पर बातचीत की ताकि इन योजनाओं को सुचारु रूप से कार्यान्वित किया जा सके। राज्यों के मुख्य मंत्रियों/शिक्षा मंत्रियों की प्रतिक्रिया काफी उपयोगी रही।

वार्षिक कार्य योजना

15.6.3 राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, जिसका उद्देश्य देश से निरक्षरता समाप्त करना है, को व्यापक रूप से मॉनीटर किया जा रहा है। कार्यक्रमों के विभिन्न धटकों को प्राप्त करने के लिए त्रैमासिक समय-आधार वाली वार्षिक कार्य-योजना (1991-92) तैयार की गई। उपलब्धियों तथा लक्ष्यों को दर्शाने वाली त्रैमासिक रिपोर्ट मंत्रिमण्डल सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को प्रत्येक (हर तिमाही) में

पेजी जाती है।

शैक्षिक सौखि

15.7.1 शैक्षिक सांख्यिकीय स्थायी समिति की 16वीं बैठक आयोजित करने की कार्यवाई शुरू की गई है ताकि आलोच्य वर्ष के दौरान शिक्षा विभाग के सांख्यिकी अनुभाग के कार्य की प्रगति की समीक्षा की जा सके।

15.7.2 आलोच्य वर्ष के दौरान, शैक्षिक सांख्यिकी पर निम्न प्रकाशन निकाले गए—

1. चुनिन्दा शैक्षिक सांख्यिकी 1989-90
2. चुनिन्दा शैक्षिक सांख्यिकी 1990-91
3. विदेश जाने वाले भारतीय छात्र/प्रशिक्षणार्थी 1986-87
4. भारत में शिक्षा खण्ड-1 (एस) 1986-87
5. भारत में शिक्षा खण्ड-1 (सी) 1986-87
6. 1976-77 से 1989-90 तक प्राथमिक शिक्षा स्तर का नामांकन।
7. स्कूल शिक्षा की चुनिन्दा जानकारी (सूचना) 1989-90
8. विज्ञान/व्यावसायिक शिक्षा पर अनुसंधान परियोजना रिपोर्ट।

15.7.3 वर्ष 1989 में "शैक्षिक सांख्यिकी का कम्प्यूटरीकरण" नामक केन्द्रीय योजना को शैक्षिक रूप से पिछड़े 9 राज्यों में शुरू किया गया था तथा अब 1991-92 में इस योजना का विस्तार सभी राज्यों/समश्रान्त क्षेत्रों में किया जा रहा है ताकि अखिल भारतीय स्तर पर शैक्षिक आंकड़ों को इकट्ठा करने तथा उनके प्रकाशन में होने वाले विलम्ब को कम किया जा सके तथा केन्द्र तथा राज्य स्तर पर आयोजना एवं निर्णय लेने के लिए कम्प्यूटरीकृत सांख्यिकी आधार तैयार किया जा सके। इससे विशिष्ट आंकड़ों का समय से तथा सतत प्रवाह सुनिश्चित होगा।

١٦٠

16. यूनेस्को और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग।

16.1.1 संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) की स्थापना के समय से भारत संघन के आदर्श तथा उद्देश्यों को ग्राह्य करने में अग्रणी रहा है। यूनेस्को के संविधान की धारा-7 के अनुपालन में 1949 में स्थापित यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग राष्ट्रीय स्तर पर नीतिगत सलाहकारी, कार्यकारी, संपर्क, धुक्का तथा समेकन करने वाला निष्ठाया है। भारतीय राष्ट्रीय आयोग यूनेस्को के कार्य में, विशेषरूप से परीक्षा और प्रशांत क्षेत्र के राष्ट्रीय आयोगों के साथ सहयोग करने वाले इसके कार्यक्रम को तैयार करने तथा इसके निष्पादन में एक सक्रिय भूमिका निभाता रहा है।

16.1.2 वर्षों के दौरान भारत ने विभिन्न कार्यशालाओं, संगोष्ठियों तथा सम्मेलनों में ध्यान लेकर, यूनेस्को के समस्त क्षेत्रों में भारत में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा अन्तर-क्षेत्रीय कार्यक्रमों का आयोजन करने, भारतीय संस्थाओं में यूनेस्को फैलाने को स्थान देने की व्यवस्था करके, यूनेस्को तथा यूनेस्को कृपण योजना के प्रशासन के सहयोगी कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाएँ कार्यान्वित करके यूनेस्को और इसके क्षेत्रीय कार्यपाली को सहयोग प्रदान किया। यूनेस्को कूरियर के हिन्दी तथा तमिल संस्करण के प्रकाशन के रूप में यूनेस्को से संबंधित सामंजस्यपूर्ण धुक्का कार्यक्रमों में भागीदारी हो रही है।

विकास के लिए परिरक्षा-प्रशासन शैक्षिक नवीकरण कार्यक्रम (एपीड)

16.2.0 विकास के लिए परिरक्षा प्रशासन शैक्षिक नवीकरण, (एपीड) भारत के यूनेस्को के क्षेत्रीय कार्यक्रम के एक प्रोत्तकर्ता के रूप में भारत ने एपीड कार्यक्रमों तथा कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से ध्यान लिया है। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय विकास समूह की स्थापना की गई है जो देश के अन्दर विकास के लिए शैक्षिक नवीकरण कार्यक्रमों का प्रता लगाने वाले, उत्तम तथा सामन्वय के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रीय विकास समूह में, जिसके अध्यक्ष, सचिव, शिक्षा निष्ठा, हैं, संबंधित मन्त्रालयों तथा विभागों और शैक्षिक अनुसन्धान से संबद्ध अग्रणी संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हैं। राष्ट्रीय विकास समूह को एपीड के अनुसार राज्यीय तथा सब शासित क्षेत्रों में राज्य विकास समूह की स्थापना किए गए हैं जो राष्ट्रीय विकास समूह के प्रति सहयोग में कार्य करते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान तथा परिरक्षा प्रोड, जो एपीड का एक प्रमुख सहयोगी केन्द्र है, राष्ट्रीय विकास समूह के सचिवालय के रूप में कार्य करती है और एपीड कार्यक्रमों, क्षेत्रीय स्तर पर नवीकरण अनुभवों के बारे में धुक्का प्रसार और देश में भुविजित एपीड के अन्दर क्षेत्रीय सहयोग के निष्कर्ष तैयार करने को सुकर बनाती है।

सम्बन्ध के लिए परिरक्षा प्रशासन शिक्षा कार्यक्रम (अवील)

16.3.1 यूनेस्को का एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रीय कार्यक्रम, जिसमें भारत ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, सम्बन्ध के लिए परिरक्षा प्रशासन शिक्षा कार्यक्रम है जिसे यूनेस्को द्वारा 1987 में नई दिल्ली में शुरू किया गया था। वर्ष 2000 तक घाटी में निष्कर्षता के अनुदान के महत्वपूर्ण उद्देश्य से यूनेस्को ने वर्ष 2000 तक पूरी तरह से निष्कर्षता अनुदान के उपायों को शुरू

करने, प्रोजेक्ट करने और समर्थित करने की आवश्यकता पर विधायनीय ध्यान अर्पित करने के लिए 1990 को अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष के रूप में घोषित किया। जर्मनिया, बाल्टिक में मार्च, 1990 में सम्बन्ध के लिए शिक्षा पर एक विश्व सम्मेलन आयोजित किया गया था। अवील और एका के अंतर्गत कार्यक्रमों को समर्थित करने के लिए भारत द्वारा स्थापित उच्च स्तरीय राष्ट्रीय समन्वय समिति की बैठक शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में 6 सितम्बर, 1991 को हुई।

16.3.2 अवील और एका से संबंधित राष्ट्रीय समन्वय समिति की छठी बैठक में भारत में खोज शिक्षा तथा साक्षरता, आर्थिक शिक्षा और आर्थिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के क्षेत्र में शुरू किए गए कार्यक्रमों पर ध्यान दिया गया। समिति को आर्थिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण की नीति के घटकों से भी अवगत कराया गया था जो परिवर्तनशील के एक मूलभूत परक अध्ययन के बाद सामने आए थे। समिति ने विशेष रूप से आर्थिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के संबंध में उत्तम सिफारिशें कीं।

यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग का कर्मोन्मा

16.4.0 यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग का कर्मोन्मा सत्र श्री अर्जुन सिंह, मानव संसाधन विकास मंत्री को अध्यक्षता में 22 जुलाई, 1991 को आयोजित किया गया था। शिक्षा, आर्थिक विज्ञान, संस्कृति तथा स्वास्थ्य से संबंधित उच्च आयुगी की बैठकों से पूर्व राष्ट्रीय आयोग का सत्र आयोजित किया गया था। प्रमुख मामलों, विमर्ष चर्चा की गई थी, 1992-93 के लिए यूनेस्को के प्रमुख कार्यक्रम और जवट से संबंधित थे। इस सत्र में यूनेस्को के महा सम्मेलन के 26वें सत्र में विचार करने के लिए उठाए जाने वाले विषयों के लिए एक राष्ट्रीय परियोजना तथा नीतिगत दृष्टिकोण विकसित करने के वाले यूनेस्को के प्रमुख कार्यक्रम से संबंधित उच्च-योगी द्वारा की गई सिफारिशों पर व्यापक विचार-विमर्श किया गया था। XXII सत्र में महा सम्मेलन में किए जाने वाले संकल्पों के प्रमुख को अनुमोदित किया गया था और राष्ट्रीय शिक्षा मन्त्रालय द्वारा यूनेस्को के महा सम्मेलन के 26 वें सत्र में उठाए जाने वाले विषयों अपना महासत्र पर राष्ट्रीय स्तर से संबंधित शिक्षा-निर्देशात्मक संकल्प के प्रमुख अनुमोदित किए गए थे और यूनेस्को के आम सम्मेलन के 26 वें सत्र में उठाए जाने वाले मामलों में भारतीय शिक्षा मन्त्रालय द्वारा अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण पर मार्गदर्शक लेखों को निर्धारित की गई थी।

यूनेस्को, पेरिस के आय सम्मेलन का 26 वां सत्र

16.5.1 यूनेस्को की आम सभा की 26 वां सत्र 15 अक्टूबर से 7 नवम्बर, 1991 तक पेरिस में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में द्विवार्षिक 1992-93 के लिए यूनेस्को का कार्यक्रम व जवट अनुमोदित किया गया था।

16.5.2 मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह ने 9 अन्य

प्रतिनिधियों के साथ सम्मेलन के लिए भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था। 18 अक्टूबर, 1991 के पूर्ण सत्र में उन्होंने अपना भाषण हिन्दी में दिया। ऐसा पहली बार हुआ है कि भारतीय प्रतिनिधि मंडल के नेता ने आम सम्मेलन को हिन्दी में सम्बोधित किया।

16.5.3 अपने सम्बोधन में मांसिंग्वि मंत्री ने यूनेस्को सहित सम्पूर्ण यूएनएन पद्धति के लिए इस आवश्यकता पर प्रकाश डाला कि वे आने वाली नई चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने आपको सुसज्जित कर लें। उन्होंने कहा कि व्यापक अन्वेषणात्मक के नए युग को बहु-पक्षीय संस्कृति व लोकतंत्र की आवश्यकता है। मांसिंग्वि मंत्री ने जोर दिया कि 26 वां आम सम्मेलन संरचनात्मक सुधार द्वारा यूनेस्को के कार्यक्रम वितरण को सुधारने का गंभीरता से सामना कर रहा था। मांसिंग्वि मंत्री ने यूनेस्को के नए राज्य सदस्यों-इस्टोनिया, लातविया, लिथुनिया तथा तुवालू का स्वागत किया। उन्होंने 21 वीं सदी में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के लिए भारत का पूरा सहयोग देने की प्रेरणा दी।

16.5.4 भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने आम सभा के विभिन्न आयोजनों की बैठकों में मुख्य भूमिका निभाई। मांसिंग्वि मंत्री ने यूनेस्को के महा निदेशक डा० फेडरिको मेयर तथा अन्य प्रतिनिधि मंडलों के कई नेताओं के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया। अन्य देशों की सामान्य इच्छा थी कि भारत के साथ आगे द्विपक्षीय संबंध दृढ़ किए जाएं तथा यूनेस्को की नीतियां व कार्यक्रम कार्यान्वित करने में भारत के साथ सहयोग किया जाए।

16.5.5 सम्मेलन के दौरान भारत को यूनेस्को के निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय निकायों के लिए चुना/पुनः चुना गया था।

1. सांस्कृतिक विकास हेतु विश्व दशक (सांविग्वि-पेप) के लिए अंतर्राष्ट्रीय समिति (अ.स)
2. मानव व जीवमंडल के अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए अंतर्राष्ट्रीय समिति
3. सामान्य सूचना कार्यक्रम हेतु अंतर्राष्ट्रीय समिति
4. यूनेस्को मुख्यालय

16.5.6 भारत का पहले अंतर्राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान आयोग के लिए भी चयन किया गया था।

अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा व्यूरो परिषद का 34 वां सत्र

16.6.0 अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा व्यूरो परिषद, का 34 वां सत्र जेनेवा में 14-16 जनवरी, 1991 को आयोजित किया गया था। इस सत्र की अध्यक्षता श्री अनिल बोर्दिया, शिक्षा सचिव ने परिषद के अध्यक्ष के रूप में की।

महिलाओं व लड़कियों के लिए कुशलता-आधारित साक्षरता प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए उच्च क्षेत्रीय कार्यशाला

16.7.0 एशिया व प्रशांत महासागर के लिए यूनेस्को के मुख्य क्षेत्रीय कार्यालय ने केरल साक्षरता समिति, त्रिवेन्द्रम तथा यूनेस्को के साथ भारतीय राष्ट्रीय सहयोग आयोग के सहयोग से 4-16 फरवरी, 1991 से त्रिवेन्द्रम में महिलाओं व लड़कियों के लिए कुशलता आधारित साक्षरता प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए एक उप-क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला के लक्ष्य थे (क) ए टी एल पी पर आधारित पाठ्यचर्या विकास के सिद्धांतों के साथ भागीदारी को परिचित करना (ख) महिलाओं व लड़कियों के लिए कुशलता आधारित साक्षरता हेतु पाठ्यचर्या विकसित करने के लिए कुछ व्यक्ति प्रदान करना।

एशिया व प्रशांत महासागर में यूनेस्को सांस्कृतिक क्रियाकलापों में क्षेत्रीय सहयोग पर विशेषज्ञों की दसवीं बैठक

16.8.0 एशिया व प्रशांत महासागर में यूनेस्को सांस्कृतिक क्रियाकलापों में क्षेत्रीय सहयोग पर विशेषज्ञों की दसवीं बैठक 15-19 मार्च, 1991 से टोकियो में आयोजित की गई थी। इस बैठक में शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव डा० आरवीए वैद्यनाथ अय्यर ने भाग लिया था। बैठक में एशिया व प्रशांत महासागर देशों में संस्कृति, पुस्तक विकास व साक्षरता के क्षेत्रों में क्षेत्रीय सहयोग के कार्यक्रम व क्रियाकलापों पर विचार-विमर्श किया गया।

बाईरैड, शिचींग राय में एशिया व प्रशांत महासागर में शिक्षा में क्षेत्रीय सहयोग पर सलाहकार समिति का छठा सत्र

16.9.1 एशिया व प्रशांत महासागर के लिए शिक्षा में क्षेत्रीय सहयोग पर सलाहकार समिति का छठा सत्र 6 से 10 मई, 1991 तक आयोजित किया गया था। शिक्षा विभाग के अपर सचिव, श्री आर० के० सिन्हा ने बैठक में भाग लिया।

16.9.2 सत्र का मुख्य विषय निम्नलिखित में सदस्य राज्यों को समर्थन देने के लिए यूनेस्को के भावी कार्यों के लिए प्राथमिकता क्षेत्रों का पता लगाना था (1) सभी के लिए शिक्षा पर विश्व घोषणा के अनुसार शिक्षा को प्रीत्रत करना तथा सभी के लिए शिक्षा पर विश्व सम्मेलन द्वारा अपनाई गई बुनियादी शिक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्रवाई रूपरेखा तथा (11) 21 वीं शताब्दी के प्रारंभ में सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी व सांस्कृतिक परिवर्तनों से आने वाली आवश्यकताओं का सामना करने के लिए शिक्षा की कोटि में सुधार करना।

शिक्षा व उत्पादक कार्य के बीच मूल्यांकन, पुनरीक्षण व उन्नत पारस्परिक क्रिया पर क्षेत्रीय कार्यशाला

16.10.0 शिक्षा व उत्पादक कार्य के बीच मूल्यांकन, पुनरीक्षण व उन्नत पारस्परिक क्रिया पर एक क्षेत्रीय कार्यशाला राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद द्वारा क्षेत्रीय शिक्षा कालेज, मैसूर में 21 से 29 मई, 1991 तक आयोजित की गई थी।

दक्षिण एशियाई देशों में जन शिक्षा तकनीकी आदान प्रदान कार्यक्रम

16.11.0 दक्षिण एशियाई देशों में यूनेस्को का जनशिक्षा तकनीकी आदान प्रदान कार्यक्रम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली में 25 अगस्त से 5 सितम्बर, 1991 तक आयोजित किया गया था। गतिविधियों में बंगलादेश, पाकिस्तान, नेपाल, मृटान, मालदीव, श्रीलंका और भारत के प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने साक्षरता, प्रारंभिक और महिला शिक्षा कार्यक्रमों के एक चटक के रूप में जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रमों की आयोजना और क्रिया-व्यय में लगे हुए विभिन्न संगठनों का दौरा किया। दौरा करने वाले विशेषज्ञों ने, जनसंख्या शिक्षा में सामग्रियों तथा विशेषज्ञताओं के आदान-प्रदान के लिए अन्तर-संस्थागत अन्तर-देश जालतंत्र (नेटवर्क) तंत्र के विकास के संबंध में अपने-अपने अनुभवों का आदान-प्रदान किया।



अक्तूबर-नवम्बर, 1991 में पेरिस (फ्रांस) में आयोजित 26वें महासभा में यूनेस्को के इंडे के तहत मानव ससाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह और राजदूत/यूनेस्को के पी० आर० सुश्री सावित्री कुनाडि को स्वागत करते हुए यूनेस्को के महानिदेशक श्री फेड्रिक मेयर

दक्षिण एशियाई देशों के लिए आर्थिक विकास प्रतिष्ठानों के लिए पर्यावरण-शिक्षा से पर्यावरण कार्यक्षेत्र।

16.12.0 पट्टीय शैक्षणिक आयोजना और प्रसारण संस्था, नई दिल्ली ने 2-13 सितम्बर, 1991 को नई दिल्ली में दक्षिण एशियाई देशों के लिए आर्थिक विकास प्रतिष्ठानों के लिए पर्यावरण-शिक्षा से जुड़े सभी आयोजित प्रतिष्ठान कार्यक्षेत्र आयोजित की। प्रतिष्ठान के उद्देश्य, अन्तर्गत वाली के साथ-साथ आर्थिक स्तर पर पर्यावरणीय शिक्षा संकल्पनाओं के एकीकरण के तरीकों से बीमारों को विकसित करने और पर्यावरण और इसके सम्बन्ध सम्बन्धों के प्रति बढ़ती हुई जागरूकता और संबन्धशीलता विकसित करना है।

दक्षिण एशियाई उप-क्षेत्र के लिए उपसंस्था-शिक्षा से एक पुनः-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

16.13.0 उपस्थान विधिविधालय, जयपुर ने 11 नवम्बर से 6 दिसम्बर, 1991 तक दक्षिण एशियाई उप-क्षेत्र के लिए उपसंस्था-शिक्षा से एक पुनः-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किया। प्रतिष्ठान के उद्देश्य, अन्तर्गत वाली के साथ-साथ, सांस्कृतिक, आर्थिक शिक्षा और महत्त्व शिक्षा कार्यक्षेत्रों से उपसंस्था शिक्षा/परिहार-कल्याण शिक्षा की आर्थिक संकल्पनाओं के एकीकरण के तरीकों से उपयुक्त कोशरों को विकसित करने से।

जयपुर से 25-29 नवम्बर, 1991 को लक्ष्मीको के लिए आर्थिक शिक्षा के संदर्भ के लिए महिना-विशालों की भूमिका पर उप-क्षेत्रीय कार्यक्षेत्र।

16.14.0 जयपुर से 25-29 नवम्बर, 1991 को लक्ष्मीको के लिए आर्थिक शिक्षा के संदर्भ के लिए महिना शिक्षाओं की भूमिका पर उपक्षेत्रीय कार्यक्षेत्र आयोजित किया। प्रतिष्ठान के उद्देश्य, अन्तर्गत वाली के साथ-साथ, सांस्कृतिक, आर्थिक शिक्षा और महत्त्व शिक्षा कार्यक्षेत्रों की शैक्षणिक शिक्षा की भूमिका से आर्थिकीको के प्रभाव का अध्ययन करना, विशेष रूप से भारतीय क्षेत्रों के आर्थिक क्षेत्रों की आर्थिकीको के रूप में आयोजित और लक्ष्मीको का चला लाया और आर्थिक क्षेत्रों की आर्थिकीको की शिक्षा और प्रतिष्ठान से कैसे सुचारु किया जाए इस तथ्य से की गई कार्याई योजना तैयार करना है।

प्रत्येक लिए शिक्षा के संदर्भ से अंतराष्ट्रीय परामर्शदात्री कोरस की तयार बैठक

16.15.0 श्री अजित मोदीया, शिक्षा सचिव ने यूनेस्को के भारतीय-क्षेत्र के प्रभाव पर प्रत्येक लिए शिक्षा संस्थानों अंतराष्ट्रीय परामर्शदात्री कोरस की तयार बैठक से चला किया जो 4 से 6 दिसम्बर, 1991 तक पेरिस से आयोजित की गई थी। कोरस ने सन् 1990 से ई.ए.ए.ए.ए. के सम्बन्ध से आयोजित विश्व सम्मेलन की विधायी-क्षेत्रों के उपसंस्था पर विचार किया।

तयार पर्यावरण विकास से पर्यावरण से संबंधित विषयों को महिना क्षेत्रों के तरीकों पर पर्यावरण से क्षेत्रीय रोचकता

16.16.0 ए.ए.ए.ए. शिक्षा प्रशिक्षण प्रशिक्षण, भारतीय द्वारा 10 से 13 दिसम्बर, 1991 तक बंगलौर से मानव संसाधन विकास से महिनाओं से संबंधित विषयों की शैक्षणिक करने के तरीकों पर पर्यावरण से एक क्षेत्रीय प्रभाव आयोजित किया गया। शैक्षणिक का विषय, विकास से महिनाओं में पर्यावरण आर्थिक और सांस्कृतिक योजना के रूप से सुचारु क्षेत्र के

महल पर विचार-विमर्श करना और योजना बनाने वालों को इस मुद्दे के प्रति संबन्धशील बनाया था।

16.17.0 उपरोक्त बैठकों के अन्तर्गत भारतीय पट्टीय आयोजन ने यूनेस्को के पर्यावरण से अन्तर्गत क्षेत्रों द्वारा आयोजित लगभग 24 पट्टीय क्षेत्रीय अन्तर्ाष्ट्रीय बैठकों, कार्यक्षेत्रों, रोचकता, सम्मेलनों आदि से चला क्षेत्र के लिए विशेषज्ञों की भूमिका किया। अन्तर्गत क्षेत्र के क्षेत्र, आयोजन ने यूनेस्को क्षेत्रों के स्वायत्तता समीक्षाओं की व्यवस्था करना की जारी रखता जिससे विश्व आर्थिक संस्थाओं से अध्ययन और जो शामिल थे।

यूनेस्को क्षेत्रों/बैठकों/कार्यक्षेत्रों/कार्य-प्रशिक्षण से चला की परामर्शदात्री

16.18.0 भारतीय विशेषज्ञों ने, यूनेस्को या इसके क्षेत्रीय कार्यक्षेत्रों द्वारा आयोजित विधिविधालय कार्यक्षेत्रों, प्रतिष्ठान पाठ्यक्रमों, रोचकता, कार्यक्षेत्र बैठकों आदि से शिक्षा विभाग, का प्रतिनिधित्व किया 4 से 8 मई, 1991 तक रोचकता, क्षेत्र से यूनेस्को के क्षेत्रों और जयपुर एशियाई आयोजन का उप-क्षेत्रीय परामर्श आयोजित किया गया।

13 से 31 मई, 1991 तक इलाहाबाद से आयोजित आयोजन से उपसंस्था शिक्षा के संकाय के लिए क्षेत्रीय कार्यक्षेत्रों 12 से 27 जून, 1991 तक रोचकता, आयोजन से आयोजित शिक्षा से पर्यावरण, जीवन और सांस्कृतिक मुद्दों की शोभा पर क्षेत्रीय बैठक।

गर्लबोर्डों तथा बंजारा बर्ग के लिए आर्थिक शिक्षा के सम्बन्ध के लिए 30 जुलाई से 8 अगस्त, 1991 तक विभाग मई, धार्मिक से आयोजित बैठक की योजना तैयार करना।

पर्यावरण और प्रभाव से पट्टीय आयोजन की 23-26 सितम्बर, 1991 तक कुआलालम्पूर, मलेशिया से बैठक आयोजित की गई।

शैक्षणिक प्रशिक्षण, 1991-शिक्षकों और शैक्षणिक प्रशिक्षण कार्यक्षेत्रों को सेवाकार्य से तथा इसके पूर्व के पर्यावरण संस्था प्रशिक्षण और विषयों पर पर्यावरण तथा प्रभाव रोचकता।

विशेषता (आयोजन) से 9-21 सितम्बर, 1991 से सभी के लिए शिक्षा प्रशिक्षण क्षेत्रों के आर्थिक विकास से सभी के लिए शिक्षा उपसंस्था को बड़ाने और कठिन शिक्षा संदर्भ पर आयोजित 1991 रोचकता।

यूनेस्को, क्षेत्रों से 10 से 13 अक्टूबर, 1991 तक शिक्षा से जीवन मुद्दों की संस्था पर आयोजित कार्यक्षेत्र। धार्मिक से 11 से 30 नवम्बर, 1991 तक, आयोजित महिनाओं तथा लक्ष्मीको के लिए क्षेत्रीय अन्तर्गत सांस्कृतिक प्रतिष्ठान के संकाय के लिए प्रशिक्षण कार्यक्षेत्र।

18 से 29 नवम्बर, 1991 तक वेणुग, मलेशिया से आयोजित "विज्ञान और प्रशिक्षण के संदर्भ से अध्ययन मुद्दों की नीति और प्रदर्शनी का विकास" सम्बन्धी क्षेत्रीय विशेषज्ञ कार्यक्षेत्र।

यूनेस्को काज के लिए योगदान

16.19.0 यूनेस्को का प्रत्येक सदस्य-राज्य यूनेस्को के प्रति द्विवार्षिक निश्चित बजट में योगदान करता है। यूनेस्को के द्विवार्षिक 1990-91 के लिए योगदान के अनुश्रुतित मानक के अनुसार भारत का हिस्सा कुल बजट के लिए 0.36 प्रतिशत निर्धारित किया गया। तदनुसार, भारत में वर्ष 1990-91 के लिए यूनेस्को को 176 लाख रुपये तथा 1991 के लिए पहले ही 198.34 लाख रुपये का योगदान किया जा चुका है। लागू 22.00 लाख रुपये की एक और राशि यूनेस्को को दिए जाने की संभावना है जो मुद्रा उधार बढ़ाव और अवमूल्यन के कारण 1990-91 में देय हुई है।

यूनेस्को अपील बोर्ड

16.20.0 श्री मुन्शीख जी शर्करा, संघ सदस्य (राज्य सभा) को छह वर्ष की अवधि के लिए यूनेस्को अपील बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

16.21.0 सुश्री सवित्री गुनाडी, यूनेस्को में भारत के अनादर/वी-आर-को मार्च 1991 से फरवरी 1992 की अवधि के लिए यूनेस्को में एशिया प्रशांत का अध्यक्ष चुना गया है।

'विश्वभार में नासकेटवर्क परम्परा और आधुनिकता पर अवार्ड' में भारा लेखा

16.22.0 भारत ने सेरिस में आयोजित यूनेस्को के महा सम्मेलन के 26वें सत्र के अवसर पर अक्टूबर-नवम्बर, 1991 के दौरान सेरिस में आयोजित 'विश्वभार में नासकेटवर्क परम्परा और आधुनिकता पर अवार्ड' में भाग लिया।

यूनेस्को का कार्याकारी बोर्ड

16.23.0 श्री एल. कुमान, सदस्य यूनेस्को कार्याकारी बोर्ड ने, 11 मई से 12 जून, 1991, 30 सितम्बर, 1991 तथा 8 और 9 नवम्बर, 1991 तक सेरिस में यूनेस्को प्रशासकीय बोर्ड के सम्मर्प 136वें 137वें और 138वें सत्र में भाग लिया।

विश्व विरासत समिति

16.24.0 1972 में लोकात विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण संबंधी कन्वेंशन के अन्वयों के अनुसरण में यूनेस्को ने उन प्राकृतिक और सांस्कृतिक स्थलों का, जो विश्व विरासत सूची में शामिल हैं, परत लागू तथा विश्व विरासत निधि के संचालन के लिए एक विश्व विरासत समिति गठित की है। इसमें इकोस सदस्य राज्य हैं। 1987 में आयोजित यूनेस्को के महा सम्मेलन के 23वें सत्र में इस समिति में भारत को एक सदस्य के रूप में चुना गया और इसका कार्यकाल 1991 में आयोजित यूनेस्को के महा सम्मेलन के 26वें सत्र के अन्त में समाप्त हो गया। विश्व विरासत सूची में, अब तक भारत के नौदश सांस्कृतिक स्मारक और पाँच प्राकृतिक स्थल, शामिल किए जा चुके हैं।

भारत पर एक्सपर्ट-आरएसी तकनीकी समिति

16.25.1 क्षेत्रीय सहयोग, संघीय दक्षिण एशियाई संघ (एएसएए-आरएसी) के राज्य अथवा सरकार के आचार्यों के इत्यानामाद में दिसम्बर, 1988 में आयोजित चौथे सम्मेलन में शिक्षा को उन मुख्य क्षेत्रों में से एक बताया किन पर इस क्षेत्र में तत्काल ध्यान देने की जरूरत है और शिक्षा को सहयोग के लोकात क्षेत्रों में शामिल करने का निर्णय

किया। तदनुसार, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ की शिक्षा संबंधी तकनीकी समिति, 1989 में स्थापित की गई। एएसएए-आरएसी शिक्षा संबंधी तकनीकी समिति की अगुआई, 1991 के दौरान इत्यानामाद में तीसरी बैठक आयोजित की गई। श्री अजित मोदीया, शिक्षा सचिव ने इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व किया।

16.25.2 इस बैठक के दौरान, शिक्षा संबंधी तकनीकी समिति के अन्वीन अब तक किए गए कार्यान्वयनों की समीक्षा की गई और एएसएए-आरएसी सदस्य राज्यों के आयोजित विभिन्न विशिष्ट गुण बैठकों की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्यावाई करने के लिए ठोस प्रस्तावों का मुद्दाव दिया। 1992 के लिए एक कार्यक्रमपत्र कार्यक्रम की अंतिम रूप दिया गया जिसके अन्तर्गत भारत शैक्षिक आयोजना और प्रबन्धन पर कार्यशाला का स्वागत करेगा।

16.25.3 भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने इस बैठक में नेतृत्व की भूमिका निभाई जिसकी सभी सदस्य देशों द्वारा सभना की गई और उसे लोकात किया गया।

विदेशी शैक्षिक सम्बन्ध

16.26.0 हिपकोय और जलप्राप्त विदेशी शैक्षिक सम्बन्ध अन्तर्देशीय कृतनीति में एक सार्विक भूमिका निभाते हैं। महात्तपूर्ण देशों के साथ भारत के शैक्षिक तालमेल को गहरा बनाने के विचार से सांस्कृतिक विनिमय कार्यान्वयन के शैक्षिक अवयव तथा अन्य द्विपक्षीय प्रबन्ध अस्था से कार्यान्वयन किए जा रहे हैं। विदेशी विश्वविद्यालयों में भारत और भारतीय विद्या के सम्बन्ध में अन्वयनों को प्रोत्साहन देने के नए मार्गों का परत लागूवा जा रहा है और भारत की प्रासंगिकता के क्षेत्रों में संस्था-संस्था की बीच तालमेल बढ़ाए जा रहे हैं। विदेशों में युनिवर्स भारतीय मिशनों से भी शिक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने में सक्रिय रुचि लेते के लिए सम्पर्क किया गया है। चीन, पाकिस्तान, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, स्टुटन और फ्रांस आदि में हमारे मिशनों के साथ इस क्षेत्र में पूर्त नए विचार स्थापित करने के लिए सम्वाद किया गया है।

विदेशों से आगन्तुक

16.27.1 यूनेस्को के महासम्मेलन के तीन तिथी प्रतिनिधि श्री जॉन गुडर ने 12 अक्टूबर, 1991 को शिक्षा सचिव से मुलाकात की। इस दौरान कन्वैडिया में यूनेस्को की पुनरीचना स्वीकृति में भारत की सहभागिता की रुचासकेतकों पर विचार-विमर्श किया गया।

16.27.2 यूनेस्को के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग के महासचिव श्री सितारात अहमद के निमंत्रण पर यूनेस्को के एशिया, और प्रशांत च बैकान के प्रमुख क्षेत्रीय कार्यान्वयन के निदेशक अपील और ई-एफएए की राष्ट्रीय समन्वयन समिति की बैठक जो 6 सितम्बर, 1991 में हुई, में भाग लेने के लिए नई दिल्ली आए।

16.27.3 यूनेस्को के दोन्नी स्थित एशियाई सांस्कृतिक क्षेत्र के पुलाक विकास और सांस्कृतिक अनुभाग के प्रमुख श्री शिजी तजिमा एशिया और प्रशांत क्षेत्रों में युवाओं और मौखिक के लिए युनिवर्सली सांस्कृतिक पठन सामग्रियों की एक उप-क्षेत्रीय कार्यशाला के 1992 के मध्य में भारत में आयोजन के सम्बन्ध में विचार-विमर्श के लिए नवम्बर, 1991 में नई दिल्ली आए।

यूनेस्को का सहभागिता कार्यक्रम

16.28.0 सहभागिता कार्यक्रम के अन्तर्गत यूनेस्को उन सदस्य राज्यों की विभिन्न संस्थाओं और संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है जो यूनेस्को महासभा द्वारा परिभाषित उद्देश्यों के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय, उप-क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर योगदान करने के लिए नवाचारी परियोजनाएँ शुरू करने के लिए यूनेस्को के कार्यक्रमों और कार्यकलापों के समर्थन में लगी हैं। 1990-91 और 1991-92 की द्विवार्षिकी के दौरान यूनेस्को द्वारा 1,09,200/- अमेरिकी डालर की वित्तीय सहायता से अनुमोदित भारत से 10 परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई शुरू की गई।

अन्तर्राष्ट्रीय सहमति के लिए शिक्षा: यूनेस्को क्लब और सम्बद्ध स्कूल

16.29.1 यूनेस्को क्लब का मुख्य रूप से शैक्षिक संस्थानों में गठित स्वेच्छक इकाया है, जिनका उद्देश्य संगठन के लक्ष्यों और उद्देश्यों को आगे बढ़ाना है। सम्बद्ध स्कूल, अन्तर्राष्ट्रीय सहमति, सहयोग और शान्ति के लिए शिक्षा से सम्बन्धित कार्यकलापों को चलाने के लिए सम्बद्ध स्कूल परियोजना में भागीदारी के लिए यूनेस्को सचिवालय से सीधे जुड़े शैक्षिक संस्थान हैं। सम्बद्ध स्कूल परियोजना के अन्तर्गत शैक्षिक संस्थानों का चयन यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग की सिफारिश पर यूनेस्को द्वारा किया जाता है। इस परियोजना के अन्तर्गत भारत से 37 स्कूल और शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान यूनेस्को के साथ जुड़े हैं।

16.29.2 यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग यूनेस्को क्लब और सम्बद्ध स्कूलों के लिए राष्ट्रीय समन्वय एजेंसी है। लगभग 250 यूनेस्को क्लब आई.एन.सी. के साथ पंजीकृत हैं। अन्तर्राष्ट्रीय सहमति, सहयोग और शान्ति को बढ़ावा देने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय दिवसों और वर्षों को मनाने, बैठकें और वाद-विवाद प्रतियोगिताएँ आयोजित करने जैसे यूनेस्को के लक्ष्यों और उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के कार्यकलापों को शुरू करने के लिए यूनेस्को क्लब और सम्बद्ध स्कूलों को वास्तविक और विन्यास सहायता दी जाती है।

एशिया प्रशांत में 16वीं फोटो प्रतियोगिता

16.30.0 यूनेस्को का भारतीय राष्ट्रीय आयोग यूनेस्को द्वारा आयोजित फोटो प्रतियोगिताओं की वार्षिक भागीदारी में यूनेस्को के एशिया सांस्कृतिक केन्द्र, (ए.सी.सी.एन्यू) जापान को अपना सहयोग देता रहा है। एशिया और प्रशांत में 16वीं फोटो प्रतियोगिता के लिए भारत के 16 व्यक्तियों को पुरस्कार प्रदान करने के लिए चुना गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार

16.31.0 यूनेस्को ने उत्कृष्ट योग्यता दिखाने वाले निरक्षरता के विरुद्ध छिड़े अभियान में विशेष सफलता दिखाने वाले संस्थानों, संगठनों या व्यक्तियों के सम्मान में प्रति वर्ष दिए जाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कारों और दिशा-निर्देशों की स्थापना की है। पुरस्कार प्रदान करने का उद्देश्य साक्षरता के बढ़ते कार्यक्रमों के प्रति लोगों के मन में सख्त-मुभूति और सहयोग की भावना जगाना है। आई.एन.सी. की सिफारिश पर यूनेस्को ने पश्चिम बंगाल को निरक्षरता के विरुद्ध छिड़े अभियान में उत्कृष्ट योगदान के लिए नोमा साक्षरता पुरस्कार प्रदान किया है। पुरस्कार की राशि 10,000/- अमेरिकन डालर है। पुरस्कार यूनेस्को के महानिदेशक द्वारा 8

सितम्बर, 1991 को पेरिस में आयोजित सम्मेलन में पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिनिधि को प्रदान किया गया।

विज्ञान की लोकप्रियता के लिए 1991 का कर्लिंग पुरस्कार

16.32.0 यूनेस्को ने विज्ञान की लोकप्रियता के लिए 1991 का कर्लिंग पुरस्कार भारत के डा० एन.के० सहगल तथा रोमानिया के डा० इफ्रीमोविस, को सयुक्त रूप से प्रदान किया। डा० सहगल राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद् के विज्ञान लोकप्रियता सम्बन्धी कार्यक्रम के प्रभारी तथा निदेशक हैं, तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में इसका सचिवालय है। डा० सहगल को पुरस्कार के लिए आई.एन.सी. ने मनोनीत किया था।

यूनेस्को कूपन कार्यक्रम

16.33.0 आयोग ने शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति तथा दूर संचार के क्षेत्र में कार्य कर रही संस्थाओं तथा व्यक्तियों की सहायता के लिए बनाई गई यूनेस्को अन्तर्राष्ट्रीय कूपन योजना का संचालन विदेशी मद्रा तथा आयात नियंत्रण की औपचारिकताओं के बिना उनकी विदेश से शैक्षिक प्रकाशनों, वैज्ञानिक उपकरणों, शैक्षिक फिल्मों आदि की वास्तविक आवश्यकताओं को आयात करने के लिए जारी रखा। कुल 10,800 अमेरिकी डालर की राशि के यूनेस्को कूपन बेचे गए।

यूनेस्को कुरियर के भारतीय भाषा संस्करणों का प्रकाशन

16.34.0 कुरियर, यूनेस्को द्वारा प्रकाशित विश्व की एक अतिविशाल शैक्षिक व सांस्कृतिक पत्रिका है। भारतीय राष्ट्रीय आयोग ने इसके तमिल और हिन्दी संस्करणों का प्रकाशन जारी रखा। इन भाषा अनुवादों का शैक्षिक संस्थाओं, पुस्तकालयों, यूनेस्को क्लबों, संबद्ध स्कूलों तथा आम जनता में व्यापक परिचालन है।

स्वैच्छक निकायों, यूनेस्को क्लबों तथा संबद्ध स्कूलों के लिए वित्तीय सहायता की योजना:

16.35.0 यूनेस्को के आदेशों एवं उद्देश्यों के समर्थन के लक्ष्य से शुरू किए गए कार्यकलापों के लिए आयोग स्वेच्छक संगठनों, यूनेस्को क्लबों तथा संबद्ध स्कूलों के लिए वित्तीय सहायता की एक योजना का संचालन कर रहा है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान विभिन्न निकायों के लिए अभी तक 15000/- रु अनुदान सहायता की मजदूरी दी गई है।

ओरोविले

16.36.1 केन्द्र सरकार द्वारा ओरोविले का प्रबंध-कार्य ओरोविले (आपात कालीन) प्रावधान अधिनियम 1980 के अन्तर्गत अस्थायीतौर पर लिया गया था ताकि परियोजना के कुप्रबंध के कारण पैदा हुई कुछ समस्याओं का समाधान किया जा सके। केन्द्र सरकार को सौंप गए ओरोविले के प्रबंध की अवधि के दौरान नगर के अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विकास हुआ है। ओरोविले के उचित प्रबंध और आगे के विकास को सुनिश्चित करने की दीर्घावधिक व्यवस्था करने के लिए तथा इसके साथ ही विभिन्न कार्यकलापों को प्रोत्साहित करने, जारी रखने तथा संयोजित करने के लिए ओरोविले फाउंडेशन अधिनियम अधिनियमित किया गया जो 28 सितम्बर, 1988 से लागू किया गया था। इस अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा ओरोविले फाउंडेशन गठित किया जाएगा जिसमें शासित निकाय, रेजिडेंट असेंबली, और ओरोविले अन्तर्राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् शामिल होगी। डा० कर्ण सिंह की अध्यक्षता में फाउंडेशन के

शसित निकाय को भी गठित किया गया है। बौर्ड की दो बैठकें 28-2-1991 और 17-8-1991 को ओरोविले में आयोजित की गयी।

16.36.2 रेजिडेंट असेबलनी जिसमें सभी ओरोविल शामिल हैं, ने 7 सदस्यों की अपनी कार्य समिति को भी चुना है। अन्तर्द्वीय सप्ताहवार समिति के गठन पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

16.36.3 फिलहाल ओरोविले की सभी कंपनियों की देख-रेख सरकार द्वारा नियुक्त अधीक्षक द्वारा की जाएगी। अधिनियम के अन्तर्गत इन्हें शीघ्र ही फाउंडेशन को सौंप दिए जाने की संभावना है। अधिनियम के अन्तर्गत फाउंडेशन को अपने दायित्व का निर्वाह करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार फाउंडेशन को

उत्तरी राशि का भुगतान अनुदान, ऋण या अन्य तरीके से कर सकती है बिना किसी सरकार जरूरी समझौता है।

16.36.4 शैक्षिक क्षेत्र में ओरोविले के विकास के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में 35.55 लाख रु० की लागत की एक स्कीम शामिल की गई है। योजना में तीन महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डाला गया है अर्थात् (i) बाल्यवस्था के प्राथमिक स्तर से शुरू होने वाली सतत शिक्षा को जारी रखने की आवश्यकता (ii) ज्ञान तथा संस्कृति के संतुलन की आवश्यकता और (iii) ओरोविले तथा निकटवर्ती गाँवों के बहुमुखी विकास के लिए एक स्थायी आधार उपलब्ध करने की आवश्यकता योजना को अवैधित परिशोधनों के साथ आठवीं पंच वर्षीय योजना में भी जारी रखा जाएगा।

ମୁଁ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭାବି ଯାଏ

('୯୯୯' ୯)

1	2	3	4	5	6
13.	পৌরস্ব অর্গানাইজেশন ফর ডেবলপমেন্ট এক্সন ডোর নং ৭-৭৫, গমনগর কালোণী, জিও চিত্তুর-৫১৭০০২ (আম্রা প্রাং)।	-বহী-	1,14,576	৫০ অননৈপচারিক শিাশা কেন্দ্র	
14.	সৌভাগ্যী ফর হেল্প এড এক্সন ফর রুরল পুজর কোংগরে ডিখালে, জিও চিত্তুর, আম্রা প্রদেশ।	-বহী-	2,51,975	৫০ অননৈপচারিক শিাশা কেন্দ্র	
15.	কলেক্টিব অর্ডার ফর রুরল রিকলেক্সন এক্সন ১৭-৬৫/৫ ফৈলেস রোড, কুপ্পম, চিত্তুর-৫১৭৪২৫	-বহী-	2,০৭,৭১৬	৫০ অননৈপচারিক শিাশা কেন্দ্র	
16.	ভারত সেবা সমিতি, সুগার ফেক্টরি, ইম্বলার্গ কালোণী, ৭৫, দৌদীপালী, চিত্তুর।	-বহী-	4,44,০৮৭	১০০ অননৈপচারিক শিাশা কেন্দ্র	
17.	নবজোন এক্সন এক্সন পো. নং-৭৭, সেলেক্স রোড, এস-কো. ডো. কালোণী, অদোণী-৫১৮৩০১	-বহী-	4,৭৮,৮০০	১০০ অননৈপচারিক শিাশা কেন্দ্র	
18.	বেয়ুধা, ১-১-৩৪২/বী, বিবেক নগর, চিক্কাডাপালী, হৈদরাবাদ-৫০০০২০।	-বহী-	2,৭৭,০১৩	১০০ অননৈপচারিক শিাশা কেন্দ্র	
19.	অসম জাহ মজদুর এক্সন মল্টিপলস, সৌভাগ্য এক্সন এক্সন রংজন, টোডাভার, জোরহট, অসম।	-বহী-	1,3২,৭৭০	৫০ অননৈপচারিক শিাশা কেন্দ্র	
20.	বারুগুডি উজয়ন সমিতি, বিলেক্স এক্স পোস্ট মুকালমুয়া, দাশবনলাবারী, অসম।	-বহী-	1,২০,০৪০	৫০ অননৈপচারিক শিাশা কেন্দ্র	
21.	জমুনামুখ অমল্টিপল অহমল্টিপল মদরাসা কমিটি বিলেক্স এক্স পোস্ট জমুনামুখ, জিও নবগাব, অসম।	-বহী-	1,২৬,৬৪৮	৫০ অননৈপচারিক শিাশা কেন্দ্র	
22.	গৌরীপুর বিবেকনন্দ কল্লা, বারুগুডি রোড, পো. গৌরীপুর, চুকাটী-৭৮৩৩৩১, অসম।	-বহী-	1,২৬,৩৮২	২৫ অননৈপচারিক শিাশা কেন্দ্র	
23.	মৌরীগাব মহিল সমিতি, মৌরীমুসিনোগাব, পো. মৌরীগাব, জিও নবগাব, অসম।	-বহী-	1,3২,৭৭০	৫০ অননৈপচারিক শিাশা কেন্দ্র	
24.	মুনিসল্লা নদর হুড এক্সন রগাল জুনাবপুর, জিও নবগাব, অসম।	-বহী-	2,14,4০০	৮০ অননৈপচারিক শিাশা কেন্দ্র	
25.	টোটল রুরল ডেবলপমেন্ট, পো. ডাভাখৌপ, জিও গালবারী, অসম।	-বহী-	1,3২,৭৭০	৫০ অননৈপচারিক শিাশা কেন্দ্র	
26.	অদালী রহমিয়া মদরাসা পো. উদালী বাজার জিও নবগাব, অসম।	-বহী-	1,4২,39০	৫০ অননৈপচারিক শিাশা কেন্দ্র	

1	2	3	4	5	6
27	जैस्टेबल एसीसिप्रेशन फर कल बेवलपमेट, के० आर० स्कूल बैतलआह, वे० चमन, बिहार।	-वही-	3,52,000	जिला ससचन इकाई	
28	मंथन खागौल रोमन कैमोसिक चर्च, खागौल, वि० पटना, बिहार।	-वही-	3,52,000	जिला ससचन इकाई	
29	क्षय चारती, छादी ग्राम, पुरा, बिहार।	-वही-	3,61,000	जिला ससचन इकाई	
30	इरिया महिला विकास केन्द्र, गाथी रोड, पो० झरिया, वि० धनबाद-828111, बिहार।	-वही-	1,20,300	25 अनैपचारिक शिक्षा केन्द्र	
31	महिला विद्यालय प्रतिष्ठान, एकनर सरय, नालंदा।	-वही-	1,26,675	25 अनैपचारिक शिक्षा केन्द्र	
32	प्राकृतिक आरोग्य आश्रम, राजगीर नालदा, बिहार।	-वही-	2,24,557	50 अनैपचारिक शिक्षा केन्द्र	
33	समन्वय आश्रम, बोध गया, बिहार।	-वही-	6,92,115	ई० एक्स० आई० + डी० आर० यु०	
34	इदिर गाथी समाज सेवा आश्रम, 221-ए पीपुल्स कोओपरेटिव कालोनी, केकरबाग, पटना।	-वही-	1,38,500	अनैपचारिक शिक्षा केन्द्र	
35	बिहार दलित विकास समिति, पटना निवर घुमेछरी राज कभलेज, बाढ़-पटना।	-वही-	2,35,189	अनैपचारिक शिक्षा केन्द्र	
36	अन्योदय लोक कार्यक्रम (आलोचक), वंस्ट चमन, बिहार।	-वही-	2,34,050	ई० एक्स० आई०	
37	सचाल पराना ग्राम उद्योग समिति, बिधामट घाम, देवगढ़, सचाल पराना, बिहार।	-वही-	1,32,419	30 अनैपचारिक शिक्षा केन्द्र	
38	सचाल पराना अन्योदय आश्रम, पुमोबा, देवगढ़, सचाल पराना, बिहार।	-वही-	1,45,995	30 अनैपचारिक शिक्षा केन्द्र	
39	बोधार्थक प्रखण्ड स्वयंसेवक विकास सम, विलेज एड पो० जगरपुर, बाबा बोधार्थक, मधुबनी-847402 बिहार।	-वही-	4,78,800	100 अनैपचारिक शिक्षा केन्द्र	
40	समग्र ग्राम स्वयंसेवक सम, इलामपुर, नालंदा, बिहार।	-वही-	1,29,965	30 अनैपचारिक शिक्षा केन्द्र	
41	बनवासी सेवा केन्द्र, अचौरा, वि० रोहतास, बिहार।	-वही-	1,27,847	100 अनैपचारिक शिक्षा केन्द्र	
42	ग्राम स्वयंसेवक समिति बालिया, साहिबपुर, पटना, बिहार।	-वही-	1,32,790	50 अनैपचारिक शिक्षा केन्द्र	
43	बि०बा० अग्रोथ एवं लोक शिक्षा केन्द्र, बिजेस जय कृष्णा नगर, पो० बाढ़वा, इलामपुर, नालंदा, बिहार।	-वही-	2,91,460	60 अनैपचारिक शिक्षा केन्द्र	
44	जन जागरण केन्द्र, विलेज और पोस्ट बाढ़, वि० इलाहाबाद, बिहार।	-वही-	1,45,949	30 अनैपचारिक शिक्षा केन्द्र	

1	2	3	4	5	6
45	सता ग्राम विकास समिति, विलेज एंड पोस्ट रामपुर कुमार, कौफ महानर रोड, वैशाली, बिहार।	-वही-	1,42,650	30	अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र
46	जन शिक्षा केन्द्र, विलेज एंड पोस्ट चक्कर, बि० मुर्गा, बिहार।	-वही-	1,42,218	30	अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र
47	नव भारत जागृति केन्द्र, बेहरा पो० धुन्दावन चंपारन, हजारीबाग, बिहार।	-वही-	2,11,909	60	अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र
48	अदिधी, 2/30 स्टेट बैंक कालोनी, बेती रोड, पधुबनी।	-वही-	57,90,679	200	अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र
49	ग्राम निर्माण मंडल, सबोदय आश्रम, रोखी द्वारा नवाधा-805106, बिहार।	-वही-	1,32,790	50	अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र
50	गुजरात खेत विकास परिषद, अहमदाबाद।	-वही-	1,32,790	50	अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र
51	आनंद निकेतन आश्रम ट्रस्ट पो० रामपुर कावला, बि० बड़ौदा-391140	-वही-	2,40,245	100	अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र
52	भावनगर महिला सघ, पनवडी चौक, भावनगर-364001, गुजरात।	-वही-	3,60,000	100	अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र
53	ग्राम निर्माण केलवानी मंडल धवा तातुख बलिया, अंकोखद, बि० मंडौच, गुजरात।	-वही-	2,22,900	100	अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र
54	लाल मर्ग गुप्त कल्ल डेवलपमेंट फंड, अविद मिस्त्र प्रिमिलेज, नरोदा रोड, अहमदाबाद-380025	-वही-	1,53,400	100	अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र
55	लोक भारतीय ग्राम विद्यापीठ, सोनोस-364230, बि० भावनगर, गुजरात।	-वही-	4,67,224	100	अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र
56	मानव सेवा मंडल ट्रस्ट, 5-ए, अगुथा श्वेताश्रम, अमीन मार्ग, न्यार नून नगर, अहमदाद-360001	-वही-	4,49,525	100	अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र
57	सबोदय आफ दि पौपुल सोसाइटी 1225 देवनी रोटी, मडविनी पोले, अहमदाबाद-380001, गुजरात।	-वही-	11,24,190	200	अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र
58	श्री पंचमहाल केलवानी मंडल, कालो, बि० पंचमहाल, गुजरात।	-वही-	3,67,788	100	अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र
59	श्री सत्यवतम, मुमेश, बि० काच्छ, गुजरात।	-वही-	5,72,505	100	अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र
60	श्रीमती बी० के० कलजोशी एन्ड्रुकेमन ट्रस्ट, 20 रतीश श्वेताश्रम, कालो 382721, बि० मेहसाणा, गुजरात।	-वही-	3,90,953	100	अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र

1	2	3	4	5	6
61	स्वराज आश्रम, बांडोली, जि० सुरत, गुजरात।	-वही-	2,47,243	100	अनै-पचारिक शिक्षा केन्द्र
62	अजुयन-ए-तालीमो इदार, कोर्ट रोड, भडोच।	-वही-	6,77,629	100	अनै-पचारिक शिक्षा केन्द्र
63	गुजरात स्टेट क्राइम प्रवेशन ट्रस्ट, सौ/ओ किशोर त्रिपाठे, 2, जोशीबाग एपार्टमेंट निक्क नक्का हाईस्कूल, सेंट जेवियर्स स्कूल रोड, अहमदाबाद-380014	-वही-	3,80,055	100	अनै-पचारिक
64	वासरा तालुका युवक मंडल एलोसियस अग्रवा लाल जि० खेडा-388230	-वही-	1,20,260	25	अनै-पचारिक
65	श्रमिक कल्याण न्यास गांधी मजूर सेवासलय शारदा अहमदाबाद-380017	-वही-	2,55,900	100	अनै-पचारिक
66	अहमदाबाद सिटी सामाजिक शिक्षा समिति, श्रमिक कल्याण भवन, रायपुर गेट के बाहर, अहमदाबाद-380022	-वही-	3,56,517	100	अनै-पचारिक
67	अमर भारती, मोती एंबेयो, चाचा बहोयाल, तालुका देहगम जिला अहमदाबाद-382308 गुजरात।	-वही-	6,34,316	100	अनै-पचारिक
68	लक्ष्मी एजुकेशन सोसायटी, मेहम (पेठतक), हरियाणा।	-वही-	4,80,600	100	अनै-पचारिक
69	शिक्षा समिति झी ए यो प्रशिक्षण कलेज, शिव नगर, सोनीपत, हरियाणा।	-वही-	6,87,130	130	अनै-पचारिक
70	विद्या महासभा कन्या मुक्तकुल महाविद्यालय, खरखोदा, जिला सोनीपत, हरियाणा।	-वही-	9,60,502	200	अनै-पचारिक
71	जनता कल्याण समिति, बस स्टैंड के सामने, रेवाड़ी, मेहतागढ़, हरियाणा।	-वही-	4,13,085	100	अनै-पचारिक
72	हरियाणा राज्य बाल बचपन परिषद्, बाल विम्वस भवन, 650, सेक्टर 16-डी मेडीनगढ़-160016	-वही-	2,75,100	100	अनै-पचारिक
73	परीक्षक केन्द्र केन्द्र, [.....] के लिए [.....] [.....] लोसभटी, पत [.....] [.....]।	-वही-	1,32,790	50	अनै-पचारिक
74	L. I. शिक्षा केन्द्र [.....] [.....] उत्तर अहि, बगवती नगर, कन्या कुम्हार-173225, जिला सोलन, हि० [.....] प्रदेश।	-वही-	1,72,762	100	अनै-पचारिक

1	2	3	4	5	6
75	विप्लव एक्शन फोर फोएल इन नीड अचारी, जिला सिरमौर -173023 हिं.प्र.।	-वही-	1,53,015	100	अनौ-शि-के-
76	मानव हित प्रयोग केन्द्र, सिरमौर जिला, हिं.प्र.-713101	-वही-	1,74,900	100	अनौ-शि-के-
77	क-ईटक कल्याण सोसायटी पोस्ट बाक्स नं.-28, बिक्रमपुर-562101	-वही-	5,11,905	1500	अनौ-शि-के-
78	केरल रा-ओरशि- विकास सच, त्रिवेन्द्रम।	-वही-	7,60,050	150	अनौ-शि-के-
79	सुलतान-उल-हिन्द शैक्षिक सोसायटी, भोपाल।	-वही-	4,03,770	100	अनौ-शि-के-
80	बाल आवास महिला कल्याण समिति, बिलागाव कवाटी गंगेशपुर, शुक्रा घवन, जेल रोड, मुर्गा, मं.प्र.-476001	-वही-	1,20,300	25	अनौ-शि-के-
81.	तरुण शंकर, 1784 इदिरा भर्किट, आजम नगर, जबलपुर-482010, मं.प्र.।	-वही-	1,16,865	25	अनौ-शि-के-
82.	कस्तूरबा गोष्ठी राष्ट्रीय स्मारक न्यास, कस्तूरबा ग्राम, इन्दौर-452020, मं. प्र.।	-वही-	3,18,943	100	अनौ-शि-के-
83	मो-रेसरे शिक्षा सोसायटी, कोचकुड, जिला उज्जैन, मं. प्र.।	-वही-	2,40,080	50	अनौ-शि-के-
84	दिशा (डी आई एस एच ए). रावपुर, मध्य प्रदेश।	-वही-	2,00,000	ई एण्ड आई	
85	एकलाव्य, भोपाल, मध्यप्रदेश।	-वही-	9,93,723	ई एण्ड आई	
86	मध्य प्रदेश बाल कल्याण परिषद होटल नं.-5, देस।	-वही-	4,49,996	100	अनौ-शि-के-
87	गायत्री शक्ति शिक्षण समाज कल्याण समिति, 1314 विज्ञा भर्किट, रांछी बस्तो. जबलपुर, मं.प्र.।	-वही-	1,86,297	25	अनौ-शि-के-
88	श्री मोनी निष्कषीठ, गोरगोटी, कोल्हापुर।	-वही-	1,32,790	50	अनौ-शि-के-
89	अखिल भारतीय माधुसर्गीय समाज प्रबोधन संस्था, 22, प्रकाश अपार्टमेंट कटभनिवाली, कल्याण (पूर्व) जिला, धाणे, महाराष्ट्र।	-वही-	1,19,358	25	अनौ-शि-के-
90	अर्पण शिक्षा सोसायटी, तालासरी (बासे), वा।छैडा निवास, औरंगाबाद, महाराष्ट्र।	-वही-	1,75,263	25	अनौ-शि-के-
91.	चरित्नी डेबल चोपड़ा जिला कल्याण, महाराष्ट्र।	-वही-	1,32,790	50	अनौ-शि-के-

1.	2	3	4	5	6
12	बोम्बे सिटी, सामाजिक शिक्षा समिति, आदर्श नगर, बोरली, बम्बई-400025, महाराष्ट्र।	-वही-	1,61,121	50 अनौ-शिक्षे	
13	नागरिक उद्धार सोसायटी, 17, फाउनेियर नगर, सेमला रोड, नागपुर-15, महाराष्ट्र।	-वही-	1,20,041	25 अनौ-शिक्षे	
14	प्राचीन अर्यप पुस्तक संस्था कस्तूर बाग, कडमाव रोड, गोधीगिलाज, जिला कोल्हापुर -416502, महाराष्ट्र।	-वही-	2,40,080	50 अनौ-शिक्षे	
15	भारतीय शिक्षा संस्थान 12B/2, जी.पी. नायक एव, क्लाउ कर्मरेड, कोलार, पुणे-411029	-वही-	1,39,4150	राज्य-शिक्षे	सेल-ई एड आई
16	प्रबन्ध और प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान, 20 अक्षयम कालोनी, पठानगेट, पोन्ना-87, औरंगाबाद -431001	-वही-	2,25,450	50 अनौ-शिक्षे	
17	जलना शिक्षा सोसायटी, आर. जी. बाबाईया आर्ट्स, एलबी- लखोडिया कोपर्स एण्ड आर बीजी सर्विस कलेज, जलाना- 431203, महाराष्ट्र।	-वही-	2,35,256	50 अनौ-शिक्षे	
18	कागल शिक्षा सोसायटी, कागल जिला, कोल्हापुर।	-वही-	199802	50 अनौ-शिक्षे	
19	पार्थ विद्या प्रसारक प्रेस, अहमदनगर।	-वही-	3,59,200	50 अनौ-शिक्षे	
100	संस्कृति संवर्धन प्रेस, शारदा नगर, ताल बालोली, जिला नंदेड-431731, महाराष्ट्र।	-वही-	1,20,040	50 अनौ-शिक्षे	
101	सत कबीर शि. प्रसारक प्रेस, कैलाश निवास, घाटी, वि. औरंगाबाद, महाराष्ट्र।	-वही-	8 50,905	100 अनौ-शिक्षे	
102	सती प्रता शिक्षण संस्था, 11, डेक्कन नगर, कामला रोड, नागपुर-440025, महाराष्ट्र।	-वही-	2,39,622	50 अनौ-शिक्षे	
103	श्री स्वर्ण शिक्षण संस्था, एम्पेक, नागपुर।	-वही-	2,15,501	50 अनौ-शिक्षे	
104	श्री तेजय गोपी शिक्षण प्रसारक प्रेस, चिमलागोन, केवलाठीडा, ताल-चिचूर, वि. परभनी, नागपुर।	-वही-	1,80,450	25 अनौ-शिक्षे	
105	श्री चारु-जीके मने शिक्षण प्रेस, अम्बेस जिला, ता. इटकनीगले, कोल्हापुर।	-वही-	1,97,385	50 अनौ-शिक्षे	
106	विदर्भा आदर्श शिक्षण समिति, केवलागुण ह्यूटी रोड, सीता कुटी, नागपुर, महाराष्ट्र।	-वही-	1,19,896	25 अनौ-शिक्षे	

1	2	3	4	5
107.	योगेश्वरी एजुकेशन सोसायटी, अन्धबाडीगी-431517, चिला बीड, महाराष्ट्र।	-वही-	1,03,989	50 अनौ-शि-के-
108	महापट्ट नागेश्वरगिऱ्या सेवा संघ, यदसी ता- कल्याणपुरी, जिला परभनी।	-वही-	1,19,134	25 अनौ-शि-के-
109.	धजहरि छत्रपति शाहू शिक्षण, प्रसारक मंडल, तुलुदभवन रोड, जिला अहमदनगर।	-वही-	1,79,735	25 अनौ-शि-के-
110	सेवाधाम ट्रस्ट, मार्फत मनोज बिलिन्क-1148, सदरविाव पथ, पूणे।	-वही-	1,83,307	50 अनौ-शि-के-
111	शिक्षण प्रसारक मंडल, मानेबस्ती, माघे, जिला सोलापुर्।	-वही-	1,20,300	25 अनौ-शि-के-
112	राहुल एजुकेशन सोसायटी, शाल्मी नगर, कोल्हापुर्, महाराष्ट्र।	-वही-	1,17,803	25 अनौ-शि-के-
113	भायवन कुशात रोग निर्मूलन सस्था, जम्बूलधाम, ता- चिमुर्, जिला चन्द्रपुर्, महाराष्ट्र।	-वही-	2,53,350	50 अनौ-शि-के-
114	अहिल्या देवी हल्कर स्मरक सस्था, ता- प्रसाद, जिला यावतभल, महाराष्ट्र।	-वही-	2,52,530	50 अनौ-शि-के-
115	श्रीनाथ शिक्षण प्रसारक मंडल 3165, तनेजा चौक, पवधामपुर्, जिला सोलापुर्, महाराष्ट्र।	-वही-	1,19,088	25 अनौ-शि-के-
116	जवाहरलाल नेहरू शिक्षण प्रसारक मंडल, उमावदारी, ता- मुळंड, जिला नंदेद, महाराष्ट्र।	-वही-	3,59,473	75 अनौ-शि-के-
117	शिक्षा और युवक सेवा अकादमी 917/25, गेणशावाडी पूणे, महाराष्ट्र।	-वही-	1,03,651	25 अनौ-शि-के-
118	सामुदायिक स्वास्थ्य अनुसधान प्रतिष्ठान, B4-ए आर-जी- थडानी मार्ग, कोरली बम्बई-400018, महाराष्ट्र।	-वही-	1,86,304	ई-एण्ड आई-
119.	शैक्षिक सुधार और परिवर्तन सोसायटी, 810 गोरा पार्क 15 बोट क्लब रोड, पूणे-411001	-वही-	2,57,460	ई-एण्ड ए-
120	देवगिरि शिक्षण प्रसारक मंडल, डा० जी०पी० गायकवाड, प्लोर नं०-12, वार्ड नं०-11, आरतीन कस्तीमी कदरवाड, परभनी, महाराष्ट्र।	-वही-	2,66,100	100 अनौ-शि-के-
121	समग्र उन्नति शिक्षण संघ, कलामनेर (खुर्द) ता- कान्हा, जिला नंदेद, महाराष्ट्र।	-वही-	1,19,829	25 अनौ-शि-के-
122	संजय गांधी विरघा संघ, उपरी ता- धोकन, जिला नंदेद (महाराष्ट्र)	-वही-	126570	25 अनौ-शि-के-

1	2	3	4	5	6
123	आवेशी पब्लिक मेरीटबल ट्रस्ट, बम्बई।	-वही-	300000	ई० एफ आई	
124	मणिपुर व्यावसायिक संस्थान, इम्फाल।	-वही-	132790	50 अनौ-शि०के०	
125	मणिपुर बैंगलिया तथा किमान विकास सघ, पोम्बा नं०-6, इम्फाल-795001, मणिपुर।	-वही-	132790	50 अनौ-शि०के०	
126	आचार्य हरिहर विश्व सदन, सत्यबाडो, ए टी/पी ओ सखीगोपाल, जिला पुरी, ओडीसा।	-वही-	371928	100 अनौ-शि०के०	
127	आर्चलिका कुमेश्वर शक्ववाटिका ससद ए टी/पी ओ कन्यास, जिला पुरी, उड़ीसा-752017	-वही-	352609	50 अनौ-शि०के०	
128	अनोदय चेतना मंडल, ए टी पी ओ बायकद वाया मोराट जिला मधुप्रभज, उड़ीसा।	-वही-	593010	100 अनौ-शि०के०-डी आर यु	
129	अनोदय चेतना केंद्र सकटपालिका पोस्ट काडीद जिला कुझ उड़ीसा-758023	-वही-	224217	100 अनौ-शि०के०-डी आर ओ	
130	अनोदय मेधा केंद्र एमचंडपुर, पोस्ट पुनबभन ड्राग नालाबो, जिला कटक-754104 उड़ीसा।	-वही-	198936	50 अनौ-शि०के०	
131	बागदेवी क्लब मकटपुर ड्रा० जानहपका ड्राग बौद्ध, जिला फुलबनी, उड़ीसा।	-वही-	271814	50 अनौ-शि०के०	
132	बनबासी सेवा समिति, डा० बालीगुडा, जिला फुलबनी, उड़ीसा-762103	-वही-	360120	50 अनौ-शि०के०	
133	बनदेवी सेवा सदन कबीरचंदनगर, जिला गजप, उड़ीसा-761104	-वही-	234840	50 अनौ-शि०के०	
134	बापूजी पाथागर डा० मुख, जिला बोलागिरि, उड़ीसा।	-वही-	257190	50 अनौ-शि०के०	
135	भागवत पाथागर, भोलामाफली जिला बोलागिरि, उड़ीसा।	-वही-	254652	50 अनौ-शि०के०	

1	2	3	4	5	6
136	पैरावी क्लब, कुसमपडा, डा० हाडनपडा, द्वारा नावायण, जिला पुरी, उड़ीसा।	-वही-	212135	50	अनौ-शि-के०
137	विद्युत क्लब, हन्दीपाडा, डा० नावपु, जिला पुरी, उड़ीसा।	-वही-	161280	100	अनौ-शि-के०
138	मोनापानी जुबक, बुटपोडुगोडी, डा० मोतियागढ, जिला मयूरभंज, उड़ीसा।	-वही-	120040	50	अनौ-शि-के०
139	सेन्टर फार अपलिफ्टमेंट एण्ड लोवर इन्फ्रम (कन्स्ट्र), चोकुलाड, जिला कटक-754422 उड़ीसा।	-वही-	377838	50	अनौ-शि-के०
140	सेन्टर फार युथ एण्ड इन्टिग्रेटेड डिबलपमेंट, पोन्डा न० 30, बमोलमाही उडिया मठ लेन, डा० और जिला पुरी-752001, उड़ीसा।	-वही-	119040	50	अनौ-शि-के०
142	सेन्टर फार युथ एण्ड स्पोर्ट्स डिबलपमेंट, 65, सत्यनगर, धुवनेश्वर।	-वही-	1522398	200	अनौ-शि-के०, डी० आर० यु०
143	कटक जिला आदिवासी हरिजन सेवा संस्कार योजना छाता, डा० चन्द्राकडा, जिला कटक-753101, उड़ीसा।	-वही-	240080	50	अनौ-शि-के०
144	धक्कोडा पुष्पक सघ डा० धक्कोडा, जि० कुझर, उड़ीसा-758049	-वही-	376356	100	अनौ-शि-के०
145	फेल्सोबाय, पुरन बाजार, भादसक, जिला बालासोर, उड़ीसा-756100	-वही-	163715	50	अनौ-शि-के०
146	गांधी सेवाश्रम, ईश्वरालाल शिशु धवन, डा० जालेश्वर बालासोर उड़ीसा।	-वही-	240300	100	अनौ-शि-के०
147	गनिया उन्नयन समिति, डा० गनिया, जिला पुरी, उड़ीसा-752085	-वही-	252360	50	अनौ-शि-के०
148	धुमुसाय महिला संगठन डा० जौ सदयगिरि, जिला फूलबनी, उड़ीसा।	-वही-	352392	100	अनौ-शि-के०
149	गोपीनाथ जुवा सघ, अलीसोसमन डा० दादा, द्वारा बाली पटना, जिला पुरी, उड़ीसा-752102	-वही-	207322	50	अनौ-शि-के०

1	2	3	4	5	6
150	ग्राम मंडल पंचायत मुं/पो: बुरिसर जिला बोलंगीर, उड़ीसा।	-वही-	477186	100	अनौ-केन्द्र
151	होयना लेओरी रिसर्च ट्रस्ट पोस्ट बैंग नं० १, भुनिपुडा जिला कोणपुर उड़ीसा।	-वही-	660746	100	अनौ-केन्द्र
152	सेकेड रूरल विकसयन एंड डिवाइस रि० सर्विस, ओ०एस०पी० रोड, गाधीनगर पद्मागढा, जि० कोणपुर उड़ीसा-765001	-वही-	309949	100	अनौ-केन्द्र
153	इटरनेशनल इन्डिसेंसी डिबेन्चान मूवमेंट मुं बिदामासी (सोबानिया नगर) पो०आ० कटक (उड़ीसा)	-वही-	396548	100	अनौ-केन्द्र
154	बांग्लाक श्रमिक संगठन मुं/पो: छारियान-766107 जि० कलहाडी, उड़ीसा।	-वही-	120040	50	अनौ-केन्द्र
155	जन कल्याण समाज, मुं गोटीबाई, पो० आ० चापक्य जि० पुरी-उड़ीसा	-वही-	11092	100	अनौ-केन्द्र
156	जयती पंचायत, जुआपडा जि० गजाम-761011, उड़ीसा।	-वही-	383486	100	अनौ-केन्द्र
157	जयती पंचायत, मुं राजपडा पो०आ० भुवनेश्वर जि० कटक-755005, उड़ीसा।	-वही-	374366	100	अनौ-केन्द्र
158	ज्योतिर्वीर अहिरा समिति बडागाव केन्द्रपडा जि० कटक, उड़ीसा।	-वही-	600549	100	अनौ-केन्द्र
159	लोकप्रिय, मुं/पो० श्रीकांतपुर जि० बालासोर, उड़ीसा।	-वही-	443383	100	अनौ-केन्द्र
160	एच०ओ० कल्याण मुं/पो० कलहाडी वाया बाधमबाई जि० पुरी-752061, उड़ीसा।	-वही-	325425	50	अनौ-केन्द्र
161	मंडल पोखरीपुष्पक सभ मुं/पो० घन्टारी, वाया बाधुदेवपुर जि० बालासोर, उड़ीसा।	-वही-	210050	50	अनौ-केन्द्र
162	नवज्योति, पो० गुरुगाम बाया कलहाडी जि० कटक-उड़ीसा-754022	-वही-	188579	50	अनौ-केन्द्र
163	नेताजी युवक सभ बालीसेखरी, मुं/पो० परमानंदपुर वाया अखुआर, जि० बालासोर-756122 उड़ीसा।	-वही-	220512	50	अनौ-केन्द्र
164	नलीचल सेवा समिति बेनोगाव (कनस) जि० पुरी-752017 उड़ीसा।	-वही-	366092	100	अनौ-केन्द्र
165	ओल्ड लुकेला एजुकेशन सोसायटी मुं बालीसेखरी, पो० लुकेला जि० बालासोर-769016 उड़ीसा।	-वही-	395300	100	अनौ-केन्द्र
166	फली मंगल युवक सभ मुं नयामारी, पो० देवली पिपारुली, जि० पुरी उड़ीसा-752064	-वही-	224477	50	अनौ-केन्द्र

1	2	3	4	5	6
167	पालीश्री मु०/पो० बासीपाट वाया बांका जि० कटक उड़ीसा।	-वही-	240080	50	अनौ-केन्द्र
168	पीपुल्स इन्स्टीट्यूट आफ पार्लिसमेंटरी ए० रिसर्च मु०/पो० महिमागढ़ी जि० भेनकनाल, उड़ीसा-759014	-वही-	363598	100	अनौ-केन्द्र
169	प्रगति पंचागाव मु० बेलागुवा जि० गजाम, उड़ीसा-761119	-वही-	256800	50	अनौ-केन्द्र
170.	राधानाथ पंचागाव मु०/पो० सोरो जि० बालासोरी, उड़ीसा-756045	-वही-	210040	50	अनौ-केन्द्र
171	रामजी युवक सभ पो० सादीपल्ली जि० बोलागोरी, उड़ीसा-767065	-वही-	476173	100	अनौ-केन्द्र
172	रूरल डेवलपमेंट सोसायटी मु० कलिया पो० के० बी० दण्डा वाया महाकालपाप जि० कटक, उड़ीसा।	वही	549411	100	अनौ-केन्द्र
173.	रूरल एजुकेशन एंड एक्सन फार चेंज जामाया, खादगिरी भुवनेश्वर, उड़ीसा-757030	-वही-	514062	100	अनौ-केन्द्र
174	रूरल वूमन डेवलपमेंट सर्विस सेंटर मु०/पो० खालाटी, वाया अगुल जि० भेनकनाल, उड़ीसा-759001	-वही-	226733	50	अनौ-केन्द्र
175	समग्र विकास परिषद मु०/पो० बालीपाल जिला बालासोरी, उड़ीसा-756026	-वही-	203014	50	अनौ-केन्द्र
176	सामाजिक सेवा सदन ग्राम धाजीकुसम पो० महिषापट जि० भेनकनाल उड़ीसा	-वही-	440221	100	अनौ-केन्द्र
177	सर्वोदय समिति, गांधी नगर जि० भूपुरगंज, उड़ीसा-757030	-वही-	210480	50	अनौ-केन्द्र
178.	सोसायटी फार डेवलपमेंट पो० कुलियागा जि० भूपुरगंज उड़ीसा-757030	-वही-	351606	100	अनौ-केन्द्र
179	सोसायटी फार हेल्थ एजुकेशन - एंड डेवलपमेंट कालेज रोड, रायगढ़ा जि० कोरपुट, उड़ीसा-765001	-वही-	386508	100	अनौ-केन्द्र
180	श्री सत्य साई सेवा समिति मु०/पो० देवभुवनपुर वाया बालीसकल जि० सुंदरगंज-770015 उड़ीसा।	-वही-	300100	50	अनौ-केन्द्र
181	श्री श्री शारदेबाई पंचागाव मु० खारदा पो० तुरा, जि० बोलागोरी, उड़ीसा-767030	-वही-	127544	50	अनौ-केन्द्र

1	2	3	4	5	6
182	सुपदा महावात सेवा सदन पु/पोन्जी- उदयगिरी वि० फलवानी, उड़ीसा।	-वही-	717359	100	अनौ० केन्द्र
183	स्वायं विवेकानन्द इन्स्टीट्यूट आफ स्टेशल वर्क एंड प्लान्स सर ओरियल रोड जिला कालिन्दी	-वही-	893059	100	अनौ० केन्द्र
184	टैगोर सोसायटी फार रूरल डेवलपमेंट 101, बापूजी नगर भुवनेश्वर-751009 उड़ीसा	-वही-	1160325	300	अनौ० केन्द्र
185	डक्कल नक्कीवन घटल पो० ओ० अगुल जिला धनकुमनल, उड़ीसा	-वही-	415768	100	अनौ० केन्द्र
186	डक्कलपिंग सेवा सघ पो० ओ० बडालिपयपुर जिला पुरी, उड़ीसा	-वही-	126959	50	अनौ० केन्द्र
187	लिकस एन-5/11, आचार्य बिहार भुवनेश्वर-751013 उड़ीसा	-वही-	235468	50	अनौ० केन्द्र
188	विवेकानन्द पाली अग्रामो प्रतिष्ठान, कालिहलपल्ली, गौड़भा जिला सम्बलपुर-768222 उड़ीसा	-वही-	448864	100	अनौ० केन्द्र
189	बैलकस (कम्प्यूनिट वेल्फेयर एंड एनरीचमेंट सोसाइटी) जी-एस० महाधना भवन विवेकानन्द मार्ग, भुवनेश्वर उड़ीसा-751002	-वही-	201372	50	अनौ० केन्द्र
190	नारी शक्ति समास कुञ्जी महल पो० ओ० जिला पुरी उड़ीसा-754015	-वही-	151795	50	अनौ० केन्द्र
191	अग्रामो पो० आ० खासीपुर, उड़ीसा-765015	-वही-	962949	100	अनौ० केन्द्र - डी० आर० यू०
192	सोसायटी फार ह्यूमन रिसोर्सिस एंड इकनॉमिक डेवलपमेंट मण्डीमहल, जिला सुलबानी, उड़ीसा	-वही-	601235	100	अनौ० केन्द्र
193	बबानी शक्ति क्लब रागपुर पो० ओ० सिमौर वि० पुरी उड़ीसा	-वही-	407769	50	अनौ० केन्द्र
194	नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ स्टेशल वर्क एंड स्टेशल साइस सूर्य नगर भुवनेश्वर उड़ीसा-751003 उड़ीसा	-वही-	467416	100	अनौ० केन्द्र
195	युवाभ्युत्थि क्लब ग्राम कुम्भडील पो० ओ० नायरी जिला पुरी उड़ीसा-752029	-वही-	124923	25	अनौ० केन्द्र
196	आचार्यिक बरदेव बालनदी एवरेसी पो० ओ० आलकुम्भ नौगाव वाया प्रीतिपुर कटक उड़ीसा	-वही-	113714	25	अनौ० केन्द्र
197	सुधर्म महिला समिति पो० ओ० पस्तलीपेक वाया कुडुग जिला कटक, उड़ीसा	-वही-	236460	50	अनौ० केन्द्र

1	2	3	4	5	6
198	यूथ ऐसोसिएशन फार रूरल रिक्लडकेशन पो० ओ० बोड़ना, जि० बेनकानाल उडीसा-7559127	-वही-	305146	50	अनौ० केन्द्र
199	धर्मनन्दन युवक सभ सीधीगामी पो० ओ० धारुअकिही, विना मुन्दरगाड उडीसा	-वही-	116072	50	अनौ० केन्द्र
200	रुचिका स्कूल 14, फोरेस्ट पार्क धुबनेश्वर-751009 उडीसा	-वही-	115421	25	अनौ० केन्द्र
201	बालैन्दरी एसी० फार रूरल रिक्लडकेशन एड एच० टैकनि० बोलकानी बरा दग कहाकालपाडा, जिला कटक उडीसा	-वही-	180969	50	अनौ० केन्द्र
202	समन्वित ग्राम्या उपायन समिति पो० ओ० जौ० दटपिंगी जिला फलबानी, उडीसा	-वही-	260915	50	अनौ० केन्द्र
203	लोक नायक क्लब पो० ओ० पटपुप बार्का जिला कटक, उडीसा-754008	-वही-	449803	100	अनौ० केन्द्र
204	बालभिकेश्वर जवक सभ जिला पुरी-उडीसा-752018	-वही-	272185	50	अनौ० केन्द्र
205	सेवा मंदिर, हिन्दुपुर ए० जौ०	-वही-	352000	छो० आर० यू०	
206	अजमेर एडल्ट एजुकेशन एसो० अजमेर ई० पो० आई० शास्त्री नगर एम्प्लेमेंटेशन विद्युत मार्ग, अजमेर-305006	-वही-	740360	100	अनौ० केन्द्र - डी० आर० यू०
207	भोलबाडा जिला एडल्ट एजुकेशन एसो० B/199, सिन्धु नगर, भोलबाडा-311001 राज०	-वही-	170951	100	अनौ० केन्द्र
208	भोक्का बेरीटेबल ट्रस्ट पो० ओ० भोक्काम (नागल कालान) जिला जुल, राज०	-वही-	425262	100	अनौ० केन्द्र
209	बीकानेर एडल्ट एजुकेशन एसो० ग्रौड शिक्षा भवन, सम्वती पार्क पो० बा० न० 28 बीकानेर-334001 राज०	-वही-	180463	50	अनौ० केन्द्र
210	गांधी विद्या मंदिर सदर शहर एजस्थान	-वही-	329024	100	अनौ० केन्द्र
211	ग्रामीण विकास विज्ञान समिति पो० ओ० मयकल, वाया प्रधनिया जि० जोधपुर, राजस्थान	-वही-	314543	100	अनौ० केन्द्र
212	जोधपुर एडल्ट एजुकेशन एसो० गांधी भवन, रेजीडेन्सी रोड जोधपुर एजस्थान	-वही-	218123	100	अनौ० केन्द्र
213	लोक शिक्षा संस्थान पी०-87, गंगोत्री बाजार जयपुर, एजस्थान	-वही-	222217	50	अनौ० केन्द्र
214	एजस्थान निधारील लोक शिक्षा फरिफर प्रताप नगर उदयपुर-313001, राज०	-वही-	248274	50	अनौ० केन्द्र
215	सेवा मंदिर, उदयपुर एजस्थान	-वही-	201392	100	अनौ० केन्द्र
216	बोस शिक्षा संस्थान, जयपुर	-वही-	553667	ई० एड० अर्ध०	

1	2	3	4	5	6
217	उजस्थान महिला विद्यालय ज्ञान मार्ग, गुलाब बाग के पास अदमपुर-313001	-वही-	255900	100	अनौ० केन्द्र
218	जिला एडवुट एजुकेशन एसो- 13-कलवार रोड, कोटा, राज्	-वही-	527000	100	अनौ० केन्द्र - डी० आर० यू०
219	वूमेन वालन्टी सर्विस आफ तमिलनाडु 19, ईस्ट सुपर टैंक रोड चैटपु मद्रास-60003	-वही-	477779	100	अनौ० केन्द्र
220	टैगोर एजुकेशन सोसायटी, त्रिबेन्द्रम-604001 जिला साठव आर्कोट तमिलनाडु	-वही-	475607	100	अनौ० केन्द्र
221	मिस्ट्री आफ दौ क्रास कान्फेरान बाबनोड त्रिवेन्दापुर-620001	-वही-	117570	50	अनौ० केन्द्र
222	जी० आर० डी० ट्रस्ट कलायकधीर मन्डन, अक्कनरी रोड कोयम्बटूर-641037	-वही-	755700	100	अनौ० केन्द्र
223	एसीरिएशन आफ मेरानल सर्विस चेनगायथी 316, एन० जी० ओ० कन्नोली चेनगायपट्ट-603001	-वही-	117850	25	अनौ० केन्द्र
224	कृष्णामूर्ति फाउंडेशन इंडिया #4 / 65, ग्रीन वेल्थ रोड मद्रास-600028 तमिलनाडु	-वही-	428071	ई० एड आई०	
225	वूमेन्स इंडिया एसो- 43, ग्रीनवेल्थ मद्रास-600028	-वही-	235840	50	अनौ० केन्द्र
226	मधर माला मेदरम बी० बटुगपलम बन्डी प्लोथम पो० ओ० कुडाली साठव आर्कोट-67004	-वही-	405612	50	अनौ० केन्द्र
227	लीग फर एजुकेशन एंड डिवलपमेंट 680 लॉथिपपागो मुयू एस० टी० के० के० नगर त्रिवेन्दापुर-600021	-वही-	240080	50	अनौ० केन्द्र
228	बाल कल्याण केन्द्र मिन्ना जिला-देवरिया	-वही-	255900	100	अनौ० केन्द्र
229	मवात्र कल्याण शिक्षा संस्थान ग्राम कनवाथी पो० ओ० नवलटोडन बि० देवरिया	-वही-	133050	25	अनौ० केन्द्र
230	आदर्श जनता शिक्षा समिति ग्रा० और पो० ओ० पी०डी, तहसील कलछना जिला इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	-वही-	445800	100	अनौ० केन्द्र
231	अमेठी महिला लैब्रिक सेवा समिति अमेठी, मुल्तीनपुर, उत्तर प्रदेश	-वही-	102299	500	अनौ० केन्द्र
232	बनवारी सेवा आश्रम पोर्निन्दपुर (बाघा तुरी) शोनमध, उत्तर प्रदेश	-वही-	1807500	500	अनौ० केन्द्र + डी० आर० यू०
233	जन कल्याण शिक्षा समिति पाथानगर फैजला नगर जिला देवरिया, उत्तर प्रदेश	-वही-	883883	100	अनौ० केन्द्र
234	लोक दि०-रा संस्थान 49, मधुबनी पोथी मार्ग, इलाहाबाद- 211001, उ०प्र०	-वही-	4,24,053	100	अनौ० पर्यावरण शिक्षा केन्द्र

1	2	3	4	5
235.	ग्रामोद्योग सेवा संस्थान ग्रामा, मुंका हॉस्पिटल रोड, खुर्जा, उ०प्र०	-वही-	4,41,969	100 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र
236	सर्वदलीय मानव विकास केन्द्र बहजोई, मुणदाबाद, उ०प्र०	-वही-	3,27,486	100 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र
237	सर्वांगीण शिक्षा सदन समिति रेलवे स्टेशन रोड, शिकोहाबाद (मैनपुरी) उ०प्र०	-वही-	2,40,080	50 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र
237	सर्वांगीण शिक्षा सदन समिति रेलवे स्टेशन रोड, शिकोहाबाद (मैनपुरी) उ०प्र०	-वही-	2,40,080	50 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र
238	युवक भगल हल पुजेपुरी, 274, आवास विकास कॉलोनी जिला उन्नाव, उ०प्र०	-वही-	3,52,050	50 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र
239	न्यू पब्लिक स्कूल समिति 261/56, नन्दन महल रोड लखनऊ, उ०प्र०	-वही-	1,20,258	25 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र
240	उ०प्र० राणा बेनी प्राथम जन कल्याण समिति गुलाब रोड पुपबरेली, उ०प्र०	-वही-	3,29,623	100 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र
241	जन जाति विकास समिति रेलवे स्टेशन रोड, रोबर्ट गज, पिर्जीपुर, उ०प्र०	-वही-	2,40,080	50 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र
242	नवजागृति समाज विकास संस्थान 25, मोहल्ला खेडा, फिरोजाबाद, आगरा	-वही-	1,13,119	25 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र
243	लिट्रेसी हाउस, डॉकमर आलमबाग, लखनऊ- 226005, उ०प्र०	-वही-	28.37 067	ई० एड आई०
244	समाजोत्थान एव शिक्षा प्रचारिका संस्थान दावेरापुर, मवाना, मेरठ	-वही-	1,10,428	25 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र
245	महिला उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र 261/4, सलिक गज रोड, मुन्दीगंज, इलाहाबाद	-वही-	1,19,780	25 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र
246.	अखिल भारतीय बाल देखभाल एव विकास समिति, आजमगढ़, उ०प्र०	-वही-	4 45,800	100 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र
247	इशान्द अकादमी शाहपीर गेट, मेरठ, उ०प्र०	-वही-	1,26,025	25 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र
248	बीचिसल बाबा सहैब डॉ० अम्बेडकर स्मारक समिति छिन्तापुर लखनऊ, उ०प्र०	-वही-	2,52,773	50 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र
249	अदरश सेवा समिति 326/1, साकेत कॉलोनी स्ट्रीट नं० मुन्सफ्फर नगर (उ०प्र०)	-वही-	1,32,790	50 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र
250	आशा सिंह पूर्वा माध्यमिक विद्यालय सम्राज्ञी नैपुडा डॉकमर बिलभान, जिला हरदोई उत्तर प्रदेश	-वही-	1,33,050	50 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र
251	गंगा रानी कलिका विद्यालय रामपुर बैजू छिन्मन, फर्रुखाबाद, उ०प्र०	-वही-	2,65,580	50 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र

1	2	3	4	5	6
252	राहीद देवेरियल सोसायटी ई- 1698, एजारी पुरम, लखनऊ- 226017	-बाही-	5,11,800	100 अनैपचारिक शिक्षा केन्द्र	
253	सार्वजनिक शैक्षिक संस्थान, गाँव-अलीपुर, डाकघर संस्थान, जिला हरदोई, उ०प्र०	-बाही-	1,33,050	25 अनैपचारिक शिक्षा केन्द्र	
254	उर्मिल समग्र कल्याण समिति, पुराना बोझिग हाउस, हरदोई	-बाही-	1.33,050	25 अनैपचारिक शिक्षा केन्द्र	
255	बर्दवान जिला साक्षरता समिति पश्चिम बंगाल	-बाही-	3.52.000	डॉ० आर०यू०	
256	इसान स्कूल (तर्मिनी गिरान क्वेर) डाकघर- गिरानगंज, पूर्णिया, बिहार	-बाही-	3,58,000	डॉ० आर०यू०	
257	पश्चिम बंगाल खेडिया स्मर कल्याण समिति-बाही- गाँव और डाकघर- एनैपचारिक पश्चिम बंगा	-बाही-	1,53,540	60 अनैपचारिक शिक्षा केन्द्र	
258	बंगाल सोशल सर्विस लीग 1/6, राजा दीनेन्द्र स्ट्रीट, कलकत्ता- 700009, पश्चिम बंगाल	-बाही-	1.56.100	100 अनैपचारिक शिक्षा केन्द्र	
259	कलकत्ता अर्बन सर्विस क्वेत्रेटियम, 16, स्टार स्ट्रीट कलकत्ता, प० बंगाल	-बाही-	5.50,200	200 अनैपचारिक शिक्षा केन्द्र	
260	टैगोर सोसायटी फॉर क्लरल डवेलपमेन्ट, 14, खुदीराम बोस रोड, 24- परगना, कलकत्ता- 6 प० बंगाल	-बाही-	6,23,718	200 अनैपचारिक शिक्षा केन्द्र	
261	श्री रामकृष्ण मत्स्यनन्द आश्रम गाँव बिधुमपुर, डाकघर बरभिट्टा, रेड- वे सलाहक, जिला 24 परगना (उत्तर) प० बंगाल	-बाही-	7.17,509	300 अनैपचारिक शिक्षा केन्द्र	
262	इस्टीरलुट ऑफ पीलटेलिकल एण्ड एन्प्लेनानल रिसर्च 27, सर्विस एवेन्यू, कलकत्ता, प० बंगाल	-बाही-	2,72,500	ई० एड आई०	
263	विलेज वेल्फेयर सोसायटी डाकघर-पल, हावड़ा	-बाही-	2,14,738	50 अनैपचारिक शिक्षा केन्द्र	
264	पब्लिक सोसायटी अफ इंस्टीट्यूट्स कलकत्ता	-बाही-	3,57,490	ई० एड आई०	
265	मिदनपुर सर्वेधायक गेग अभिधाय समिति, मिदनपुर, प० बंगाल	-बाही-	3,09,044	डॉ० आर०यू०	
266	अभिला आरतीय समन्वयन समिति ए-3/51 एन०आई०जी० रोड सेक्टर- VII नई दिल्ली- 110034	-बाही-	4,80,089	100 अनैपचारिक शिक्षा केन्द्र	
267	पी०एच०डी० क्लरल डवेलपमेन्ट, पी०एच०डी० हाउस, धम्म फ्लैट, पुश्याई खेल गाय के सप्पने, नई दिल्ली- 110016	-बाही-	4,08,496	100 अनैपचारिक शिक्षा केन्द्र	

1	2	3	4	5	6
268	पीपुल्स इस्टेड्यूट फॉर डवेलपमेन्ट एण्ड ट्रेनिंग, 4-ए, शाहपुर जट, नई दिल्ली- 110016	-वही-	1,25,392	200	अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र
269	नेहरू बाल समिति ई-63, साकथ एक्सप्लोरेशन पार्क-1, नई दिल्ली- 110049	-वही-	1,86,610	50	अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र
270	लेडी इडिन कॉलेज, सिकन्दरा रोड, नई दिल्ली	-वही-	5,26,205	ई० एड आर्ष०	
271	बेसिक शिक्षा परिषद् इलाहाबाद	-वही-	64,23,000	ई० एड आर्ष०	
272	दिगान्त शिक्श एव खेलकूद समिति, जयपुर	-वही-	1,48,176	ई० एड आर्ष०	
273	सिद्ध कानु ग्राम उन्नयन समिति पहेरवाटी, पश्चिम बंगाल	-वही-	2,06,944	ई० एड आर्ष०	
274	प्रज्ञाया नेशनल बेसिक एड्युकेशनल इस्टेड्यूट, पुरुलिया, प० बंगाल	-वही-	3,60,700	ई० एड आर्ष०	
275	याग इंडियन अघेरी (प०) बम्बई	-वही-	1,15,398	25	अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र
276	चेतना-विकास, गोपुरी बर्षा एम-एस०	-वही-	2,37,000	डी०आर०व्यू	
277	गांधी सेवा आश्रम जलालपुर बाजार सारण, बिहार	-वही-	1,53,540	60	अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र
278	आत्मरंजना महिला समिति (सेवा) खादीग्राम मुंगेर, बिहार	-वही-	2,55,900	100	अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र
279	श्रीनिवास महिला मण्डली दर्सी अग्रहरम मधुपुर मण्डल जिला प्रकाशन, आन्ध्र प्रदेश	-वही-	1,32,790	50	अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र
280	सेंट जेवियर हाई स्कूल पोन्बोर्न न० 30 चार्ल्स जिला सिंहभूम, बिहार	-वही-	2,55,200	100	अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र
281	अनंदि वेल्गेलर संगम सत्राती स्ट्रीट तिरुवनेमेल, तिरुचि- 620095	-वही-	2,19,112	100	अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र
282	माध्यम सत्यकथ शिक्षा केन्द्र, गोवर्धपुर, उ०प्र०	-वही-	1,32,790	50	अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र
283	तिलक शैक्षिक समिति, 69-ए, तिलकनगर इलाहाबाद	-वही-	1,20,058	25	अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र
284	सर्वोदय शिक्षा सदन समिति रेलवे स्टेशन रोड, शिकोहाबाद, उ०प्र०	-वही-	2,40,080	50	अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र
285	जवाहर सेवा सदन, पटुना, चिरौडीगढ़, उत्तराखण्ड	-वही-	1,46,150	30	अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र

1/04/90 से 31/03/91 की अवधि के दौरान निम्नी संस्थाओं/संगठनों/वैयक्तियों को संस्वीकृत सहायक अनुदान जहाँ कुल मुक्त किया गया अनुदान (आवर्ती) 25,000 अथवा कुल मुक्त किया गया अनुदान (अनावर्ती) = 75,000 हों, को दर्शाने वाला विवरण
 मन्त्रालय:— मानव संसाधन विकास मन्त्रालय
 विभाग:— शिक्षा विभाग

क्र.सं.	एजेंसी/संगठन का पते सहित नाम	संगठन के सक्षित कार्यकलाप	1990-91 में सहायक अनुदान की राशि	किस प्रयोजनार्थ अनुदान प्रयुक्त हुआ	कैफियत
1	2	3	4	5	6
II	श्रीव शिक्षा	सभी स्वेच्छिक एजेंसियाँ निम्नलिखित कार्यकलापों में से किसी एक अथवा अन्य में लगी हुई हैं 1 बालबाड़ी/आयनबाड़ी चलाना 2 स्कूल/कमलोन को चलाना 3 आई० सी० डी० एस० केन्द्र का चलाना 4 बच्चों के टीकाकरण 5 टेलरिंग पाठ्यक्रमों को चलाना 6 टैक्सा/तकनीकी संस्थानों को चलाना			
1	श्री गौरी ब्रह्मद्वै शैक्षिक सोसायटी, गोरान टोला पोस्ट, अमरगढ़ जिला, आन्ध्र प्रदेश-515231	-वही- कुल		48,2329 70,000 1,11,239	प्रो-शि-के० ज-शि-नि०
2	सेवा मन्दिर, सि-डुपु, जिला अमरगढ़, आन्ध्र प्रदेश-515212	-वही- कुल		2,80,227 5,13,288 7,93,515	प्रो-शि-के० ज-शि-नि०
3	पयलसीमा सेवा समिति न० 9 ओल्ड हुजूर क्वार्टर, लिफ्ट-517501, जिला बिजूर एन्धी-	-वही- कुल		2,81,227	प्रो-शि-के०
4	बालनट्टेन एन्ड कम्पनिज, बलपमेट सोसायटी, 13/73-सी, बिजूर रोड, धमावोटी, कृष्णा-516269 आन्ध्र प्रदेश	-वही-		3,08,400	प्रो-शि-के०
5	वीसस इन्डिया, 33/379, अमरा रोड, मिस्त्राट्टेरे, गुन्टूर जिला-522616, आन्ध्र प्रदेश	-वही-		1,80,000	प्रो-शि-के०
6	ग्राम नव निर्माण समिति, गृह सं० 4-2/ए, इन्डिरा नगर, गुन्टूर-505468, कापिथनगर, जिला आन्ध्र प्रदेश	-वही-		94,512 35,000	प्रो-शि-के० ज-शि-नि०
7	धर्मोन्नत महिला संगम, गृह सं० 12-14, ... जिला, आन्ध्र प्रदेश-508211	-वही-		1,20,600	प्रो-शि-के०
III	कुल एन्टरप्राइज एन्ड सी-एन सपोर्ट सेन्टर धर्म लक्ष्मीपुरम, कोयल (एन-ओ-1) श्री-गुन्टूर जिला (आन्ध्र प्रदेश)	-वही-		1,17,012	प्रो-शि-के०

1	2	3	4	5	6
9	नेताजी युवा सघ, वाटपामु, फुलाकोटा मण्डल श्रीकाकुलम जिला, आन्ध्र प्रदेश-532440	-वही-		1,80,000	प्रो-शि-के.
10	महिला मण्डली, राजघ, श्रीकाकुलम जिला-532127 आन्ध्र प्रदेश	-वही-		1,80,000	प्रो-शि-के.
11	चैतन्य यूथक्लब, मुलुग, कृष्णा कलानी-506343 वांगल जिला, आन्ध्र प्रदेश	-वही-		90,000 31,500	प्रो-शि-के. ज-शि-नि.
12	गुडु स्मार्टिन्स रुल डेवलपमेंट सोसाइटी छायापेटा, साउथ कंबिन लाइन नौदावावोली, आन्ध्र प्रदेश-534301	-वही-		94,512 35,000 1,29,512	प्रो-शि-के. ज-शि-नि.
13	कृष्णहैसिड रुल ऑपरेशन सर्विस सोसाइटी (क्वाम), 1-69 ओरुपुरी नचयम, हेदराबाद-501507 (आन्ध्र प्रदेश)	-वही-		3,02,357 2,62,500	प्रो-शि-के. ज-शि-नि.
14	आन्ध्र महिला सभा कालेज कैम्पस युनिवर्सिटी रोड, हैदराबाद-500007	-वही-		5,64,857	प्रो-शि-के.
15	अकादमी आफ हल्ट डेवलपमेंट एण्ड रिसर्च, गुडामली पोस्ट वाया (नागला चेरेकुपल्ली मण्डल गुन्डूर जिला आन्ध्र प्रदेश-522259	-वही-		6,34,080 1,05,000 8,89,480	प्रो-शि-के. ज-शि-नि.
16	अलग झारी तरुण सघ विलेज अलगझारी, डाकखाना राजघाट वाया मंगलदाई, दारुग जिला, आसाम-784125	-वही-		1,27,500	प्रो-शि-के.
17	पापुला प्रीमियम यूनिट, हलकुपा, डाकखाना हालकुपा, (महामायस्त) जिला धुबरी, आसाम, पिन-78335	-वही-		1,36,300	प्रो-शि-के.
18	बैकवइतारे महिला समिति, डाकखाना बैकवटी, जिला गोलमकुडा, आसाम-783125	-वही-		1,20,041	प्रो-शि-के.
19	आसाम चारु मजदूर मल्टीमसर्स रोशाल प्रमोशन एन्ड प्रमोशन रंगपुर, टीआई डाकखाना राजघाट, वाया टीआई, जिला औरंगजेब आसाम-785630	-वही-		1,16,843	प्रो-शि-के.
20	ग्राम स्वराज परियोजना ग्राम तथा डाकखाना राजघाट जिला कचमरु, आसाम	-वही-		1,62,600	प्रो-शि-के.
21	ग्राम महिला समिति, ग्राम राजघाट	-वही-		10,24,431	टी.एन.टी.

1	2	3	4	5	6
35	समाज कल्याण मण्डल (बिहार) कटिपथा चक, डाकखाना केसरीपुर, जिला नालंदा, बिहार-801302	-वही-		14,50,000	टी एल सी
36.	भारतीय कला मन्दिर, भोइल्ला नवाटोली, डाल्टनगंज-822101, जिला पलामू, बिहार।	-वही-		1,80,000	श्री-शि-के
37	बिहार दलित विकास समिति डाकखाना बाढ़, जिला पटना, बिहार-803213	-वही-		1,57,000	श्री-शि-के
38	जोबिन्स इन्स्टीट्यूट आफ सोशल सर्विस, पुरुलिया रोड, डाकखाना बाक्स नं-7, दल रोही-834001 बिहार।	-वही-		5,390 2,69,250	श्री-शि-के श्री-आर-यू
39	निर्मली मखण्ड स्वयंसेवा संघ, डाकखाना भारतीयारो, जिला सदरमा, बिहार-852105	-वही-		9,50,000	टी एल सी
40	जे.पी. स्वयंसेवा सेवाश्रम, फोडिया चौक डाकखाना जोरपुल, जिला-समस्तीपुर (बिहार)-848505	-वही-		11,00,000	टी एल सी
41.	शिक्षा एवम् कला सर्वांगीण विकास गृहीय संस्थान, ग्राम तथा डाकखाना इन्धेला, जिला सरन, बिहार, पिन-841207	-वही-		1,27,500	श्री-शि-के
42.	आल्टेनेटिव फर इन्डिया डेवलपमेंट फर्टिलिजर्स स्ट्रीट, 4 कास्टमा कालोनी, बेसेन्ट नगर, मद्रास (तमिलनाडु)-60090.	-वही-		9,00,000 3,15,000	श्री-शि-के ज-शि-वि
43	जेबिपर्स चम्पारण, सेन्ट जैविपर्स हाई स्कूल, पोस्ट बाक्स नं-10, वाईबासा-833201, सिंहभूम जिला, बिहार	-वही-		12,15,000	श्री-शि-के
44	लोक धारती (बिहार) आदर्श नगर, धुनाथ पंच, सीतामढ़ी जिला, बिहार।	-वही-		3,20,000	श्री-शि-के
45.	इन्डियन सोसाइटी फोर कम्प्यूटरी एप्लीकेशन, मार्फत गुणधत्त निवासी,0, अहमदाबाद-380001	-वही-	कुल	94,512 42,000 1,36,512	श्री-शि-के ज-शि-वि
46.	गुणधत्त निवासी,0, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380001,	-वही-		32,55,000	ज-शि-वि
47	गुणधत्त स्टेट प्रोग्राम डिप्लोमा टूर, आशीर्वाद, 9 / बी, केराव नगर सोसाइटी, गुणधत्त पुल के समीप, अहमदाबाद-380027.	-वही-		6,30,00 4,23,000	के-मे. के डी आर यू
		कुल		10,53,000	

1	2	3	4	5	6
48	નૂતન ધાર્મી, 88-44-44 મકાન નં-385519, તાલુકા પાલનપુર, જિલ્લા અમરકાંઠા, ગુજરાત ।	-વહી-		3,20,000	પ્રૌશિકેન્
49	અનુભવ ધાર્મી-પ-ઇદર, ફોર્ટ રોડ, લાલ કાગર, ધર્મી-392001.	-વહી-		2,81,227	પ્રૌશિકેન્
49	ઇસ્ટીડ્સ પાર ફરલ ટેકોરોલી, ઇસ્ટ રોડર જી, અફિસ સ્ટોટ, ધર્મી-392001	-વહી-		1,26,350	પ્રૌશિકેન્
50	શિવશક્તિ કેલવની મથક, 40, હરીકૃષ્ણ સોસાઇટી, હકોર-386225, તાલુકા ધાસરા, જિલ્લા છાદા, ગુજરાત ।	-વહી-		1,26,350	પ્રૌશિકેન્
51	આનંદ તાલુકા યુવક મથક એસોસિયેશન, લક્ષ્મી નિવાસ, 25 અજંતા સોસાઇટી, આનંદ-388001, જિલ્લા છેદા ।	-વહી- કુલ		8,15,320 1,05,000 9,20,320	પ્રૌશિકેન્ જનશિક્ષણ
52	ધાસરા તાલુકા યુવક મથક એસોસિયેશન હકોર, ધાસરા તાલુકા જિલ્લા છાદા, પિન-386230	-વહી- કુલ		4,84,514 38,892 5,23,406	પ્રૌશિકેન્ જનશિક્ષણ
53	શ્રી માધ્યમ તાલુકા સેવા મંડળ માર્કેટ હોલ બિલ્ડિંગ વિદ્યાપીઠ આશ્રમ કાન્ધલા સમી જિલ્લા મેરુઆના-384245	-વહી-		1,80,000	પ્રૌશિકેન્
54	પ્રીયતી ધૌકેન્ બાળાઓ પૂર્વકેન્, 20, રોડર સોસાઇટી, કાન્ધલા-384001, જિલ્લા મેરુઆના, ઉત્તરી ગુજરાત ।	-વહી- કુલ		94,512 2,10,000 3,04,512	પ્રૌશિકેન્ જનશિક્ષણ
55	ધોળ સેવા મથક, દાહાદી જિલ્લા પંચમહલ, ગુજરાત-389001	-વહી- કુલ		9,00,000 2,62,500 11,62,500	પ્રૌશિકેન્ જનશિક્ષણ
56	રાજલી માધ્યમ પ્રુપ કેલવાનો મહલ રાજલી કાન્ધલાના ધોળી કમળ તાલુકા મોદાસા, જિલ્લા-અમરકાંઠા ।	-વહી-		1,27,000	પ્રૌશિકેન્
57	જન સેવા હાઈ કાન્ધલાના ચિત્રમ મહલ પુત્રો, તાલુકા, મોદાસા, જિલ્લા અમરકાંઠા 385346	-વહી-		1,18,574	પ્રૌશિકેન્
58	ગ્રામ સેવા સમાજ, કાન્ધલાના વાન્કલ, જિલ્લા સુરત-394430	-વહી-		2,14,512	પ્રૌશિકેન્
59	આનંદ નિકેતન આશ્રમ રાપુર (અમરકાંઠા), છોટા ડેવપુર, જિલ્લા વડોદરા-391740	-વહી-		17,97,100	પ્રૌશિકેન્
60	નવના કાન્ધલા સમિતિ, વસ મટલ ક સામન મેરુઆ મધ્યમકાંઠા જિલ્લા જિલ્લા	-વહી- કુલ		9,00,000 1,94,250 10,94,250	પ્રૌશિકેન્ જનશિક્ષણ

1	2	3	4	5	6
61	विद्या महासभा कन्या गुरुकुल महाविद्यालय, खरकेदा, जिला सोनभद्र, हरियाणा।	-वही- कुल		10,65,330 1,57,500 12,22,830	प्रौ-शि-के- अ-शि-वि-
62	भारत विकास सेवा (अनार्गट्रीव), भंडलरी, रेओबेयूर, टी-क्यू, धारवाड जिला, कर्नाटक पिन-581211	-वही- कुल		90,000 21,000 1,11,000	प्रौ-शि-के- अ-शि-वि-
63	श्री बामवेधर लिबरल एजुकेशन सोसाइटी, हेरूर कालाकेरी, हनागल्ल ताल्लुक, धारवाड जिला, कर्नाटक पिन-581148	-वही-		1,35,650	प्रौ-शि-के-
64	कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट, डाकघर बक्स नं-12 कस्तूरबाग्राम, अमरसिंकेरे-573103, जिला हासन, कर्नाटक।			2,76,750	डी-अर-यू-
65	घासा अल्पसंख्यक विकास न्यास, लिमिटेड, रे-यूकल्लहल्ली, गुदोवादा डाकखाना, कोलार जिला-561209, कर्नाटक।	-वही-		1,20,565	प्रौ-शि-के-
66	मामीग विद्यापीठ ट्रस्ट, भलावल्लू तालुक, मण्ड्या जिला-571430, कर्नाटक।	-वही- कुल		1,80,000 1,80,000	प्रौ-शि-के-
67	इन्स्टीट्यूट ऑफ एंग्लाइड लैंग्वेज आइ-नो-ए, बोगादी रोड, मैसूर-570006	-वही-		2,27,250	एम एम सी
68	हरिन संवक संघ शान्तिनिकेतन कलाकला डाकखाना, त्रिवेन्द्रम जिला, केरल-695572	-वही-		2,10,000	अ-शि-वि-
69	केरल शास्त्र सार्वत्रिक परिसर परिसर धवन, त्रिवेन्द्रम-695037	-वही-		20,00,000	अ-शि-वि-
70	मित्रनिकेतन, मित्रनिकेतन डाकखाना, बेल्लानाद-675543, त्रिवेन्द्रम जिला, केरल।	-वही-		1,12,063	प्रौ-शि-के-
71	मिनोबा निकेतन, मिनोबा निकेतन डाकखाना, भलायल्ली, त्रिवेन्द्रम जिला, केरल-695542.	-वही-		1,21,008	प्रौ-शि-के-
72	भारतीय मामीग महिला संघ, 146, त्रिकेन्द्र कलानी, इन्दौर, मध्य प्रदेश।	-वही- कुल		17,33,447 5,62,680 22,96,127	प्रौ-शि-के- अ-शि-वि-
73.	भदसौर जिला समग्र सेवा संघ, सर्वोदय समाज केंद्र, ग्राम पूरुसोदे, डाकखाना पाकरी, गणेश, भदसौर जिला।	-वही-		16,50,000	टी एल सी
74.	महात्मा गांधी सेवा आश्रम, जोगूरा, जिला मुन्ना, मध्य प्रदेश।	-वही-		11,53,316	टी एल सी
75.	दिशा ट्रस्ट, बिलादी बादा-हन्टी फल कड, रायपुर, एम-डी-492001	-वही-		1,02,900	ए अर

1	2	3	4	5	6
76	सोसाइटी फोर एक्शन इन लिमिटेड एजुकेशन एण्ड इक्वलिटी (सेक्रेड), मार्फत प्रबन्ध, प्रशासन और अनुसन्धान संस्थान, 49, समर्थ नगर, औरंगाबाद-431001 (एम्-एस-)	-वही-		10,19,105	प्रौ-शि-के-
77	आधुनिक विमान शिक्षण संस्था, बस्मपुरी इन्फान्ट्री, चन्द्रपुर जिला, महाराष्ट्र-441206	-वही-		1,16,843	प्रौ-शि-के-
78	रेनूकादेवी शिक्षण संस्था, इन्फान्ट्री विमानवाह (रेनूकादेवी), भोकरन तालुका, जालना जिला, महाराष्ट्र-431203	-वही-		1,16,843	प्रौ-शि-के-
79	सावित्री बाई फुले, महाराष्ट्र विमानवाह (महाराष्ट्र), इन्फान्ट्री भोकरन, जिला जालना-431114, महाराष्ट्र।	-वही-		1,23,417	प्रौ-शि-के-
80	समीक्षा शिक्षण संस्था, 11-बैकटेरा नगर, छात्रागृह, नागपुर (महाराष्ट्र)-440025	-वही-		1,33,262	प्रौ-शि-के-
81	सर्वोदय शिक्षण संस्था, इन्फान्ट्री पारमेश्वरी, जिला नागपुर महाराष्ट्र-441105	-वही-		1,26,300	प्रौ-शि-के-
82	विदर्भ आधुनिक बसवा संस्थान केशवाजी बूटी रोड, भोकरन, नागपुर-440012, महाराष्ट्र।	-वही-		2,45,274	प्रौ-शि-के-
83	गण्डाय ग्रामिक विकास केंद्र डा काके का बागला 253, शिवाजी बाग नागपुर-440010	-वही-		12,73,190	प्रौ-शि-के-
84	समाई अम्बिका शिक्षण संस्था महाराष्ट्र जिल्हा रोड, प्रधान महाराष्ट्र-431401	-वही-		1,17,885	प्रौ-शि-के-
85	महाराष्ट्र मातृ वर्ग सेवा मंदिर इन्फान्ट्री 'वसन्तनगर' रोड, तालुका भोकरन जिला प्रभागा महाराष्ट्र-431701	-वही-		1,45,719	प्रौ-शि-के-
86	भारतीय शिक्षा संस्थान 128 / 2, जे.पी. नॉर्थ रोड, कोठरुड, पुणे-411029	-वही-		9,06,000	डी आर यू
87	महाराष्ट्र देवी अहिल्याबाई होल्कर एजुकेशन सोसाइटी, 23, 'मनम हाउसिंग सोसाइटी', मेमिनाथ नगर, गेट हाऊस, सांगली-416416, महाराष्ट्र।	-वही-		5,00,000	टी आर जी
88	स्व. मोतीलाल नेहरू एजुकेशन सोसाइटी, इन्फान्ट्री विमानवाह, तालुका दीगरी, जिला येवतकर, महाराष्ट्र-445203.	-वही-		14,06,000	प्रौ-शि-के-
89	श्री विरुद्ध शिक्षण संस्था, शिवमाला, जिला, महाराष्ट्र-445001	-वही-		1,16,843	प्रौ-शि-के-

1	2	3	4	5	6
90	कमेटो आफ रिसेर्स आरगनाइजेशन फर मासजोआम आफ फन्कशनल लिटरेसी, मार्फत डा० माधव चक्रवर्त, रसायनिक प्रौद्योगिकी विभाग, बम्बई विश्वविद्यालय, माटुंगा, बम्बई-400019	-वही-		4,23,000	डी आर यू
91	मणिपुर व्यावसायिक संस्थान, मेकेला बाजार, बी०पी०ओ० लाइफएक्सेम, (इम्फाल), इम्फाल रोड-11, डेवलपमेंट ब्लॉक, इम्फाल जिला, मणिपुर-795001	-वही-	कुल	5,99,466	प्रौद्योगिकी जनशिक्षण
92	इंटीरिटर हरल डेवलपमेंट सोसाइटी लीमिटेड डाकखाना, इम्फाल जिला, मणिपुर-795130	-वही-		6,08,926	प्रौद्योगिकी
93	बामजिग नुसेन्स एण्ड गर्ल्स सोसाइटी, बामजिग बाजार, डाकखाना बामजिग थोडवाल ब्लॉक, थोडवाल जिला, मणिपुर-795148	-वही-		3,02,675	प्रौद्योगिकी
94	मामीग विक्कस सोसाइटी बामजिग बाजार, डाकखाना बामजिग थोडवाल सी०डी० ब्लॉक, थोडवाल जिला, मणिपुर-795148	-वही-		2,72,384	प्रौद्योगिकी
95	नेताजी युवक संघ, डाकखाना गौडलगाँव, बाबा टीटीलगाँव जिला मोलनागौर, उड़ीसा-767033	-वही-		2,28,239	प्रौद्योगिकी
96	रामजी युवक संघ, डाकखाना सदाइपली, बाबा चन्द्रनभाटी जिला बालनगौर, उड़ीसा-767065	-वही-	कुल	1,16,843	प्रौद्योगिकी
97	नवजाति, डाकखाना गकटागन, बाबा कोटसाही, जिला कटक, उड़ीसा-754022	-वही-		1,80,000 31,500	प्रौद्योगिकी
98	मामीग पुनर्निर्माण हेतु युवा संघ, डाकखाना कोइगुडा, धुटहमलीक, जिला धेनकागल, उड़ीसा, पिन-759127.	-वही-		9,25,000	सी बी ए
99	मामीग पुनर्निर्माण हेतु युवा संघ, डाकखाना बाइदा, हमलीक, जिला धेनकागल, उड़ीसा, पिन-759127	-वही-		9,25,000	सी बी ए
100	विद्यास, खारियार रोड, नन्काकडा ब्लॉक, कलसालाडी, जिला, 766104, उड़ीसा	-वही-		5,37,500	टी एल सी
101.	अन्योदय चेतना मन्दल, बारकन्द डाकखाना, बाबा थोड़दा, मयूरभवन जिला, उड़ीसा-757016	-वही-		7,50,000	टी एल सी

1	2	3	4	5	6
102	स्थानीय समिति (लोकल कमेटे), दि चौफ खालसा दीवान, हरन तारण, अमृतसर, पञ्जाब-143401	-वही-		2,28,239	प्रौशिके
103	अजमेर प्रौढ शिक्षण समिति, शास्त्री नगर एक्सटेन्शन, विद्युत मार्ग, अजमेर-305006 राजस्थान।	-वही-		3,54,191 2,30,847	प्रौशिके जंशिके
104	श्री हरी कृष्ण शिक्षा प्रसार समिति, कुर्जा हाउस, महल चौक, अलवर-301001	-वही- कुल		1,80,000 42,000 2,22,000	प्रौशिके जंशिके
105	बिला महिला जागृति परिषद, स्टेशन रोड, बाइपैर-344001, राजस्थान।	-वही-		1,95,471	प्रौशिके
106	भीलवाडा जिला प्रौढ शिक्षा सच, B / 199, सिन्धु नगर, भीलवाडा-311001, राजस्थान।	-वही- कुल		2,81,227 3,15,000 5,96,227	प्रौशिके जंशिके
107	बीकानेर प्रौढ शिक्षा सच, सरस्वती पार्क, पोस्टा- 28, पुणनी गिजानी, बीकानेर-334001, राजस्थान।	-वही- कुल		24,33,327 3,15,000 27,48,327	प्रौशिके जंशिके
108	प्रयास, गांव देवाडा (देवीलिया), बासा प्रतापगढ़, जिला जिकीठाग, राजस्थान-312621	-वही-		2,10,000	प्रौशिके
109	गाम्भी विद्या मन्दिर, सरदार शहर, राजस्थान-331401	-वही- कुल		2,46,814 63,000 3,09,814	प्रौशिके जंशिके
110	लोक शिक्षण संस्थान, पी-87, नगरपालदे रोड, गाम्भीरी बाजार, जयपुर-302002	-वही- कुल		4,14,512 1,05,000 5,19,512	प्रौशिके जंशिके
111	प्रगति ट्रस्ट, मनोहर निलय, 1-सरदार पटेल रोड, जयपुर, राजस्थान-302001	-वही-		1,16,065	प्रौशिके
112	राधा बाल मन्दिर, पिछालय समिति, बस स्टैण्ड, पीपल शहर, बीकानेर, राजस्थान-342601	-वही- कुल		90,000 31,500 1,21,500	प्रौशिके जंशिके
113	भास्करा बाल निवास संस्थान, पीपल शहर, बीकानेर, राजस्थान, पिन-342601	-वही- कुल		90,000 3,15,000 1,12,500	प्रौशिके जंशिके
114	जैन विश्व धारणी, अनन्ताशाला लाइवू, तहसील लाइवू, नागौर जिला, राजस्थान-341306	-वही-		2,83,500	जंशिके

1	2	3	4	5	6
115	इन्दिरा शिक्षा समिति, कबीरपुर ब्राम्ह अफिम, रोशन रोड, गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर, पञ्चस्थान-322201	-वही-		1,80,000 42,000	प्रौ-शि-के
		कुल		2,22,000	
116	सेवा मन्दिर, उदयपुर-313001, पञ्चस्थान।	-वही-		10,30,640 3,67,500	प्रौ-शि-के ज-शि-नि
		कुल		13,98,140	
117	दुधस्वामी जैनसर सोशल एजुकेशन एंसेसिएशन, विलवाधयनापुर, पक्कम पोस्ट, महुपकम तालुक, बेंगलोरु जिला, (तमिलनाडु)-603301	-वही-		1,13,843	प्रौ-शि-के
		कुल		1,13,843	
118.	डॉ. जी.अरविन्द जी टाट, कलाई कटिथार विल्डिंग्स अन्नायारी रोड, चेन्नै-641037 तमिलनाडु।	-वही-		2,83,536 73,500	प्रौ-शि-के ज-शि-नि
		कुल		4,67,236	
119	श्री ल एंसेसिएशन, मधुपमलीनगर पुरम, विजुली ब्लॉक, कमधमार जिला, तमिलनाडु।	-वही-		1,12,712	प्रौ-शि-के
		कुल		1,12,712	
120.	तमिलनाडु वैदिक एजुकेशन सोसाइटी गांधी निवेदन अन्नम, टी. कल्याणी, मद्रास-626702	-वही-		58,532 98,000	प्रौ-शि-के ज-शि-नि
		कुल		1,16,843	
121	वेलपेथर एंसेसिएशन फर दिएरल मास कन्सल्टी ग्राम तथा बालक नर्स आरकोट जिला तमिलनाडु-606709	-वही-		15,250	प्रौ-शि-के ज-शि-नि
		कुल		1,32,093	
122	कालवी अलाम एजुकेशनल सोसाइटी बालक लेटेरी, नार्थ अरकोट जिला, तमिलनाडु-632202.	-वही-		5,22,784 1,40,000	प्रौ-शि-के ज-शि-नि
		कुल		6,62,784	
123.	निरुपुट्ट कल अफिलिटेड प्रोजेक्ट एग्रीकल्चर (ग्रुप) वीरकुटलपट्टी, निरुपुट्ट तालुक पञ्चस्थान, मधुपमलीनगर जिला, तमिलनाडु-623215.	-वही-		1,16,843 21,000	प्रौ-शि-के ज-शि-नि
		कुल		1,37,843	
124.	कन्सल्टन्सी केन्टरल ट्रस्ट बोर्ड, वेल्थ, सलेम जिला, तमिलनाडु-638182	-वही-		2,72,640 3,38,548	प्रौ-शि-के ज-शि-नि
		कुल		6,11,188	
125	मयार नाला बोर्ड निरुपुट्ट, निरुपुट्टीग्राम मैन रोड, पञ्चोपग्राम, बालक कुटुम्बिक, साउथ अरकोट जिला, तमिलनाडु-607401	-वही-		7,01,140	प्रौ-शि-के

1	2	3	4	5	6
126	मि.डि.पन एडुकेशन डेवलपमेंट समाज, 12 बाथलावा स्ट्रीट, विल्लुपुत्रम, ऐसय्यो विला, तमिलनाडु-605602	-वही-		9,07,609 70,000	प्रौ-शि-के- ज-शि-नि-
		कुल		9,77,609	
127	कॉमर्शियल आफ दि सिग्नल आफ दि ब्रॉड आल च्चन्नोद पोन्ना नं-395, ओल्ड गुड्डा, रोड रोड, टेमाकुलम, तिरुविथपल्ली तमिलनाडु-620002	-वही-		2,92,714 2,10,000	प्रौ-शि-के- ज-शि-नि-
		कुल		5,02,714	
128	छात्राभारत लेखन प्रोसेसिंग आफ द छात्राभारत, तिरुविथपल्ली विला, तमिलनाडु-620023	-वही-		94,512 2,59,215	प्रौ-शि-के- ज-शि-नि-
		कुल		3,53,727	
129	पञ्चाय प्रोसेसिंग, लावणा रण अक्का, पोन्ना नं-416, 170, 171, 172, पीटर्स रोड, धनपेट्टेड, मद्रास-600014	-वही-		12,79,350 1,75,000	प्रौ-शि-के- ज-शि-नि-
		कुल		14,54,350	
130	कृपेस कालिन्धी सर्विस आफ तमिलनाडु, 19 ईस्ट स्ट्रीट रोड, चेन्नै, मद्रास-60031, तमिलनाडु	-वही-		1,89,024 1,62,750	प्रौ-शि-के- ज-शि-नि-
		कुल		4,06,026	
131	कृपेस डिविजन प्रोसेसिंग, 43, श्री विम रोड, मद्रास-60028, तमिलनाडु	-वही-		4,75,275 31,500	प्रौ-शि-के- ज-शि-नि-
		कुल		5,69,775	
132	जयप्रकाश बुक रिस्चो सेन्टर, फर्स्ट फ्लोर स्ट्रीट, 4 कल्लु कल्लोमी, बेसेन्ट नगर, मद्रास-60090	-वही-		4,40,600	प्रौ-शि-के-
		कुल		4,40,600	
133	भारतीय शिक्षण सेवा (प्रा.प.), दिल्लीय बिल्डिंग, कपपुत, विला इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश-221502	-वही-		1,26,707 21,000	प्रौ-शि-के- ज-शि-नि-
		कुल			
134	आदर्श शिक्षा समिति, पूरे भन्ना, कपपुत, विला इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश-221502	-वही-		1,99,374 10,314	प्रौ-शि-के- ज-शि-नि-
		कुल		2,09,688	
135	वि देवा आदर्श शिक्षा समिति वि देवा नगर, नई बाजार, कैनी, विला इलाहाबाद- उत्तर-221008	-वही-		1,16,843	प्रौ-शि-के-
		कुल			

1.8.23

1	2	3	4	5	6
136	ग्राम्य विकास सेवा संस्थान, भैलपुरी डिस्ट्रिक्ट, 28-बी/4-ए1, अल्लपुर, इलाहाबाद, उ०प्र०-211001	-वही-		1,16,843	प्रौ०शि०के०
137	नेहरू बाल मण्डल, 8-ए, पञ्चराम कालोनी, अरुण नगर, इलाहाबाद-211001, उ०प्र०	-वही-		1,66,525 34,355	प्रौ०शि०के० अ०शि०नि०
		कुल		2,00,880	
138.	डा० अमेरुल सम्राज सेवा मंडल, ग्राम बेल्ही, पो०डा० सैदपुर, जिला इलाहाबाद, उ०प्र०-221508	-वही-		4,67,976	प्रौ०शि०के०
139.	बालमंदी आवास शिक्षा समिति 23/47/55, बिदवर्ग नगर, अल्लपुर, इलाहाबाद, उ०प्र०-211006	-वही-		1,16,843	प्रौ०शि०के०
140	महिला उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, 261/4, सलीक गज रोड, मुदीनगर, इलाहाबाद, उ०प्र०-211002	-वही-		1,80,000 36,500	प्रौ०शि०के०
141.	जन शिक्षण अभियंता, 501, पार्क रोड, इलाहाबाद, उ०प्र०-211002	-वही-		1,63,654	प्रौ०शि०के०
142	पूर्वांचल ग्राम विकास संस्थान, ग्राम जगदीशपुर तन्कोवा रामपुर, पो०डा० आननाराज जिला, उ०प्र०-276001	-वही-		1,35,287	प्रौ०शि०के०
143.	अतीथर ग्रामोद्योग सेवा मंडल जीबतापुर बाजार, आननाराज महधन-271801, उत्तर प्रदेश	-वही-		1,23,500 31,500	प्रौ०शि०के० अ०शि०नि०
		कुल		1,55,000	
144	छात्री ग्रामोद्योग समिति, ग्राम बहोली बाबा, आननाराज बाजार, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश, पिन-272182	-वही-		1,55,000 1,25,116	प्रौ०शि०के०
145	नरी विकास संस्था, भारतखर्वा, नबीमान्द, बिजनौर जिला, उत्तर प्रदेश।	-वही-		4,14,512	प्रौ०शि०के०
146	महिला सेवा संस्थान, भोहरा कान्हा, आननाराज बाजार, बिजनौर जिला, उत्तर प्रदेश-246725	-वही-		1,16,843	प्रौ०शि०के०
147.	म्याना ग्रामोद्योग सेवा संस्था मुरारी नगर, जी० टी० रोड, खुर्बा, जिला मुन्डेराह, उत्तर प्रदेश।	-वही-		5,08,140 63,000	प्रौ०शि०के० अ०शि०नि०
		कुल		5,71,140	

1	2	3	4	5	6
149	गोमती प्रवाग जन कल्याण परिषद्, बाकु-दा, डा० च० दुनगलवाली, जिला चम्पौली, उ० प्र०-246446	-वही-		1,58,227	प्रौ-शि०के०
150	जन कल्याण शिक्षा समिति, पावा नगर डाकघर फर्रिदा जिला नगर, जिला देवरिया-274401	-वही-		1,10,005	प्रौ-शि०के०
151	मानव सेवा संस्थान, अचारहा, डाकघर गौनारीया, कमतानगज, जिला देवरिया, उ० प्र०-274301	-वही-		11,00,000	टी एल सी
152	207, सराय मिश्रा, पट्टा (उ० प्र०)	कुल		1,23,662	
153	श्री हरि प्राथ उद्योग सेवा संस्थान श्री हरि निकुंज, निकट महकरी बैंक, श्रीरागाबाद इटावा, उ० प्र०-206001			1,16,843 92,500	प्रौष्ठ शिक्षा केन्द्र जन शिक्षण निलयम
154	मचन बिक्रम क्षेत्र समिति, भित्ति, जिला फैजाबाद, उत्तर प्रदेश-224132	-वही-		1,16,843	प्रौष्ठ शिक्षा केन्द्र
155	सामाजिक स्वाम्य कल्याण प्रायोग विकास तथा शिक्षा संस्थान, रुलपुर (दियारा), दोमपुर फैजाबाद, उ० प्र०	-वही-		1,80,000	प्रौष्ठ शिक्षा केन्द्र
156	रतन प्रायोग सेवा संस्थान, गाव ब पो ओ० बीकपुर, जिला फैजाबाद, उ० प्र०-224205	-वही-		14,00,000	पूर्ण साक्षरता अभियान
157	विवेकानन्द संस्थान, अनवरपुर, फैजाबाद, उ० प्र०-224122	-वही-		12,50,00	पूर्ण साक्षरता अभियान
158	जे०पी० सेवा समिति, पी० ओ० फर्रिदापुर, अमेलर फर जिला फर्रिदापुर, उ० प्र०	-वही-		1,17,299	प्रौष्ठ शिक्षा केन्द्र
159	राष्ट्रीय हरिजन स्कूल बहरीदाबाद, तहसील सैदपुर जिला गाजीपुर, उ० प्र०-233001	-वही-		1,16,843	
160	अशोक संस्थान, कुम्हैस, जिला गाजीपुर उ० प्र०-233234	-वही-		13,00,000	पूर्ण साक्षरता अभियान
161	प्राथमिक विकास समिति गांव परपुरपुष्पपुर पी० ओ० सधमान, तहसील तरताम जिला गैडा-271403 उ० प्र०	-वही-			
		कुल		1,49,187	
162	आदर्श जन कल्याण परिषद् बिलाम, जिला हारदोई, उ० प्र०	-वही-		14,00,000	पूर्ण साक्षरता अभियान

1	2	3	4	5	6
163	ग्रामिक विद्यपीठ 15/96 सिविल लाईन कानपुर उ० प्र०-208001	-वही-		1,20,600	ग्रैड शिक्षा केन्द्र
164.	सामाजिक उत्थान समिति, शिक्षा विद्या मन्दिर, धवन ओपूला, पी० ओ० हरिजन-दा नगर, कानपुर, उ० प्र०	-वही-		90,000 *15,750	ग्रैड शिक्षा केन्द्र जन कल्याण निराश्रित
165	भारतीय महिला औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान, तथा पुनर्वास 460, देवपुर, पी० ओ० धनजीपुर, उ० प्र० लखनऊ (उ० प्र०) 226017	-वही-		*4,91,145 1,05,000	ग्रैड शिक्षा केन्द्र जन शिक्षण निराश्रित
166	न्यू पब्लिक स्कूल समिति, 504,63 टैगोर मार्ग, निकट बन्दी माता मन्दिर, डालीगांव, लखनऊ	-वही-		3,18,239 15,750	ग्रैड शिक्षा केन्द्र जन शिक्षण निराश्रित
167	ग्राम सेवा निवेदन. 295/23, अश्वमेधबाद लखनऊ-226003 (उ० प्र०)	-वही-		1,13,968	ग्रैड शिक्षा केन्द्र
168	भारत साक्षरता बोर्ड साक्षरता धवन, पी० ओ० आलम बाग, लखनऊ (उ० प्र०) 226005	-वही-		89,89,092 1,29,405	ग्रैड शिक्षा केन्द्र जन शिक्षण निराश्रित
169	अखिल भारतीय अनाथ आश्रम सेवा संस्थान, 98 बेमाधन पी० ओ० तथा गांव जहांगीरबाद जिला बुलन्दशहर उ० प्र० 202394	कुल -वही-		1,06,247 1,16,843	ग्रैड शिक्षा केन्द्र
170.	श्री महिला उद्योग समाज उत्थान समिति, किशोरीपुर, वृन्दावन, जिला मथुरा उ० प्र०-21121	-वही-		2,28,239 42,000	ग्रैड शिक्षा केन्द्र जन शिक्षण निराश्रित
171	इराद अकदमी मीर्जाह शाहयेर गेट, मेरठ, उ० प्र०-250002	-वही-		1,20,065 21,000	ग्रैड शिक्षा केन्द्र जन शिक्षण निराश्रित
172.	बनबानी सेवा आश्रम गोविन्दपुर (दण्ड तुर्ग) जिला मिर्जापुर (खेनभद्र) उ० प्र०-231221	कुल -वही-		1,41,065 3,37,300 63,000	ग्रैड शिक्षा केन्द्र जन शिक्षण उत्थान एवम्
173	वसन्तीगंज, मिर्जापुर, उ० प्र० 231001	-कुल-		1,15,250	
174.	महिला पुनर्स्थापन समिति गांव तथा पी० ओ० बरकज्वा जिला मिर्जापुर, उ० प्र० 231001	-वही-		1,16,121	ग्रैड शिक्षा केन्द्र
175.	खामी निवेदन-द शिक्षा समिति स-कया घाट मिर्जापुर उ० प्र० 231001	-वही-		1,16,121	ग्रैड शिक्षा केन्द्र
176.	विशेष शिक्षा समिति, कचहरी रोड, पीली बरेली, मिर्जापुर, उ० प्र०-231001	-वही-		1,16,143	ग्रैड शिक्षा केन्द्र

1	2	3	4	5	6
177.	ब.सी सेवा आश्रम गोविन्दपुर झर-पुर, जिला निर्मलपुर उ० प्र०-231221	-वही-		55,00,000	एच० एस० सी०
178	भारतीय महिला विकास संस्थान पी० जे० बनौरा पर जिला मुपदाम-244231 उ० प्र०	-वही-		1,16,617	ग्रौंड शिक्षा केन्द्र
179	अमोक्षी विकास पञ्चाल कल्या, खेडा, सत्या कवन मिदल्ली रोड, जेवा जिला मुपदाम-244222 उ० प्र०	-वही-		1,17,897	ग्रौंड शिक्षा केन्द्र
180	आदर्श सेवा समिति, 326/1, साकेत कॉलोनी गली नं० 6, मुजफ्फरगंज पिन 251001	-वही-		94,512 70,000	ग्रौंड शिक्षा केन्द्र जन शिक्षण निलय
		कुल		1,64,512	
181	विशाल शिक्षा समिति अस्ताना नदी बस्ती, हल्दवानी, जिला नैनीताल, उ० प्र०, पिन 263139	-वही-		4,14,512 35,000	ग्रौंड शिक्षा केन्द्र जन शिक्षण निलय
182	यू० पी० उणा बेनी प्राध्व जन कल्याण समिति, गुलाब रोड, रंग बरेली, उ० प्र०	-वही-		1,83,557 1,57,500	ग्रौंड शिक्षा केन्द्र जन शिक्षण निलय
		कुल		*16,41,057	
183	अपेठी महिला सौचिक सेवा समिति अपेठी, जिला सन्तानपुर-227405	-वही-		1,16,843 31,500	ग्रौंड शिक्षा केन्द्र जन शिक्षण निलय
		कुल		1,48,343	
184	सदन क्षेत्र विकास समिति, सेवापुरी, बागमही, उ० प्र०-221403	-वही-		19,30,000	पूर्ण साक्षरता अभियान
185	सिन्दु-कन्दु आभोग्रथन समिति मेघाही, जिला दुर्गम पश्चिम बंगाल-713514	-वही-		3,70,000 52,500	ग्रौ० शिक्षा केन्द्र जन शिक्षण निलय
186	पञ्चकुल विद्यान जन शिक्षा मंदिर बेलूर मठ, हावड़ा-711202 पश्चिम बंगाल	-वही-		3,20,000 14,000	ग्रौ० शिक्षा केन्द्र जन शिक्षण निलय
		कुल		4,89,988	
187	पञ्चकुल शिक्षा विद्यान 7-रिवरसाई रोड, बैरकपुर, जिला-24 परगना पश्चिम बंगाल-743101	-वही-		3,67,723 35,000	ग्रौ० शिक्षा केन्द्र जन शिक्षण निलय
		कुल		4,02,723	
188	अमीन विद्या की टैगोर सोसायटी गाव च जो ओ० देवागिरिया (झर-गोसवा) जिला-24-परगना (दक्षिण) पश्चिम बंगाल	-वही-		1,20,000	ग्रौ० शिक्षा केन्द्र
		कुल		1,20,600	

1	2	3	4	5	6
189.	धम्कृष्ण मिशन लोकशिक्षा परि- धम्कृष्ण मिशन आश्रम पो० ओ० नरेन्द्रपुर 24, परगना (दक्षिण)	-वही-		2,18,736 22,20,030	श्री० शि० केन्द्र एस० एस० सी०
190	पश्चिमी बंगाल क्षेत्रिया सवपर कल्याण संमिति गांव व पो० ओ० धननोबाग जिला पुरुलिया-723128 एस-609754	-वही-		24,38,766 1,80,000	श्री० शि० केन्द्र
191	ग्रामीण विकास के लिए टैगोर सोसायटी 14-खुदी राम ब्रेस रोड कलकत्ता-700006	-वही-		7,36,000 21,000	श्री० शि० केन्द्र जन शिक्षण निलय
		कुल		7,57,600	
192	बंगाल समाज सेवा लीग 1/6 राज देवेन्द्र हॉट कलकत्ता-700009	-वही-		1,80,000	
193	जन शिक्षा एवं विकास अखिल भारतीय परिषद् 60, पदुआगोला लैन कलकत्ता-700009	-वही-		4,00,000 5,35,500	श्री० शि० केन्द्र जन शिक्षण निलय
		कुल		9,35,500	
194	भारतीय रेडक्रस सोसायटी पश्चिम बंगाल शाखा 27, बेलवेडरे रोड कलकत्ता-700027	-वही-		1,20,600	श्री० शि० केन्द्र
195	श्री धम्कृष्ण सत्यानन्द आश्रम 46/2, देराबन्धु रोड (पश्चिम) कलकत्ता, 35	-वही-		2,89,009 46,284	श्री० शि० केन्द्र जन शिक्षण
		कुल		2,10,000 5,45,293	निलय
196	पञ्जाब पिछड़ा वर्ग विकास बोर्ड 1143,36-सी, चट्टीगढ़, पञ्जाब	-वही-		3,96,396 1,05,000	श्री० शि० केन्द्र जन शिक्षण निलय
		कुल		5,01,396	
197	सर्व भारत श्री विकास प्रचार प्रतिष्ठान, 393, सेक्टर-38, चट्टीगढ़-160036	-वही-		1,17,950 70,000	श्री० शि० केन्द्र जन शिक्षण निलय
		कुल		1,87,950	
198	भारतीय ग्रैड शिक्षा सघ 17-बी० आई० पी० इस्टेट, नई दिल्ली-110002	-वही-		3,20,000	श्री० शि० केन्द्र
199	पी० एच० डी० ग्रामीण विकास प्रतिष्ठान पी० एच० डी० भवन, धारपुर फ्लोरो परामन खेल गांव के सामने नई दिल्ली-110083	-वही-		3,20,000	श्री० शि० केन्द्र जन शिक्षण निलय
200	जन जागृति सैनिक सोसायटी एम-186, मंगोलपुरी, दिल्ली-110083	-वही-		90,000 17,750	श्री० शि० केन्द्र जन शिक्षण निलय
		कुल			

1	2	3	4	5	6
201	एचि भारतीय शलषल सलतल डोललललत नगर, शललदल दललुल-110032	-कलु-		1,07,750	डुल शल कलु
202	डललल कलुनल कलु एफ 26, डुलकुल दलल कलुलुल लुलुलु एलु, नल दललुल-110003	-कलु-		4,14,512 84,000	डुल शल कलु कन शलषल नललतत
	कुल			4,98,912	
203	अललल भारतीय शललरु एलु डललुल डलकलस कलु 5, डलल डुलर ललल डलल डुलडलकुल, नल दललुल-110001	--कलु-		*3,57,900	डुल शल कलु
204	लुललडलड डलकलस लुललल 1, दलरडललल, नल दललुल-110002	-कलु-		2,44,500	डुललुल
205	भलरलुल लुललल डुललल ड डलललल लुललल (एलु अलुलु डुल डुलु एलु) 17-डुल अलुलुलु डलल, नल दललुल 110016	-कलु-		72,000 2,66,000	एलु एलु लुल लुल अलु डुल
	कुल			3,38,000	
207	डुल एलु डुल डलललल डुलडुललल डुलस ललक लललल, डललदुल शलल अलुल डलल, नल दललुल-110002	कुल	-कलु-	13,12,165 3,15,000	डुल शलषल कलु कनशलषल नललतत
				16,27,165	
208	डलकलस, डुलस तडल शलल दललुलु कलुलुलल एलुलललडुलललल "कलुनललतत" अलुल डुलस नल दललुल-110001	-कलु-		1,80,000	डुल शलषल कलु

गैर सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों के नाम निम्न वर्ष 1990-91 के दौरान 1 लाख रुपये तथा उसके कमि- की आती अनुदान - प्राप्त प्राप्त की
क्रम एरोसी/संगठन का नाम पते संगठन की संविधान 1990-91 में सामान्य उद्देश्य जिसके लिए कैफियत
से स्थित स्थापना कार्यवाही अनुदान संस्थान की उचित अनुदान प्रयोग में लाया गया।

1	2	3	45	6
1.	राज्य संस्थान केन्द्र विद्याभवन, मुद्रा कालोनी पटना-800001	ग्रैंड शिक्षा कार्यक्रमों के लिए सार्वजनिक संस्थानों के लिए अनुदान	112.42	राज्य संस्थान केन्द्र के रख-रखाव के लिए अनुदान तथा वृत्ति संस्थागत मूल्य के अनुदान के अंतर्गत संस्थागत किर्तियों के लिए करने के लिए
2.	ग्रैंड शिक्षा राज्य संस्थान केन्द्र साधना, पौन, ओम अंतराष्ट्रीय, साधना-2260005	-वही-	100.22 रु	-वही-
3.	ग्रैंड शिक्षा राज्य संस्थान केन्द्र भारतीय भारतीय महिला संघ, 680, विजय नगर, अमरपुरी रोड इन्दौर-452009	-वही-	22.37 रु	-वही-
4.	अन्तराष्ट्रीय शिक्षा राज्य संस्थान केन्द्र, सतत शिक्षा अभियान केन्द्र, नवी, दूतरी गली, बैकडेहार नगर, अहमदाबाद-600020	-वही-	36.29 रु	-वही-
5.	ग्रैंड शिक्षा राज्य संस्थान केन्द्र केरल संघ अन्तराष्ट्रीय शिक्षा (के।।।।) साधना पवन विमान-695014	-वही-	8.00	-वही-
6.	अन्तराष्ट्रीय शिक्षा के लिए राज्य संस्थान केन्द्र, भारतीय शिक्षा संस्थान, द्वारा भारतीय शिक्षा संस्थान 128/2 जीपी नयक रोड, कोयंबटूर, पुणे-411029	-वही-	137.07	-वही-
7.	ग्रैंड शिक्षा के लिए राज्य संस्थान केन्द्र जम्मिया मिलिया इस्लामिया जम्मिया नगर, नई दिल्ली-110025	-वही-	8.00	-वही-
8.	ग्रैंड शिक्षा के लिए राज्य संस्थान केन्द्र, गुजरात निवासी, आश्विन टेड, अहमदाबाद-380014	-वही-	8.00	-वही-
9.	ग्रैंड शिक्षा के लिए राज्य संस्थान केन्द्र, उपस्थान, ग्रैंड शिक्षा संघ, 7-ए, शांतिना बुंगारी, औद्योगिक क्षेत्र जयपुर-302004	-वही-	33.00	-वही-
10.	ग्रैंड शिक्षा के लिए राज्य संस्थान केन्द्र, बंगाल मन्त्रालय सेवा लीग, 1/6, राजा टीनेड स्ट्रीट कलकत्ता-700009	-वही-	12.79	-वही-
11.	ग्रैंड शिक्षा के लिए राज्य संस्थान केन्द्र, प्लॉट सं- 159, (विष्णु मंदिर के पास) राहीद नगर, पुणे-751007	-वही-	134.50	-वही-

1	2	3	45	6
12	मौड़ शिला के लिए राज्य लेखाचन केन्द्र, कर्नाटक राज्य मौड़-शिला परिषद, 501, विन चानु रोड, अ और ब ब्लाक, जुम्लिना मैसूर-570023	-वही-	17.75	-वही-
13	मौड़ शिला के लिए राज्य लेखाचन केन्द्र, मिन्नेली हाऊस ऑफ एजिड सफा (ए एन एस), एएनएस बिल्डिंग कैम्पस, मून्नेली रोड, है.ए.ए.ए.-500007	-वही-	15.38	-वही-
14	राज्य लेखाचन केन्द्र कर्नाटक विच- विभाग, श्रीनगर	-वही-	1.00	-वही-
15	केन्द्रीय लेखाचन केन्द्र एनएस विच- विभाग, (बंगलौर)	-वही-	6.82	-वही-
16	कर्मचारी विभाग, कर्नाटक	-वही-	6.82	-वही-
17	उत्तर-पूर्व पर्यटन विभाग, कर्नाटक	-वही-	1.00	-वही-

सन् 1990-91 के दौरान 1 लाख रुपए या इससे अधिक आयर्ली अनुदान प्राप्त करने वाले	
क्रम संख्या	पञ्चोत्ती/संज्ञा का नाम व पता
1	समान के सहित कार्यकर्ता

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

सकल शिक्षा	सकल शिक्षा से सुधार
1	राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान में सुधार
2	विज्ञान विभाग अकादमी शिक्षा संस्था, मध्याह्न
3	तमिलनाडु विज्ञान मण्डल, मद्रास

शिक्षा के लिए धन-सहायता प्रशिक्षण	उत्तराखण्ड सेवा शिक्षा, अल्मोड़ा (उत्तर प्रदेश)
1	उत्तराखण्ड सेवा शिक्षा, अल्मोड़ा
2	प्राथमिक शिक्षा केन्द्र, अहमदाबाद
3	एच.के.एन.एच. 440000000, शिक्षा-प्रदेश (अन्य प्रदेश)

क्रम सं	एजेंसी/संगठन का नाम पता	संगठन की स्थापना/संस्थापिका	1991-92 में अनुदान की राशि	अनुदान को किस उद्देश्य के लिए खर्च किया गया	कैफियत
1	2	3	4	5	6
घावाओं की प्रतिक्रिया					
1	आन्ध्र प्रदेश हिन्दी प्रचार सभा, हैदराबाद	हिन्दी शिक्षण केन्द्र, हिन्दी महाविद्यालय और हिन्दी प्रचार केन्द्रों आदि का संचालन	3 73,350 रुपए	शिक्षण केन्द्र महाविद्यालय प्रचारक सम्मेलन तथा हिन्दी डायरी का प्रकाशन।	
2	हिन्दी प्रचार सभा, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश	हिन्दी शिक्षण केन्द्र, हिन्दी पुस्तकालय, हिन्दी टंकण कक्षाएँ तथा हिन्दी कक्षाएँ तथा हिन्दी प्रचारक प्रशिक्षण महाविद्यालयों तथा अन्य प्रचार कार्यक्रमों का संचालन	1,03,875 रुपए	हिन्दी टंकण एवं आशुलिपि केन्द्र	
3	नगर हिन्दी वर्ग संचालक अध्यापक संघ हैदराबाद	हिन्दी शिक्षण केन्द्र, हिन्दी पुस्तकालय, हिन्दी टंकण कक्षाएँ तथा अन्य प्रचार कार्यक्रमों का संचालन	1,33,230 रुपए	हिन्दी शिक्षण, हिन्दी टंकण एवं आशुलिपि कक्षाएँ हिन्दी पुस्तकालय, वाचनालय स्टॉफ का वेतन, किराया, पुस्तकों, दौलतजीन आदि को खरीद	
4	सामाजिक सेवा समिति, लखीमपुर, असम	हिन्दी प्रचार का प्रसार	2,16,750 रुपए	टंकण / आशुलिपि कक्षाएँ	
5	असम राज्य राष्ट्र भाषा समिति, जोरहाट	हिन्दी की प्रोन्नति	1,12,500 रुपए	हिन्दी टंकण कक्षाएँ।	
6	हिन्दी विद्यापीठ, टेक्कर, बिहार	शिक्षण कक्षाएँ, टंकण और आशुलिपि कक्षाएँ	1,97,635 रुपए	हिन्दी टंकण और आशुलिपि कक्षाओं के आवश्यक सस्थान और लिपिही प्रक्रियाओं का प्रकाशन।	
7	पुनर्गत विद्यापीठ, अहमदनगर	हिन्दी की प्रोन्नति	1,08,750 रुपए	हिन्दी पुस्तकालय, हिन्दी टंकण केन्द्र।	
8	गोमंतक राष्ट्रीय विद्यापीठ मद्रास, गोआ	हिन्दी की प्रोन्नति	1,15,650 रुपए	हिन्दी शिक्षा केन्द्र, हिन्दी पुस्तकालय आदि।	
9	कनिटक हिन्दी प्रचार समिति जयपुर, बंगलौर।	शिक्षण केन्द्र, पुस्तकालय आदि का संचालन	6,52,538 रुपए	हिन्दी शिक्षण केन्द्र, हिन्दी पुस्तकालय आदि।	
10	कनिटक महिला हिन्दी सेवा समिति, बंगलौर	हिन्दी शिक्षण कक्षाएँ, पुस्तकालय, बाल-विवाद आदि।	6,60,000 रुपए	हिन्दी शिक्षण कक्षाएँ, वाचनालय एवं पुस्तकालय, हिन्दी टंकण कक्षाएँ, शिक्षण-प्रशिक्षण कालिज, हिन्दी महाविद्यालय आदि।	
11	मैसूर हिन्दी प्रचार परिषद, रायपुर	हिन्दी शिक्षण केन्द्र, टंकण एवं आशुलिपि कक्षाएँ आदि।	10,33,657 रुपए	हिन्दी शिक्षण कक्षाएँ, हिन्दी पुस्तकालय, हिन्दी टंकण आशुलिपि कक्षाएँ।	
12	हिन्दी प्रचार सभा मुंबई, कनिटक	हिन्दी शिक्षण कक्षाओं का संचालन	1,10,325 रुपए	हिन्दी शिक्षण केन्द्र हिन्दी पुस्तकालय / हिन्दी महाविद्यालय आदि।	
13	केरल हिन्दी प्रचार सभा, त्रिवेन्द्रम	केन्द्रीय महाविद्यालय टंकण एवं आशुलिपि कक्षाएँ, पुरस्कृत आदि।	4,27,550 रुपए	हिन्दी पुस्तकालय, केन्द्रीय महाविद्यालय, हिन्दी प्रचारक पुनर्बाध पाठ्यक्रम, पुरस्कृत आदि।	

1	2	3	4	5	6
14.	हिन्दी सभा, बम्बई।	हिन्दी की श्रैष्ठिति	1,29,150 रुपए	हिन्दी शिक्षण केन्द्र, पुस्तकमलय पत्रिकाएँ आदि।	
15.	पट्टभाषा प्रचार सभा बर्मा	पाठ्यपुस्तकों, सांस्कृतिक कार्यक्रम, हिन्दी प्रकाशकों के लिए सेमिनार आदि का आयोजन	2,39,925 रुपए	हिन्दी महाविद्यालय, हिन्दी शिक्षण केन्द्र, हिन्दी टंकण एवं आर्गुलिनि कक्षाएँ।	
16.	बम्बई हिन्दी निधानी	शिक्षण केन्द्र, पुस्तकमलय छाफालय, प्रचारक केन्द्र सेमिनार, नाटक आदि	7,58,190 रुपए	हिन्दी प्रशिक्षण केन्द्र, आदि	
17.	महापट्ट राष्ट्र सभा 388, नागपण पब पुना	हिन्दी की श्रैष्ठिति	1,50,750 रुपए	केन्द्रीय शब्दावलय आदि	
18.	मणिपुर हिन्दी पत्रिका इम्फाल	-कहीं-	2,04,450 रुपए	हिन्दी कक्षाएँ	
19.	मणिपुर राष्ट्र भाषा प्रचार, समिति, इम्फाल	-कहीं-	1,59,750 रुपए	हिन्दी कक्षाएँ	
20.	उत्कल भारतीय राष्ट्र भाषा प्रचार सभा कटक	हिन्दी शिक्षण केन्द्रों, हिन्दी टंकण एवं आर्गुलिनि केन्द्रों का संचालन	2,12,205 रुपए	हिन्दी शिक्षण कक्षाएँ, हिन्दी पुस्तकमलय प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि।	
21.	झारखण्ड पट्टभाषा परिषद जगन्नाथ, पुरी	-कहीं-	1,94,925 रुपए	हिन्दी कक्षाओं तथा हिन्दी का प्रचार	
22.	स्थापन संस्थान बीधपुर	हिन्दी का प्रचार प्रसार	2,00,000 रुपए	पुस्तकमाला हिन्दी कक्षाएँ, कक्षा का निर्माण	
23.	हिन्दी प्रचार संस्थान, जयपुर	-कहीं-	2,11,050 रुपए	हिन्दी की श्रैष्ठिति	
24.	दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा (मद्रास, हैदराबाद, तिरुचिपल्ली, चेन्नई और पुनाकुलम में अपनी शाखाओं के लिए)	निरुक्त हिन्दी कक्षाएँ आयोजित करना, महाविद्यालय, टंकण एवं आर्गुलिनि कक्षाएँ, पुस्तक आदि।	23,73,237 रुपए	हिन्दी पुस्तकमलय, केन्द्रीय विद्यालय, हिन्दी प्रचारक अनुस्थापन कार्यक्रम आदि।	
25.	अनुसंधान प्रतिष्ठान को-4/245, सफरदारा पकटोव, नई दिल्ली	हिन्दी की श्रैष्ठिति	20,000 रुपए	हिन्दी की श्रैष्ठिति	
26.	केन्द्रीय सांस्थान हिन्दी परिषद, नई दिल्ली	विभिन्न हिन्दी प्रयोगिकारों आयोजित करना, हिन्दी भाषाओं में हिन्दी के विकास के लिए सेमिनारों, संगोष्ठियों, आदि का आयोजन	3,63,000 रुपए	हिन्दी की विभिन्न प्रयोगिकारों के आयोजन, हिन्दी पत्रिकाओं और पुस्तकों आदि का प्रकाशन के लिए खर्च सहन करना।	
27.	अखिल भारतीय हिन्दी संस्थान राँचे, नई दिल्ली	हिन्दी प्रचार प्रसार कार्यक्रम	6,35,412 रुपए	स्थापना व्यय और हिन्दी प्रचार प्रसार कार्यक्रमों को जारी रखना।	
28.	भारतीय अरावर परिषद, 9 हैलीरोड नई दिल्ली	हिन्दी की श्रैष्ठिति	1,33,148 रुपए	हिन्दी की श्रैष्ठिति	
29.	दैवतल प्रतिष्ठान अम्बिका, हैदराबाद	आरम्भिक शिक्षा का प्रकाशन	1,57,000 रुपए	अनुसंधान अनुदान	
30.	अनुसंधान तल्लि-ए-उर्दू (हिन्दी), नई दिल्ली	उर्दू की श्रैष्ठिति	1,38,000 रुपए	अनुसंधान अनुदान	
तीव्र					
1	श्री गंगारानी आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, कटका, मधुरा	शिक्षण	6,71,249-00	वेतन / छात्र-शिक्षकों / आकाशिक व्यय / पुस्तकें, पत्रिकाएँ, कार्ड्स, सामग्री, विज्ञान का मुद्रण तथा मरम्मत।	
2.	जगदीश नाथन । जगदीश आश्रम संस्कृत महाविद्यालय लगमा, कक्षा लोहा रोड धर्मपुर, जिला दारभंग, बिहार	शिक्षण	5,41,558-00	वेतन / छात्र-शिक्षकों / आकाशिक व्यय / क. ई. व्य. / पुस्तकें / छात्रों की मरम्मत।	

1	2	3	4	5	6
3.	भगवान दास संस्कृत महाविद्यालय झाकखाना मुख्यपुल कोमडी हरिद्वार (उत्तर प्रदेश)	-वही-	5,41,558-00	वेतन/छानवृत्तियां/आकर्षक क व्यय/ फर्नीचर/ यात्रा भत्ता दैनिक भत्ता/पुस्तकें/पचन खर्च भरसमत तथा पुस्तकों का मुद्रण।	
4	दीवान कृष्ण किरौरी समाजतन्त्र्य आदर्श संस्कृत कालिदास, अल्मारा छावनी, (हरियाणा)	-वही-	5,20,220-00	वेतन/छानवृत्तियां/पब्लिशिंग निधि अकार्षिक व्यय/ फर्नीचर/ पुस्तकें तथा टंकण यंत्रों की छपरे।	
5	श्री एकरसादे संस्कृत महाविद्यालय मैनपुरी (उत्तर प्रदेश)	-वही-	5,73,490-00	छानवृत्तियों/आकर्षक व्यय फर्नीचर/पुस्तकें/पचन खर्च भरसमत।	
6	यद्वास संस्कृत कालिदास एवं एस एस वी पाठशाला, B4, गेयावीठ हाई रोड, मथुरापुर, यद्वास।	-वही-	6,45,480-00	वेतन/छानवृत्तियों/फर्नीचर आकर्षिक व्यय/पचन खर्च भरसमत।	
7	मुन्नादेवी संस्कृत महाविद्यालय मार्फत भारतीय विद्याभवन, के.एस. मुंशी मार्ग, बम्बई	-वही-	7,91,200-00	वेतन/छानवृत्तियों/अकार्षिक क व्यय/ यात्राभत्ता एवं दैनिक भत्ता/ पुस्तकभत्ता, पुस्तकें।	
8	हरियाणा संस्कृत विद्यापीठ झाकखाना मंगोला, जिला फरीदाबाद, हरियाणा	-वही-	4,72,798-00	-वही-	
9	कुमुदानी शाली अनुसंधान संस्थान, B4-गेयावीठ रोड मथुरापुर, यद्वास	अनुसंधान	3,95,513-00	अनुसंधान/वेतन/फर्नीचर/ प्रकाशन पचन खर्च भरसमत/विकासन।	
10	कालीकट आदर्श संस्कृत विद्यापीठ बालपुरी, जिला कालीकट, केरल	शिक्षण	4,79,612-00	वेतन/आकर्षिक व्यय/यात्रा एवं दैनिक भत्ता/छानवृत्तियां/पुस्तकें एवं फर्नीचर।	
11	वैदिक समशीर्षन मंडल लिखक विद्यापीठ नगर, पूना-9	अनुसंधान	4,72,019-00	वेतन/आकर्षिक व्यय/प्रकाशन पुस्तकें	
12	श्री चन्द्रशेखरेन सरस्वती न्याय शास्त्र संस्कृत महाविद्यालय नं० 3, ईस्ट मज्जा स्ट्रीट, छोटा कांचीपुरम	शिक्षण	4,08,321-00	-वही-	
13	लक्ष्मी देवी शरण, आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, काली राजा, गज झाकखाना देवगढ़, (बिहार)	-वही-	7,47,743-00	-वही-	
14	पञ्चकुम्भी गणेश शर्मा, आदर्श संस्कृत पाठशाला, कोलकाता पटोरी बिल्डर	-वही-	5,57,289-00	-वही-	
15	श्रीमान् आदर्श संस्कृत महाविद्यालय जंगला रोडक, मिर्जापुर प्रदेश	-वही-	4,58,172-00	-वही-	
16	सामी म. गुप्तास्वर्ण संस्कृत महाविद्यालय, बुलासरीग, गया	-वही-	4,75,475-00	-वही-	
17	संस्कृत शब्दकोश प्रियोजना, पूना	संस्कृत शब्दकोश संस्करण करना	20,00,000-00	अनुसंधान (प्रकाशन) अनुसंधान	
18	राजा केद कल्याण चन्द्रावत वी 76/III प्रजरा, स्ट्रीट, श्री नगर काली पी, कुम्भकोनम	शिक्षण	2,16,600-00	वेतन/छानवृत्तियां	
19	भारतीय अनुर्वन के.भवन न्यास, लंदेरी सदन दिल्ली, दिल्ली, कानपुर	-वही-	1,59,600-00	-वही-	

1	2	3	4	5	6
20	मुख्याधीश धार्तर, कन्या गुरुकुल महाविद्यालय हाथरस, जिला अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश)	-वही-	1,10,700-00	-वही-	
21	सम्पूर्णसंद संस्कृत विश्वविद्यालय, बाधगपसी (उत्तर प्रदेश)	-वही-	6,25,000-00	-वही-	
22	कन्या गुरुकुल नरेला दिल्ली	-वही-	1,01,700-00	-वही-	
23.	कल्पतरु अनुसंधान अकादमी पोस्ट बाक्स संख्या 1857 बंगलौर	प्रतिमा कोश के तीसरे एवं चौथे खण्ड को तैयार करना एवं उनका प्रकाशन	2,03,006-00	-वही-	

उच्चतर शिक्षा

1.	पारसी विश्वविद्यालय संघ, नई दिल्ली	19,37,000 00 रु०
2	डा० जाकिर हुसैन पैमेरियल कलेज ट्रस्ट	6,00,000 00 रु०
3	श्री अरविन्दों अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान संस्थान आरोकिरे	16,24,468.00 रु०
4	श्री अरविन्दों अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र पांडिचेरी	14,69,016.00 रु०
5.	मित्रा विवेकानंद, बेल्लानाद	2,00,000.00 रु०

केन्द्रीय प्राथमिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ये जनाओं*
के कार्यन्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों
के सहायता संबंधी परिशिष्ट

*नवीन विद्यालय पूर्ण रूप से केन्द्र सरकार द्वारा वित्तपोषित किए जाते हैं।

आग्नेय एशियाई क्षेत्र के लिए राज्यों/संघों के प्रतिष्ठित क्षेत्रों को लक्ष्यता

क्र० सं०	राज्य/संघ का नाम	जारी की गई जनसंख्या					(लाख रुपये)
		1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92 अनुमानित	
1	आन्ध्र प्रदेश	621.62	1590.77	1209.29	2095.00	3320.00	
2	अरुणाचल प्रदेश	63.17	71.81	46.76	82.16	82.16	
3	असम	826.69	0.00	692.41	420.48		
4	बिहार	1868.41	2151.64	1407.66	1684.02	991.26	
5	गोवा	12.03	23.62	37.32	47.47	24.77	
6	गुजरात	466.43	0.00	727.44	503.10	1021.06	
7	हरियाणा	62.93	117.33	111.39		370.32	
8	हिमाचल प्रदेश	148.75	280.94	458.09	297.03	456.20	
9	जम्मू व कश्मीर	156.90	347.04	0.00		617.22	
10	कर्नाटक	168.67	853.09	537.08	717.54	1434.54	
11	केरल	151.11	223.44	0.00	156.12	82.90	
12	मध्य प्रदेश	1194.10	1981.26	0.00	1344.78	652.47	
13	महाराष्ट्र	545.03	0.00	788.33	612.22	1167.03	
14	मणिपुर	38.03	98.78	0.00	47.88	62.12	
15	मेघालय	78.37	0.00	0.00	100.49	177.09	
16	मिजोरम	11.80	22.88	8.74	8.87	51.26	
17	नागालैंड	25.66	24.67	42.98	5.85	5.85	
18	उड़ीसा	753.00	1105.45	864.25	1818.32	954.63	
19	पंजाब	334.11	384.25	115.69	219.29	502.59	
20	राजस्थान	1175.55	1123.68	1568.63	3456.83	2345.18	
21	सिक्किम	41.57	9.06	0.00	15.36	15.36	
22	तमिलनाडु	480.80	856.92	1213.02	510.24	449.96	
23	त्रिपुरा	42.12	0.00	49.59	7.70	60.22	
24	उत्तर प्रदेश	1759.43	1893.44	2757.26	860.94	1512.00	
25	पश्चिम बंगाल	0.00	384.34	0.00	349.46	140.02	
26	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह		0.00	0.00	8.27		
27	चंडीगढ़	0.00	0.00	1.17			
28	दादरा और नागर हवेली		1.99	0.00	0.00	4.14	11.99
29	दमन व दीव	0.00	1.19	0.00			
30	दिल्ली	32.49	0.00	32.39	53.59		
31	लक्षद्वीप	0.48	0.00	0.00			
32	पुडुचेरी	0.00	27.20	20.32	10.72	10.72	
	कुल	11061.24	13572.80	12698.08	15009.12	16939.40	

अनौपचारिक शिक्षण योजना के लिए राज्यों/संघ शामिल क्षेत्रों के सहायता

(लाख रुपये)

क्र० सं०	राज्य/संघ शामिल क्षेत्र का नाम	जारी की गई धनराशि				
		1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92 (अनुमान)
1	आन्ध्र प्रदेश	318 14	498 00	650 55	581 78	616 36
2	असम	182 01	203 23	264 96	159 40	181 88
3	बिहार	1030 76	466 25	88 02	667 72	233 55
4	हरियाणा	11 46				—
5	जम्मू व कश्मीर		64 68			—
6	कर्नाटक	23 80	57 03			—
7	मध्य प्रदेश	340 60	605 64	628 32	781 95	695 86
8	पिछोरा	2 19	2 07	2 22	2 06	2 44
9	उड़ीसा	100 11	341 33	259 85	109 84	241 56
10	राजस्थान	183 36	164 69	165 89	236 61	361 61
11	तमिलनाडु	7 02	6 39			—
12	उत्तर प्रदेश	1082 33	544 31	485 30	925 47	1616 35
13	पश्चिम बंगाल	267 18	100 00	41 49		—
14	अडमान व निकोबार द्वीपसमूह		0 18			—
15	चंडीगढ़	1 29	1 42	0 85	2 82	2 25
16	दादरा और नागर हवेली		2 06			—
17	मणिपुर		10 27		24 59	62 47
18	गुजरात			40 74		—
	कुल	3552 49	3065 31	2628 19	3492 24	4014 03

वित्तीय प्रतिक्षण कार्यक्रम के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सहायता

(लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र के नाम	जारी की गई धनराशि				
		1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92 (15.1.92 तक)
1	आन्ध्र प्रदेश	267.76	276.85	416.39	106.00	365.25
2	अरुणाचल प्रदेश	35.70	3.00	0.00	—	—
3	असम	182.75	264.90	182.45	35.00	88.30
4	गोवा	0.00	0.00	28.30	2.00	5.50
5	गुजरात	281.29	183.23	0.00	—	—
6	हरियाणा	66.50	178.40	10.00	52.82	78.23
7	हिमाचल प्रदेश	0.00	129.30	0.00	—	—
8	जम्मू व कश्मीर	150.35	156.15	174.70	—	168.20
9	केरल	60.74	100.40	280.00	94.81	49.70
10	मध्य प्रदेश	448.42	490.60	439.20	386.28	—
11	महाराष्ट्र	0.00	380.80	0.00	—	—
12	मणिपुर	0.00	33.70	0.00	1.00	—
13	मिजोरम	31.50	3.00	0.00	31.85	23.50
14	नागालैण्ड	0.00	32.00	0.00	28.00	—
15	उड़ीसा	274.05	211.95	198.77	33.00	140.67
16	पंजाब	179.00	86.00	152.30	108.40	—
17	राजस्थान	335.40	349.85	547.04	438.15	149.56
18	सिक्किम	0.00	35.50	0.00	—	36.88
19	तमिलनाडु	208.70	342.50	798.52	105.00	319.00
20	त्रिपुरा	0.00	0.00	26.60	—	—
21	उत्तर प्रदेश	536.46	363.87	250.63	363.59	—
22	पश्चिम बंगाल	132.69	15.00	0.00	147.69*	—
23	दिल्ली	56.20	14.90	63.97	40.05	74.57
24	पांडिचेरी	—	—	—	—	30.00
	कुल	3247.51	3651.90	3568.87	1678.26	1529.36

*परियोजनाओं का क्रियान्वयन न होने के कारण वर्ष 1987-88 और 1988-89 में जारी की गयी सस्वीकृतियां मार्च, 1991 में रद्द कर दी गईं।

संवसारीकरण योजना के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सहायता

(लाख रुपए)

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र के नाम	जाते की गई धनराशि				
		1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92 (दिसम्बर 1991 तक)
1	आन्ध्र प्रदेश	562.63	730.32	177.06	886.85	225.54
2	अरुणाचल प्रदेश					
3	असम	30.10	82.61		42.62	140.20
4	बिहार	136.09		7.41	558.61	
5	गोवा	68.53	28.47	64.59	80.63	49.00
6	गुजरात		236.64	1173.31	778.031	455.00
7	हरियाणा	276.12	353.03	129.87	184.83	150.00
8	हिमाचल प्रदेश	30.90	1.86	98.06	177.475	54.00
9	जम्मू व कश्मीर				16.50	
10	कर्नाटक	93.00	244.70	49.21	156.80	
11	केरल		226.42	223.44	353.23	
12	मध्य प्रदेश	57.16	745.00	1121.48	1221.42	
13	महाराष्ट्र	495.90	469.66	509.38	267.21	400.00
14	मणिपुर		11.68			
15	मेघालय				20.75	
16	मिजोरम	21.42	7.12		16.58	
17	नागालैंड	8.00			14.84	
18	उड़ीसा	156.19	600.00	83.72	510.40	
19	पंजाब	211.09		50.25	371.71	
20	राजस्थान	58.34	159.22	72.35	561.543	59.93
21	सिक्किम				5.325	
22	तमिलनाडु	112.50	225.00	358.11	279.558	
23	त्रिपुरा					
24	उत्तर प्रदेश	829.88	800.00	203.69	707.25	97.35
25	पश्चिम बंगाल	40.69				
26	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह			3.34	3.238	
27	चंडीगढ़		42.70	42.70	12.34	12.15
28	दादरा व नगर हवेली					
29	दमन व दीव					
30	दिल्ली	36.52		4 1842.86		
31	लक्षद्वीप					
32	पुद्दुचेरी				16.63	
कुल		3225.62	4964.43	4372.05	7287.33	1022.50

*वर्ष 1988-89 में चंडीगढ़ के लिए 42.70 लाख रु. दर्शाए गए थे जिनका वर्ष 1988-89 के दौरान चंडीगढ़ सरकार द्वारा दावा नहीं किया जा सका।

विज्ञान शिक्षा योजना के लिए राज्यो / संघशासित क्षेत्रो को सहायता

(लाख रुपए)

		जारी की गई धनराशि				
क्र.सं.	राज्य / संघशासित क्षेत्र का नाम	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92 (दिसम्बर, 91 तक)
1	आंध्र प्रदेश	99.25	107.25	400.37	132.25	—
2	अरुणाचल प्रदेश		3.72			—
3	असम		295.32	90.25	141.66	—
4	बिहार		365.44	11.24		—
5	गोआ	35.99		36.03	56.76	—
6	गुजरात			142.31		—
7	हरियाणा		279.66			—
8	हिमाचल प्रदेश	99.55	216.13		139.84	—
9	जम्मू व कश्मीर	30.67		97.95	167.10	—
10	कर्नाटक	417.70	95.69	45.75	167.88	—
11	केरल	200.92		199.43	152.72	—
12	मध्य प्रदेश	113.55	300.00	244.56	7.28	—
13	महाराष्ट्र	626.10			5.42	—
14	मणिपुर		108.00		87.05	—
15	मिजोरम				35.20	—
16	मिजोरम	13.78		87.76	84.42	—
17	नागालैंड	71.55		8.40		—
18	उड़ीसा	200.00		268.82		—
19	पंजाब	130.06		1.37	349.97	171.14
20	राजस्थान	349.52			139.84	—
21	सिक्किम			12.41	20.14	—
22	तमिलनाडु	217.69	194.41	251.13	93.37	—
23	त्रिपुरा		27.45		0.74	—
24	उत्तर प्रदेश	313.47	300.00	98.10	13.45	—
25	पश्चिम बंगाल		514.37		147.18	—
26	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	7.34		21.52	5.84	—
27	चंडीगढ़	5.82			20.18	—
28	दादरा व नगर हवेली				5.22	—
29	दिल्ली	53.47	73.42	102.59	55.60	—
30	दमन व दीव			4.56		—
31	लक्षद्वीप	0.23		1.28		—
32	पॉण्डिचेरी		20.82	7.03	4.32	—
	कुल	2926.66	2901.58	2132.86	2033.43	171.14

शैक्षिक प्रौद्योगिकी योजना के लिए राज्यों / संघशासित क्षेत्रों को सहायता

(लाख रुपए)

जारी की गई धनराशि

क्र.सं.	राज्य / संघशासित क्षेत्र का नाम	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92 (15.1.92 तक)
1	आंध्र प्रदेश	247 00	278 11	113 00	227 90	37 74
2	अरुणाचल प्रदेश	—	1 72	1 14		
3	असम	—	20 92	42 20	73 53	
4	बिहार	—	23 54	8 33		6 49
5	गोआ	3 24	3 31	1 76	5 29	
6	गुजरात	273 75	—	173 65	96 19	
7	हरियाणा	—	7 04	39 90	50 00	
8	हिमाचल प्रदेश	9 62	10 72	45 80		
9	जम्मू व कश्मीर	—	9 00	17 82	102 99	
10	कर्नाटक	22 52	60 38	66 37	15 81	
11	केरल	7 16	13 46	27 87		12 11
12	मध्य प्रदेश	—	193 80	30 46	29 16	
13	महाराष्ट्र	—	72 00	93 00	126 20	
14	मणिपुर	—	1 82	1 21	10 08	16 14
15	मेघालय	—	0 90	4 23	5 00	5 08
16	मिजोरम	2 18	6 03	9 13		0 11
17	नागालैंड	2 82	—	7 72		
18	उड़ीसा	45 84	78 03	128 80	258 25	
19	पंजाब	—	19 84	48 23	60 00	
20	राजस्थान	—	113 62	91 92		
21	सिक्किम	—	2 82	1 88	3 50	
22	तमिलनाडु	—	30 00	70 00	100 00	
23	त्रिपुरा	—	0 26	0 17	0 06	
24	उत्तर प्रदेश	72 00	112 26	20 84		
25	पश्चिम बंगाल	—	19 46	12 97		
26	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	—	0 48	0 32	0 50	
27	चंडीगढ़	—	1 37	0 48	1 11	
28	दिल्ली	78 64	36 11			
29	दमन व दीव	—	0 18	0 12		
30	दादरा व नागर हवेली	0 33	—	0 22		0 38
31	लक्षद्वीप	0 16	0 03	0 13		
32	पांडिचेरी	—	1 84	1 23		
	कुल	715 26	1119 05	1060 90	1165 57	78 14

ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ (ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ)

ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ / ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ
 1987-88 1988-89 1989-90 1990-91 1991-92 (ਫਿਕਸਡ, 1991 ਰੁਪਏ)

1	ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ	22.27	4.81	20.16	
2	ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ	4.81			
3	ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ	4.20			
4	ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ	20.17			
5	ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ			8.45	
6	ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ				
7	ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ		0.66		
8	ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ	9.15			
9	ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ	8.04	24.11	58.90	
10	ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ		2.07		
11	ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ	9.60	28.80		
12	ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ		9.73		
13	ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ	1.82	1.97		
14	ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ	18.47		16.56	
15	ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ	37.52		33.86	
16	ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ	17.73	16.55	9.12	
17	ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ	3.04			
18	ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ		13.85		
19	ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ	2.48	7.73	9.71	
20	ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ	0.94		2.16	
21	ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ				12.85
22	ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ	160.34	110.29	158.92	

विकलांग बच्चों की एकीकृत शिक्षा के लिए राज्यों / क्षेत्राधिकार क्षेत्रों को आवंटित

(लाख रुपए)

जारी की गई धनराशि

क्र.सं० राज्य / क्षेत्राधिकार क्षेत्र का नाम	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92 (31.12.91 तक)
1. आंध्र प्रदेश		14.71		12.80	
2. बिहार	10.10	1.70	2.62	7.67	
3. गुजरात	4.24		8.57	5.87	21.04
4. हरियाणा			20.55	19.77	
5. हिमाचल प्रदेश		8.24	5.63	7.40	7.21
6. जम्मू और कश्मीर				19.98	
7. कर्नाटक	16.29	28.78	10.86		12.24
8. केरल	61.08	55.00	60.00	100.47	0.00
9. मध्य प्रदेश		0.63	1.16	17.40	
10. मणिपुर				3.97	
11. महाराष्ट्र	16.40	19.42	14.27		
12. मिजोरम	10.00	10.00	16.79	24.79	31.72
13. नागालैंड	5.55	10.76	10.74	9.36	10.74
14. उत्तरांचल	18.47	13.99	15.03	23.87	22.47
15. पंजाब	4.17	4.58			10.00
16. राजस्थान	48.26		33.23	33.44	3.67
17. तमिलनाडु				5.76	
18. उत्तर प्रदेश	9.55		11.95	16.97	
19. अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	11.41	14.28	15.65	13.90	16.04
20. दिल्ली	10.58	11.77	12.17	18.92	
21. पंडिचेरी			0.09	0.45	
22. दमन व दीव				0.49	0.55
कुल	226.10	193.86	239.31	343.28	137.90

Table 9-6: (continued)

Table 9-6

Table 9-6: (continued)

Year	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93
1	115.80	227.90	270.92	287.25	67.82	273.15
2	19.12	42.48	61.59	44.85	6.58	43.30
3	159.94	296.13	372.11	375.94	104.79	344.45
4	10.61	17.99	20.12	25.81	4.32	21.30
5	32.72	73.27	85.24	86.89	25.44	82.40
6	50.87	94.18	124.73	110.51	47.29	121.45
7	71.16	109.65	128.34	140.70	31.79	123.35
8	88.13	125.46	143.66	148.62	30.57	154.20
9	110.23	223.88	247.72	259.37	57.06	252.50
10	75.09	140.47	142.85	183.92	39.86	150.90
11	161.18	285.10	323.43	317.15	96.87	322.15
12	128.35	211.99	261.49	272.70	71.53	269.25
13	17.29	67.88	77.30	88.01	25.24	72.90
14	28.66	29.20	36.17	35.02	3.13	29.25
15	17.73	18.85	17.63	19.16	3.68	13.35
16	13.34	12.16	12.83	12.22	9.35	4.60
17	97.06	155.21	171.21	162.32	43.30	164.60
18	45.71	67.56	99.44	96.38	30.36	98.35
19	86.08	201.19	254.58	243.33	93.88	248.85
20	7.99	7.04	9.24	13.18	1.01	9.60
21	—	4.08	13.39	10.35	4.31	12.25
22	171.72	307.60	402.42	407.17	119.76	366.95
23	12.83	18.30	28.85	32.50	3.98	24.40
24	4.04	5.77	9.79	11.02	7.15	10.85
25	—	8.79	10.24	9.34	3.32	10.00
26	4.35	10.46	12.38	12.48	4.20	11.45
27	15.27	17.25	14.35	14.53	0.30	11.30
28	—	16.34	8.13	15.24	2.97	7.90
29	28.21	45.26	54.56	55.36	10.01	54.95
30	555.45	2836.62	3414.04	3490.93	942.74	3314.70
31	128.71	45.26	54.56	55.36	10.01	54.95
32	—	16.34	8.13	15.24	2.97	7.90

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢١٣١٤١٥١٦١٧١٨١٩٢٠٢١٢٢٢٣٢٤٢٥٢٦٢٧٢٨٢٩٣٠٣١٣٢٣٣٣٤٣٥٣٦٣٧٣٨٣٩٤٠٤١٤٢٤٣٤٤٤٥٤٦٤٧٤٨٤٩٥٠٥١٥٢٥٣٥٤٥٥٥٦٥٧٥٨٥٩٦٠٦١٦٢٦٣٦٤٦٥٦٦٦٦٧٦٨٦٩٧٠٧١٧٢٧٣٧٤٧٥٧٦٧٧٧٨٧٩٨٠٨١٨٢٨٣٨٤٨٥٨٦٨٧٨٨٨٩٩٠٩١٩٢٩٣٩٤٩٥٩٦٩٧٩٨٩٩١٠١١١٢١٣١٤١٥١٦١٧١٨١٩٢٠٢١٢٢٢٣٢٤٢٥٢٦٢٧٢٨٢٩٣٠٣١٣٢٣٣٣٤٣٥٣٦٣٧٣٨٣٩٤٠٤١٤٢٤٣٤٤٤٥٤٦٤٧٤٨٤٩٥٠٥١٥٢٥٣٥٤٥٥٥٦٥٧٥٨٥٩٦٠٦١٦٢٦٣٦٤٦٥٦٦٦٦٧٦٨٦٩٧٠٧١٧٢٧٣٧٤٧٥٧٦٧٧٧٨٧٩٨٠٨١٨٢٨٣٨٤٨٥٨٦٨٧٨٨٨٩٩٠٩١٩٢٩٣٩٤٩٥٩٦٩٧٩٨٩٩

विवरण—2
साक्षरता दर भारत—1951-1991

वर्ष	व्यक्ति	पुरुष	महिलाएँ	
1951	18.33	27.16	8.26	
1961	28.31	40.40	15.34	
1971	34.45	45.95	21.97	
1981	43.56	56.37	29.75	
	(41.42)	(53.45)	(28.46)	
1991	52.11	63.86	39.42	

टिप्पणी: 1. वर्ष 1951, 1961 तथा 1971 की साक्षरता अनुपात पाच वर्ष और इससे अधिक उम्र वाली जनसंख्या से संबंधित है। वर्ष 1981 और 1991 का यह अनुपात सात वर्ष और इससे अधिक उम्र वाली जनसंख्या से संबंधित है। वर्ष 1981 से संबंधित पाच वर्ष और इससे अधिक उम्र वाली जनसंख्या का साक्षरता अनुपात कोष्ठक में दर्शाया गया है।

2. वर्ष 1981 के अनुपात में असम शामिल नहीं है क्योंकि वहां 1981 की जनगणना नहीं हो पायी थी वर्ष 1991 की जनगणना में जम्मू और कश्मीर को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि वहां अभी 1991 की जनगणना पूरी नहीं हो पाई है।

सात वर्ष वर्ष और इससे अधिक आयु वाली जनसंख्या में साक्षरों की संख्या—भारत
1981-1991

वर्ष	व्यक्ति	पुरुष	महिलाएं
(1)	(2)	(3)	(4)
साक्षर			
1981	233,947	156,953	76,994
1991	352,082	224,288	127,794
	118,315	67,335	50,980
1981 से 1991 में वृद्धि			
निरक्षर			
1981	301,933	120,902	161,031
1991	324,030	126,694	197,336
	22,097	3,792	16,305
1981 से 1991 में वृद्धि			

1 इन आंकड़ों में असम तथा जम्मू और कश्मीर के आंकड़े शामिल नहीं हैं। क्योंकि असम की 1981 की जनगणना का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है क्योंकि 1981 की जनगणना वहां नहीं हो पाई जबकि जम्मू और कश्मीर का 1991 की जनगणना आंकड़ा नहीं है क्योंकि 1991 की जनगणना वहां अभी होनी शेष है।

2 1991 का साक्षर जनसंख्या का आंकड़ा 1991 की जनगणना के अग्रिम परिणामों के अनुसार है। सात वर्ष और इससे अधिक आयु वर्ग की निरक्षर जनगणना के आंकड़े का अंदाजा जनसंख्या आयु संरचना पर आधारित कुछ संकल्पनाओं के आधार पर लगाया है और इसमें परिवर्तन हो सकता है।

विवरण—4

सात वर्ष और इससे ऊपर की आयु वर्ग की अनुमानित जनसंख्या में साक्षरों की प्रतिशतता

भारत	व्यक्ति	1981		1991	
		पुरुष	महिलाएँ	व्यक्ति	महिलाएँ
भारत	43 57	56 37	29 75	52 11	63 86
1 आन्ध्र प्रदेश	35 66	46 83	24 16	45 1156 24	33 71
2 अरुणाचल प्रदेश	25 54	35 11	14 01	41 22	51 10
3 असम	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	53 42	62 34
4 बिहार	32 03	46 58	16 51	38 54	52 63
5 गोआ	65 71	76 01	55 17	76 95	85 46
6 गुजरात	52 21	65 14	38 45	50 91	72 54
7 हरियाणा	43 85	58 49	26 89	55 33	67 85
8 हिमाचल प्रदेश	51 17	64 27	37 72	63 54	74 57
9 जम्मू व कश्मीर	32 68	44 18	19 55	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
10 कर्नाटक	46 20	58 72	33 16	55 98	67 25
11 केरल	81 56	87 56	75 65	90 59	94 45
12 मध्य प्रदेश	34 22	48 41	18 99	43 45	57 43
13 महाराष्ट्र	55 83	69 66	41 01	63 05	74 84
14 मणिपुर	49 61	64 12	34 61	60 96	72 98
15 मेघालय	42 02	46 62	37 15	48 26	51 57
16 मिजोरम	74 26	79 37	68 60	81 23	84 06
17 नागालैंड	50 20	58 52	40 28	61 30	66 09
18 उड़ीसा	40 96	56 45	25 14	48 55	62 37
19 पंजाब	48 12	55 52	39 64	57 14	63 68
20 राजस्थान	30 09	44 76	13 99	38 81	55 07
21 सिक्किम	41 57	52 98	27 35	56 53	64 34
22 तमिलनाडु	54 38	68 05	40 43	63 72	74 85
23 त्रिपुरा	50 10	61 49	38 01	60 39	70 08
24 उत्तर प्रदेश	33 33	47 43	17 18	41 71	55 35
25 पश्चिम बंगाल	48 64	59 93	36 07	57 72	67 24
26 अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	63 16	70 28	53 15	73 74	79 68
27 चंडीगढ़	74 81	78 89	69 31	78 73	82 67
28 दादरा और नगर हवेली	32 70	44 69	20 38	39 45	52 07
29 दमन और दीव	59 91	74 45	46 51	73 58	85 67
30 दिल्ली	71 93	79 28	62 57	76 09	82 63
31 लक्षद्वीप	68 42	81 24	55 32	79 23	87 06
32 पांडिचेरी	65 14	77 09	53 03	74 91	83 91

वर्ष 1981 के साक्षरता अनुपात में असम शामिल नहीं है जहां 1981 की जनगणना नहीं हो पाई थी तथा 1991 के साक्षरता अनुपात में जम्मू और कश्मीर शामिल नहीं है जहां 1991 की जनगणना अभी की जानी है। वर्ष 1981 और 1991 का भारत का साक्षरता अनुपात निम्नलिखित है, इसमें असम तथा जम्मू और कश्मीर के आंकड़े नहीं हैं।

	व्यक्ति	पुरुष	महिलाएँ
1981	43 66	56 49	29 84
1991	52 07	63 90	39 31

बिबरण-5

भूमिगत, फुल्लों, पट्टिलानों के बीच लक्षरता दर लेखनी राज्य/संघ शासित प्रदेशों का अवरोही क्रम: 1991

क्रमांक	राज्य / संघ शासित प्रदेश	व्यक्ति	पुरुष	महिलाएं
क्रमांक	राज्य / संघ शासित प्रदेश	साक्षरता राज्य/ संघ शासित प्रदेश दर	साक्षरता राज्य/ संघ शासित प्रदेश दर	साक्षरता दर
1	केरल	90.59	केरल	86.93
2	मिजोरम	81.23	मिजोरम	78.09
3	लक्षद्वीप	79.23	दमन और दीव	79.61
4	चंडीगढ़	78.73	गोवा	70.88
5	गोवा	76.96	मिजोरम	68.20
6	दिल्ली	76.09	पंडिचेरी	68.01
7	पंडिचेरी	74.91	चण्डीगढ़	66.22
8	अ० और नि० द्वीप समूह	73.74	दिल्ली	65.79
9	दमन और दीव	73.58	अ० और नि० द्वीप समूह	61.38
10	तमिलनाडु	63.72	तमिलनाडु	55.72
11	हिमाचल प्रदेश	63.54	महाराष्ट्र	52.46
12	महाराष्ट्र	63.05	हिमाचल प्रदेश	52.29
13	नागालैंड	61.30	मणिपुर	50.51
14	मणिपुर	60.96	गुजरात	50.01
15	गुजरात	60.91	त्रिपुरा	49.72
16	त्रिपुरा	60.39	हरियाणा	48.64
17	पश्चिम बंगाल	57.72	कर्नाटक	48.50
18	पंजाब	57.14	पश्चिम बंगाल	47.23
19	सिक्किम	56.53	नागालैंड	47.15
20	कर्नाटक	55.98	सिक्किम	44.78
21	हरियाणा	55.33	पंजाब	44.34
22	असम	53.42	उड़ीसा	43.70
23	उड़ीसा	52.11	असम	40.94
24	मेघालय	48.26	मध्य प्रदेश	34.40
25	आन्ध्र प्रदेश	45.11	आन्ध्र प्रदेश	33.71
26	मध्य प्रदेश	43.45	उत्तर प्रदेश	29.37
27	उत्तर प्रदेश	41.71	छत्तीसगढ़	28.39
28	अरुणाचल प्रदेश	41.22	बिहार	26.10
29	दादरा और नगर हवेली	39.45	दादरा और नगर हवेली	26.02
30	छत्तीसगढ़	38.81	मेघालय	23.10
31	बिहार	38.54	अरुणाचल प्रदेश	20.84

जम्मू और कश्मीर शामिल नहीं है जहां 1991 की जनगणना अभी होनी बाकी है।

चित्रण संख्या 6
परिष्ठीलित जनसंख्या
(1 मार्च-1991 की व्याख्या के अनुसार)

(‘00 में)

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	सभी आयु वर्ग		6-11 वर्ष			11-14 वर्ष		अनु-जनजाति
		योग	अनु-जा०	अनु-जा०	योग	अनु-जा०	अनु-जा०	योग	
1	आन्ध्र प्रदेश	663049	39595	39319	70270	10450	4167	39492	2342
2	अरुणाचल प्रदेश	8584	42	5987	1070	4	748	578	404
3	असम	222946	13910	24502	31767	1938	4066	18501	1129
4	बिहार	863388	125252	71748	104836	15211	8712	58089	8429
5	गोवा	11686	254	113	1320	28	12	762	16
6	गुजरात	411741	29448	58550	46264	3313	6588	26695	1912
7	हरियाणा	163177	31119	0	20210	3854	0	11136	2123
8	हिमाचल प्रदेश	51111	12579	2361	5889	1450	271	2325	843
9	जम्मू कश्मीर	77187	6412	0	8679	721	0	4920	409
10	कर्नाटक	448174	67522	22050	52639	7932	2585	29936	4511
11	केरल	290112	29055	2988	30805	3807	317	17690	1773
12	मध्य प्रदेश	661359	93258	151914	76979	10854	17682	42647	6013
13	महाराष्ट्र	787067	56165	72331	81383	5811	7479	48075	3432
14	मणिपुर	18267	228	4987	2356	30	641	1184	15
15	मेघालय	17606	73	14185	2288	8	1844	1259	4
16	मिजोरम	6862	0	6423	803	0	751	490	0
17	नागालैंड	12156	0	10207	1368	0	1149	815	0
18	उड़ीसा	315121	46190	70682	35313	5177	7921	20542	3012
19	पंजाब	201908	54255	0	21468	5766	0	12515	3362
20	राजस्थान	438806	74781	53578	57892	10073	7069	30752	5351
21	सिक्किम	4036	231	935	591	34	137	322	19
22	तमिलनाडु	556383	102080	5953	57960	10636	620	32986	6053
23	त्रिपुरा	27448	4144	7812	2923	443	531	1598	242
24	उत्तर प्रदेश	1387604	293562	2914	171272	36241	359	94481	19992
25	पश्चिम बंगाल	679827	149474	38655	74010	16275	4637	41430	911
26	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2780	0	334	427	0	52	214	0
27	चंडीगढ़	6407	904	0	819	115	0	467	65
28	दादरा और नगर हवेली	1385	32	1097	168	4	132	98	2
29	दमन और दीव	1014	22	10	"	"	"	"	"
30	दिल्ली	93705	16901	0	10209	1839	0	6001	1081
31	लक्षद्वीप	517	0	483	60	0	54	31	0
32	पांडिचेरी	7894	1258	0	745	119	0	452	72
	भारत	843909	1307746	670118	981113	154526	76134	553724	87211

1. ये परिष्ठीलित जनसंख्या के आंकड़े 1981 की जनगणना पर आधारित हैं।
2. * गोवा में सम्मिलित है।

विवरण संख्या 7
साक्षरता दर 1981

(1-3-1981 की यथा स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	सामान्य			अज्ञान			अज्ञानता		
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
1	आन्ध्र प्रदेश									
2	अरुणाचल प्रदेश	39.26	20.39	29.94	24.82	10.26	17.65	12.02	3.46	7.82
3	असम	उन्नत	उन्नत	उन्नत	उन्नत	उन्नत	उन्नत	उन्नत	उन्नत	उन्नत
4	बिहार	38.11	13.62	26.20	18.02	2.51	10.40	26.17	7.75	16.99
5	गोवा	54.44	32.30	43.70	53.14	25.61	39.79	30.41	11.64	21.14
6	गुजरात	48.20	22.27	36.14	31.45	7.06	20.15	—	—	—
7	हरियाणा	53.19	31.46	42.43	41.94	20.63	31.50	38.75	12.82	25.93
8	हिमाचल प्रदेश	36.29	15.88	26.67	32.34	11.70	22.44	—	—	—
9	जम्मू कश्मीर	48.81	27.71	38.46	29.35	11.55	20.59	29.96	10.03	20.14
10	कर्नाटक	75.26	65.73	70.42	62.33	49.73	55.96	37.52	26.02	31.79
11	केरल	39.49	15.53	27.87	30.26	6.87	18.97	17.74	3.60	10.68
12	मध्य प्रदेश	58.78	34.79	47.18	48.85	21.52	35.55	32.38	11.94	22.29
13	महाराष्ट्र	53.24	29.06	41.35	41.44	24.75	33.63	48.88	30.35	39.74
14	मणिपुर	37.89	30.08	34.08	25.28	16.30	25.78	34.19	28.91	31.35
15	मेघालय	50.06	33.89	42.57	—	—	—	47.32	32.99	40.32
16	मिजोरम	47.10	21.12	34.23	55.26	9.40	22.41	23.27	4.76	13.96
17	नागालैंड	47.16	33.69	40.86	30.96	15.67	23.86	—	—	—
18	उड़ीसा	36.30	11.42	24.38	24.40	2.69	14.04	18.85	1.20	10.27
19	पंजाब	43.95	22.20	34.25	35.74	19.65	28.06	43.10	22.37	33.13
20	राजस्थान	58.26	34.99	46.76	40.65	18.41	29.67	26.71	14.00	20.46
21	सिक्किम	51.70	32.00	42.12	43.92	23.24	36.89	33.46	12.27	23.07
22	तमिलनाडु	38.76	14.04	27.16	24.83	3.90	14.96	31.12	8.69	—
23	त्रिपुरा	50.67	30.25	40.94	34.28	13.70	24.37	21.16	5.01	13.21
24	उत्तर प्रदेश	58.72	42.74	51.56	—	—	—	38.43	23.24	31.11
25	पश्चिम बंगाल	28.94	11.32	20.79	45.88	22.38	37.14	20.79	7.31	14.04
26	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	69.00	59.31	64.79	46.04	25.31	37.07	—	—	—
27	चंडीगढ़	36.32	16.78	26.67	58.52	44.74	51.20	25.46	8.42	16.86
28	दादर और नगर हवेली	68.40	53.07	61.54	50.21	25.89	39.30	—	—	—
29	दमन और दीव	65.59	47.56	56.66	48.79	27.84	38.38	33.65	18.89	26.48
30	दिल्ली	65.24	44.65	55.07	—	—	—	63.34	42.92	53.13
31	लक्षद्वीप	64.46	54.91	59.88	88.33	53.33	64.44	64.12	55.12	59.63
32	पांडिचेरी	65.84	45.71	55.85	43.11	21.21	32.36	—	—	—
33	योग	46.89	24.82	36.23	21.12	10.93	21.36	24.52	8.04	16.35

ये जनगणना नहीं की गई

भाग की जनगणना, प्रक्रिया

भाग के 1981 की जनगणना और निम्नलिखित क्षेत्रों में जनगणना के लिए किया जा जाने का अनुमानित जनगणना हरियाणा जम्मू और कश्मीर पंजाब चंडीगढ़ दिल्ली और पांडिचेरी में किसी जाति को अनुसूचित जनजाति नहीं घोषित किया गया है।

साक्षरता दर में 0.4 वर्ष के उम्र वाले शामिल हैं।

विवरण सं० 8
अंजा की साक्षरता दर में राज्यो/स्थगित राज्यो का क्रम 1981 जनगणना

(13.1981 की पथस्थिति अनुसार)

श्रेणी	राज्य : स शा० रा	अंजा : साक्षरता %
1.	मिजोरम	84.41
2.	केरल	55.46
3.	दादरा और नगर हवेली	51.21
4.	गुजरात	30.74
5.	दिल्ली	32.30
6.	गोआ दीव दमन	38.32
7.	अरुणाचल प्रदेश	37.41
8.	चंडीगढ़	37.07
9.	महाराष्ट्र	25.55
10.	त्रिपुरा	23.84
11.	मणिपुर	22.07
12.	पाकिस्तान	32.32
13.	हिमाचल प्रदेश	21.52
14.	तमिलनाडु	20.07
15.	सिक्किम	28.22
16.	मेघालय	20.74
17.	पश्चिम बंगाल	24.27
18.	पंजाब	23.82
19.	जम्मू कश्मीर	22.00
20.	उड़ीसा	21.4
21.	कर्नाटक	20.52
22.	हरियाणा	20.2
23.	मध्य प्रदेश	18.27
24.	आन्ध्र प्रदेश	17.22
25.	उत्तर प्रदेश	14.00
26.	गजपति	14.00
27.	बिहार	10.41
28.	नागालैंड	—
29.	लक्षद्वीप	—
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	—
31.	असम*	—
	कुल	2.22

*असम में जनगणना नहीं हुई थी।

स्रोत: 1981 की जनगणना प्रकाशन

टिप्पणी नागालैंड, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में अनुसूचित जाति नहीं है। साक्षरता दर में 0-4 वर्ष के उम्र वर्ग वाले शामिल हैं।

विवरण सं० ९

वर्ष 1981 की जनगणना के आधार पर अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दरों में राज्यों/सघ शासित राज्यों की स्थिति

(1-3-1991 की दथस्थिति)

1	मिजोरम	59.63
2	लक्षद्वीप	53.15
3	नागालैंड	40.32
4	मणिपुर	39.74
5	सिक्किम	33.13
6	केरल	31.79
7	मेघालय	31.35
8	अंडम और निकोबार	31.11
9	दमन और दीव	26.48
10	हिमाचल प्रदेश	25.93
11	त्रिपुरा	23.07
12	महाराष्ट्र	22.29
13	गुजरात	21.14
14	तामिलनाडु	20.46
15	उत्तर प्रदेश	20.45
16	कर्नाटक	20.14
17	बिहार	16.97
18	दादरा और नगोव	16.86
19	अरुणाचल प्रदेश	14.04
20	उड़ीसा	13.96
21	पश्चिम बंगाल	13.21
22	मध्य प्रदेश	10.68
23	राजस्थान	10.27
24	आन्ध्र प्रदेश	7.82
25	पंजाब	—
26	हरियाणा	—
27	चंडीगढ़	—
28	जम्मू और कश्मीर	—
29	दिल्ली	—
30	असम	—
31	पांडिचेरी	—
	योग	16.35

असम में जनगणना नहीं हो पाई थी।

वर्ष 1981 की जनगणना प्रकारान

एक ही हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, पंजाब चंडीगढ़, दिल्ली और पांडिचेरी में अनुसूचित जनजातियां नहीं हैं।

0—4 आयु वर्ग को जनसंख्या साक्षरता दर में शामिल है।

विवरण सं० 10

वर्ष 1951 के मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं की वृद्धि

वर्ष	प्राथमिक	अपर प्राथमिक	हार्ड / हायर मेकेण्डरी स्कूल इटर मीन / प्रिडिमी जूनियर कॉलेज	सामान्य शिक्षा कॉलेज	व्यावसायिक शिक्षा कॉलेज	विश्वविद्यालय
1950-51	209671	13596	7416	370	208	27
1960-61	330399	49663	17329	967	852	45
1970-71	408378	90621	37051	2285	992	82
1980-81	494503	115335	51624	3421	1156	110
1990-91	558392	146636	78619	4862	886	146

विषय सं० 12
स्कूल के प्रकार के अनुसार वर्ष 1951 से शिक्षकों का वितरण

वर्ष	प्राथमिक			अपर प्राथमिक			हाई / हायर सेकेंडरी		
	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	कुल
1950-51	456	82	538	73	13	86	107	20	127
1960-61	615	127	742	262	83	345	234	62	296
1970-71	835	225	1060	463	175	638	474	155	629
1980-81	1020	343	1363	598	253	851	658	254	912
1990-91	1167	470	1637	706	353	1059	857	416	1273

विश्वविद्यालय संख्या 13
शैक्षणिक संस्थाएं (1990-91)

30 सितम्बर, 1990 की यथा स्थिति

क्र.सं.	राज्य / संघशासित क्षेत्र का नाम	प्रादेशीय	मिडिल	हाई स्कूल हायर सैकेंडरी इंटरमीडिएट पि-टिग्री जूनियर कॉलेज	साथ-अन्य कॉलेज	शिक्षा प्रौ. और शिक्षा	विश्वविद्यालय*
1	ओडिशा प्रदेश	48731	6118	6695	403	82	17
2	अरुणाचल प्रदेश	1122	254	113	4	0	1
3	असम	28876	5702	3443	213	15	3
4	बिहार	53252	13170	4097	557	31	11
5	गोआ	1014	112	372	15	4	1
6	गुजरात	13174	17084	5075	230	59	10
7	हरियाणा	4922	1321	2266	119	22	4
8	हिमाचल प्रदेश	7522	1101	1037	39	4	3
9	जम्मू व कश्मीर	8712	2320	1097	27	9	3
10	कर्नाटक	23539	16318	5110	403	132	9
11	केरल	6772	2911	2568	133	31	6
12	मध्य प्रदेश	66849	13977	3973	448	37	12
13	महाराष्ट्र	39121	18849	10374	582	195	18
14	मणिपुर	3226	693	440	31	4	1
15	मेघालय	4163	693	303	23	1	1
16	मिजोरम	1109	544	205	13	1	1
17	नागालैंड	1287	341	148	15	1	0
18	उड़ीसा	40033	9405	4926	244	20	5
19	पंजाब	12372	1425	2743	171	26	4
20	राजस्थान	30231	8629	3733	159	41	9
21	सिक्किम	510	122	75	1	0	0
22	तमिलनाडु	29979	5624	5158	214	71	15
23	त्रिपुरा	2083	436	454	13	2	1
24	उत्तर प्रदेश	76545	14582	5999	418	24	25
25	पश्चिम बंगाल	50827	4179	6804	302	62	11
26	अरुणाचल प्रदेश	186	41	66	2	1	0
27	अरुणाचल प्रदेश	54	27	68	12	2	2
28	दार्जिल और नगर हवेली	120	41	11	0	0	0
29	दमन और दीव	46	20	19	1	0	0
30	दिल्ली	1655	485	1130	63	6	11
31	लक्षद्वीप	19	4	11	0	0	0
32	पंडिचेरी	341	107	106	7	3	1
	घात	558392	146636	78619	4862	886	184

* विश्वविद्यालय और संस्थान समूहों जिनके राष्ट्रीय प्रवर्तक के विश्वविद्यालय और संस्थान शामिल हैं।

इन्फोर्मेशन, प्रौद्योगिकी, जलविद्युत, विज्ञान तथा शिक्षक प्रशिक्षण के कॉलेजों को शामिल है। आंकड़े वर्ष 1988-89 से सम्बंधित हैं।

स्रोत: चुनावी शैक्षणिक आंकड़े 1990-91

विवरण सख्या— 14
विभिन्न स्तरों पर भाषाकर्म 1990-91

30.9.1990 की यथा स्थिति के अनुसार

		प्राथमरी			मिडिल			माध्यमिक			उच्चतर मा-			उच्चतर शिक्षा		
क्र-सं-	राज्य एवं शासित प्रदेश	मानक	मानिक	योग	मानक	मानिक	योग	मानक	मानिक	योग	मानक	मानिक	योग	मानक	मानिक	कुल
1	आंध्र प्रदेश	4301744	3234834	7536578	1343686	780407	2124093	915175	466376	1381551	187723	77444	26516			
2	अरुणाचल प्रदेश	65043	47154	112197	15956	10133	26089	10688	5008	15696	1293	312	61			
3	असम	1893197	1656888	3550085	64027	43770	1076197	341313	235458	576771	78246	33212	1146			
4	बिहार	5723455	2941810	8565263	1559587	560989	2120576	1043970	252742	1296712	401154	94041	2404			
5	गुजरात	77483	64373	135856	43464	57449	80913	32234	26811	59045	5735	5815	1			
6	हरियाणा	3222030	2458000	5680030	1138000	750000	1888000	701000	428000	1129000	158325	113975	212			
7	हिमाचल प्रदेश	954497	734971	1689467	439607	251214	690815	283906	126104	410010	44943	29204	764			
8	झारखण्ड प्रदेश	371102	319123	690225	188467	746131	334798	171205	105178	276383	7249	3357	1303			
9	कर्नाटक	450374	286386	736760	190878	100860	291738	122903	58410	181313	16395	10958	211			
10	केरल	3064914	2617318	5682232	1015914	697952	1713866	798367	377862	1116229	178459	76858	2523			
11	कोलकाता	1623059	1532817	3155876	461533	908127	1869660	573061	589066	116227	77285	88771	1660			
12	मध्य प्रदेश	4862414	3131075	7993489	1764639	889261	2653900	758169	248660	1006829	164317	71032	2352			
13	महाराष्ट्र	5397629	4626412	10022041	2293177	4602467	384644	1968072	1051583	3019655	399508	243778	6402			
14	मणिपुर	143515	121074	264589	42340	36360	78700	39543	29037	68580	12642	8319	200			
15	महाराष्ट्र	124393	181777	306170	39409	12451	69360	31437	27167	58604	4339	2859	100			
16	मिजोरम	63182	57117	120300	19568	19509	39077	11440	10167	21607	1281	918	200			
17	नागालैंड	78610	66602	145410	28617	26904	55521	13641	10974	24615	2072	1007	100			
18	ओडिशा	2174000	1446000	3620000	5485000	427300	973800	614966	313215	928201	50228	17423	600			
19	पंजाब	1106729	947026	2053755	467970	364470	852440	362704	251615	614319	42235	38492	8072			
20	राजस्थान	3141437	13771810	4513247	1033330	285398	1318734	642283	152889	795172	74256	24958	902			
21	सिक्किम	38873	33625	72498	7776	7036	14814	5124	3588	8712	0	0	0			
22	तमिलनाडु	4182459	3581414	7763873	1814246	1344281	3158547	988149	648138	1636287	149787	80977	2100			
23	त्रिपुरा	221284	181220	402504	68964	52502	121466	39797	26023	65820	7330	3505	201			
24	उत्तर प्रदेश	8889785	5050215	13940000	3240428	1229582	4470010	2246912	698903	2947815	359801	115796	4731			
25	पश्चिम बंगाल	5113432	3946089	9274121	1578095	1164672	274267	1588516	540100	1598616	146157	134837	3100			
26	अरुणाचल और मिजोरम द्वीप समूह	21042	18770	39812	9886	8022	17908	6631	5583	12214	962	778	100			
27	चंडीगढ़	26382	21748	48130	13584	7362	25946	23132	18024	41156	7099	6865	730			
28	दार्जिल और नगर प्रखण्ड	9621	6797	16412	2820	1598	4418	1526	905	243	11	11	100			
29	दमन और दीव	42292	4787	47079	4063	3438	7501	7981	2504	6295	202	168	100			
30	दिल्ली	490985	529868	920833	280346	225354	505700	215397	170505	385802	74349	54634	2800			
31	राष्ट्रपति	4518	3830	8348	1743	1409	3152	1081	653	1734	0	11	100			
32	विश्वकर्मा	55394	52036	105630	10551	25298	55849	15418	12683	28101	2964	2321	500			
भारत		58094716	41023604	99118320	20844291	12438708	33282999	14003571	6843831	20847402	2706356	1351614	407707			

* इसमें (सीमेंट) (कोई-को-डेक-को-वाग), विभिन्न (ग्राम-को-को-ग्र) और शिक्षा प्रशिक्षण (को-एड-को-एड) को छोड़कर (को-एड-को-एड-को-एड) और सभी व्यवसायिक (को-एड-को-एड) के बिना यथा स्थिति में शामिल नहीं हैं।
नोट: कुलित सार्वजनिक आवास 1989-90

बिवरण 16
कक्षाओं में दाखिला (अनुसूचित जाति) 1990-91

(30 9 90 को यथास्थिति)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	प्राथमिक			मिडिल			मा. / उ. मा.			उच्च शिक्षा		
		लड़के	लड़कियाँ	कुल योग	लड़के	लड़कियाँ	कुल योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	आन्ध्र प्रदेश	323476	199536	523012	58966	24287	83253	29441	10102	39543	3274	830	4104
2	अरुणाचल प्रदेश	48200	33962	82162	10884	6468	17352	7672	2859	10531	997	207	1204
3	असम	32216	271020	593236	74245	49960	124205	49559	31392	80951	6747	2552	9299
4	बिहार	471823	247489	719312	99885	40445	140330	42816	15432	58248	0	0	0
5	गोवा	198	123	321	35	12	47	3	0	3	0	0	0
6	गुजरात	514000	366000	880000	124000	69000	193000	61300	31600	92900	13400	7135	20535
7	हरियाणा	८८	८८	८८	८८	८८	८८	८८	८८	८८	८८	८८	८८
8	हिमाचल प्रदेश	15642	12146	27788	6793	3319	10112	4244	1689	5933	255	56	311
9	जम्मू काश्मीर	८८	८८	८८	८८	८८	८८	८८	८८	८८	८८	८८	८८
10	कर्नाटक	122261	100988	223249	35223	23860	59083	19854	10182	30036	4318	832	5150
11	केरल	22000	20012	42012	8142	7783	15925	3889	3652	7541	315	258	573
12	मध्य प्रदेश	940731	393331	1334062	215472	111288	326760	86091	16553	102644	10058	2037	12095
13	महाराष्ट्र	509215	387919	897134	145486	78313	223799	78299	31530	109829	8765	2157	10922
14	मणिपुर	50666	42074	92740	9188	7282	16470	7036	5179	12215	1574	892	2466
15	मेघालय	104420	98926	203346	30401	28470	58871	25293	22002	47295	2617	1913	4530
16	मिजोरम	62666	56336	119002	19368	19298	38666	10847	9699	20546	212	110	322
17	नागालैंड	77039	71301	148340	21227	18039	39266	9516	7687	17203	1696	871	2567
18	उड़ीसा	522000	246000	768000	93100	38100	131200	34048	13172	47220	2842	612	3454
19	पंजाब	८८	८८	८८	८८	८८	८८	८८	८८	८८	८८	८८	८८
20	राजस्थान	373292	111834	485126	95273	10410	105683	53498	3088	56586	5070	143	5213
21	सिक्किम	8250	7218	15468	1728	1657	3385	1038	892	1930	0	0	0
22	तमिलनाडु	39003	29552	69555	11823	7183	19006	5594	3506	9100	473	158	631
23	त्रिपुरा	76830	55577	132407	16169	10036	26205	6951	3194	10145	364	100	464
24	उत्तर प्रदेश	21584	12625	34209	5353	1634	6987	5933	1522	7455	1228	502	1730
25	पश्चिम बंगाल	316631	134878	451509	43094	14830	57924	20092	10560	30652	775	284	1059
26	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1763	1621	3384	1038	894	1932	1403	1282	2685	18	8	26
27	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	68	32	100	95	27	122
28	दादर और नगर हवेली	8345	5527	13872	2067	974	3041	853	390	1243	0	0	0
29	दमन और दीव	669	578	1247	499	492	991	259	142	401	75	32	107
30	दिल्ली	298	274	572	247	148	395	225	158	383	397	238	635
31	लक्षद्वीप	4393	3729	8122	1682	1336	3018	976	565	1541	0	0	0
32	पांडिचेरी	८८	८८	८८	८८	८८	८८	८८	८८	८८	८८	८८	८८
भारत		4957611	2910576	7868187	1131388	575518	1706906	566798	238081	804859	65565	21954	87519

* इसमें इजीप्ट (बी-ई/बी-टेक/बी-आर) निक्स (एम-बी-एस) और शिक्षक प्रशिक्षण (बी-एस/बी-टी) को छोड़कर पी-एच-डी/एम-फिल और सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में किया गया दाखिला शामिल नहीं है।

आंकड़े वर्ष 1988-89 से सम्बंधित हैं।

भारत के राष्ट्रपति द्वारा नागालैंड, अ- और नि- द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप के लिए कोई भी जाति अनुसूचित नहीं है।

नोट. जुनैदा शैक्षिक आंकड़े, 1989-90

विवरण सं- 17
प्रत्येक एक लाख जनसंख्या में नामांकन 1990-91

० राज्य / संघ शासित प्रदेश	योग		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति	
	आइएम०	मिडिल	आइएम०	मिडिल	आइएम०	मिडिल
1 आन्ध्र प्रदेश	11367	3204	15069	3551	13302	2117
2 अरुणाचल प्रदेश	13070	3039	2381	357	13723	2898
3 असम	15924	4827	26619	7641	24212	5069
4 बिहार	9921	2456	8656	1605	10026	1956
5 गोवा	11626	6924	12319	3988	2841	416
6 गुजरात	13795	4585	18541	6068	15030	3296
7 हरियाणा	10353	4234	12152	3255	—	—
8 हिमाचल प्रदेश	13504	6550	13333	5085	11770	4283
9 जम्मू काश्मीर	9571	3780	9357	3767	—	—
0 कर्नाटक	12679	3824	13154	3519	10125	2680
1 केरल	10878	6445	12569	6987	14060	5330
2 मध्य प्रदेश	12088	4013	12361	3513	8782	2151
3 महाराष्ट्र	12733	4948	25976	9134	12403	3094
4 पंजाब	14485	4308	17382	4570	18596	3303
5 मेघालय	13778	3940	35534	12603	14335	4150
6 मिजोरम	17531	5695	—	—	18527	6020
7 नागालैंड	11962	4567	—	—	114533	3847
8 ओडिसा	11488	3097	14895	3165	10866	1856
9 पंजाब	10182	4222	12950	3548	—	—
0 राजस्थान	10285	3005	9303	2344	9055	1973
1 सिक्किम	17963	3670	18468	2896	16543	3620
2 तमिलनाडु	13954	5677	14982	5396	11516	3193
3 त्रिपुरा	14657	4425	17737	4770	16949	3354
4 उत्तर प्रदेश	10046	3221	8275	1431	11740	2398
5 पश्चिम बंगाल	13642	4035	9763	1670	11680	1498
6 अरुणाचल और निकोबार द्वीप समूह	14321	6442	—	—	10132	5784
7 चंडीगढ़	7746	4050	15253	5842	—	—
8 दार्जिल और नगर हवेली	11994	3190	5750	12645	2772	—
9 दमन और दीव	*	*	*	*	*	*
10 दिल्ली	9827	5397	12418	4615	—	—
11 लकाद्वीप	16147	6097	—	—	10816	6248
12 पंजाब	13381	7075	16886	7424	—	—
घात	11745	3944	12078	3181	11741	2547

*गोवा में शामिल है।

विषय संख्या 18
स्कूल बीच में छोड़ जाने वालों की दर 1987-88

क्र. सं.	राज्य/संघ शामिल प्रदेश	कक्षा I-V		कुल	कक्षा I-VIII		कुल
		लड़के	लड़कियाँ		लड़के	लड़कियाँ	
1.	आन्ध्र प्रदेश	52.42	58.52	55.03	67.77	77.01	71.68
2.	अरुणाचल प्रदेश	58.75	58.43	58.63	75.20	75.91	75.44
3.	असम	51.59	59.47	55.01	70.91	74.45	72.44
4.	बिहार	63.88	68.93	65.63	76.77	84.19	79.08
5.	गोवा	2.19	8.78	5.33	20.69	27.63	23.95
6.	गुजरात	38.06	46.87	41.92	56.30	67.69	61.67
7.	हरियाणा	24.35	31.61	27.32	33.01	48.22	38.62
8.	हिमाचल प्रदेश	28.06	29.32	28.63	16.92	34.42	24.68
9.	जम्मू कश्मीर	28.08	41.45	33.44	46.63	58.51	51.25
10.	कर्नाटक	43.28	57.36	50.16	61.04	72.07	66.10
11.	केरल	-5.12	-3.62	-4.39	15.97	15.00	15.49
12.	मध्य प्रदेश	36.64	48.04	41.04	49.88	66.65	55.78
13.	महाराष्ट्र	34.69	45.71	39.82	53.07	68.01	59.87
14.	मणिपुर	31.43	33.40	32.35	66.42	61.61	64.22
15.	मेघालय	37.28	38.72	37.98	45.35	42.49	43.98
16.	मिजोरम	37.22	33.43	35.43	58.15	55.13	56.90
17.	नागालैंड	40.15	37.32	38.97	60.28	71.25	64.86
18.	उड़ीसा	36.81	37.81	37.27	59.69	67.26	63.23
19.	पंजाब	53.12	60.75	52.25	62.81	76.82	66.33
20.	राजस्थान	60.19	58.50	59.86	63.83	60.11	62.51
21.	सिक्किम	19.44	24.46	21.78	44.08	53.14	48.22
22.	तमिलनाडु	39.14	58.02	58.65	73.95	75.96	74.83
23.	त्रिपुरा	47.84	47.24	47.65	49.88	63.34	59.20
24.	उत्तर प्रदेश	62.35	65.76	63.81	74.32	76.91	75.41
25.	पश्चिम बंगाल	18.60	22.74	20.54	38.35	39.59	36.31
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	21.00	24.41	4.78	5.54	13.01	8.94
27.	चंडीगढ़	29.37	45.58	36.14	63.98	70.52	66.81
28.	दादर और नगर हवेली	2.24	8.82	5.34	21.03	27.97	23.95
29.	दमन और दीव	14.40	25.40	19.76	9.64	24.20	16.73
30.	दिल्ली	-2.96	11.38	4.02	40.96	56.82	48.45
31.	लक्षद्वीप	11.55	0.83	-5.59	3.11	31.52	16.29
32.	पुद्दुचेरी	71.35	72.04	71.67	76.58	87.86	77.90
योग		43.35	49.42	46.97	58.80	67.55	62.29

स्कूल बीच में छोड़ जाने वालों की दर निम्नलिखित रूप से प्रकटित की गई है:

(1983-84 में कक्षा I में दाखिल छात्रों की संख्या)	
(1987-88 में कक्षा V में दाखिल छात्रों की संख्या)	
(1983-84 में कक्षा I में दाखिल छात्रों की संख्या)	×100
(1980-81 में कक्षा I में दाखिल छात्रों की संख्या)	
(1987-88 में कक्षा VIII में दाखिल छात्रों की संख्या)	
(1980-81 में कक्षा I में दाखिल छात्रों की संख्या)	×100

इस सूचकांक में निम्नलिखित दो ध्यान में नहीं रखा गया है:

(I) रिटायर और (II) वे बच्चे जो इस सूचकांक में कक्षा I के बाद दाखिल हुए।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित क्षेत्रों में कक्षा छोड़ने वालों की दर 1987-88

क्र.सं.	राज्य / संघ शासित प्रदेश	कक्षा I से V अनुसूचित	कक्षा I से V अनुसूचित	कक्षा I से VIII अनुसूचित	कक्षा I से VIII अनुसूचित
1	आन्ध्र प्रदेश				
2	अरुणाचल प्रदेश	64 10	68 84	82 01	88 04
3	असम	55 48	64 47	63 24	77 27
4	बिहार	69 65	72 33	84 07	86 60
5	गोवा	44 23	63 72	61 04	78 84
6	गुजरात	36 94	—	57 27	—
7	हरियाणा	34 71	36 81	39 79	39 99
8	हिमाचल प्रदेश	उत्तर	—	उत्तर	—
9	जम्मू कश्मीर	66 38	43 83	73 96	66 90
10	कर्नाटक	उत्तर	18 69	24 99	46 48
11	केरल	42 93	55 93	57 43	71 39
12	मध्य प्रदेश	47 24	63 24	64 10	78 93
13	महाराष्ट्र	35 04	77 57	86 27	83 35
14	मणिपुर	56 99	77 82	78 46	90 42
15	महाराष्ट्र	—	36 11	—	61 22
16	मिजोरम	52 26	74 26	74 16	86 59
17	नागालैंड	45 46	—	78 29	—
18	उड़ीसा	62 46	75 40	73 28	76 61
19	पंजाब	72 45	60 25	78 26	56 95
20	राजस्थान	24 48	37 91	54 54	39 21
21	सिक्किम	63 15	77 40	81 10	83 93
22	तमिलनाडु	48 43	54 73	58 01	59 92
23	त्रिपुरा	58 17	64 56	80 96	85 09
24	उत्तर प्रदेश	—	4 07	—	40 12
25	पश्चिम बंगाल	13 00	64 61	67 09	77 89
26	अडमान और निकोबार द्वीप समूह	उत्तर	—	उत्तर	—
27	छत्तीसगढ़	उत्तर	43 89	36 67	76 80
28	दादरा और नगर हवेली	28 78	—	55 39	—
29	दमन और दीव	38 60	21 74	57 85	57 02
30	दिल्ली	—	उत्तर	—	50 22
31	लक्षद्वीप	उत्तर	39 19	उत्तर	51 43
32	पॉण्डिचेरी	उत्तर	—	29 45	—
	योग	48 84	62 37	67 73	78 51

असम में जनगणना नहीं हुई थी

मान (1) पाचवीं अखिल शैक्षणिक सर्वेक्षण

(11) शिक्षा विभाग की वार्षिक सांख्यिकी

टिप्पणी भारत के राष्ट्रपति द्वारा नागालैंड, अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप में किसी भी जाति अनुसूचित जाति तथा हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, छत्तीसगढ़, दिल्ली तथा पॉण्डिचेरी में किसी भी जाति को अनुसूचित जन जाति घोषित नहीं किया गया।

निवर्ण सं. 20
सिक्कों की संख्या 1990-91

क्र. सं.	राज्य / संघ शासित प्रदेश	ग्रामपंचायत स्कूल			मिडिल स्कूल			मा. उच्चतर माध्यमिक स्कूल		
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
1	आन्ध्र प्रदेश	79219	31638	110857	28270	13557	41827	56993	25856	82849
2	अरुणाचल प्रदेश	1896	470	2366	1355	316	1671	1788	385	2173
3	असम	57732	14586	72316	31742	6304	38046	33301	9150	42451
4	बिहार	95355	22286	117641	78917	19447	98364	40623	6521	47144
5	गोवा	1123	1789	2912	364	476	840	3291	3832	7123
6	गुजरात	22500	13800	36300	73500	61750	135250	43808	13983	57791
7	हरियाणा	9012	5449	15461	7167	4648	11815	28047	19168	47215
8	हिमाचल प्रदेश	10980	6020	17000	5700	1300	7000	9100	3800	12900
9	जम्मू काश्मीर	8159	5565	13724	11822	5807	17629	12987	6015	19002
10	कर्नाटक	29903	11599	41502	56112	35620	91732	40365	12188	52553
11	केरल	18231	31542	49773	19875	31755	51630	36125	56972	93097
12	मध्य प्रदेश	136161	40043	176204	60932	19956	80888	39282	11472	50754
13	महाराष्ट्र	72626	48485	121111	93365	55555	148920	135277	58681	193958
14	मणिपुर	8187	2397	10584	4187	1168	5355	5130	2184	7314
15	मेघालय	4243	2486	6729	1895	1114	3009	1495	1446	2941
16	मिजोरम	2858	1689	3747	2626	636	3262	1244	242	1486
17	नागालैंड	4531	1701	6232	2807	791	3598	2161	1031	3192
18	उड़ीसा	78155	26265	104420	31026	6375	37401	33797	7805	41602
19	पंजाब	22139	25702	47841	5267	4205	9472	27771	21956	49727
20	राजस्थान	55440	18768	74208	52897	17456	70353	48401	13721	62122
21	सिक्किम	1608	637	2245	1078	487	1565	1243	838	2401
22	तमिलनाडु	70452	49921	120373	33608	21928	65536	67660	42157	109817
23	त्रिपुरा	6847	17755	8602	3286	840	4126	7118	2808	9926
24	उत्तर प्रदेश	215553	48176	263729	76442	18837	95279	80256	16439	96695
25	पश्चिम बंगाल	144112	40636	184748	18092	7136	25228	78326	41691	120017
26	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	473	251	724	351	349	700	1179	931	2110
27	चंडीगढ़	78	686	764	85	506	591	986	2233	3219
28	दादर और नगर हवेली	110	50	160	169	215	384	114	44	158
29	दमन और दीव	119	159	278	139	91	230	166	57	223
30	दिल्ली	8243	13943	22186	2269	3396	5665	17080	23581	40661
31	लक्षद्वीप	153	71	224	75	49	124	268	67	335
32	पॉण्डिचेरी	1086	849	1935	1063	729	1792	1717	1188	2905
भारत		1166484	470414	1636898	706483	352812	1059295	856999	415503	1274802

आकड़े वर्ष 1988-89 से सम्बंधित हैं।
स्रोत: चुनावी शैक्षणिक आंकड़े, 1989-90

वर्ष 1990-91 के लिए राज्यो/संघ शासित क्षेत्रों के शिक्षा विभागों का बजट कुल राज्य बजट में शिक्षा बजट की प्रतिशतता कमतर

(तारख रूप में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	शिक्षा विभाग का बजट		राज्य के कुल बजट में शिक्षा बजट की प्रतिशतता	
		योजनागत	योजनेतर	कुल योग	
1	2	3	4	5	6
1.	पश्चिम बंगाल	12363	145051	157414	28.0
2.	केरल	3307	64978	68285	26.3
3.	दिल्ली	2606	24323	26929	26.2
4.	बिहार	7447	111807	119254	25.7
5.	चंडीगढ़	372	3747	4119	24.3
6.	भारतपुर	789	5638	6427	23.5
7.	असम	9598	30814	40412	22.0
8.	दमन और दीप	107	308	415	21.9
9.	गोवा	1189	5236	6425	21.8
10.	गजस्थान	7664	67989	75653	21.8
11.	कर्नाटक	8895	76481	85376	21.3
12.	हिमाचल प्रदेश	3327	14694	18021	21.1
13.	गुजरात	1731	84149	85880	20.7
14.	आन्ध्र प्रदेश	10740	97463	108203	20.6
15.	त्रिपुरा	1849	8898	10747	20.3
16.	तमिलनाडु	3997	92375	96372	20.0
17.	उड़ीसा	15722	34770	50492	19.8
18.	पंजाब	541	47181	47722	18.8
19.	पाकिस्तान	872	2654	3526	18.1
20.	पाकिस्तान	764	1518	2282	17.8
21.	महाराष्ट्र	2445	144734	147179	17.6
22.	मध्यप्रदेश	1288	4503	5791	17.3
23.	उत्तर प्रदेश	15896	144572	160468	16.6
24.	मध्य प्रदेश	12112	67466	79578	15.6
25.	हरियाणा	3451	26324	29775	15.5
26.	मिजोरम	741	3131	3872	14.8
27.	जम्मू और काश्मीर	2395	11415	13810	14.4
28.	अरुणाचल प्रदेश	983	2077	3060	13.4
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	306	1463	1769	12.3
30.	नागालैंड	685	3491	4176	11.7
31.	लक्षद्वीप	55	328	383	10.2
32.	दादरा और नगर हवेली	48	263	311	10.1
	कुल राज्य/संघ शासित क्षेत्र	131893	1318424	1450317	20.0

चित्राण सं० 22
शिक्षक पर स्केटर चार योजनागत + योजनाएँ व्यव सातवीं योजना अवधि (1985-90) के दौरान

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	आरम्भिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा प्रोब शिक्षा सहित यू० और ए० तकनीकी शिक्षा					(रू० लाखों में)	
		आरम्भिक शिक्षा	माध्यमिक शिक्षा	प्रोब शिक्षा	शिक्षा सहित यू० और ए० तकनीकी शिक्षा	अन्य	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आन्ध्र प्रदेश	161479	102131	3804	72479	10215	2778	352886
2	अरुणाचल प्रदेश	8045	4386	176	741	—	1188	14536
3	असम	86408	36979	2474	15194	3529	5455	150039
4	बिहार	239233	55769	13301	48313	4262	2517	363395
5	गोवा	5633	10229	188	2854	1042	233	20179
6	गुजरात	151323	92352	1958	28243	8239	4157	286272
7	हरियाणा	44776	42945	2464	16037	2449	906	109577
8	हिमाचल प्रदेश	30719	13903	665	5306	620	1411	57624
9	जम्मू काश्मीर	25978	20756	950	7468	1847	840	57839
10	कर्नाटक	143150	76251	3794	36917	6974	1739	268825
11	केरल	137849	75196	1830	35855	11003	2013	263746
12	मध्य प्रदेश	130381	54995	3129	31139	9361	1112	230117
13	महाराष्ट्र	233552	207899	3976	55515	21298	12584	554824
14	मणिपुर	10669	7051	447	4602	240	311	23320
15	मेघालय	7496	5647	428	1485	172	448	15676
16	मिजोरम	6943	3350	624	1148	220	493	12978
17	नागालैंड	10593	4011	806	1160	282	89	16941
18	उड़ीसा	82968	38518	2307	22159	2915	857	149724
19	पंजाब	57001	82237	1300	24292	2123	1123	168876
20	राजस्थान	124250	80897	4062	24948	3327	1807	239291
21	सिक्किम	2611	4714	260	194	—	215	7994
22	तमिलनाडु	167814	111095	3805	44682	12672	1501	343569
23	त्रिपुरा	9906	14330	1630	2174	480	214	28734
24	उत्तर प्रदेश	304976	195732	9380	47534	16243	1696	575561
25	पश्चिम बंगाल	142032	153174	3942	46885	7481	14742	368256
26	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3590	1589	40	284	107	218	5828
27	चंडीगढ़	2593	1777	82	6315	1687	107	12561
28	दादर और नगर हवेली	693	203	12	—	2	98	1008
29	दमन और दीव	606	342	7	92	93	69	1209
30	दिल्ली	19285	64441	433	735	4227	2255	91376
31	लक्षद्वीप	759	466	18	235	—	55	1533
32	पुडुचेरी	4858	3013	115	1523	1694	294	11497
	कुल राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2378169	1571378	68608	586510	134803	63525	4802993

स्रोत राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के कलट दस्तावेज

नोट उपर्युक्त आंकड़े 1985-89 के लिए वास्तविक और 1989-90 के लिए संशोधित अनुमानों के अनुसार हैं।

निबन्ध सं० 23
कुल शिक्षा व्यय में सेक्टर-चार की प्रतिशतता (योजनगत + योजनेतर)

क्र. सं.	राज्य / संघ शासित प्रदेश	आरम्भिक शिक्षा	माध्यमिक शिक्षा	विशेष शिक्षा	वि० एच उच्च शिक्षा	तकनीकी शिक्षा	अन्य शिक्षा
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आन्ध्र प्रदेश	45.8	28.9	1.1	20.5	2.9	0.8
2	अरुणाचल प्रदेश	55.3	30.2	1.2	5.1	—	8.2
3	असम	57.6	24.6	1.6	10.1	2.4	3.6
4	बिहार	65.8	15.3	3.7	13.3	1.2	0.7
5	गोवा	27.9	50.7	0.9	14.1	5.2	1.2
6	गुजरात	52.9	32.3	0.7	9.9	2.9	1.5
7	हरियाणा	40.9	39.2	2.2	14.6	2.2	0.8
8	हिमाचल प्रदेश	53.3	32.8	1.2	9.2	1.1	2.4
9	जम्मू कश्मीर	44.9	55.9	1.6	12.9	3.2	1.5
10	कर्नाटक	53.3	28.4	1.4	13.7	2.6	0.6
11	केरल	52.3	28.5	0.7	13.6	4.2	0.8
12	मध्य प्रदेश	56.7	23.9	1.4	13.5	4.1	0.5
13	महाराष्ट्र	45.7	37.5	0.7	10.0	3.8	2.3
14	मणिपुर	45.8	30.2	1.9	19.7	1.0	1.3
15	मेघालय	47.8	36.0	2.7	9.5	1.1	2.0
16	मिजोरम	53.5	25.8	6.3	8.8	1.7	3.8
17	नागालैंड	62.5	23.7	4.5	6.8	1.7	0.5
18	उड़ीसा	55.4	25.7	1.5	14.8	2.0	0.6
19	पञ्जाब	33.9	48.9	0.8	14.5	1.3	0.7
20	राजस्थान	51.9	33.8	1.7	10.4	1.4	0.8
21	सिक्किम	32.7	59.0	3.3	2.4	—	2.7
22	तमिलनाडु	49.1	32.5	1.1	13.1	3.7	0.4
23	त्रिपुरा	34.5	49.9	5.7	7.6	1.7	0.7
24	उत्तर प्रदेश	53.0	34.0	1.6	8.3	2.8	0.3
25	पश्चिम बंगाल	38.6	41.6	1.1	12.7	2.0	4.0
26	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	61.6	27.3	0.7	4.9	1.8	3.7
27	चंडीगढ़	20.6	14.1	0.7	50.3	13.4	0.9
28	दादरा और नगा हवेली	68.8	20.1	1.2	—	0.2	9.7
29	दमन और दीव	50.1	28.3	0.6	7.6	7.7	5.7
30	दिल्ली	21.1	70.5	0.5	0.8	4.6	2.5
31	लक्षद्वीप	49.5	30.4	1.2	15.3	—	3.6
32	पुद्दुचेरी	42.3	26.2	1.0	13.2	14.7	2.6
	सभी राज्य संघ शासित क्षेत्र	47.5	32.7	1.4	12.2	2.8	1.3

नियम सं० 24
1991-92 के लिए सेक्टर-वार स्वीकृत योजनागत परिव्यय

क्र० सं०	राज्य / संघ शासित प्रदेश	प्रारंभिक शिक्षा	प्रौढ शिक्षा	सामान्य शिक्षा तकनीकी शिक्षा	कुल (कथलम 5+कथलम 6)	
1	आन्ध्र प्रदेश	2000	195	3451	390	3841
2	अरुणाचल प्रदेश	2065	88	2950	—	2950
3	असम	5740	300	7176	703	7679
4	बिहार	8800	1200	11000	2500	13500
5	गोवा	392	40	1120	300	1420
6	गुजरात	1604	300	2724	2295	5019
7	हरियाणा	1740	100	3630	1600	5230
8	हिमाचल प्रदेश	2000	50	3600	544	4144
9	जम्मू काश्मीर	2000	111	5174	139	5311
10	कर्नाटक	3084	332	6236	814	7050
11	केरल	164	25	1062	1900	2961
12	मध्य प्रदेश	7759	550	16412	2811	19221
13	महाराष्ट्र	2533	297	5300	3000	8330
14	मणिपुर	543	65	1086	83	1164
15	मेघालय	1418	88	2025	25	2050
16	मिजोरम	445	15	817	70	887
17	नागालैंड	500	27	907	134	1041
18	उड़ीसा	2770	310	3832	1032	4802
19	पंजाब	1539	101	2300	3720	6020
20	राजस्थान	4174	115	8825	1455	10280
21	सिक्किम	615	6	1000	75	1075
22	तमिलनाडु	5300	345	6370	450	6820
23	त्रिपुरा	1182	58	2253	25	2250
24	उत्तर प्रदेश	6041	340	13288	5134	18421
25	पश्चिम बंगाल	2900	450	7564	1489	9050
26	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	355	5	778	195	970
27	चंडीगढ़	165	5	577	200	770
28	दादरा और नगर हवेली	119	3	178	20	199
29	दमन और दीव	60	2	104	109	210
30	दिल्ली	4450	40	6700	1800	8500
31	लक्षद्वीप	17	3	125	—	121
32	पांडिचेरी	400	8	849	326	1171
	सभी राज्य / संघ शासित क्षेत्र	72874	5575	129393	33338	16273

स्रोत: योजना आयोग द्वारा 1991-92 की वार्षिक योजना का विस्तारण

चित्रण सं. 25
 राष्ट्रीय योजना परिषद की सेक्टर-वार प्रतिशतता (1991-92)

क्र.	राज्य / संघ शासित प्रदेश	आर्थिक शिक्षा	ग्रैज शिक्षा	सामान्य शिक्षा	तकनीकी शिक्षा
1	2	3	4	5	6
1	आंध्र प्रदेश	52.1	5.1	89.8	10.2
2	अरुणाचल प्रदेश	70.0	3.0	100.0	NIL
3	असम	72.9	3.8	91.1	8.9
4	बिहार	65.2	8.9	81.5	18.5
5	गोवा	27.6	2.9	78.9	21.1
6	गुजरात	32.0	6.0	54.3	45.7
7	हरियाणा	33.3	1.9	69.4	30.6
8	हिमाचल प्रदेश	48.3	1.2	86.9	13.1
9	जम्मू कश्मीर	37.6	2.1	97.4	2.6
0	कर्नाटक	43.7	4.7	88.5	11.5
1	केरल	5.5	0.8	35.9	64.1
2	कोयला प्रदेश	40.4	2.9	85.4	14.6
3	महाराष्ट्र	30.5	3.6	63.9	36.1
4	मणिपुर	46.4	5.6	92.9	7.1
5	मेघालय	69.2	4.3	98.8	1.2
6	मिजोरम	50.2	1.7	92.1	7.9
7	नागालैंड	48.0	2.6	87.1	12.9
8	उड़ीसा	56.9	6.4	78.8	21.2
9	पंजाब	25.6	1.7	38.2	61.8
0	राजस्थान	40.6	1.1	85.8	14.2
1	सिक्किम	57.2	0.6	93.0	7.0
2	तमिलनाडु	77.7	5.1	93.4	6.6
3	त्रिपुरा	52.3	2.6	98.9	1.1
4	उत्तर प्रदेश	32.8	1.8	72.1	27.9
5	पश्चिम बंगाल	32.0	5.0	83.6	16.4
6	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	36.5	0.5	80.0	20.0
7	चंडीगढ़	21.2	0.6	74.3	25.7
8	छत्तीसगढ़ और नगर इक्वेली	60.1	1.5	89.9	10.1
9	दमन और दीव	28.2	0.9	48.8	51.2
0	दिल्ली	52.4	0.5	78.8	21.2
1	लक्षद्वीप	13.6	2.4	100.0	NIL
2	पंजाब केरी	34.0	0.7	72.3	27.7
	सभी राज्य / संघ शासित क्षेत्र	44.8	3.4	79.5	20.5

राज्य के 1988-89 के शुद्ध घरेलू उत्पादन के अनुसार राज्यो/संघ शासित क्षेत्रों के शिक्षा विभागों का बजट प्रावधान

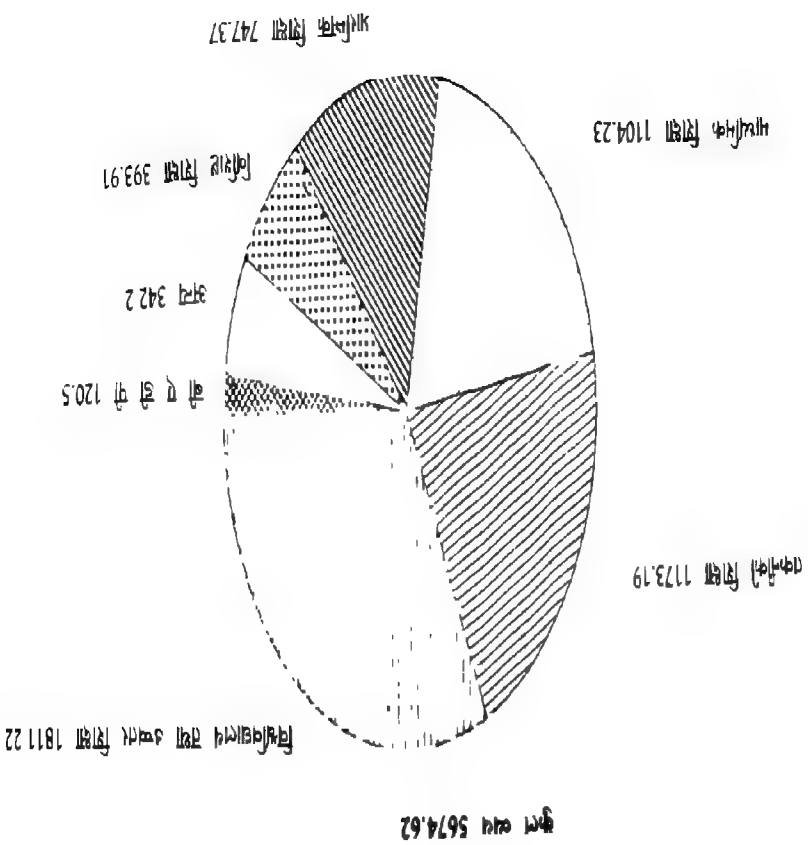
क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	राज्य के शुद्ध घरेलू उत्पादन में शिक्षा विभाग के बजट की प्रतिशतता
1	आन्ध्र प्रदेश	4.0
2	अरुणाचल प्रदेश	10.0
3	असम	4.8
4	बिहार	3.3
5	गोवा	5.3
6	गुजरात	3.4
7	हरियाणा	2.6
8	हिमाचल प्रदेश	6.8
9	जम्मू और कश्मीर	एन०ए०
10	कर्नाटक	3.9
11	केरल	3.1
12	मध्य प्रदेश	3.3
13	महाराष्ट्र	2.8
14	मणिपुर	५.5
15	मेघालय	एन०ए०
16	मिज़ोरम	एन०ए०
17	नागालैंड	10.3
18	उड़ीसा	4.3
19	पंजाब	2.8
20	राजस्थान	4.2
21	सिक्किम	एन०ए०
22	तमिलनाडु	3.4
23	त्रिपुरा	एन०ए०
24	उत्तर प्रदेश	3.0
25	पश्चिम बंगाल	3.7
26	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	५.6
27	चंडीगढ़	एन०ए०
28	दादरा नगर हवेली	एन०ए०
29	गोवा दमन और दीव	एन०ए०
30	दिल्ली	3.2
31	लक्षद्वीप	एन०ए०
32	पॉण्डिचेरी	5.7

नोट आकड़े राज्य के शुद्ध घरेलू उत्पाद के आकड़ों पर आधारित हैं जैसा कि आर्थिक सर्वेक्षण 1990-91 में बताया गया है। एन०ए० उपलब्ध नहीं है।



પ્રાણી પત્ર સભા (સંસ્કાર) સંસ્કૃત સપ્તકાર - સપ્તકાર પત્ર સભા (પત્ર સપ્તકાર + પત્ર સપ્તકાર)

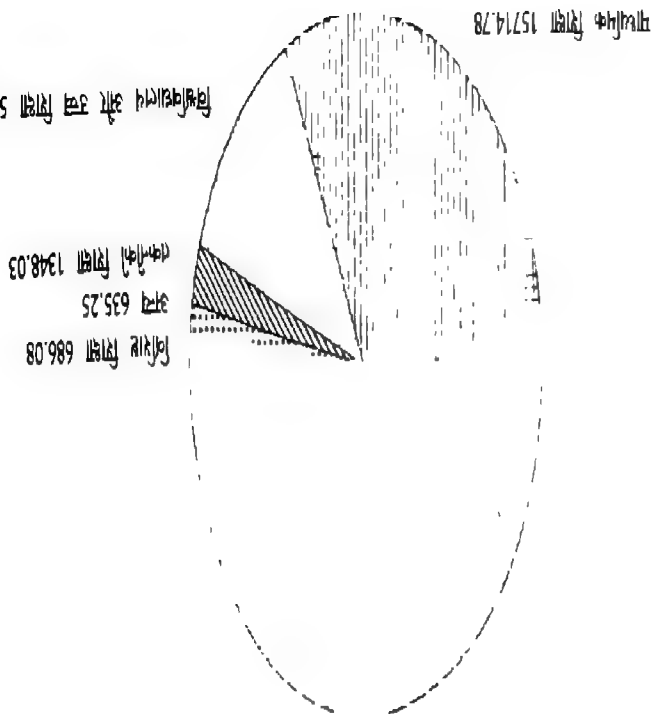
(કાર્ય સપ્તકાર)



(ਅੰਕ ੨੫੨ ਦੇ)

ਕੁਲ ੪੪ 48029.93

ਸ਼ਾਹਿਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 23781.69



(ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ + ਸੈਕੰਡਰੀ)

ਸਕੂਲ/ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ - 1/2 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ

ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ (ਸਕੂਲ)

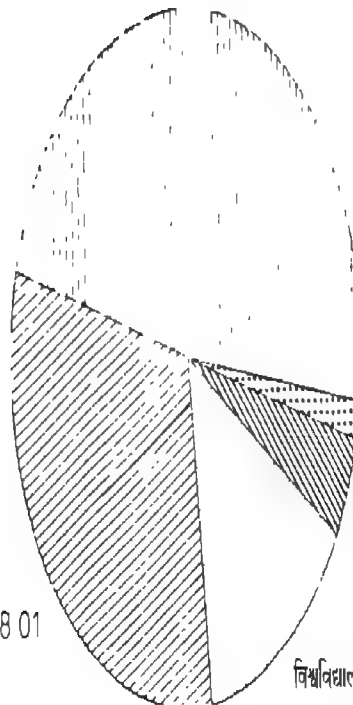
शिक्षा पर व्यय (क्षेत्रवार) केन्द्रिय क्षेत्र + राज्य क्षेत्र (योजनागत + योजनेतर)

7वीं योजना अवधि

(करोड़ रुपये में)

कुल व्यय 53704.55

प्रारंभिक शिक्षा 24529.06



शिक्षा पर क्षेत्रवार व्यय (पंजनागत + पंजनेतर) जम्मा + राज्य

(करोड़ रुपये में)

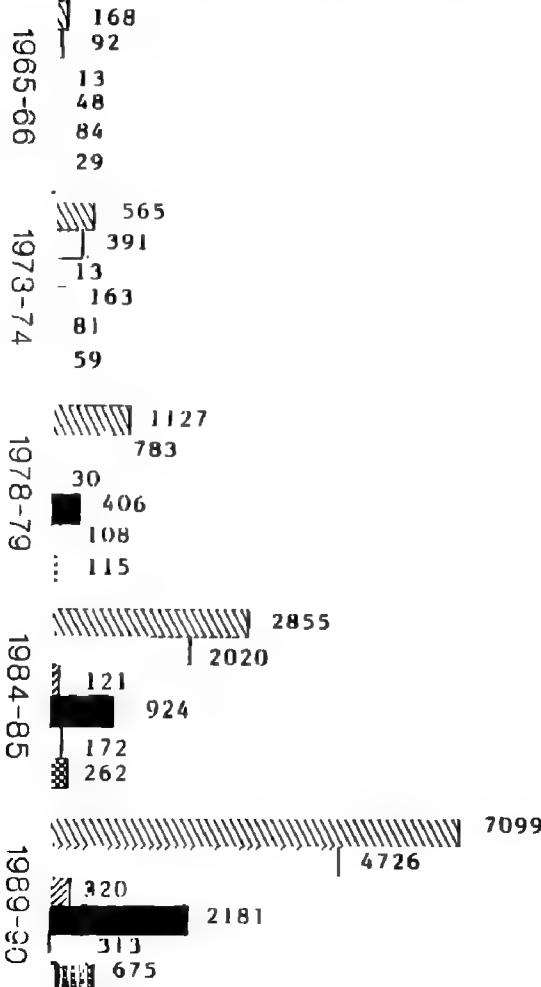
8

6 -

4 -

2 -

0



ସଂଗ୍ରହ ୫୫ ଲକ୍ଷ (୧୫୫୫୫)
 ସଂଗ୍ରହ ୫୫ ଲକ୍ଷ / ୫୫ ଲକ୍ଷ
 (୧୫୫୫୫ + ୫୫୫୫୫)

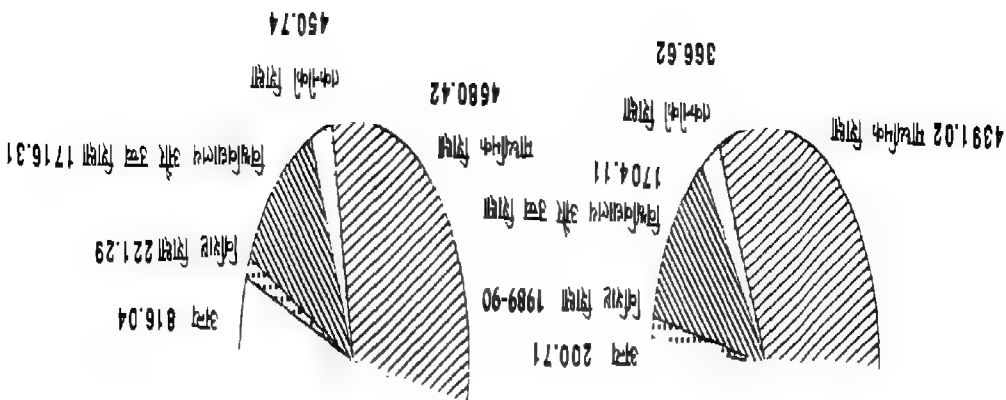
(କୃଷି ଲକ୍ଷ)

1990-91 (୧୫୫୫୫)

1989-90 (୧୫୫୫୫)

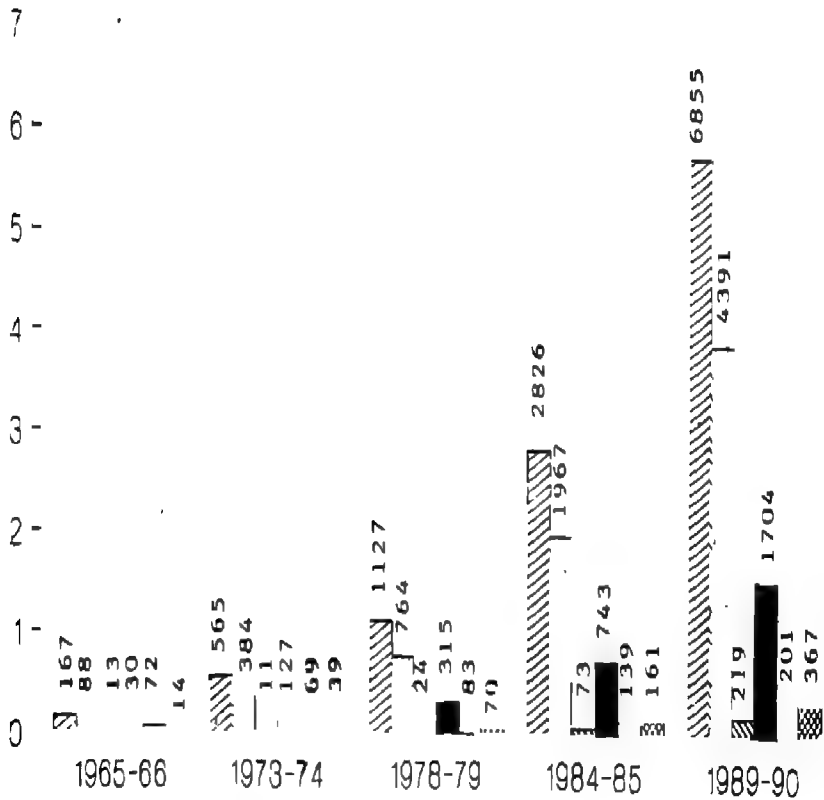
୫୫୫୫୫ ୫୫୫୫୫

୫୫୫୫୫ ୫୫୫୫୫



शिक्षा पर क्षेत्रवार व्यय (योजनागत + योजना-तर) राज्य/संघ शासित प्रदेश

(करोड़ रुपये में)



▨ प्रारंभिक शिक्षा | ▨ माध्यमिक शिक्षा ▨ विशेष शिक्षा ■ विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा
 | | अन्य ▨ तकनीकी शिक्षा

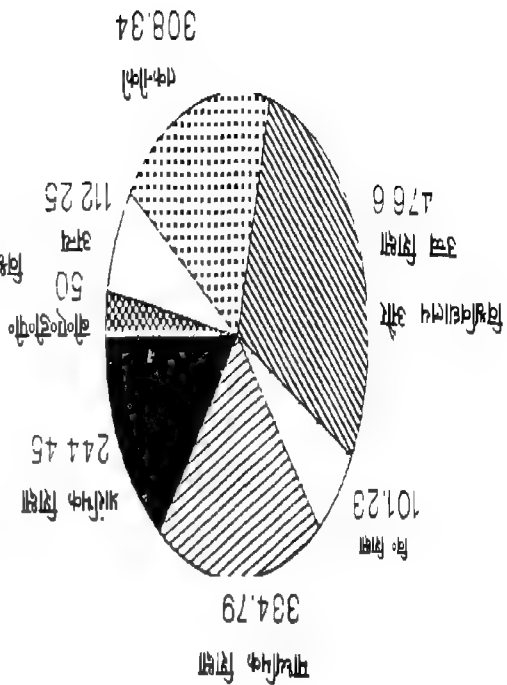
ਪ੍ਰਿਥਮ ਪੜਾਅ (ਭਾਗ 1)

ਭਾਗ

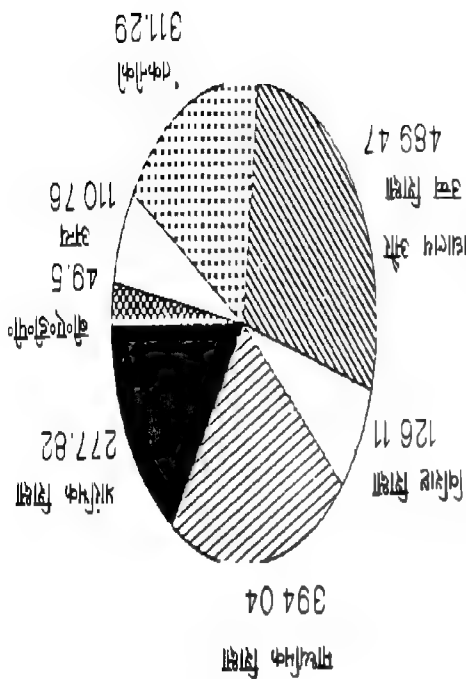
(ਪ੍ਰਿਥਮ ਪੜਾਅ + ਪ੍ਰਿਥਮ ਪੜਾਅ)

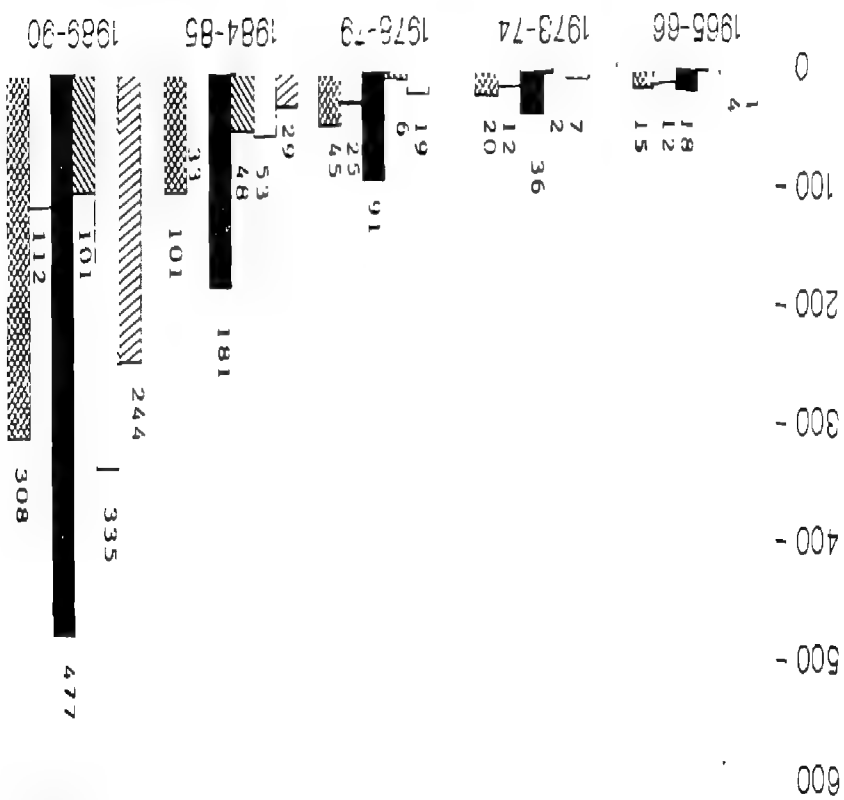
(ਕਮੀ 44.1 ਫੀ)






1989-90



1990-91





 1965-66
 1973-74
 1976-79
 1984-85
 1989-90

1965-66 + 1973-74
 1976-79 + 1984-85
 1989-90

(in millions of years)

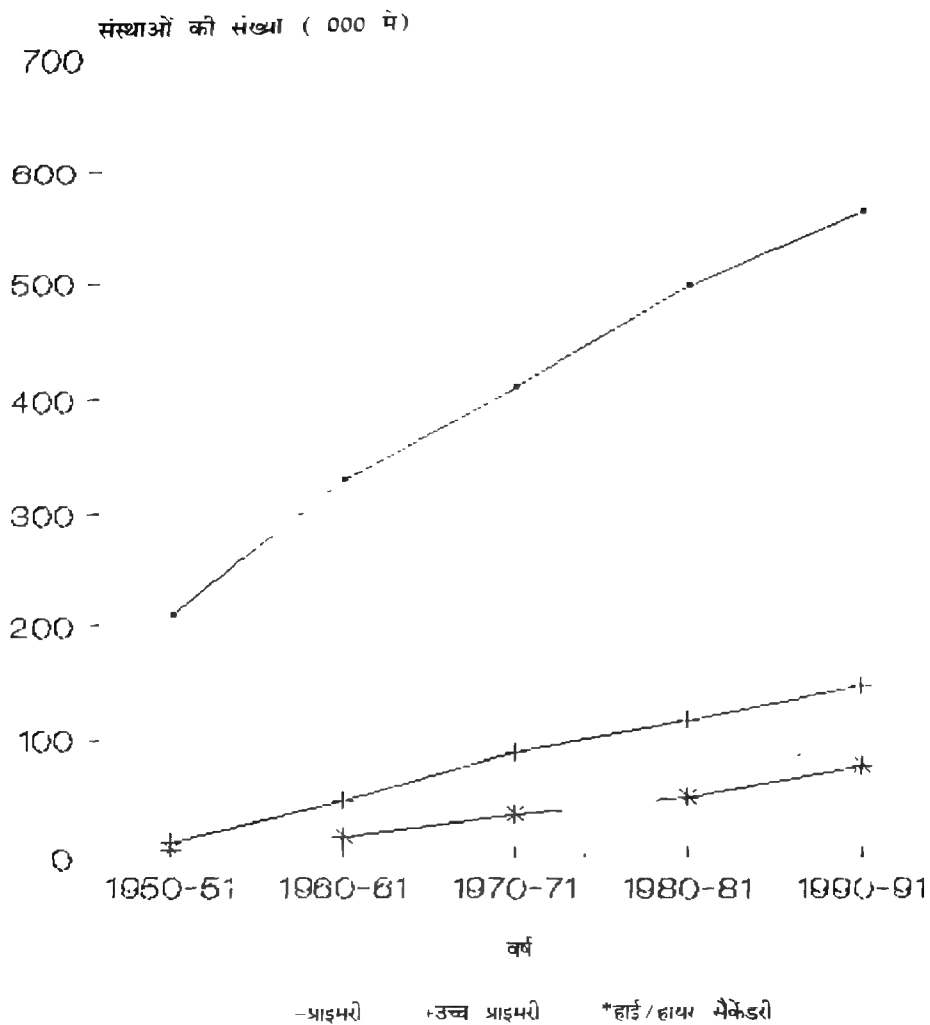
स क्षर द 1991

केरल	90.59
मिजोरम	81.23
लक्षद्वीप	79.23
चंडीगढ़	78.73
गोवा	76.96
दिल्ली	76.09
पांडिचेरी	74.91
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	73.74
दमन और दीव	73.58
तमिलनाडु	63.72
हिमाचल प्रदेश	63.54
महाराष्ट्र	63.05
नागालैण्ड	61.30
मणिपुर	60.96
गुजरात	60.91
त्रिपुरा	60.39
पश्चिम बंगाल	57.72
पंजाब	57.14
सिक्किम	56.53
कर्नाटक	55.98
हरियाणा	55.33
असम	53.42
भारत	52.11
उड़ीसा	48.55
मेघालय	48.26
अन्ध्र प्रदेश	45.11
मध्य प्रदेश	43.45
उत्तर प्रदेश	41.71
अरुणाचल प्रदेश	41.22
दादर नगर हवेली	39.45
राजस्थान	38.81
बिहार	38.54

महिले + क्षेत्र दर 1991

केरल	86.93
मिजोरम	78.09
चंडीगढ़	73.61
लक्षद्वीप	70.88
गोवा	68.20
दिल्ली	68.01
अडमान और निकोबार द्वीप समूह	66.22
पांडिचेरी	65.79
दमन और दीव	61.38
नागालैण्ड	55.72
हिमाचल प्रदेश	52.46
तमिलनाडु	52.29
महाराष्ट्र	50.51
त्रिपुरा	50.01
पंजाब	49.72
मणिपुर	48.64
गुजरात	48.50
सिक्किम	47.23
पश्चिम बंगाल	47.15
मेघालय	44.78
कर्नाटक	44.34
असम	43.70
हरियाणा	40.94
भारत	39.42
उड़ीसा	34.40
आन्ध्र प्रदेश	33.71
अरुणाचल प्रदेश	29.37
मध्य प्रदेश	28.39
दादर नगर हवेली	26.10
उत्तर प्रदेश	26.02
बिहार	23.10
राजस्थान	20.84

1951 से मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं की वृद्धि स्कूल स्तर



1951 से मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं की वृद्धि कालेज स्तर

संस्थाओं की संख्या (1000 में)

6 -

5 -

4 -

3 -

2 -

1 -

0

1950-51

1960-61

1970-71

1980-81

1990-91

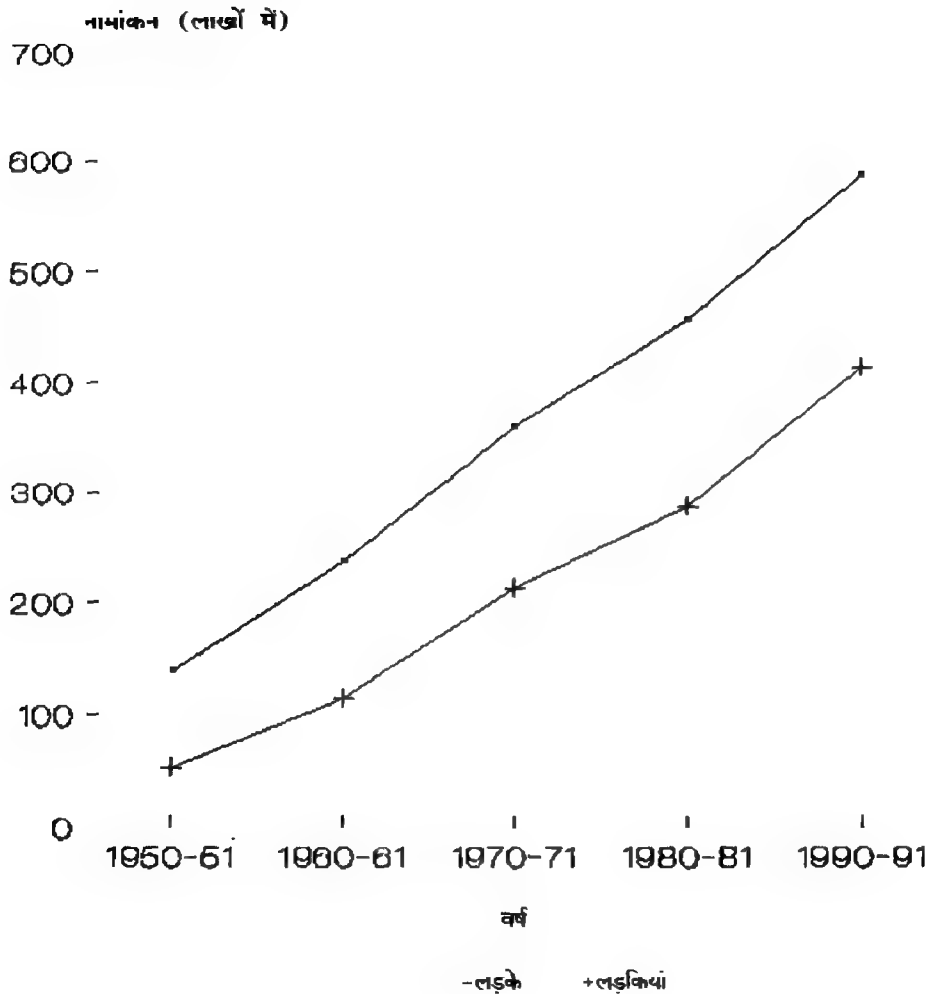
वर्ष

-कालेज सामान्य

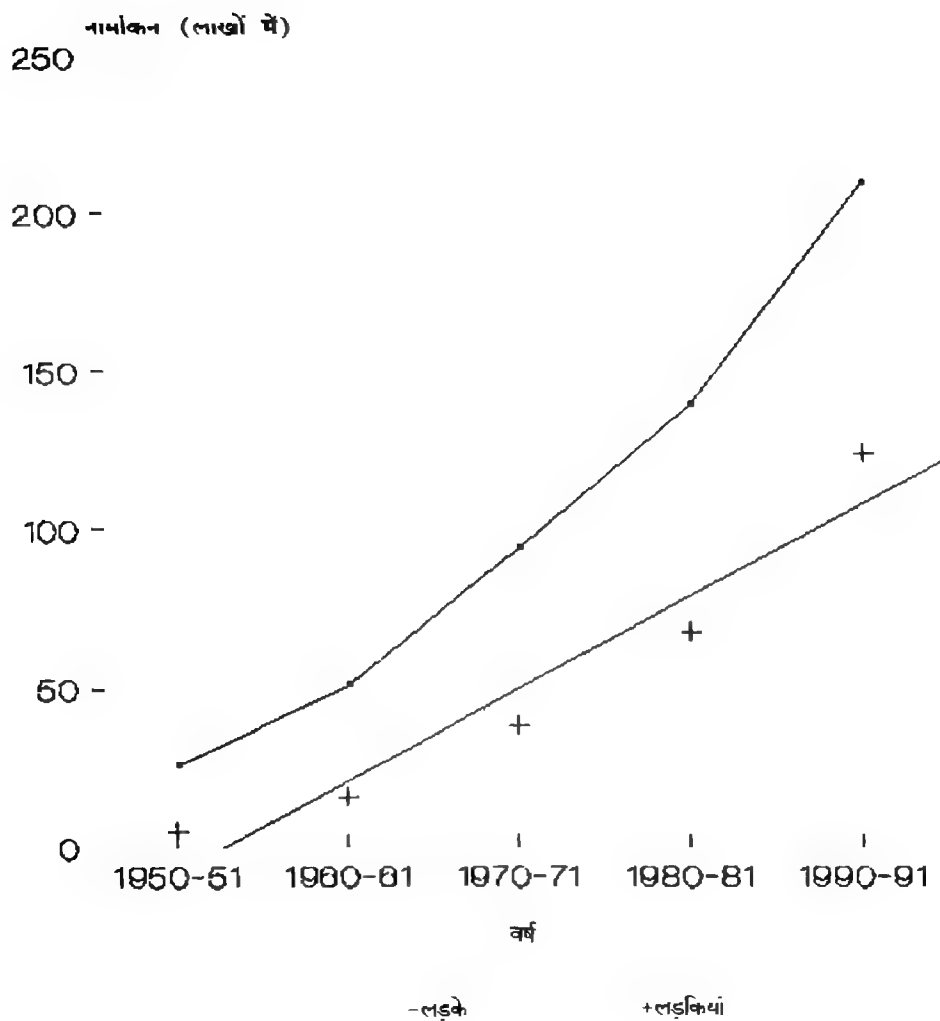
+कालेज व्यावसायिक

*विश्वविद्यालय

प्राइमरी कक्षाओं (I-V) में नामांकन

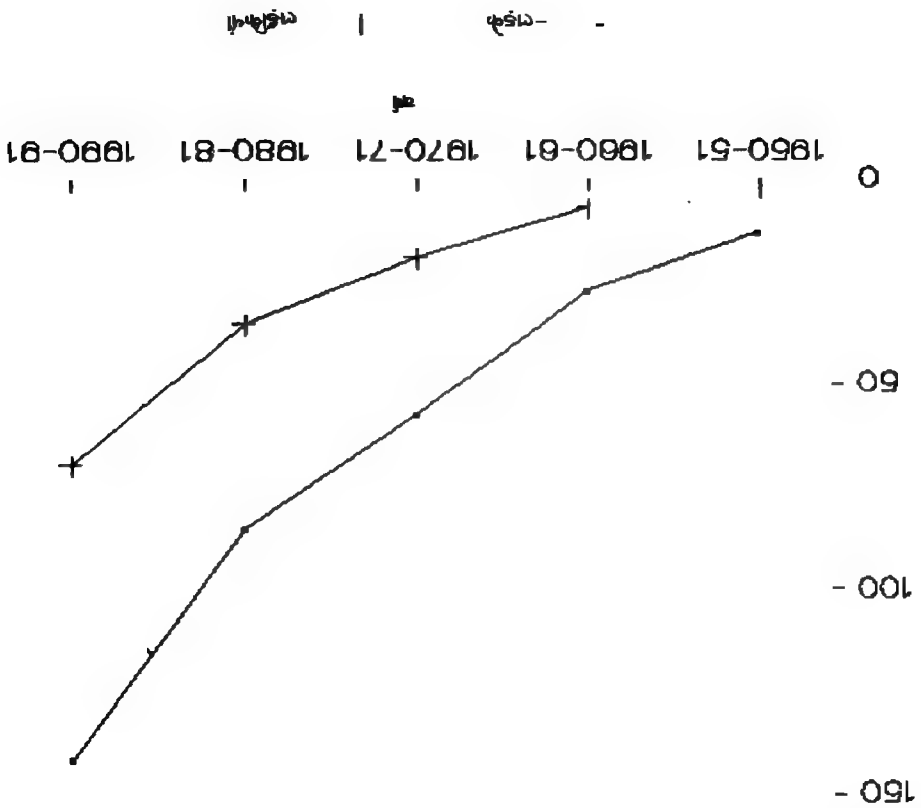


मेडल की कक्षाओं (VI-VIII)

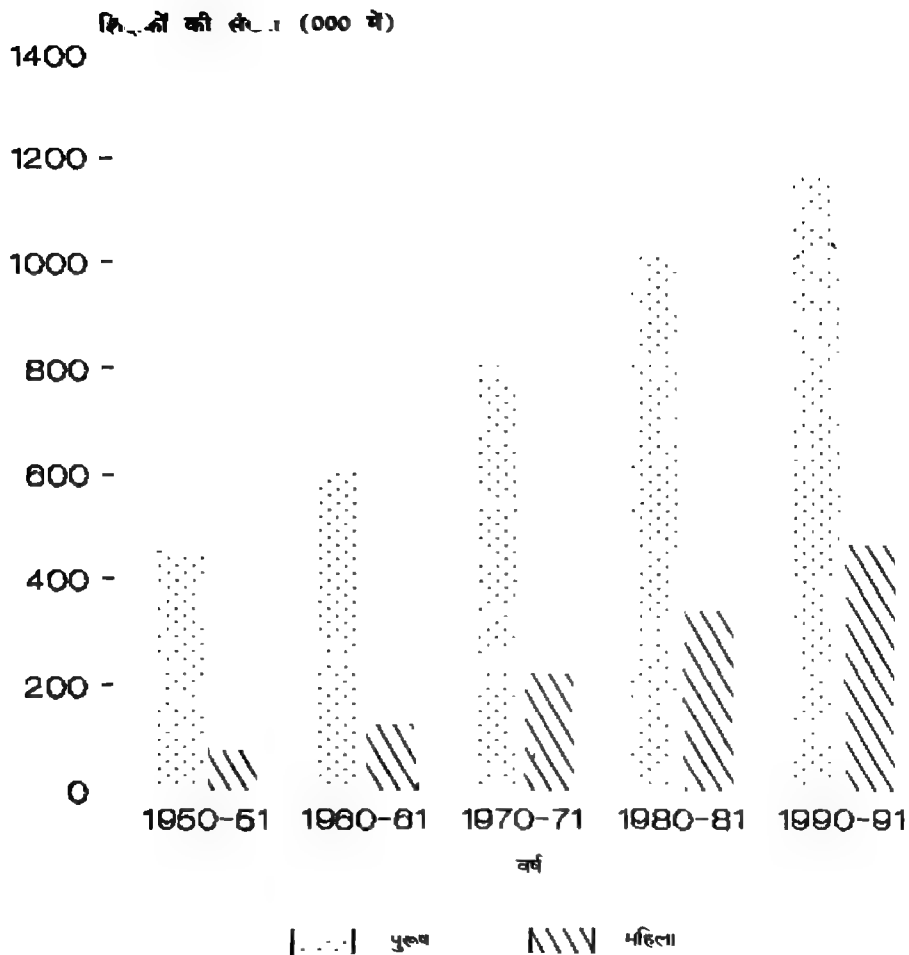


IX ਤੇ XII ਨਕ ਕੇ ਕਸ਼ਤੀਓਂ ਤੇ ਮਾਮਿਕਮ

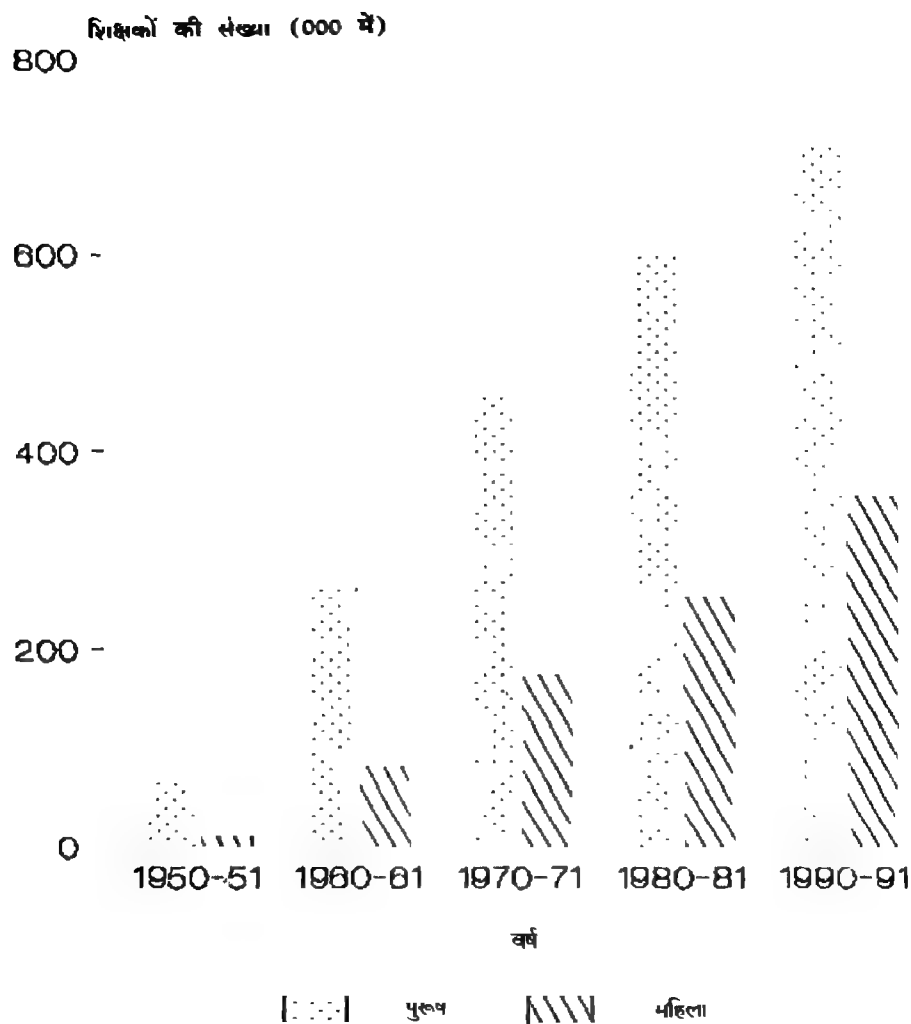
ਮਾਮਿਕਮ (ਮਾਮਿ ਤੇ)



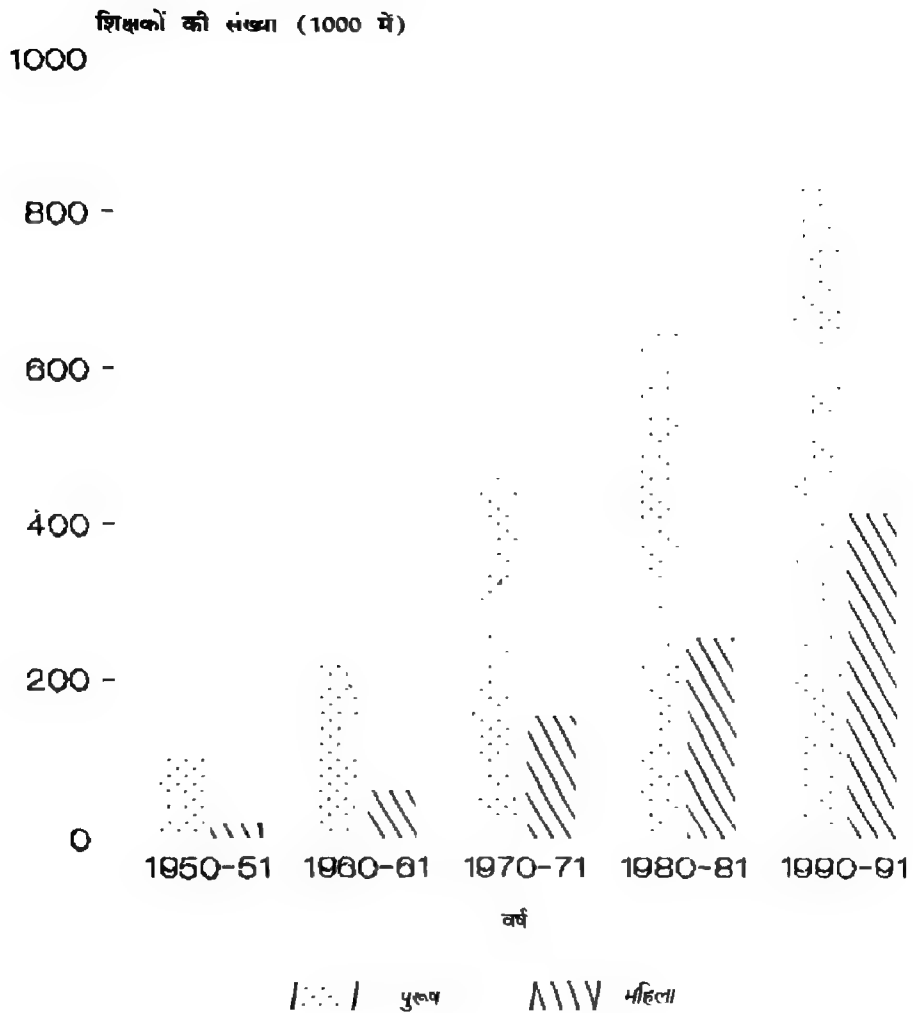
शिक्षकों का संवितरण प्राइमरी स्कूल



शिक्षकों को संवितरण मिडिल स्कूल



शिक्षकों का संवितरण हाई/हायर सेकेंडरी स्कूल



ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ମିଳିତ ଓ ଶାସନ

(୨୨୨-୨)

सकल पूर्ण कार्यक्रमों के लिए वित्तीय आवंटन

क्रमिक विवरण	योग-नागत / गैर योग-नागत	बजट भाकलन 1991-92 मूल	(लाख रु०)	
			बजट भाकलन 1992-93	संशोधित
1	2	3	4	5
आरंभिक शिक्षा				
1. आश्रमन लोक बोर्ड	योग-नागत	10000 00	17000 00	9914.00
2 (I) 9-14 वर्ष के उच्च वर्ग के लिए गैर औपचारिक केंद्र (समुदाय)	योग-नागत	4500.00	2400 00	4085 00
(II) लक्ष्मियों के लिए गैर औपचारिक शिक्षा केंद्र	योग-नागत	3000 00	1600 00	2725.00
(III) लैंगिक एजेंसियों के लिए अनुदान	योग	3000.00	1000 00	2200 00
		15.00	NIL	NIL
(IV) एस०आई०एच० की वित्तीय सहायता से धनस्थान में शुरू की गई शिक्षा कर्मी परियोजना	गैर-योग योग	230 00	230 00	470 00
(V) विहार शिक्षा परियोजना	योग-नागत	600 00	600 00	1200.00
(VI) एन० सी० टी० ई०	योग-नागत	100 00	30 00	50.00
(VII) मुख्य आयोजना का प्रचालन	योग-नागत	—	—	86.00
(VIII) यू०ई०ई० का अनुसंधान	योग	—	—	300 00
(IX) अभ्यर्थियों की उपलब्धता का सुधार	योग	—	—	200 00
(X) लोक जलविद्युत शिक्षा बैंक सहायता	योग	—	10 00	200 00
(XI) यू०ई० परियोजना	योग	—	—	10 00
(XII) दक्षिणी खोसा परियोजना	योग	—	—	10 00
3 शिक्षक शिक्षा				
(i) स्कूली शिक्षकों के लिए जन अवस्थान कार्यक्रम				
(ii) जिला शिक्षा और प्रशिक्षण	योग-नागत	6424 00	4000 00	6450 00
(iii) शिक्षक शिक्षा कलेज और शिक्षा के लिए उच्च अध्ययन संस्थान				
(iv) राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एस०आई०आई०एच०)				
माध्यमिक शिक्षा				
1 शिक्षा का व्यावसायिकरण	योग-नागत	8900 00	6500 00	7900.00
2 विकलांग बच्चों की समन्वित शिक्षा	योग-नागत	400 00	400 00	350.00
3 योग	योग-नागत	80 00	80.00	60 00
	गैर-योग-नागत	30.00	30 00	30.00
4 राष्ट्रीय खुला विद्यालय	योग-नागत	100.00	100.00	150.00
	गैर-योग-नागत	46 00	46.00	46.00
5 एन०सी०ई०आई०टी० के लिए अनुदान	योग-नागत	350 00	203 72	300.00
	गैर-योग-नागत	2282 00	2012.78	2220 00
6 अ. न. ए.	योग-नागत	100 00	100.00	100 00
7 विज्ञान शिक्षा	योग-नागत	2397 00	1898 00	2198.00
		300 00	200.00	290.00
उच्च शिक्षा				
शैक्षणिक विकास	योग-नागत	1727.27	1427.27	1400.00
	गैर योग-नागत	142 00	NIL	NIL
विश्वविद्यालय	योग-नागत	600 00	600 00	600.00
केंद्रीय विद्यालय	गैर-योग-नागत	16301 00	16301 00	16301 00
केंद्रीय विद्यालय	योग-नागत	421 00	421 00	421 00

1	2	3	4	5	6
13	नवोदय विद्यालय समिति	योग-नागत योग-नागत	6000 00 4450 00	7660 00 4450 00	7500 00 4450 00

उच्च शिक्षा और अनुसंधान

1	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	योग-नागत गैर-योग-नागत	12800 00 23820.00	14168.00 26820 00	12400 00 24709 00
2	भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, विम्बल	योग-नागत गैर-योग-नागत	35 00 110 50	35 00 109 00	35 00 110 50
3.	भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद	योग-नागत गैर-योग-नागत	45 00 65 00	45 00 55 00	40.00 65 00
4	भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद	योग-नागत गैर-योग-नागत	35 00 130 00	32 00 130 00	35 00 130 00
5	अखिल भारतीय उच्च अध्ययन संस्था	योग-नागत गैर-योग-नागत	20 00 17 85	34 75 17 85	38 00 19 00
6.	भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद	योग-नागत गैर-योग-नागत	275 00 424 25	324 00 424 25	250 00 424.25
7.	शास्त्री पारत-कमला संस्थान	योग-नागत गैर- योग-नागत	— 61 25	— 61 25	— 85 00
8	विश्वविद्यालय और कालेजों के शिक्षकों के वेतनमान में संशोधन	योग-नागत योग-नागत	7000.00	6000.00	6000 00
9.	राष्ट्रीय होच प्रोफेसर	योग-नागत योग-नागत	— 6 00	— 6 00	— 6 00
10.	पंजाब विश्वविद्यालय के लिए फ्रान्स	योग-नागत योग-नागत	50 00 —	50 00 —	50 00 —
11	डा० जफिर हुसैन मेमोरियल कलेज ट्रस्ट	योग-नागत योग-नागत	20 00 6 30	20 30 6 30	25 00 6 30
12	भारतीय विश्वविद्यालय संघ	योग-नागत योग-नागत	10.00 12 15	10 00 22 15	12 00 12 15
13	हिंदी गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय	योग-नागत योग-नागत	1900 00 776 00	657 00 500.00	1000 00 753 00
14	प्रशासन तज्ञ को और सुदृढ़ करना	योग-नागत योग-नागत	5 00 —	5 00 —	5 00 —
15	राष्ट्रीय उच्च शिक्षा परिषद	योग-नागत योग-नागत	1 00 —	1 00 —	5 00 —
16.	राष्ट्रीय परीक्षण सेवा	योग-नागत	10 00	10 00	23 00

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

1	ग (5) पारत में यूनेस्को अभ्यारणों के लिए आई. एन. सी. के रूप में पुस्तकालय का पूर्ण विकसित प्रोजेक्ट और स्टैटिक केन्द्र के रूप में पुनर्गठन	योग-नागत	100 00	100 00	150 00
2	ग (6(5) (6) यूनेस्को के लक्ष्यों और क्षेत्रों को और आगे बढ़ाने के लिए समितियों/परिषदों की बैठकों आयोजित करना				
3	ग (6(5) (7) यूनेस्को कार्यक्रमों और कार्यक्रमों में शामिल क्षेत्रीयसंगठनों को और सुदृढ़ करना	योग-नागत	400 00	300 00	350 00
4.	ग (1) (2) ओपेनले प्रबंध	योग-नागत	200 00	150 00	200 00
5.	बाध्य शैक्षिक समर्थन का सुदृढ़ीकरण	योग-नागत	1000 00	1000 00	10000.00
6.	ग 6 4(2) यूनेस्को कुरियर के हिन्दी और तमिल संस्करणों के प्रकाशन का खर्च	योग-नागत	1800 00	1800 00	1800 00
7	ग 6(4) (9) अन्य प्रदे आई एन सी. के कार्यक्रम के लिए गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान	योग-नागत	30.00	25 00	25 00
8	ग 6 (4) (9) अन्य प्रदे यूनेस्को के समूह सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय सहयोग आयोग	योग-नागत	65.00	60.00	60 00
9.	ग 6 (4) (9) अन्य प्रदे	संस्था और संरक्षण	5.00	5 00	—

1	2	3	4	5	6
10	ग 6(4) (1) यूनेस्को को योगदान	योजनेतर	2350 00	29000 00	29700 00
		योजनेतर	500.00	500 00	500 00
11	ग 6(4) (5) बिदेसी शिष्ट मङ्गलें द्वारा भारत का दौरा	योजनेतर	500.00	500 00	500 00
12	ग 6(4) (6) प्रतिनिधि मङ्गलें और शिष्ट मङ्गलें द्वारा विदेशों का दौरा	योजनेतर	600 00	1600 00	1600 00
पुस्तक प्रोजेक्ट और प्रतिनिध्याधिकार					
1	क्षेत्रीय कार्यालय / पुस्तक केन्द्र	योजनेतर	25 00	23 25	25 00
2	नेहरू बाल पुस्तकालय	योजनेतर	50 00	42 15	50 00
3	आदान-प्रदान	योजनेतर	10 00	4 65	9 00
4	आर्थिक सहायता योजना	योजनेतर	20 00	11 65	20 00
5	पत्राचार में पुस्तकें का पुन प्रकाशन	योजनेतर	6 00	5 54	5 00
6	सामान्य प्रौद्योगिकी कार्यक्रम	योजनेतर	25.00	24 05	30 00
7	नेहरू भवन	योजनेतर	5 00	5 00	5 00
8	उत्तर मास्टर शाखा के लिए प्रकाशन	योजनेतर	15 00	12 75	10 00
9	विद्यालय पुस्तकालय कार्यक्रम के लिए प्रकाशन	योजनेतर	8 00	2 80	4 00
10	उच्च कोटि के साहित्य का प्रकाशन	योजनेतर	3.00	1 90	2 00
11	आई एस बी एन (एन ई अफ सी)	योजनेतर	1.00	0 01	Nil
12	विदेशी विद्यालयों के पाठ्य पुस्तकों के पुनप्रकाशन हेतु सहयोग कार्यक्रम	योजनेतर	2 00	2 00	2 00
13	पुस्तक निर्यात प्रौद्योगिकी कार्यक्रम	योजनागत	12.00	10 00	12.00
14	पुस्तक निर्यात प्रौद्योगिकी कार्यक्रम	योजनागत	1 00	1 00	2 00
15	राष्ट्रीय लेखक बोम्बार्डों की स्थापना	योजनागत	6 00	11 00	4 00
16	नई बिस्को प्रोजेक्ट उपाय	योजनागत	2.00	1 25	3 00
17	कार-बुक परियोजना	योजनागत	6 00	6 00	5 00
18	बिस्को मण्डलों के लिए आर्थिक सहायता तथा पुस्तक प्रोजेक्ट कार्यक्रम	योजनागत	2 00	2 00	2 00
19	राष्ट्रीय पुस्तक विकास परिषद	योजनागत	168.00	153 53168 00	
20	अनुसूचित, अवस्थापना और प्रकाशन	गैर-योजनागत	42 00	30 95	42 00
21	सामान्य प्रौद्योगिकी कार्यक्रम	गैर-योजनागत	20 00	21 00	25 00
22	डब्ल्यू आई पी ओ (वाइपीओ) के लिए भारत का अग्रदान	गैर-योजनागत	2.00	2 00	2 00
23	अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिध्याधिकार सम (मेप)	गैर-योजनागत	50 00	50 00	5 00
24	विश्व पुस्तक मेला	गैर-योजनागत	110 00	90 00	100 00
छात्रवृत्ति					
1	राष्ट्रीय छात्रवृत्ति	योजनागत	285 00	285 00	285 00
2	राष्ट्रीय श्रृंग छात्रवृत्ति योजना	योजनागत	14 20	14 20	14 20
3	राष्ट्रीय श्रृंग छात्रवृत्ति योजना-वर्द्धित खाते में डालना आदि	गैर-योजनागत	22 0022 00		22 00
4	राष्ट्रीय श्रृंग छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत श्रृंग छात्रवृत्ति के संदर्भ में राज्य सरकार की 50% भागीदारी	गैर-योजनागत	35 00	25 00	55 00
5	अज्ञा/अज्ञा की गुणवत्ता में लगभग के लिए योजना	योजनागत			
6	ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर पर छात्रवृत्तियां	योजनागत	85 00	35 00	60 00
7	संस्कृत की छात्रवृत्ति अरबी, फारसी जैसी प्राचीन भाषाओं के अध्ययन में परंपरागत संस्थानों में शिक्षा प्राप्त लोगों के लिए शोध छात्रवृत्ति	गैर-योजनागत	220 00	120 00	205 00
8	अनुसूचित आंचलीय माध्यमिक विद्यालयों में छात्रवृत्ति	गैर-योजनागत	34 10	34 10	34 10
भाषाओं की प्रोजेक्ट					
हिन्दी					
1	केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय	योजनागत	65 00	63 00	63 00
		योजनेतर	121 50	123 50	127 03

18 00

1	2	3	4	5	6
3	केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा	योजनागत योजनागत	55 00 177 00	52 00 177 00	52 00 177 00
4.	हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति और उनका प्रशिक्षण	योजनागत	260 00	185 00	185 00
5	गैर-सरकारी संगठनों दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा और हिन्दी में प्रकाशित सहित को सहायता अन्य गै. म. स.	योजनागत योजनागत	180 00 102 50	180 00 102 50	180 00 102 50
6.	विदेशों में हिन्दी का प्रचार	योजनागत योजनागत	20 00 11 00	20 00 11 00	20 00 11 00
7	हिन्दी विश्वविद्यालय	योजनागत	5 00	1 00	1 00
आधुनिक भारतीय भाषाएं					
8.	केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान और जनजातीय भाषा विकास समिति इसके क्षेत्रीय भाषा केन्द्र।	योजनागत योजनागत	85 00 214 00	88 00 220 00	88 00 224 90
9	पुनर्गठन, समिति सहित तरकीब-ए-उर्दू बोर्ड	योजनागत योजनागत	70 00 42 00	70 00 43 37	70 00 43 37
10	गैर सरकारी संगठनों (सिंधी उर्दू और हिन्दी के अलावा) तथा यूएल=बी= को वित्तीय सहायता	योजनागत योजनागत	30 00 10 00	26 00 10 00	26 00 10 00
11	सिंधी लिखत बोर्ड, सिंधी भाषा में पुस्तकों के प्रकाशन के वित्त पोषण के लिए गैर सरकारी को वित्तीय सहायता	योजनागत	10 00	10 00	10 00
12	आधुनिक भाषा शिक्षक	योजनागत	100 00	41 00	41 00
अंग्रेजी					
13	अंग्रेजी शिक्षक और जिला केन्द्र, आर. आई. ई. और ई-एलटी-आई, इन संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने और इलेक्ट्रॉनिक जन माध्यम आदि के प्रयोग के प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता	योजनागत	85 00	72 00	72 00
संस्कृत					
1	सैद्धांतिक संस्कृत संगठनों, आदर्श संस्कृत महाविद्यालयों, शोध मन्थनों को अनुदान।	योजनागत	75 00	105 00	80 00
2	श्रीलाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति	योजनागत	10 00	10 00	10 00
3.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति का अनुदान	योजनागत	10 00	10 00	10 00
4	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली को अनुदान	योजनागत	151 00	110 00	151 00
5	रज्जु/सच शामिल क्षेत्रों में संस्कृत का विकास	योजनागत	56 00	56 00	56 00
6.	राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान	योजनागत	45 00	45 00	45 00
7	वैदिक पाठ की भौतिक परंपरा का परिरक्षण और अखिल भारतीय शिक्षा प्रतियोगिता	योजनागत	7 00	7 00	7 00
8	श्रेष्ठ भाषा (अरबी और फारसी) के लिए अनुदान/अनुवर्तित	योजनागत	14 00	14 00	15 00
1	सै. संस्कृत संगठन, आदर्श संस्कृत महाविद्यालय/शोध संस्थान को अनुदान	योजनागत	95 00	120 00	95 00
2	श्रीलाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठों को अनुदान	योजनागत	93 00	80 00	93 00
3	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति को अनुदान	योजनागत	70 00	53 65	70 00
4	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान को अनुदान	योजनागत	315 00	258 85	315 00
ग्रीक शिक्षा					
1	आयोग नव्यात्मक साक्षरता	योजनागत	2500 00	1500 00	1500 00

1	2	3	4	5	6
2	नेहरू युवक केन्द्र संगठन	योजनागत	125 00	125 00	150 00
3	उत्तर साक्षरता और स्तर शिक्षा	योजनागत	1000 00	1000 00	1000 00
4	प्रशासनिक सचचा को सुदृढ़ बनाना	योजनागत	500 00	595 00	700 00
5	कर्मचारी साक्षरता के जन कार्यक्रम	योजनागत	500 00	400 00	375 00
6	प्रौद्योगिकी प्रदर्शन	योजनागत	100 00	55 00	50 00
7	शैक्षिक एजेंसियां	योजनागत	1500 00	1200 00	1800 00
8	श्रमिक विद्यार्थी	योजनागत	100 00	119 00	130 00
9	ग्रैंड शिक्षा निदेशालय	योजनागत	110 00	144 00	250 00
10	राष्ट्रीय भाषाभाषा मिशन	योजनागत	10 00	10 00	10 00
11	सांस्कृतिक विनियम कार्यक्रम	योजनागत	5 00	2 00	5 00
12	विशेष परियोजना	योजनागत	5375 00	5150 00	5865 00
13	राष्ट्रीय ग्रैंड शिक्षा मंत्रालय	योजनागत	175 00	100 00	150 00
1	ग्रामीण कार्यकारी साक्षरता परियोजना	योजनागत	270 00	294 00	270 00
2	साक्षरता गृह, लखनऊ	योजनागत	17 20	16 84	17 08
3	श्रमिक विद्यार्थी	योजनागत	113 30	113 30	114 54
4	ग्रैंड शिक्षा निदेशालय	योजनागत	124 00	128 00	133 00
5	प्रिन्टिंग प्रदे	योजनागत	3 50	2 86	3 38
6	उत्तर साक्षरता	योजनागत	30 00	—	30 00
तकनीकी शिक्षा					
निर्देशन और प्रशासन					
1	राष्ट्रीय तकनीकी जनशक्ति	योजनागत	100 00	50 00	100 00
	सूचना पद्धति (गैर-जोड़)	योजनागत	50 00	57 00	50 00
2	अभ्यास-शिक्षा: तथा इसकी	योजनागत	100 00	10 00	180 00
	समर्थन/कोडों का पुनर्गठन	योजनागत	—	—	—
	पुनर्गठन और सुदृढ़ करना (डी-13)	योजनागत	—	—	—
3	विद्यार्थी मंत्रालयों को सुदृढ़ करना तथा गैर-समर्थित और अनियोजित	योजनागत	10 00	10 00	—
	क्षेत्रों के लिए नई मंत्रालयों को स्थापना (डी-12)	योजनागत	—	—	—
II प्रशिक्षण					
4	क्षेत्रीय इकोनॉमिक कालज	योजनागत	2400 00	1890 00	2400 00
	(क्षेत्रीय) डी-6(2)	योजनागत	2186 00	2072 00	2186 00
5	प्रशिक्षण प्रशिक्षण	योजनागत	250 00	233 00	250 00
	डी-2(5) और डी-2(6)	योजनागत	508 00	495 00	508 00
6	क्षेत्रीय मंत्रालय	योजनागत	—	—	—
	— तकनीकी शिक्षा प्रशिक्षण मंत्रालय	योजनागत	500 00	330 00	600 00
	डी-2(1)	योजनागत	490 70	372 00	501 90
	— राष्ट्रीय औद्योगिक इकोनॉमिक प्र म	योजनागत	150 00	150 00	150 00
	(गैर-जोड़-प्र-स) डी-2(2)	योजनागत	266 30	266 00	266 20
	— राष्ट्रीय दलाई एवं भट्टी प्रो-म	योजनागत	100 00	100 00	100 00
	(गैर-जोड़-प्र-स) डी-2(3)	योजनागत	117 60	117 60	117 60
	— आर्थिक एवं वास्तुशिल्प स्कूल	योजनागत	250 00	250 00	250 00
	(गैर-जोड़-प्र-स) डी-2(4)	योजनागत	180 00	170 00	180 00
III अनुसंधान					
7	भारतीय औद्योगिकी मंत्रालय	योजनागत	1500 00	1640 00	1600 00
	(गैर-जोड़-प्र-स) डी-6(1) से डी-6(1)(5) तक	योजनागत	9388 30	9438 80	9481 10
8	भारतीय प्रबंध मंत्रालय	योजनागत	900 00	800 00	800 00
	(गैर-जोड़-प्र-स) डी-6(4)(1) से डी-6(4)(4)	योजनागत	959 20	959 00	959 20
9	आतंकवाद पाठ्यक्रमों का विकास	योजनागत	110 00	50 00	100 00
		योजनागत	400 00	400 00	400 00
10	गैर विश्वविद्यालय केंद्रों पर प्रबंध शिक्षा पाठ्यक्रमों का	योजनागत	30 00	1 00	40 00
	विकास डी-6(3)	योजनागत	9 85	—	10 35

1	2	3	4	5	6
11	संस्थागत नेटवर्क योजना डि० 7(1)(1)	योजनागत योजनागत	100 00 —	100.00 —	— —
12.	अन्तर्राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा केन्द्र (अन्विप्रौ०शि० केन्द्र) डि० 3(2)	योजनागत योजनागत	1 00 —	10.00 —	10 00 —
13	चुनिदा उच्च तकनीकी संस्थाओं में शोध और विकास, डि० 3(4)	योजनागत योजनागत	350 00 —	350 00 —	250 00 —
14.	सामुदायिक पालिटेक्निक डि० 5(1)	योजनागत योजनागत	200 00 165 00	200 00 175 00	300 00 184 90
15	आधुनिकीकरण और अभ्यन्तरी को दूर करना डि० 6(5)(3)	योजनागत योजनागत	3300 00 —	3000 00 —	3000 00 —
16	तकनीकी शिक्षा के महत्वपूर्ण क्षेत्र (i) प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, सुविधाओं का सुदृढीकरण जहाँ कमी विद्यमान है। डि० 6(5)(1) (ii) उपर्युक्त प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में आधारभूत ढांचा सबसे सुविधाओं का सृजन। डि० 6(5)(2) (iii) नए और उन्नत प्रौद्योगिकी के कार्यक्रमों को प्रोत्साहित क्षेत्रों में पाठ्यक्रमों को प्रकाश करते हैं। डि० 2(8)	योजनागत योजनागत योजनागत योजनागत योजनागत	800 00 — 900 00 220 00 800 00	731 00 — 900 00 220 00 800 00	750 00 — 900 00 220 00 750 00
17	संस्था-उद्योग अन्वेषण क्रिया डि० 6(6)	योजनागत योजनागत	100 00 —	80 00 —	80 00 —
18	सतत शिक्षा डि० 6(7) (iv) अन्य योजनाएँ	योजनागत योजनागत	149 00 —	65 00 —	100 00 —
19	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, असम डि० 6(1)(6) और एफ 3(15)(1)	योजनागत योजनागत	300 00 —	340 00 —	800 00 —
20	लोगोवाल इन्वॉन्टरी और प्रौद्योगिकी संस्थान डि० 7(6)	योजनागत योजनागत	500 00 —	800 00 —	500 00 —
21	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योजनाएँ डि० 4(1)	योजनागत योजनागत	2200 00 —	2230 00 —	2200 00 —
22	भारत शैक्षिक प्रामाणिकता लिंग (प्रान्ता-शैक्षिक) एच एए 1(1)	योजनागत योजनागत	10 00 —	10 00 —	— —
23	सुपर संगणक आई०आई०एस०सी० बंगलौर डि० 4(2)	योजनागत	220 00	732 00	600 00
24	राष्ट्रीय प्रत्ययन बोर्ड डि० 1(4)	योजनागत योजनागत	15 00 —	1 00 —	20 00 —
25.	स्टाफ विकास एवं प्रशिक्षण डि० 2(9)	योजनागत योजनागत	5 00 —	1 00 —	18 00 —
26	प्रौद्योगिकी पूर्वानुमान डि० 3(5)	योजनागत योजनागत	5 00 —	1 00 —	20 00 —
27	व्यावसायिक निष्कर्षों को सहायता डि० 7(7)	योजनागत योजनागत	5.00 —	1.00 —	20 00 —
28	तकनीकशिक्षण शिक्षा को विश्व बैंक परियोजना सहायता डि० 3(3)(1)	योजनागत योजनागत	60 00 —	25 00 —	30 00 —
29	क्षेत्रीय कार्यालय डि० 1(1) — डि० 1(3)	योजनागत	46 40	46 40	50 00
30.	कोटि कोटि प्रचार कार्यक्रम डि० 2(7)	योजनागत	190 40	290 40	290 00
31.	विदेश जाने वाले भारतीय वैज्ञानिकों को आर्थिक वित्तीय सहायता (आ-वि०स०) डि० 3(3)	योजनागत	2 00	1 00	2 00
32.	भारतीय तकनीकी शिक्षा सोसाइटी (प्रान्त-शैक्षिक) डि० 7(3)	योजनागत	0 60	0 50	0 60
33.	ए०आई०टी०, बैकक डि० 7(4)	योजनागत	12 15	12 00	12 15
34	सांस्कृतिक विनियम कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रतिनिधि पेंडल	योजनागत	1 00	0 50	1 00
35	तकनीकी संस्थाओं के शिक्षकों के वेतनमान का संशोधन/ राज्य/संस्थाओं के कलेक्टरों को सहायता एफ (8)(1)	योजनागत	850 00	850.00	800 00

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

शिक्षा विभाग

मानव संसाधन विकास मंत्री

શિક્ષા સચિવ

(શ્રી અનિલ બોદિયા)

शिक्षा सलाहकार

पञ्चमः

Find

अपर भविष्य

(श्री आः कं मिम)

[illegible]